

अपनी मृत्यु के पूर्व सन् १८१६ में दरमुज पर उमने पुर्तगाली पताक फहरा दी। इस तरह थोड़े ही काल में एलबुर्क की दूरदर्शिता, चतुरता और वीरता से पूर्व में पुर्तगाल एक बड़ी शक्ति बन गया।

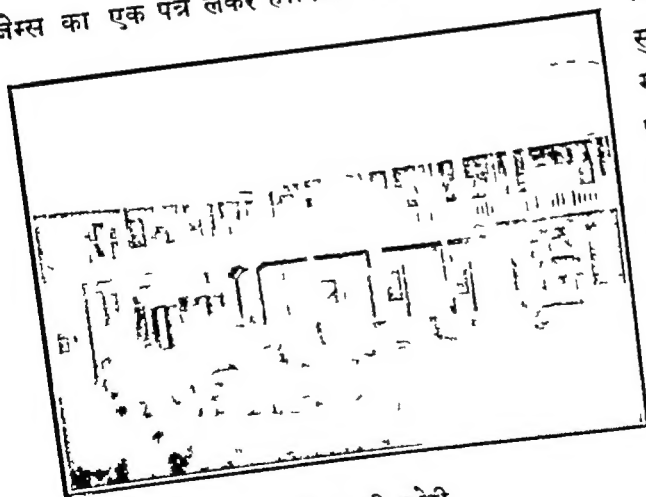
**पुर्तगालियों का पतन**—परन्तु यह शक्ति बहुत दिन तक कायम रह सकी। एलबुर्क के मरने पर इसका संचालन ऐसे लोगों के हाथ आया, जिन्हें वास्तविक व्यवस्था का पूरा ज्ञान न था। पुर्तगाली कटर डेस थे, पोप के आज्ञा पत्र के बल पर उन्होंने भारतवर्ष में अपना राज्य जमाना चाहा था। वास्कोडुगामा पहली बार जब भारतवर्ष में आया था, उस अनुमान था कि मुसलमानों को छोड़कर सब भारतवासी ईसाई हैं। इस विश्वास पर कालीकट के निकट एक हिन्दू-मन्दिर में पुर्तगालियों ने पूजन किया था। हिन्दू-मूर्तियों को वे ईसाई-सन्तों की मूर्तियाँ समझते थे। पुर्तगाल के राजा भी इसी भुलावे में थे, केवल को आज्ञा-पत्र देते समय इन 'पथभ्र' ईसाइयों को 'सदुपदेश' देने के लिए कहा गया था। वास्कोडुगामा कु लोगों को पकड़ ले गया था, वे पकड़े ईसाई बनकर वापस आये। कालीकट निवासियों ने उनके साथ खाना-पीना अस्वीकार किया, तब पुर्तगालियों आखिरी गुली, और उनको अपनी भूल का पता लगा। तभी से ईसाई-के प्रचार का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ।

धर्म-प्रचार की धुन में व्यापार और साम्राज्य का ध्यान जाता एलबुर्क सा दूरदर्शी शामक भी इसी धुन में पड़ गया। गैर-ईसाई ज की तरह तरह की पीड़ाएँ दी जाने लगीं। सैन्यामियों का रूप धारण भोली भाली जनता को धोखा दिया जाने लगा, और 'ज्ञानोपदे' नाम से ईसाई-मत का प्रचार होने लगा। पादरी लोग राज-काज हस्तक्षेप करने लगे। ये लोग उत्तरी भारत भी जा पहुँचे और सम्राट् अकबर तक को ईसाई बनाने का स्वप्न देखने लगे। भारतवर्ष ईसाई न बन सका, पर इस धर्म-प्रचार का यह फल अवश्य हुआ



**ईस्ट इंडिया कम्पनी**—सन् १७८८ में अंगरेजों ने स्पेन के एक बड़े भारी जहाजी वेडे 'आर्मेटा' को नष्ट कर डाला। इस विजय के आनन्द में अंगरेजों को सागर-साम्राज्य का स्वान दिव्यलाई देने लगा। अंगरेज-जहाज स्पेन और पुर्तगाली जहाजों को लूटने लगे। इन दोनों जातियों के व्यापार में भी हस्तक्षेप करने का यह अच्छा अवसर मिल गया। सन् १६०० में लन्दन के व्यापारियों की एक कम्पनी स्थापित हुई, जिसको पूर्व में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजबेथ ने आज्ञा दी। कुछ दिनों तक तो समाले के टापुओं में व्यापार जमाने का प्रयत्न होता रहा, पर सन् १६०३ में मिल्डन हाल नामक अंगरेज फिर सम्राट् अकबर के पास भेजा गया। इस बार भी पुर्तगालियों ने सम्राट् के कान भर दिये, और मिल्डन हाल को कोरे ही विलायत वापस जाना पड़ा।

**हाकिंस और सर टामस रो**—सन् १६०८ में इंग्लैंड के राजा पहले जेम्स का एक पत्र लेकर हाकिंस सम्राट जहागीर के दरबार में पहुँचा, और



सूरत की कोठी

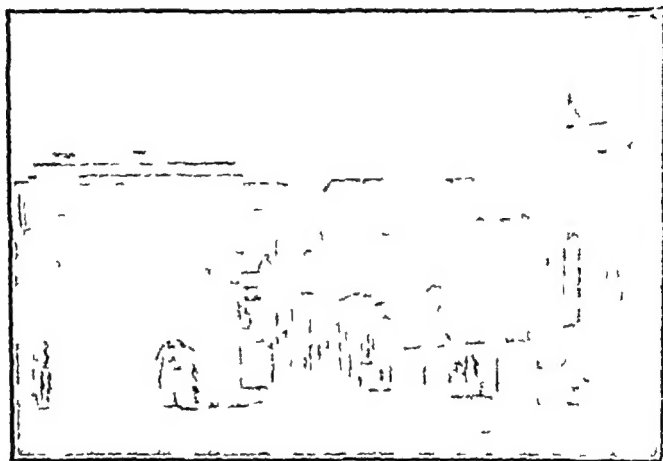
विचित्र कहानियाँ सुना सुनाकर उसने मन-मौजी सम्राट् पर अपना खूब रंग जमाया। जहांगीर उसको 'इंगलिश-खा' कहा करता था, परन्तु पुर्तगालियों के पड़्यंत्र में उसे भी शीघ्र ही दरबार छोड़ना पड़ा। सन् १६१२ में गुजरात के मुगल सूबेदार के अनुग्रह से जैसे तैसे सूरत में अंगरेजों की सबसे पहली कोठी खोली गई। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर सूरत उन

दिनों सबसे मुख्य म्थान था। यहाँ सब तरह का व्यापार होता था, और पूर्वीय द्वीपों के जहाज़ ठहरते थे। यहाँ भी पुर्तगालियों ने अँगरेजों का पीछा न छोड़ा, वे मुगल सूबेदार को अँगरेजों के विरुद्ध बहकाने लगे, परन्तु अँगरेजों ने समुद्र पर उनकी अच्छी खबर ली। फारस की खाड़ी में ईरानियों की नवायता से उन्होंने समुज छीन लिया, और पुर्तगाली जहाज़ों का अच्छी तरह लूटा। हाकिम के चले जाने पर कुछ दिनों तक मुगल दरबार में अँगरेजों की कोई सुनवाई न हुई। सन् १६१५ में कम्पनी की प्रार्थना पर इंग्लैंड के राजा पहले जेम्स ने सर टामस रो को अपना राजदूत बनाकर जहागीर के दरबार में भेजा। टामस रो तीन वर्ष तक मुगल दरबार में रहा, सब तरह से अपने सम्राट् को रिक्साया, पर इंग्लैंड से छोटे द्वीप के राजा के साथ मुगल सम्राट् बराबर की सन्धि करने के लिए राजी न हुआ। अन्त में रो को गाँही फरमान पर ही सन्तोष करना पड़ा। इसके द्वारा गुजरात के सूबेदारों को आज्ञा दी गई कि वे सुरत और अहमदाबाद के अँगरेज कोठीवालों का तग न किया करें साथ ही उन्हें देश भर में व्यापार करने तथा अपने धर्मानुसार रहने के अधिकार दिये गये। चलते समय रो ने कम्पनी को सदा व्यापार में लगे रहने की सलाह दी, और राजनैतिक झगड़ों में पड़ने से मना किया। इसका मत था कि व्यापार और युद्ध दोनों एक साथ नहीं हो सकते।

**मदरास, कलकत्ता और बम्बई**—पश्चिमी तट पर रुई एक कोटिया खोलकर अँगरेज पूर्व की ओर बढ़ने लगे। सन् १६०५ में नीलोर जिले में अरमगांव में उन्होंने एक कोठी खोली, पर यहाँ के शासकों से तग आकर सन् १६३६ में पूर्वी तट पर उन्होंने कुछ जमीन भाटे पर ली। बाद में यहाँ के नायक से समझौता करके चन्द्रगिरि के राजा के आज्ञानुसार उन्होंने भागत-भूमि पर सेंट जार्ज नाम का पहला किला बनाया। यह किला और इसके आस-पास की आबादी ही आधुनिक मदरास है। सुरत के अँगरेज डाक्टर वाइटन के इलाज से सम्राट् गाहजर्हा की लट्ठी जहाँनाग अच्छी हो गई, इस पर अँगरेजों को दंगाल में भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई। सन् १६३३ में पहले बालासोर में एक कोठी बनी फिर सन् १६५१ में हुगली के



पास एक बस्ती बसाई गई। सन् १६१० में कम्पनी के एक गुमास्ता जोन चार्नक ने वर्तमान कलकत्ता नगर की नींव डाली, यहीं पर फोर्ट-विलियम किला बना। सन् १६६१ में इंग्लैंड के राजा दूसरे चार्ल्स को बम्बई का द्वीप दहेज में मिला। यह द्वीप पुर्तगालियों के पास था, उच्च लोगों के विरुद्ध

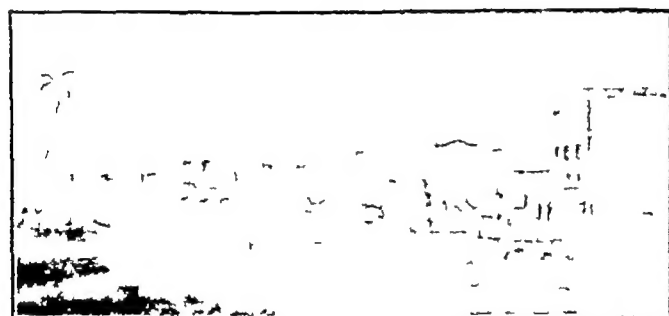


मद्रास किले का एक भीतरी दृश्य

अंगरेजी सहायता लेने की आशा से पुर्तगाल ने इस स्थान को दहेज में दिया था। उस समय चार्ल्स इस स्थान के महत्त्व को न समझ सका, और केवल दस पाँड सालाना पर उसने यह द्वीप कम्पनी को दे दिया। जैसे जैसे अंगरेजों की बढ़ती होती गई, इन स्थानों में अधिक भूमि मिलती गई, और अन्त में ब्रिटिश भारत के ये तीन मुख्य प्रान्त होगये। ये तीनों प्रांत प्रेसीडेंसी कहलाते हैं। प्रेसीडेंसी पहले उस जगह का नाम था, जहाँ कम्पनी की किसी कोठी का अध्यक्ष यथवा प्रेसीडेंट और उसकी कौंसिल बैठते थे।

**मुगलों के साथ युद्ध**—सन् १६६३ में जोशिया चाइल्ड सूत की कोठी का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। इस समय भारतवर्ष में गौरगजेब का शासन

ग, उनकी नीति से प्रजा असन्तुष्ट हो रही थी। दक्षिण में मराठों ने बगावत कर दी थी, दूसरे प्रान्तों में भी अशान्ति की आग सुलग रही थी। ऐसी दशा में अंगरेजों को भी अपना राज्य स्थापित करने की सूझने लगी। वे बंगाल के इस्तेमाल से लड़ बैठे। फल यह हुआ कि मुगल सम्राट् की आज्ञा से पटना कासिम-बाजार और मछली-पट्टन की कोठियाँ अंगरेजों से छीन ली गईं। पुरत में भी अंगरेजों को निकाल बाहर करने की आज्ञा हो गई। अंग-



पुराना कलकत्ता

रे की इस समय क्या शक्ति थी कि वे मुगल सम्राट् का सामना कर सकते। बिना सोचे-समझे उन्होंने सेना भेजने के लिए विलायत लिख दिया था। अब उन्हें अपनी भूल मालूम हुई। परन्तु उन्होंने इस समय पर ही बुद्धिमानी से काम लिया। पश्चिमी तट पर जो मुगल जहाज थे उन्हें हटा लिया, और हज्ज के लिए मक्का शरीफ जानेवाले मुसलमान यात्रियों का रस्ता बंद कर दिया। इस पर अंगरेजों ने अपनी नीति बदल दी, ५ हजार पाँड ज़रमाना लेकर कम्पनी को क्षमा कर दिया, और फिर से व्यापार करने की आज्ञा दे दी।

**नयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी**—सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में डच ने कम्पनी के बहुत से दिरंगी उत्पन्न होगये। इसका मान्य-मूल देखकर और व्यापारी भी भारतवर्ष में व्यापार करने का विचार करने

लगे। थोड़े दिन बाद उन्होंने एक नई कम्पनी बनाई। पुरानी कम्पनी के संचालक इसे सहन न कर सके, फल यह हुआ कि दोनों में खूब झगडा चल पडा। इंग्लैंड और भारत दोनों देशों में दोनों कम्पनियों के कर्मचारी आपस में लड़ने लगे। इस परम्पर की फट से व्यापार को बहुत धक्का पहुँचा, और दोनों कम्पनियों को ज्ञात होगया कि इसमें किसी का भी लाभ न होगा। इस पर दोनों ने समझौता कर लिया और मन् १७०० में ये दोनों कम्पनियाँ एक में मिला दी गईं। आगे चल कर इसी मयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारतवर्ष में राज्य हुआ।

अन्य विदेशी कम्पनियों की तरह इसका संचालन इंग्लैंड के सरकार के हाथ में न था। पांच सौ पाँड के हिस्सेदारों की एक मन्थी, जो 'कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स' कहलाती थी, कम्पनी के सम्बन्ध की मावातों का अन्तिम निर्णय इस संस्था के हाथ में था। इसमें से चुने हुए कुछ मेम्बरो की एक छोटी समिति थी, जो 'कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स' के नाम से प्रसिद्ध थी। कम्पनी का संचालन और साधारण प्रबन्ध इस मन्थी के हाथ में था। इन दोनों संस्थाओं में बड़ी खटपट रहती थी। मन्थी वर्ष में बम्बई, मदरास और कलकत्ता ये तीन मुख्य स्थानों में जहाँ इसके अव्यक्त रहते थे। इन अव्यक्तों की एक छोटी सी कांसिल भी रहती थी। इंग्लैंड के राजा दूसरे चार्ल्स के एक आज्ञा-पत्र से इनको अपना रक्षा के लिए कुछ सेना रखने और गैर-ईसाई शक्तियों से युद्ध तथा सन्धि करने के भी अधिकार मिल गये थे। इनका व्यापार वनियों के द्वारा होता था। हर एक वनिये के कई एक गुमाश्ते रहते थे, जो अव्यक्त का परवाज लेकर माल खरीदने के लिए जमीन्दारों के पास जाते थे। गाँवों में इस रहने का स्थान कचहरी कहलाता था। हरकारों के द्वारा यहाँ वह दल और जुलाहा को बुलाता था, और उनको कुछ पेशगी देकर लिखा जाता था कि अमुक समय तक इतना माल उनको इतने दाम पर देना होगा।

इन दिनों कम्पनी के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम होता कोठियों के अव्यक्तों को पचास रुपया माहवार से अधिक न मिलता था।

निजी लाभ के लिए वे किसी प्रकार का व्यापार न कर सकते थे इसका एकमात्र अधिकार केवल कम्पनी को था। ऐसी दशा में अनुचित उपायो से वे अपना काम चलाते थे। इंग्लैंड से इनका निरीक्षण अशुभव था था, क्योंकि कम से कम एक वर्ष में तो वहां से पत्र ही आता था। सारा काम बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ में था। कम्पनी के सचालक, डाइरेक्टरो को, उनकी कार्यवाहियों का पता तक भी न लगता था।

**फ्रांसीसी कम्पनी**—पुर्तगाल, हालैंड और इंग्लैंड की देखादेखी नवहवीं शताब्दी में फ्रांस ने भी भारतवर्ष से व्यापार प्रारम्भ किया। सन् १६४२ में फ्रांसीसी मंत्री रीगलू के उद्योग से एक कम्पनी स्थापित हुई पर इसका काम नहीं चला, इसलिए सन् १६६४ में एक दूसरी कम्पनी स्थापित की गई। इस कम्पनी ने एक कोटी सूरत में और दूसरी मद्रासी-पट्टन में खोली। इसके दस वर्ष बाद पाटुचेरी की नींव पड़ी। कलकत्ता के पास चन्द्रनगर में भी इन लोगों ने एक कोटी खोली। इन दिनों यूरोप में हालैंड और फ्रांस में युद्ध छिटा हुआ था, इसका प्रभाव भारत-वर्ष में भी पड़ा। यहाँ भी फ्रांसीसी और डच लोगों में झगडा होने लगा। सन् १६६५ में डच लोगों ने पाटुचेरी पर अधिकार कर लिया, परन्तु बाद की स्थिति हो जाने पर लौटा दिया। फ्रांसीसियों ने भी डच व्यापार को ग़रब जति पहुँचाई। इन दोनों की अनवरत से इंग्लैंड ने मनमाना लाभ उठाया। मुगल साम्राज्य का पतन होने पर फ्रांस को भी भारत में राज्य स्थापित करने की सूझी, पर इस उद्योग में उसको इंग्लैंड ने घोर लड़ाई करनी पड़ी, जिसका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा।

**अन्य कम्पनियाँ**—सन् १६५६ में डेन्मार्क-निवासियों ने भी एक कम्पनी बनाई। सन् १६७६ में कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में इनकी बोड़ी खुली। सन् १७३१ में स्वेडनवालों ने भी इसके लिए प्रयत्न किया। सन् १७४४ में प्रणिया के राजा, और सन् १७८४ में आस्ट्रिया के सम्राट् न भी कम्पनियाँ स्थापित कीं। प्रणिया की कम्पनी के साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करने में। जब सचालकों को यह पता

लगा, तब उन्होंने इसको रोकने के लिए बड़ी कड़ी याज्ञा दी। यूरोप के राजनैतिक झगड़ों और उच्च तथा अंगरेजों के प्रबल विरोध के कारण, इन कम्पनियों को सफलता प्राप्त न हुई, और थोड़े ही दिनों में इनका काम बन्द हो गया।

**अंगरेजों की सफलता**—सत्रहवीं शताब्दी में भारत की अतुल सम्पत्ति देखकर यूरोप की सभी जानियाँ ललचा रही थीं। उनके व्यापार में सभी ने हिस्सा लगाना चाहा, पर अन्त में अंगरेजों के मिव और किसी की दाल न गली। इसके कई कारण थे। पुर्तगाली सबसे पहले आये, पर वे भारत की परिस्थिति को न समझ सके। धर्मप्रचार के धुन में पड़कर उन्होंने अपना व्यापार अपने हाथ चौपट कर डाला। उनकी संकीर्ण नीति और उसके परिणामों का उल्लेख किया जा चुका है। अल मिडा की सलाह पर न चलकर उन्होंने भारी भूल की। उनकी जहाज शक्ति सदा कमजोर रही। पुर्तगालियों के बाद उच्च लोग आये। ये बहादुर और वीर थे, इनके पास धन की कमी न थी, और राज्य की ओर भी पूरी सहायता मिलती थी। परन्तु इनका ध्यान भारत की अपेक्षा मनातों के टापुओं की ओर अधिक था, इसके अलावा जहाजी ताकत में अंगरेजों को मुकाबला करना सहज न था। फ्रांसीसी औरों की अपेक्षा देर में आये उनकी कम्पनी सरकारी कम्पनी थी, उसके कारबार में वहाँ के राजकर्मचारियों वरावर हस्तक्षेप किया करते थे। फ्रांसीसी व्यापार-जला में दखल न थे, इसलिए व्यापार में उन्होंने कोई विशेष उन्नति नहीं की। अंगरेजों ने प्रारम्भ से ही अपनी जहाजी ताकत बढ़ाने का प्रयत्न किया। भारत के व्यापार में वनागरो का महत्त्व भली भाँति समझते थे। उनके नाविक चतुर और साहसुर थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य में विशेष सम्बन्ध न था। प्रसिद्ध व्यापारियों के उद्योग में ही उसकी स्थापना हुई थी। इस समय इसका संगठन ऐसा था कि राजकर्मचारियों को मनमाना हस्तक्षेप करने का अवसर बहुत कम मिलता था। इंग्लैंड के राजा रुपये के लालच से सदा इसकी सहायता करने के लिए उद्यत रहते थे। कम्पनी के कर्मचारी बड़े व्यापार-कुशल

## परिच्छेद २

### फ्रांसीसी और अंगरेज

माल, दबाह

॥ अराजक अशान्ति—मुगल सम्राट् आरगजेव के जीवन काल में अराजक अशान्ति की नीति के कारण देश भर में अशान्ति की आग सुलग गई, इसके मरने पर तो वह पूर्ण रूप से भस्म हुई। पाट ही दिनों में अराजक का दिल्ली तक आतक जम गया। पंजाब में सिख रिगड़ पड़। माल व साम्राज्य से अलग होगये। चतुर मुगलमान सरदार भी स्वतंत्र हो। सा प्रयत्न करने लगे। सन् १७२२ में दक्षिण का सूबेदार शम्सुद्दौला की बर बनाया गया, दो ही वर्ष में उसने दिल्ली दरबार की दुर्दशा देख ली। सन् १७२४ में वापस जाकर हैदराबाद में निजाम राज्य का नींव डाला। सीधे के सूबेदार सादतुल्लाह ने दिल्ली में सम्मन्ध तोड़ दिया। पंजाब के सिंधुदर अलीवर्दीखाने ने राज्य-वर भेजना बन्द कर दिया। गंगा व उत्तरी गंगा में रहेंलो ने रहेंलखंड का राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह सन् १७२४ में सारा मुगल साम्राज्य बिखर-भिन्न हो गया, सुबेदार स्वतंत्र हो गये, आर अकबर के उत्तराधिकारी नाम-मात्र के लिए सम्राट् रह गये। सारे देश में अशान्ति फैल गई, और आसन ही में घुट गया। ऐसी दशा में यूरोप के लोगों का भारत में अपनी शक्ति बढा करण का अच्छा अवसर मिल गया। इनमें इस समय सबसे आगे और फ्रांसीसियों का ही अधिक जोर था। इन दानों ने पहले दक्षिण

में कभी एक का और कभी दूसरे का पक्ष लेकर राजनीति में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया।

**फ्रांसीसी शक्ति की वृद्धि**—सन् १७०१ में पांडुचेरी की नाव डालनेवाला मार्टिन फ्रांसीसियों के अधिकृत स्थानों का मुख्य अभ्यन्त्र बनाया गया। इस समय पांडुचेरी के अतिरिक्त मछलीपट्टन, सूरत, कालीकट, बालेश्वर, ढाका, पटना, चन्द्रनगर और कामिमतवाजार में फ्रांसीसियों की थोड़ी बहुत जमीन थी। मार्टिन की अध्यक्षता में पांडुचेरी की बहुत कुछ उन्नति हुई, उसकी आबादी बढ़ गई, और उसमें अच्छी अच्छी इमारतें बन गईं। मार्टिन देशी शासकों से बहुत मेल रखता था और उनके अधीन रहकर ही फ्रांसीसी शक्ति को दृढ़ करना चाहता था। सन् १७०३ में कम्पनी की आर्थिक दशा सुधर जाने से इसके व्यापार में भी बहुत कुछ उन्नति हुई। दस ही पन्द्रह वर्ष में इसका व्यापार इतना बढ़ गया कि अंगरेज घबड़ा उठे। अंगरेजी कम्पनी के संचालकों ने इंग्लैंड से लिख भेजा कि फ्रांसीसी व्यापार की पूरी देख-रेख रखनी चाहिए, और उनको इसका बराबर पता मिलना चाहिए। अंगरेजों को इस बात की बड़ी शिकायत थी कि फ्रांसीसी उनके जुलाहों को बहका ले जाते थे। इसको रोकने के लिए उन्हें देशी शासकों से सहायता लेनी पड़ती थी।

**ड्यूमा की सफलता**—सन् १७३५ में ड्यूमा पांडुचेरी का अध्यक्ष बनाया गया। यह बड़ा दूरदर्शी और चतुर मनुष्य था, मार्टिन की नीति पर चलकर इसने देशी शासकों से बड़ा मेल-जोल पैदा किया। कर्नाटक के नवाबों का यह बड़ा मित्र था। जब मराठों ने आक्रमण किया, तब इसने नवाब के कुटुम्ब को पांडुचेरी में स्थान दिया। इस पर मराठे बहुत बिगड़े, पर इसने बड़ी चतुरता से राघोजी भोंसला का क्रोध शान्त किया। माही इसके पहले ही फ्रांसीसियों के हाथ में आ गई थी, तजोर के राजा को कुछ रण-सामग्री देकर इसने कारीकल पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसकी प्रशंसा दूर दूर तक पहुँचने लगी। मुगल सम्राट् ने प्रसन्न होकर मिका डालने का अधिकार फ्रांसीसियों को दे दिया, और ४,५०० सवारों का

प्रारम्भ कर दिया। इस पर इंग्लैंड ने मदरास के अंग्रेजों को उदासीन रहने के लिए लिख भेजा पर वहाँ से जवाब मिला कि सरकारी वेडा उनके अर्थी नहीं है। पाटुचेरी सुरक्षित स्थान न होने से इंग्लैंड लडाई के लिए तैयार न था, इसलिए उसने अफ़ाट के नवाब अनवरुद्दीन से फ़ार्मीसियों की रक्षा करने की प्रार्थना की। नवाब ने अंगरेजों को लिख भेजा कि यदि वे पाटुचेरी पर हमला करेंगे तो उनके लिए अच्छा न होगा। इस पर अंगरेजों ने मदरास पर आक्रमण करने से फ़ार्मीसियों को रोकने के लिए भी कहा।



मदरास पर फ़ार्मीसियों का अधिकार

इधर इंग्लैंड ने भी फ़ार्मीसी सरकार के एक जहाजी वेडे को बुला भेजा। इस वेडे का अर्थ लाने वाला था। यह पहले भी भारतवर्ष आ चुका था।



इसने आने ही मदराम पर धावा कर दिया, और बिना लटे-भिड़े अंगरेजों को निमाल बाहर किया। उस तरह मच १७४६ में मदराम पर फ्रांसीसी पताका फहराने लगी।

इसले और लावरडोने की आयु में न पटती थी, ये दोनों बड़े घमडी और उहड़ स्वभाव के आदमी थे। इसले भारतवर्ष में फ्रांसीसियों का अध्यक्ष था, लावरडोने फ्रांस के सरकारी जहाजों का अफसर था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अपने अधीन समझते थे। लावरडोने जब से पाटुचरी आया था, तभी से उसका इसले से झगडा चल रहा था। वह इसले की आज्ञा प्राप्त किये बिना ही एक बड़ी रकम के बदले में तीन महीने के अन्दर अंगरेजों को मदराम लौटा देने का वचन देकर फ्रांस वापस चला गया। इसले ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया।

**सेंट टोम की चढ़ाई—**फ्रांसीसियों ने अर्कांट के नवाब की आज्ञा से सिद्ध मदराम पर धावा किया था, इस पर अंगरेजों ने नवाब का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। परन्तु इसले ने नवाब को मदराम दे देने का वादा कर दिया, तब नवाब ने अंगरेजों को डाल दिया। किन्तु जब नवाब ने देखा कि इसले का विचार मदराम छोड़ने का नहीं है और वह उसे रातों रातों डाल रहा है तब उसने अपने लटके की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। मदराम के निरुद्ध अदयार नदी के तट पर मेलापुर नामक स्थान में इस सेना का फ्रांसीसी सेना से सामना हुआ। फ्रांसीसी सेना जब कवायद जानती थी और उसके पास बन्दूकें भी अच्छी थीं, इसलिए घंटी बजाते हुए भी रात की रात में उसने अव्यवस्थित बड़ी भारी मुगल सेना को परास्त कर दिया। जिस स्थान पर यह लड़ाई हुई थी, वहां पर सेंट टोम नाम का एक पुर्तगाली किला था, इसीलिए यह लड़ाई सेंट टोम की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने इस लड़ाई का बड़ा महत्व दिया है। इसका कहना है कि इससे भारतीय सेना की कमजोरियों का पता यूरोप-निवासियों को अच्छी तरह मिल गया और पाश्चात्य युद्ध-प्रणाली में प्रगति मिल गई। फ्रांसीसियों के लिए यह बड़ी भारी विजय थी।

इस समय तक वे अपने को नवाब के अधीन मानते थे, जब वही नवाब उनसे सन्धि की प्रार्थना करने लगा। इस युद्ध में दक्षिण में इंग्लैंड का भी खराब ख़ास जम गया।

**एलागपल की सन्धि**—इस पर फ़ार्मीगियों ने अंगरेजों के दूसरे किले ग्रेट डेविड को जीतने का प्रयत्न आरम्भ किया, परन्तु अंगरेजी अफ़्ग़ान लारेंस की वीरता और चतुरता के कारण इंग्लैंड का ख़ास प्रयत्न निष्फल गया। इधर अंगरेजों के तेरह जहाज और आठ पट्टे और उन्होंने पाटुचेरी पर धावा बोल दिया। सुरक्षित स्थान न होने पर भी इंग्लैंड ने बड़ी बुद्धिमान और चतुरता के साथ पाटुचेरी की रक्षा की। इतने ही में यूरोप में एलागपल की सन्धि के समाचार आगये, जिसमें दोनों दलों को युद्ध बन्द करना पड़ा। इस सन्धि के अनुसार सन् १७४८ में इंग्लैंड को मद्रास अंगरेजों को वापस कर देना पड़ा।

**दूसरा युद्ध**—इस सन्धि से यूरोप में तो कुछ काल के लिए अंगरेज और फ़ार्सीलियों में शान्ति स्थापित होगई, पर भारतवर्ष में ऐसा न हो सका। दोनों के पास काफी सेनाएँ थीं, दोनों को लड़ाई का चस्का लगा हुआ था। दोनों ने समझ लिया था कि किसी एक को नष्ट किये बिना दूसरे का गुजर नहीं है, इसलिए युद्ध जारी रखने का उन्होंने एक दूसरे ही का निकाल लिया। इन दिनों देशी शासकों में बड़ा झगडा चल रहा था। ऐसी दशा में विरुद्ध पक्ष लेकर उन्होंने एक दूसरे की शक्ति नष्ट करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया।

**निज़ाम की मृत्यु**—सन् १७४८ में दक्षिण के सूबेदार वृद्ध आसफ़ जाह की मृत्यु हो गई। यह नाम-मात्र का मुग़ल सम्राट् के अधीन था। वास्तव में इसका दिल्ली से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। इसका कोई लडके थे। सबसे बड़ा लडका दिल्ली में रहता था, उसका दक्षिण के राज्य की पवाह न थी, इसलिए उसका दूसरा भाई नासिरजंग

यह एक स्थान का नाम है, जो हालेट में है।

जिसमें फ्रांसीसी सेना की सहायता में चान्दा साहब की विजय हुई, और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया। दूसरे ही दिन अर्काट पहुँच कर चान्दा साहब कर्नाटक की गद्दी पर बैठ गया और मुजफ्फरजंग ने अपने निजाम होने की घोषणा कर दी। सहायता के बदले में चान्दा साहब ने फ्रांसीसियों को अस्सी गाँव दिये। इस सफलता से डूप्ले का हौसला खूब बढ़ गया। अब उसको व्यापार में ही सन्तोष न रहा और वह भारतवर्ष में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखने लगा। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि व्यापार में अँगरेजों का मुकामला करने की अपेक्षा यूरोपीय ढंग में संगठित सेना द्वारा निर्मल तथा व्यसक्त देशी शासकों का विध्वंस करना ऊँहीं सहज है। इसलिए उसने अपना मार्ग ही बदल दिया। परन्तु उसके इस मार्ग में भी अँगरेजों का बाधक बन बैठे।

**अँगरेजों का प्रयत्न**—अम्बर की लड़ाई से अनवरुद्दीन का एक लड़का मुहम्मदअली भाग निकला और त्रिचनापल्ली पहुँचकर उस अँगरेजों से सहायता मांगी। उधर निजाम नासिरजंग ने भी मुजफ्फरजंग के विरुद्ध अँगरेजों से सहायता की प्रार्थना की। डूप्ले की उन्नति से जले हुए अँगरेज ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों से सहायता देना स्वीकार कर लिया। डूप्ले का मत था कि जब तक मुहम्मदअली त्रिचनापल्ली में है तब तक चान्दा साहब सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए वह त्रिचनापल्ली से मुहम्मदअली को निकालना चाहता था। परन्तु इस समय उसके फौजी अफसर उसका साथ नहीं दे रहे थे, दूसरे चान्दा साहब तजोर के राजा के पीछे पड़ा था, ऐसी दशा में उसको सफलता हुई। उधर अँगरेजों की सहायता से नासिरजंग ने मुजफ्फरजंग को हरा दिया। इसलिए डूप्ले का बना बनाया काम बिगड़ गया, पर उसका साह नहीं हटा। उसने ऐसी चाल चली कि नासिरजंग की सेना में फूट फै गई और उसी के आदमियों ने उसको मार डाला। इस पर मुजफ्फरजंग निजाम बन गया।

**फ्रांसीसियों की सफलता**—हूण्ड ने जैना कुछ भी। दक्षिण के सूबेदार और कर्नाटक के नवाबों से सन्धि सुनते ही चान्दा आये थे। जिस स्थान पर नासिरजंग मारा गया था, वहाँ पर हमने एक वेजयन्तम्भ खड़ा किया और उस स्थान का नाम हूण्डे-फतेहाबाद रखा। मुजफ्फरजंग ने प्रसन्न होकर फ्रांसीसियों को कई गाँव और बहुत सा धन दिया। कहा जाता है कि उस समय हूण्डे को भी एक बड़ी क्रम थार जागीर मिली। हूण्डे को वह दक्षिण का स्वामी समझने लगा और अपने कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अन्तरीप तक उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेया। चान्दा साहब भी फिर अर्काट पहुँच गया और इस बार भी हमने फ्रांसीसियों को बहुत धन दिया। इसी समय एक छोटी सी लड़ाई में मुजफ्फरजंग मारा गया। इसका फल यह हुआ कि सूबेदारी के लिए फिर लड़ा चल पड़ा। इस पर भी फ्रांसीसी घबड़ाये नहीं। उनके सेनापति फ्रांसीसी की सहायता से आसफजाह का तीसरा लड़का मलायतजंग सन् १७५१ में सूबेदार बन गया। इसी उसका संरक्षक नियुक्त हुआ और बहुत दिनों तक हैदराबाद में बना रहा। निज़ाम से निश्चिन्त होकर हूण्डे ने त्रिचनापली में वापिस से प्रयत्न प्रारम्भ किया। फ्रांसीसी सेना के साथ चान्दा साहब त्रिचनापली को घेर लिया।

**हूण्डे की चाल**—अब अंगरेजों ने देखा कि मुहम्मदअली की सहायता रखे किसी न किसी तरह त्रिचनापली की रक्षा करनी चाहिए। कर्नाटक भर में यहाँ एक ऐसा स्थान रह गया था, जिस पर फ्रांसीसियों का विश्वास था, और मुहम्मदअली ही तब तक उनके अधीन न बन पाया था। परन्तु उसका कोई ठीक उपाय उनकी समझ में न आ रहा था। इस समय हूण्डे ने दिमाग में उनकी सहायता की, हमने एक ऐसी चाल ढूँढ़ निकाली, जिससे हमारा घटना-चक्र ही घटल गया। सन् १७४४ में वह भारतवर्ष आया था, और मदरास में लेखक के पद पर काम करता था। जब सन् १७४६ में फ्रांसीसियों ने मदरास छीन लिया, तब वह अन्य कर्मचारियों के साथ गेट विंड के किले में चला गया। फ्रांसीसियों के आक्रमण करने पर

जिसमें फ्रांसीसी सेना की सहायता में चान्दा सरस की अध्यक्षता में बड़ी कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन खाना में भाग लिया। तंजौर के मराठा सेना उसने अपनी वीरता और चतुरता का परिचय दिया। इस फ्रांसीसी सेना में उसको एक छोटा सा पद मिल गया। उसने सोचा कि चान्दा साहब त्रिचनापल्ली घेरे हुए हैं, उसकी राजधानी अर्काट खाली है इसलिए यदि अर्काट पर आक्रमण किया जाय तो चान्दा साहब त्रिचनापल्ली छोड़ कर अर्काट की रक्षा के लिए दौड़ेगा, अर्काट मुहम्मदअली का संकट दूर हो जायगा।



साहब

अर्काट घेरा—मदरास अध्यक्ष साडर्स उसकी इस सलाह मान लिया, बड़े थोड़ी सी सेना साथ अर्काट पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। वह तीस सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और दो सौ अंगरे

सैनिकों के साथ चल पड़ा। मार्ग में उसने सिपाहियों को कवायद का खर्च अभ्यास कराया, और सरल व्यवहार से उन सबको अच्छी तरह अपने वश में कर लिया। उसके पहुँचते ही अर्काट के सरंजामों ने हिम्मत हार

और प्रिना लड़े-मिड़े अलत।—दुर्ग के हाथ आ गया। क़ाद्व ने जैसा कुछ सोचा था, वैसा ही हुआ। अंगरेजी विजय का समाचार सुनते ही चान्दा माहव ने अपनी सेना का एक बड़ा भारी भाग अपने लडके रजा माहव की अध्यक्षता में अर्काट के छीनने के लिए भेज दिया। रजा माहव ५३ दिन तक अर्काट को घेरे पड़ा रहा, पर क़ाद्व को न निकाल सका। क़ाद्व और उसके सेनिकों ने बड़ी वीरता और धैर्य से दुर्ग की रक्षा की। सिपाहियों ने अपनी अनुपम स्वामि-भक्ति का परिचय दिया, अन्न की कमी होने पर अंगरेजों को भात खिलाकर माँह से अपना पेट भरा पर साहय नहीं छोड़ा।

अन्त में तंग आकर रजा माहव ने धावा किया, पर बुरी तरह हार कर भागा। अंगरेजों ने पीछा किया और ग्रामी में उसको फिर से हराया। दाद को मराठों की सहायता से क़ाद्व तक में भी ली और



मुहम्मद अली

का आदमी था। उसकी प्रशंसा उन दिनों के अंगरेज भी करते थे। ऊर्मर मत है कि यदि फ्रांसीसी सेना बराबर उसके अधीन रहती, तो उसकी यह शक्ति न होती। चान्दा साहब की मृत्यु पर अंगरेजों ने मुहम्मदअली को कर्नाटक का नवाब बनाया, जो इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य था। इस तरह अंगरेजों की धाक जमाकर क्वाइट अवस्थ होने के कारण इंग्लैंड वापस चला गया।

**बुसी और उत्तरी सरकार—**कर्नाटक निकल जाने पर भी फ्रांसियों का प्रभुत्व नष्ट नहीं हुआ। हैदराबाद में वीर सेनापति बुसी का आतंक जमा हुआ था। उसने मराठों से निजाम सलाबतजग की रक्षा की थी, इसलिए निजाम उसको खूब मानता था। उसकी सेना के लक्ष्यों के लिए निजाम ने उत्तरी सरकार का इलाका दे दिया था। बराबर युद्ध के कारण यह इलाका बहुत तबाह हो गया था, पर तब भी बुसी ने यहां इंग्लैंड को भी रुपये की मदद दी। थोड़े ही दिनों में वह स्वयं बहुत धनी हो गया।

**इंग्लैंड का पतन—**इतने दिन के युद्ध से सारा व्यापार चौंका हो गया था, इलाकों की आमदनी काफी न थी, फ्रांसीसी सरकार से कोई सहायता न मिलती थी, इसलिए इंग्लैंड को रुपये की बड़ी कमी हो रही थी। फ्रांस-सरकार से उसका बहुत दिनों से मतभेद था। वहां के अधिकांश उसकी नीति को पसन्द न करते थे। वे व्यापार की दृष्टि से लडाइयों को हानि कारक समझते थे। इधर क्वाइट की सफलता से अंगरेजों का पक्ष प्रबल हो रहा था, और उनको धन की कोई कमी न थी। ऐसी दशा में इंग्लैंड को अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि उसकी मनोकामना का सिद्ध होना असम्भव है। इसलिए उसने अंगरेजों से सन्धि करने का प्रस्ताव किया। परन्तु उन्होंने इंग्लैंड का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सन् १७५४ में फ्रांस-सरकार ने इंग्लैंड को भारतवर्ष से हटाने की आज्ञा दे दी। वह बिना किसी विरोध के फ्रांस वापस चला गया। वहां उस पर सरकार की ओर से अभियोग चलाया गया। इस तरह अपमानित होकर सन् १७६३ में वह मर गया।

**उसकी नीति**—इंग्लैंड उन दिनों की राजनैतिक अशान्ति में लाभ उठाना चाहता था। वह दक्षिण के राजा और नवाबों को खूब पहचानता था। देशी सेना की कमजोरियों को उसने अच्छी तरह समझ लिया था। उसका विश्वास था कि पारचात्य रण-प्रणाली वहीं श्रेष्ठ हैं, और उसने हिन्दुस्तानी महज ही से सीख सकते हैं। कोई विदेशी शक्ति भारतवर्ष में अपने देश की सेना पर निर्भर नहीं रह सकती है, इसलिए भारतवासियों की सेना घनाना आवश्यक है। उसका खर्चा चलाने के लिए देशी राजा और नवाबों की सहायता करनी चाहिए। देश की तत्कालीन स्थिति में केवल व्यापार ही पर भरोसा करना ठीक नहीं है। स्थायी आय के लिए कुछ भूमि पर भी अधिकार होना आवश्यक है। इस तरह अपनी शक्ति बढ़ाकर भारतवर्ष में विदेशी साम्राज्य स्थापित करना असम्भव नहीं है। देशी शासक पारचात्य देश पर संगठित सेनाओं का सामना करने में असमर्थ हैं। इनको परास्त करना कठिन नहीं है। परन्तु यदि इस कार्यक्रम में किसी में बाधा पड़ने का भय है, तो वे अंगरेज हैं, इसलिए देशी शासकों की सहायता से या सीधे सीधे लड़कर उनकी शक्ति को पहले नष्ट कर डालना चाहिए।

आय कहा जाता है कि भारतवर्ष के यूरोप-सम्बन्धी इतिहास में इस नीति को इंग्लैंड ही ने सबसे पहले टूट निकाला, और बाद के अंगरेजों ने उसी का अनुकरण किया। परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं जान पड़ता है। हिन्दुस्तानी सेना रखना, उसको बचावद सिखाना कोई नई बात नहीं थी। पुर्तगालियों ने सैंकड़ों वर्ष पहले हिन्दुस्तानियों को सेना में रखना प्रारम्भ कर दिया था। बन्दूक और तोप का काम सिखाने के लिए मुगल सेनाओं में विदेशी शिक्षक रहते थे। देशी सेना की कमजोरियों को बर्नियर ऐसे यात्रियों ने सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही समझ लिया था। उसका कहना था कि अव्यवस्थित मुगल सेना को परास्त करना कोई कठिन काम नहीं है। देशी शासकों की सहायता से अपनी सेना का खर्च चलाना इंग्लैंड ने अंगरेजों से ही सीखा था। तत्कालीन राज



नैतिक अशान्ति में फ्रांसीसी साम्राज्य का स्वप्न देखना कोई बड़ी भारी बात थी। मुग़लों का पतन होने पर छोटी बड़ी सभी शक्तियाँ इसी धुन में थीं।

डूप्ले ने पहले से ही अपनी कोई नीति स्थिर नहीं की थी, वह चक्र में पड़कर वह बराबर आगे कदम बढ़ाता गया था। पहले उसका ध्यान केवल व्यापार की ओर था, राजनीति में वह मार्टिन और ड्यूमा की नकल का ही अनुयायी था। सन् १७४६ के बाद, जब उसका प्रभुत्व अत्यन्त तरह कम गया तब, उसने अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित समझा। फ्रांसीसी राज्यों ने उसकी नीति का अधिक अनुकरण तो नहीं किया, पर उसकी शूर से लाभ अवश्य उठाया। उस नीति में जो कुछ कमी थी, उसकी पूर्ति इन अंगरेजों ने उसको सफल बना दिया।

**असफलता के कारण**—डूप्ले की असफलता के कई कारण सबसे मुख्य बात तो यह थी कि उसके पास कोई जहाजी सेना न थी। यूरोप से सम्बन्ध रखने का रास्ता अंगरेजों के हाथ में था। डूप्ले को अपनी हिंदुस्तानी सेना पर ही निर्भर रहना पड़ता था। फ्रांस से उसको किसी प्रकार की सहायता न मिलती थी। वहाँ की सरकार से भी उसका मतभेद था। रुपये की उसके पास बड़ी कमी थी। व्यापार चौपट हो गया था, कर्नाटक और उत्तरी सरकार के जिले निर्धन थे, नवाबों के बाड़े बड़े बड़े होते थे, पर उतना रुपया न मिलता था। फ्रांस-सरकार लड़ाई के लिए रुपया भेजने पर राजी न थी। उसकी सेना में फूट थी, अफसर स्वार्थी थे और एक दूसरे से जलते थे, उनको अपने देश के लाभ का कुछ भी ध्यान न था। डूप्ले स्वयं योद्धा न था, उसको ऐसे अफसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिनकी कमी कभी उसकी आज्ञा भी न मानते थे।

यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि यदि वह भारतवर्ष में बना रहता तो क्या फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित होने की कोई सम्भावना थी? उत्तर में कहा जाता है कि इसमें बहुत सन्देह है, क्योंकि उसके चले जाने के बाद अंगरेजों के हाथ में बगाल सा धनी सूबा आगया था और क्लाइव मरीखा चतुर सेनाध्यक्ष मिल गया था। परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान

पता लगा कि दूप्ले की नीति न मानने में बड़ी भूल हुई। इस भूल को सुधार के लिए फिर से प्रयत्न किया गया। इस बार लैली सेनापति और अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। यह सन् १७७८ में भारतवर्ष पहुँचा, परन्तु फ्रांसीसियों का पासा पलट चुका था, उनकी शक्ति को फिर से स्थापित करना बड़ा कठिन था। दूप्ले के जाने के बाद से इस समय तक अंगरेजों की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। दक्षिण में उनकी पूरी धाक जम गई थी, बंगाल में एक तरह से उनका राज्य ही हो गया था, वहाँ के नवाब उनका हाथ की कठपुतली थे। पर तब भी लैली ने अंगरेजों को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय किया।

**लैली का उद्योग**—इस बार फ्रांस-सरकार ने कोई बात उठा रखी। लैली को काफी सेना और धन दिया गया। पर उसके भाग्य में सफलता बड़ी न थी। वह तेज मिज़ाज का आदमी था, उसके आते ही पांडुचेरी में उसका विरोध प्रारम्भ हो गया। वहाँ के कर्मचारी अब फिर लड़ाई-झगड़े में पड़ना न चाहते थे, उन्हें केवल अपने मतलब का ध्यान था परन्तु लैली ने इसकी कुछ भी परवाह न की, और अंगरेजों से सेंट डेविड ब किला छीनकर मदरास पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर पर पांडुचेरीवालों ने उसको सहायता देना बिलकुल बन्द कर दिया। रसद कम पड़ गई, और उसके सिपाही भूखो मरने लगे। इधर अंगरेजों की जहाजी सेना भी आगे इस पर लैली को पांडुचेरी भागना पड़ा।

लैली ने आते ही निजाम-दरबार से बुसी को बुला लिया था, इससे फल यह हुआ कि हैदराबाद से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जाता रहा। निजाम भी उन दिनों यही चाहता था। इधर क्लाइव ने कर्नल फोर्ड की अध्यक्षता में सेना भेजकर उत्तरी सरकार पर कब्जा कर लिया। यहाँ से भी आमदनी बंद हो जाने पर लैली ने तंजौर के राजा पर चढ़ाई करके रुपया लेना चाहा, पर वह राजा पहले ही से तैयारी कर चुका था, इसलिए लैली का यह प्रयत्न निष्फल गया। उधर बंगाल में क्लाइव ने चन्द्रनगर पहले से ही छीन लिया था। इसलिये आमदनी का अब कोई भी द्वार बाकी न रह गया।

**वांडवाश की लड़ाई**—लैली अब बिलकुल हताश हो गया पर तब भी वह जैमे-तैसे अंगरेजों का मुकाबला करता रहा। सन् १७६० में वांडवाश के निकट सर आयरकूट ने हमको अच्छी तरह हराया। वीर बुम्पी पकड़ लिया गया और लैली पाहुचरी भाग गया। अंगरेजों ने हमका बराबर पीछा किया, और पाहुचरी को घेर लिया। आठ महीने तक लली ने दूधे धैर्य और साहस के साथ पाहुचरी की रक्षा की। रसद की गैसी बसी हो गई थी कि एक कुत्ता भी चौबीस रुपये में बिकता था। अन्त में, परेशान आकर लैली ने शस्त्र डाल दिये और वह कंद करके इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ से वह फ्रांस चला गया। परन्तु फ्रांस-सरकार ने हमके साथ भी



आधुनिक पाहुचरी

प्रशाय किया। उस पर भी अभियोग चलाया गया और अन्त में हम गिरा दिया गया।

पाहुचरी पर भी अंगरेजों का अधिकार हो गया। उन्होंने मदगान और मिट्टे के पिट्ट का पूरा दबला लिया। पाहुचरी की बिनाल इमारतें गिरवा दी गईं और सारा नगर उजाड़ कर दिया गया। नगर-निवासियों को तीन

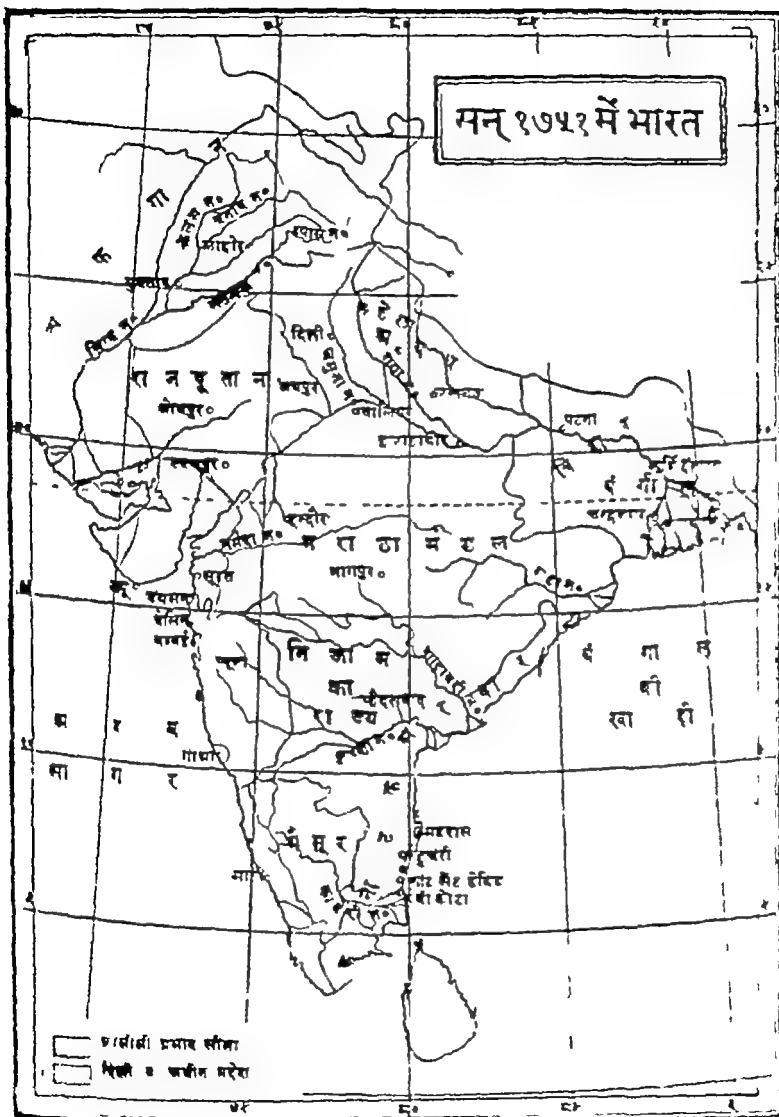
महीने के अन्दर नगर छोड़ देने की आज्ञा दे दी गई। इतिहासकार इसे लिखता है कि कुछ ही महीने में उस त्रिणाल सुन्दर नगर में एक भी मनुष्य बच न रह गई।

**फ्रांसीसियों की पराजय**—पादुचेरी के पतन से फ्रांसीसी हत हो गये। थोड़े दिन बाद जिजी और माही भी उनके हाथ से निकल गये। सन् १७६१ में सूरत और कालीकट की कोठियों को छोड़कर उनके पास कोई भी स्थान नहीं रह गया। इस तरह भारतवर्ष में फ्रांसीसी साम्राज्य अन्त हो गया। सन् १७६३ में यूरोप का युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस की सन्धि से पादुचेरी, चन्द्रनगर और माही फ्रांसीसियों को लौटा दिए गये। ये स्थान अब भी फ्रांसीसियों के पास हैं।

अन्त में अंगरेजों की ही पूरी विजय हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि इस समय उनका जहाजी बेड़ा प्रचल था। समुद्र के सब रास्ते उनके हाथ में थे। उनके जहाजी बेड़े को नष्ट करके भारतवर्ष से सम्बन्ध रखना फ्रांस की शक्ति के बाहर था। इसके अतिरिक्त अंगरेजों को धन का अभाव न था। उनकी कम्पनी का संगठन अच्छा था। फ्रांस-सरकार की तरह इंग्लैंड-सरकार उसके काम में बाधा न डालती थी। उसके कर्मचारियों में एका या और वे सबके सब फ्रांस की शक्ति को नष्ट करने पर तुले हुए थे। इसके प्रतिकूल फ्रांसीसियों की दशा थी, जिसका वर्णन किया जा चुका है। ऐसी दशा में फ्रांसीसियों की हार निश्चित थी।

---

सन् १७५३ में भारत





## परिच्छेद ३

### साम्राज्य की नींव

बंगाल के नवाब—पहले बंगाल मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, परन्तु शारंगजेब के मरने पर नवाब मुर्शिदकुलीनवा म्बाधीन हो गया था। यह पहले हिन्दू था। सन् १७०४ में मकसूदाबाद को हुसने अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम मुर्शिदाबाद रखा। सन् १७४१ में उसके बगजे को हटाने पर अलीवर्दीखाना नाम का एक सरदार नवाब बन गया। यह बड़ा चुनारामसर था। हुसका मारा जीवन मराठों से अपने राज्य की रक्षा करने में व्यतीत हुआ।

इन नवाबों के समय के बंगाल की दशा का वर्णन करते हुए गुलाम हुसने लिखता है कि पिछले साठ वर्ष से साम्राज्य का पतन हो रहा था, नवाब प्रयास थे, सरदार और उमरा विगड़ रहे थे, परन्तु तब भी इनमें से कोई भी इन नियमों से हटना नहीं चाहता था, जिनसे साम्राज्य की दृढ़ता हुई थी। इनके राज्य की दशा अच्छी थी, प्रजा सन्तुष्ट थी और प्राराम से रहती थी। तब तक ऐसे लोग थे, जिनको दुख या कष्ट था। अलीवर्दीखाना के समय तक यही दशा रही। उसने चुन चुनकर अपने योग्य कुटुम्बियों और मित्रों को रहे बर छोड़े दिये। वह सदा प्रजा का ध्यान रखता था। युद्धप्रिय और भास्वावाही होने पर भी प्रजा और जमीन्दारों के साथ, जो पूर्ण रूप से अपना वर्तमान पालन करते थे, उसका व्यवहार बड़ा अच्छा और उदार होता

था। प्रजा के लिए वह सचमुच पिता-तुल्य था। अपने फौजदारों पर उसकी बराबर निगाह रहती थी और वह उनको कभी अत्याचार न करने देता था। वह अपनी सारी प्रजा को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक ही माता-पिता की सन्तान समझता था और योग्य हिन्दू तथा अन्य गैर-मुसलमान व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करता था। उसके शासन में प्रान्त रूपका प्रान्त ही में रहता था, जिसमें उसी के राज्य की उन्नति होती थी। जनता को जीवन-निर्वाह की चिन्ता न थी, उसके शासन-काल में वह 'शान्ति और सुख' से रही। कहीं कहीं एक आध जमीन्दार बिगड़ जाता था, पन्द्रहवाँ राज्य में 'पूर्ण शान्ति और समृद्धि' थी।<sup>१</sup>

**विदेशियों के प्रति नीति**—बंगाल के शासक गुरु से ही विदेश व्यापारियों पर तीव्र दृष्टि रखने लगे। शासनागार्यों ने तो अंगरेजों को निष्काश ही दिया था, परन्तु मुर्शिदाकुलीयों के समय में बहुत सा रुपया देकर उन्होंने अपना व्यापार फिर से जमा लिया था। सम्राट् फर्ग्युमियर का उक्त एक नया फरमान भी मिल गया था, जिसके अनुसार बिना चुंगी के व्यापार का अधिकार दे दिया गया था। अंगरेजों के अतिरिक्त फ्रांसीसी और हालैंड निवासी उच्च भी बंगाल में व्यापार करते थे। इनकी कोठियाँ चन्द्रनगर और चिन्सुरा में थीं। नवाब अलीवर्दीखा इन व्यापारियों को अच्छी तरह पहचानता था, और उनसे खूब रुपया फ़ैलता था। सन् १७४४ में मराठों से लड़ने के लिए उसने अंगरेजों को कलकत्ता में एक खाई बनाने की आज्ञा दी थी, परन्तु अंगरेजों को अपना किला अधिक दृढ़ करने की इजाजत उसने कभी नहीं दी। जब कभी अंगरेज इसके लिए प्रार्थना करते थे, तब वह कह करता था कि तुम लोग व्यापारी हो तुम्हें किले से क्या काम, मेरी संरक्षणा में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। दक्षिण की दशा वह सुन चुका था विदेशियों की शक्ति और एकता का उसे सदा ध्यान रहता था। वह प्रायः कहा करता था कि विदेशी व्यापारी शहद की मक्खियों का एक छत्ता हैं।

१ सियर-उल-मुताखरीन, अंगरेजी अनुवाद, जि० ३, पृ० १७९-८०।



तममें गहद तो निकाल लेना चाहिए, पर मक्खियों को छेड़ना न चाहिए, इन्हें नें वे काट काट कर जान ले डालेगी।<sup>१</sup>

उन दिनों उसके कर्मचारियों और श्रंगरेजों में बराबर खटपट हुआ करती



अलीवर्दीख़ा

१. श्रंगरेज बिना महसूल के व्यापार करने के लिए नवाब की इम्नदे

१. खैरतन, रिप्लेगन ओन दि गवर्नट ऑफ़ इंडोस्तान, ६० पृ. १।

वनियों को दे देते थे और उनमें स्वयं लाभ उठाते थे। इतना ही नहीं, अक्सर आवादियों में माल लाने पर वे चुगी लगाते थे, और विवाह के अवसरों पर या जमीन बेचने पर भी टैक्स लेते थे। नवाब के दरबार में इसकी शिकायतें होती थीं। अंगरेज अपने पक्ष के समर्थन में मुगल सम्राट की फरमान पर जोर देते थे, नवाब फरमान के हट्टे अर्थ को कभी न मानता था। इस तरह उसके जीवन-काल ही में यह झगड़ा चलता रहा, परन्तु उस मरने पर इसने प्रचंड रूप धारण कर लिया।

**सिराजुद्दौला की नवाबी**—सन् १७५६ में अलीवर्दीखा के मृत्यु पर उसका पोता सिराजुद्दौला नवाब हुआ। बचपन के बहुत लाड-प्यास इसका स्वभाव विगड़ गया था। मुसाहिव लोग जो कुछ समझा देते बिना सोचे-विचारे यह वही करने लगता था। अलीवर्दीखा इसकी क्रूर शक्तों को अच्छी तरह जानता था। उसने पहले ही कह दिया था कि जब यह नवाब होगा तब भारतवर्ष के सभी तटों पर 'टोपवालों' का अधिकार हो जायगा<sup>१</sup>।

**अंगरेजों से झगड़ा**—नवाब अंगरेजों से पहले से ही चिढ़ा हुआ था। उन्होंने उसका कई बार अपमान किया था। उन्होंने कामिश्वाजा को छोटी और बंगलो में उसको ठहराने से इनकार कर दिया था। अलीवर्दीखा के दरबार में वे उसको कभी भी न पूछते थे। जब वह समनद बैठा तब भी उन्होंने बहुमूल्य उपहार नहीं भेजे। सिराजुद्दौला कुछ अतक इन सब बातों को सहन करता रहा, परन्तु अंगरेज बराबर डीठें डेते गये। अपने एक मुसाहिव राजवल्लभ पर नवाब नाराज हो गया, उस लडका कृष्णदास कलकत्ता भाग गया। जब नवाब ने उसको भेज देने के लिए अंगरेजों को लिखा, तब कलकत्ता के गवर्नर डेक ने कोरा जवाब दे दिया कि नवाब को अपने जासूसों से यह भी पता चला कि पुरखिया के नवाब अंगरेज उसके विरुद्ध बहका रहे हैं। दस्तकों का दुरुपयोग पहले से ही

हा था और इससे नवाब की आमदनी को बहुत कुछ हानि पहुँच रही थी।  
 १७५६ में इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। यह समाचार  
 मिलते ही नवाब से बिना पूछे बताये अंगरेज और फ्रांसीसियों ने अपने अपने  
 केलों को ठीक कराना प्रारम्भ कर दिया। इस पर नवाब बहुत विगड़ा  
 और दोनों को यह काम बन्द कर देने के लिए लिख भेजा। फ्रांसीसियों ने तो  
 बकाया देना दिया, पर कलकत्ता के गवर्नर डेक ने बड़ा कटा उत्तर लिख  
 भेजा और जो दूत पर्वाना लेकर आया था, उसको कलकत्ते से बाहर निकलवा  
 दिया। उत्तर पाते ही नवाब आगबबूला हो गया और उसने अंगरेजों को  
 हार करने का प्रण कर लिया।

**कलकत्ता पर आक्रमण**—सन् १७५६ के सई महीने में नवाब न  
 सिममराजार की कोठी छीन ली। इस अवसर पर उसने सिपाहियों को मोटी  
 माल लूटने से मना कर दिया और सिवा युद्ध-सामग्री के कोई सामान नहीं  
 ले लिया।<sup>१</sup> यहाँ से वह बड़ी तेजी के साथ कलकत्ता पहुँचा। मई जून की मही  
 १९ में, ग्यारह दिन में, उसने १६० मील का सफर तय कर डाला। कलकत्ता  
 की लड़ाई के लिए काफी सेना न थी, पर तब भी गवर्नर डेक ने लड़ना ही  
 मैचित किया। सबसे पहले उसने मेठ अमीरचन्द और गरम में शान्ति  
 वृणदास को गिरफ्तार कर लिया। उसका अनुमान था कि इन्हीं दोनों ने  
 नवाब को बुलाया है। अमीरचन्द के भाई ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी।  
 इससे पकड़न के लिए गोरे लोग जनाने मकान में घुसने लगे, इस पर मेठ के एक  
 नमादार ने घर की १३ स्त्रियों को मारकर उनके सम्मान की रक्षा की।<sup>२</sup>

इस अमीरचन्द के आदमियों से नवाब को कलकत्ता में घुसने का सन्ता  
 हुआ हो गया। अंगरेजों ने किले की रक्षा की पर अन्त में वे घबड़ा गये।  
 गवर्नर डेक और बहुत से अंगरेज अपने प्राण लेकर नदी के मार्ग से भाग  
 निकले। किले में कुछ मैनिक्स के साथ हालबेल रह गया। उसने अमीरचन्द

<sup>१</sup> हिल, रंगाल इन १७५६-५७, भूमिका पृ० २८।

पृ०, पृ० ७८।

को बीच में डालकर पहले सन्धि करने का प्रयत्न किया, परन्तु कोई फल न हुआ। अन्त में लाचार होकर ता० २० जून को हालवेल ने किला नका को सौंप दिया। उसके सिपाहियों ने लूट-पाट मचा दी पर किसी श्रेण को तंग नहीं किया।

**कालकोठरी**—उसी दिन मन्थ्या समय अंगरेज केंडी नवाब के सामने लाये गये। नवाब ने हालवेल की हथकड़ियों को गुलवा दिया और उस कष्ट न देने का वचन दिया। केंडियों पर कोई कड़ी देख रेख न थी। कई यूरोपियन किले से चले भी गये, पर किसी ने रोका नहीं। इसी मजहूर गोरे सैनिकों ने शराब पीकर हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तंग करना शुरू किया। शराब करने पर गोरे जिन कोठरी में बन्द कर दिये जाते थे, उन्हीं को बन्द करने की आज्ञा देकर नवाब आराम करने चला गया। कहा जाता है कि इस पर उसके सिपाहियों ने १४६ गोरो को उस छोटी सी कोठरी में भर दिए रात को गरमी में प्यास से तड़प तड़प कर इनमें से १०३ आदमी मर गये।

हालवेल ने इस घटना का बड़ा हृदय-विदारक वर्णन किया है, पर उसकी सत्यता में बहुत कुछ सन्देह है। कोठरी की जितनी लम्बाई चांदा बतलाई जाती है,<sup>१</sup> उतने में १४६ आदमियों का किसी तरह अटना सम्भव नहीं है। मरे हुए आदमियों में ५६ से अधिक के नाम का पता नहीं लगता है। उस समय के हिन्दुस्तानियों द्वारा लिखे हुए इतिहास या कम्पनी कागजात में इसका कोई उल्लेख नहीं है।<sup>२</sup> जान पड़ता है कि इस घटना के वर्णन में हालवेल ने बहुत कुछ नमक मिर्च मिलाया है। उसकी कई बातें यह दोष पाया गया है। यदि इसमें कुछ सत्यता भी हो तब भी तब उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रात की घटना उसकी जानकारी में नहीं हुई थी। यह बात ठीक है कि बाद में उसने इसके लिए किसी

१ विस्मन का कहना है कि यह कोठरी १८ फीट लम्बी और १४ फीट १० इंच चौड़ी थी।

२ मिस्टर लिटिल का लेख, बंगाल पास्ट एंड प्रेजेंट, जि० ९।

हट नहीं दिया। परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इमानी के कर्मचारियों ने इसके लिए अनुरोध भी नहीं किया। सन्धि की शर्तों में इसकी कोई भी चर्चा नहीं थी। इसी से सिद्ध होता है कि यह एक आधारभूत घटना थी और इसमें नवाब निर्दोष था।



मिराजुद्दौला

अलीनगर की सन्धि—बलकत्ता का नाम अब अलीनगर रखा

गया। राजा भाणिकचन्द को वहाँ का किलेदार बनाकर नवाब मुहम्मद

वापस चला गया। डेक सहित भागे हुए अंगरेज फलता पहुँचे और वहाँ से उन्होंने कुल हाल मद्रास लिख भेजा। यहाँ इन लोगों को नवाब और मे कोई विशेष रुष्ट नहीं दिया गया। बंगाल की दुर्घटना का समाचार मिलने पर बहुत कुछ वहम के बाद मद्रास कैम्पिल ने कजाइव और वायस को स्थल और जल-सेना का अयन बनाकर बंगाल भेजा। इन दोनों जनवरी मन् १७५७ में बिना अधिक लड़े भिड़े कलकत्ता फिर में छीन लिया इतिहासकार उर्म लिखता है कि किले में नवाब के सैनिकों ने कम्पनी सामान को कोई विशेष हानि न पहुँचाई थी। इसके बाद अंगरेजों ने दुर्ग की रसद को नष्ट कर डाला। यह समाचार मिलने पर नवाब फिर कलकत्ता पहुँचा और सन्धि की बातचीत प्रारम्भ हुई। यह बातचीत हो ही रही थी तभी एक दिन रात को अंगरेजों ने नवाब के पड़ाव पर आवा कर दिया, निर नवाब बहुत घबड़ा गया और फरवरी मन् १७५७ में उसने सन्धि-पत्र हस्ताक्षर कर दिये।

इस सन्धि के अनुसार नवाब ने अंगरेजों के व्यापारसम्बन्धी अधिकारों को मान लिया और किले की मनमानी मरम्मत करने की अनुमति दे दी। बंगाल, विहार और उड़ीसा में अंगरेजी दस्तकवाले माल पर महसूल ले बन्द कर दिया गया और सिक्का चलाने का अधिकार भी अंगरेजों को दिया गया। नवाब ने हरजाना देना भी मंजूर किया, पर हरजाने की सी ठीक रकम का कोई निर्णय नहीं हुआ। इसी तरह फ्रांसीसियों की कोई सयता न करने का भी उसने वचन दिया, पर सन्धि-पत्र में इस विषय की क शर्त रखना मंजूर नहीं किया।

**चन्द्रनगर पर अंगरेजों का अधिकार**—फ्रांसीसी शक्ति को न करने पर क्लाइव तुला ही हुआ था। नवाब के साथ सन्धि हो जाने पर उस चन्द्रनगर छीनने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। बिना नवाब की अनुमति ऐसा करना सम्भव न था, इसलिए बहुत सी चालें चली गईं और मुस हियों को घूस देकर फ्रांसीसियों के विरुद्ध नवाब के कान भरे गये। इधर मुग सम्राट् के आने का समाचार सुनकर नवाब कुछ घबड़ाया हुआ था और अ

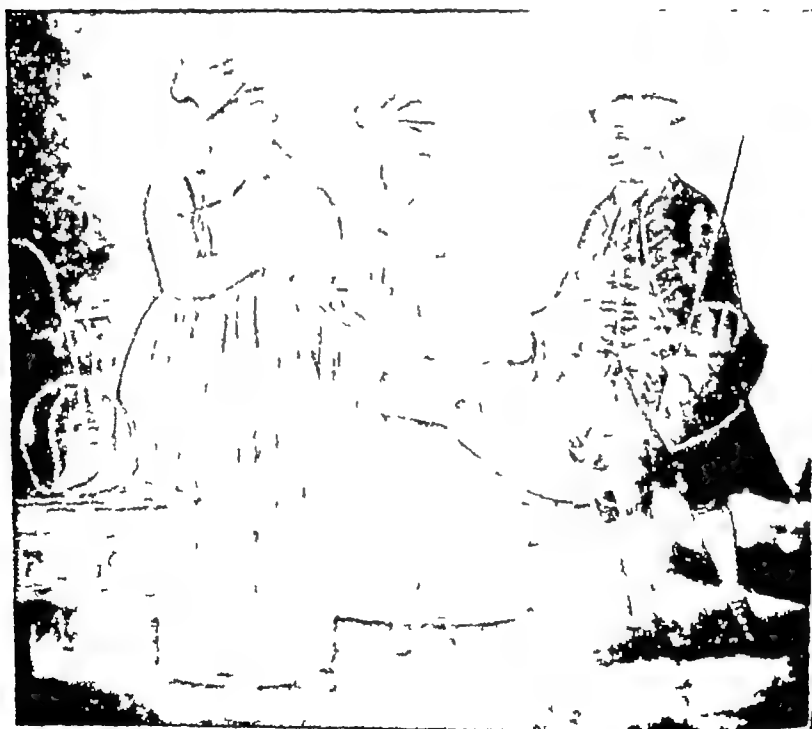
संग्रहीतों का विरोध न करना चाहता था। एक दिन वह फ्रांसीसियों से लोगों को बहुत रूठ हो गया और अंगरेजों को उन पर आक्रमण करने की उम्मेद अनुमति देकर दे दी। पटना में नवाब से मिलने का बहाना करके एक बड़ी सेना ब्रह्मपूर में माध कलाहव चन्द्रनगर पहुँच गया। फ्रांसीसी बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन उनके पास अधिक सेना नहीं थी, इसलिए अन्त में उन्होंने हार मान ली। मार्च सन् १७५७ में, चन्द्रनगर अंगरेजों को दे दिया। दो दिनों के बाद पाडुचैरी की तरह यहाँ की भी विशाल इमारतों को अंगरेजों ने नष्ट कर डाला।

**नवाब के विरुद्ध पड़्यंत्र—**कलाहव मदराय से जब चला था तभी जिन लोगों ने यह निश्चित कर लिया था, कि नवाब को बिना पड़्यंत्र किये हुए बगाल बाजारों अंगरेजों की रक्षा होनी कठिन है। इसलिए बगाल में भी हमने दखल देना सीखा ही नहीं से ही काम लिया। सन्धि हो जान के बाद कामिमाजाग की

गोती का अर्धवृत्त वाट्स नवाब के दरबार में अंगरेजों का प्रतिनिधि बनाया गया। वाट्स हिन्दुस्तानी अच्छी तरह बोल सकता था और वह नवाब तथा जो अंगरेजों के सुमाहिरों की कमजोरियों को खूब पहचानता था। धन के लालच में वह नवाब और अमीरचन्द अपने अपमान को भूल गया था और वह भी अंगरेजों की गोती में फँसने के लिए तैयार था। मिराजुद्दौला के बड़े बड़े सुमाहिरों में से बहुतों का व्यवहार के कारण सदा असन्तुष्ट रहते थे। वाट्स और अमीरचन्द ने बिना किसी संशय के धन का लालच देकर अपने पक्ष में गाँठ लिया। ये लोग नवाब को बहुत सलाह देने लगे। अंगरेजों ने भी अपनी माँगें बढ़ा दी, वे अरन

कोर्ट को खोलने और नवाब के कर्मचारियों को अंगरेजी दस्तखत न मानने के लिए बाध्य कर देने का अधिकार चाहने लगे। हरजाना की रकम के लिए भी नवाब को बाध्य कर देने लगा। सन्धि की शर्तों को न मानने और दखल में आने की इच्छा से फ्रांसीसी गणतन्त्रता मार्ग के लिए नवाब दोषी ठहराया जाने लगा। अन्त में नवाब ने सदा लोगों ने नवाब को गद्दी से उतारकर उसकी जगह पर मीरजाफर को बैठा दिया। मीरजाफर अलीवर्दीवा का बहनोई और नवाब का बड़ा बेटा था।

**मीरजाफर के साथ सन्धि**—मीरजाफर और अंगरेजों ने एक गुप्त सन्धि की, जिसमें मीरजाफर ने अंगरेजों के मंत्र अधिकारों को मान लिया और फ्रांसीसियों को व्यापार न करने देने का वचन दिया। कलकत्ता के हरजाने में एक करोड़ रुपया देना मंजूर किया और अंगरेजों को कलकत्ता तथा चौबीस परगना की जमीन्दारी देने का वादा किया। इसके बदले में अंगरेजों ने उनकी सहायता और रक्षा करने का भार उठाया।



मीरजाफर के साथ सन्धि

**अमीरचन्द को धोखा**—अमीरचन्द बड़ा लालची था। इस पट्टे पर से वह अपना पूरा फायदा उठाना चाहता था। उसने कहा कि यदि मुझे



नवाब के जवाहरात का चौथाई हिस्सा और नकद रुपये पर पाँच प्रति सैकड़ा कमीशन न दिया जायगा तो मैं यह हाल सबसे कह दूँगा। अपना कमीशन पहा करने के लिए वह यह चाहता था कि मीरजाफर और अंगरेजों के बीच जो सन्धि हो, उसमें यह शर्त लिख दी जाय। इस अवसर पर क्लाइव ने उसको गृह छोड़ा। उसने एक नकली सन्धि-पत्र बनाकर अमीरचन्द को दिखला दिया। वाटसन ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके हस्ताक्षर बना दिये गये। बाद को जब यह भेद खुला तब अमीरचन्द को दहा दुख हुआ। अमीरचन्द ऐसे वर्त के साथ ऐसा ही व्यवहार उचित था यह कहने से क्लाइव और उसके साथियों के आचरण पर जालसाजी का जा धक्का लगता है, वह मिट नहीं सकती। अमीरचन्द ने अंगरेजों को कोई प्रस्ताव न दिया था। ता० १० अप्रैल सन् १७५७ को 'गैलेक्ट कम्पैनी' की जो बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हमें इस "उदार और धनी" न्यायारी का कृतज्ञ रहना चाहिए। इस कृतज्ञता का बदला उसी समय प्रसार दिया गया परन्तु भी मरते समय वह बहुत सा धन लन्दन के एक अस्पताल में दे गया।

**पलासी का युद्ध**—फ्रांसीसियों के सबत परन पर भी नवाब या उन पद्वित्र पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब वाटसन उसके दरबार में तिरस्र भाग गया तब उसे इसका पता लगा। परन्तु मीरजाफर ने बुरान की नगर लबर स्वाभिक्त रहने का वचन दिया और जेमे तैसे नवाब को सन्तुष्ट किया। इन दिनों नवाब की ५० हजार सेना का पठाव पलासी में पठा हुआ था। यह स्थान मुर्शिदाबाद से २३ मील है। तीन हजार सिपाही लेकर क्लाइव दहा आ पहुँचा। ता० २३ जून सन् १७५७ को उसने सन्ध्या समय हमला किया। शरक ही धावे में नवाब का वीर सेनानायक मीरसदन मारा गया। मीरजाफर ने युद्ध में कोई भाग न लिया, वह दूर से खट हुए यही देखता रहा कि किस पर की विजय होती है। मीरसदन की मृत्यु और मीरजाफर की घेरावदारी के बाद नवाब हताश हो गया। उसी समय रायदुर्जन ने उसके भागने का सफा दी। उसके भागते ही नारी सेना तितर-बितर हो गई और अंगरेजों का पराजय हुई।

पलासी युद्ध-क्षेत्र से भागकर नवाब मुर्शिदाबाद पहुँचा और अपने खजाने का बहुत सा धन लुटाकर सेना को अपने पक्ष में करना चाहा, पर सफल न हुआ। दूसरे ही दिन अंगरेजी सेना के साथ मीरजाफर भी मुर्शिदाबाद पहुँच गया और सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ा। रास्ते में वह पकड़ लिया गया और मीरजाफर के लडके मीरन ने उसको बड़ी निर्दयता से मरवा डाला। सिराजुद्दौला के विषय में इतिहासकार मलेमन लिखता है कि “उसमें चाहे जो कुछ दोष रहे हों, पर उसने देश को बचा न था। ता० ६ फरवरी से २३ जून तक की घटनाओं पर विचार करनेवाले प्रत्येक निष्पन्न अंगरेज को यह मानना पड़ेगा कि ईमानदारी में सिराजुद्दौला का पद क्लाइव से कहीं उच्च है। इस दुःखमय नाटक के प्रधान पात्रों में वही एक पात्र था, जिसने योग्य देने का प्रयत्न नहीं किया था”।<sup>१</sup>

**युद्ध का परिणाम**—मैनिक दृष्टि से पलासी का युद्ध कोई युद्ध न था, परन्तु अंगरेजों की दृष्टि में यह युद्ध बड़े महत्त्व का है। इसकी विजय ने भारत वर्ष में अंगरेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। नवाब उनके हाथ का सिलौना बन गया और बंगाल सा धनी प्रान्त उनके अधिकार में आ गया। यहाँ की शाय से अन्य राजाओं के साथ लड़न का खर्चा चलने लगा और उत्तरी भारत में उनका आतंक जम गया। इस विजय से अंगरेज जाति का ही लाभ नहीं हुआ बल्कि कम्पनी और उसके प्रधान कर्मचारियों को भी बहुत सा धन मिला। क्लाइव को ३० लाख रुपया नकद मिला और कौंसिल के अन्य सदस्यों को १२ लाख तथा मैनिकों को ४० लाख रुपया दिया गया। इस समय करीब एक करोड़ रुपया नावों में भरकर मुर्शिदाबाद के खजाने से कलकत्ता लाया गया।<sup>२</sup>

**मीरजाफर की नवाबी**—मीरजाफर ने अंगरेजों को इतना रुपया देने का वादा कर दिया था कि सिराजुद्दौला का कुल खजाना खाली हो जान पर भी वह रकम पूरी नहीं हुई। इसलिए तीन चार साल तक राज्य की आमदनी में उसने बाकी रुपया देना स्वीकार किया। दूरदर्शी नवाब अलीवर्दी

<sup>१</sup> डिमादमिव प्रैटिस आफ इंडिया, पृ० ७१।

<sup>२</sup> टाउवेल, दृष्टि प्ले क्लाइव, पृ० १३६।

मर्मा ने अच्छी तरह समझ लिया था कि बिना हिन्दुओं के सहयोग के शासन करना सम्भव नहीं है, इसलिए उसने बड़े बड़े पदों पर हिन्दुओं को नियुक्त कर रखा था। जगतमोह से धनी हिन्दू धन से नवाब की पूरी सहायता करते थे। मिराजुद्दौला भी इसी नीति पर चलता रहा पर अंगरेजों का सहारा मिल जाने से मीरजाफर ने इस नीति को त्याग दिया। वह बिहार के हाकिम रामनारायण और राज्य के दीवान दुर्लभराय से लड़ बैठा। हिन्दुओं के विरोध का फल यह हुआ कि उसको आर्थिक सहायता मिलनी बन्द हो गई, जिसके कारण वह अंगरेजों के पक्ष में बराबर फैसला चला गया।

**अलीगढ़ की बहादुरी**—बंगाल की दशा देखकर आम्रपाय के सभी राजा और नवाबों को लाभ उठाने की इच्छा होने लगी। इन दिनों मुगल सम्राट् का लड़का अलीगढ़ बेकार घूम रहा था। इन सब ने मिलकर उसको खटा लिया। अवध के नवाब की सहायता से सन् १७५६ में उसने बंगाल पर हमला किया। मीरजाफर बड़ा व्यसनी और आत्मसी नवाब था। उसको अफीम खाने की भी आदत पड़ गई थी, इस नई आफत से देखकर वह घबरा गया और उसने बलाइव से, जो सन् १७५८ में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, रक्षा करने की प्रार्थना की। बलाइव भोला सी मर्मा को लेकर पठने की ओर बढ़ा। इधर अवध के नवाब ने अवसर पाया इलाहाबाद पर कब्जा कर लिया और शाहजादा को अकेला ही छोड़ दिया। शाहजादा बंगाल और बिहार का सूबेदार बनकर आया था, परन्तु अब उसे बलाइव के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। इस समय तक मुगल सम्राट् का नाम बना हुआ था और उसको अपमानित करने का साहस अंगरेजों को न था इसलिए बलाइव ने ५०० अश्वारि कों भेड़ करके उसको बाराक कर दिया। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर मीरजाफर ने उसको एक जागीर दे डाला, जिसकी सालाना आमदनी २०,००० पौण्ड जी। उसी के कहने पर बंगाल ने बाराक व्यापार का डेका भी कम्पनी को दे दिया गया।

**दिल्ली की पराजय**—“बलाइव का गधा” होने पर भी कुछ बल था मीरजाफर को अंगरेजों का भार समझ होने लगा। उसने दिल्ली

के डच लोगों से बातचीत शुरू की। उन्होंने बिना सोचे-विचारे जावा में सेना बुला भेजी। फ्रांसीसी नष्ट हो ही चुके थे, यूरोप की शक्तियों में केवल यही अंगरेजों का सामना करने के लिए भारतवर्ष में रह गये थे। डालेंड और हालेड में वैर न था, इसलिए इन लोगों के साथ किसी प्रकार की छेड़ खानी न की जा सकती थी। इस बहाने से इनको भी नष्ट करने का क्लाइव को अच्छा अवसर मिल गया। उसने उनके जहाजों को पकड़ लिया और विदेरा की लड़ाई में उन्हें हरा दिया। इस तरह अंगरेजों के मार्ग से यूरोप का एक और कंठक भी दूर हो गया।

**क्लाइव की वापसी**—फरवरी सन् १७६० में बहुत सा धन लेकर क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। चार वर्षों में कम्पनी की स्थिति में उसने आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया, फ्रांसीसी और डच लोगों की शक्ति को नष्ट कर डाला तथा दक्षिण और उगाल के नवाबों को अपने हाथ में कर लिया। इस तरह उसने अंगरेजों को व्यापारी से शासक बना दिया। उसके जाने पर वैनसिटाट बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ।

**शासन का अभाव**—मीरजाफर में शासन की योग्यता न थी, वह नाम मात्र को नवाब था। सारा शासन अंगरेजों के हाथ में था। इसका परिणाम यह हुआ कि शासन की जिम्मेदारी किसी पर भी न रही और बड़े बड़े कर्मचारी मनमानी करने लगे। शाहजादा और मराठों के भय से नवाब को बार बार अंगरेजों से सहायता माँगनी पड़ती थी। इस सहायता के लिए नवाब को अंगरेजी सेना का भार उठाना पड़ता था और कम्पनी के कर्मचारियों को प्रमत्त रखना पड़ता था। इसके लिए उसके पास धन न था, क्योंकि अंगरेज उसकी आमदनी में बराबर हस्तक्षेप करते थे। अंगरेज गुमास्ता हिन्दुस्तानी व्यापारियों को बिना महसूल व्यापार करने के लिए अंगरेजी दस्तकें देते थे, जिससे नवाब की आमदनी में बड़ा घाटा होता था। ढाका के कुछ अंगरेज व्यापारियों ने नमक और सुपाड़ी का कुल व्यापार अपने हाथ में ले रखा था। वे न तो किसी हिन्दुस्तानी को इसमें भाग लेने देते थे और न नवाब को एक पैसा देते थे। महसूल माँगने पर वे नवाब के कर्मचारियों के साथ

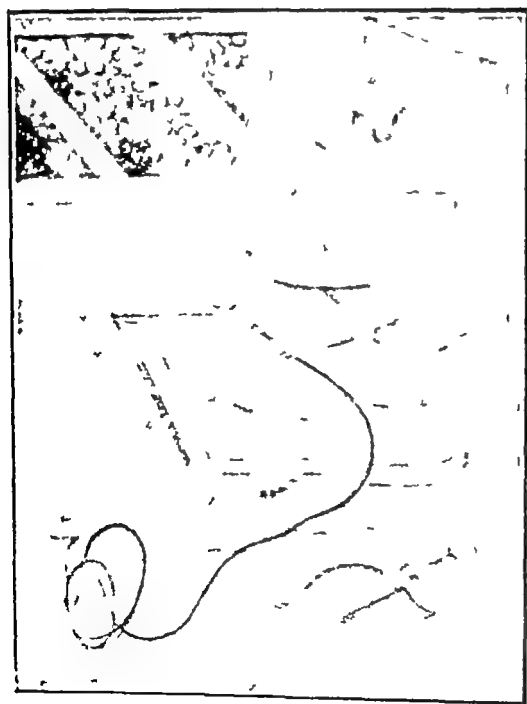
बड़ा बुरा बर्ताव करते थे। ऐसी दशा में सरकारी खजाना भरने के लिए प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार होते थे। कई सालों में सेना का वेतन घासी पड़ा था, जिसके लिए सिपाही नवाब को बराबर तग किया करते थे। इस तरह नवाब का खजाना खाली था और उसका कोई शासन न था।

दूसरी ओर कम्पनी की भी ऐसी ही दशा थी। उसके कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे थे, कम्पनी के लाभ की ओर कुछ भी ध्यान न देते थे। अगर नवाब से बड़ी बड़ी रकमें ऐंठते थे। क्लाइव ऐसे बड़े बड़े अफसरों में से एक थे। वह इस तरह बहुत सा धन कमाया था, तब फिर साधारण कर्मचारियों का बहना ही क्या था। वे तो अपने अफसरों का ही अनुकरण कर रहे थे। गृह रक्षक मिल जाने से वे इन दिनों बड़ी शान में रहते थे और कम्पनी के हानि या लाभ की कुछ भी परवाह न करते थे। कम्पनी को गृह रक्षक मिलने का समाचार पहुँचने पर इंग्लैंड में धन की सहायता आनी बन्द हो गई थी। मरहट्ट और मद्रास से बराबर धन की माँग आ रही थी। दक्षिण भारत में इन दिनों कलकत्ता का खजाना खाली था। सेना में वेतन न मिलने के कारण बड़ी अशान्ति फैल रही थी। कम्पनी की शान्त सत्ता का सर्वे तक नहीं चलता था।

**दूसरा पड़्यंत्र**—कम्पनी की इस अवस्था को देखकर अंगरेज अधिकारियों ने दूसरा पड़्यंत्र रचना प्रारम्भ किया। मीरजापुर अंगरेजों की लूट-पगोट में परेशान था गया था। उसका लड़का मीरन जैसे तेरे दास बना रहा था। सेना उसके काबू में थी। सन् १७६० में उसके एक-एक सैनिक सेना में बड़ी अशान्ति फैल गई और नवाब बिल्कुल हताश हो गया। इस अवसर पर उसके दामाद मीरकासिम ने उसकी सहायता की। उसने लालच देकर सिपाहियों को शान्त किया। इससे सेना पर उसका बड़ा रोब जम गया। अंगरेजों ने अब इसी को नवाब बनाना चाहा। मीरकासिम ने भी बहुत सा धन देने का लालच दिया और सेना का सर्वे चलाने के लिए एक लाख रुपया माहवार देने का वादा किया। पहले तो क्लाइव और गवर्नर ने मीरजापुर को धमकाकर इस बात पर राजी किया कि वह

मीरकासिम को नायब बना दे, पर बाद में थोड़ी सी सेना भेजकर मीरजाफर को गद्दी से उतार दिया और मीरकासिम को नवाब बना दिया। इस तरह बिना लड़े भिड़े शक्तों पर सन् १७६० में मीरकासिम बंगाल का नवाब बन गया। कौंसिल के कई एक सदस्यों की राय में पहले सहायता का वचन देकर फिर मीरजाफर को गद्दी से उतारना एक ऐसा कलंक का धब्बा था जो मिट नहीं सकता।

**मीरकासिम की नवाबी**—मीरकासिम एक योग्य शासक था। उसने शासन में बहुत कुछ सुधार किया। एक लाख रुपया मासिक के बदले में



मीरकासिम

छोड़कर बाकी लोगों के माल पर चुगी वसूल करने के लिए उसने अपने

उसने अंगरेजी फौज का सर्वा चलाने के लिए बर्दवान, मिर्जापुर और चटगांव के जिले कम्पनी को दे दिये। इन जिलों की आमदनी बहुत अधिक थी। मीरजाफर के समय में कई एक जमीन्दारों ने रुपया देना बन्द कर दिया था। मीरकासिम ने इन सबसे रुपया वसूल किया। फौज का बहुत सा वेतन बाकी था, उसको भी चुकाने के उसने प्रयत्न किया कम्पनी के माल के

फाजदारों को कड़ी ताकीद की। वह अपने को बगाल का मुख्य शासक समझना था और अंगरेजों के हाथ का गिल्लाना बनकर न रहना चाहता था।

**अंगरेजों से झगड़ा**—मीरकामिस के सुधार अंगरेजों को बहुत नटके, इसलिए वे तरह तरह की बाधाएँ डालने लगे। पटना के जमीन्दार रामनारायण म जब नवाब ने हिमाचल मींगा, तब वहाँ की कोठी के अध्यक्ष कूट ने इसको बहका दिया। मीरकामिस बगाल की सूबेदारी के लिए मुगल सम्राट् की मनन चाहता था परन्तु कूट ने यह भी न होने दिया। पटना में मुल्ते तौर में हमन नवाब का अपमान किया। कूट के बाद पटना में एलिय नियुक्त हुआ। यह बड़े उद्वेग स्वभाव का आदमी था। हमने नवाब को और भी तंग किया। नवाब ने कुछ अंगरेज अपराधियों को मुँगेर में छिपा रखा है ऐसा यहवर हमने मुँगेर किले की तलाशी लेन का उद्योग किया। अंगरेज अपराधियों के वृत्ति व्यवहार से परेशान होकर मीरकामिस ने उन्हें तंग बलवत्ता लिख भेजा कि हमसे तो यही अन्धा है कि मेरे हाथ से शासन-भार ले लिया जाय।

**दस्तवों का दुरुपयोग**—हमनी के गुमास्ते दस्तवों या दुरंगों बहुत दिनों से बर रहे थे। वे हिन्दुस्तानी व्यापारियों से रपश लेकर दस्तवों का महसूल वे व्यापार करने देते थे। हमसे नवाब को २५ लाख रुपये का हिसाब हुआ था। अंगरेज व्यापारी केवल कपड़े का ही काम नहीं करते थे, रस्ते नमक, सुपारी, तमाकू, चीनी, घी, तेल, चावल, गोबर आदि का काम अपने हाथ में ले रखा था और इन चीजों पर वे एक पैसा भी महसूल पर वे लिए तैयार न थे। हिन्दुस्तानियों से इन वस्तुओं को हमने दान पर परीक्षक वे मनमाने भाव से बेचते थे। हमसे जनता को बड़ा नफ़ा मिलता था। नवाब तक को मोरा मिलना मुश्किल हो गया था। हमसे दस्तवों अंगरेजों के हाथ में था, इसलिए वे किसी को हमसे न करने देने दे। अंगरेज गुमास्तों ने जगह जगह पर अपनी बच्छरिया गोल कर दी। दस्तवों के लोगों को यह देते थे और तरह तरह के नजराने वसूल करते थे। नवाबों फाजदारों को कोई पहुँचा तक न था।

घा, जिन्होंने जिस दिन से वह नवाब हुआ, जरा जरा भी बात से उसके सामन को रोकने तथा उसके अफसरो को अपमानित करने और धमकाने से काँट कंगूर उठा न रची ।<sup>१</sup>

**मीरजाफर की दूसरी नवाबी**—मीरजाफर को दूसरी बार मयनद पर बिठलाने के समय अंगरेजों ने उसके साथ एक नई सन्धि की । इसके

अनुसार मीरकायिम की त्रिना चुगी के व्यापार की आज्ञा सह कर दी गई । यह अधिकार केवल अंगरेजों के ही हाथ में रह गया । केवल समय पर ढाई सक्ता चुगी देना अंगरेजों ने रबी-बार दिया । कम्पनी का सिक्का जायज मान लिया गया और महाजना वो इस पर चढ़ा लेने से मना कर दिया गया । नवाब की सेना घटा दी गई । उसको



दंगाल के बन्दूकچی

दंगाल ५२ हजार सवार और ५२ हजार पैदल रखने की छाना मिली । इसके दरबार में एक अंगरेज रेजीडेंट भी नियुक्त कर दिया गया । नवाब



ने कम्पनी को ३० लाख रुपया हरजाना देने का वादा किया और कम्पनी के अफसरों का जो कुछ नुकसान हुआ था, उसको भी पूरा करने का वचन दिया। थोड़े दिन बाद अंगरेजी सेना के खर्च के लिए नवाब ने ५ लाख रुपया माहवार देना भी स्वीकार कर लिया।

**आर्थिक दुर्दशा**—उसको के दुरुपयोग से व्यापार को जो हानि पहुँच रही थी, उसका उल्लेख किया ही जा चुका है। इसके अतिरिक्त देश की कलाओं को भी नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। वोल्ट्स लिखता है कि जुलाहा को दाढ़ी डकर मुचलका लिखवा लिया जाता था, इसके अनुसार उसे कुल माल कम्पनी का देना पड़ता था। मुचलके पर जरूरतों हमाकर करवा लिये जाते थे और दाढ़ी का रुपया कोड़े लगा लगाकर जुलाहा के मध्ये मड़ दिया जाना था। वे गुमास्तों के गुलाम बन जाते थे और किसी दूसरे के हाथ अपना मान बेच न सकते थे। उन पर बराबर पहरा रहता था, जिसका खर्चा भी उन्हीं को देना पड़ता था और थान पूरा होते ही करघे में उतार लिया जाता था।<sup>१</sup> इस माल का दाम कम्पनी मनमाना देती थी। सन् १७८६ के एक पत्र में संचालकों ने भी इसको माना है। वे लिखते हैं कि जुलाहे कम्पनी के अधीन काम करना पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनको पूरा दाम नहीं मिलता है। अन्य विदेशी हमसे २० से ३० सैकड़ा अधिक दाम देते हैं। इसका फल यह हुआ कि बहुत से जुलाहे ने अपना काम छोड़ दिया।

खेती की भी यही दशा थी। वोल्ट्स का कहना है कि खेत खेती के साथ साथ कटाई बुनाई का काम भी करती थी, पर गुमास्तों के अत्याचार के कारण खेती में भी बाधा पड़ने लगी। किसानों को लगान तब देना मुश्किल हो गया, जिसके लिए उन्हें मालविभाग के अफसर तंग करने लगे। इनका अत्याचार कभी कभी इतना बढ़ जाता था कि बेचारे किसानों को अपने बच्चे बेचकर लगान चुकाना पड़ता था या देश छोड़कर भाग जाना पड़ता था। व्यापार और खेती की यह दशा होने के कारण जनता की आर्थिक

<sup>१</sup> वोल्ट्स, कमीशनर आन इण्डियन अफेयर्स, पृ० १९१-९४।

दगा बड़ी मोचनीय हो गई। इसके अतिरिक्त बहुत सा धन इंग्लैंड चला गया नवाबी शासन के पतन में बहुतों की रोजी मारी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में बेकारी बहुत बढ़ गई और लूट-मार होने लगी।

**बक्सर की लड़ाई**—मीरक़ासिम भागकर अवध पहुँचा। वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला ने उसका बहुत आदर किया। इन दोनों ने एक दूरी सेना एकत्र की और मुगल सम्राट् शाहजहाँसह को साथ लेकर, दिसम्बर मन् १७६४ में, बिहार तथा बंगाल पर धावा कर दिया। मुगल सम्राट् वही शाहजहाँसह था, जो पहले बिहार पर हमला कर चुका था। इन लोगों की सेना ४० से ६० हजार तक बढ़ी जाती है। मीरक़ासिम ने इन सेना को अच्छी शिक्षा दी थी। ता० २३ अक्टूबर मन् १७६४ को बक्सर में अंगरेजों ने लड़ाई हुई। उनकी सेना में ७०७० सिपाही थे, जिसमें २४७ गोरे और २० तोपें थीं। मेजर मनरो इस सेना का सेनापति था। पहले २० म तीसरे पहर तक घोर युद्ध हुआ। नवाब की सेना बड़ी पीड़ा में पड़ी, पर सम्राट् की सेना ने पूरा साथ नहीं दिया और शुजाउद्दौला से भी दूर भूल हुई, इसलिये अन्त में अंगरेजों की ही विजय हुई। शुजाउद्दौला तथा मीरक़ासिम मैदान से भाग निकले और शाहजहाँसह अंगरेजों के हाथ में आ गया। अंगरेजों ने शुजाउद्दौला का पीछा किया और मुगल तथा इलाहाबाद के बिले छीन लिये। बक्सर की विजय न पलायी का दारण पूरा कर दिया।

**मीरजापुर की मृत्यु**—सन १७६५ में बड़ नवाब मीरजापुर म गया और उसका लटका नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा। इसके बाद अंगरेजों ने फिर एक नई सन्धि की। इसके अनुसार नवाब को अपनी सेना और नौबानी परा और अंगरेजी सेना को बराबर ५ लाख रुपये माहवार देना मन् कराना पड़ा। सुल्तानमदरिजा की नायब बनाया गया और नवाब के बड़े बेटे मीरजापुर को नियुक्त करने का निन्ताने का अधिकार अंगरेजों को दिया गया। मीरजापुरी मालगुजारी वसूल करने के लिए सुतनदिये का रखना और निन्ताने का भी अंगरेजों के ही हाथ में रखा गया। अगस्त के दिवस में मीरजापुर

प्रधान मंत्रिपति का पद भी दिया गया और गायन के देशों को दूर करने के लिए बहुत से अधिकार दिये गये।

**कलाइव के सुधार**—भारतवर्ष पहुँचकर कनाइव ने पहले कम्पनी के कर्मचारियों को ठीक करने की ओर ध्यान दिया। मजालको ने हमके आने के बहुत पहले नवाबों से इनाम न लेने और निजी व्यापार न करने के लिए लिख भेजा था परन्तु कलकत्ता की काँगिल ने हम पर कुछ भी ध्यान न दिया था। मजालको की आज्ञा के विरुद्ध काँगिल तक के मेम्बर नवाबों ने खूब धन देने थे। कम्पनी के प्रायः सभी कर्मचारी धूम खाते थे। हम दशा का वर्णन करते हुए स्वयं कनाइव, ता० ३० गिनम्बर सन् १७६५ के पत्र में, मजालको को लिखता हूँ कि भारतवर्ष पहुँचने पर मैंने देखा कि गायन का कहीं नाम तक नहीं रह गया है। खूब धन मिलने से अफसर लोग बड़ी गान से रहते हैं और उनके मातहत भी उन्हीं का अनुकरण करने हैं। मेना-विभाग को भी हमका चस्का लग गया है और व्यवस्था का पन्थन जाना ही नहीं है। धूमगोरी और आरामतलबी अधिक बढ़ जाने से कोई गान गान नहीं रह सकता है। कम्पनी के सुमायता रैयत पर अत्याचार होता है। मुझे भय है कि हम देश में अंगरेजों के नाम पर यह भ्रष्टाचार फैल गया है जो कभी न छूटेगा। सहस्वाकाशा सफलता और गायन-व्यवस्था से एक नहीं गायन-व्यवस्था उत्पन्न हो गई है, जिससे अंगरेजों का प्रभाव घट रही है तथा कम्पनी में विश्वास उठ रहा है। यह साधारण बातें हम मानवता के भी विरुद्ध हैं।

हम दशा का सुधारने के लिए हमने कर्मचारियों से एक नया प्रविष्टि-पत्र लिखाया जिसमें उन्होंने भेट या नजराना न लेने का वचन दिया। परन्तु हमसे यह न समझना चाहिए कि यह प्रथा बन्द हो गई। नये प्रविष्टि-पत्र का प्राण्य बेंगल इतना ही था कि चार हजार से कम की रकम के लिए वासिक की अनुमति लेनी पड़ेगी और अधिक होने से उस रकम को कराना पड़ेगा। हमका फल यह हुआ कि कर्मचारियों के नजराना लेने से कम्पनी की जेब हानि होती थी, वह बन्द हो गई। इन पर इन्तिहाजद्वारा भी

ने ठीक लिया है कि नजराने की रकम अब बजाय कर्मचारियों के कम्पनी की जेब में जाने लगी। इस सुधार में क्लाइव को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परन्तु अन्त में उसने सबको दबा लिया।

कर्मचारियों के निजी व्यापार को वह घन्ट न कर सका, इसका मुख्य कारण यह था कि उन दिना इसके बन्द करने की उपयोगिता में उसको श्रद्धा विश्वास न था। उसका कहना था कि कर्मचारियों को अच्छा वेतन नहीं मिलता है, उनका नजराना लेना भी बन्द करा दिया गया है, ऐसी दशा में बिना निजी व्यापार के उनका गुर्चा पूरा नहीं पड़ता है। इसलिए उसने बड़े बड़े अफसरों की एक मोगायटी को नमक, सुपारी, अफीम और तमाकू के व्यापार का ठेका दे दिया। इसके लाभ का कुछ हिस्सा कम्पनी को मिलता था और बाकी हिस्सेदारों में बँट जाता था। कम्पनी के मंचालक इसके विरुद्ध थे, पर तब भी उसने इसका प्रबन्ध कर दिया।

इन दिनों कलकत्ता की कौंसिल में बड़ा गोलमाल था। कम्पनी का सारा प्रबन्ध और शासन इस कौंसिल के हाथ में था। कौंसिल के सदस्य प्रायः बड़ी बड़ी कोठियों के अध्यक्ष होते थे। जब उनके प्रबन्ध की आलोचना कौंसिल में होती थी, तब वे निष्पक्ष भाव से विचार नहीं करते थे। क्लाइव को यह भी पता लगा था कि कई एक सदस्यों ने नवाब नजमुद्दौला और नायब मुहम्मदरिजा रॉस से बड़ी बड़ी रकमें ली हैं। इस कौंसिल में जब जगहे पाली हुई तब क्लाइव ने मदरास से चार आदमियों को बुलाकर मेम्बर बनाया। वह मदरास के कर्मचारियों को अधिक ईमानदार समझता था। कौंसिल को न्याय में निष्पक्ष रखने के लिए उसने यह भी नियम बना दिया कि कौंसिल के मेम्बरों को कोई और पद न दिया जाय।

क्लाइव ने सेना के संगठन में भी बहुत कुछ सुधार किया। मेजर कार्नर को उसने सेनापति बनाया और पैदल सेना के तीन बड़े बड़े दल कर दिये। इनका भार योग्य अफसरों को दिया गया। इन दिनों सेना का खर्च खूब बढ़ा हुआ था। कम्पनी की कुल आमदनी इसी में खर्च हो जाती थी। अफसरों को वेतन के अतिरिक्त भत्ता मिलता था। मीरजाफर ने इस भत्ते की रकम

को दुगुना दिया था। जब तक नवाबों से यह रकम मिलती रही, तब तक तो कोई बान न थी, पर लड़ाई बन्द हो जाने से यह रकम इस समय अम्बनी को देना पड़ना था। दुगुने भत्ते का नियम बगाल ही से था, मदरास से हुनना भना न मिलता था, इसलिए वहाँ के अफसर बहुत असन्तुष्ट थे। अम्बनी का खर्चा कम करने और मदरास के अफसरों को शान्त करने से निराशा होकर न 'दुबल भत्ते' के नियम को रद्द दिया। इनके विरुद्ध अफसरों ने बड़ा आन्दोलन मचाया पर इनसे सबको शान्त कर दिया।

**राजनैतिक प्रवृत्ति**—ब्लाडव के आने के पूर्व बंगाल का युद्ध हो चुका था, परन्तु इस समय तक कोई सन्धि नहीं हुई थी। बंगाल में आंग्ल-गुजराट्टाला न मराठों और मल्लों को मिलान का प्रयत्न किया, परन्तु इससे क्या सफलता न हुई। दूसरे अंगरेजों ने इनके कई अफसरों को फाँट दिया।<sup>१</sup> इसलिए गुजराट्टाला इस समय सन्धि के लिए तैयार था। आंग्ल-मराठों की कोई शिन्ती ही न थी। बंगाल की विजय पर अंगरेजों को 'मन मग्न' पड़ने पड़ा ही था। मीरकासिम आगा हुआ था।

**इलाहाबाद की सन्धि**—अंगरेज सन १७६४ में इलाहाबाद की सन्धि हुई। गुजराट्टाला से बड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर आंग्ल-मराठों का सन्धि मग्न। अंगरेजों के प्रार्थना करने पर इससे बंगाली को दोगाव दिया और 'दीवानी' अर्थात् कर वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस 'अपनी हृच्छा के विरुद्ध' ऐसा करना पड़ा।<sup>२</sup> अंगरेजों ने सूरदास को २६ लाख रुपया सालाना खजाना देना स्वीकार किया और बंगाली राजा या भार अपने हाथ से लिया। गुजराट्टाला ने अंगरेजों को ३० लाख रुपया हरजाना देना स्वीकार किया और अवध से दिना महसूल के बन्दगी बत की अनुमति दे दी। अंगरेज अवध से भी बन्दगी के दिना से बन्दगी भारत थे, परन्तु बगाल की दशा देखकर गुजराट्टाला ने इन सन्धियों को मजबूत

१ १५००० आग पराजित करण्डम, जि० ९, पृ० २५।

२ निरुद्ध-गुजराट्टाला, जि० ९, पृ० ९।



लक्ष्य रहा। इसी लक्ष्य में लगे हुए गुजराटोला के साथ सन्धि की। लगाते ही समय दिल्ली तक पहुँच चुके थे और पूर्व की तरफ बराबर बढ़ रहे थे। धीरे-धीरे जोर पकड़ रहे थे। गुजराटोला इन दोनों को मिलाकर अंगरेजों की शक्ति नष्ट करना चाहता था। ऐसी दशा में गुजराटोला से सन्धि कर लेने ही में बलाहव ने अंगरेजों का हित देखा। अब कोई शक्ति उत्तर-पश्चिम की ओर से बिना गुजराटोला से लड़े हुए बंगाल पर आक्रमण न कर सकती थी। इस तरह बंगाल की पश्चिमी सीमा को लगे हुए बना दिया। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक अंगरेजों ने अवध के सम्बन्ध में इसी नीति को काम लिया। अवध इस समय बंगाल की बड़ी भारी शक्ति थी। इनके तात्कालिक बुद्धिमानी न थी।

शाहजहाँपुर से शीवानी लेने में भी एक बड़ा भारी रहस्य था। मुल्ताली का २६ लाख रुपये मालाना देना बलाहव ने यहाँ की सरकार नहीं कर दिया था। वह अंगरेजों की शरण में था और नवाब वजीर ने इसका मान ले लिया था। बलाहव यह अच्छी तरह जानता था कि मुगल सम्राट् का मान बना हुआ है। स्वतंत्र होते हुए भी देशी शासक उसी में साम्राज्य के अधिकारी होने में अपना मान समझते हैं। ऐसी दशा में बिना यहाँ की सरकार के अंगरेजों का सम्मान नहीं हो सकता, साधारण जनता में वे व्यापारी हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त बंगाल में प्रामाणिकी और उच्च लोगों का पक्ष न था। यहाँ हा गया था। उनकी सरकारों को देश की वास्तविक स्थिति का पता न था, वे इस समय भी मुगल सम्राट् को भारतवर्ष का सच्चा शासक मानते थे। ऐसी दशा में बिना मुगल सम्राट् की आज्ञा के बंगाल की राजधानि को सम्भालना उचित नहीं जान पड़ता था। विदेशी सरकारों की दृष्टि में अपने बायो को नियमानुसार निष्ठा करने के लिए यहाँ परम्परा का भी आवश्यकता थी।<sup>१</sup>

बंगाल के नवाब के साथ भी इसी नीति का अवनमन करने के लिए भारत की प्रथा चलाई गई। यदि अंगरेज चाहते तो बंगाल के नवाब को

नया अन्य यूरोपियनों को जलन होती है, अब भी मदा की मांग नवान के हाथ में है।<sup>११</sup>

अपनी नीति में हृष्टले की भूलों को सुधारते हुए हमने हमका बहुत कुछ अनुकरण किया। हमके दोहरे शासन को आगे चलाना असम्भव हो गया, परन्तु हम समय हमके अतिरिक्त और कोई उपाय न था। भारतवर्ष में दस यूरोपियनों से बड़ा घबड़ाना था और उनके नष्ट करने का हमारा प्रयत्न किया करता था।

**उसका चरित्र**—अमीचन्द को भोगवा देने और मीरजापुर में बड़ी बड़ी रकमें लेने का हमके चरित्र पर बड़ा भारी कलक लगाया जाता है। इतिहासकार स्मिथ की राय में जाली मन्थि का समर्थन “वार्मिक या राजनितिक दृष्टि से किसी दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। नजराना और चागीने लेना उन दिनों साधारण बात थी। फ्रांसीसियों ने भी ऐसा ही किया था और राज बरगनी के और कर्मचारी भी यही करते थे। यदि मजादर के साथ कोई भेद था, तो इतना ही कि वह स्वार्थ के वण होकर बरगनी के लिए बिलकुल न भूल जाता था। जब इंग्लैंड वापस जान पर हम उस नीति को बदलाया गया, तब पार्लामेंट की कामस सभा ने यही वाक्य उपाय के लिए लिया कि नजराना लेने के “साथ ही साथ राबर्ट लार्ड बलाहव न होने दी। इसी भारी भार योग्य सेवा की।”

बरगनी के संचालकों की आज्ञा के विरुद्ध उसने कर्मचारियों के लिए व्यापार जारी रखने दिया, इसकी इतिहासकार मिल ने बड़ी निन्दा की है। वह उसकी घनाई हुई ‘सोमायटी’ के वायों को “लजाजनक” बताना है। उसने इस मत का इतिहासकार स्मिथ भी समर्थन करता है। वह लिखता है कि किसी निष्पक्ष इतिहासकार के लिए यह कहना असम्भव है कि वह उपाय अनियोजित लोगों के साथ उन्हीं के हल-पट की चालों को न बदलता था। उन लोगों के साथ जो लालच न था, और बिना किसी सोच-विचार के उनकी शक्ति के बिना दा घटा न करता था। हम निर्णय से उसकी मूर्ति पर निन्दित हैं।



## परिच्छेद ४

### देश की दशा

**पानीपत का प्रभाव—**पहले तीन पेशवाओं के समय में अंगरेजों की दक्षिण दिशा में जान पड़ता था कि किसी दिन गुरु भाग्य में उनका साम्राज्य स्थापित हो जायगा, परन्तु सन् १७६१ में पानीपत के मैदान में उनका सदा के लिए विलीन हो गई। मुगल साम्राज्य का पतन ही ही पक्ष में, सराटा की हार के साथ-साथ अंगरेजों का मार्ग साफ हो गया। अंगरेजों ने बलाहक न जिस साम्राज्य-वृक्ष का आरोपण किया था उससे अलग होकर पानीपत के, परन्तु अंगरेजों के साम्राज्य में कुछ बाल के लिए अंगरेजों की गति न हो गई और इस अवसर में उस वृक्ष की जड़ें दंगल की अवस्था में शक्ति नष्ट हो गई। इसी लिए कुछ इतिहासकारों का मत है कि अंगरेजों ने भारत में इतिहास में पलायनी के युद्ध की अपेक्षा पानीपत का युद्ध अधिक महत्वपूर्ण था। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिसमें अंगरेजों को उत्तर-पश्चिम की ओर से कोई भय न रह गया।

कर लेने ही मे अपना हित नमस्का और तब मे बगबन लका गाय देना  
 रहा । अंगरेजो की नीति को वह गृध्र नमस्कता था, इसी लिए, उनसे  
 बहुत कुछ कहने सुनने पर भी हमने उनका अवध मे केन्द्रिया गोलन की  
 अनुमति नहीं दी । हलाहाबाद की सन्धि मे हमको अवध तो वापस मिल  
 गया, पर वह बिल्कुल तबाह हो गया । कहा जाता है कि हम गम पर  
 हमने अपना बेगम की सधनी तक देखकर अंगरेजो को स्या दिग था ।<sup>१</sup>

महोली का राज्य—मल्लखंड में जो पहले 'कटे' कहलाता था  
 बहुत न अफगानी बसत थे। ये बड़े वीर और लड़ाकू थे। आंगरेजों के मरने  
 पर अलीमुहम्मद नाम के एक सरदार ने यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित  
 कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि पहले बड़े एक जाट हिन्दू था।  
 उसने अपनी सेना का अच्छा संगठन किया और अपनी रक्षात्मक मर्यादा के  
 सब सरदारों को मिला लिया। आखिर में इसकी राजधानी थी। मरने के बाद  
 उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई। मरने के पूर्व वह अपना राज्य छोड़  
 कर भाग गया और हाफिज रहमतगार को यहाँ अपना राज्य स्थापित करवा दिया।  
 यहाँ पर बसना शुरू किया।

हाफिज रहमतखा ने शायन में कई एक सुधार किए। धाराएँ बहाई गईं, बरतों के लिए खेतों में सब प्रकार के मसूर मूले उगा दिये। सरसों के बगैचे बनाये, चिराघ किया, बघोवि हूयसे उनवी आथ का बरी हाजि पहुँची, परन्तु इन प्रजाहित की दृष्टि से इस चिराघ की कुछ भी फदाई नहीं था। इन सबसे धाराएँ से रहलखंड को बड़ा लाभ हुआ। इनसे शान-आन ने हिन्दू प्रजा की भी रक्षा होती थी और उसके साथ कोई कलह-करनाई नहीं पैदा था। हाफिज रहमतखा पीलीभीत में रहता था। वह नया सिक्का बनाया था। उसके पास पुरतके का एक अच्छा संग्रह था जो उसके नाम पर लगभग चला गया। रहलखंड की पश्चिमोत्तर सीमा पर मगधों का जंगल रहता था जो पूर्व की ओर अवध का राज्य था। इन दोनों की मर्यादा थी-

कर लेने ही में अपना हित समझा और तब से बराबर उनका साथ देता रहा। अंगरेजों की नीति को वह खूब समझता था, इसी लिए उनके बहुत कुछ कहने सुनने पर भी उसने उनको अवध में कोठिया खोलने की अनुमति नहीं दी। इलाहाबाद की सन्धि से उसको अवध तो वापस मिल गया, पर वह बिल्कुल तबाह हो गया। कहा जाता है कि इस समय पर उसने अपनी बेगम की नधनी तक बँचकर अंगरेजों को रुपया दिया था।<sup>१</sup>

**रहेल्लों का राज्य**—रहेलखंड में, जो पहले 'कठेर' कहलाता था बहुत से अफगानी बसते थे। ये बड़े वीर और लड़ाकू थे। अंगरेजों के मरन पर अलीमुहम्मद नाम के एक सरदार ने यहाँ अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि पहले वह एक जाट हिन्दू था। उसने अपनी सेना का अच्छा संगठन किया और अपनी उदारता से प्रान्त के सब सरदारों को मिला लिया। आँवला में इसकी राजधानी थी। सन् १७४६ में यहाँ उसकी मृत्यु हुई। मरने के पूर्व वह अपना राज्य अपने लड़के को बाँट गया और हाफिज रहमतखाँ को उनका संरक्षक तथा दुदीखा का सेनाध्यक्ष बना गया।

हाफिज रहमतखाँ ने शासन में कई एक सुधार किये। व्यापार की उन्नति के लिए उसने सब प्रकार के महसूल उठा दिये। सरदारों ने इसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी आय का बड़ी हानि पहुँची, परन्तु उसने प्रजाहित की दृष्टि से इस विरोध की कुछ भी पर्वाह नहीं की। इस स्वतंत्र व्यापार से रहेलखंड को बड़ा लाभ हुआ। उसके शासन-काल में हिन्दू प्रजा की भी रक्षा होती थी और उसके साथ कोई अत्याचार न होने पाता था।<sup>२</sup> हाफिज रहमतखाँ पीलीभीत में रहता था। वह बड़ा विद्वान था। उसके पास पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह था, जो उसके मरन पर लगनउ चला गया। रहेलखंड की पश्चिमोत्तर सीमा पर मराठों का जोर रहता था और पूर्व की ओर अवध का राज्य था। इन दोनों की अति के

<sup>१</sup> नियर-उल-मुतागरान, जि० २, पृ० ७८५।

<sup>२</sup> रटची, हेस्टिंग ऐट दि रहेल वार, पृ० ३०-३१।

रोकने के लिए रहेले कभी मराठों से मित्रता करते थे और कभी नवाब वजीर से।

**सिखों का संगठन**—इधर पंजाब में सिखों का जोर बढ़ रहा था। अपने बल का ज्ञान होने पर धीरे धीरे इनमें भी जमीन के मालिक बनने की इच्छा हो रही थी। इनके कई एक दल बन गये थे, जो 'मिसल' कहलाते थे। इनमें १२ मिसले मुख्य थीं। जो सरदार जिस मिसल को स्थापित करता था, वह मिसल उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती थी। एक मिसल को स्थापित करनेवाला सरदार भाग ग्रहण पीता था, इसलिए उसकी मिसल 'भगी' कहलाती थी। इन मिसलों के जहाँ जो जमीन मिल गई, उसी पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इसका फल यह हुआ कि थोड़े ही काल में पंजाब मुगल बादशाहों के हाथ में जाना रहा। सरदार जसाविह ने लाहौर जीत लिया और वह अपना सिक्का चलान लगा। अहमदशाह दुर्रानी कई बार आक्रमण करके भी सिखों का क्या न सका, उन्होंने सरहिन्द जीत लिया और मुसलमानी व्यवहार का भरपूर बदला लिया। अन्त में दुर्रानी ने पटियाला के एक सरदार को सरहिन्द का हाकिम बना दिया।

इन भिन्न भिन्न मिसलों को एकता में बांधनेवाले दो बन्धन थे, एक तो सिख धर्म की रक्षा और दूसरे ग़ालिबा की उन्नति। इन दो के सिवा मिसलों में और कोई परस्पर का सम्बन्ध न था। कोई बाहरी शत्रु न होने पर ये दल आपस ही में लड़ा करते थे। इन मिसलों के अतिरिक्त श्रमृतसर में 'अकालियो' का दल था, जिसके हाथ में गुरुद्वारों का प्रबन्ध था। ये अकाली हर समय लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। खालसा की नीति निर्धारित करने के लिए एक सभा रहती थी, जो 'गुरुमाता' कहलाती थी। अकालियो के आमंत्रित करने पर श्रमृतसर में प्रतिवर्ष दो बार इसकी बैठक होती थी। सर जान मालकम लिखता है कि इस अवसर पर सिख सरदारों को परस्पर के वेर को भूलकर एकता की शपथ लेनी पड़ती थी। वे किसी एक योग्य सरदार को अपना नेता मान लेते थे और उसी की अध्यक्षता में बाहरी शक्ति का सामना करते थे। पर भय की आशंका दूर

हो जाने पर फिर सब मिसले\* अलग अलग हो जाती थीं और आपस में ही लड़ने लगती थीं। सिख साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन मिसलों का एक होना बड़ा आवश्यक था।

**जाट और राजपूत**—आगरा और जयपुर के मध्य का भाग जाटों के हाथ में था।

सूरजमल इनका राजा था, जो भरतपुर में रहता था।

पानीपत के युद्ध के अवसर पर पहले इसने मराठों का साथ दिया था, पर सदाशिवराव भाऊ के दृढ़ व्यवहार से रूष्ट होकर यह वापस चला आया था। इतिहासकार गुलामहुसेन का कहना है कि शासन की योग्यता में उससे दसवें उम्र समय कोई दूसरा हिन्दू राजा न था।<sup>१</sup> इसके मरने पर मराठों ने जाटों को भी



दवाना प्रारम्भ कर

सूरजमल

\* नियर-उल-मुताखरीन, जि० ४, पृ० २७।

रखा।<sup>१</sup> इस तरह मैसूर से निश्चिन्त होकर उसने सन् १७६३ में वेदनूर का ज़िला जीत लिया। उन दिनों वेदनूर व्यापारिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध नगर था और ग्राह मील के घेरे में बसता था। इस अवसर पर बहुत सा धन हैदरअली के हाथ लगा। वास्तव में उसकी भावी प्रसिद्धि का प्रारम्भ यहीं से हुआ जैसा कि वह स्वयं कहा करता था। सन् १७६६ में हिन्दू राजा के मरने पर वह एक प्रकार से मैसूर का राजा ही बन गया। कालीकट पर आक्रमण करके उसने मल्लवार पर भी अधिकार कर लिया। उसका राज्य मराठों और निजाम के राज्य से मिला हुआ था, इसलिए उन दोनों से उसका बराबर युद्ध हुआ करता था। मराठों ने कई बार उस पर आक्रमण किया, पर समय के अनुसार कभी वह उनसे लड़ता था और कभी उनको धन तथा भूमि देकर अपनी रक्षा करता था। इस तरह तीन चार बार मराठों ने उससे बहुत सा धन लिया। दूसरी ओर निजाम से कोई दम न था, इसलिए हैदर ने उसके कई एक जिलों को दबा लिया।

**अंगरेजों के साथ युद्ध—**हैदरअली की बढ़ती देखकर अंगरेज चिन्तित हो रहे थे और हैदरअली भी जानता था कि बिना अंगरेजों को नष्ट किये वह निश्चिन्तता से राज्य न कर सकेगा। इसलिए दोनों युद्ध का अवसर ढूँढ़ रहे थे। अंगरेजों से युद्ध करने के पहले हैदरअली के लिए यह आवश्यक था कि वह निजाम और मराठों को अपने पक्ष में मिला लेवे। इन्हीं दिनों मराठों ने निजाम और मैसूर पर आक्रमण किया। निजाम ने पृथक् समझौते के अनुसार अंगरेजों से सहायता माँगी। हैदरअली ने बहुत सा धन देकर मराठों को लोटा दिया और कर्नाटक का लालच देकर निजाम को फोटा लिया। जब अंगरेजी सेना कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में मराठों के विरुद्ध निजाम की सहायता करने को पहुँची, तब उसको निजाम और हैदर की सेना न सामना करना पड़ा। सन् १७६७ में चंगामा और त्रिनेमली

काटा जाता है कि खाटेराव के कैद होने पर मैसूर की रानी ने उसकी प्राण-रक्षा या प्रायना की, उत्तर में हैदरअली ने कहा कि मैं उसको तोते की तरह पालूँगा।  
 १. इसी लिए वह उसको दूध भात खिलाकर एक पिंजरे में दब्ड रखता था।

की लड़ाइयों में हैदरअली की हार हुई। निज़ाम से उसको कोई सहायता न मिली, उसने अंगरेजों से फिर सन्धि कर ली, पर हैदरअली अकेले ही लड़ता रहा।

**मद्रास की सन्धि**—सन् १७६८ में हैदरअली ने कप्तान निक्सन के दल को नष्ट कर डाला और अपने कई एक स्थान अंगरेजों से छीन लिये। वह बराबर अंगरेजों को दबाता हुआ मद्रास के निकट तक पहुँच गया। अंगरेजों ने सन्धि का प्रस्ताव किया, उत्तर में हैदरअली ने दूत से कहला भेजा कि “मैं मद्रास के द्वार पर आ रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर गवर्नर और कांसिल की शर्तों को सुनूँगा।” इस पर अंगरेज घबड़ा गये और सन् १७६९ में उन्हें मजबूर होकर सन्धि करनी पड़ी। इस सन्धि के अनुसार दोनों दलों ने जीते हुए देश लौटा दिये और अंगरेजों ने किसी के हमला करने पर हैदरअली की सहायता करने का वचन दिया। इसमें मद्रास के गवर्नर ने बड़ी भूल की। अब उसको समय पड़ने पर हैदरअली की सहायता करने के लिए वचनबद्ध हो जाना पड़ा। इस तरह हैदरअली की पूर्ण विजय हुई और मैसूर का पहला युद्ध समाप्त हुआ।<sup>१</sup>

**मराठों की शक्ति**—पानीपत के युद्ध में मराठों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, उत्तरी भारत में उनकी तीव्र गति कुछ काल के लिए अवश्य रुक गई, परन्तु इस शक्ति को दक्षिण में पूरा करके वे शीघ्र ही दिल्ली फिर जा पहुँचे। युद्ध के बाद बालाजी के मरने पर उसका दूसरा लड़का माधवराव बल्लाळ पेशवा हुआ। योग्यता, साहस, वीरता और राजनीतिज्ञता में वह पहले

---

<sup>१</sup> कहा जाता है कि इस अवसर पर हैदरअली ने मद्रास के किले के फाटक पर एक व्यंगचित्र लटकवा दिया था, जिसमें कांसिल के मेम्बर और गवर्नर हैदरअली के सामने पुटन टेक रहे थे। हैदरअली गवर्नर को लम्बों नाक को, जो हाथा को सँड व तरफ था, पकड़े हुए था और उसमें मोहरें गिर रही थी। पासही कर्नल स्मिथ सन्धिपत्र को हाथ में लिये हुए अपनी तलवार के दो टुकड़े कर रहा था। पृ० २४६।

तीन पेशवाओं से किसी प्रकार कम न था। गद्दी पर बैठने के समय उसकी अवस्था १६ वर्ष की थी। उसके चचा रघुनाथराव ने सोचा था कि पूना का

शासन-भार उसी के हाथ में रहेगा। परन्तु माधवराव अपने चचा का मिलाना बनकर न रहना चाहता था, साल ही भर में मय राजकाज वह स्वयं करने लगा। समय कई बार मसूर और निजाम पर आक्रमण किया और दोनों से बहुत सा धन तथा वस्त्र छीन लिया। सन् १७६६ में उसने एक सेना उत्तरी भारत की ओर भेजी। इस



माधवराव वल्लाल

सेना के साथ माहादजी सिन्धिया और तुकोजी होलकर थे। इन दोनों ने पहले गजपूताना से दस लाख रुपया वसूल किया, फिर भरतपुर के निकट जाटों को हराकर और उनसे ६५ लाख रुपया लेकर वे दिल्ली जा पहुँच। वहाँ पहुँचकर माहादजी ने शाहआलम को फिर से दिल्ली





भी माधवराव ने इनको मिर उठाने नहीं दिया, परन्तु अंगरेजों की शक्ति बढ़ जाने से मराठा-मंडल में भी एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई।

**मराठा और अंगरेज**—अंगरेजों पर शिवाजी का कितना भारी दम-

दबा था, इसका उल्लेख ईस्ट इंडिया कम्पनी के इतिहास में जगह जगह पर मिलता है। बंगाल के अंगरेज व्यापारियों को तो शिवाजी अमर प्रतीत होते थे। उनकी मृत्यु का समाचार मिलने पर वे लिखते हैं कि “हम उसे तब मरा हुआ समझेंगे जब उसके समान साहस-पूर्ण काम करनेवाला मराठा में कोई न पाया और हमें मराठों के पजे से छुटकारा मिलेगा”। शम्भाजी तथा राजाराम का अंगरेजों से अधिक सम्बन्ध नहीं रहा, परन्तु इतने ही में कान्हेजी आंग्रे का प्रताप बहुत बढ़ गया और कोकण प्रान्त के किनारे पर अंगरेजों में उसकी मुठभेड़ होने लगी। यह पहले शिवाजी की जहाजी सेना में ग्लामी का काम करता था। अपने पराक्रम के कारण राजाराम के समय में उसका मुख्य सेनापति हो गया था। शाहू महाराज ने कुलाबा, सुवर्णदुर्ग, विजय-दुर्ग तथा अन्य कई किलों के साथ उसको ‘सरखेल’ की उपाधि प्रदान की थी। उसके पास दस बड़े जहाज थे, जिन पर १६ से ३० तक, और ५० छोटे छोटे जहाज थे, जिनपर ४ से १० तक तोपें चढ़ी रहती थीं। उसने कम्पनी के कई एक जहाजों को पकड़कर लूट लिया। बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी अंगरेज उसको दबा न सके।

पहले तो पुर्तगालियों को दवाने के लिए अंगरेज मराठों का साथ देते रहे, पर जब पुर्तगालियों की शक्ति नष्ट हो गई और वेसीन (वसई) के बिले पर मराठों का अधिकार हो गया, तब अंगरेजों को बम्बई के लिए चिन्ता होने लगी और वे मराठों के साथ भी कूटनीति से काम लेने लगे। सन् १७३६ में बप्पान इचवर्ड को भेजकर पेशवा के साथ एक व्यापारिक सन्धि की गई। दूसरी और सन् १७४०-४१ में कप्तान गार्डन शाहू महाराज के पास बुद्ध नजर लेकर भेजा गया। उससे कहा गया कि “शाहू राजा के दरबार में उसके मुख्य सलाहकार बान हे, उनके विचार कैसे हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका पता सूक्ष्म दृष्टि से लगाना। दरबार में

**पेशवा माधवराव की मृत्यु**—सन् १७७२ में २८ वर्ष की अवस्था

में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। उसने हैदराबली को नीचा दिखा-  
लाया था और शासन में बहुत से सुधार किये थे। सामलतदार तथा राज्य  
के अन्य अफसरों पर उसकी बड़ी कड़ी निगाह रहती थी। देश में धन की  
कमी न थी, इसलिए मालगुजारी वसूल करने में कठिनाई न होती थी। न्याय  
का बड़ा अच्छा प्रबन्ध था। प्रधान न्यायाधीश रामशास्त्री अपनी योग्यता  
और निष्पक्षता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इतिहासकार डफ की राय में  
माधवराव पेशवा की अकाल-मृत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध में  
कुछ कम घातक न थी। उसके मरने के बाद से ही जो आपस की फूट, राज्य  
की दुर्ग्वस्था और सैनिक प्रबन्ध में ढिलाई शुरू हुई, उसने साम्राज्य का अन्त  
ही कर दिया। उसका छोटा भाई नारायणराव गद्दी पर बैठे। उसमें न कोई  
योग्यता ही थी और न साहस, इसलिए रघुनाथराव को अपना प्रभुत्व जमाने का  
अवसर मिल गया। सन् १७७२ में रघुनाथराव और उसकी स्त्री आनन्दी-  
बाई के पट्ट्यंत्र से नारायणराव मार डाला गया और रघुनाथराव स्वयं  
पेशवा बन बैठा। उसने निजाम को परास्त किया और उसके पैरों पड़ने पर  
दया करके सब धन लौटा दिया। परन्तु इस विजय से भतीजे के बंध का  
बलब वह अपने मर्त्ये से न मिटा सका। बहुत से राजकर्मचारी, जिनमें मुख्य  
नाना फडनवीस था, उसके विरुद्ध हो गये। सन् १७७४ में इन 'वारह  
भाइयो' ने नारायणराव के पुत्र सवाई माधवराव को, जो अपने पिता की मृत्यु  
के बाद उत्पन्न हुआ था, पेशवा मान लिया। इस पर रघुनाथराव पृथा में भाग-  
पर थंगरेजों की शरण में चला गया।

**निजाम और कर्नाटक**—वाडवाण के युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन

हो जाने पर हैदराबाद दरबार में भी थंगरेजों का प्रभुत्व जम गया। सन्  
१७६५ में क्लाइव ने बिना निजाम से पूछे बताये सम्राट् में लिखा-पट्टी  
बख्शे उत्तरी सरकार की सनद कम्पनी के नाम करा ली। इसके बड़ी  
सुविधा में निजाम ने स्वीकार किया और दोनों में मित्रता की मन्त्रि हो गई।  
इसके बाद ही निजाम ने हैदर का साथ देना निश्चित किया, परन्तु उसकी हार

हो जाने पर सन् १७६८ में अंगरेजों से फिर सन्धि कर ली। सन् १७७२ में हेदराबाद दरबार में अंगरेज रेजीडेंट रख दिया गया। इसी समय मदरास सरकार ने निजाम के भाई ब्यालनजग से मिलकर गद्दूर पर अधिकार कर लिया। इससे निजाम बहुत चिढ़ गया।

युद्ध के पहले के कर्नाटक का वर्णन करते हुए स्कैफ्टन लिखता है कि राज्य की ओर से बड़े बड़े तालाब बनवा दिये गये थे, कर देने पर जिनमें सिंचाई के लिए पानी मिलता था। डाकुओं से देश ऐसा शून्य था कि वहाँ के लोगों की याद में भी कोई डकैती नहीं हुई थी। जवाहरात के व्यापारी, जो प्रायः इस देश में आने-जाने थे, अपनी रजा के लिए कोई हथियार तक नहीं रखते थे। यहाँ यह नियम था कि जिस जगह लूट होती थी, वहाँ के हाकिम को या तो लूट का माल डूँडकर निकालना पड़ता था, या हरजाना देना पड़ता था। हर एक गाँव या नगर के किनारे पर वृक्षों का बड़ा बगीचा होता था जहाँ गुलाबों का काम करते थे। अच्छा शासन होने का इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता था कि देश से कितना अधिक कर वसूल होता था। कई एक प्रान्त यूरोप के सबसे धनी देशों के बराबर रुपया देते थे। वहाँ हमारे देश की सी खाने न थीं, वहाँ के लोग अपने हाथों के बल धन कमाते थे।<sup>१</sup>

परन्तु फ्रांसीसी और अंगरेजों के युद्ध से थोड़े ही दिनों में कर्नाटक तगह हो गया। सन् १७६७ की सन्धि से निजाम ने मुहम्मदअली को कर्नाटक का स्वतंत्र नवाब मान लिया। उसकी यह स्वतंत्रता नाम मात्र की थी। कम्पनी की ओर से रुपये की माग बराबर बढ़ती जाती थी, जिसे देने के लिए उसको अंगरेज महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था। इन महाजनों के तग करने पर उसने मालगुजारी वसूल करने का अधिकार इनको दे दिया। ये लोग प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। फुलर्टन लिखता है कि इनकी लूट से दरबार का खर्चा बढ़ गया।<sup>२</sup> जार्ज स्मिथ का कहना है कि

<sup>१</sup> स्कैफ्टन, रिफ्लेक्शंस, पृ० १३-१४।

<sup>२</sup> फुल्टन, ए व्यू ऑफ दि रिलीश इन् इण्डिया, पृ० २७८।

चार ही पचास वर्ष में खेती की बुरी दशा हो गई, आबादी घट गई और व्यापार चापट हो गया।<sup>१</sup>

**तंजौर के साथ अन्याय**—तंजौर के राज्य को शिवाजी के भाई ने स्थापित किया था। मराठा राज-मंडल से अलग होने के कारण मराठों के लिए इसकी रक्षा करना बड़ा मुश्किल था। यहाँ की अतुल सम्पत्ति देवस्वर दक्षिण के सभी राज्यों की इस पर दृष्टि लगी रहती थी। सन् १७४६ से इसका सम्बन्ध अंगरेजों से हुआ। इस अवसर पर राजा शाहू और प्रतापसिंह ने तद्दी के लिए झगडा चल रहा था। अंगरेजों ने शाहू का पक्ष लेकर उसकी सहायता के लिए एक सेना भेजी, पर अन्त में शाहू का पक्ष निर्बल देखकर प्रतापसिंह से समझौता कर लिया और देवीकोट पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह सहायता का वचन देकर अन्त में शाहू को राखा दिया गया। सन् १७६६ में हैदरअली के साथ जो सन्धि हुई उसमें तंजौर का राजा अंगरेजों का मित्र मान लिया गया। परन्तु सन् १७७१ में मुहम्मदअली के कहने पर तंजौर घेर लिया गया और ४ लाख पैसों का वसूल किया गया। इतने ही में सन्तोष न हुआ, सन् १७७३ में फिर आक्रमण किया गया। राजा ने अंगरेजों को बहुत कुछ समझाया। उसका कहना था कि “मेरे ऊपर आक्रमण करने के पूर्व मेरा अपराध बतलाना चाहिए, इस राज्य के दान में लाखों मनुष्यों का पालन होता है, इसकी रक्षा करने में अंगरेजों की रीति बटेगी।”<sup>२</sup> परन्तु इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा, राजा को बंद करके तंजौर नगर के राज्य में मिला लिया गया। इस घटना का समाचार इंग्लैंड पहुँचने पर सदराम वें प्रेसीडेंट की बड़ी निन्दा की गई और उसकी जगह पर तंजौर वापस करने की आज्ञा देकर दूसरा प्रेसीडेंट भेजा गया।

पैसों का बहाना है कि जब मैंने सन् १७६६ में तंजौर देखा था, तब इसकी बड़ी अच्छी दशा थी। खूब व्यापार होता था। बम्बई तथा सूरत में रुई

१. ए. ए. स्मिथ अपोलिटिक, पृ० १२०, दत्त, पृ० १००।

२. ए. ए. स्मिथ अपोलिटिक, पृ० १२०, दत्त, पृ० १२०।

बंगाल से रेशम, पीगू से सोना हाथी तथा घोड़े, और चीन से बहुत २ माल आता था। तजेव, छ्वाट, रुमाल तथा छुपे मोटे कपड़े अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका तक जाते थे। मन् १७७१ तक इसकी अच्छी दशा थी। पर चार ही पाँच वर्ष में जब यह नवाब के अधीन रहा, यहाँ की दशा बदल गई। कलाएँ नष्ट हो गईं, व्यापार मन्डा पड़ गया, खेती की अव्यवस्था हो गई और हजारों आदमी राज्य छोड़कर चले गये।<sup>१</sup> इस तरह यह 'दक्षिण का बाग' थोड़े ही दिनों में वीरान हो गया।

**जनता की स्थिति**—इस समय भी जनता की ऐसी शोचनीय दशा न थी, जैसी कि प्रायः दिखलाई जाती है। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, पर साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रान्तों में ऐसे शासक उत्पन्न हो गये थे, जो अपना पक्ष प्रबल बनाने के लिए बराबर लोकप्रिय बनने का प्रयत्न करते थे। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष का सामाजिक संगठन ऐसा था कि जिसके कारण राजनैतिक विप्लवों का जनता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। भारतवर्ष की अधिकांश जनता प्राचीन समय से गाँवों में रहती है। उन दिनों इनका संगठन ऐसा था कि जिससे वहाँ की सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। भारतीय शासक यथासम्भव इस संगठन में हस्तक्षेप न करते थे। सर चार्ल्स मैटकाफ की राय में राजनैतिक अस्थिरता के समय में भी जनता की दशा अच्छी रहने का यह सबसे मुख्य कारण था। वह लिखता है कि राजवंश नष्ट हो गये, साम्राज्यों का पतन हो गया, पर इन गाँवों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।<sup>२</sup>

यह बात ठीक है कि कभी कभी निष्ठुर स्वार्थी शासक की क्रूरता का जनता शिकार अवश्य बनती थी, पर साधारणतः इस समय के शासकों को भी उसका ध्यान रहता था। इन दिनों की अराजकता का जो मर्मस्पर्श चित्र प्रायः गींचा जाता है, उसकी सत्यता में तत्कालीन अँगरेजों के ही दिये

<sup>१</sup> जेम्स रिपोर्ट, मन् १७८२, अपेंडिक्स नं० २२, दत्त, पृ० १०५-१०६।

<sup>२</sup> के, लार्ड ऑफ सर चार्ल्स मैटकाफ, जि० २, पृ० १९१-९२।

हुए विवरण से सन्देह होने लगता है। अंगरेजों के हस्तक्षेप के पहले कर्नाटक तथा बंगाल की जो दशा थी, दिखलाई जा चुकी है। महाराष्ट्र देश का वर्णन करते हुए, सन् १७६२ में, पेरन लिखता है कि वहाँ मन्युग की मादगी और सुत्र का अनुभव होता है। शुद्ध के कष्ट दिखलाई नहीं देते। सब लोग प्रमत्त, फुर्ताले और खूब तन्दुरुस्त हैं।<sup>१</sup> मैसूर के सम्बन्ध में फुलर्टन लिखता है कि हैदराबली के शासनकाल में प्रजा की जैसी कुछ उन्नति हुई वेसी किसी हिन्दुस्तानी शासक के समय में नहीं हुई। उसके राज्य के सभी भागों में किसान, कारीगर तथा व्यापारी धनी बन गये। खेती बढ़ गई, बहुत सी नई चीजें बनने लगीं और राज्य में धन भर गया।<sup>२</sup> परन्तु जहाँ जहाँ अंगरेजों का हस्तक्षेप होना लगा बड़ा कलाह नष्ट होने लगी, लगान कड़ाई से लिया जाने लगा, गाँवों का सगठन छिन्न भिन्न होने लगा और धन बाहर जाने लगा।

**सामाजिक जीवन**—शताब्दियों से साथ रहने, कबीर तथा नानक के उपदेश और अकबर की उदार नीति के कारण हिन्दू और मुसलमानों के परस्पर सम्बन्ध में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। औरंगजेब की उलटी नीति फौज पर भी एकता के भाव सर्वथा नष्ट हो गये थे। कट्टर हिन्दू तथा मुसलमान शासक कभी कभी अपनी हार्दिक संकीर्णता का परिचय अग्रग्न्य देते थे, पर इसका प्रभाव गाँवों में बहुत कम दिखलाई देता था। वहाँ दोनों का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन बहुत कुछ एक था। हिन्दू घरानों में मृत पतनवर मुसलमान जुलाहों के पास जाता था, खेती-बारी का काम साथ साथ पाता था। मुसलमान गाँव की विरादरी में शामिल थे। दोनों जानियाँ एक दूसरे के रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा त्योहारों में भाग लेती थीं। इस समय भी मुसलमान राज्यों में बड़े बड़े पदों पर हिन्दू और हिन्दू राज्यों में मुसलमान पास बरते थे। परन्तु इस परस्पर के सम्बन्ध में भी राजनैतिक क्षेत्र में एक नई

शक्ति को आ जाने से बाधा पड़ने लगी। हिल लिखता है कि इस समय बंगाल में हिन्दू भावों की फिर से जागृति हो रही थी और हिन्दू, यूरोपियन लोगों की सहायता से, मुसलमानों की शक्ति को नष्ट करना चाहते थे।<sup>१</sup> परन्तु अली-वर्दीखाने के समय तक बंगाल में इसका पता नहीं लगता। उसके शासन का काम जगतसेठ के धन से चलता था। मिराजुद्दौला के समय से अमीर-चन्द ऐसे लोग धन का लालच देकर अवश्य फोड़े जाने लगे। नव नरु यूरोपियन लोग भी भारतवासियों से बिलकुल अलग न रहते थे। राजकीय भाषा फारसी थी। अंगरेजों को राजदरबारों के साथ इसी भाषा में पत्रव्यवहार करना पड़ता था, पर प्रान्तों में नीचे कीरे प्रान्तीय भाषाओं का प्रचार बढ़ रहा था।

उस समय बालविवाह, पर्दा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ हिन्दू समाज में सती-प्रथा भी जारी थी। पर सती न होने के लिए घरवाले स्त्रियों को बहुत समझाते थे और ब्राह्मण भी इस पर अधिक जोर न देते थे।<sup>२</sup> ऊर्म, हालवेल, हाजेज तथा अन्य तत्कालीन लेखकों ने अपनी आंखों देगे हुए दाह का वर्णन करते हुए स्त्रियों के साहस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है। उस समय मध्य श्रेणी के लोगों को भी पढ़ाने-लिखाने का प्रबन्ध था। बालकों की शिक्षा कमरों में नहीं बल्कि खुली जगहों में होती थी। उसी समय के एक इतिहासकार का लिखना है कि “इन पाठशालाओं में, जहाँ विशाल भवनो के अभाव की पूर्ति स्वच्छ आकाश के चँदोआ से होती है, केवल कारबार की ही शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि जीवन के कर्तव्य, माता-पिता के लिए आदर, ज्येष्ठों के लिए सम्मान, मनुष्यमात्र के लिए न्याय तथा दया और सजातियों के लिए स्नेह के भाव सिखलाये जाते हैं।”<sup>३</sup>

उसी का कहना है कि हिन्दू, मुसलमान तथा भारतवर्ष में बसनेवाले अन्य लोगों में जाति, धर्म, नियम और रीति-रिवाजों की भिन्नता होते हुए भी,

<sup>१</sup> हिल, बंगाल इन १७५६-५७, जि० १, भूमिका।

<sup>२</sup> मेन्वायम ऑफ दि लेट वार इन एशिया, सन् १७८८, जि० २, पृ० २३४।

<sup>३</sup> वही, पृ० २०८।



आतिथ्य-संस्कार नव में पाया जाता है। शिष्टाचार, रहन-सहन की सुन्दरता और वातचीत में हिन्दू किसी सुशिक्षित फ्रांसीसी से कम नहीं है। “फ्रांसीसी



### दीपक-प्रवाह

अपनी प्रतिष्ठा का खयाल करके शायम्नगी का व्यवहार करते हैं, हिन्दुस्तानी इग्नो अथवा कर्तव्य समझते हैं। यदि फ्रांसीसी अपना ध्यान रखकर, तो हिन्दुस्तानी दूसरे का खयाल करके शिष्टता दिखलाते हैं।” भारतवर्ष में खान-पहनने का स्वर्च बहुत कम होता है। यहाँ रपया रटानवाले व्यसन अधिक नहीं पाये जाते हैं। हिन्दुस्तानी मितव्ययी और परिश्रमी होते हैं।<sup>१</sup> हेस्टिग्स का भी कहना है कि ये गुण सभी में पाये जाते हैं, उनका खाना बहुत सादा होता है और वे शराब तथा अन्य मादक वस्तुओं से पूरा परहेज करते हैं।<sup>२</sup>

## भारत में ब्रिटिश साम्राज्य

बड़े घरानों में जगजग का व्ययन अवश्य फैल रहा था, पर साधारण जनता उससे मुक्त थी।

हाजेज लिखता है कि गांवों में गव यावादी हैं, पर तब भी बड़ी सफाई रहती है। हिन्दुओं में सफाई का भाव देखकर आश्चर्य होता है। गांवों की गलिया बराबर बंदोरी और छिड़की जाती हैं।<sup>१</sup> फुलटन का कहना है कि हिन्दु-स्तानी सभ्य, चतुर तथा शिष्ट होते हैं। युद्ध का भी उन्हें अभ्यास है, साथ ही साथ कला, विज्ञान तथा शान्ति के समय के अन्य गुणों में भी वे प्रवीण हैं।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> टाउन, इ. स. जन गट्या, मन १७८०-८५, पृ० ३७, ३४।  
<sup>२</sup> फुलटन, मन १७८५, पृ० १०।

## परिच्छेद ५

### नींव की दृढ़ता

बंगाल का शासन—क्लाइव के जान क पञ्चान बेरेल्लन्द और मार्टियर ने कुछ काल तक गवर्नर के पद पर काम किया। इन दोनों के समय में कोई विशेष राजनैतिक घटना नहीं हुई, परन्तु क्लाइव के चलाये हुए शासन के दोष प्रत्यक्ष दिखलाई देने लगे। मुगल शासन के दो मुख्य अंग थे, एक दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी विभाग कर वसूल करता था, और न्याय तथा शासन निजामत विभाग के हाथ में रहता था। सन् १७६५ में दीवानी और निजामत को मिल गई थी, पर औरगेजों ने कर वसूल करने का काम नवाब के बर्मचारियों के हाथ में ही छोड़ दिया था, वे केवल दूसरा निरीक्षण करते थे। सन् १७६६ में हिन्दुस्तानी ग्रामिलो को हटाकर औरगेज 'धर्मात' रख दिये गये थे और इनका काम देखने के लिए सन् १७७० में पटना और मुर्शिदाबाद में दो बोर्ड बना दिये गये थे। इस तरह जो कुछ ग्रामिलो होती थी उसमें से मद्राट् और नवाब को देकर जो रकम बच रहता था उसमें कम्पनी का सर्चा चलता था। कर वसूल करनेवाले गुमान्ता और फौजदार होने से जो बहुत ना रकम खा जाते थे। इसलिए कम्पनी की ग्रामिलो दिन प्रतिदिन घटती जाती थी। नवाब केवल नाम के लिए नाजिम था मगर औरगेजों के हाथ में थी। दिना सेना की प्रतायता के शासन और न्याय करना सम्भव था। न्यायालय के निर्णयों की किसी को भी परवाह नहीं थी। औरगेज

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य

गुमास्ता जानने के कि उनको दंड देने में नवाब असमर्थ है, इसी लिए वे मनमाना अत्याचार करत थे।

इस प्रथा में जिसके हाथ में शक्ति थी, उसकी कोई जिम्मेदारी न थी, और जिसकी जिम्मेदारी थी, उसके हाथ में कोई शक्ति न थी। इसका फल यह होता था कि दोनों के बीच बेचारी प्रजा पिसती थी। उसकी कहीं भी सुनवाई न थी। गुमास्तों की शिकायत करने पर अंगरेज कहते थे कि न्याय नवाब के हाथ में है, और दूसरी ओर नवाब कहता था कि वह दंड देने में असमर्थ है। इस तरह इन निना प्रजा एक प्रकार में अनाथ थी।

### भीषण दुर्भिक्ष

सन् १७७० में बंगाल में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। कहा जाता है कि इसमें वहाँ की तिहाई आबादी मर गई। मनुष्य को खाने लगे आंग मड़कों पर लाशों के ढेर लग गये। कई साल तक इस दुर्भिक्ष के कारण बंगाल की दशा न सुधर सकी। प्रजा के कष्ट-निवारण के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। इन दिनों सर्वत्र अन्न पहुँचाने के लिए आजकल की तरह मेले न थी। राज्य की ओर से किसी प्रकार का प्रयत्न न था। व्यक्तिगत दान और उदारता से, जिसकी उन दिनों कोई कमी न थी, इतनी बड़ी आपत्ति का सामना करना सम्भव नहीं था। राजकर्मचारियों की निष्ठुरता का इसी से पता चलता है कि उस दुर्भिक्ष के समय में उन्होंने सरकारी आमदनी में कोई कमी नहीं आने दी। कम्पनी के गुमास्तों ने चावल खरीद लिया और उसे मनमाने दाम पर बेचा, जिसका फल यह हुआ कि वे मालामाल हो गये।

### हेस्टिंग्स की नियुक्ति

बंगाल की शोचनीय दशा देखकर सन् १७७२ में कम्पनी के संचालकों ने वागेन हेस्टिंग्स को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। सन् १७८० में वह लेखक होकर भारतवर्ष आया था। सिराजुद्दौला ने जय कामिभवाजार का कोठी को छीन लिया था, तब वह कैद कर लिया गया था, परन्तु पीछे में भाग निकला था। बजबज के युद्ध में वह नवाब के विरुद्ध लड़ा था। उसकी योग्यता देखकर क्लाइव ने उसको मीरजापुर के दरबार में रेजीडेंट बना दिया था। उसी के परामर्श से बादशاهी के मीरजापुर

बनाया गया था। ब्लाइट के लौटने पर सन् १७६१ में वह, २६ वर्ष  
 पचा में, कलकत्ता की कैमिल का मेम्बर हो गया। सन् १७६४ में वह

गपम चला

गपम की उमकी  
 योग्यता और नारतवर्ष-  
 मन्त्रन्धी ज्ञान का परि-  
 चय मिलने पर सन्  
 १७६६ में कम्पनी के  
 संचालको ने दम्को  
 सदराम कैमिल का  
 मेम्बर बनाकर फिर से  
 भेजा। सन् १७७२ में  
 बंगाल की दशा सुधा-  
 रने के लिए उन्होंने उसे  
 पोर्ट विलियम की  
 कैमिल का सभापति  
 और बंगाल का गवर्नर  
 बना दिया। इस समय  
 उसकी अवस्था ४० वर्ष  
 की थी और कम्पनी के  
 संचालको को उस पर  
 पूरा भरोसा था।



वारेन हेस्टिंग्स

नया प्रवन्ध—हेस्टिंग्स जब कलकत्ता पहुँचा तब वहाँ की दशा  
 दयकर होरान हो गया। सब विभागों में पिछला काम पटा हुआ था।  
 बिना दिनाग का क्या काम है और उसकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी कोई  
 व्यवस्था नहीं। बड़े बड़े कर्मचारी अपनी मनमानी करते थे और कोई भी  
 किसी की न सुनता था। हेस्टिंग्स दोहरे शासन के दोषों को अच्छी तरह



के साथ पहले ने कोई सम्बन्ध न था। किसानों को नया पट्टा लिखवा दिया गया और कई एक अनुचित कर हटा दिये गये। परन्तु इन सुधारों से किसानों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। नीलाम में बहुत से नये तथा पुराने जमीन्दारों ने बड़ी बड़ी बोलियाँ बोलकर ठेके ले लिये। मालगुजारी के लिए रुपया वसूल करने में वे रयत पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे। माल-विभाग का मुख्य दफ्तर मुर्शिदाबाद और पटना से हटाकर कलकत्ते में खोला गया और उसके निरीक्षण एक बोर्ड को सौंप दिया गया।

न्याय-विभाग की दशा सुधारने के लिए हर एक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें खोली गईं। ये दोनों अदालतें कलेक्टर के अधीन थीं। दीवानी में वह प्रान्तीय दीवान की सहायता से फैसला करता था और फौजदारी में उसके साथ जिले के काजी तथा मुफ्ती भी बैठते थे। इस तरह कलेक्टर को दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार दिये गये। दीवानी अदालत में मुसलमानों का न्याय 'हदीस' के अनुसार होता था। औरंगजेब के समय में उनके सब नियमों का एक संग्रह बन गया था, परन्तु हिन्दू नियमों का कोई ऐसा संग्रह न था। हेस्टिंग्स ने उस पड़ितों की सहायता में हिन्दू नियमों का एक संग्रह तैयार करवाया। फौजदारी अदालत के फैसले प्रायः मुसलमानों वानून के अनुसार होते थे। औरंगजेब कलेक्टरों को इसका ज्ञान न था, इस-लिए हर एक फौजदारी अदालत में दो मौलवी रख दिये गये थे।

इन जिला अदालतों की अपील के लिए कलकत्ता में दो बड़ी अदालतें खोली गईं, जो 'सदर दीवानी अदालत' और 'सदर निजामत अदालत' के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 'सदर दीवानी अदालत' में खालसा के दीवान, बामिल के दो मेम्बर और कुछ हिन्दुस्तानी जजों की सहायता से गवर्नर फैसला करता था। 'सदर निजामत अदालत' का अध्यक्ष 'दारोगा अदालत' बालता था और उसकी सहायता के लिए प्रधान काजी, प्रधान मुफ्ती और दो मौलवी रहते थे।

**मन्यासियों का दमन**—इस तरह न्याय की व्यवस्था करके जमने देश में शान्ति स्थापित करने की ओर ध्यान दिया। इन दिनों कुछ लोगों का,

## भारत में ब्रिटिश साम्राज्य

हेलो के विरुद्ध नवाब वजीर की सहायता करने का भी वचन दे दिया और नवाब ने सेना का खर्चा भी देना स्वीकार कर लिया। सन् १७७३ में मराठों ने रूहेलो पर आक्रमण किया, परन्तु पूना में गडबड होने के कारण और नवाब वजीर तथा आंगरेजों को रूहेलों की सहायता के लिए तुले देखकर वे बिना लड़े ही वापस चले गये। इस पर नवाब वजीर ने रूहेलो से ४० लाख रूपया मांगा। जब उन्होंने देने में हीला-हवाला किया, तब उसने रूहेलपुड पर आक्रमण कर दिया और बनारस के मम-



मांगी। कर्नल चैम्पियन की अध्यक्षता में एक आंगरेजी सेना भेजी गई। अप्रैल सन् १७७४ में मीरनपुर कटरा में रूहेलो के साथ वोर युद्ध हुआ, जिसमें रूहेला सरदार हाफिज रहमतखां मारा गया और नवाब वजीर की विजय हुई। रूहेले बड़ी वीरता के साथ लड़े, इसका वर्णन करते हुए स्वयं चैम्पियन लिखता है कि रूहेलो को युद्ध-विद्या का अच्छा

ज्ञान था और जिम साहस के साथ वे लड़े उसका वर्णन करता असम्भव है।<sup>१</sup> नवाब वजीर के सैनिकों ने रूहेलो को खूब लूटा। लूट में भाग लेने से गोरे सिपाहियों को मनाही थी, इसलिए वे बड़े असन्तुष्ट थे। परन्तु नवाब वजीर ने ६ महीन में ७ लाख रूपया देने का वादा करके उनको सन्तुष्ट किया। कहा जाता है कि सेना के अत्याचार से लगभग २० हजार



रहेलो को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। इन अत्याचारों का वरान बहुत बड़ा-चढ़ाकर किया गया है और नवाब वजीर को न रोकने के लिए अंगरेजों को भी दोष दिया गया है। कुछ दिन बाद नवाब वजीर और रहेलो में मन्धि हो गई, जिसके अनुसार रहेला सरदार फ़ैजुल्लाख़ाँ को रामपुर का इलाका दे दिया गया, जो अब भी मौजूद है और बाकी रहेलखंड अवध में मिला लिया गया।

इस युद्ध के सम्बन्ध में हेस्टिंग्स की नीति की बढ़ी तीव्र आलोचना की गई है। कहा जाता है कि बनारस के समझौते की सब बातों को हेस्टिंग्स ने कांसिल को नहीं बतलाया था।<sup>१</sup> कम्पनी के संचालकों की आज्ञा थी कि आत्मरक्षा के अतिरिक्त और किसी प्रकार के युद्ध में भाग न लिया जाय। हेस्टिंग्स ने इस आज्ञा के विरुद्ध रहेलो के साथ युद्ध किया। अंगरेजों से रहेलो की कोई शत्रुता न थी। मगड़ा नवाब वजीर और रहेलो के बीच था। उसमें हेस्टिंग्स का पड़ना बेजा था। रहेलो के साथ जो अत्याचार हुए उनके रोकने का कोई प्रयत्न हेस्टिंग्स ने नहीं किया।

इन आक्षेपों के उत्तर में हेस्टिंग्स का कहना है कि उसने बनारस के समझौते का सब हाल कांसिल के सदस्यों को जवानी बतला दिया था। इन दिनों उत्तरी भारत में मराठों का जोर बढ़ रहा था। उनके साथ रहेलो का सम्बन्ध मन्देहजनक था। वे नवाब वजीर के विरुद्ध उनकी सहायता करते थे और नवाब वजीर को धोखा देते थे। यदि रहेलो के साथ मराठे अवध पर धावा करते तो वे बंगाल की सीमा तक पहुँच जाते। इसलिए उनके रोकने की दृष्टि से रहेलो के विरुद्ध नवाब वजीर की सहायता करना आवश्यक था। रहेलखंड के अवध में मिल जाने से नवाब वजीर के राज्य की परिधि-मात्र सीमा गंगा और पहाड़ों के कारण दृढ़ हो गई। इसमें उसने सचा-लकों की आज्ञा का वास्तव में उल्लंघन नहीं किया। इससे अतिरिक्त इन

दिने कम्पनी को रुपये की बड़ी आवश्यकता थी। इस युद्ध में उसके लिए ४० लाख रुपये का ढ़िकाना हो गया और सेना के खर्च का कुछ भार नवाब वजीर के मध्ये चला गया।

हेस्टिंग्स की नीति का यह समर्थन ठीक नहीं जँचता। नवाब वजीर की निर्बलता को वह अच्छी तरह जानता था। बिना अंगरेजों की सहायता के उसको अपनी रक्षा करना कठिन हो रहा था। अवध और मराठों के बीच रहनेवाले का राज्य एक प्रकार की आड़ था। उसके नष्ट हो जाने से अब नवाब वजीर को मराठों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वह सधिया अयोग्य था। इसका परिणाम यह हुआ कि नवाब वजीर अंगरेजों के और भी अधीन हो गया। इस युद्ध में हेस्टिंग्स का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ था, इसी लिए वह नवाब को बढ़ावा दे रहा था, इसको उसने स्वयं माना है। परन्तु जब उसका यह उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि नवाब वजीर उतनी बड़ी रकम को न दे सका, तब वह कड़ने लगा कि उसका मुख्य उद्देश्य अवध की पश्चिमोत्तर सीमा को दृढ़ करके बंगाल की मराठों से रक्षा करना था। ऐसी दशा में यह कहना पड़ता है कि अंगरेजों का इस युद्ध में पड़ना न्याय-संगत नहीं था। रहलपड़ की प्रजा का भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ। रहमत खां के उदार शासन के स्थान पर, जिसमें प्रजा सन्तुष्ट थी, नवाब वजीर का शासन हो गया, जिसमें प्रजा पर अधिक अत्याचार ही हुआ।

**इंग्लैंड-सरकार का हस्तक्षेप**—बंगाल में कम्पनी का प्रभाव देख-कर इंग्लैंड-सरकार को चिन्ता हो रही थी। कम्पनी के कर्मचारी माला माल होकर अपने देश को लौटते थे और वहां नवाबा की तरह रहते थे। इस धन में इंग्लैंड-सरकार ने भी अपना हिस्सा लगाना चाहा और सन् १७६७ में दो साल तक ४ लाख पौंड सालाना देने के लिए कम्पनी को मजबूर किया। बंगाल की अतुल सम्पत्ति देखकर कम्पनी को भी खूब धन मिलने की आशा हो रही थी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। पिछले दुर्भिक्ष से प्रान्त की आर्थिक दशा बिगड़ गई, निजी व्यापार के कारण बहुत सा धन उसके कर्मचारियों की जेब में चला गया। व्यापार मन्दा पड़ गया और बराम

लड़ाई रहने के कारण सेना का खर्चा बेहद बढ़ गया। क्लाइव और हेस्टिंग्स के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी उसकी आर्थिक दशा न सुधर सकी और मन् १७७२ में एक बड़ी रकम कर्ज लेने के लिए उसको ईंग्लैंड-सरकार में प्रार्थना करनी पड़ी। कम्पनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का यह अच्छा अवसर सरकार के हाथ में आया और उसने पूरी जांच करने के लिए दो कमेटियाँ नियुक्त कीं। इन कमेटियों की रिपोर्ट मिलने पर पार्लामेंट ने मन् १७७३ में दो कानून पास किये। पहले कानून के अनुसार यह निश्चित हुआ कि कम्पनी अपना छमाही हिस्सा ईंग्लैंड-सरकार को दिखलाया करे और दूसरे कानून से भारतीय शासन-व्यवस्था में बहुत कुछ हेर-फेर किया गया। यह दूसरा कानून 'रेग्यूलेटिंग ऐक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है।

**रेग्यूलेटिंग ऐक्ट**—इस नई शासन-व्यवस्था के अनुसार बंगाल का गवर्नर, 'गवर्नर-जनरल' बनाया गया और चार मेम्बरो की उसकी एक कौंसिल बनाई गई। गवर्नर-जनरल कौंसिल का सभापति रखा गया और उसको उस सभ्यता से एक वोट अधिक देने का अधिकार दिया गया। गवर्नर-जनरल इस कौंसिल के सर्वथा अधीन बना दिया गया और उसे इसके विरुद्ध कोई काम करने की अनुमति नहीं दी गई। गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल की प्रथम ५ साल की रखी गई और इनकी पहली नियुक्ति का अधिकार ईंग्लैंड-सरकार को दिया गया। बाद को भी बिना सरकार की अनुमति के कम्पनी के सेवकों को इन पदाधिकारियों के नियुक्त करने का अधिकार न रखा गया।

बंगाल के गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल को बम्बई तथा मद्रास प्रान्तों के निरीक्षण का भी भार दिया गया। इन प्रान्तों के गवर्नरों से युद्ध तथा सन्धि के अधिकार ले लिये गये और अपने अपने प्रान्तों का कुछ हात गवर्नर-जनरल को लिखने और बराबर उसकी सलाह से काम करने के लिए उन्हें भर्जा दी गई। कलकत्ते में 'सुप्रीम कोर्ट' नाम की एक बड़ी सरकारी अदालत भी खोली गई। इसमें प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर चार जज रखे गये। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बसनेवाली ब्रिटिश प्रजा तथा कम्पनी के सेवकों के न्याय का अधिकार इन अदालतों को दिया गया।

का विरोध करता था। उसका साथ क्लेवरिंग और मानसन भी देने थे। इस तरह कैमिल मे फ्रांसिस के दल की अधिकता थी और हेस्टिंग्स को, नये कानून के अनुसार, उसकी बात माननी पड़ती थी। इन नये मेम्बरो को भारतवर्ष की परिस्थिति का पूरा ज्ञान न था, इसलिए वे प्रायः हेस्टिंग्स की नीति का, बिना अच्छी तरह समझे हुए,

विराय करने लगते थे।

उन्होंने हेस्टिंग्स के

नियुक्त किये हुए कई

अफसरों को निकाल

दिया और उसकी बहुत

सी कार्यवाहियों को उलट

दिया। यह झगडा

आठ साल तक बराबर

चलता रहा। सन्

१७७६ में मानसन के

मरने पर फ्रांसिस के

दल की अधिकता नष्ट

हो गई और हेस्टिंग्स

को बुद्धि शान्ति मिली।

फ्रांसिस और हेस्टिंग्स

की शत्रुता इतनी बढ़

गई कि सन् १७८० में

पाना में एक उन्मत्त युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसिस घायल होकर इंग्लैंड वापस चला

गया। तब से हेस्टिंग्स को निर्विघ्न काम करने का प्रबन्ध मिला।

**नन्दकुमार को फाँसी—** अपना काम निकालने के लिए, सचालद्वारा

१८२५ से, पहले हेस्टिंग्स ने ही नन्दकुमार को बचाया दिया था, पर

नन्दकुमार सिद्ध हो जाने के बाद से वह उसका विरोधी हो गया था। के लिये



फिलिप फ्रांसिस

में हेस्टिंग्स के विरोधी दल को प्रबल देखकर नन्दकुमार ने भी बदला लेना निश्चित किया। कौमिल से उसने हेस्टिंग्स की कई एक शिकायतें की। इन शिकायतों में मुख्य बात यह थी कि हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम से साढ़े तीन लाख रुपया ब्रूस में लिया है, और १४ लाख रुपया मुहम्मद रिज़ाखा तथा शिताब राय से लेकर उनको अदालत में कुड़वा दिया है। इन अपराधों को सिद्ध करने के लिए कौमिल की एक बैठक में नन्दकुमार बुलाया गया। हेस्टिंग्स गवर्नर-जनरल और कौमिल का सभापति था। वह इस अपमान को न सह सका और बारवेल के साथ कौमिल से उठकर चला गया। बाकी मेम्बरों ने नन्दकुमार की सब बातें सुनकर हेस्टिंग्स को दोषी ठहराया और सब कागजात कम्पनी के वकील को देकर हेस्टिंग्स से कुल रुपया वापस लेने की आज्ञा दे दी। हेस्टिंग्स ने डेढ़ लाख रुपया मुन्नी बेगम से लिया था, यह बात ठीक है। इसको उसके समर्थक सर जेम्स स्टिफ़न ने भी उचित नहीं माना है।<sup>१</sup> इस तरह नन्दकुमार की शिकायतें निराधार न थीं। इधर हेस्टिंग्स और बारवेल ने सुप्रीम कोर्ट में नन्दकुमार तथा उसके कुछ साथियों पर, दोनों के विरुद्ध, पड़्यत्र रचने का अभियोग चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल नन्दकुमार को बारवेल के विरुद्ध दोषी ठहराया। इसी अवसर पर मोहन-प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने नन्दकुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया। कहा जाता है कि किमी दीवानी के मामले में नन्दकुमार ने एक जाली दस्तावेज बनाई थी। अदालत की सहायता के लिए १२ श्रंगरेजों की जुरी बनाई गई, जो एक सप्ताह तक मुकदमे को सुनती रही। अन्त में अदालत ने नन्दकुमार को दोषी पाया और उन दिनों के कानून के अनुसार उसको फांसी देने की आज्ञा दी। नन्दकुमार बड़े धैर्य और साहस के साथ फांसी पर चढ़ा।<sup>२</sup>

१ जेम्स स्टिफ़न, दि स्टार आफ नन्दकुमार, जि० १, पृ० ७२। हेस्टिंग्स का कहना है कि यह रकम भत्त का थी, जो मुर्शिदाबाद जाने पर गवर्नरों को नवाने के खाने से मिला करता था और हिमाय में देने रहता था।

२ कौमिल के नाम अपन अन्तिम पत्र में नन्दकुमार का कहना था कि मैं अब मर

कहा जाता है कि इस मामले में नन्दकुमार के साथ न्याय नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट को यह मुकदमा सुनने का अधिकार ही न था। जाल माली का मामला बदला लेने के लिए हेस्टिंग्स ने चलवाया और अंगरेजी अदालत ने निष्पक्ष भाव से निर्णय नहीं किया। प्रधान जज इम्पी हेस्टिंग्स का सहपाठी था, उसने हेस्टिंग्स का पक्षपात किया। इस तरह "न्याय के नाम में नन्दकुमार की हत्या की गई"। कॉमिल में हेस्टिंग्स के विरुद्ध शिकायत करने के बाद ही, यह पुगना गड़ा हुआ मुकदमा मोदकर निकाला गया था, इससे हेस्टिंग्स पर मन्देह अवश्य होता है। पर हेस्टिंग्स शपथ लेकर अपने को इस मामले में निर्दोष बतलाता है। इसको देखने में देरी होने का कारण यह बतलाया जाता है कि जालमाली का पूरा सचूत तब तक न मिल सका था। अदालत की निष्पक्षता का प्रश्न बड़ा उठित है। मुकदमा सुनने में जज स्वयं ही गवाहों में जिरह करने लगते हैं। अदालत में जब अंगरेज थे, नन्दकुमार अंगरेजों का घोर शत्रु था, पगाल के नवाबों का उनके पजे से मुक्त करने का वह बराबर प्रयत्न करता था। इसी दाप के पीछे अंगरेजों ने उसको हटाकर मुहम्मद रिजाग्या को नायब बनवाया था। गवर्नर-जनरल पर भी उसने घूस खाने के अपराध लगान की छुट्टी दी थी। उन दिनों की राजनैतिक परिस्थिति में ऐसे भयानक मनुष्य के साथ कुछ न्याय कहाँ तक किया जा सकता था, यह कहना बड़ा कठिन है। इस पर भी यदि अदालत की निष्पक्षता स्वीकार कर ली जाय तब भी यह कहना पड़गा कि नन्दकुमार को जो दंड दिया गया वह सर्वथा अनुचित था। यह दंड इंग्लैंड के कानून के अनुसार दिया गया था। अपराध सिद्ध हो जान पर यह दंड देने के लिए अदालत मजबूर थी, यह बात ठीक है। परन्तु यह जागते हुए कि भारतवर्ष में ऐसा निष्ठुर दंडविधान नहीं है, उसका क्रम न

---

। १५१। इन लोक के लिए मैं परलोक को न दिगाइगा। न मत्स्य ५२० १ कि मत्स्यजान के मामल ने न निर्दोष ह। केवल बदला लेने के लिए नन्दकुमार को १५५१वा गवा ह। पारस्य, मेलेपदास, जि० १, पृ० ४००-२१

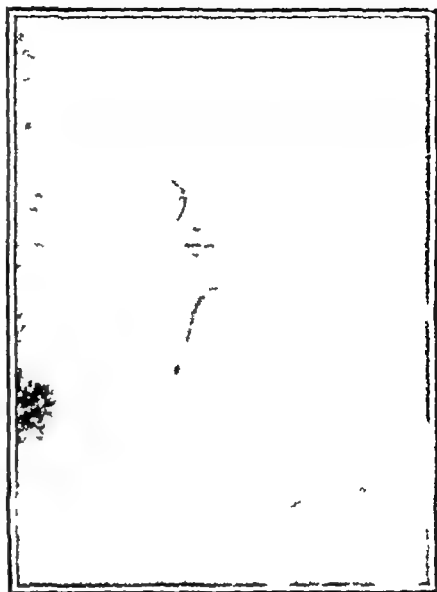
कम इतना कर्तव्य अवश्य था कि वह नन्दकुमार पर दया दिसलाने की सिफारिश करती।

**कौंसिल और कोर्ट**—रेग्युलेटिंग ऐक्ट में कौंसिल और कोर्ट के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या न की गई थी, इसका फल यह हुआ कि दोनों में झगडा होने लगा। कोर्ट के हस्तक्षेप में शासन में बड़ी बाधाएँ पड़ने लगीं। इसके जज अपने को इंग्लैंड-सरकार के अधीन समझते थे और कौंसिल की कुछ भी परवाह न करते थे। पटना के एक मुसलमान जमीन्दार के मरने पर उसकी सम्पत्ति के विषय में उसकी विधवा स्त्री और भतीजे में झगडा हुआ। कोर्ट ने यह कहकर कि जमीन्दार कम्पनी के नौकर है, इसलिए उनके सम्बन्ध के मामले उसके अधीन है, प्रान्तीय कौंसिल के निर्णय को रद्द कर दिया। एक दूसरे मामले में और भी तमाशा हुआ। कोसीगुरा के जमीन्दार के विरुद्ध किसी ने दावा किया। सम्मन देने में जमीन्दार के साथ बड़ी जबरदस्ती की गई। इस पर हेस्टिंग्स की कौंसिल ने कोर्ट के जमादार और सिपाहियों के गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी। स्टिफ़न लिखता है कि कौंसिल का यह कार्य सर्वथा अनुचित था। इसको इतिहासकार स्मिथ भी मानता है, पर साथ ही साथ वह लिखता है कि परिस्थिति बड़ी कठिन थी। कोर्ट के इन वनावटी अधिकारों को रोकने बिना शासन-व्यवस्था का जारी रखना असम्भव था। शासक को कभी कभी कानून के विरुद्ध भी काम करना पड़ता है।<sup>१</sup> स्वयं हेस्टिंग्स ने भी माना है कि शासन के माग में कोर्ट बड़ा बाधक था।<sup>१</sup>

प्रधान जज इम्पी की हेस्टिंग्स से मित्रता होने के कारण यह झगडा आगे न बढ़ने पाया। उसने इसे मिटाने के लिए सन् १७८० में इम्पी को 'सदर दीवानी अदालत' का भी अध्यक्ष बना दिया। इस पद के वेतनस्वरूप इम्पी को २ हजार रुपया माहवार अधिक मिलने लगा। लार्ड मैकाले का कहना है कि नन्दकुमार के मामले में सहायता करने का बदला इस तरह चुकाया

१ स्मिथ, नाक्मपोर्ट हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ५३०-३१।

गया। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इम्पी ने इस वेतन को लिया न था। पार्लामेंट ने इस प्रबन्ध को अनुचित समझकर इम्पी को वापस बुला लिया। इम्पी और हस्तिगज के मन के भाव चाहे जो कुछ रहे हों, यह मानना पड़गा कि उस पद पर थोड़े ही दिन रहकर इम्पी ने कई एक अन्धे सुधार किये। वह फारसी और बँगला दोनों भाषाएँ जानता था। उसने अदालत के नियमों का एक संग्रह तैयार किया और उसका फारसी तथा बँगला में अनुवाद कराया। कार्यवाही में यथासम्भव एकता और सुगमता लाने का भी प्रयत्न किया गया। बहुत दिनों तक भारत की अंगरेजी अदालतों में इन्हीं नियमों के अनुसार काम होता रहा।



एलाइजा इम्पी

**मराठों के साथ युद्ध—**बंगाल और मदरास की बेंगाल-बेंगाली बम्बई-मराठों को भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने की धुन लगी हुई थी। मराठों की पर-पर फूट में इसके लिए उसमें अच्छा अवसर मिल गया। यह बतलाया जा चुका है कि रघुनाथ राव, जो राघोबा के नाम से प्रसिद्ध था, पूना से भागकर अंगरेजों की शरण में चला गया था। राघोबा ने बम्बई के निम्न के दो स्थान—**पसीन और सालसट—**देने का वचन देकर अंगरेजों से सहायता मांगी। बम्बई-मराठों ने सहायता देना स्वीकार करके पहले ही से सालसट पर अधिकार कर लिया। सूरत की सन्धि से राघोबा को यह अधिकार मानना पड़ा। रेग्युलेशन ७४ के अनुसार सूरत की सन्धि के लिए गवर्नर-जनरल की अनुमति



लेनी आवश्यक थी, परन्तु बम्बई-सरकार को नई शासन-व्यवस्था का पता भी न था। हेस्टिंग्स को जब यह समाचार मिला तब उसने बम्बई-सरकार के इस कार्य को “असामयिक और नीति तथा न्याय के विरुद्ध” बतलाया। उसका कहना था कि रावोबा के अधिक पक्षपाती नहीं हैं। स्वयं बम्बई-सरकार के पास मराठा ऐसे प्रबल शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए न तो काफी सेना है और न धन। मराठों का राज्य स्वतंत्र है, उसमें हस्तक्षेप करना अनुचित है। इस निर्णय के अनुसार बम्बई-सरकार को रावोबा की सहायता करने के लिए मना कर दिया गया। साथ ही साथ कर्नल अप्टन को पूना भेजकर, पुरन्दर नामक स्थान पर, एक नई सन्धि की गई, जिसके अनुसार अंगरेजों ने रावोबा का साथ छोड़ दिया। इधर बम्बई-सरकार सालसट और बेसीन को न छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कम्पनी के संचालकों से लिखा-पढ़ी करके सूरत की सन्धि को स्वीकार करवा लिया और रावोबा की सहायता करने के लिए आज्ञा ले ली। पूना-सरकार के विरोध करते रहने पर भी मास्टिन फिर प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। इसके पहुँचने के थोड़े ही दिन बाद मन्त्रियों में फूट हो गई और दीवान सप्पाराम बापू रावोबा के पक्ष में हो गया।

इस पर हेस्टिंग्स भी उस युद्ध का समर्थन करने लगा, जिसको स्वयं उसने “असामयिक और नीति तथा न्याय के विरुद्ध” बतलाया था। फ्रांसिस ने इस तरह पुरन्दर की सन्धि के प्रतिकूल जाने का घोर विरोध किया। उसकी तथा ह्वीलर की राय में बम्बई-सरकार का निर्णय “नियम, नीति तथा न्याय के विरुद्ध” था। हेस्टिंग्स का अपने समर्थन में कहना था कि नाना फडनवीस अंगरेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के एक दूत के साथ बातचीत कर रहा था। इसके अतिरिक्त पूना के स्वयं प्रधान मन्त्रि ने रावोबा को गद्दी पर बिठलाने की प्रार्थना की थी। कम्पनी के संचालकों ने भी सूरत की सन्धि को मान लिया था। इसलिए बम्बई-सरकार की अब सहायता करना अनुचित न था। बहुमत से कैसिल ने हेस्टिंग्स की सलाह मानकर बम्बई सेना भेजने की आज्ञा दे दी।

**वड़गाँव का समझौता**—इस लिखा-पढ़ी और वाद-विवाद के समय में भी युद्ध बराबर जारी रहा। बम्बई-सरकार पहले से ही रावोबा

सहायता करने के लिए एक सेना भेज चुकी थी। इस सेना का सामना करने के लिए नाना फडनवीस तैयार था, होलकर और सिन्धिया अपनी बड़ी बड़ी सेनाएँ लिये हुए पड़े थे। नाना फडनवीस को

अपने जासूसों से बम्बई-सरकार की सब बातों का पता मिल जाता था। उसने ऐसा प्रबन्ध कर रखा था कि अंगरेजी सेना का कोई रसद न मिले। राघोबा को लेकर जो अंगरेजी सेना आई थी उसको, मराठों के बराबर आक्रमण और रसद न मिलने के कारण, विवश होकर उनके साथ जनवरी सन् १७७६ में वडगाँव नामक स्थान पर समझौता करना पड़ा। इसके अनुसार अंगरेजी सेना ने राघोबा का साथ छोड़ दिया, जो भागकर सिन्धिया की शरण में चला गया और कोकण के कई एक स्थानों को लूटने तथा सिन्धिया



राघोबा

को ४१ हजार रुपया देने का वादा किया। बम्बई-सरकार ने इस समझौते को नहीं माना। उसका कहना था कि बिना उसकी अनुमति के सेना को ऐसा समझौता करने का कोई अधिकार न था। हेस्टिंग्स लिखता है कि इस समझौते के पढ़ने पर उसकी लज्जा का कोई ठिकाना न रहा।

इन्हीं दिनों नाना फडनवीस ने पेशवा की ओर से इंग्लैंड के वाटगाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने बड़ी योग्यता से यह दिखलाया कि शुरू से ही अंगरेजों ने मराठों के साथ अपने वचन का पालन नहीं किया। वह लिखता है कि बम्बई और बंगाल की सरकारों के साथ हमने सन्धि के अनुसार ही व्यवहार किया, परन्तु उनका लिखना कुछ और कहना कुछ और है। उन्हें भार बलवत्तावाले एक दूसरे के किये हुए इकरारों को नहीं मानने ह। परन्तु मत भेद होते हुए भी दोनों के काम करने की पद्धति नीति से एक ज्ञान बढ़ना

का उम्मेद इन् समय ध्यान न था, वह दिल्ली में अपना प्रभुत्व जमान के लिए चिन्तित हो रहा था। नाना फडनवीस की यह बात कि मराठा साम्राज्य के हित का संपर्नाश किये बिना भी गिनिधिया उत्तरी भारत में अपना उद्देश्य सफल बना सकती है, क्योंकि यदि मराठा आपस में मिलकर दृढ़ता के साथ काम करेंगे तो अंगरेजों का प्रभुत्व दिल्ली में कभी न जम सकेगा,<sup>१</sup> गिनिधिया की समझ में न आई। वह हेस्टिंग्स की नीति का गढ़ रहस्य न समझ सका। उसके इन कार्य में मराठों की दृढ़ता नष्ट हो गई। हेस्टिंग्स की चतुरता ने मंगल की पश्चिमोत्तर सीमा दृढ़ हो गई और मराठा साम्राज्य में अंतरंग का पर जम गया।

**चेतसिंह पर जुरमाना**—बनारस का राजा पहले अवध के नवाबों के अंग्रेज था। सन् १७७२ में अवध के नवाब न बनारस का इलाका कम्पनी के हवाले कर दिया। राजा चेतसिंह न कम्पनी का २३ लाख रुपया बालाना देना स्वीकार किया और कम्पनी न इसके अतिरिक्त आर क्रिया करने में न मागन का वचन दिया। सन् १७७८ में इंग्लैंड आर फ्रांस में फिर लड़ाई छिड़ गई। इस पर हेस्टिंग्स न चेतसिंह से नियत 'पर' के प्रतिशत २ लाख रुपया सालाना ३ वर्ष तक लेना निश्चित किया। पहल साल ११ लाख न रुपया दे दिया, परन्तु दूसरे साल रुपया देने में देरी हान के कारण हेस्टिंग्स न उस पर जुरमाना कर दिया। तीसरे साल भी उसका एक लाख रुपया जुरमाना देना पड़ा। इस अवसर पर उसने अपना रत्ना करन के लिए स्वयं हेस्टिंग्स को २ लाख रुपया दिया। हेस्टिंग्स न इसका कम्पनी के गजाने में अपने नाम में जमा करा दिया, पर चेतसिंह से वह बराबर तमाजा करना गया। दक्षिण में युद्ध छिड़ जाने के कारण इन दिना रुपये का रुई आस-पसरता थी। चेतसिंह से दो हजार सवार भी मागे गये। बड़ी कोशिश में उन १०० सवार तैयार भी किये, पर हेस्टिंग्स को सन्तोष न हुआ। राजा को

व्यापारियों में मम्ता पड़ता है, जिससे जुलाहों और कारीगरों का बड़ा नुकसान होता है। इसको दूर करने के लिए सन् १७७३ में अंगरेजों को जिले में ब्रम्मे की मनाही कर दी गई और गुमास्तों को आज्ञा दी गई कि वे जुलाहों को दादनी देकर कम्पनी के हाथ माल बेचने के लिए मजबूर न किया करें। दस्तकों की प्रथा बिलकुल रूठा दी गई। नमक, मुषारी और तमाखू को छोड़कर सब पर महसूल घटा दिया गया और अंगरेज तथा हिन्दुस्तानी दोनों से यह महसूल लिया जाने लगा। नमक तथा अफीम का व्यापार कम्पनी के ही हाथ में रखा गया और उनके टेकें भी नीलाम किये जाने लगे। भारतवर्ष में बहुत सा माल तुर्की, सिन्ध और बयरा जाया करता था, परन्तु तुर्की में राजनैतिक अस्थिरता होने के कारण यह व्यापार बन्द सा हो गया था। हेस्टिंग्स ने एक जहाज हिन्दुस्तानी माल में भरवाकर सिन्ध भेजा और फिर से व्यापार का सम्बन्ध जारी किया। भूटान और तिब्बत से भी व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने का उद्योग प्रयत्न किया। 'मिठा' रूपा भी इसी ने चलाया।

**महेलों के साथ युद्ध**—सन् १७७० में महेलों ने नवाब वजीरके साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार मराठों के आक्रमण करने पर उनके "युद्ध या समझौता हुआकर" हटा देने के लिए उन्होंने नवाब वजीर को ४० लाख रुपये देने का वचन दिया। इस सन्धि पर अंगरेज सेनापति वार्कर ने मही की। सन् १७७३ में बनारस में नवाब वजीर की अंगरेजों के साथ भी एक सन्धि हुई, जिसके द्वारा हेस्टिंग्स ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले २० लाख रुपये में नवाब वजीर के हाथ बेच दिये। नवाब वजीर ने इस रकम को तीन वर्ष में अदा करने का वचन दिया और सहायता करने के लिए अपने खर्चे से कम्पनी की कुछ सेना रखना स्वीकार किया। यह प्रबन्ध भी हेस्टिंग्स की चाल में वाला था। उसने स्वयं स्वीकार किया है कि इससे वजीर और मराठों में एक झगडा पैदा हो जायगा, जिसके कारण वजीर को अंगरेजों की सहायता पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा।<sup>१</sup> इसी अवसर पर हेस्टिंग्स ने ४० लाख रुपये के बदले में

१ भारत, सेलेक्शन फ्रॉम दि स्टेट पेपर्स, जि० १, पृ० २८।

सेना और रुपया भेजने में हीला-हवाला करते देखकर हेस्टिंग्स ने उस पर ५० लाख रुपया जुरमाना करना निश्चित किया और उसको वसूल करने के लिए वह स्वयं बनारस आया। हेस्टिंग्स के पहुँचने पर राजा ने बहुत कुछ अनुनय विनय की, पर उसकी एक भी न सुनी गई, और हेस्टिंग्स की आज्ञा से उसके महल पर गोरो का पहरा बैठा दिया गया। बनारस नगर में इस समाचार के फैलते ही उपद्रव मच गया। रामनगर में मैनिंगो ने आकर गोरो को मार डाला। राजा चेतसिंह महल की एक गिडकी से कूदकर लतीफगढ़ की तरफ चला गया। हेस्टिंग्स ने चेतसिंह को दमन करने के लिए एक सेना भेजी। रामनगर की तंग गलियों में सेना के दो दल नष्ट कर डाले गये। चेतसिंह के सिपाही बड़ी वीरता से लड़े। हेस्टिंग्स को अपने प्राण लेकर चुनार भागना पड़ा। इसके बाद पतीता में फिर युद्ध हुआ। यहाँ भी चेतसिंह के सिपाहियों ने बड़ी वीरता दिखाई। रामनगर की ढली हुई तोपें और वारूद देखकर अंगरेज अफसर दग रह गये।<sup>१</sup> मितम्बर सन् १७८१ में अंगरेजों ने लतीफगढ़ पर अधिकार कर लिया। गजाने में जो कुछ रुपया था, उसको सिपाहियों ने लूट लिया। चेतसिंह दक्षिण भाग गया। हेस्टिंग्स ने बनारस लौटकर उसके भानजे को राजा बना दिया, जिसने कम्पनी को ४० लाख रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया।

हेस्टिंग्स का कहना है कि चेतसिंह कम्पनी का एक साधारण सनदयाफ्त जमीन्दार था। आपत्ति के समय पर अपने स्वामी की सहायता करना उसका कर्तव्य था। उसके पास धन और सेना की कमी न थी। वह मराठों और नवाब वजीर से मिलकर विद्रोह करना चाहता था। बनारस का उपद्रव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह जान-बूझकर कम्पनी की सहायता करने में हीला-हवाला करता था। परन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि चेतसिंह एक साधारण जमीन्दार न था। यह बात ठीक है कि कम्पनी ने उससे जमीन्दारी की सनद दी थी और उसने एक कबूलियत लिख दी थी। इस सनद

<sup>१</sup> फारेस्ट, सेलेशम, जि० १, पृ० २२८।



का व्यवहार सर्वथा अनुचित था।<sup>१</sup> लायल के मतानुसार हेस्टिंग्स ने इस मामले में बड़ी भूल की और उसने अपनी स्वाभाविक विचारशीलता से काम नहीं लिया।<sup>२</sup>

यह बात ठीक है कि इन दिनों रुपये की बड़ी आवश्यकता थी पर माय ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि हेस्टिंग्स राजा चेतसिंह से चिड़ा हुआ था। उसके विरुद्ध कौंसिल के सदस्यों में चेतसिंह की मित्रता थी। इसका वह बदला लेना चाहता था। कम्पनी की मांगों को पूरी करने के लिए चेतसिंह ने यथाशक्ति प्रयत्न किया था। दंगल तथा विहाग में कम्पनी के मातहत और भी तो कई राजा तथा जमीन्दार थे, विपत्ति के समय में उनमें सहायता क्यों नहीं मांगी गई? “चेतसिंह की लूट” से कम्पनी के हाथ एक पैसा तक नहीं लगा। यदि उसके साथ नरमी का बर्ताव किया जाता तो कुछ सहायता मिल भी जाती। वह २२ लाख रुपया देने के लिए तैयार था परन्तु हेस्टिंग्स ५० लाख पर ही उड़ा रहा। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में हेस्टिंग्स ने अधिकतर अपने व्यक्तिगत भावों से ही काम लिया।

**अवध के साथ व्यवहार—**सन् १७७५ में नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई। फ्रैंकलिन का कहना है कि अपने समय को देखते हुए वह एक योग्य शासक था। विपत्ति के समय में भी उसका धैर्य न हूटता था। कभी कभी निष्ठुर होते हुए भी उसे न्याय से प्रेम था और राज्य की उन्नति के लिए बराबर चिन्ता रहती थी। अपने योग्य अफसरों की सहायता से उसने राज्य में शान्ति स्थापित रखने की बड़ी चेष्टा की।<sup>३</sup> नये नवाब आसफुद्दौला के साथ दूसरी सन्धि की गई, जिसके अनुसार सेना का माहवारी खर्चा बढ़ा दिया गया, बनारस का इलाका ले लिया गया और अगरेजों के अतिरिक्त यूरोप के

१ मिथ, पृ० ५३८।

२ सर एफ्रेट लायल, वारेन हेस्टिंग्स, पृ० १२५-२७।

३ फ्रैंकलिन, हिस्ट्री ऑफ दि रेन ऑफ शाहआलम, पाणिनि आर्किस सत्करण, पृ० ६४।

त्रिनी अन्य निवासी को नौकर रखने की मनाही कर दी गई। मालगुजारी वसूल करने में भी वह कम्पनी की सेना में सहायता लेने लगा और इसमें कई एक अंगरेज अफसरों को भी रखा लिया। इसका फल यह हुआ कि खर्चा घटने लगे और सन् १७८१ में कम्पनी का कर्जा बढ़ने लगे डेढ़ करोड़ तक पहुँच गया। इन्हीं दिनों हेमिंटज बनारस में भागकर चुनार आया। हमने नवाब का खर्चा घटाने के लिए कुछ सेना वापस बुला ली और कई अंगरेज अफसरों को निकाल दिया। कम्पनी का खर्चा कम होने के लिए यहाँ पर नवाब के साथ एक नवान्ध प्रबन्ध किया गया।

**बेगमों की दुर्दशा**—कहा जाता है कि नवाब की माँ और दादी के पास बड़ा धन था। कम्पनी का कर्जा चुकाने के लिए आनन्दोला इन धन को लेना चाहता था। बेगमों ने २६ लाख रुपया देने दिया भी था जिसके रुपये में उन्हें एक जागीर दी गई थी। सन् १७७५ में अंगरेज रेजीडेंट तथा गवर्नर यमिल के यह विश्वास दिलाने पर कि फिर उनसे रुपया न माँगा जाएगा और उनकी जागीर न छीनी जायगी, बेगमों ने ३० लाख रुपया और देने का वचन दिया था। इसका कुछ भी पान न रखकर अब हेमिंटज ने बेगमों से पान हीन तथा जागीर जब्त करने की अनुमति नवाब को दे दी। रेजीडेंट ने हेमिंटज से लिख भेजा कि बेगमों के प्रति हमारा दिवंगत की बातें सत्य नहीं हैं। इस पर अंगरेजी सेना के साथ नवाब की सेना पलायन पहुँच गई और उसने बेगमों के साथ बड़ा घटोर वर्ताव किया। उन्हें दो विभागों में बाँट कर गिरफ्तार कर लिये गये और कहा जाता है कि उन्हें गोलियों से लपेटा गया। इस तरह बेगमों से चलाने वाला दान भरकर कम्पनी का कर्जा चुकाया गया।



हेस्टिंग्स का कहना है कि बेगमों का धन राज्य की सम्पत्ति थी। उस पर उनका कोई निजी अधिकार न था। कर्जा चुकाने के लिए नवाब उसको ले सकता था। यह बात ठीक है कि सहेलों की लूट से बेगमों को यह धन मिला था, परन्तु विपत्ति के समय पर उन्होंने शुजाउद्दौला की सहायता करने में कोई कसर उठा न रखी थी। अंगरेजों को रुपया देने के लिए इलाहाबाद की सन्धि के समय पर बहू बेगम ने अपनी नाक की नथनी तक निकालकर उसको दे दी थी। ऐसी दशा में शुजाउद्दौला से बाद को जो कुछ धन उसको मिला था उसे यदि वह निज की सम्पत्ति समझती थी, तो इसमें उसका क्या दोष था? दूसरे एक बार ३० लाख रुपया लेकर और बेगमों को यह विश्वास दिलाकर कि उनसे और रुपया न मांगा जायगा, फिर इस तरह बलात् रुपया लेना किसी तरह उचित न था। यदि यह मान भी लिया जाय कि बिना रुपये के काम न चलता था, तब भी जिन उपायों से रुपया लिया गया, वे सर्वथा निन्दनीय थे। हेस्टिंग्स कलकत्ता में रहता था, लखनऊ और फैजाबाद में क्या हो रहा था इसका उसे कुछ पता न था, ऐसा कहने से हेस्टिंग्स अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। रेजिडेंट मिडिलटन के यह लिखने पर भी कि “इस देश की स्त्रियों के साथ जितना कड़ा बर्ताव किया जा सकता है, किया जा चुका है” वह मिडिलटन को और सख्ती के साथ काम लेने के लिए बराबर लिखता रहा। लगभग साल भर तक बेगमों के खोजे कैद रहे, मिडिलटन और ब्रिस्टो कुल हाल कलकत्ता लिखते रहे, परन्तु हेस्टिंग्स ने उनकी करतूतों की निन्दा में कभी मुँह से एक शब्द भी नहीं निकाला, उल्टे नरमी दिखलाने के लिए उन्हीं को डाँटता रहा। अपनी माता और दादी के साथ कुत्सित व्यवहार का जब स्वयं नवाब को पश्चात्ताप हुआ, तब हेस्टिंग्स बिगड़कर कहने लगा कि वह अपने वजीर के प्रभाव में पड़कर मेरी अनुमति से किये हुए कार्यों का, क्रोध और घृणापूर्ण अनुचित शब्दों में, विरोध कर रहा है।

अपनी नीति के समर्थन में हेस्टिंग्स का कहना था कि बेगमों अंगरेजों के विरुद्ध चेतसिंह का साथ दे रही थीं, इसका कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है। दूसरे, यदि ऐसा हो भी तो चेतसिंह के साथ अनुचित व्यवहार,

देवकर आत्म-रक्षा के लिए वेगमो का घबड़ाकर दमका साथ देना कुछ अस्वाभाविक न था। इसको कम्पनी के संचालकों ने भी माना है। मिस्र के यह कहने से कि बिना बल का प्रयोग किये हुए भारतवर्ष में अपना वसूल करना सहज न था, हेमिंस्ट्रज की नीति का समर्थन नहीं हो सकता। सर एल्फ्रेड लायल मरीश हेमिंस्ट्रज के प्रशंसक को भी मानना पड़ा है कि अंगरेज अफसरों की अय्यता से शारीरिक श्रमना पहुँचाकर स्त्रियों और उनके नौकरों से बलान्तर अपना श्रानना एक "वृष्टि का कार्य" था। इकार के विरुद्ध उनके साथ नवाय का मनमाना व्यवहार भले ही उचित हो, परन्तु उनके विरुद्ध नवाय को उत्तेजित करना और दमकी सहायता करना सर्वथा निन्दनीय था, जिसका बाह्य समर्थन नहीं हो सकता।<sup>१</sup>

**मैसूर के साथ दूसरा युद्ध—**अमरीका के विद्रोही दलियों का साथ देने के कारण मई १७७८ में इंग्लैंड और फ्रांस में फिर युद्ध छिड़ गया। यह समाचार मिलने पर फ्रांसीसियों ने पाटुचरी छीन ली गई और मन्नार नद पर माही का बन्दरगाह नष्ट कर डाला गया। यह बन्दरगाह फ्रांसीसी व राज्य में था और यहाँ से दमकी मदद आती जाती थी। इससे मन्नार राजा का यह कार्य उसको बहुत बुरा लगा। मन्नार की मन्त्रिण सन्तुषा अंगरेजों ने मराठों के आक्रमण करने पर हैदराबादी की सहायता नहीं दी, जिससे कारण वह पहले ही से अंगरेजों से चिढ़ा था। इस मन्नार दमक मन्त्रिण निकालने का उसको अच्छा अवसर मिल गया। मराठों से अंगरेजों का युद्ध हो रहा था, इसलिए वे लोग भी साथ देने के लिए तयार थे। दूसरे दिनाम भी अपने मित्र अंगरेजों से चिढ़ा हुआ था। राधाबाई के सन्तुषा मन्नार पर अंगरेजों ने दमका भी साथ नहीं दिया था दूसरे दिनाम दमका सन्तुषा व मन्त्रिण सरकार में गृह का जिला अपने प्रधान कर लिया था। इन्हीं फ्रांसीसी निजाम और मराठा तीनों मिलकर अंगरेजों के विरुद्ध लड़ने का प्रयत्न कर रहे थे।

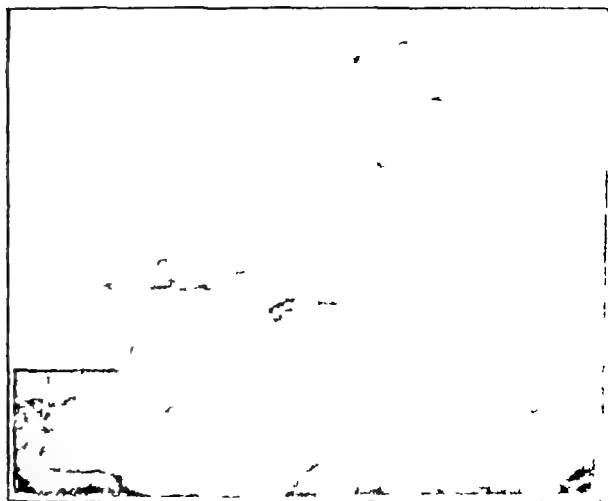
सन् १७८० में हैदरअली अपने बेटे टीपू के साथ एक बड़ी भारी सेना लेकर कर्नाटक पर दूट पड़ा। उसने मारा देश उजाड़ दिया। मद्रास के निकट कुछ गांवों को रात में जलने देकर अंगरेजों को उसके आ जाने का पता लगा। बक्सर-विजयी सेनापति हेक्टर मनरो के उसने लुके लुड़ा दिये। कर्नेल बेली के दल को टीपू ने घेरकर नष्ट कर डाला और उसको गिरफ्तार कर लिया। इस लड़ाई में अंगरेजों के पांच हजार मिशही तथा सात सौ गोरे मारे गये और लगभग दो हजार गोरे कैद कर लिये गये। हेस्टिंग्स को जब यह समाचार मिला तब उसने मद्रास के गवर्नर को अयोग्यता के कारण पद से हटा दिया और आयरकूट को सेनापति बनाकर दक्षिण की ओर भेजा। इस अवसर पर धैर्य न छोड़कर उसने बड़ी नीति से काम लिया। एक ओर मराठा राज-मंडल में फूट फैलाकर सिन्धिया से सन्धि का प्रस्ताव किया और मराठों को हैदरअली के विरुद्ध उत्तेजित कर दिया।<sup>१</sup> दूसरी ओर गद्दर वापस करके निजाम को शान्त कर दिया और हैदरअली मुगल सम्राट् से दक्षिण की सूबेदारी के लिए लिजा-बंदी कर रहा है, ऐसा सुझाकर निजाम को भी उसके विरुद्ध कर दिया। इस तरह इस समय का एक बड़ा भारी राजनैतिक गुट, जिसका परिणाम अंगरेजों के लिए बड़ा भयानक होता, हेस्टिंग्स की चतुर नीति से टूट गया और हैदरअली फिर अकेला रह गया। इतने पर भी उसका साहस न झूटा और वह डच तथा फ्रांसीसियों की सहायता से बराबर लड़ता रहा।

**हैदरअली की मृत्यु**—बड़ी कठिनता से आयरकूट की अध्यक्षता में अंगरेजी सेना ने उसको पोर्टो नोवो, शालिगढ और पालीलूर की लड़ाइयों में हराया। परन्तु दूसरी ओर टीपू ने कर्नेल ब्रेथवेट के दल को फिर नष्ट कर डाला और बेली की तरह उसको भी पकड़ लिया। इस तरह जब युद्ध बंद ही रहा था, दिसम्बर सन् १७८२ में हैदरअली का सहसा देहान्त हो गया मरने के पूर्व वह अच्छी तरह जानता था कि अंगरेजों पर विजय पाना सहज

<sup>१</sup> फारेस्ट, मराठा प्रिरीन, जि० १, पृ० १७४।

नहीं है और हमने अपने मंत्री पुर्णिया से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि "मे अंगरेजों की शक्ति को भूमि पर नष्ट कर सकते हैं पर समुद्र को नहीं सुग्रा सकते हैं।

प्राप्तिमी और मराठों ने हमका साथ नहीं दिया, हमका हमें बड़ा दुःख था। मराठों के विषय में यह कह देना उचित है कि हम समय समय मराठा-महल में फूट पोल रही थी और वे हदरशली की सहायता करने में अग्रमर्थ थे।



### हदरशली

नाता फाटनवीस विवश था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब तक हदरशली की सहायता का समाचार नाता फाटनवीस को नहीं मिला, तब तक हमने सायराट की सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये।

हदरशली ने अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता और साहस से थोड़े ही काम में सफलता की दृष्टि का सत्रमे प्रबल राज्य बना दिया था। निजाम और अंगरेज दोनों ही उसकी शक्ति से डरते थे। कई बार हदरशली मराठे हमने साथ सघेत रहते थे। उसको किसी प्रकार का अन्तिमान न था। सायराट में भी साधारण प्रजा को भी अपना दुःख स्वयं निवेदन करने का अधिकार प्राप्त था। उसमें धार्मिक पक्षपात बिल्कुल न था। उसके दटे दटे अदालत और मंत्री हिन्दू थे। कहा जाता है कि सन् १७६१ में त्रिपुली में शासन करने के समय पर उसने श्रीगजी के मन्दिर के लिए बहुत सा धन

दिया था।<sup>१</sup> किसी प्रकार की अडचन को वह सहन न कर सकता था। अपने बड़े बड़े अफसरों तथा बेटे टीपू तक की चाबुक से खबर लेता था। शासन के सभी विभागों को वह अपने आप देखता था। प्रजा के सुख का उसे बराबर ध्यान रहता था। अपनी सेना को उसने बड़े अच्छे ढंग में संगठित किया था। वह कुछ भी पढ़ा लिखा न था, पर अकबर और रणजीतसिंह की तरह उसको सभी बातों का ज्ञान था। उसकी सरणशक्ति बड़ी तीव्र थी। वह बड़े लम्बे-चौड़े हिसाब जवानी ही बतला देता था। वह पाँच भाषाओं में बोल सकता था। अपने दिमाग पर उसका ऐसा अधिकार था कि वह कई एक काम एक साथ ही करता था। कहा जाता है कि वह महफिल में बैठकर नाच देखता था, मंत्रियों से गूढ़ विषयों पर परामर्श भी करता था और चार-चार पाँच-पाँच पत्र एक साथ ही लिखावाता था। फारेस्ट का कहना है कि उसमें कुछ ऐसे गुण थे, जिनका अंगरेज आदर करते हैं।

इतिहासकार स्थिर की राय है कि “हैदरअली का न कोई धर्म था, न कोई नीति और न उसमें दया का कोई भाव था।”<sup>२</sup> इसके प्रतिकूल उस डे जीवन-चरित के लेखक बावरिंग का कहना है कि “एक पूर्वज होते हुए भी वह अपने कौल का पक्का था। अंगरेजों के प्रति उसकी नीति निष्कपट थी। शासन में वह कठोर था, उसके नाम से भय उत्पन्न होता था, इतने पर भी यदि प्रशंसा से नहीं तो आदर के साथ उसका नाम मैसूर में लिया जाता है। उसकी समय समय पर की कठोरताएँ भूल गईं, पर उसकी शक्ति और सफलता को जनता की स्मृति में सदा स्थान प्राप्त रहेगा।”<sup>३</sup>

**मंगलोर की सन्धि**—कहा जाता है कि मरने पर हैदरअली की पगड़ी में एक पर्चा मिला था, जिसमें उसने टीपू को अंगरेजों से सन्धि करने की सलाह

दी थी।<sup>१</sup> परन्तु टीपू अपने पिता की इस अन्तिम आज्ञा के विरुद्ध अंगरेजों से लड़ता रहा। आयरकूट के मर जान से टीपू का साहस बढ़ गया और हमन कई एक स्थान अंगरेजों से छिन्न लिये। मदरास के गवर्नर ने छत्रा कर जल्दी में सन्धि का प्रस्ताव कर दिया। यूरोप में सन्धि हो जाने पर फ्रान्सीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया। मराठों और अंगरेजों में भी सन्धिवाह की सन्धि हो गई। ऐसी दशा में टीपू ने भी सन्धि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना उचित समझा। मार्च सन् १७८२ में मैंगलूर नगर में सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये। इसके अनुसार दोनों के जीते हुए देश लौटा दिये गये और कदी छोड़ दिये गये। इस अवसर पर टीपू के यहाँ से २६८० गोरे तथा हिन्दुस्तानी कंदियों को नुटकारा मिला। कुछ गोरे उनके हाथ में मर गये जिनकी हमन खब खबर ली।

एंग्लिश को जब इस सन्धि का समाचार मिला तब उनके क्रोध का कोहँ उठाना न रहा। उसका कहना था कि मदरास या गवर्नर सन्धिवाह या भी हाथ से गये देखेगा। हेम्लेट-सरकार सन्धि के पक्ष में थी इसलिये अपनी हस्ता के विरुद्ध हेम्पट्रिज को यह "निन्दनीय तथा अन्याय" सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। इस सन्धि में पेशवा और मिर्जा की सहायता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था जिससे वारण से बहुत विरक्त उन दोनों को एक पत्र लिखकर हेम्पट्रिज ने जयें तैय्ये गान्त दिया।

**हेम्पट्रिज के अन्य सुधार—**युद्ध में बराबर लगे रहने पर भी हेम्पट्रिज का यान सध और रहता था। सन् १७७७ में पाँच सालवाला सन्धिवाह का बन्दोबस्त समाप्त हुआ। अगले बन्दोबस्त के विषय में हेम्पट्रिज और फ्रान्सिस में बहुत वाद-विवाद हुआ। फ्रान्सिस इम्पेरारी बन्दोबस्त के पक्ष में था। अन्त में सालाना बन्दोबस्त फिर जारी किया गया परन्तु नतीजालास करन की प्रथा उठा दी गई और यषामन्ननव मोरुसी जमीन्दारों को उर्मात करी के हाथ में ही देना निश्चित किया गया। बन्दोबस्त के बन्दोबस्त

को भूमि लेने से मना कर दिया गया। प्रान्तीय बोर्डों की जगह कलकत्ता में एक बोर्ड बना दिया गया। कलेक्टरों के हाथ में माल और न्याय दोनों विभाग रहने से कभी कभी प्रजा पर बड़ा अत्याचार होता था, इसलिए इन दोनों विभागों को अलग करने का भी प्रयत्न किया गया और न्याय के लिए नई अदालतें खोली गईं। सन् १७८१ में फौजदारी अदालतों में भी कुछ सुधार किये गये। दीवानी अदालतों के अंगरेज जजों को दारोगा के पास अपराधियों के चालान करने के अधिकार दिये गये और अग-भग के कई कठोर दंड उठा दिये गये। सुप्रीम कोर्ट की अधिकार-सीमाएँ कलकत्ता भर में ही परिमित कर दी गईं।

हेस्टिंग्स को पूर्वीय साहित्य में बड़ा प्रेम था। उसको अरबी तथा फारसी का ज्ञान था और वह हिन्दुस्तानी अच्छी तरह बोल सकता था। सन् १७८१ में



उसने 'कलकत्ता मद्रसा' खोला, जो आजकल एक बड़ा मुसलमानी कालेज है। बंगाल की सुप्रसिद्ध 'एशियाटिक सोसायटी' के स्थापित करने में उसने सर विलियम जोन्स की दड़ी सहायता की। जोन्स ने संस्कृत के कई एक ग्रन्थों का अंगरेजी में अनुवाद किया। इस सोसायटी से पूर्वीय साहित्य का बड़ा उपकार हो रहा है। हेस्टिंग्स ने कई एक संस्कृत पंडितों को कलकत्ते में बसाया था और वह उनकी बराबर सहायता करता था। सन् १७८१ में उसने मेजर

सर विलियम जोन्स

रेनल के द्वारा बंगाल का पहला 'अटलस' तैयार करवाया। रेनल सन् १७६४ से ही बंगाल में पैमायश का काम करता था। उसका

भांगालिक ज्ञान दृढ़ता बढ़ा-चढ़ा हुआ था कि 'वह भारतीय सुगोल का जन्म-दाता माना गया है'।

**पिट का इंडिया ऐक्ट**— फ्रांसिस जेम्स म हेन्स्लेड वापस गया था नमी में हेम्स्टिज के विरुद्ध मंत्रियों के कान भर रहा था। सन् १७८० में पार्लामेंट में भारतवर्ष का प्रश्न फिर छिड़ गया। इसी साल बंगाल के शासन और कर्नाटक-युद्ध के कारणों की जांच करने के लिए दो कमेटियाँ नियुक्त की गईं। इन कमेटियों के रिपोर्ट करने पर क्रामस रूखा न दृष्टि में गवर्नर और हेम्स्टिज को वापस बुलाने का निश्चय किया। परन्तु कम्पनी के संचालकों ने इसको न माना। इस पर फ्रांसिस ने एक बिल पेश किया जिसके अनुसार वह कम्पनी के सब राजनैतिक अधिकार हेन्स्लेड-मशकार के हाथ में देना चाहता था। कई कारणों से यह बिल पास न हो सका। सन् १७८१ में पिट ने एक नया कानून पास करवाया, जिसके अनुसार ६ सदस्यों की एब 'निरीक्षण समिति' बनाई गई, जो 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के नाम से प्रसिद्ध हुई। भारतवर्ष में कम्पनी के शासन की सब दखल-भाल इस बोर्ड में की गई। आगे चलकर बोर्ड नाम मात्र का रह गया और सब अधिकार इसके सभापति के हाथ में चले गये। बोर्ड की आज्ञाओं से भारतवर्ष भेजने और वहाँ के सब बागजात बोर्ड के सामने पेश करने में पिट कम्पनी के तीन संचालकों की एक 'गुप्त कमेटी' भी बनाई गई। सन् १७८३ तक वा शेष राजनैतिक मामलों से बोर्ड सम्बन्ध न रह गया परन्तु कम्पनी के कर्मचारियों को नियुक्त करने और निशान्ते का अधिकार 'बोर्ड ऑफ ट्राइब्यूनल' के हाथ में ही छोड़ दिया गया। 'बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटी' के अधिकार कम कर दिये गये और बोर्ड की कार्यवाही में लंबा बाई सम्बन्ध न रह गया। भारतवर्ष में राज्य की वृद्धि के लिए हुए बरना 'राज' की नीति, प्रतिष्ठा तथा दृष्टि के विरुद्ध बनलादा राज के संचालकों की बिना अनुमति के अपनी या अपने अधीन राज्यों की रक्षा के लिये निराला प्रकार के युद्ध या सन्धि करने के लिए गवर्नर-जनरल और कम्पनी के अधिकार स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। भारतवर्ष में गवर्नर-जनरल के



कौंसिल के सदस्यों की संख्या चार से तीन कर दी गई, और मदनराय तथा बम्बई प्रान्त, युद्ध, मालगुजारी तथा राजनीति के विषय में उसके पूर्ण रूप से, अधीन बना दिये गये। इस तरह भारतवर्ष में कम्पनी के नाम से इंग्लैंड-सरकार का शासन प्रारम्भ हुआ।

**हेस्टिंग्स का इस्तीफ़ा**—इस कानून से हेस्टिंग्स को अच्छी तरह ज्ञात हो गया कि उसकी नीति का अब इंग्लैंड-सरकार समर्थन नहीं कर सकती। उसकी राय थी कि “पचासो वर्क, फाक्स और क्रामिस” इसमें खराब कानून नहीं बना सकते थे। इंग्लैंड-सरकार की निगाह फिरी हुई देखकर, उसके अधीन अफसर भी उसकी पवाह न करते थे। मदनराय के गवर्नर ने उसकी इच्छा के प्रतिकूल मैंगलोर की “अपमानजनक” सन्धि कर ली थी। इन सब बातों से दुखी होकर उसने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और फरवरी सन् १७८५ में वह भारतवर्ष से वापस चला गया।

**पार्लामेंट का अभियोग**—इंग्लैंड पहुँचने पर भी उसको शान्ति न मिली। सन् १७८६ में वर्क के प्रस्ताव पर उसके शासन की जांच फिर से प्रारम्भ की गई। पार्लामेंट की कामस सभा ने सहोदर और मराठा युद्ध के सम्बन्ध में उसको निर्दोष पाया, पर चेतसिंह और अवध की बेगमों के प्रति उसके व्यवहार की बड़ी तीव्र आलोचना की। इस पर सन् १७८८ में पार्लामेंट की लाइड्स सभा में उस पर अभियोग चलाया गया। इस अभियोग में नवाब वजीर के साथ सन्धि तोड़ने, उसके शासन में हस्तक्षेप करने, उसकी सेना को बढ़ा देने, बेगमों और चेतसिंह के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा कई मामलों में धूस खाने के बीस अपराध लगाये गये। इसमें क्रामिस की सहायता से—वर्क, फाक्स और शेरिडन—इंग्लैंड के तीन सुप्रसिद्ध वक्ताओं ने बड़े जोरों से बहस की। हेस्टिंग्स ने बड़े साहस और धैर्य के साथ अपनी नीति का समर्थन किया। यह अभियोग सात वर्ष तक चलता रहा। इतने दिनों में बहुत से परिवर्तन हो गये और अन्त में हेस्टिंग्स निर्दोष प्रमाणित होकर छोड़ दिया गया।

इस अभियोग का एक फल अवश्य हुआ। जिस शासन-प्रकार का संचालन एंस्ट्रिज कर रहा था, वह किन्ना अधूरा था यह सिद्ध हो गया और अफ़मरों को पूरी ज़तावनी मिल गई। साथ ही साथ वर्र के उदार विचारों का प्राण चलकर भारतीय शिक्षित समाज पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। अभियोग के भारी उर्वर स एंस्ट्रिज निर्धन हो गया। 'ग्रेट सरबार ने वर्रपनी के संचालकों को उम्मीद यथेष्ट सहायता न बन दी। वह निर्दोष सिद्ध हो गया एंस्ट्रिज का यही दृष्टा भारी सन्ताप था। सन् १८५८ में उम्मीद सृष्टि हो गई।



ग्रेट सरबार

निर्बल बना दिया। मैसूर-युद्ध के समय पर निजाम, हैदराबादी तथा मराठों के प्रबल गुट को उसने तोड़ डाला। जिन दिनों वह भारतवर्ष में था, अमरीका में अंगरेजों की बराबर हार हो रही थी। उसने इसका प्रभाव भारतवर्ष पर न पड़ने दिया। उसके समय में भारतवर्ष की अधिक भूमि कम्पनी के हाथ नहीं लगी, यह ठीक है। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि कम्पनी की शक्ति को उसने ऐसा बना दिया कि जिससे सभी डरने लगे।

अपनी पर-राष्ट्र नीति के समर्थन में, पार्लामेंट के प्रति उसका कड़वा था कि कम्पनी के राज्य की स्थापना दूसरों की बीरता से हुई, "मैंने उसकी वृद्धि की और उसको एक निश्चित स्वरूप दिया। मैंने उसकी रक्षा की और चौदह वर्षों में उसकी सेनाओं को शत्रुओं के अज्ञात देश में भेजकर आपके अन्य अधिकृत स्थानों की सहायता की। एरु (बम्बई) को मैंने अप्रतिष्ठा और अपमान से बचाया और दूसरे (मदरास) की नष्ट तथा पराधीन हो जाने से रक्षा की। मैंने उन लड़ाइयों को जारी रखा, जिनको मैंने नहीं, पर आप या दूसरों ने छेड़ा था। मैंने प्रबल भारतीय गुट के एक सदस्य (निजाम) को (गद्दर) वापस करके फोड़ लिया, दूसरे (भोसला) के साथ गुप्त सम्बन्ध जारी रखकर उसको मित्र बना लिया, तीसरे (सिन्धिया) का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करके उसको सन्धि का साधन बना लिया। जब आप सन्धि के लिए चिन्ता रहे थे और वे लोग, जिनमें सन्धि करनी थी, सुन रहे थे, मैं अपनी मांगों को बढ़ाकर अपने विरुद्ध जानेवाली बातों को रोकने और ऐसी सन्धि की, जो मुझे आशा है, एरु (मराठों के) राज्य के साथ स्थायी होगी। साथ ही साथ मैंने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये, जिनके द्वारा दूसरे (टीपू) के साथ, यदि इतनी स्थायी नहीं हो तो कम से कम समयेचित, सन्धि करना सम्भव हो गया।"

"मैंने आपको सब कुछ दिया, परन्तु आपने उसके इनाम में मेरा धन लिया, मेरा अपमान किया और मुझ पर अभियोग चलाया।"

इस समर्थन की भाषा वैसी ही है, जैसी भाषा में उस पर अभियोग चलाया गया था। वह लिखता है कि देश को उस समय शान्ति की आवश्यकता थी, मैं स्वयं शान्ति चाहता था, परन्तु अपमान के साध नहीं। मुझे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ राज्य की रक्षा के लिए लड़नी पड़ीं।<sup>१</sup> यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मराठों या रुहेलों ने कम्पनी के राज्य पर कभी आक्रमण नहीं किया था। उपायों के उचित या अनुचित होने की बात छोड़कर इसमें कोई नन्देह नहीं कि उसने भारतवर्ष में अंगरेजी शक्ति को बड़ी प्रबल बना दिया।

**उसका शासन और चरित्र**—हेस्टिंग्स के समय में जिस ढंग से शासन किया जा रहा था, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। जमीन को नीलाम करने और थोड़े काल के लिए ठेके पर उठाने का फल यह हुआ कि प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार होने लगे। जमीन्दार और सरकारी कर्मचारियों को अपने मतलब के सिवा और किसी का ध्यान न रहा। मन् १७८८ के एक पत्र में कोलमुक लिखता है कि हेस्टिंग्स ने देश को क्लेक्टर और जजों से भर दिया, जिनका एक मात्र उद्देश्य रुपया कमाना था। जहाँ ये पहुँच गये वहाँ इन्होंने जनता को लूट लिया। न्याय की तो बिक्री होती थी। जो सब से अधिक धन देता था जज उसी की सुनते थे।<sup>२</sup> इनको रोकना तो दूर रहा, रावर्ट्स का कहना है कि मनुष्यों को अपने पक्ष में लाने के लिए कभी कभी स्वयं हेस्टिंग्स खुले तौर पर ऐसे उपायों का प्रयोग करता था, जो बाद की नैतिक दृष्टि से उचित नहीं कहे जा सकते।<sup>३</sup> सर जान मालकम लिखता है कि उसके शासन-काल में धूम गृह चलती थी।<sup>४</sup> यह बात ठीक है कि इन दिनों ऐसे अत्याचारों का

<sup>१</sup> हेस्टिंग्स, मेम्बार्स रिलेटिव टु दि स्टेट ऑफ इंडिया, मन् १७८६।

<sup>२</sup> वामनदास वसु, राज ऑफ दि ब्रिटिश एण्ड पावर इन इंडिया, जि० २, पृ० १७।

<sup>३</sup> रावर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पृ० २०३।

<sup>४</sup> मालकम, स्कैच ऑफ दि पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ० ४०।

रोकना भइज न था। शासन-व्यवस्था को सुधारने का हेस्टिंग्स ने प्रयत्न अवश्य किया था।

खर्च करने में उसका हाथ खूब खुला हुआ था, इसी लिए उसे रुपये की हर समय आवश्यकता रहती थी। कानूनी सबूत न होने के कारण घूसखोरी के सम्बन्ध में लार्ड मैकाले भी उसे निर्दोष पाता है। पर मुन्नी बेगम, चेतसिंह तथा आसफुद्दौला से उसे जो रकमें मिलीं थीं, उन्हें उचित नहीं कहा जा सकता। यह बात ठीक है कि चेतसिंह तथा नवाब की रकमें उसकी जेब में नहीं गईं, पर इससे वह निर्दोष नहीं माना जा सकता। चेतसिंह का रुपया अपने नाम से कम्पनी को देना 'सेलेक्ट कमेटी' की राय में एक प्रकार का धोखा था। नवाब की रकमवाले कुल मामले को लायल ने "हर तरह से दूरदर्शितारहित" बतलाया है।

हेस्टिंग्स की नीति तथा उसके कार्यों की बड़ी तीव्र आलोचना की गई है। केवल मिल ने ही नहीं बल्कि मार्शमैन, थार्नटन, बेवरिज तथा अन्य इतिहासकारों ने भी उसके कई एक कार्यों की निन्दा की है। बेवरिज का कहना है कि वह बड़ा घमडी था और प्रायः चालबाजी से काम लेता था।<sup>१</sup> हेस्टिंग्स के समर्थन में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया जाता है कि उसे बड़ी कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ा था। मिल ने भी इसको माना है। परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सी कठिनाइयाँ स्वयं उसकी पैदा की हुई थीं। इसमें सन्देह नहीं कि वह बड़ा नीतिनिपुण था। उसका दिमाग बड़ा तेज था। अवसर पड़ने पर उसको बड़ी दूर की सूझती थी। धैर्य और साहस की उसमें कमी न थी। विपत्ति-काल में वह कभी घबड़ाता न था। कौंसिल के विरोध और इंग्लैंड सरकार की घुड़कियों की उसने पर्वाह न की। अभियोग के समय पर उसको छेड़ने और उत्तेजित करने के लिए कोई बात उठा न रखी गई, पर वह बराबर गम्भीर तथा शान्त रहा।

उसके शासन में दोष थे, उसके उपाय निन्दनीय थे, उसके सिद्धान्त नैतिक दृष्टि में उच्च न थे, इन सब बातों को मानते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि वह बड़ा प्रतिभाशाली मनुष्य था। पग पग पर बाधाएँ होते हुए भी उसने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की नींव को ऐसा दृढ़ बना दिया कि जिस पर आगे चलकर साम्राज्य का निर्माण हो सका।

**सर जान मैकफर्सन**—हेस्टिंग्स के जाने पर कौंसिल के बड़े मेम्बर मैकफर्सन को चार्ज मिला। यह पहले मदरास में काम करता था, पर वहाँ से निकाल दिया गया था। अर्काट के नवाब ने इसको अपना गुप्त दूत बनाकर ट्रेंगल्लेड-नरकार के पास भेजा था। बाद में कम्पनी के संचालकों ने इसको कलकत्ता की कौंसिल का मेम्बर बना दिया था। सेना का ५० लाख रुपया बाकी था, उसको हमने चुका दिया और खर्चा कम करने के लिए बहुतांश का वेतन घटा दिया। नवाब वजीर की भी यह कुछ सहायता करना चाहता था, पर हेस्टिंग्स के विचारों का ध्यान रखते हुए, उसने उसकी नीति में परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। इसी समय मुगल सम्राट् के नाम से माहादजी सिन्धिया ने आंगरेजों से कर माँगा, पर मैकफर्सन ने साफ जवाब दे दिया। लार्ड कार्नवालिस का कहना है कि मैकफर्सन कमजोर तथा भूढ़ा था और उसके जमाने में घूस ले लेकर कर्मचारी रखे जाते थे। वह २० वर्षों तक गवर्नर-जनरल के पद पर रहा।

## परिच्छेद ६

### हस्तक्षेप न करने की नीति

कार्नेवालिस की नियुक्ति—पिट के इंडिया ऐक्ट की नीति को काम में लाने के लिए कार्नेवालिस गवर्नर-जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। वह



एक उच्च श्रेणी का रईस था। अमरीका के स्वतंत्रता-युद्ध में हारकर इंग्लैंड वापस आया था। पहले दो बार वह गवर्नर-जनरल के पद को अस्वीकार कर चुका था। इंग्लैंड से चलने के पूर्व उसने 'रेग्युलेटिंग ऐक्ट' के एक बड़े दोष को दूर करवा लिया। उस ऐक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल कौंसिल के सर्वथा अधीन था, जिसमें शासन में बड़ी अड़चने पड़ती थीं, जैसा कि हंस्टिंग्स के सम्बन्ध में दिखलाया जा चुका है। अब

कार्नेवालिस

आवश्यकता पटने पर कौंसिल के विरुद्ध भी काम करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। सन् १७८६ में कार्नेवालिस भारतवर्ष पहुँचा।

**नौकरियों का सुधार**—भारतवर्ष पहुँचने पर कार्नवालिस ने देखा कि कम्पनी के कर्मचारियों में घूम खाने का बाजार गरम है। बनारस के रेजीडेंट का मासिक वेतन तो एक हजार रुपया था, पर उसकी सालाना आमदनी चालीस हजार रुपये से भी अधिक थी। कहने के लिए तो कम्पनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार बन्द हो गया था, पर शायद ही कोई ऐसा कलेक्टर रहा होगा, जो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के नाम से व्यापार न करता हो। इस व्यापार में वे लोग, जज और शासक की हँसियत से, तरह तरह के दयाव डालकर अनुचित लाभ उठाते थे। सचालक भी इस ओर अधिक ध्यान न देने थे। कर्मचारियों की सम्पत्ति से वे स्वयं लाभ उठाते थे। कार्नवालिस लिखता है कि इसका रोकना तो दूर रहा, वे लूट में अपने मित्रों को हिम्मा दिलाने के लिए लडा करते थे। इन दिनों कर्मचारियों का वेतन बहुत कम था, पेंशन मिलने की प्रथा न थी, इसलिए जब तक वे भारत में रहते थे, उनको धन बटोरने की ही चिन्ता रहती थी। इस दोष को दूर करने के लिए कार्नवालिस ने कलेक्टरों तथा बड़े बड़े अफसरों का वेतन बढ़ा देना ही उचित उपाय समझा। बहुत लिखा-पढ़ी के बाद संचालकों ने उसकी राय को स्वीकार करके वेतन बढ़ाने की आज्ञा दे दी। नौकरी के सम्बन्ध में वह गिफ्टारियों का बटा विरोधी था। इस मामले में वह इंग्लैंड के राजकुमार तक की न सुनता था।

**अदालतों का प्रबन्ध**—कलेक्टर के हाथ में न्याय, शासन तथा माल नीति विभागों के रहने के कारण अधिकारों का बटा दुरुपयोग होता था। माल और शासन के मामलों में कलेक्टर ही अपराधी होता था और वही न्याय करता था। ऐसी दशा में प्रजा के साथ क्या न्याय हो सकता था ? इस दोष को दूर करने के लिए उसने इन विभागों को अलग अलग कर दिया। कलेक्टर के हाथ में केवल माल का महकमा रह गया, न्याय से उसका कोई सम्बन्ध न रहा। दीवानी विभाग में छोटे छोटे मामलों को तय करने के लिए सदर अमीन और मुगियों की अदालतें खोली गईं। उनकी अपील के लिए जिला जज की अदालत रखी गई। यह जज अंगरेज होता था, जो अफसरों की महा-



यता से निर्णय करता था। इसकी अपील के लिए कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में चार प्रान्तीय अदालतें स्थापित की गईं। इनके अंगरेज जजों के साथ भी हिन्दुस्तानी 'असेसर' रखे जाते थे। इन प्रान्तीय अदालतों की अन्तिम अपील कलकत्ता की 'मदर टीवानी अदालत' में होती थी, जिसमें गवर्नर-जनरल और कैम्पिल के मेम्बर बैठते थे।

फौजदारी का काम भी इन्हीं टीवानी अदालतों को सौंपा गया। नायब नाजिम को फौजदारी के मुकदमों करने का अधिकार नहीं रहा। अंगरेज जज द्वारा करके ये मुकदमों सुनते थे। इनकी अपील 'सदर निजामत अदालत' में होती थी। मुसलमानी कानून से इन दिनों भी काम होता था, पर उसके कई एक कठोर ढंड हटा दिये गये थे। कार्नवालिस ने अदालतों की सहायता के लिए नियमों का एक संग्रह भी तैयार करवाया था, जो 'कार्नवालिस कोड' के नाम से प्रसिद्ध है।

हेस्टिंग्स ने पुलिस का काम फौजदारों और थानेदारों के हाथ में छोड़ दिया था, परन्तु शान्ति स्थापित रखने का भार अधिकतर जमोन्दारों के ही मथे था। कार्नवालिस ने इस काम को भी कम्पनी के अधीन कर लिया। इसके लिए कई एक थाने खोल दिये गये, जिनमें हिन्दुस्तानी दारोगा रख दिये गये। इन लोगों का वेतन २० या २५ रुपया मासिक से अधिक न होता था। इस वेतन के अतिरिक्त किसी चोर या डाकू के पकड़ने पर दस रुपया इनाम और चोरी का माल पकड़ने पर कुछ कमीशन मिलता था। तीन चार सौ मील में कहीं एक थाना होता था, जिसमें १५ या २० सिपाही रहते थे। इनके लिए इतने बड़े हलके में पूरी देख-भाल करना असम्भव था। वेतन कम होने के कारण और इनाम के लालच में पड़कर दारोगा बदमाशों की अपेक्षा भले आदमियों को ही अधिक तग करता था।

भारतवर्ष के लिए कार्नवालिस की न्याय-व्यवस्था बड़ी जटिल थी। साधारण प्रजा को प्राचीन पंचायत या देशी अदालतों का ही ढाग सीमा और सुगम जान पड़ता था। उसमें विशेष खर्चा न था, वादी प्रतिवादी स्वयं अपनी बात न्यायाधीश को मझ में समझा सकते थे। परन्तु इन अदालतों के पेचीदा

कानून-कायदों का प्रजा को ज्ञान न था, दूसरी ओर अंगरेज जजों को भारतीय नीति-रिवाजों का पता न था। इसलिए बिना वकील के काम चलाना असम्भव हो गया। वकीलों के मेहनताने के अतिरिक्त अदालतों में बहुत सी नई फीमें पढ़ने लगीं, जिनसे मुकद्दमों का खर्चा बढ़ गया और न्याय में भी अधिक समय लगने लगा। इन दोषों से कर्नवालिस अनभिज्ञ न था। कम्पनी का खर्चा और समय बचाने के लिए उसने दूसरे ही कायदे बना दिये थे, जिनके अनुसार बिना किसी प्रकार के झगड़ों में पड़े हुए कम्पनी का काम सहज में निकल जाता था। इस पर इतिहासकार मिल ठीक पूछता है कि किस सिद्धान्त के अनुसार मुल्क और सुगम न्याय सरकार के लिए उचित, पर प्रजा के लिए अनुचित, समझा गया ?

बनाइव और हेस्टिंग्स के समय में हिन्दुस्तानी बड़े बड़े पदों पर काम करते थे, पर कर्नवालिस इसके पक्ष में न था। उसका मन था कि “प्रत्येक हिन्दुस्तानी धूम खाता है।”<sup>१</sup> वह लिखता है कि “मेरी समझ में जितने सुधार (कौजदारी विभाग में) किये गये हैं, वे सब व्यर्थ हो जायेंगे, यदि उनका काम में लाना किसी हिन्दुस्तानी के हाथ में रहेगा।” क्या केवल हिन्दुस्तानी ही धूम खाते थे ? बतारम और लखनऊ के रेजिडेंट तो अंगरेज थे, पर उनकी क्या दशा थी ? यह दोष दूर करने के लिए अंगरेजों के वेतन बढ़ा दिये गये, पर हिन्दुस्तानियों के लिए यह क्यों उचित न समझा गया ? मार्शमैन ने इसको कर्नवालिस की “घड़ी भारी भूल” बतलाया है। उसका कहना है कि इससे हिन्दुस्तानियों के लिए बड़े बड़े ओहदों का दरवाजा बन्द हो गया। इस भूल का प्रभाव अब तक चल रहा है।

**बंगाल के ज़मीन्दार—**मुगलों के शासनकाल में किसान अपनी पदावार का नियत भाग राज्य को लगान के रूप में देता था। यह लगान प्रायः गांव के मुखिया या ग्रामिणों द्वारा वसूल किया जाता था। इस तरह राजा और न्याय में सीधा सम्बन्ध था। लगान वसूल करने के लिए देश में अधिकतर इमी

<sup>१</sup> कर्नवालिस, करप्पाटम, म० रॉम, जि० ६, पृ० २८८ ।



जमीन्दार खेती की उन्नति का ध्यान नहीं रखते हैं। कम्पनी की एक तिहाई भूमि पर जंगल खड़े हैं। जमीन्दारों को यदि यह विश्वास हो जायगा कि माल-गुजारी नहीं बढ़ेगी, तो वे जंगलों को कटवाकर उस भूमि पर खेती करवाने लगेगे। दस वर्ष के बन्दोबस्त से उनकी पूरी दिलजमई न होगी। इसके अतिरिक्त सरकार को बार बार बन्दोबस्त का भ्रंश न करना पड़ेगा और उसकी आमदनी नदी के लिए निश्चित हो जायगी। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जमीन्दार खेती की उन्नति करेंगे और प्रजा के सुख का ध्यान रखेंगे। ईंग्लैंड-सरकार ने कार्नवालिस की राय को मान लिया और सन् १७६३ से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में इम्तमरारी बन्दोबस्त करने की आज्ञा दे दी। दो वर्ष बाद बनारस के इलाके में भी यही बन्दोबस्त कर दिया गया। यह प्रबन्ध जमीन्दारों के साथ किया गया था, इसलिए इसको 'जमीन्दारी बन्दोबस्त' भी कहते हैं।

**सरकार की हानि**—इम्तमरारी बन्दोबस्त से सरकार की बड़ी हानि हुई। कुछ दिनों में बंगाल की दशा सुधर गई, खेती भी अधिक होने लगी, पर सरकार का उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उसको अब तक वही चँधी हुई रकम मिलती है। इतिहासकार स्मिथ का कहना है कि इस बन्दोबस्त में सरकार को ३ करोड़ रुपया मालाना का घाटा सहना पड़ता है, जिसको भारतवर्ष के अन्य प्रान्त पूरा करते हैं। इस मामले में कार्नवालिस ने बड़ी तल्लीनी की। यदि जान शेर की सलाह मानकर दस साल तक इतना म्याद प्रबन्ध न किया जाता, तो उतने समय में खेती की ठीक ठीक दशा का पता लग जाता और जमीन्दारों की पूरी आमदनी मालूम हो जाती, जिसमें सरकार को इतना बड़ा घाटा न सहना पड़ता। इस बन्दोबस्त से मालगुजारी में हमें एक पैसा भी बढ़ाने का अधिकार नहीं रहा।

**जमीन्दारों का लाभ**—इस बन्दोबस्त से सबसे अधिक लाभ जमीन्दारों का हुआ। वे अब जमीन के मालिक हो गये। जिस तखमीना पर मालगुजारी घाटी गई थी, उसमें कई गुनी आमदनी बट गई। यह सब रुपया उन्हीं की जेबों में जाने लगा। परन्तु इस बन्दोबस्त से पहले उनका

भी नुकसान हुआ। कार्नवालिस ने यह नियम बना दिया था कि यदि समय पर मालगुजारी वसूल न हो, तो जमीन्दारी जप्त करके नीलाम कर दी जाये करे। यह बड़ा कठोर ढङ था। मुगलों के समय में मालगुजारी अदा न करने के लिए कभी कभी जमीन्दारों को कोड़े तक सहन पड़ते थे, पर उनकी रोजी न छीनी जाती थी। कार्नवालिस के इस कठोर नियम से राजगाही, टीनाजपुर और नदिया के प्राचीन राजवराने नष्ट हो गये। जमीन के मालिक हो जाने से जमीन्दारों को उसके रहन-व्यय करने का भी अधिकार मिल गया। इससे खर्च में उनका हाथ खुल गया और जमीन्दारियां कुर्क होकर नीलाम होने लगीं। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही काल में बंगाल के पुराने रईसों की श्रेणी नष्ट हो गई और उनकी जगह पर ऐसे लोग जमीन्दार बन गये, जिनका रैयत से कोई सम्बन्ध न था।

**प्रजा पर प्रभाव—**इस बन्दोबस्त से कार्नवालिस रैयत की दशा भी सुधारना चाहता था, पर वास्तव में इसका परिणाम उलटा हुआ। शताब्दियों के सम्बन्ध से पुराने जमीन्दारों को प्रजा से कुछ स्नेह था, पर नये जमीन्दारों में इसका पूरा अभाव था। ये लोग बड़े बड़े शहरों में रहकर आनन्द में पड़ गये और इनके कारिन्दे प्रजा पर मन-माने अत्याचार करने लगे। काश्तकारों को बेदखल करने का अधिकार भी जमीन्दारों को दे दिया गया। इस अधिकार का बराबर दुरुपयोग होने लगा। इसका फल यह हुआ कि कितने ही काश्तकारों की जमीनें, जो बहुत दिना से उनके पास थीं, और जिनमें एक प्रकार से उनका मौरूसी हक हो गया था, उनके हाथ से निकल गईं। लगान बाधने के समय पर पैदावार का पता कानूनगो के कागजात से लगता था। अब यह पद भी तोड़ दिया गया और पटवारी जमीन्दारों के नाँव होकर उन्हीं का पत्र करने लगे। जमीन्दारों के अत्याचार का बदला लेने के लिए काश्तकार कभी कभी लगान देना बन्द कर देते थे। वे जानते थे कि समय पर मालगुजारी न दे सकने से जमीन्दारों को अपनी जमीन्दारी से हाथ धोना पड़ेगा। इसका फल यह होता था कि देने में बराबर झगड़ा हुआ करता था। जमी

न्दार और काश्तकारों में 'पट्टा' और 'कबूलीयत' का कोई ठीक प्रबन्ध न होने में काश्तकार की रक्षा का कोई उपाय न रह गया। सन् १८१६ में इनकी रक्षा के लिए एक नया कानून बनाना पड़ा। इस्तमरारी बन्दोस्त का मिद्वान्त अवश्य ठीक है। पर कई बातों का ध्यान न रखने तथा जल्दी करने के कारण इस बन्दोबस्त में बहुत से दोष रह गये।

**व्यापार की अवनति**—कम्पनी के कर्मचारियों के अत्याचार से पीड़ित होकर जुलाहे अपना काम छोड़ रहे थे, इसका उल्लेख किया जा चुका है। इस समय कपड़े के व्यापार को एक और धक्का लगा। हिन्दुस्तानी कपड़े का व्यवहार इंग्लैंड में अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही बन्द कर दिया गया था, पर कम्पनी के द्वारा यह माल इंग्लैंड होकर यूरोप के अन्य देशों में जाता था। इंग्लैंड में तभी से सूती कपड़ा बनाने का प्रयत्न हो रहा था। इसमें देश का ही काम न चलता था, बल्कि यह कपड़ा बाहर भी भेजा जाता था। सन् १७६४ तक बाहर जानेवाले कपड़े की तादाद अधिक न थी। अन्य देशों में भारतवर्ष का ही बढ़िया माल अधिक खपता था। इधर बीस-पच्चीस वर्षों में कई एक नई कलों का आविष्कार हो गया, जिनसे सूती कपड़ा बहुत अच्छा बनने लगा। सन् १७८३ में विलायती तंजैब का नमूना बगाल भेजा गया। कम्पनी की आमदनी पूर्वीय व्यापार से होती थी, उसका हित भारत-वर्ष में कपड़ा बनाने की कला की रक्षा करने में था, पर तब भी उसका ध्यान इसकी ओर नहीं गया। इसके कई एक कारण थे। वह अंगरेजों की संस्था थी, जिनको अपने देश के हित का सदा ध्यान रहता है। पार्लामेंट का उस पर पूर्ण अधिकार था। इंग्लैंड की जनता देश के व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, उसके प्रतिवृत्त जाना कम्पनी की शक्ति के बाहर था। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानी माल पर इंग्लैंड में बराबर चुगी बढ़ती जाती थी, जिसके कारण इसको अन्य देशों में भी भेजने से कोई लाभ नहीं होता था। इन्हीं कारणों से हिन्दुस्तानी कपड़ों की उन्नति के बजाय सन् १७८८ में कम्पनी के संचालकों ने मैनेजर्स के माल को रखाने के लिए लिख भेजा और अंगरेज कारीगरों की सहायता करने के लिए बगाल, सूरत तथा भड़ौच से रुई भी मँगाना प्रारम्भ कर दिया।

फ्रांस में भी हिन्दुस्तानी माल बहुत चलता था। भारतवर्ष में फ्रांसीसियों का व्यापार चौपट ही हो गया था, इसलिए यह माल इंग्लैंड होकर जाता था। फ्रांस में राजविप्लव होने पर इंग्लैंड में उसका व्यापारिक सम्बन्ध टूट गया और वहाँ भी हिन्दुस्तानी कपड़ा जाना बन्द हो गया। नेपोलियन के साथ युद्ध छिड़ने पर इंग्लैंड में हिन्दुस्तानी कपड़े की चुगी २७ पौंड सैकड़े से बढ़ाकर ६७ पौंड कर दी गई। इस तरह कपड़े का रोजगार बन्द होने लगा और विलायती माल की खपत बढ़ने लगी। सन् १७८६ में लाभदायक न होने तथा अन्य “कई आवश्यक कारणों” से सूत का भी विलायत भेजना बन्द कर दिया गया। इंग्लैंड में सूती कपड़ा इतना बढ़िया बनने लगा कि अँगरेज महिलाओं ने रेशमी कपड़ा पहनना छोड़ दिया, जिसका फल यह हुआ कि रेशम और रेशमी कपड़े का व्यापार भी मन्दा पड़ गया।

इस समय तक भारतवर्ष में बाहर माल भेजने और वहाँ से माल लाने का अधिकार केवल कम्पनी ही को था। सन् १७६३ के नये आज्ञापत्र से पार्लामेंट ने अन्य व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत व्यापार करने की आज्ञा दे दी। कलकत्ते में बैक खुल जाने से अँगरेज व्यापारियों को बड़ी सुविधा हो गई। सन् १७८८ में कार्नवालिस ने भारतवर्ष में भी चुगी उठा दी और चाँकियों को तोड़ देने के लिए आज्ञा दे दी। सन् १७८७ में उसने जुलाहों को भी मुक्त कर दिया। दादनी देकर मुचलका लिखाने की प्रथा को बिलकुल उठा दिया और चाहे जिसके हाथ माल बेचने की आज्ञा दे दी। देश का निजी व्यापार कम्पनी की नीति के कारण पहले ही चौपट हो चुका था, इसलिए इन सुधारों से इस समय कोई विशेष लाभ न हुआ।

**मैसूर का तीसरा युद्ध—**अँगरेजों से सन्धि हो जाने के बाद से टीपू का धमड़ बहुत बढ़ गया। वह अपने को ‘सुलतान’ कहने लगा और मराठों से अकारण ही भिड़ गया। इस पर सन् १७८७ में मराठों ने निजाम से मिलकर टीपू को ऐसा दबाया कि उसे कुछ देश और ३० लाख रुपये देकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। यद्यपि टीपू और अँगरेजों में सन्धि थी, तब भी दोनों एक दूसरे से जलते थे। इधर कार्नवालिस ने एक ऐसा काम किया

को अपने पक्ष में मिलाये रखने के लिए उसने लिख भेजा कि यदि कर्नाटक बालाघाट कभी अंगरेजों के हाथ आ जायगा, तो निजाम का ध्यान रखा जायगा। सहायता के लिए एक अंगरेजी सेना भी भेजी जायगी, पर यह सेना कम्पनी के किसी मित्र के विरुद्ध काम में न लाई जाय। मित्रों की सूची में मराठा, कर्नाटक और अवध के नवाब वजीर तक का नाम लिख दिया गया, पर टीपू का कहीं भी जिक्र न किया गया।

इस पर टीपू विगड गया। सन् १७८४ में जो कानून पार्लामेंट ने पार किया था, उसके अनुसार बिना संचालकों की अनुमति के गवर्नर-जनरल को किसी देशी शक्ति के विरुद्ध सन्धि करने का अधिकार न था। इसको टालने के लिए ही निजाम को पत्र लिखने की चाल चलनी पड़ी। डफ लिखता है कि इस पत्र की चाल से तो खुले तौर पर टीपू के विरुद्ध सन्धि कर लेना ही अच्छा था। इधर टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर राज्य कम्पनी का मित्र था। उसकी रक्षा के लिए टीपू के साथ लटना पिट के इंडिया ऐक्ट के विरुद्ध न था, इसलिए कार्नवालिस को अब खुले तौर पर युद्ध की घोषणा करने का अवसर मिल गया।

कोई कानूनी बाधा न रहने पर उसने निजाम और पेशवा के साथ टीपू के विरुद्ध सन्धि कर ली। टीपू इस युद्ध के लिए तैयार न था। उसके गुप्त भाव चाहे जो कुछ रहे हों, इस समय तक वह सन् १७८५ की सन्धि के विरुद्ध न गया था। त्रावणकोर के विषय में उसका कहना था कि उस राज्य ने दो स्थानों पर अधिकार कर लिया था। ये स्थान कोचीन के थे, जो मैसूर राज्य के अधीन था। इसके उत्तर में अंगरेजों की सलाह से त्रावणकोर राज्य की ओर से कहा जाता था कि ये दोनो स्थान डच लोगों से मोल लिये गये थे। इसके पहले वे पुर्तगालियों के पास थे और उनसे कोचीन का कोई सम्बन्ध न था। टीपू इस प्रश्न को लिखा-पढी करके तय करना चाहता था, पर कार्नवालिस ने लटना निश्चित कर लिया था। समझौते का समर्थन करने के लिए मद राम के गवर्नर हालेड को कार्नवालिस की कड़ी डाट सुननी पड़ी और पद-त्याग करना पड़ा। उसके स्थान पर मेडोज गवर्नर बनाया गया, जिस



गवर्नर-जनरल के आज्ञानुसार युद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी। त्रावणकोर का झगड़ा तो केवल एक बहाना था। मराठे तथा निजाम को टीपू के विरुद्ध देखकर उसको दबाने का कार्नेवालिस यह सबसे अच्छा अवसर समझता था।

जनरल मेडोज ने डिडीगल छीन लिया। बम्बई की ओर से एक दूसरी सेना ने आकर मलाबार पर अधिकार कर लिया, परन्तु रसद की कमी और वरमात होने के कारण कोई गहरी लड़ाई न हुई। दिसम्बर सन् १७६० में स्वयं कार्नेवालिस सेनापति बनकर आया और उसने बगलोर छीन लिया। मराठों की सेना ने धारदार से टीपू की सेना को निकाल भगाया और दूसरी ओर निजाम ने एक किले पर कब्जा कर लिया। सन् १७६२ में कार्नेवालिस ने श्रीरंगपट्टन का घेरा डाल दिया, तब विवश होकर टीपू को सन्धि का प्रस्ताव करना पड़ा।

**श्रीरंगपट्टन की सन्धि**—कार्नेवालिस भी इस युद्ध को अधिक न बढ़ाना चाहता था। निजाम और मराठों पर उसका पूरा विश्वास न था, प्रायः से लड़ाई छिड़नेवाली थी, सेना में बीमारी फैली हुई थी और कम्पनी के संचालक सन्धि के लिए उत्सुक थे। बहुत दिनों तक सन्धि की गतें तय होती रहीं, अन्त में मार्च सन् १७६२ में सन्धि हो गई। इस सन्धि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा भाग और तीन करोड़ रुपये देना पड़ा। यह रकम और राज्य अंगरेज, मराठों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। मराठों का तुंगभद्रा नदी तक का प्रदेश मिल गया। कडापा प्रान्त निजाम के हाथ आ गया। अंगरेजों को मैसूर के पश्चिम में मलाबार और कुर्ग, दक्षिण में डिडीगल और पृथ्वी में सेलम जिले के कुछ भाग मिल गये। इनके मिल जाने से बम्बई तथा मदरास के अहाते बहुत बढ गये और लगभग ४० लाख रुपये सालाना की आमदनी हो गई। इन जिलों के निकल जाने से टीपू चारों ओर घेर गया और पश्चिम में उसके लिए समुद्र का मार्ग बन्द हो गया। तीन करोड़ रुपये के अतिरिक्त अफमरो को घाटने के लिए तीस लाख रुपये टीपू से 'दरबार खर्च' के नाम में और मांगा गया। वह उस समय दूट करोड़ से अधिक रुपया न दे सका, बाकी के लिए उसको अपने दो बेटे अंगरेजों के पास बन्धक रखने पड़े। इस रुपये को उसने टीक समय पर

अदा कर दिया। इस युद्ध के परिणाम के विषय में कार्नवालिस का लिखना है कि “बिना अपने मित्रों की शक्ति इतनी बढ़ाए हुए कि जिसमें किसी प्रकार का भय हो, हमने अपने शत्रु को निर्बल बना दिया”।<sup>१</sup>

**कर्नाटक और अवध—**कर्नाटक के नवाब पर कम्पनी का बहुत देना हो गया था। देहरे शामन के कुफल यहाँ भी दिखाई दे रहे थे। तलवार अंगरेजों के हाथ में थी और रुपया वसूल करना नवाब का काम था। अंगरेज अफसरों को बड़ी बड़ी दावतें और बहुमूल्य भेंटें लेने में किसी प्रकार का सकोच न था। सेना का खर्च चलाने के लिए नवाब को बड़ी बड़ी रकमें कर्ज लेनी पड़ती थीं। अंगरेज महाजन उससे मन-माना सूद खाते थे। पाल बेनफील्ड नामक एक अंगरेज ने तो राज्य की कुल आय को हड़प करने का ही विचार कर लिया था। उसका कम्पनी के संचालकों पर ऐसा प्रभाव था कि वह नवाब के कर्जों की जाँच कभी न करने देता था। कार्नवालिस के आने पर सन् १७८१ में नवाब के साथ फिर एक नई सन्धि की गई। उसकी रक्षा और शामन में सहायता करने के लिए अंगरेजी सेना बढ़ा दी गई। नवाब ने उसका कुल स्वर्ग देना स्वीकार किया। साथ ही साथ यह भी तय हुआ कि यदि नवाब समय पर रुपया न दे सके, तो मालगुजारी कम्पनी की निगरानी में वसूल की जाय करे। समय पर रुपया देना नवाब के लिए असम्भव था। मैसूर से लड़ाई छिड़ने पर सन् १७६० में कार्नवालिस ने कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में ले लिया। मालगुजारी वसूल करने के लिए अंगरेज अफसर रख दिये गये। नवाब को केवल हिसाब देखने का अधिकार रह गया। यह प्रबन्ध सन् १७८१ की सन्धि के विरुद्ध था, परन्तु कार्नवालिस का कहना था कि लड़ाई के समय में कर्नाटक का शासन विषयी नवाब और उसके अयोग्य अफसरों के हाथ में छोड़ना न उसी के लिए हितकर था और न कम्पनी ही के लिए। लड़ाई समाप्त होने पर यह तय कर दिया गया कि जब कभी युद्ध छिड़ेगा, कर्नाटक का इसी प्रकार से शामन किया जायगा।<sup>२</sup>

१ कार्नवालिस, कारस्पेंडेंस, जि० २, पृ० १५४।

२ मालकम, हिन्दी ऑफ इंडिया, जि० १, पृ० ९२-१०१।

अवध के नवाब वजीर की दशा भी कर्नाटक के नवाब की तरह थी। उस पर भी कम्पनी का बहुत देना हो गया था। उसके राज्य की रक्षा के लिए अंगरेजों की एक बड़ी सेना रहती थी। इसके अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करने में महायत्ना देने के लिए भी एक सेना रहती थी। अंगरेज अफसर नवाब से गृह बहुमूल्य भेंटें ऐंठते थे। कई एक अंगरेज, जो कम्पनी के नौकर नहीं थे, पर सचालको और मन्त्रियों के रिश्तेदार या मित्र थे, अवध में नाम मात्र के लिए नवाब की नौकरी कर लेते थे और छोड़े ही दिनों में माला-माल हो जाते थे। कभी कभी अंगरेज अफसर मालगुजारी का ठेका ले लेते थे और प्रजा को मनमाना चूमते थे। 'गोरखपुर के अत्याचारी' होने का नाम प्रसिद्ध है। कम्पनी का इस और कोई ध्यान न था और इन अंगरेजों को अवध में बाहर निकालना नवाब की शक्ति के बाहर था। नवाब की राज-नतिक निर्बलता के कारण उसकी आर्थिक दशा न सुधर पाती थी और दिन प्रतिदिन अंगरेजों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती थी। सन् १७८४ में हम्ब्रिज के वचन देने पर भी फतहगढ़ में अंगरेजी सेना नहीं हटाई गई। कार्नवालिस के आने पर नवाब ने अपने विश्वासपात्र और योग्य सचिव हैदर-अली को कलकत्ता भेजा, पर वहाँ से भी जवाब मिला कि नवाब तथा कम्पनी की रक्षा के लिए अवध में अंगरेजी सेना का रहना नितान्त आवश्यक है। हैदरअली के बहुत कुछ कहने सुनने पर कार्नवालिस ने यह स्वीकार किया कि नवाब को ५० लाख रुपया साल से अधिक न देना पड़ेगा। रेजी-डेंट का शासन में अधिक हस्तक्षेप न करने के लिए लिख दिया गया और बिना गवर्नर-जनरल की अनुमति के किसी अंगरेज को अवध में रहने का अधिकार न रहा। दूसरे साल एक व्यापारिक सन्धि की गई, जिसके अनुसार कम्पनी को अवध में कार्टिया खोलने का अधिकार भी मिल गया। इलाहाबाद की सन्धि के समय से यह प्रश्न टल रहा था, पर इस समय नवाब को विवश हो-कर अंगरेजों की बात माननी पड़ी।

**कार्नवालिस की वापसी**—सन् १७९३ में कार्नवालिस इंग्लैंड वापस चला गया। उसके जाने के पहले, इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई छिड़



हम्माईलवेग नाम का एक दूसरा सरदार, राजपूताना भागकर, वहाँ के राजाओं को सिन्धिया के विरुद्ध भड़का रहा था। सन् १७६० में डीवोयन की सेना ने उसके पाटन के युद्ध में हरा दिया। मिरघा के युद्ध में वीर राठोरो को भी हार माननी पड़ी। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के राजाओं को सिन्धिया का आधिपत्य मानकर चौथे देना स्वीकार करना पड़ा। राजपूतों के, विशेषकर उदयपुर के घराने के, मान का सिन्धिया को बराबर ध्यान रहता था। उदयपुर के महाराणा के साथ उसके मित्रता का व्यवहार था। कर्नल टाड का कहना है कि उहंड जागीरदारों के दमन करने में महाराणा को सिन्धिया के प्रसिद्ध सूबेदार अम्बाजी ने बड़ी सहायता मिली। इस तरह उत्तरी भारत में सिन्धिया का आतंक पूर्ण रूप में जम गया। उहंड जागीरदारों की उसने जागीरें छीन लीं। मालगुजारी वसूल करने के लिए उसने गोपालराव को 'सरसूया बनाया और उसके नीचे डीवोयन तथा तीन मराठा सरदारों को सूबेदार नियुक्त किया।

सिन्धिया को शाहआलम के सम्मान का बड़ा ध्यान रहता था। वह उसके 'मुत्तारलमुल्क' की हैमियत में उत्तरी भारत में शासन करता था। दिल्ली के तबू को मराठे नष्ट न करना चाहते थे। देश की परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए ऐसा करना सम्भव भी न था। मुगल सम्राटों की ओर से सारे देश में अपनी सत्ता स्थापित करना वाम्बव में शुरू ही में उनकी 'वाड-गाही नीति' थी। दीवानी लेने में अंगरेजों ने भी उन्हीं की नीति का अनुसरण किया था।

**अंगरेजों के साथ सम्बन्ध—**हेस्टिंज को सिन्धिया बहुत मानता था। उसके चले जाने पर अंगरेजों के प्रति सिन्धिया का भाव कुछ बदल गया। मालशई की सन्धि की भूल का उसको पता लग गया। उसके प्रभुत्व में अंगरेजों को भी चिन्ता हो रही थी। सन् १७८६ के एक पत्र में सिन्धिया-दरबार का अंगरेज प्रतिनिधि गेडर्सन कार्नवालिस को लिखता है कि उस पर पूरी दृग्-रेख रखनी चाहिए। सम्भव है किसी समय उसकी गति को रोकने की आवश्यकता पड़ जाय। ऐसी दशा में बिना लड़ें ही अपना काम निकाल

का पेशवा पर पूरा प्रभाव पड़ा। यह देखकर नाना फडनवीस ने भी अपनी नीति बदल दी और उत्सव में सिन्धिया का पूरा साथ दिया।



### माहादजी सिन्धिया

सिन्धिया और नाना—ये दोनों अपने समय के बड़े प्रतिभाशाली मनुष्य थे, जो पानीपत के युद्ध से जीवित बच गये थे। दोनों की शिक्षा माधवराव बल्लाल के उच्च स्वदेश-प्रेम के आदर्श में हुई थी। दोनों सारे देश में मराठा साम्राज्य का स्वप्न देखते थे। दोनों का जीवन सादा और धार्मिक था। यदि नाना फडनवीस में चतुरता थी तो सिन्धिया में

विरुद्ध" है। इस नीति को काम में लाने के लिए कार्नवालिस की सलाह से सर जान गोर गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा गया। सर जान गोर सन् १७६९ में आठ रुपया मासिक वेतन पर नौकर होकर भारतवर्ष आया था। हेम्टिंग्स के नीचे यह बहुत दिनों तक काम कर चुका था और इन्तसराती बन्दोबस्त में कार्नवालिस को इससे बड़ी सहायता मिली थी। हेम्टिंग्स पर इन दिनों अभियोग चल रहा था। उसके कई एक मामलों से सर जान गोर का भी सम्बन्ध था। ऐसी दशा में वर्क की राय में उसको यह पद देना उचित न था। कम्पनी के किसी कर्मचारी को गवर्नर-जनरल के पद पर नियुक्त करने के विरुद्ध कार्नवालिस भी था, परन्तु सर जान गोर से वह ऐसा प्रसन्न



जान गोर

था कि उसने स्वयं उसकी सिफारिश की। बहुत कहने सुनने पर सर जान गोर ने इस पद को स्वीकार किया। अक्टूबर सन् १७६३ में वह कलकत्ता पहुँचा।

**मराठे और निजाम**—इन दोनों में बराबर झगडा हुआ करता था। निजाम ने बहुत दिनों से मराठों को चौप नही दी थी। इस पुराने हिस्साब को साफ करने के लिए नाना फटनवीस जोर देने लगा। निजाम का पहला दिवान रकुनुद्दीन मराठों को किसी न किसी तरह समझाये रखता था, परन्तु यह बात नये 'मणीरलमुल्क' में न थी। निजाम ने फ्रांसीसी रेर्मा की अध्यक्षता में एक सेना तैयार कर ली थी, इसलिए वह अब मराठों से दबता न था। नये दिवान की सलाह से उसने मराठों को एक पैसा तक देने से इनकार कर दिया और उल्टे अपना बहुत सा हिस्सा निकाल दिया। मणीरलमुल्क ने मुल्क

**मराठों की विजय**—अंगरेजों से निराग होकर निजाम को मराठों से अकेले ही युद्ध करना पड़ा। सन् १७६५ में अहमदनगर जिले के खर्दा नामक स्थान पर मराठों की पूर्ण विजय हुई। नाना फडनवीस के चरणों पर अपनी तलवार रखकर निजाम को सन्धि के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। उमने पेशवा के अपमान करनेवाले मशीरुलमुल्क को मराठों के हवाले कर दिया और दालताबाद का किला, कुछ देश तथा बहुत सा रुपया नकद देने का वचन दिया। यह अन्तिम समय था जब पेशवा की पनाका के नाँव सिन्धिया, होलकर, भोगला और गायकवाड की सेनाएँ एकत्र हुई थी। वाम्बव से यह नाना फडनवीस की नीति और योग्यता की विजय थी।

निजाम की रक्षा करने के लिए जो अंगरेज सेना रहती थी, उमने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद लौटने पर निजाम ने अंगरेजी सेना को हटा दिया और वह फ्रांसीसी रेमा की सेना बढ़ाने लगा। हैदराबाद के दरबार में इस प्रकार अंगरेजों का प्रभुत्व उठते देखकर गवर्नर-जनरल को भी चिन्ता होने लगी। परन्तु निजाम में स्वतंत्र रहने का दम कहाँ था? इसी अवसर पर उसके एक लडके ने बगावत कर दी, जिससे डरकर निजाम को अंगरेजी सेना फिर से वापस बुलानी पड़ी।

**कर्नाटक और अवध**—सन् १७६५ में कर्नाटक के वृद्ध नवाब मुहम्मदअली के मरने पर उसके बेटे उमदनुलउमरा के साथ अंगरेज एक नई सन्धि करना चाहते थे, जिसके अनुसार वे कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध किले, कुछ जंगल तथा मालगुजारी वसूल करनेवाले पालीगारों पर अधिकार चाहते थे। सर जान शोर के लिखने और मदरास के गवर्नर के बहुत कुछ समझाने पर भी नये नवाब ने इन शर्तों का स्वीकार नहीं किया, जिससे परिणाम यह हुआ कि अंगरेज महाजनो का उस पर वर्जा बटने लगा। लार्ड कार्नवालिस ने अवध के नवाब वजीर आसफुद्दौला को यह वचन दिया था कि ५० लाख रुपया मालाना से अधिक न माँगा जायगा और अंगरेजी सेना फिर न बढ़ाई जायगी। परन्तु सर जान शोर की राय में अवध में अंगरेजी सेना बाफ़ी न थी, इसलिए उसने सेना बढ़ा देने का निश्चित किया और



साठनअली के साथ सब बातें पहले ही तय हो गई थीं। अब उसके साथ एक नई सन्धि की गई, जिसके अनुसार इलाहाबाद का किला अंगरेजों को मिल गया और उसके समस्त के लिए आठ लाख रुपया भी लिया गया। गद्दी पर बैठिलाने में सहायता करने के लिए कम्पनी ने १२ लाख रुपया लिया, वजीरअली को डेढ़ लाख की पेंशन दिलवाई और सालाना रकम को २६ लाख से बढ़ाकर ७६ लाख कर दिया। नवाब वजीर की निजी सेना घटाकर ३५ हजार कर दी गई। किसी बाहरी शक्ति से सन्धि करने का उसे अधिकार न रहा।

सर हेनरी लारेंस का कहना है कि इस सन्धि में अवध की प्रजा का कुछ भी ध्यान न रखा गया, सबसे अधिक रुपया देनेवाले के हाथ वह बेच दी गई। 'अवध की ससनद' सर जान शोर के लिए एक प्रकार से कम्पनी की सम्पत्ति सी हा गई थी जिसका वह चाहे जिसके हाथ बेच सकता था। नवाब वजीर-अली के साथ व्यवहार करने में सर जान शोर ने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। उसका यह हस्तक्षेप पुरानी सन्धियों के समर्थन विरुद्ध था। सर जान शोर का मत था कि अंगरेजों ने दया करके अवध का राज्य गुजाबटोला को लौटा दिया था। सन्धियों के अनुसार अवध का अंगरेजों के साथ पारंगत जो कुछ सम्बन्ध हो, अवध की जनता और बाहरवालों की दृष्टि में अवध अंगरेजों ही के अधीन था।<sup>१</sup> इस अनुचित हस्तक्षेप के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि उन दिनों अफगानिस्तान के जर्माशाह ने, जो प्रसिद्ध अहमद-शाह दुर्रानी का पोता था, भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। वह लाहौर तक पहुँच गया था। ऐसी दशा में कम्पनी के राज्य की रक्षा के लिए अवध का हट करना और उसमें अंगरेजी सेना बटाना बड़ा आवश्यक था। परन्तु यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिख और मराठों के 'उदल नाले' को तोड़-कर जर्माशाह का अवध तक पहुँचना साधारण बात न थी। पश्चिमोत्तर सीमा के पहाड़ों से आक्रमण करके विजय करने के दिन व्यतीत हो चुके थे।

वह किसी प्रकार का पर्दा न करती थी, दरबार में बैठकर स्वयं सब मामले सुनती थी।

उसका रहन-सहन  
बड़ा और स्वभाव  
धार्मिक था।  
भारतवर्ष के प्राय  
सभी बड़े बड़े  
तीर्थों में उसके घन-  
वाये हुए मन्दिर  
और धर्मशाले अत्र  
तक मौजूद हैं।  
उसके दरबार में  
गुणामयी की डाल  
न गलती थी।  
उसके साथ न्याय  
धरने और प्रजा  
को यथाशक्ति  
सुख पहुँचाने का  
चाह धरावर प्रयत्न  
करती थी।



अहिल्याबाई

उसके विषय में सर जान मालकम लिखता है कि उसने राज्य का शासन बड़ी योग्यता से किया। उसके समय में बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। राज्य में पूर्ण शान्ति रही। प्रजा से लगान बहुत कम लिया जाता था और गांवों में अधिकारों की बराबर रहा होती थी। अपने चारों ओर सबको सुख देना उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। “उसकी उदारता केवल अपने राज्य के लिए ही न थी। भूमि के पशु, आकाश के पक्षी और नदियों की मछलियाँ भी उसकी दया के पात्र थीं।” वह एक “सर्वो हिन्दू विश्वा की तरह अपना जीवन

व्यतीत करती थी। अपने राज्य में वह अवतार मानी जाती थी। निजाम और टीपू भी उसका आदर करते थे। धार्मिक जीवन में कटर होते हुए भी उसमें अमहिष्णुता का नाम न था। हिन्दू मुसलमान दोनों ही उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। “उसके चरित्र के विषय में खूब सोच-विचार करके भी यह कहना पड़ता है कि अपने परिमित क्षेत्र में सबसे पवित्र और आदर्श नामों में से वह एक थी।”<sup>१</sup>

---

<sup>१</sup> मालकम, ए मेम्बरायर ऑफ सेंट्रल इंडिया, जि० १, पृ० १५७-१५।

# परिच्छेद ७

## साम्राज्य के लिए युद्ध

### ( १ )

वेलेजली की नियुक्ति—मर जान शेर की नीति से अग्रगण्य

होकर इंग्लैंड-सरकार लार्ड कार्नवालिस को फिर से गवर्नर-जनरल बनाना चाहती थी, परन्तु लार्ड कार्नवालिस को, जिस तरह भारतीय सेना के अफसरों के साथ सम्मति किया गया था, वह पसन्द न था। दूसरे दूनों आयरलैंड की दशा बिगड़ रही थी। फ्रांस की घोर राज्य-क्रान्ति का प्रभाव वहाँ भी पड़ रहा था। इसलिए इंग्लैंड-सरकार न हमको आयरलैंड और वेलेजली को भारतवर्ष भेजना निश्चित किया। वेलेजली का जन्म आयरलैंड में हुआ था।



लार्ड वेलेजली

सन १७८७ से वह इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सदस्य

था। प्रधान सचिव पिट से उमकी बड़ी घनिष्ट मित्रता थी। भारतवर्ष की राजनीति से वह अपरिचित न था। सन् १७६३ में वह 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' में काम करता था। वहाँ भारतवर्ष सम्बन्धी सभी बातों का उसने पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। बोर्ड के सभापति डुडाज को उमकी योग्यता में बड़ा विश्वास था। अँगरेजी भाषा का वह अच्छा पंडित था। पार्लामेंट में उसके भाषण बड़े चाव से सुने जाते थे। वेलेजली की योग्यता देखकर पार्लामेंट के सभापति का कहना था कि वह यहाँ पिसा जाता है, उसके लिए विन्यृत क्षेत्र की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारतवर्ष में बढ़कर विन्यृत क्षेत्र कौन हो सकता था ?

इन दिनों इंग्लैंड की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी नाजुक हो रही थी। अमरीका के उपनिवेश उसके हाथ से जाते रहे थे। फ्रांस की भीषण राज्य-क्रान्ति ने सारे यूरोप में हलचल मचा दी थी। आयरलैंड में अगान्ति फैल रही थी। अँगरेजी शक्ति के इस ह्रास को कहीं न कहीं पूरा करना था। कहा जाता है कि इंग्लैंड से चलने के पहले पिट ने वेलेजली को अच्छी तरह समझा दिया था कि पश्चिम में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति पूर्व में ही हो सकती है। तेरह वर्ष पहले इंडिया ऐक्ट में पिट ने ही यह सिद्धान्त निश्चित किया था कि भारतवर्ष में राज्यवृद्धि के लिए युद्ध करना इस (अँगरेज) "राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा और नीति के विरुद्ध है"। परन्तु वही पिट अब इस सिद्धान्त का अनुयायी न रहा था। फ्रांस से उठी हुई "स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता" की आवाज से अँगरेज राजनीतिज्ञों के मत में भारी परिवर्तन हो रहा था। राज्य-क्रान्ति की विकराल मूर्ति से स्वतंत्रता का बर्फ सरीखा उपासक भी भयभीत हो गया था।

**भारतवर्ष की स्थिति**—कहा जाता है कि सरजान शोर की नीति से भारतवर्ष में भी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। निजाम का अँगरेजों पर से विश्वास उठ गया था। वह फ्रांसीसी अफसरों की अध्यक्षता में अपनी सेना बटा रहा था। मराठों से पराजित होकर और अँगरेजों से धोखा खाकर वह टीपू से नाता जोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। खर्दा की विजय से मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। आगरा और दिल्ली में सिन्धिया का दबदबा था।

वरार से उड़ीसा तक भोगमला का राज्य फैला हुआ था। गायकवाड गुजरात को दबाये बैठा था। मालवा में होलकर का आतंक जमा हुआ था। पूना-दरबार में नाना फडनवीस का बोलचाला था। इन सब मराठा राजाओं के यहाँ सेना के बहुत से अफग़र फ़ार्सीसी थे। इनकी अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी गिपाहियों को पाश्चात्य रण-पद्धति की शिक्षा दी जा रही थी। पिछली हार में टीपू जल-भुन रहा था। उसके राज्य में फ़ार्सीगी अफग़रों की संख्या मधुमे अधिक थी। उसके दूत फ़ार्स, काबुल और कुस्तुननुनिर्या ढोड रहे थे। उत्तरी भारत में जर्माशाह के महंगा टूट पड़ने का भय हो रहा था। फ़ार्स का सेनापति वीरवर नेपोलियन मित्र की तरफ बढ़ रहा था। टीपू के साथ उसके पत्र-व्यवहार हो रहा था। भिन्न भिन्न राज्यों के फ़ार्सीगी अफग़र बड़ी उत्सुकता से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे।



नेपोलियन

भारतवर्ष में फ़ार्सीमियों के इस नये प्रभुत्व में इंग्लैंड-सरकार को बड़ी चिन्ता हो रही थी। इसको नष्ट करने के लिए वेलेजली पूर्ण रूप से उपयुक्त था। वह फ़ार्सीमियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। इनकी निन्दा में उसने कई एक कवितायें रची थीं।

**वेलेजली का आगमन**—इस तरह भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य की वृद्धि और फ़ार्सीमियों के नये प्रभुत्व का नाश ये दो मुख्य उद्देश्य पहले ही में निश्चित हो गये थे। इनकी प्राप्ति के लिए केवल उपाय सोचना बाकी था। नवम्बर सन् १७६७ में वेलेजली इंग्लैंड से रवाना होकर फरवरी सन् १७६८ में गन्तरीप 'गुडहोप' पहुँचा। यहाँ मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर तथा कुछ अंग-

रेज अफसरों से, जो टीपू के कैंदी रह चुके थे, उसकी भेंट हुई, जिनमें उसको मैसूर का बहुत कुछ हाल मालूम हो गया। कर्क पैट्रिक पहले मिन्धिया और बाद को निजाम के दरबार में रेजीडेंट रह चुका था। वह इन दोनों दरबारों में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को अच्छी तरह जानता था। उसमें भी वेलेजली को बहुत सहायता मिली और उसकी प्रसिद्ध 'सहायक प्रथा' के मुख्य अंग यहीं तय हो गये। मई सन् १७६८ में वह कलकत्ता पहुँचा। भारतवर्ष के मुख्य राजाओं में सबसे निर्मल निजाम ही था, इसलिए सबसे पहले वेलेजली ने उसी को सहायक प्रथा का शिकार बनाना निश्चित किया।

**निजाम के साथ व्यवहार**—खुदा के युद्ध के समय में अंगरेजों पर से निजाम का विश्वास उठ गया था, इसका उल्लेख किया जा चुका है। अपने बेटे के विद्रोह करने पर उसने अंगरेजों सेना को फिर से बुला लिया था, यह ठीक है, पर उसका ध्यान फ्रांसीसी अफसर रेर्मा की सेना को बढ़ाने की ओर ही अधिक था। रेर्मा की पलटन में १४ हजार गिवाही और ३० तोपें थीं। इसका खर्चा चलाने के लिए उसने कर्नाटक की सीमा के कुछ जिले दे रखे थे। लार्ड वेलेजली की दृष्टि में इस पलटन से कम्पनी को बड़ा भय था। कहा जाता है कि टीपू की ओर से फ्रांसीसी एक सेना एकत्र कर रहे थे। निजाम के फ्रांसीसी अफसर भी उनका साथ देना चाहते थे। ऐसी दशा में टीपू के साथ लड़ाई छिड़ने पर निजाम से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं की जा सकती थी। शान्ति के समय में भी फ्रांसीसी अफसर निजाम से फ्रांस की शक्ति तथा सफलता की प्रशंसा किया करते थे और "अंगरेजों के आचरण, शक्ति तथा नियत की हर तरह से बुराई करते थे।"

इसलिए उसने निजाम को समझा बुझाकर इस पलटन का तोड़ना निश्चित किया। यह काम हैदराबाद के नये रेजीडेंट कर्नल कर्क पैट्रिक ( मेजर कर्क पैट्रिक के भाई ) और जान मालकूम को सौंपा गया। दूसरी ओर मदरास के गवर्नर हैरिस को सेना तैयार रखने की आज्ञा दे दी गई।

निजाम जानता था कि रेर्मा की पलटन तोड़ने का परिणाम यह होगा कि उसको सदा अंगरेजों के अधीन रहना पड़ेगा, परन्तु वह विवश था। उसको

मराठों का भय था। उनमें रक्षा करने का अब उम्मेद विश्वास दिलाया जा रहा था। चतुर कर्क पैटिक ने उम्मेद डीवान को अपने पक्ष में मिला लिया था। यह वही डीवान था जिम्मे निजाम को मराठों से भिड़ा दिया था। अन्त में लाचार होकर सितम्बर सन् १७६८ में निजाम को हैदराबाद की नई सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस सन्धि के अनुसार यह निश्चित हुआ कि अंगरेज अफसरों की अध्यक्षता में ६ हजार मिशहियों की एक सेना निजाम की रक्षा के लिए रहा करेगी। इसका खर्चा २४ लाख रुपया सालाना निजाम को देना पड़ेगा। इस सेना के पहुँचने पर निजाम फ़ार्मीसी अफसरों को निकाल देगा और उनकी पलटनों को इस तरह छिन्न-भिन्न कर देगा कि “उनके अस्तित्व का कोई निशान बाकी न रह जाय।” बिना कम्पनी की अनुमति के किसी फ़ार्मीसी या यूरोप के अन्य निवासी को निजाम न तो नौकर रख सकेगा और न अपने राज्य में बसने की इच्छा आजा दे सकेगा।

फ़ार्मीसी पलटन तोड़ने की आज्ञा देने में निजाम हिचकिचा रहा था, पर अन्त में उम्मेद यह आज्ञा भी देनी पड़ी। अंगरेजी सेना ने पलटन की टुकड़ों को घेर लिया। रेमा मर चुका था। फ़ार्मीसी अफसर आपस ही में लड़-मागट रहे थे। उन्होंने बिना लड़े-भिड़े अपने को अंगरेजों के हाथों पर दिया। मिशहियों ने पहले तो विरोध किया, परन्तु मालकम के समझाने पर उन्होंने भी हथियार डाल दिये। बेल्लेजली की नीति की यह पहली विजय हुई। बात की बात में उसने १४ हजार सैनिकों की शक्ति को नष्ट कर डाला और निजाम को सदा के लिए अंगरेजों के अधीन बना लिया। ईंग्लैंड-सरकार और कम्पनी के संचालकों ने इसके लिए उसकी बड़ी प्रशंसा की।

**टीपू पर सन्देश—**बलवत्ता पहुँचने पर, जून सन् १७६८ में, मागिस (मिच के टापू) के फ़ार्मीसी गवर्नर का एक घोषणा-पत्र बेल्लेजली के हाथ में पड़ा था। इसमें टीपू के दूतों के आतंक उल्लेख करते हुए, अंगरेजों के विरुद्ध उसकी सेना में भरती होने का अनुरोध किया गया था। बेल्लेजली की दृष्टि में अंगरेजों के प्रति टीपू की शत्रुता का यह स्पष्ट प्रमाण था। इसका फलना था कि ‘फ़ार्म के टीपू’ में दूतों को भेजने का “भारतवर्ष में अंगरेज जाति



को बाहर निकालने की प्रबल इच्छा' के अनिरीक्षित और कोई उद्देश्य न था। इस पर इंग्लैंड से 'गुप्त कमेटी' ने लिख भेजा कि यदि वास्तव में यह बात ठीक है, तो टीपू की ओर से लड़ाई छिड़ने की बिना प्रतीक्षा किये हुए ही उस पर आक्रमण कर देना उचित है। पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि बिना "नितान्त आवश्यकता" के युद्ध न छेड़ा जाय। यह पत्र उसको अक्तूबर में मिला, परन्तु वेलेजली इस समय तक लड़ाई के लिए तैयार न था, इसलिए वह चुप रहा।

फ्रांसीसी गवर्नर के घोषणा-पत्र मिलने पर ही वेलेजली ने मदरास-मरकार को सेना एकत्र करने के लिए लिख दिया था। वह मराठों में भी बराबर पत्र-व्यवहार कर रहा था और निजाम को नई सन्धि में जकड़ने के प्रयत्न में लगा था। जब उसको यह ज्ञात हो गया कि मराठे अपने आपस के झगड़ों के कारण उसके विरुद्ध टीपू का साथ न देंगे, जब निजाम के साथ नई सन्धि हो गई, बम्बई तथा मदरास की सेनाएँ पूर्ण रूप से तैयार हो गईं और काफी रुपये का कर्ज द्वारा प्रबन्ध हो गया, तब टीपू से बेधड़क बातचीत करने में उसके लिए कोई रुकावट न रह गई। युद्ध की धमकी देते हुए उसने निजाम के डंग की सन्धि करने के लिए टीपू को लिख भेजा।

सेना का स्वयं निरीक्षण करने के लिए वह कलकत्ता से मदरास की ओर चल पड़ा। जनवरी सन् १७६६ में मदरास पहुँचने पर उसको टीपू का उत्तर मिला। इसमें उसने सेना की तैयारी और लड़ाई की धमकी पर आश्चर्य प्रकट करते हुए लिखा कि मैंने अपना कोई दूत मोरिशस नहीं भेजा था। मैसूर के कुछ व्यापारी वहाँ गये थे। उसी समय पर वहाँ के गवर्नर ने अँगरेजों से झगड़ा कराने के लिए उस घोषणा-पत्र को निकाल दिया, जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँ से ४० फ्रांसीसी आये थे, जिनमें से कुछ मेरे यहाँ नौकर हो गये और बाकी चले गये। फ्रांसीसियों पर मुझे स्वयं विश्वास नहीं है, वे "बुराई और दगावाजी से भरे हुए हैं"।<sup>१</sup> अपनी मित्रता का विश्वास दिलाते हुए, अन्त में उसने लिखा कि नई सन्धि की कोई आवश्यकता नहीं

<sup>१</sup> वेलेजली, डेम्पचेज, स० माटिन, जि० १, पृ० ३८१-८३।

जान पड़ती। इस उत्तर से वेल्लेजली को सन्तोष नहीं हुआ और ता० ३ फरवरी को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी गई।

**मैसूर का अन्तिम युद्ध—**सन् १७६२ की सन्धि के विस्मृति टीपू ने कोई काम नहीं किया था। रुपये की बड़ी रकम को उसने समय से चुका दिया था। फ़ारसीमियों से उसका सम्बन्ध अवश्य था, पर इसमें अंगरेजों की सलाह लेने की उसके लिए आवश्यकता न थी। वह स्वतंत्र शासक था और चाहे जिसके साथ सम्बन्ध रख सकता था। वेल्लेजली का अनुमान था कि फ़ारसीमियों से साथ मिलकर टीपू अंगरेजों की शक्ति को नष्ट करना चाहता था। इसके समर्थन में श्रीरंगपट्टन के किने से मिले हुए नेपोलियन के कुछ पत्रों पर वह जोर देता है। परन्तु जिस तरह अंगरेजों को टीपू का भय था, उसी तरह टीपू को अंगरेजों का भय हो सकता था। बग़ाल, अवध और कर्नाटक का इतिहास उसमें छिपा नहीं था। निजाम अंगरेजों के समक्ष अधीन था। मराठों की नीति पर उसको विश्वास न था। ऐसी दशा में यदि वह फ़ारसीमियों से सम्बन्ध जोड़ता था, तो इसमें उसका कौन सा दोष था? फ़ारसी के साथ सन्धि हो जाने पर उसकी शर्तों के विरुद्ध जब कोई घटना होती, तभी प्रायः युद्ध किया जाता है। केवल भय के अनुमान पर युद्ध नहीं किया जाता है। यदि ऐसा होने लगे तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति कभी स्थापित ही नहीं रह सकती है।

यदि वेल्लेजली और उसके समर्थकों की यह धारणा भी ली जाय कि टीपू फ़ारसीमियों के साथ मिलकर अंगरेजों को निबालना चाहता था, तब भी यह प्रश्न होता है कि क्या ऐसा होना सम्भव था? टीपू के पास जो दैतल से अधिक फ़ारसीमी अफ़सर न थे। फ़ारसीसी उसकी अधिक सहायता कर सकेंगे, इसमें स्वयं वेल्लेजली को सन्देह था। अक्टूबर सन् १८६८ में पत्र में वह लिखता है कि मुझे विश्वास है कि टीपू को जितनी फ़ारसीमी सहायता मिल रही है, उससे जब तक अधिक न मिलेगी, वह आक्रमण करने का साहस न करेगा। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि इंग्लैंड की सरकार और हमारा जहाजी दैतल फ़ारसीमियों को इस ओर न जाने देंगे।

का भरपूर प्रयत्न करेगा।<sup>१</sup> फिर इस समय फ्रांसीसी सहायता की तो कोई सम्भावना ही न थी। नेपोलियन की जहाजी सेना नाइल के युद्ध में हार चुकी थी और उसके वेड़े को नेल्सन नष्ट कर चुका था। नेपोलियन का ध्यान इन दिनों यूरोप की तरफ था और एंगियार्ड ऋगडो में पड़ने के लिए उसके पास समय न था।

रेमां की पल्टन टूटने से निजाम पगु हो ही चुका था, मराठों को आपस के ऋगडो से ही छुट्टी न थी, अकेले टीपू में अंगरेजों का सामना करने की सामर्थ्य न थी। कर्नल बीटसन का अनुमान था कि “पिछली लड़ाई के समय से टीपू की सेना की संख्या कम हो गई है और व्यवस्था भी बिगड़ गई है। अब उस पर सेना को विश्वास नहीं है। उसकी आर्थिक दशा में भी बड़ा गड़बड़ है और मंत्रियों में दलबन्दी हो गई है। फ्रांसीसियों से सहायता मिलने की आशा न होने से, जर्माशाह के वापस चले जाने से, हैदराबाद तथा पूना के दरबारों में उसकी चालों की असफलता से और हमारे सेना-सम्बन्धी विस्तृत प्रबन्ध, तेजी तथा असामान्य जोर से, उसकी हिम्मत हार गई है।”<sup>२</sup> फिर भला ऐसे शत्रु से कौन सा भय था? यह अनुमान ठीक न हो तब भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि इस समय टीपू के साथ युद्ध “नितान्त आवश्यक” न था। वास्तव में बात यह थी कि अंगरेज हर तरह से प्रबल थे और टीपू को दबाने का यह “अच्छा अवसर” था। अपने “गुप्त भावों” को प्रकट करते हुए, ता० १३ दिसम्बर सन् १७९८ के पत्र में वेलेजली ने इसे स्वयं स्वीकार किया है।<sup>३</sup>

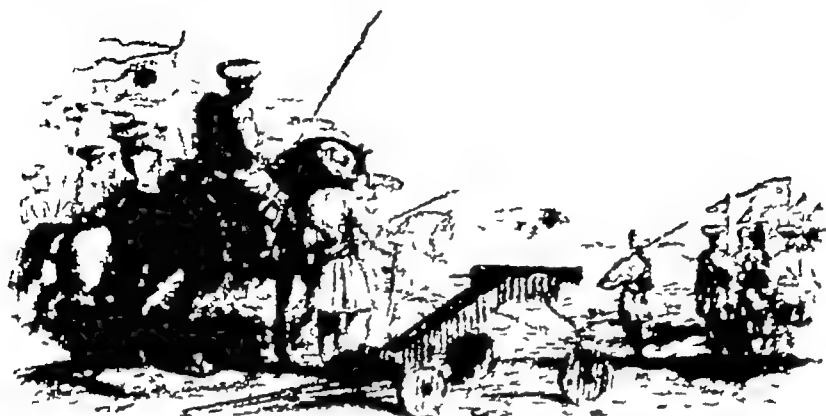
कहा जाता है कि वह वेलेजली की शर्तों पर सन्धि के लिए राजी न था, इसलिए युद्ध के सिवा और कोई चारा न था। ये वे ही शर्तें थीं, जिन पर निजाम के साथ सन्धि की गई थी। इनके अतिरिक्त हरजाने की एक बड़ी रकम और कुछ भूमि के बदले में कनाडा प्रान्त भी माँगा जाता था, जिसमें समुद्र

१ वेलेजली, डेमपैचेज, जि० १, पृ० २७५।

२ बीटसन, वार विद टीपू सुलतान, सन् १८००, पृ० ५७।

३ रेनियर के नाम पत्र, डेमपैचेज, जि० १, पृ० ३६८-६९।

ने टीपू का कोई सम्बन्ध न रह जाय । इन शर्तों को स्वीकार करके स्वाभि-  
मानी टीपू जान-बूझकर अपने आप पैरों में बेडियां न डालना चाहता था ।



### टीपू का तोपगाना

इस तरह के समर्थन से तो यह स्पष्ट कह देना कहीं अच्छा था कि टीपू ब्रिटेन-  
जली की आँखों में खटकता था । उसकी शक्ति को नष्ट करके कन्नड़ी के राज्य  
को हट और विस्तृत बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था । यह बंगल अनुमान  
ही नहीं है, बलकत्ता पहुँचते ही जितनी शीघ्रता से युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ  
कर दी गई थीं, वे ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । टीपू को अपनी बात सम-  
मान के लिए भी पूरा समय नहीं दिया गया और पहले से ही छिपे छिपे युद्ध  
की तैयारियाँ की जाने लगी । जिन अफसरों को कैद करके टीपू “बन्दर की  
तरह” नचाया करता था, उनकी सलाह से टीपू का नाम भारतवर्ष पहुँचने ही,  
बलेजली ने निश्चित कर लिया था । श्रीरंगपट्टन के पतन पर बलेजली  
या यथार्थ देते हुए, ता० १७ मई सन् १७६६ के पत्र में, सर ओलार्ड क्लार्क  
लिखता है कि इस तारीख के ठीक १२ महीने पूर्व ताम्रनगर लेने समय, टीपू  
को नीचा दिखलानेवाली आपकी बात मुझे स्मरण है ।’ इन सब बातों

को ध्यान में रखने हुए, वेलेजली मद्रास सिद्ध-हम्म लेखक के योग्यतापूर्ण और जोरदार समर्थन<sup>१</sup> में कितना तत्त्व है, इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

**टीपू का अन्त**—लड़ाई दो ही महीने में समाप्त हो गई। अंगरेजों की पूरी तैयारी थी। टीपू की प्रजा, उसके अफसर तथा मैसूर के हिन्दू राज-घराने को भडकाने के लिए, गवर्नर-जनरल के भाई आर्थर वेलेजली की अध्यक्षता में एक कमीशन पहले से ही काम कर रहा था।<sup>२</sup> टीपू अकेला था, वस्त्रों से बढ़ती हुई स्टुअर्ट की सेना को वह रोक न सका। मद्रास की सेना ने उसके साथ मिलकर टीपू को मलावली नामक स्थान पर हराया। वहाँ से हटकर टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टन में चला आया। अंगरेजी सेना ने इसका घेरा डाल दिया। टीपू ने एक बार फिर सन्धि का प्रयत्न किया, परन्तु अब वेलेजली पिछली शर्तों के अतिरिक्त आधा राज्य, दो करोड़ नकद और मुख्य अफसर तथा टीपू के चारों लड़कों को जमानत में माँगता था।<sup>३</sup> इस सन्धि के अपमान से टीपू ने युद्ध में प्राण देना ही उचित समझा। ता० ४ मई के युद्ध में अपने किले के फाटक पर बड़ी वीरता से लड़ते हुए वह मारा गया। इस तरह हैदर के राज्य का अन्त हो गया और अंगरेजों की पूर्ण विजय हुई।

युद्ध के समय में प्रजा की रक्षा करने के लिए गवर्नर-जनरल ने घोषणा निकाली थी, परन्तु उसका कुछ भी ध्यान न रखकर सेना ने नगर को सूब लूटा। आर्थर वेलेजली ने सिपाहियों की कोडो से खबर लेकर जैसे तैसे शान्ति स्थापित की। किले में अंगरेजों को बहुत सी युद्ध-सामग्री के अतिरिक्त एक करोड़ पैसों से अधिक का सामान मिला। श्रीरंगपट्टन का विशाल नगर आजकल उजाड़ है।

१ 'सीक्रेट डिपार्टमेंट मिनिट' ता० १० अगस्त सन् १७९८, टेसपैचेज, जि० पृ० १५९-२०८।

२ वेलेजली, टेसपैचेज, जि० १, पृ० ४४२-४८।

३ माल्कम, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जि० १, पृ० २२८।

टीपू का चरित्र—अपने पिता के प्रतिफल वह फारसी का अच्छा विद्वान् था। उसको उर्दू और कनाडी का भी ज्ञान था। हस्तलिखित



### टीपू का महल

पुस्तकों का उसके पास एक अच्छा संग्रह था। उसमें बला, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, साहित्य सभी विषयों के ग्रन्थ थे। यह पुस्तकालय कलकत्ता भेजा गया। वह अपने को सब विषयों का ज्ञाता मानता था। नये नये नाम रखने का उसको घटा शौक था। वही स्थानों के नाम उसने बदल दिए थे। माल और महीना के भी उसने नये नाम रखे थे। लिखने में उसका हाथ चूब चलता था। हर एक बागज पर वह अपने हाथ से बटे बटे हुक्म लिखता था।

यह योजना कागज पर ही रह गई। हर एक काम को वह अपनी आंख से देखता था और सबेरे से शाम तक बराबर काम करता था। उस समय के अन्य मुसलमान शासकों की तरह वह अपना समय आरामतलवी में व्यतीत न करता था। उसके दफ्तर में सब कागजात ठीक ढंग से रखे जाते थे। हैदरअली की तरह उसका रहन सहन तो सादा था, पर उसमें घमंड की मात्रा बहुत बढ़ी हुई थी। वह अपने को 'सुलतान' कहना या और कुछ दिनों तक उसने एक नया सिक्का भी चलाया था।

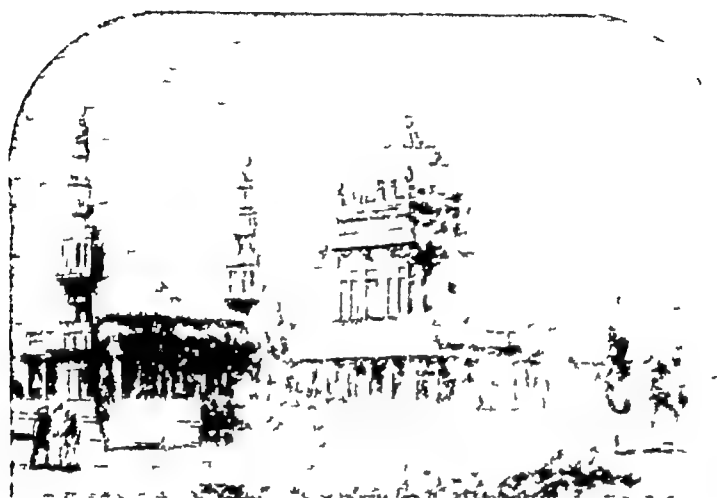
हिन्दू राजाओं के समय से जैसा कुछ शासन चला आ रहा था, उसमें उसने अधिक हस्तक्षेप नहीं किया था। समय पड़ने पर वह रुपया लेने में सख्ती जरूर करता था, पर साधारणतः प्रजा सुखी थी और राज्य में खेती का अच्छा प्रबन्ध था। शराब का बनाना और बेचना उसने अपने राज्य में बन्द कर दिया था। मलाबार में ब्रह्मपति-विवाह की प्रथा को रोकने का भी उसने प्रयत्न किया था। मेजर डिरोम का कहना है कि उसका शासन कड़ा और मनमाना अवश्य था, पर वह एक योग्य शासक की तरह प्रजा का पालन भी करता था। जिनको वह अपना शत्रु समझता था, उन्हीं के साथ उसका व्यवहार कठोर होता था।<sup>१</sup> मूर ने भी माना है कि उसके राज्य की दशा देखते हुए यह नहीं जान पड़ता था कि प्रजा पर अत्याचार हुआ है।<sup>२</sup>

इस्लाम धर्म का वह पक्का अनुयायी था। अपने राज्य को वह 'खुदा-वाद' (ईश्वर-दत्त) कहा करता था। कट्टर मुसलमान होते हुए भी उसका विश्वासपात्र दीवान पुर्णिया एक हिन्दू था। अपने पिता की तरह वह भी मन्दिरों को दान देता था। विपत्ति के समय पर पड़ितों से प्रार्थना करवाने में भी उसको विश्वास था। ईसाइयों के साथ उसका व्यवहार कभी कभी अवश्य कठोर होता था, परन्तु इसके कारण धार्मिक की अपेक्षा अधिकतर

१ मेजर डिरोम, कैम्पेन विद टीपू सुलतान, सन् १७९३, पृ० २५०।

२ मूर, नैरेटिव, पृ० २०१।

राजनैतिक थे। अंगरेज इतिहासकारों ने उसकी निर्दयता और कठोरता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखा है। मुसलमानों की दृष्टि में वह 'गर्हाद' था। हैदराबली के सुन्दर मकबरे में वह भी दफन किया गया। उसकी कब्र पर मरने की तारीख



हैदर और टीपू का मकबरा

घतलाने हुए ये शब्द लिखे हुए हैं—“नूर इस्लाम व दीन अज दुनिया रफ्त” (दुनिया से इस्लाम और दीन का नूर उठ गया)।

**राज्य का बंटवारा**—वैलेजली की राय में युद्ध के दिनों के अनुसार टीपू का राज्य विजेताओं का था और जिस तरह चाहें उसके दख्खाना का इनको अधिकार था। निजाम और अंगरेज उसको दगदग दगदग बांट सकते थे, पर वैलेजली का कहना था कि ऐसा करने से निजाम की शक्ति बहुत घट जाती। सन् १७६२ के सम्झौता के अनुसार मराठों को निहाटे भाग देना भी उसकी राय में उचित न था, क्योंकि मराठों ने युद्ध में कोई सहायता नहीं की थी। तब भी वे यदि नई सन्धि करने के लिए तैयार हो जा तो इनको कुछ जिले दे देने में कोई हानि न थी। इन सब बातों को मे-स-



विचार कर वेलेजली ने मैसूर के एक छोटे राज्य को बनाये रखना निश्चित किया। बाकी राज्य के बटवारे में कनाडा, कोयमटूर, दारापुरम, वयनाड, श्रीरंगपट्टन और मलाबार तट के कुछ जिले कम्पनी को मिले। इस तरह अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कुल समुद्र-तट अंगरेजों के अधिकार में आ गया। कम्पनी से कुछ कम हिस्सा निजाम को मिला। इसमें मैसूर राज्य के उत्तर-पूर्व के जिले थे। निजाम से आधा हिस्सा महायुद्ध सम्बन्ध स्वीकार करने पर मराठों को देना निश्चित हुआ, परन्तु इन गये बीते जिलों के बदले में मराठों ने अपनी स्वाधीनता बेचने में इनकार कर दिया। इस पर ये जिले भी निजाम और अंगरेजों ने आपस में बांट लिये। सैनिक दृष्टि से प्रसिद्ध गढ़ और स्थान अंगरेजों के ही हाथ में रहे, बटवारे में वेलेजली ने इसका बड़ा ध्यान रखा।

**मैसूर का राज्य**—बचे हुए आधुनिक मैसूर राज्य के सम्बन्ध में टीपू के बेटों का कुछ भी ध्यान न रखा गया। वेलेजली की राय में अंगरेजों के साथ उनकी मित्रता असम्भव थी। उनको टीपू से शिक्षा मिली थी, जो अंगरेजों का घोर शत्रु था। वे टीपू की मृत्यु और पराजय के अपमान को कभी भूल न सकते थे। उनको राज्य देने से “मैसूर की शक्ति कमजोर हो जाती, पर नष्ट न होती”, वे सदा स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया करते। इसलिए उसने टीपू के बेटों को पेंशन देकर विल्लौर भेज दिया और मैसूर की गद्दी पर हिन्दू राज-घराने के एक पाँच वर्ष के बालक को बिठला दिया। इस सम्बन्ध में वह कम्पनी के सचालको को लिखता है कि इससे उनकी “उदारता” का परिचय मिलेगा और मैसूर का घराना सदा उनका ऋणी तथा कृतज्ञ रहेगा। मैसूर के हिन्दू राजाओं को हैदर और टीपू के क्रूर व्यवहार और उनके अन्त का बराबर ध्यान रहेगा। “वे न कभी अपने शत्रुओं का साथ देंगे और न कभी अंगरेजों के विरुद्ध सिर उठावेंगे।”<sup>१</sup> अंगरेजों की इस “उदारता” के विषय में इतिहासकार ग्रिविल का कहना है कि मैसूर के इस हिन्दू राज्यनिर्माण द्वारा वेलेजली,

मराठों और निजाम को अधिक भूमि मिलने से, वंचित रखना चाहता था। यदि वह राज्य स्थापित न होता तो कम से कम निजाम को 'आधा हिस्सा अवश्य ही देना पड़ता।' हम प्रबन्ध से निजाम की शक्ति भी न बढ़ने पाई और मसूर का राज्य अंगरेजों के संघर्षा अधीन हो गया।

नहं सन्धि के अनुसार मैसूर राज्य को सहायक प्रथा की सब शर्तें माननी पड़ीं। वेलेजली दोहरे शासन के दोषों से अनभिज्ञ न था इसलिए उसने मैसूर का शासन पुराने योग्य दीवान

पुर्गिया के हाथ ही में छोड़ दिया।

नाथ ही साथ यह तय कर लिया कि

शासन की देख-भाल और आवश्यकता

पटने पर हमको अपने हाथ में ले लेने

का अधिकार अंगरेजों को रहेगा।

बन्दोबस्त के लिए एक बर्मीशन नियुक्त

किया गया जिसमें गवर्नर-जनरल के

दाना भाई आर्थर और हेनरी थे। इस

बर्मीशन के टूटने पर मैसूर दरबार में

अंगरेज रेजीडेंट रख दिया गया और

सहायक सेना का आर्थर वेलेजली सेना-

पति बना दिया गया। सेना के खर्चा

व लिए कुछ भूमि अलग कर दी गई।

इस तरह सन्धि के नाम से मैसूर की स्वतन्त्रता का अपहरण किया गया।

पुर्गिया ने प्रजा की दशा सुधारने का अच्छा प्रयत्न किया। उसने २८ बट

तालाबों की मरम्मत करवाई और लगान कम करके तथा कहीं कहीं दानों के

बराब गरीब किसानों की सहायता की।

**हैदराबाद की सहायक सन्धि**—मैसूर-युद्ध के पहले निजाम के

साथ जो सन्धि की गई थी, उससे वेलेजली संतुष्ट न था। उसने दूसरी



पुर्गिया

सहायक प्रथा का पूर्ण रूप से अनुसरण न किया गया था। इसलिए अक्टूबर सन् १८०० में एक नई सन्धि की गई। इस सन्धि के अनुसार मैसूर के बटवारे से निजाम को जो कुछ भूमि मिली थी, वह सब सहायक सेना का खर्चा चलाने के लिए ले ली गई। अन्य राज्यों के साथ बिना कम्पनी से पूछे हुए सम्बन्ध जोड़ने का अधिकार निजाम को न रहा और उनमें से किसी के साथ झगडा होने पर कम्पनी को पच बनाना निजाम को स्वीकार करना पडा।

**कर्नाटक का अन्त**—कर्नवालिस के बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी नवाब उमदतुलउमरा कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में देने के लिए राजी नहीं हुआ था, इसका उल्लेख किया जा चुका है। टीपू से लडाई छिड़ने पर वेलेजली ने इसके लिए फिर से प्रयत्न किया। उसने बहुत समझाया कि कर्ज लेकर बराबर किस्त अदा करने में उसका राज्य नष्ट हो रहा है। कम्पनी के हाथ में शासन दे देने से वह सब झगडा से बच जायगा। परन्तु नवाब वेलेजली के पजे में न आया, वह अपनी ही बात पर डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर कहा जाता है कि टीपू के कागजात में उसके और उसके बाप मुहम्मद-अली के कई एक पत्र मिले, जिनसे पता चला कि वे दोनों अंगरेजों के विरुद्ध टीपू के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहते थे। युद्ध में भी नवाब से किसी प्रकार की सहायता न मिली थी। इन बातों की जाच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। उसकी रिपोर्ट मिलने पर वेलेजली की राय में अंगरेजों के प्रति नवाब की शत्रुता सिद्ध हो गई और उसने “सम्भव हो तो सन्धि द्वारा नहीं तो घोषणा द्वारा” कर्नाटक का शासन ले लेना निश्चित कर लिया। इस कार्य के लिए वह स्वयं मदरास जाना चाहता था, परन्तु अवध के झगडा में फँसे होने के कारण यह काम मदरास के गवर्नर लार्ड क्लाइव को सौंपा गया।

इन दिनों नवाब उमदतुलउमरा बहुत बीमार था। उसकी हालत खराब होने पर महल में गोरो का पहरा कर दिया गया। मृत्युशय्या पर पड़े हुए नवाब ने इस अपमान का विरोध किया, परन्तु उसको समझा दिया गया कि गड

बट होने का भय था, इसलिए ऐसा किया गया। नवाब के मरते ही, कर्नाटक के शासन का क्या प्रबन्ध होगा, इस पर परामर्श होने लगा। उसके १८ वर्ष के बेटे अलीहुसैन को नई मन्त्रि स्वीकार करने के लिए “एकान्त में” लाई बलाहव ने कई बार बहुत कुछ फुसलाया, पर वह राजी न हुआ। इस पर उसके मिपाही गिरफ्तार कर लिये गये और उसका चचेरा भाई अजी-मुद्दौला मगनद पर बिठला दिया गया। नई मन्त्रि द्वारा कर्नाटक का कुल शासन कम्पनी के हाथ में आ गया और अजीमुद्दौला केवल नाम के लिए नवाब रह गया।

कर्नाटक का अंगरेजों से बहुत पुराना सम्बन्ध था। पहले पहले मुहम्मद-अली ही का साथ देकर अंगरेजों ने फ्रांसीसियों से अपनी रक्षा की थी। हैदर और टीपू नवाब के घोर शत्रु थे। अंगरेजों के विरुद्ध उनकी सहायता करना अधिक सम्भव नहीं था। यदि ऐसा हो भी, तो बेचारे अलीहुसैन का क्या दोष था ? दोषी था उसका चाप समदतुलउमरा, जिस पर कोई अभियोग नहीं चलाया गया था। गवर्नर-जनरल की राय में वाक्यादा अभियोग चलाये भी कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण मिलने पर इस तरह के व्यवहार करने का राज्यों का स्वयंनिष्ठ अधिकार है।<sup>१</sup> बर्मापत्र की मिश्र मिलने के पहले ही बेल्लेजली ने कर्नाटक के सम्बन्ध में सरनी राय मायन बर ली थी। नवाबों पर जो अपराध लगाये गये थे, उनकी पूरी तरह जांच भी नहीं की गई थी। बिल्लन को भी मानना पड़ा है कि टीपू के नाम उनके पत्रों से ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका “वाम्बदिक विजासदान सिद्ध न होना था। तिस पर भी जो दंड दिया गया, वह तो हर तरह से बढोर था।”

कर्नाटक के शासन में बहुत से दोष थे, प्रजा पर अत्याचार होना था, शासन व्यसनी थे, यह सब ठीक है। पर इसके लिए अधिकतर जिम्मेदार ईान था ? नवाब के हाथ में कोई शक्ति न थी, सेना अंगरेजों की थी, जिन्हें सबेरे ही केटे

हट न थी। भेटों और दावतों की भरमार थी। समय पर किस्त अदा न करने से शासनाधिकार छीन लेने का भय दिखालाया जाता था, जिसके कारण तीन रुपया सैकड़ा माहवार कर के सूद पर नवाब को अंगरेज महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था।<sup>१</sup> महाजनों को मन्तुष्ट रखने के लिए मालगुजारी वसूल करने का ठेका उन्हीं को दिया जाता था। प्रजा में उनका कोई सम्बन्ध न था, इसलिए उनको तरह तरह के अत्याचार करने में भी किसी प्रकार का संकोच न होता था। नवाब की ओर से जरा भी स्वतंत्रता कम्पनी की आँखों में खटकती थी। इंग्लैंड के राज-वराने के साथ नवाबों के पत्र-व्यवहार से वेलेजली बहुत चिढ़ता था। उनकी धृष्टता, अंगरेजों के प्रति शत्रुता और प्रजा के ऊपर अत्याचारों को दिखलाने हुए, उसने अपनी नीति का बड़े जोरो से समर्थन किया है। इस पर एक इतिहासकार का कहना है कि भेड़ का बघ करने के लिए शेर अपना हर समय समर्थन कर सकता है।

**तंजौर का झगड़ा**—राजा तुलजाजी के कोई सन्तान न थी। मरते समय उसने सरफोजी नाम के एक लड़के को गोद लिया था। जिस ढंग से वह गोद लिया गया था, उसमें कुछ झगड़ा था, इसलिए अंगरेजों की सलाह से तुलजाजी का भाई अमरसिंह गद्दी पर बिठला दिया गया। उसके साथ सन् १७६३ की सन्धि करके अंगरेजों ने उसको तंजौर का राजा मान लिया। बाद में “पंडितों की सलाह” से पता लगा कि गद्दी का अधिकारी वास्तव में तुलजाजी का दत्तक पुत्र सरफोजी है। इसके अतिरिक्त अमरसिंह का शासन भी ठीक नहीं है। इस “अन्याय” को दूर करने के लिए अब सरफोजी को गद्दी पर बिठलाना निश्चित किया गया। सरफोजी की शिक्षा एक पादरी की निगरानी में हुई थी। वह वेलेजली की सब शक्तों को मानने के लिए तैयार था। कर्नल वेयर्ड की राय में राजा अमरसिंह एक योग्य शासक था और उसने अंगरेजों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया था। वेलेजली की शक्तों को मान करके वह अपनी बची-खुची स्वतंत्रता को खोना न चाहता था, यही

रमका स्वयं बड़ा अपराध था। बहुत दिनों से अंगरेज रेजीडेंट रमको हाथ में लाने के लिए मार, दाम, डंड, भेड़ से काम ले रहा था। सफलता न होने पर रमको गद्दी से उतारने के बिना और कोई उपाय न था। ब्रेलेजली की राय से रमके शासन की जाँच करने के लिए किसी कमीशन के नियुक्त करने की आवश्यकता न थी। इस जाँच-पढ़ताल से “नजोर की प्रजा के सुख और समृद्धि में बड़ी बाधा पड़ती।” इस तरह राजा अमरसिंह गद्दी से उतार दिया गया। मरफोजी के साथ नई सन्धि कर ली गई, जिसके अनुसार पेंशन देकर वह नजोर के किले में रख दिया गया और राज का शासन अंगरेजों के हाथ में आ गया।

**अवध के साथ जबरदस्ती**—ब्रेलेजली की राय से अवध सुरक्षित न था। नवाब वजीर की मना किसी काम की न थी। रमको स्वयं अपनी राज के लिए अंगरेजों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। अवध की निर्दलना से कमरनी को अपने राज्य की रक्षा के लिए भय हो रहा था। अवध की पश्चिमोत्तर सीमा पर मराठों की शक्ति बढ़ रही थी। जर्मणा आक्रमण करने की तैयारी धमकी दे रहा था। बनारस से भागकर वजीरअली उधम मचा रहा था। इन शत्रुओं को रोकने के लिए अवध से वापसी अंगरेजी मना न थी। ये मना थी भी इसी का स्वर्चा चलाना नवाब के लिए कठिन हो रहा था। शासन-व्यवस्था ठीक न होने से नवाब वजीर की शासनी घट रही थी।

इस तरह टीपू से युद्ध छिड़ने के पूर्व ही अवध के विषय में वेलेजली की राय निश्चित हो गई थी। युद्ध में निश्चिन्त होने पर नवम्बर सन् १७६६ में उसने नवाब को अपनी सेना तोड़ने और अंगरेजी सेना बढ़ाने के लिए लिख भेजा। नवाब की स्वीकृति बिना मिले ही अवध में अंगरेजी सेना बढ़ा दी गई और उसका गर्चा नवाब से मांगा जाने लगा। वेलेजली की राय में नवाब की स्वीकृति की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि सर जान शोर के साथ जो सन्धि हुई थी, उसमें अवध की रक्षा का भार कम्पनी ने ले लिया था। इसलिये भय की आशका होने पर कम्पनी को अपनी सेना बढ़ा देने का अधिकार था और उसका खर्च देने के लिए नवाब मजबूर था।

नवाब वजोर का कहना था कि मैं किस्तों को बराबर अदा कर रहा हूँ, सेना बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी निज की सेना तोड़ देने से मेरा बड़ा अपमान होगा। पिछली सन्धि में यह वचन दिया गया था कि “मौरूसी राज्य, सेना तथा प्रजा पर मेरा पूरा अधिकार रहेगा” परन्तु सेना का प्रबन्ध छीन लेने से मेरा क्या अधिकार रह जायगा? वेलेजली की दृष्टि में नवाब का यह उत्तर “दृष्टता-पूर्ण” था। उसका कहना था कि सेना बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय गवर्नर-जनरल कर सकता है न कि नवाब। उसने स्वयं माना है कि वह शासन में सुधार करने के अयोग्य है, ऐसी दशा में समय पर किस्तों का अदा होना असम्भव है।

“जाल में फँसी हुई चिड़िया की तरह नवाब फटफटा रहा था।” मस-नद से उतरकर देश से बाहर चले जाने तक की नवाब ने धमकी दी, परन्तु गवर्नर-जनरल पर इसका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। कई महीने तक आपस में पत्र-व्यवहार होता रहा। नवाब को अपमानित करने और बुरा-भला कहने में वेलेजली ने अपने पत्रों में कोई बात ठाठ न रखी। अब केवल अंगरेजी सेना बढ़ाने से ही वेलेजली को सन्तोष न था, प्रत्युत अवध के सम्पूर्ण शासन को कम्पनी के हाथ में लेना उसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी प्राप्ति में वह किसी प्रकार की बाधा को सहन न कर सकता था।<sup>१</sup> जनवरी सन् १८०१ में नवाब

<sup>१</sup> वेलेजली, डेसपैचेज़, जि० २, पृ० ४२६।

को लिया गया कि या तो वह तजोर के राजा की तरह पेशन स्वीकार करने चुपचाप अलग पड़ा रहे, या अंगरेजी सेना का यहाँ तक का खर्चा देकर आगे के लिए अपना आधा राज्य कम्पनी को दे देवे। अप्रैल में रेजीडेंट कर्नेल स्काट को लिख दिया गया कि यदि इन शर्तों के मानने से नवाब हीला-हवाला कर, तो दोआब और रहैलखंड पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया जाय।<sup>१</sup> नवाब के विरोध की ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया, उल्टे हमके चेतावनी दी गई कि इन शर्तों के न मानने का परिणाम “हमके राज्य, तथा हमारे वंशजों के लिए अच्छा न होगा।”

**लखनऊ की सन्धि** — जुलाई मन् १८०१ में शर्तों को मंजूर कराने के लिए गवर्नर-जनरल का भाई हनरी लखनऊ भेजा गया। थोड़े दिन बाद स्वयं गवर्नर-जनरल भी बलकत्ता में चल पड़ा। अपनी रजा या कोई इनाम न दखकर नवम्बर मन् १८०१ में नवाब को सन्धि पर हस्ताक्षर करन पड़े। इस सन्धि में दोआब और रहैलखंड के कुछ जिले अम्बता को मिल गये। बल्लेजली ने छोटकर अवध की सीमा पर के जिले में लिया। इन बिना के निबल जान में मराठा या अन्य किसी दाहरी शक्ति से अरब में राज या स्वयंश न रह गया। चारों ओर के जिला पर अंगरेजों का अधिपार हो गया। नवाब की सना घटा दी गई और आवश्यकता पड़ने पर बिना सन्धि के नवाब की सैनिक सहायता वरन के लिए वचन दिया गया। अंगरेज सन्धि की सलाह से नवाब ने इस वचन-खुचे राज्य का गायन वरन स्वीकार लिया।



कम्पनी की माँग बराबर बढ़ती जाती थी। वीस पचीस लाख रुपया सालाना से बढ़ते बढ़ते यह रकम एक करोड़ पैंतीस लाख तक पहुँच गई थी। जब नवाब ने इतनी बड़ी रकम देने में अपनी अवमर्थता प्रकट की तब उसका आधा राज्य छीन लिया गया। सन् १७८७ में कार्नवालिस ने और सन् १७६८ में सर जान शोर ने शासन में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। परन्तु इसका कुछ भी ध्यान न रखकर अंगरेज अफ़मरो की सलाह से शासन करने के लिए नवाब से कहा गया। इंग्लैंड लौटने पर, पाल नामक एक अंगरेज की सहायता से, जो बहुत दिनों तक अवध में रह चुका था, इस सम्बन्ध में वेलेजली पर भी पार्लामेंट में अभियोग चलाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई।

**अवध का शासन**—नवाब से छीने हुए जिले का हेनरी वेलेजली लेफ्टिनेंट-गवर्नर बनाया गया। यह गवर्नर-जनरल का छोटा भाई था और उसके प्राइवेट सेक्रेटरी का काम करता था। हेनरी वेलेजली कम्पनी का नौकर न था। उसकी नियुक्ति से कम्पनी के सचालक वेलेजली से बहुत चिढ़ गये। अन्त में उनकी आज्ञा से हेनरी को यह पद छोड़ना पड़ा। इन जिलों में अंगरेजी कानून-कायदे जारी कर दिये गये। जनता के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान न रखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अदालतों द्वारा न्याय की अपेक्षा अधिकतर अत्याचार होने लगा। मनमाना लगान लिया जाने लगा, जिससे थोड़े ही दिनों में इन जिलों की आमदनी बहुत बढ़ गई। नवाब से जितना रुपया नरुद मिलता था, उससे कहीं अधिक इन जिलों से मिलने लगा। नवाब सादतअली ने भी सुधार का प्रयत्न किया। उसने मालगुजारी वसूल करने के लिए राज्य को 'चकलों' और 'इलाकों' में बाँट दिया और उनको ठेके पर उठा दिया। हेनरी लारेंस का कहना है कि वह एक योग्य शासक था। यदि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता तो बहुत कुछ सुधार होने की सम्भावना थी। अंगरेज रेजीडेंट बराबर उसके शासन में बाधा डालते थे और किसी प्रकार की उन्नति न होने देते थे। तिस पर भी थोड़े ही काल में उसने खजाने को धन से भर दिया था।

**सूरत का अपहरण**—भारतवर्ष आने पर अंगरेजों ने पहले पहल सूरत में ही पैर जमाया था। मई १७५६ में उन्होंने जैमे तैमे किले पर कब्जा कर लिया और नवाब के साथ सन्धि करके दोहरा शासन चला दिया। इस सम्बन्ध में एक डच यात्री का कहना है कि कानून-कायदे सब अंगरेजों के हाथ में थे तबपर भी नवाब को गद्दी पर बिठलाये रखन का दांग दिखना जाता था। अंगरेजों की मांगें बराबर बढ़ती जाती थीं। बेंलेजली की राय में नवाब का शासन ठीक न था और रजा के लिए सेना बढ़ाने की आवश्यकता थी। नवाब के मरने पर अंगरेजी सेना सूरत पहुँच गई और हमारे भाई को पेंशन स्वीकार करके सूरत का शासन अंगरेजों के हाथ में सौंप देना पड़ा। यह एक लाख रुपये सालाना देने के लिए तैयार था, पर बेंलेजली ने इतने में सन्तोष न था। सूरत के अंगरेज प्रतिनिधि की राय में अधिक न्यून देना नवाब के लिए सम्भव न था, हमारे राज्य छीन लेना हमारा विवशमयन था। बेंलेजली का कहना था कि शासन और सैनिक प्रदत्त करनी के हाथ में आ जाने से ही सूरत की दशा सुधर सकती थी, इसलिए हमारे ने सेना वरपनी का “वर्तव्य और अधिकार” था। इस मामले में एक पैगार था। वहना है कि न्याय तो बेचारे नवाब की ओर था, अंगरेजों की लालच और चालबाजी और धोखाधड़ी थी। ५

उनको राजदूत, मंत्री, जज और गायको का काम करना पड़ता है। जब तक उनकी शिक्षा, योग्यता और आचरण का ध्यान नहीं रखा जायगा, शासन में सफलता होना अशक्य है। इन लोगों के लिए पाश्चात्य राजनीति, विज्ञान और साहित्य के साथ साथ पूर्वीय इतिहास, भारतवर्ष सम्बन्धी कानून-कायदे और देशी भाषाओं का ज्ञान बड़ा आवश्यक है।<sup>१</sup> सचालको की स्वीकृति बिना मिले हुए ही उसने यह कालेज बड़ी धूम-धाम से खोल दिया।

इसमें बहुत से अंगरेज अफसर और पाठडी अध्यापक नियुक्त किये गये। देशी भाषाएँ सिखलाने तथा रीति-रिवाजों को बतलाने के लिए पंडित और मोलवी रखे गये। इंग्लैंड से आने पर कम्पनी के साधारण कर्मचारियों को इस कालेज में तीन वर्ष पढ़ने के लिए नियम बना दिया गया। कम्पनी के संचालक वेलेज़ली से सहमत न थे, कर्मचारियों की शिक्षा के लिए वे अपने को जिम्मेदार न मानते थे। इसके अतिरिक्त कालेज के चलाने में बड़ा खर्च पड़ता था। उनकी आज्ञा के विरुद्ध दो वर्ष तक इसीफे की धमकी देकर जैमे-तैसे वह इस कालेज को चलाता रहा। अन्त में उसे उनकी आज्ञा मानकर इसको तोड़ना पड़ा। अंगरेज लेखको को, जो कहते हैं कि भारतवर्ष में शिक्षा-प्रचार के लिए इस कालेज की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना चाहिए कि यह कालेज कम्पनी के केवल अंगरेज कर्मचारियों के लिए खोला गया था। हिन्दुस्तानियों को पढ़ाने की इसमें कोई व्यवस्था न थी। उनकी शिक्षा के लिए वेलेज़ली को कुछ भी चिन्ता न थी। इसमें सन्देह नहीं कि कालेज की योजना से वेलेज़ली की दूरदर्शिता और योग्यता का परिचय मिलता है। इससे कर्मचारियों की शिक्षा की ओर सचालको का ध्यान भी आकर्षित हो गया। कुछ दिनों बाद इसी ढंग का एक कालेज इंग्लैंड में खोला गया, जो बहुत दिनों तक चलता रहा।

**धार्मिक नीति**—वेलेज़ली भारतवर्ष में ईसाई मत की उन्नति और प्रचार के लिए उत्सुक था। भारतवर्ष में अंगरेजों को पथ-भ्रष्ट होते

दृष्ट देवकर उसको बड़ी चिन्ता हो रही थी। इन दोष को दूर करने के लिए फोर्ट विलियम कालेज में धार्मिक शिक्षा का ग्याम प्रबन्ध किया गया था। कालेज का अध्यापन नियमानुसार एक पाठ्यही हो सकता था। इस कालेज में हिन्दुस्तानियों को ईसाई बनाने में भी सहायता ली गई। वेलेजली की आज्ञा से ब्राह्मण का ग्याम देशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। परन्तु धर्म के प्रचार में वह पुर्नगालियों की गी भूल करनेवाला न था। इस सम्बन्ध में यह आधुनिक दृष्टि से काम लेना चाहता था। खुले तौर पर जबरदस्ती ईसाई बनाना उसकी नीति के विरुद्ध था। लस्का के गवर्नर को स्पष्ट शब्दों में हमसे लिए मना कर दिया गया था। उसकी राय में धर्म-प्रचार के लिए हमसे जा बुद्ध किया, हमसे कोई "ईसाई गवर्नर" कम न कर सकता था और न किसी "ब्रिटिश गवर्नर" को हमसे अधिक करना ही राजिज था।<sup>१</sup> सन् १८०० में उसी आज्ञा से बाल-हत्या बन्द कर दी गई। गर्त-प्रण की जात करने और रोवने का भी प्रयत्न किया गया परन्तु अधिक सफलता न हुई।

# परिच्छेद ८

## साम्राज्य के लिए युद्ध

( २ )

मराठों की स्थिति—बर्दा की विजय मराठों की अन्तिम विजय थी ।



सवाई माधवराव

परन्तु इससे यदि किसी को भ्रम नहीं हुआ था, तो वह युवक पेशवा था । विजय की बधाई मिलने पर उसका कहना था कि बिना लड़े-भिड़े मुगलों की बेढव हार और मराठों के गर्व को देखकर मुझे दोनो की पतित अवस्था पर दुख हो रहा है ।<sup>१</sup> मराठों की इस अवस्था का प्रमाण उस समय का इतिहास है । इस अवसर पर नाना फडनवीस न

१ मैकडोनाल्ड, मेम्बायर ऑफ नाना फडनवीस, पृ० ९७ ।

मराठा-महल में जो एकता स्थापित की थी वह एक दुर्घटना के कारण थोड़े ही काल में छिन्न-भिन्न हो गई।

राघोबा के मरने पर नाना फटनवीस ने उसके बेटे बाजीराव को केंद्र कर लिया था। वह जानता था कि देशद्रोही राघोबा की मन्तान में मराठा-महल का गिरावला असम्भव है। बाजीराव संस्कृत का अच्छा विद्वान् था और उसका सीढ़ी सीढ़ी बातें बनाना गूढ़ आता था। वह गुप्त नीति में पेशवा के साथ पत्र-व्यवहार करने लगा। पेशवा ना भावुक था ही, ओंठे ही काल में उस पर बाजीराव का रंग जम गया। हमसे लिए नाना फटनवीस को कई बार पेशवा की भर्त्सना करनी पड़ी। हयर कुछ दिनों में उस का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वह बराबर उदास रहा करता था। अक्टूबर मई १७६५ में वह रुत पर न गिरकर मर गया।<sup>१</sup> यह माधवराव का निम्कर मरना ही न था बल्कि उसमें पेशवाई का पतन था।



मराठा-मंडल में जो एकता स्थापित की थी वह एक दुर्घटना के कारण थोड़े ही काल में छिन्न-भिन्न हो गई।

राघोबा के मरने पर नाना फडनवीस ने उसके बेटे बाजीराव को कैद कर रखा था। वह जानता था कि देशद्रोही राघोबा की मन्तान में मराठा-मंडल का हित होना असम्भव है। बाजीराव संस्कृत का अच्छा विद्वान् था और हमें मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता था। वह गुप्त रीति में पेशवा के साथ पत्र-व्यवहार करने लगा। पेशवा तो भावुक था ही, थोड़े ही काल में उस पर बाजीराव का रंग जम गया। इसके लिए नाना फडनवीस को कई बार पेशवा की भर्त्सना करनी पड़ी। इधर कुछ दिनों से उस का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और वह बराबर उदास रहा करता था। अक्टूबर मन् १७६५ में वह छत पर से गिरकर मर गया।<sup>१</sup> यह साधवराव का गिरफ्तार मरना ही न था ब्राम्ह में पेशवाई का पतन था।

साधवराव के कोई मन्तान न थी। मरने समय उसने बाजीराव को गद्दी पर बिठलाने की इच्छा प्रकट की थी। नाना फडनवीस इसका परिणाम जानता था। सिन्धिया और होलकर की सलाह से वह एक दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठलाना चाहता था, परन्तु बाजीराव के पट्ट्यंत्र में नाना का सारा प्रयत्न व्यर्थ गया और बाजीराव पेशवा हो गया। वह अपने कुटुम्ब के प्रति नाना फडनवीस का व्यवहार भूल न सकता था। कभी वह उसके विरुद्ध सिन्धिया को भटवाता था, कभी सिन्धिया को दवाये रखने के लिए उससे नाना जोड़ता था। पूना में इन दिनों घटा हलचल मचा था। कितने ही राजनैतिक दल हो गये थे। सबको अपने स्वार्थ-साधन की सूझ रही थी, मराठा-



उमने अपने विचारों के अनुसार बाजीराव को सदा उसके हित की सलाह दी । यदि मराठा शासन बिना अंगरेजों की सहायता के फिर अच्छी तरह चलाया जा सकता था, तो वह लार्ड वेलेज़ली के प्रभाव को मानकर अंगरेजी सेना बुलाने के सर्वथा विरुद्ध था । अंगरेजों का वह आदर करता था, उनके चरित्र की न्ययता तथा उनके शासन की दृढ़ता की वह प्रशंसा करता था । परन्तु



नाना फटनवीस

राजनैतिक शत्रु की दृष्टि से अंगरेजों का भय था उनका जलन उम्मे अर्धक विषयी को न थी । वह जानता था कि गवर्नर-जनरल के इच्छानुसार अंगरेजों को पैर जमाने की आज्ञा देने का अन्तिम परिणाम यह होगा कि उनका प्रभाव

जिस बात को नाना फडनवीस और सिन्धिया चार वर्ष से टाल रहे थे, जिसके लिए बेल्लेजली ने कोई कमर उठा न रखी थी, वही बात अब आप ही आप सम्भव हो गई। पूना से भागकर बाजीराव ने अंगरेजों से सहायता मांगी। हमने उनकी सब गतों को स्वीकार कर लिया और दिसम्बर सन् १८०० में अंगरेजी जहाज पर बेसीन पहुँचकर सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। हमने अपने सर्व से अंगरेजी सेना को रखना स्वीकार किया और इसके लिए २६ लाख रुपया मालाना की आमदनी के जिले को देने का वचन दिया। यूरोप के किसी अन्य निवासी को अपने यहाँ नौकर न रखने तथा किसी राज्य से ब्रिटिश सरकार की इच्छा बिना युद्ध या सन्धि न करने की भी प्रतिज्ञा की, और निजाम तथा गायकवाड सम्बन्धी झगड़ों में अंगरेजों को पक्ष मान लिया। अंगरेजों ने उसको फिर से गद्दी पर बिठला देने और बराबर उसकी रक्षा करने का वचन दिया। इस तरह गद्दी के लालच से पड़कर बाजीराव ने राष्ट्रीय सम्मान और स्वतन्त्रता को अंगरेजों के हाथ बँच दिया। राधोबा के बेटे से हमके अतिरिक्त और आशा ही क्या की जा सकती थी ?

कार्नवालिस के मैसूर-युद्ध की आलोचना करते हुए फ्रांसिस ने ठीक कहा था कि हिन्दुस्तानी राजा अपने तात्कालिक लाभ के लिए यशों की तरफ दसुर रहते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उपायों को टूट निसालने में वे बड़े चतुर होते हैं। उनके चुनने में उन्हें किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। सुदृढ़, स्थायी तथा दूरवर्ती लाभ का उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। यदि ऐसा न होता तो क्या यह सम्भव था कि बंगाल के नवाबों का नाश, अवध के नवाबों की अधीनता और स्वयं दादगाह तथा अन्य राजाओं को, जो ब्रिटिश मित्रता के गिवार बन चुके थे, निगाह में रखने हुए भी वे ऐसी सन्धियाँ करते, जिनमें उनको हमारी सहायता माँगने की आवश्यकता पड़ती ?

आजका भी ।<sup>१</sup> इसे सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मराठों को इन दिनों अपने ही झगड़ों से छुट्टी न थी, फिर अन्य राज्यों पर आक्रमण का कहना ही क्या था ? यह भी कहा जाता है कि पेशवा ने अंगरेजों से सहायता माँगी थी, उसको सहायता न देना केवल नीति-विरुद्ध ही नहीं बल्कि “नीचता” थी ।<sup>२</sup> परन्तु जब कम्पनी के परम मित्र निजाम पर सफ़ट पड़ा था, तब यह उदारता कहाँ चली गई थी ? इसके अतिरिक्त होलकर को, जिसने बाजीराव को निकाल बाहर किया था, ढड़ देने की क्या व्यवस्था की गई थी ? मराठों के झगड़ों में पड़ने की आवश्यकता भले ही न रही हो सन्धि का तात्कालिक परिणाम कुछ ही हुआ हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि अन्ततः अंगरेजों का इसमें पूरा लाभ हुआ । मिडनी आ्यन का कहना है कि इस समय तक भारत में एक “ब्रिटिश साम्राज्य” था, परन्तु इसमें कम्पनी के हाथ में “भारत का साम्राज्य” आ गया । उत्तर, दक्षिण और पूर्व में अंगरेजों का प्रभुत्व स्थापित ही हो चुका था, अब पश्चिम के मराठा साम्राज्य में भी उनका आतंक जम गया ।<sup>३</sup>

**बाजीराव की वापसी**—अप्रैल मन् १८०३ में आर्थर वेलेजली ने एक बड़ी सेना के साथ पूना आकर बाजीराव को फिर से गद्दी पर बिठला दिया । बेगीन की सन्धि से चिढ़कर सिन्धिया और भोंसला ने बाजीराव का साथ नहीं दिया । होलकर भी चुपचाप रहा और बेचारे अमृतराव ने पेशवा की मदद कर ली । पेशवा की रक्षा के लिए पूना में अंगरेजी सेना रक दी गई । गवर्नर-जनरल लिखता है कि अधिकांश मराठा जागीरदार बाजीराव के पक्ष में थे और प्रजा उसको फिर से गद्दी पर बिठलाने में सहायता देने के लिए तैयार थी । यदि ऐसा न होता तो मैं उसको मयनद पर बिठलाने का प्रयत्न फौरन ही द्वाँट देता । प्रजासत्त के प्रतिवृत्त मराठों पर किसी नामक का रखना “न्याय और

बुद्धि" के विरुद्ध था ।<sup>१</sup> दक्षिण के जागीरदारों के सम्बन्ध में आर्थर वेलेजली लिखता है कि जय तक गृह सेना एकत्र करके उनको यह अच्छी तरह नहीं दिखला दिया जायगा कि हम बिना अपना मतलब मिट्ट किये हुए नहीं हटेंगे, तब तक वे हमारा साथ न देंगे ।<sup>२</sup> यदि गवर्नर-जनरल के कथनानुसार अधिकांश जागीरदार बाजीराव के ही पक्ष में थे, तो फिर इस सैनिक भय के दिखलाने की क्या आवश्यकता थी ? प्रजा उसके अत्याचार से पीड़ित थी, उसी की अनुमति से सिन्धिया ने पूना में लूट मचा रखी थी । फिर उसके साथ प्रजा की सहानुभूति कैसे हो सकती थी ?

बाजीराव की अयोग्यता गवर्नर-जनरल से छिपी न थी । उसकी राय में वह निर्बल, कपटी और शासन के अयोग्य था । आर्थर का कहना था कि सार्वजनिक बातों का तो उसे कभी ध्यान ही न आता था । उसका व्यक्तिगत जीवन "भयंकर" था ।<sup>३</sup> यदि प्रजा के हित का ही ध्यान था तो अमृतराव, जो आर्थर के शब्दों में "बड़ा योग्य" था, पेशवा क्यों न बनाया गया ? उत्तर में आर्थर का, जो अपने भाई की तरह नीति-निपुण न था, स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यदि वह विद्रोह करता तो अंगरेजों के मार्ग में बाजीराव से भी बढकर कटक होता ।<sup>४</sup> यह ठीक है कि शासक की अयोग्यता ही में अंगरेजों का हित था ।

**सिन्धिया और भोंसला**—पूना दरबार से सिन्धिया को हटाने के लिए वेलेजली पहले ही से प्रयत्न कर रहा था । वह जानता था कि सिन्धिया की उपस्थिति में बाजीराव का फैसना असम्भव है । इसलिए पहले उसको उत्तरी भारत में जर्माशाह के आक्रमण का भय दिखलाया गया । इस पर भी जब वह नहीं हटा, तब उसके विरुद्ध निजाम और भोंसला के साथ गुप्त मन्थि का प्रयत्न किया गया । इसमें भी असफलता होने पर यह दिखलाया

१ वेलेजली, टेम्पैचेज, लि० ३, पृ० ४२-४३ ।

२ वेलेजली, टेम्पैचेज, पृ० २००-२०१ ।

३ वही, पृ० ३६७ ।

४ वही, पृ० ३६७ ।

जाने लगा कि उत्तरी भारत में सिन्धिया के राज्य में अशान्ति फैली हुई है। मन् १७६६ में ही क्लार्क को अवध की सीमा पर सेना एकत्र करने के लिए आज्ञा दे दी गई थी। साथ ही साथ यह भी लिख दिया गया था कि सिन्धिया या उसके सूबेदार अम्बाजी के कारण पुन्हुने पर यह कह देना चाहिए कि अवध का पदच्युत नवाब वजीरअली बनारस में भागकर जर्मागह के पास जानेवाला था। उन देना के आक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा। इतना ही नहीं यह भी कह दिया गया था कि लडाइ छिटके ही राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए और सिन्धिया के कुटुम्बियों तथा नौकरों को, जो हमसे अमनुष्ट हो, सहायता का वचन देकर भड़काना चाहिए।<sup>१</sup> इस तरह पहले ही से सिन्धिया के विरुद्ध तैयारियाँ प्रारम्भ हो गई थीं, परन्तु इस समय उनका गुप्त रहना आवश्यक था। सिन्धिया को विपण होकर कुछ काल के लिए पूना छोड़ना ही पड़ा, पर वह गीघ ही फिर लौट आया।

सिन्धिया के विरुद्ध भोयला को हाथ में लाने का काम बोलब्रुक ने संपादित किया। परन्तु टीपू के पतन से अंगरेजों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि भोयला मराठों की रक्षा के लिए चिन्तित हो रहा था। मई मन् १८०१ में निराण होकर बोलब्रुक वापस चला गया। भोयला ने दो प्रतिनिधियों को पूना भेजा और सिन्धिया तथा होलकर के परस्पर वैर को मिटाने का प्रयत्न कुछ प्रयत्न किया, परन्तु वेसीन की सन्धि हो जाने से इसका फलना फल बराम दिगट गया।

**मराठों का दूसरा युद्ध**—वेसीन की सन्धि के सम्बन्ध में सिन्धिया या अन्य किसी मराठा राजा से कोई परामर्श नहीं किया गया था। इसकी क्या शर्तें थी, इसका भी उनको ठीक ठीक पता न था। सिन्धिया और भोयला की राय में सन्धि के पूर्व अंगरेजों तथा पेशवा का उनके साथ परामर्श करना बर्तव्य था। जब सिन्धिया, होलकर और भोयला को सन्धि के समाचार मिले, तब उन लोगों ने इस सम्बन्ध में परस्पर विचार करना आवश्यक

समझा। इसी उद्देश्य से फरवरी मन् १८०३ में सिन्धिया उज्जैन में चलकर बरहानपुर पहुँचा। यहाँ उसको अँगरेज रेजीडेंट कालिंस मिला। मई में नागपुर से भोसला भी चल पड़ा। कालिंस की राय में इन दोनों का उद्देश्य पूना की ओर बढ़ने का था। इन दोनों के मिलने में वह अँगरेजों का हित न समझता था। वह सिन्धिया का स्पष्ट मन जल्दी जानना चाहता था, इसी लिए निजाम की सीमा में सेना हटाने का आग्रह कर रहा था। ता० २७ मई को कालिंस के बहुत जोर देने पर सिन्धिया की ओर से उसको विश्वास दिलाया गया कि अँगरेजों के मार्ग में वह किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहता। कहा जाता है कि इसी अवसर पर सिन्धिया ने यह भी कहा कि भोसला में भेट होना के बाद कहा जा सकता है कि “युद्ध होगा या सन्धि”।

बरार में मलकापुर नामक स्थान पर सिन्धिया और भोसला की भेट हुई। इन दोनों ने कालिंस को विवश दिलाया कि निजाम के राज्य की सीमा पार करने या पूना की ओर बढ़ने का उनका कोई विचार नहीं है। वेसीन की सन्धि की रक्षा करने का वे गवर्नर-जनरल को वचन दे चुके हैं। परन्तु कालिंस की राय में यह सब बहानाबाजी थी। उस स्थान से हटना ही मित्रता का केवल प्रमाण हो सकता था। इस पर ता० २८ जुलाई को सिन्धिया और भोसला ने कहला भेजा कि यदि जनरल वेलेजली अपनी सेना लेकर हट जाय, तो वे भी बरहानपुर वापस चले जायेंगे। ता० ३१ जुलाई के पत्र में सिन्धिया ने गवर्नर-जनरल को भी स्पष्ट लिख दिया कि इस समय तक पेशवा ने सन्धि के विषय में मुझे कुछ नहीं लिखा है, सब हाल जानने के लिए मैं पेशवा के यहाँ दूत भेज रहा हूँ। पेशवा, भोसला तथा अन्य मराठा सरदारों के साथ मेरे जो परस्पर के प्राचीन सम्बन्ध हैं, यदि उनमें वेसीन की सन्धि से कोई रूकावट नहीं पड़ती है, तो उसके विरुद्ध जाने का मेरा कभी विचार नहीं है।<sup>१</sup> इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया, निजाम की सीमा से हटने के लिए कोई तारीफ भी निश्चित नहीं की गई और न अँगरेजी सेना हटाने के विषय में

ही कुछ कहा गया। ता० ३ अगस्त को कालिस दरबार छोड़कर चला गया और ता० ६ अगस्त को अहमदनगर पर आक्रमण करके मेनाध्यक्ष आर्थर वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी।

**युद्ध पर विचार**—मिन्धिया और भोमला बेसीन की सन्धि से अग्रन्तुष्ट अवश्य थे, पर इस युद्ध में पढ़ने का न उनका विचार ही था और न वे तैयार ही थे। ता० १६ अप्रैल के पत्र में स्वयं गवर्नर-जनरल गुप्त कमेटी को लिखता है कि मिन्धिया बराबर अंगरेजों से झगटा चला रहा है। भोमला में बेसीन की सन्धि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशंका नहीं है। मिन्धिया, हालकर और भोमला आत्मरक्षा के लिए एक गुट बनाना चाहते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शत्रुता का भाव सिद्ध नहीं होता है।<sup>१</sup> ता० २३ अप्रैल के पत्र में आर्थर वेलेजली ने भी स्टिवेंसन से ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं।<sup>२</sup> ता० १५ मई के पत्र में पूना का रेजीडेंट कर्नेल क्लोज भी गुप्त कमेटी को लिखता है कि किसी शत्रुता के भाव से मिन्धिया इस गुट में शामिल हो यह “विलकुल असम्भव” है। मिन्धिया और भोमला ने कोई आक्रमण नहीं किया था। उनकी सेनाएँ उनके राज्य में थीं, तब भी आर्थर वेलेजली के हटने पर वे दरहानपुर वापस जाने के लिए तैयार थे और गवर्नर-जनरल तथा रेजीडेंट कालिस को अपनी मित्रता का सब तरह से विस्मय दिला रहे थे। युद्ध की कोई तैयारी न थी। कालिस ही के गढ़ों में मिन्धिया के पास पचास हजार से अधिक रुपया न था।

दूसरी ओर गवर्नर-जनरल ने सन् १७६६ में ही निश्चिन कर लिया था कि अच्छा अवसर मिलने पर मिन्धिया की शक्ति को नष्ट कर डालना चाहिए। जनवरी सन् १८०२ में ही सेनापति लेक को मिन्धिया के राज्य की सीमा पर सेना एकत्र करने की आज्ञा दे दी गई थी। वेलेजली लिखता है कि ऐसा करने में उसका उद्देश्य केवल भय दिखलाना था। इस तरह भय दिखलाने

१ वेलेजली, एम्पेचेज, जि० १, पृ० ७०-८०।

२ वेलेजली, एम्पेचेज, पृ० ८०७।

का पार्लामेंट को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। हिन्दुस्तानी राजाओं के दूत पार्लामेंट के सामने नहीं आते हैं। उन्हीं का देश लूटा जाता है, उन्हीं की सम्पत्ति अफसरों की जग्गी है और उन्हीं पर युद्ध छेड़ने तथा शान्ति-भंग करने का दोष लगाया जाता है। मराठा युद्ध के जो कारण बतलाये जाते हैं, उनमें कुछ भी तत्त्व नहीं है। देशी राजाओं के दोष दिखलाना उन्हीं विषयों बतलाना एक आधारणी बात है। बेंलेजली की सरकार जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, उसी में सन्देह होता है। मिन्धिया को जैसा बुरा-भला कहा गया है वह छिपा नहीं है। जिन फ्रांसीसियों के भय पर जोर दिया जाता है, मिन्धिया की सेना में उनके अफसरों की संख्या १२ से अधिक नहीं थी। मिन्धिया स्वयं विदेशियों को सेना में रखने का पक्षपाती नहीं है, यह सबको ज्ञात है। इस तरह मराठों के विरुद्ध युद्ध का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता। बेगीन की सन्धि की उद्द गतों पर जोर का होना स्वाभाविक था। यदि ऐसा न होता तो आश्चर्य की बात थी। मराठा साम्राज्य की राजधानी को विदेशियों के हाथ में देकर योंन मराठा राजा जिसमें किंचित् भी सम्मान था, चुप रह सकता था ? इस कारण से उनके सहायता के लिए कहना निम्नन्देह अपमान करके लात मारना है। इस अवस्था का रवय अनुभव करना चाहिए। ऐसे मामलों में मनुष्य-स्वभाव सर्वत्र एक ही था है।<sup>१</sup>

**युद्ध के उद्देश्य और क्षेत्र—**इस युद्ध में बेंलेजली के उद्देश्य पहले ही से निश्चित थे। फ्रांसीसी अफसरों की सेना को नष्ट करके वह गंगा और जमुना के बीच का मिन्धिया का तुलु राज्य जीतना चाहता था और इस तरह बम्पनी के राज्य की सीमा को जमुना नदी तक पहुँचा देना चाहता था। दिल्ली तथा आगरा के किलों पर अधिकार करके वह इस सीमा को सुरक्षित रखना चाहता था। इसी विचार से वह बृद्ध मुगल सम्राट् शाहआलम को भी अपने हाथ में लाना चाहता था, जिसमें उसकी निर्दलता के कारण



का प्रयत्न किया गया था। रेजीडेंट कालिम के मिन्धिया-दरबार छोटने पर आर्थर वेलेजली ने अहमदनगर के किले पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर घूम से काम लिया गया।<sup>१</sup> सैनिक दृष्टि से वह किला बड़े महत्व का था। इससे निजाम-राज्य के पश्चिम-दक्षिण की सीमा सुरक्षित हो गई और पूना से सहायता आने का मार्ग साफ हो गया।

**असेई और अरगाँव**—अहमदनगर के पतन का समाचार सुनकर मिन्धिया और भोगला निजाम के राज्य में घुसे। उनका पीछा करते हुए आर्थर वेलेजली भी आ पहुँचा। ता० २३ मितम्बर को असेई का विख्यात युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। मिन्धिया का कुल तोपखाना अंगरेजों के हाथ में आ गया और उसकी सेना ग्वाल्देर की ओर चली गई। इस युद्ध में मिन्धिया मौजूद न था, वह घोड़सवार सेना के साथ हैदराबाद की ओर बढ़ गया था। मिन्धिया की गोलाबारी में अंगरेजों के बहुत सैनिक मारे गये। आर्थर वेलेजली ता० ३ अक्टूबर सन् १८०३ के एक पत्र में लिखता है कि मिन्धिया की पैदल सेना टीपू की सेना से यहाँ अट्ठी गी। उसका तोपखाना तो ऐसा था कि जिसमें अपनी सेना में बहुत काम लिया जा सकता था। इस युद्ध में मिन्धिया के यूरोपियन अफसरों ने उसका पूरा साथ नहीं दिया। फोर्टेरेक का कहना है कि इस अवसर पर यदि पालमैन नामक जर्मन अफसर ने अपने कर्तव्य का पालन किया होता, तो आर्थर वेलेजली घटी मुश्किल में पड़ता।<sup>२</sup> इतिहासकार डफ लिखता है कि ब्रिटिश सरकार की एक घोषणा द्वारा मिन्धिया की नौकरी छोटनेवाले अंगरेज तथा अन्य यूरोपियन अफसरों को पूरा वेतन देने का वचन दिया गया था। इस पर बहुतों ने नौकरी छोड़ दी थी।<sup>३</sup> ता० २४ अक्टूबर के एक पत्र में आर्थर वेलेजली ने ऐसे १६



अकेले गिन्धिया के साथ गन्धि की बातचीत करके भोगला में उसको अलग करना था। ये सब बातें इस समझौते में हो सकती थीं, परन्तु बराबर इसकी पाबन्दी करने का विचार इसका कभी न था। इसको उसने स्वयं स्वीकार किया है। ता० २४ नवम्बर के पत्र में वह जनरल स्टुअर्ट को लिखता है कि मैं जब चाहूँ, इस समझौते को तोड़ सकता हूँ।<sup>१</sup>

अरगाव में बढ़कर आंगरेजी सेना ने भोगला के प्रसिद्ध दुर्ग गाविलगढ़ पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही साथ दक्षिण का युद्ध समाप्त हो



गाविलगढ़

गया। इसमें सन्देह नहीं कि इस युद्ध में आर्थर वेलेजली ने बड़ी वीरता

से काम लिया। मराठों की हर एक बात का उम्मे पता रहता था, रसद का पूरा प्रबन्ध था, गेम्मी तोपें साथ में थीं, जो आसानी से सेना के साथ जा सकती थीं। इस युद्ध ने उसको नेपालियन के साथ युद्ध करने के योग्य बना दिया। बड़े कठिन समय में उसने स्पेन की रक्षा की और वाटरलू के युद्ध में स्वयं नेपालियन को हराया। इंग्लैंड का वह प्रधान सचिव भी हुआ। इतिहास में वह 'ड्यूक ऑफ वेलिगटन' के नाम से प्रसिद्ध है।

**गुजरात और बुंदेलखंड**—मालवाई की सन्धि में भडौंच और गुजरात का कुछ भाग सिन्धिया के हिस्से में पड़ा था। व्यापार की दृष्टि में भडौंच बड़े महत्व का स्थान था। बम्बई-सरकार की बहुत दिनों से इस पर दृष्टि लगी हुई थी। बडौदा से भडौंच पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया गया। गायकवाड ने इस पर कुछ आपत्ति की, परन्तु उसको स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि अंगरेजों की सहायता करना उसका कर्तव्य है। मराठा राज्यों में सबसे पहले गायकवाड ही अंगरेजों की शरण में गया था, इसका उम्मे ध्यान रखना चाहिए था। भडौंच के विजय करने में कोई कठिनता न हुई और थोड़े ही काल में गुजरात में सिन्धिया के अन्य स्थानों पर भी अंगरेजों का अधिकार हो गया।

बुंदेलखंड पर पहले पेशवा के समय में मराठों ने अधिकार कर लिया था। उसी के वंशज इस समय भी कई स्थानों में शासन कर रहे थे। बुंदेलखंड की सीमा कम्पनी के राज्य से मिली हुई थी, इसी लिए अंगरेज इसको बहुत दिनों से चाहते थे। यह देश पहाड़ियों के ऊँचे स्थल पर बसा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह "भारतवर्ष का स्विट्ज़र्लैंड" है। इन दिनों पेशवा का इस पर नाम मात्र के लिए अधिकार था, वास्तव में बहुत से सरदार स्वतंत्र थे। वेसीन की सन्धि से वाजीराव ने सहायक सेना के खर्च के लिए कुछ जिले अंगरेजों को दक्षिण में दिये थे। अब अंगरेजों ने उन जिलों के बदले में बुंदेलखंड ले लिया था, परन्तु बुंदेला सरदार अंगरेजों का आधिपत्य मानने के लिए तैयार न थे।

इन सरदारों को दवाने के लिए एक अंगरेजी सेना भेजी गई। मुख्य दुंदेला सरदार राजा हिम्मतबहादुर गोमाई अंगरेजों से मिल गया। निन्धिया का एक अंगरेज अफसर भी, जिसका नाम शेफर्ड था अपनी पैदल सेना लेकर अंगरेजों की सहायता के लिए आ गया।<sup>१</sup> पहले कालपी पर आक्रमण किया गया। यह स्थान उन दिनों गंडे के व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। यहाँ के सूबेदार नाना गोविन्दराव को हार माननी पड़ी। हमी अक्सर पर भूमि के सूबेदार से भी मिल गए और निन्धिया का मुख्य सरदार अम्बाजी इग्लिया भी अंगरेजों से मिल गया। माहादजी के समय में उत्तरी भारत का यह मुख्य सूबेदार बनाया गया था। ग्वालियर का किला, उसमें ग्राम-ग्राम के जिले तथा गोंडवा भी हमी के अधीन था। अम्बाजी ने दुंदेलगड का कुछ भाग अपने लिए लेकर ग्वालियर का किला और उसके ग्राम-ग्राम की भूमि अंगरेजों को देना स्वीकार कर लिया।<sup>२</sup> निन्धिया के साथ यह सबसे बड़ा विचारमंशन किया गया।



दुंदेलगड के गोमाई

उत्तरी भारत की रक्षा के लिए ग्वालियर निन्धिया का मुख्य स्थान था। यहाँ उसका सबसे मजबूत किला था, जिसमें सर सेनिक नाम्नी रहता था। गुजरात के समय में उदा राजकुमारों को बंद करने के लिए यह किला काम

में लाया जाता था। नील और कपड़े का यहाँ अच्छा व्यापार होता था। वास्तव में दक्षिण की ओर से भारत का यह मुख्य द्वार था। विश्वामघाती अम्बाजी की आजा न मानकर भी यहाँ के किलेदार ने इसकी रक्षा करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसकी क्या चल सकती थी। अन्त में यह किला भी अंगरेजों के हाथ में आ गया।

**उड़ीसा पर अधिकार—**इलाहाबाद की सन्धि में उड़ीसा की दीवानी अंगरेजों को मिल गई थी, परन्तु दो जिलों को छोड़कर बाकी प्रान्त भोसला के हाथ में था। मराठों को न छेड़ना क्लाइव की नीति थी। मन् १७६७ में पूरा उड़ीसा मिल जाने पर कम्पनी ने १३ लाख रुपया चाँय देना भी स्वीकार किया था, परन्तु भोसला के बकील उदयपुरी गोसाईं ने उड़ीसा देने से इनकार कर दिया था। उन दिनों उड़ीसा में नित्य दुर्भिक्ष न पड़ा करते थे। गेहूँ रुपये का ७० सेर तक मिलता था।<sup>१</sup> मेजर थोर्न लिखता है कि खेती की दशा बहुत अच्छी थी। कटक प्रान्त में पगडियो के लिए बड़ी बढ़िया तजेब बुनी जाती थी।<sup>२</sup> पूर्व की ओर बालासोर में अंगरेजों ने अपनी पहली कोठी खोली थी। बंगाल और मद्रास के प्रान्तों को एक में मिलाने तथा मार्ग में किसी प्रकार की बाधा न रखने के लिए कटक का लेना बड़ा आवश्यक था। इसी उद्देश्य से इस अवसर पर बंगाल, मद्रास तथा समुद्र तीनों ओर से उड़ीसा पर आक्रमण किया गया। सबसे पहले जगन्नाथ जी के पड़ों को मिलाकर पुरी पर अधिकार कर लिया गया। मन्दिर पर हिन्दू सिपाहियों का पहरा रख दिया गया और वहाँ के प्रबन्ध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया गया। जनता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और अंगरेजी सेना को उससे बराबर सहायता मिलने लगी। बहुत से जमीन्दार भी अंगरेजों से मिल गये। बालासोर और कटक के जीतने में कोई विशेष

<sup>१</sup> जर्नल ऑफ दि एशियाटिक सोसायटी बंगाल, जि० ५२ पृ० २४८।

<sup>२</sup> थोर्न, मेम्वार्यर्स, पृ० २५४-५६।

कठिनाई न हुई। उन्हीमा पर अधिकार हो जाने में उस ओर से भोग्यता के राज्य पर आक्रमण करने में भी सुभीता हो गया।

**उत्तरी भारत की लड़ाइयाँ—**माहादजी गिन्धिया दक्षिण जाते समय दिल्ली और उसके आस-पास का राज्य फ्रांसीसी अफसर डीबोयन को सौंप गया था। जब डीबोयन चला गया तब उसकी जगह पर पेरा नियुक्त किया गया। सेना का खर्च चलाने के लिए दोआब के कुछ जिले पहले ही से दे दिये गये थे। पेरा यहाँ बड़े डाट-बाट में रहता था। राजाओं और सरदारों से गन्धि तथा युद्ध करने के उसे पूरे अधिकार थे। दोलतराव गिन्धिया को दक्षिण के भागों में ही रुकनी पड़ी, इसलिए उत्तर का राज्य उसने बिलकुल पेरा के हाथ ही में छोड़ रखा था। उसकी कुछ सेना दिल्ली में बृद्ध शाहआलम की रक्षा के लिए रहती थी, कुछ सेना गिन्धिया के साथ थी और बाकी सेना का पठाव अलीगढ़ में था। पेरा की जागीर को बेल्लेजनी जसुना-नट पर “फ्रांसीसी का राज्य” कहा करता था। इसमें उसका सारा भय रहता था और जब से वह भारतवर्ष आया था, उसमें नष्ट खर्च में प्रयत्न में लगा था।

**कोयल और अलीगढ़—**युद्ध छिटकने के पहले ही बेल्लेजनी ने उत्तरी भारत में पूरा प्रबन्ध कर लिया था। अन्धे दादशाह की तरह तमक की आगाएँ दिलाई गईं। मिर्खे को उदासीन रखने के लिए चष्टा की गई और राजपूतों तथा गजरो को अपने पक्ष में मिलाने के लिए भी बड़ा उद्योग किया गया। गिन्धिया के विदेशी सैनिक अफसरों को फँसने में जोर देकर उठा न रखा गया। नाबरी छोड़कर अपने देश को वापस जाने के लिए पेरा को बहुत से लालच दिये गये। इन सब बातों की सफलता से बेल्लेजनी को उत्तरी भारत के युद्ध में बहुत कुछ सहायता मिली। लटार्ड छिटकने के समाचार मिलने पर सेनापति लेक कानपुर से आगे बढ़ा। कोयल जीवने में उसको कोई विशेष बख्तिता न हुई। ता० २६ अगस्त के पत्र में वर गवर्नर-जनरल को लिखता है कि पेरा की एक पलटन के कुछ अफसर पकड़े गये।





अवसर पर मिन्धिया की ढाई हजार सेना हमसे मिल गई।<sup>१</sup> आगरा का किला जीतने में कोई विरोध कठिनाई नहीं हुई।

**लासवाड़ी की लड़ाई**—मिन्धिया की बची-बूची सेना आगरा में कुछ दूर लामवाड़ी नामक स्थान पर पड़ी हुई थी। बिना योग्य नेताओं के इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही थी। परन्तु जब लेक ने इस पर आक्रमण किया, तब यह बड़ी वीरता से लड़ी। स्वयं लेक लिखता है कि ये सैनिक “भूतों की तरह” लड़े, यदि इनका कोई फ़ार्मीमी सेनानायक होता तो जीतना वरिष्ठ हो जाता। जीवन भर में मुझे कभी ऐसी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ी थी।<sup>२</sup> इस लड़ाई में उत्तरी भारत का युद्ध समाप्त हो गया। लामवाड़ी की विजय के लिए बधाई देने हुए शाहजहाँ ने लेक को गिनत भेजी, जिसको हमने एक दरबार में सम्मान के साथ प्रदत्त किया। हमी के बाद अलवर, जयपुर और जोधपुर के राजाओं के साथ सन्धियाँ की गईं, जिनमें अंगरेजों ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया। बेगम समर की सेना भी मिन्धिया का साथ छोड़कर दक्षिण में वापस आ गई। हमसे साथ भी सन्धि कर ली गई।

**देवगाँव और अर्जुनगाँव की सन्धियाँ**—इस तरह सशस्त्र शक्ति नष्ट हो जाने पर भोसला और मिन्धिया ने दिग्गदर सन्धि १८०३ में सन्धि करना स्वीकार कर लिया। देवगाँव की सन्धि में भोसला ने बटार तथा अन्य कई स्थान अंगरेजों को दे दिये और वरार के कुछ जिले पर नियाम का अधिकार मान लिया। अंगरेजों से गज्रता रखनेवाले किसी देश के निवासी को नौकर न रखने का भी हमने वचन दिया। अर्जुनगाँव की सन्धि में मिन्धिया को दोश्याब के सब जिले अंगरेजों को देने पड़े। शाहजहाँन और राजपूत राजाओं पर भी हमका किसी प्रकार का अधिकार न रहा। गुजरात में भौराच और दक्षिण में अहमदनगर तथा अन्य कुछ स्थान अंगरेजों को मिल गये। मिन्धिया ने भी अंगरेजों से गज्रता रखनेवाले किसी देश के निवासी को

<sup>१</sup> बेल्लेवली, ऐन्थोपचज डि० २, पृ० १००।

<sup>२</sup> वही, पृ० ११०-१११।

नौकर न रखने का वचन दिया और पेगवा तथा निजाम के साथ कोई झगडा होने में अँगरेजों को पच मान लिया।

गवर्नर-जनरल इन दोनों को भी सहायक सम्बन्ध के जाल में बाँधना चाहता था, परन्तु आर्थर वेलेजली इसके विरुद्ध था। उसने अच्छी तरह समझ लिया था कि सिन्धिया का अधिक दवाना असम्भव है। गवर्नर-जनरल को इन सन्धियों में सन्तोष न था। वह इनकी शर्तों का मनमाना अर्थ लगाकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता था। उसकी इस नीति में आर्थर वेलेजली भी तग आ गया था। स्वालियर का वापस न करना और देवगाँव की सन्धि के पहले छोटे छोटे जमीन्दारों के साथ जो जगती समझौते हुए थे, उन पर जोर देना उसकी राय में गवर्नर-जनरल की मर्रासर जबर-दस्ती थी। वह स्पष्ट शब्दों में लिखता है कि गवर्नर-जनरल जिसको “नम्रता” कह रहा है, दूसरों की दृष्टि में उसी का नाम “महत्वाकांक्षी” है। उसको अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ गया है। कलकत्ते में डर की वजह से उसको कोई उचित सलाह देनेवाला नहीं है। देशी राजाओं के साथ नम्रता का व्यवहार करने ही से हित हो सकता है।<sup>१</sup> वेलेजली इन बातों को कब सुनने-वाला था ? जून तक फरवरी सन् १८०४ में सिन्धिया के साथ दूसरी सन्धि नहीं हो गई, उसको सन्तोष नहीं हुआ। भोसला के दरबार में भी रेजीडेंट रस दिया गया और घूस देकर सब भेदों का पता लगाये रखने की उसको पूरी ताक़ीद कर दी गई।<sup>२</sup>

**मराठों की हार के कारण**—इन दिनों आपस ही में फूट थी, पहले से युद्ध की कोई तैयारी न थी, विदेशी अफसरों ने धोखा दिया था, इन सब का उल्लेख किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि मराठों ने अपनी युद्ध-पद्धति छोड़कर कवायदी ढंग से काम लेने और पैदल सेना पर अधिक जोर देने में बड़ी भूल की। एक मराठा लेखक का कहना

१ वेलिंगटन, टेसपैचेज, पृ० ३६९-७०, ३९७, ३९९।

२ वही, पृ० ३५८-६०।

हं कि “तिस दिन मराठों ने घोटों की मचारी छोड़ी उसी दिन उनका राज्य भी चला गया” । आर्थर वेलजली का भी कुछ ऐसा ही मन था, वह अपने भाई गवर्नर-जनरल की इस बात को पसन्द न करता था कि मराठा यूरोपियन आफसर न रहें । उसका कहना था कि पुराने ढंग की घोड़मवार मराठी सेना से लड़ना सहज नहीं है ।<sup>१</sup> किसी अंश में यह बात ठीक है । परन्तु अपने ढंग से लड़ाई लड़कर अन्त में मराठों की विजय हुई होती, इसमें बहुत सन्देह है । युद्ध के नये माधनों को स्वीकार करने में भूल न थी, वाम्ब में भूल थी विदेशी सरदारों के रहने में । माहादजी के समय में डिशेयन का जो प्रभाव और उपयोग था, वह डालनराव सिन्धिया के समय में न रहा था ।

**होलकर के साथ युद्ध—**ग्रिटि होलकर ने पूना पर आक्रमण न किया होता, तो बहुत सम्भव था कि पेशवा आंगरेजों की सरकार से न जाना । होलकर को इसका कुछ सन्देह भी न था । वह आक्रमण के पहले आग राद में भी पेशवा को अपनी मित्रता का प्रि/वाय दिला रहा था आग उसकी रक्षा करने के लिए तयार था । उसको जलन केंद्रल सिन्धिया से भी निम्न पेशवा खुले तार पर पक्षपात करता था । घेमीन की सन्धि हो जाने पर जोगता इन दोनों में मेल कराना चाहता था, परन्तु आंगरेजों की मुक्ति नीति के सामने उसका कुछ भी न चली । मराठों के परस्पर वैर में लाभ स्थान के पेशवा की मुख्य नीति थी । वह पहले ही से सिन्धिया को दबाये रहने के लिए होलकर को जिस तरह सम्भव हो सिलाये रहने का प्रयत्न कर रहा था । पेशवा आंगरेजों का मित्र था । जिस समय होलकर ने पूना पर आक्रमण किया, आंगरेज रेजीडेंट वहाँ मौजूद था, परन्तु उसने किसी तरह का विरोध प्रकट नहीं किया । आक्खवार राज्य पर आक्रमण करने के लिए टीपू के साथ युद्ध छेड़ दिया गया था, परन्तु कम्पनी के परम मित्र निजाम के राज्य में आक्खवार लूटने के लिए होलकर को उठ देना तो दूर रहा, स्पष्ट नीति के विरोध न

नहीं किया गया। इस तरह एक ओर तो होलकर को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न किया गया और दूसरी ओर गुप्त रीति में उसके मुख्य सेनानायक श्रीरामजी को फोड़ने में कोई कसर उठा न रखी गई। होलकर अंगरेजों की इन चालों को समझ न सका। वह किसी न किसी तरह सिन्धिया का नाश देखना चाहता था, इसी लिए वह युद्ध में चुपचाप रहा।

होलकर की यह बड़ी भूल थी। यदि इस अवसर पर उसने सिन्धिया और भोसला का साथ दिया होता, तो अंगरेजों का इस तरह विजय पाना सहज न था। उन दोनों के हारने पर उसकी आँखें खुलीं। अंगरेजों की विजय में उसका कोई लाभ भी नहीं हुआ और मराठों की शक्ति नष्ट हो गई। जिस तरह अथ सिन्धिया, भोसला और पेशवा के साथ व्यवहार किया जा रहा था, उसे देखकर होलकर को अपने लिए भी चिन्ता होने लगी। अपना सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए वह कुछ प्रश्नों को समझौता द्वारा निपटाना चाहता था। उसका कहना था कि चौध वसूल करना मेरा पुराना अधिकार है, उसमें अंगरेजों को हस्तक्षेप न करना चाहिए और दोआब, बुंदेलखंड तथा दक्षिण की कुछ भूमि को, जो मेरे पूर्वजों के पास थी, वापस कर देना चाहिए। ऐसा करने से वह सिन्धिया के ढंग की सन्धि करने के लिए तैयार था।

परन्तु विजय की उमंग में अंगरेज उसकी इन बातों को कब सुननेवाले थे? अपना काम निरुल जाने पर यह कहा जाने लगा कि वह तो गद्दी का अधिकारी तक नहीं है, वास्तव में गद्दी उसके भाई काशीराव को मिलनी चाहिए। अंगरेजों के अधीन जयपुर के राजा पर वह आक्रमण करने का विचार कर रहा है, समरूपेगम तथा रुहेलों को अपने पक्ष में मिलाने के प्रयत्न में लगा हुआ है और हिन्दू तथा मुसलमानों को अंगरेजों के विरुद्ध भड़का रहा है। जब होलकर ने देखा कि समझौते की कोई आशा नहीं है, तब उसने अपनी सेना के तीन अंगरेज अफसरों को, जो उसकी नौकरी छोड़कर सेनापति लेकर मिलना चाहते थे, मरवा डाला। वह सिन्धिया की सी भूल करनेवाला न था, उसको विदेशियों पर कभी विश्वास न था। उसका यह कार्य भी अंगरेजों प्रति शत्रुता के भावों का प्रमाण समझा जाने लगा।

युद्ध के लिए समय उपयुक्त न था। इसके अतिरिक्त अपनी ओर से लड़ाई छेड़ने के दोषारोपण से भी गवर्नर-जनरल बचना चाहता था। इसलिए कुछ दिना तक मन्त्रि की बातचीत होती रही। परन्तु सेनापति लेकर तो लड़ाई के लिए कमर कसे चंडा था। वह लिखता है कि “मुझे किसी न इतना परेशान नहीं किया जितना कि यह शंकान कर रहा है।” जब तक हम “लुटेरे” की शक्ति नष्ट नहीं की जायगी, भारतवर्ष में शान्ति स्थापित होना असम्भव है।<sup>१</sup> हमकी बात मानकर, अप्रैल मन् १८०४ में, गवर्नर-जनरल न होलकर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी।

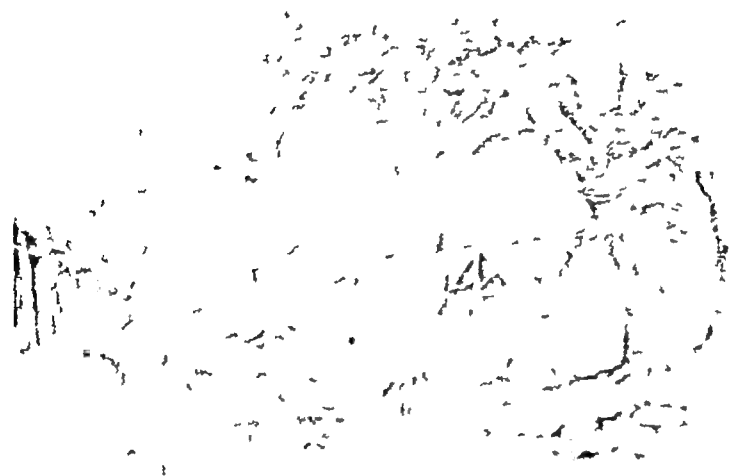
**आर्थर वेलेजली का मत—**आर्थर वेलेजली की दृष्टि में भी होलकर बेचल एक “लुटेरा सरदार” ही था, परन्तु हम अवसर पर हमके साथ युद्ध करने का वह पक्षपाती न था। हमकी राय में होलकर “मराठों में सबसे अधिक शक्तिशाली” था। श्रृंगरजों की सेना पिछले युद्ध में घकी हुई थी। होलकर की सेना में गिन्धिया तथा भोगला के बहुत से सिपाही मिल गये थे। धन की भी बसी थी। सब रणया युद्ध में सर्वे हा जान स रमरनी के संगानक वेलेजली की नीति से असन्तुष्ट हो रहे थे। गिन्धिया तथा भोगला सिपाही तब से छुटपटा रहे थे और बदला निवादन के लिए प्रवसर ताक रहे थे। गवर्नर जनरल सन्धियों का मनमाना आर्थ लगाकर इन दोनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था कि जिससे इन दोनों से किसी प्रकार की सहायता मिलन की सम्भावना न थी। उलटे होलकर के पक्ष में इन दोनों के मिल जात का प्रयास भय था। दक्षिण में दुर्भिक्ष पट रहा था। ऐसी दशा में दोनों राजाओं के साथ नम्रता की नीति का अनुसरण करके इनको सन्तुष्ट करना ही उचित था। परन्तु सेनापति लेकर गवर्नर-जनरल को दगावर दृष्टि दे रहा था। विजय के मद में वास्तविक स्थिति का हमको ज्ञान न था और न हम समय उसका बार्ह रूप नलाए ही देनेवाला था। आर्थर वेलेजली की सन्धि

राय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सन्धियों के समय से ही दोनों भाइयों में मतभेद था। युद्ध या सन्धि करने का पूरा अधिकार इस बार लेकर को दिया गया। आर्थर वेलेजली की एक एक बात सच निकली। यदि उसकी राय मानी गई होती, तो इस युद्ध में अंगरेजों की जैसी कुछ दुर्दशा हुई, न हो सकती।

**युद्ध का प्रारम्भ**—इस युद्ध में भी दक्षिण, गुजरात और उत्तरी भारत में तीनों ओर से होलकर पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया गया। पूर्ण सहायता देने के लिए सिन्धिया को लिखा गया और पंजाब में मिर्जा को शान्त रखने का भी प्रयत्न किया गया। पहले तो कोई अड़चन न पड़ी और उत्तरी भारत में होलकर के मुख्य स्थान रामपुरा पर अधिकार कर लिया गया। इस पर वह मालवा की ओर हटने लगा। उसका पीछा करने या बरसात भर आगे न बढ़ने की आर्थर वेलेजली ने मलाह दी, पर सेनापति लेकर ने, उसकी बात न मानकर, कर्नल मानसन को होलकर का मार्ग रोकने के लिए भेज दिया। इतने ही में समाचार मिला कि बुंदेलखंड की रक्षा के लिए जो अंगरेजी सेना थी, उसको अमीरखां ने लूट लिया और बहुत सी तोपें छीन लीं। अंगरेजों के बहुत कुछ लालच देने पर भी उसने होलकर की नौकरी छोड़ी नहीं। इस समय तक अंगरेजी सेना की बराबर विजय होती रही थी, यह एक ऐसा धक्का लगा, जिसकी गवर्नर-जनरल को कभी सम्भावना नहीं थी। वह लिखता है कि ब्रिटिश सेना के लिए यह बड़ी लज्जा की बात थी, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई थी। इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा यह अनुमान करना कठिन है।<sup>१</sup>

दूसरी ओर कर्नल मानसन की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। वह एक सेना लेकर चम्बल की ओर इस आशा से बढ़ रहा था कि मालवा की तरफ से कर्नल मरे आ रहा होगा। परन्तु जब वह मुकुन्दरा पहुँचा तब उसको पता लगा कि होलकर के पड़ाव का समाचार पाकर कर्नल मरे गुजरात लौट गया। होलकर पर अकेले आक्रमण करने का मानसन को साहस न हुआ, रसद भी चुक गई, इस

पर वह पीछे हटने लगा। होलकर के मवार अवसर पाकर भागती हुई अंगरेजी सेना पर दृढ़ पड़े। उन्होंने रमद लूट ली और मारी सेना को छिन्न-भिन्न कर



### मुकुन्दरा

दिया। बची हुई सेना बेतहाशा भाग निकली। इनके हाथों में अस्त्र-प्रारम्भ हो गई और नदियों का पार करना मुश्किल हो गया। ईर नेम मानसून रामपुरा पहुँचा। यहाँ हमको कुछ और सेना मिली परन्तु भी हमें सैन्य पर आक्रमण करने का साहस न हुआ।

**भरतपुर का घेरा—**होलकर की सफलता देखकर उसका दल धीरे धीरे बढ़ने लगा। सिन्धिया और पेशवा को गवर्नर-जनरल अपने पत्र में किसी न किसी तरह मिलाये रखना चाहता था। होलकर के जीते हुए राज्य को उसने उन्हीं दोनों में बाँट देने तक का वचन दे दिया था। पहले सिन्धिया ने भी अंगरेजों की सहायता के लिए एक सेना भेजी, परन्तु अब यह सेना होलकर से मिल गई। सिन्धिया ने अपने एक अंगरेज अफसर को कैद कर दिया और वह खुले तौर पर होलकर की सहायता करने का विचार करने लगा। मध्य भारत के कुछ राजा भी अंगरेजों के व्यवहार से असन्तुष्ट थे और होलकर का साथ देने के लिए तैयार थे। इनमें सबसे मुख्य भरतपुर का राजा रण-जीतसिंह था। यह पहले सिन्धिया के अधीन था, परन्तु युद्ध छिड़ने पर इसने अंगरेजों के साथ सन्धि कर ली थी। अब वह अंगरेजों के व्यवहार से बहुत असन्तुष्ट हो रहा था। उसके शासन में किसी तरह का हस्तक्षेप न करने का वचन दिया गया था, पर अंगरेज इसके लिए बराबर प्रयत्न कर रहे थे और उसके राज्य में अपनी अदालतें खोलना चाहते थे। तीर्थस्थानों में भी गोवध करने में अंगरेजों को संकोच न होता था। इससे हिन्दू जनता बड़ी चिन्तित हो रही थी। अंगरेजों के विरुद्ध भरतपुर के राजा को यह बड़ी भारी शिकायत थी।<sup>१</sup>

होलकर ने पहले मथुरा पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली छीनने का भी प्रयत्न किया, पर लेक के बढ़ने का समाचार पाकर वह आगरे की तरफ हट गया। मानसून की हार से लेक मुँकला गया था और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। होलकर अपनी घोड़सवार सेना के साथ फतेहगढ़ के निकट पड़ा हुआ था। लेक ने उस पर सहसा आक्रमण कर दिया। उसके पहले से इसका कुछ पता भी न था। वहाँ से बढ़कर लेक ने डीग के किले पर, जहाँ पहले ही से युद्ध हो रहा था, अधिकार कर लिया। भरतपुर का पहला राजा सूरजमल डीग ही में रहता था। थॉर्न लिखता है कि यहाँ का



बिला उठा दूर बना हुआ था। दमक पास ही राजा का मुन्दर मकल जग  
विशाल दघान था।



राग व रंगार

की हिम्मत ऐसी टूटी हुई थी कि उनसे आगे बढ़ा न जाता था, इस पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने आगे बढ़कर अपने साहस का परिचय दिया।<sup>१</sup> इन धावों में लगभग तीन हजार अंगरेजी सैनिक मारे गये। अन्त में लेक को इस किले के लेने का विचार छोड़ना पड़ा। सुरंग और तोपों से किले को तोड़ने का जो ढंग है, उससे काम न लेकर बार बार धावा करने में सेनापति लेक ने अपना हठ दिखाया। यदि ऐसा न किया जाता तो सम्भव था कि अंगरेजों की इतनी हानि न होती। इसके बाद ही सन्धि की बात-चीत होने लगी। एक छोटे से राज्य के लिए अंगरेजों की शक्ति से अधिक दिनों तक टक्कर लेना असम्भव था। दूसरे होलकर की भी हार हो रही थी। बीस लाख रुपया राजा से हरजाना माँगा गया, पर उसने तीन लाख से अधिक नहीं दिया। अंगरेजों ने उसको डींग भी वापस कर दिया और जैसे तैसे इस मामले को, जिससे उनकी चारों ओर बदनामी हो रही थी, समाप्त किया।

**वेलेजली की वापसी**—कम्पनी के संचालकों और वेलेजली में बहुत दिनों से मतभेद चल रहा था। वे लोग रुपया चाहते थे, वेलेजली शान चाहता था। जहाँ वे बचत करना चाहते थे, वहाँ वह खर्च करना चाहता था। वे लोग प्रत्येक कार्य को आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखते थे, पर वेलेजली को रुपये की पर्वाह न थी, उसे किसी न किसी तरह साम्राज्य का निर्माण करना था। इस मतभेद के कारण दोनों में जरा जरा सी बात पर झगडा होता था। वेलेजली ने उनसे बिना पूछे ही अपने दोनो भाइयों को बड़े बड़े ओहदे दे दिये थे, फोर्ट विलियम कालेज खोल दिया था, कलकत्ते में गवर्नर-जनरल के रहने के लिए शानदार कोठी बनवा ली थी और अवध का मामला भी अपने मनमाने ढंग से निपटा लिया था। उसकी इन सब बातों से संचालक बहुत चिढ़ रहे थे। निजी व्यापार के सम्बन्ध में भी दोनों की राय एक न थी। इंग्लैंड की सरकार वेलेजली के पक्ष में रहती थी, इसलिये वह संचालकों की कुछ भी पर्वाह न करता था। खुले तौर पर वह उनकी आज्ञाओं

का उल्लंघन करता था और उनको 'त्रितिया' कहकर सदा उनका निरस्कार किया करता था।

ब्रेमीन की सन्धि से हैंग्लेट-सरकार को भी समझी नीति में सन्देह होन लगा था। मिन्धिया और भोगला के साथ युद्ध में विजय होने पर यह सन्देह कुछ काल के लिए दब गया और समझी बटी प्रशंसा की गई। सचालको ने भी समझी बधाई दी, पर साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के व्यापमान होने में उनको सन्देह है। उनकी हृम्य "अनुनादना" में वेलेजली बहुत चिढ़ गया। वह पहले दो बार हम्मीफा दे चुका था, लेकिन कैमन्री के समझाने-बुझाने पर ठहरा हुआ था।

परन्तु सन् १८०४ की दुर्घटनाओं में यह स्थिति एकदम बदल गई। अब हैंग्लेट-सरकार को भी समझी समर्थन करना कठिन हो गया। कम्पनी का ऊर्जा दुगुना हो गया था। उन्हें का कोई अन्त न था, मरना जानी था, युद्ध के शीघ्र समाप्त होन की आशा न थी, हालांकि लगातार यह रहा था और मिन्धिया भी युद्ध की तैयारी कर रहा था। ब्रेमिन्स, मनमाना नियुक्ति और बार बार आजा उल्लंघन करने के लिए संचालक समझी नीति पर गत थे। वेगविल की बैठकों में अनुपस्थित रहना 'दार्त' गोप बर्तन' की शपथ भी अनुचित था। आर्थर वेलेजली और जनरल ह्यूम्स को समझी तथा युद्ध के पूर्ण अधिकार दे देना चाहते की दृष्टि में नियम-विन्यस्त था।



का उल्लंघन करता था और उनको “वनिया” कहकर सदा उनका तिरस्कार किया करता था।

बेसीन की सन्धि से इंग्लैंड-सरकार को भी उसकी नीति में सन्देह होने लगा था। सिन्धिया और भोसला के साथ युद्ध में विजय होने पर यह सन्देह कुछ काल के लिए दब गया और उसकी बड़ी प्रशंसा की गई। संचालको ने भी उसको बधाई दी, पर साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के न्याय-सगत होने में उनको सन्देह है। उनकी इस “अनुदारता” से बेलेजली बहुत चिढ़ गया। वह पहले दो बार हस्तीफा दे चुका था, लेकिन कैसलरी के समझाने-बुझाने पर ठहरा हुआ था।

परन्तु सन् १८०४ की दुर्घटनाओं से यह स्थिति एकदम बदल गई। अब इंग्लैंड-सरकार को भी उसका समर्थन करना कठिन हो गया। कम्पनी का कर्जा दुगुना हो गया था, खर्च का कोई अन्त न था, खजाना खाली था, युद्ध के शीघ्र समाप्त होने की आशा न थी, होलकर बराबर लड़ रहा था और सिन्धिया भी युद्ध की तैयारी कर रहा था। बेहद खर्च, मनमानी नियुक्ति और बार बार आज्ञा उल्लंघन करने के लिए संचालक उसकी निन्दा कर रहे थे। कैसिल की बैठकों में अनुपस्थित रहना ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ की राय में भी अनुचित था। आर्थर बेलेजली और जनरल स्टुअर्ट को सन्धि तथा युद्ध के पूर्ण अधिकार दे देना बहुतों की दृष्टि में नियम-विरुद्ध था। मानसन की दुर्दशा का समाचार मिलने पर संचालको ने उसको वापस बुलाना निश्चित कर लिया। बेलेजली के सबसे बड़े समर्थक, इंग्लैंड के प्रधान सचिव, पिट की भी राय थी कि गवर्नर-जनरल “बिना कुछ सोचे विचारे विलकुल नियम-विरुद्ध काम कर रहा है, अब उसके हाथ में शासन रखना ठीक नहीं है।” बेलेजली भी किसी तरह जाना चाहता था, इंग्लैंड-सरकार को वह लिख भी चुका था। परन्तु उसके पत्र पहुँचने के पहले ही लार्ड कार्नवालिस दूसरी बार भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल नियुक्त कर दिया गया। ता० ३० जुलाई सन् १८०५ को वह कलकत्ता पहुँचा और १५ अगस्त को बेलेजली इंग्लैंड वापस चला गया।

टामस मनरो, जो वेलेजली के समय में इस नीति का पक्षपाती<sup>६०</sup> में लिखता है कि जिस राज्य में रक्षा के लिए सहायक सेना उसका राजा निर्बल और अत्याचारी हो जाता है। समाज में आत्म-सम्मान के भाव नष्ट हो जाते हैं और साधारण प्रजा दरिद्र तथा पतित हो जाती है। पहले राजा को प्रजा का कुछ भय रहता था, परन्तु रक्षा के लिए अंगरेजी सेना मिल जान से, वह निश्चिन्त होकर भोग-विलास में पड़ जाता है और प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करने लगता है। इन सन्धियों में जो शर्तें रखी जाती हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करना असम्भव है। भारतवासियों में आत्म-सम्मान का भाव एकदम नष्ट नहीं हो गया है। वे चुपचाप अपमान को सहन न करेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि उनके राज्य कर्नाटक की तरह जन्त कर लिये जायेंगे। यह रक्षक नीति भूचक का काम करेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाय कि इससे शान्ति स्थापित हो जायगी, तब भी यह कहना पड़ेगा कि इसके लिए स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और मनुष्य को उच्च बनानेवाले सभी भावों का बलिदान करना पड़ेगा। इस तरह भीतरी फूट फैलाकर राज्यों के अपहरण करने से लड़कर जीत लेना कहीं अच्छा है।<sup>१</sup>

मिडनी ओयन का भी ऐसा ही मत था। वह लिखता है कि राज-सत्ता के जो वास्तविक चिह्न हैं, उनके छीन लेने से किसी राजा में अच्छा शासन करने का सम्भाव नहीं रह जाता है। वह विषयी हो जाता है और प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। इस प्रथा से वास्तव में “राज्य की रीढ़ टूट जाती है” और राजनैतिक जीवन चला जाता है। ऐसी दशा में उनको ब्रिटिश राज्य में मिला लेने के अतिरिक्त शासन के सुधार का कोई उपाय नहीं रह जाता है।<sup>२</sup> केवल सेना हाथ में न होने से राजाओं में ये दोष क्यों आ जाते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में विल्यम लिखता है कि “जब जिम्मेदारी

<sup>१</sup> अवैयनट, मेलेक्विस फ्राम दि मिनिट्स ऑफ सर टामस मनरो, पृ० ११४-१५।

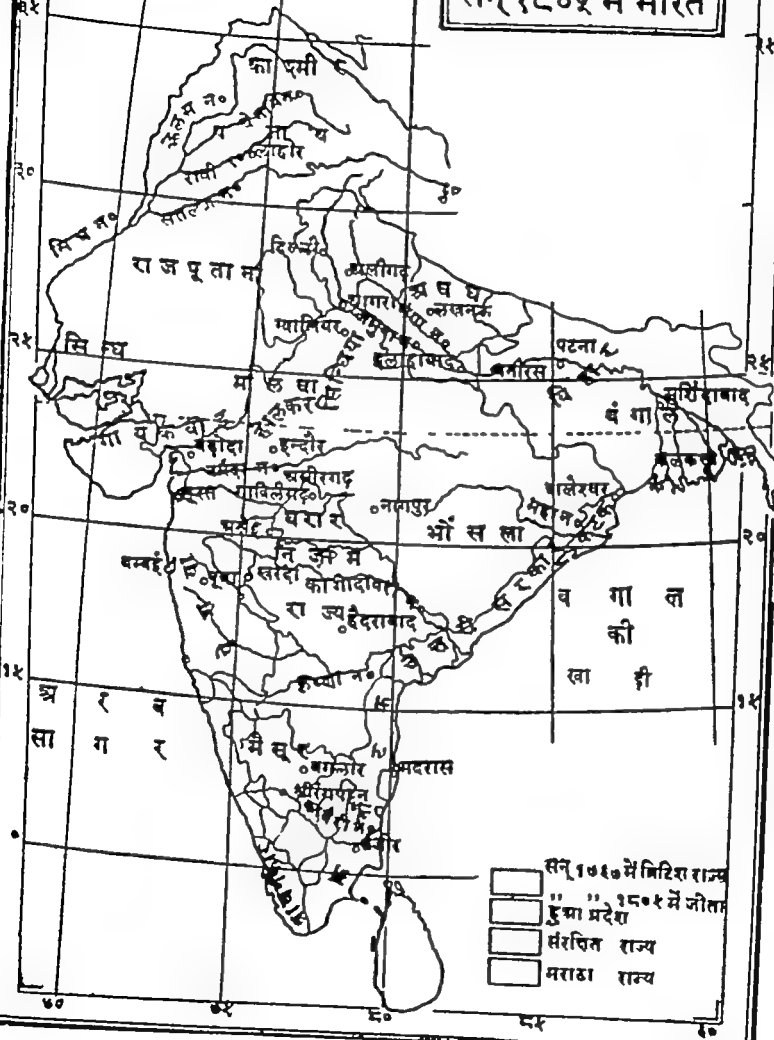
<sup>२</sup> वेलेजली, टेम्पेवेज, स० ओयन, भूमिका, पृ० ७७-७८।

सहायक प्रश्न रक्षा के लिए निश्चितता हो जाती है, तब अच्छे काम करने सहायक मन्त्रियों नष्ट होती हैं, या नष्ट हो जाती हैं और व्यक्तिगत सुख में चिर अंगरेजों की रुचि उत्पन्न हो जाती है” ।<sup>१</sup>

आर्थर वेलेजली भी इन मन्त्रियों के पक्ष में न था। उसकी राय में इनका एक और बुरा परिणाम हुआ। राजाओं की निजी सेनाएँ टूट जाने से बहुत से सैनिक बेकाम हो गये और वे लूट-पाट मचाने लगे। उसने गवर्नर-जनरल को इसके समझाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर इन लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया।

**वेलेजली का उद्देश्य**—उसका उद्देश्य और उसकी नीति पहले से निश्चित थी। घटनाओं के अनुसार अपनी नीति स्थिर करने की उसके लिए कोई आवश्यकता न थी। उसे तो किसी न किसी तरह घटनाओं को खींच-तानकर अपनी नीति के अनुसार लाना था। जो अधीन राज्य थे, उनमें हस्त-क्षेप करने के लिए शासन ठीक न होने का बहाना था। जो स्वतंत्र राज्य थे, उनको अधीन बनाने के लिए जर्माशाह और फ्रांसीसियों के भय का दिखावा था। सारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य था। परन्तु इसको छिपाकर जय कहा जाता है कि भारत में शान्ति स्थापित करना और जनता की दशा सुधारना उसका उद्देश्य था, तब उसकी नीति की विस्तृत रूप से आलोचना करने की आवश्यकता होती है। जर्माशाह और फ्रांसीसियों के आक्रमण के भय में कितना तत्त्व था, यह दिखलाया जा चुका है। अवध और कर्नाटक में शासन की जो दशा थी, उसके भी कारण दिखलाये जा चुके हैं। टीपू और मराठों को किस तरह लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। इतने पर भी हटन लिखता है कि उसको रुपये-पैसे की पर्वाह न थी। स्थायी शासन, अत्याचार से रक्षा, स्वतंत्रता तथा उन्नति के लिए भारत व्याकुल हो रहा था। कोई भी हिन्दू या मुसल

# सन् १८०५ मे भारत



- सन् १७६० में ब्रिटिश राज्य
- सन् १८०५ में जीता
- मुगल प्रदेश
- संरक्षित राज्य
- मराठा राज्य



और कमजोरियों को उसने थोड़ा ही काल में अच्छी तरह समझ लिया था। संचालकों के प्रति उसकी दृष्टता की कई एक इतिहासकारों ने निन्दा की है। महत्वाकांक्षा की मात्रा उसमें कितनी अधिक थी, यह उसके कार्यों ही में प्रकट है। परन्तु इसमें व्यक्तिगत लाभ का उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अपने भाइयों की उसको अवश्य बड़ी चिन्ता रहती थी। यश और मान की उसमें एक बड़ी भारी कमजोरी थी। अपने पद का ध्यान रखते हुए उपाधियों पर अत्यन्तोप प्रकट करना उसके लिए शोभा न देता था। वह अपने को एक व्यापारिक सस्था का सेवक न समझता था। उसको भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के शासक होने का अभिमान था। अपने बोल-चाल, रहन-सहन, सभी में वह इस बान के दिखलाने की चेष्टा करता था। तडक-भडक को वह बहुत पसन्द करता था। उसको लोग “सुलतानी अंगरेज” कहा करते थे।

साहित्य से उसको बहुत प्रेम था। अंगरेजी भाषा लिखने में वह बड़ा निपुण था। अपनी बात के समर्थन में वह दलीलों की भरमार करता था। बोलने-चालने में उसका मुकाबला करना सहज न था। व्यंग और हास्य की भी उसमें कमी न थी। स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वह काम से कभी घबड़ाता न था। उसका कहना था कि काम करने में मुझे कुछ कठिनाई अवश्य होती है, पर ये कठिनाइयाँ ही मेरे प्रतिदिन का भोजन है, जिनसे मेरे शरीर का पालन होता है।<sup>१</sup> उसका ध्यान सभी ओर रहता था। भारतवर्ष के पशु-पक्षियों का अध्ययन करने के लिए उसने डाक्टर बुकानन को नियुक्त किया था। उसी की सहायता के लिए वारिकपुर में पशुओं का अज्ञा यत्रघर बनवाया गया। कलकत्ता नगर की शोभा बढ़ाने के लिए बेल्लेजली बराबर चिन्तित रहता था। शहर की सफाई और सड़कों के प्रबन्ध के लिए उसने एक योजना तैयार की थी। कलकत्ता का विशाल और सुन्दर ‘सरकारी भवन’ उसी का बनवाया हुआ है। इंग्लैंड जाकर वह बहुत दिनों तक जीवित रहा। उस पर भी अभियोग चलाने का प्रयत्न किया गया, पर सफ

<sup>१</sup> हटन, बेल्लेजली, पृ० १९६।

लता न हुई। बाद में कम्पनी के मंचालको ने भी उसकी योग्यता को स्वीकार किया। भारतवर्ष में उसकी एक मूर्ति स्थापित करने की आज्ञा दी



कलकत्ता का सरकारी भवन

गर्ह और २० हजार पाँड़ उसको भेंट किये गये। सन् १८४२ में उसका देहान्त हुआ।

## परिच्छेद ६

### मराठों का पतन

नीति में परिवर्तन—इंग्लैंड की सरकार और कम्पनी के संचालक दोनों वेलेजली की नीति से तंग आ गये थे। खजाना खाली हो रहा था और लडाइयों का कोई अन्त न था। वे किसी न किसी तरह भारतवर्ष में शान्ति स्थापित करना चाहते थे। यह कार्य वृद्ध कार्नवालिस को सौंपा गया। ६७ वर्ष की अवस्था में वह दूसरी बार गवर्नर-जनरल होकर जुलाई सन् १८०५ के अन्त में भारतवर्ष पहुँचा। इस समय सिन्धिया को किसी तरह युद्ध से अलग रखना था। उसके साथ सबसे बड़ा झगडा ग्वालियर और गोहद का था। पिछले युद्ध में इन दोनों स्थानों पर अधिकार कर लिया गया था और अर्जुनगाव की सन्धि हो जाने पर भी ये स्थान उसको वापस नहीं किये गये थे। आर्थर वेलेजली की राय में गवर्नर-जनरल की यह सरासर जबरदस्ती थी। सिन्धिया के कुछ सरदारों को १६ लाख रुपया साल की पेंशन देना भी निश्चित हुआ था। इसके हिसाब में भी झगडा पड रहा था। इन सब बातों से चिढ़कर सिन्धिया ने नायब रेजिडेंट को निगरानी में रख छोड़ा था और होलकर से मेल करने का प्रयत्न कर रहा था।

इन झगडों के मिटाने के लिए कार्नवालिस ने ग्वालियर और गोहद का वापस करना निश्चित कर लिया। सन्धि के लिए वह ऐसा उत्सुक कि नायब रेजिडेंट को मुक्त करने की शर्त पर भी वह इस समय जोर उचित न समझता था। वह जमुना नदी को कम्पनी के राज्य की

पश्चिमी सीमा बनाना चाहता था। राजपूत राजाओं के झगड़े में पड़ना उसकी राय में भूल थी। वह ग़ाहग़ालम को दिल्ली में रखकर उसकी रक्षा का भार लेने का भी पक्षपाती न था। मछेरी (अलवर) और भरतपुर के साथ जो सन्धियाँ हुई थीं, उनको भी वह तोड़ देना चाहता था। उसका अनुमान था कि इस तरह कम्पनी उनकी रक्षा की जिम्मेदारी से बच जायगी और सिन्धिया उनके झगड़ों में पड़ जायगा। जीती हुई भूमि को लौटाकर वह होलकर के साथ भी सन्धि करने के लिए तैयार था। उसका कहना था कि पिछली घटनाओं से ब्रिटिश सरकार के “न्याय तथा नम्रता” पर से देशी राज्यों का विश्वास उठ गया है। मैं उसको फिर से स्थापित करना चाहता हूँ। मेरी राय में “कम्पनी के राज्य की रक्षा तथा शान्ति के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है।”<sup>१</sup>

**कार्नवालिस की मृत्यु**—सेनापति लेक की राय में कार्नवालिस का यह प्रबन्ध राजपूत तथा अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ सरासर “विश्वासघात” था। सिन्धिया के साथ युद्ध के समय पर उनको रक्षा का वचन दिया जा चुका था। अब उनको इस तरह छोड़ देना किसी तरह उचित न था। यह समझते लेक के ही किये हुए थे। अपनी बात को इस तरह जाते हुए देखकर उसे बड़ा दुख हो रहा था और वह इस्तीफ़ा देकर वापस जाना चाहता था। परन्तु कार्नवालिस अपनी बात पर तुला हुआ था। लेक का उसे पहले ही से अनुभव था। वेल्लेजली की तरह उसको पूर्ण स्वतंत्रता देकर वह युद्ध को बढ़ाना न चाहता था। उसकी राय में गवर्नर-जनरल और सेनापति के पदों को अलग अलग रखना नीतियुक्त न था। इसी लिए वह सेनापति भी बनकर आया था। भारतवर्ष में पहुँचते ही उसने युद्ध स्थगित करने के लिए लिख दिया था। सब झगड़ों को निपटाने के लिए वह कलकत्ते से उत्तरी भारत के लिए स्वयं चल पड़ा, परन्तु ता० ५ अक्तूबर को गाजीपुर ही में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अवस्था बहुत हो चुकी थी, कर्तव्यवश उसने

गवर्नर-जनरल के पद को स्वीकार किया था। भारतवर्ष पहुँचने पर उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। गाजीपुर में उसका मकबरा बना हुआ है।

कार्नेवालिस का यह विश्वास था कि मराठों के साथ अन्याय किया गया है। वह लिखता है कि होलकर एक "योग्य और शक्तिशाली" शासक था। किसी न किसी तरह गिन्धिया और भोमला के साथ युद्ध शान्त हो जाने पर उसके साथ भिडना वेल्लेजली की बड़ी भूल थी। टीपू में वह स्वयं अकारण लड़ बैठा था, परन्तु बुढापे में वह मराठों के साथ अन्याय को दूर करने के लिए चिन्तित था। आते ही उसने गिन्धिया और भोमला को महानुभूति-सूचक पत्र लिखे थे और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए वचन दिया था। साथ ही साथ उसका यह भी विश्वास था कि कम्पनी की आर्थिक दशा देखते हुए अधिक दिनों तक युद्ध का चलाना असम्भव था। वह लिखता है कि वास्तव में शासन का साधारण काम चलाने के लिए भी रुपया नहीं था। इसके लिए उसको मद्रास से रुपया मँगाना पड़ा था और चीन को जो चाँदी जा रही थी, उसे रोक लेना पड़ा था। इस लड़ाई से कम्पनी को अधिक लाभ होने की भी उसे आशा नहीं थी क्योंकि जो कुछ मिलना था, वह मिल चुका था। ऐसी दशा में उसने केवल "शान" के लिए धन का लुटाना और नरहत्या करना उचित न समझा।

इस नीति के लिए प्रायः सभी अंगरेज इतिहासकारों ने उसको बहुत बुरा-भला कहा है। कुछ का तो कहना है कि बुढापे में उसकी मति ठिकाने न थी। उन लोगों की राय में यदि वेल्लेजली कुछ दिन भारतवर्ष में और रह जाता, तो वह सबको ठीक कर देता। उन दिनों की स्थिति देखते हुए इसका विश्वास नहीं होता। होलकर पचाव अवश्य भाग गया था, पर मराठों में धीरे धीरे एका हो रहा था। वेल्लेजली के अकारण हस्तक्षेप से बहुत से राजा असन्तुष्ट हो रहे थे। फिर सबसे भारी बात तो यह थी कि कम्पनी का खजाना खाली था, २० लाख रुपया अवध के नवाब से लेकर युद्ध का खर्च चलाया जा रहा था। वेल्लेजली स्वयं इस समय जैसे-तैसे सन्धि करने के लिए तैयार हो रहा था। भारतवर्ष छोड़ते समय इस सम्बन्ध में वालों ने उसमें

परामर्श भी किया था ।<sup>१</sup> दूसरी बात यह कही जाती है कि उन राजाओं का, जिनको रत्ना का वचन दिया गया था, कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया । इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि मराठों के लूटने पर लाखों करोड़ों गरीब किसानों की क्या दशा होगी, इसका कार्नेवालिस ने कुछ भी विचार न किया ।<sup>२</sup> वचन का पालन न करना हर समय निन्दनीय है । परन्तु भारतवर्ष के इतिहास में अंगरेजों को इसका ध्यान ही कब रहा ? वेलेजली ने किस सन्धि का पालन किया ? जिस रीति से उसने सन्धियों का पददलन किया, शायद ही किसी दूसरे गवर्नर-जनरल ने किया हो । इसके लिए उसको दोष नहीं दिया जाता है, परन्तु उन सन्धियों को, जो केवल स्वार्थवश की गई थीं, तोड़ने के लिए कार्नेवालिस बड़ा दोषी ठहराया जाता है ।

**सर जार्ज बार्लो**—कार्नेवालिस के मरने पर कौंसिल का सबसे बड़ा मेम्बर बार्लो गवर्नर-जनरल हुआ । मराठों से युद्ध करने के लिए वेलेजली को सबसे अधिक परामर्श इसी ने दिया था । उसका मत था कि भारतवर्ष में एक भी ऐसे देशी राज्य को नहीं छोड़ना चाहिए, जिसकी रत्ना का भार और नीति का संचालन अंगरेजों के हाथ में न हो ।<sup>३</sup> परन्तु अपने मालिकों की निगाह फिरी हुई देखकर अब उसको अपनी बात बदलने में भी किसी प्रकार का सकोच न था । उसने भी कार्नेवालिस की नीति का ही अनुसरण करना निश्चित कर लिया ।

**युद्ध का अन्त**—नवम्बर सन् १८०५ में सिन्धिया के साथ फिर से सन्धि की गई । ग्वालियर और गोहद उसको वापस कर दिये गये । 'ब्रिटिश शान' को बनाये रखने के लिए यह कहा गया कि उसके "मित्रता के भावों का ध्यान रखकर" ऐसा किया गया । सिन्धिया के सरदारों को जो १६ लाख रुपये की पेंशन दी जाती थी, वन्द कर दी गई और स्वयं

१ जान के, लाइफ ऑफ़ मेटकाफ़, जि० १, पृ० १७२ ।

२ स्मिथ, आवमफोर्ट हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ६०८ ।

३ हटन, वेलेजली, पृ० ९१ ।

उसको ४ लाख रुपया सालाना देने का वचन दिया गया। इस चार लाख के बटले में बालों होलकर की मुख्य जागीर टोंक-रामपुरा सिन्धिया को देना चाहता था। मालकम लिखना है कि इस तरह से वह सिन्धिया और होलकर में परस्पर का बैर बराबर बनाये रखना चाहता था, परन्तु सिन्धिया ने उसकी इस चाल को समझकर उस जागीर को मुफ्त लेने में भी इनकार कर दिया।<sup>१</sup> सिन्धिया की स्त्री और लटकी के लिए उत्तरी भारत में ३ लाख रुपये की जागीरें दी गईं। उसके राज्य की चम्बल नदी उत्तरी सीमा मान ली गई। चम्बल के उत्तर या कोटा के पूर्व किसी राज्य में चौथ लेने का अधिकार सिन्धिया को न रहा। जयपुर के राजा के साथ जो सन्धि की गई थी, वह तोड़ दी गई। अपनी मित्रता का विश्वास दिलाने पर भी यह कहा गया कि वह शत्रुओं का साथ दे रहा था। उदयपुर, जोधपुर, कोटा तथा मालवा के कई राज्यों के साथ सन्धि न करने का अंगरेजों ने वचन दिया और यह मान लिया कि अपने अधीन राज्यों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करने का सिन्धिया को पूरा अधिकार है। इस तरह राजपूत राज्यों को जो रक्षा का वचन दिया गया था, वह तोड़ दिया गया। इन मनमानी शर्तों को पाकर सिन्धिया ने होलकर का साथ छोड़ दिया।

होलकर सिखों से सहायता लेने की आशा से पजाब गया था। परन्तु सिखों के राजा रणजीतसिंह को पहले अपनी शक्ति दृढ़ करने की पड़ी थी, इन दिनों वह अंगरेजों से डरकर न लेना चाहता था। इसके अतिरिक्त अंगरेजों ने कई एक सिख सरदारों को पहले से ही अपने पक्ष में मिला रखा था।<sup>२</sup> इस अवसर पर होलकर ने काबुल से भी सहायता लेने का विचार किया था। परन्तु फारस दूत भेजकर अंगरेजों ने अफगानिस्तान की सीमा पर भी युद्ध छिड़वा रखा था। इसलिए वहाँ से भी सहायता की आशा न थी। सिन्धिया

१ मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जि० १, पृ० ३६३।

२ कहा जाता है कि रणजीतसिंह होलकर की सहायता करने के लिए तैयार था, परन्तु सिन्ध के राजा ने समझाकर उसको मना कर दिया। इस राजा का अंगरेजों से मिल था।

ने साथ छोड़ ही दिया था। ऐसी दशा में होलकर न भी सन्धि कर लेना उचित समझा। जनवरी सन् १८०६ में जो सन्धि की गई, उसके अनुसार दक्षिण में उसका जितना राज्य जीत लिया गया था, वापस कर दिया गया। चम्बल नदी के उत्तर की ओर उसका कुछ अधिकार न रहा, परन्तु उसके दक्षिण में उसको स्वतंत्रता दे दी गई। होलकर ने बिना अंगरेजों की सलाह के किसी यूरोपियन को नौकर न रखने का वचन दिया।

होलकर वंश के साथ अंगरेजों की यह पहली सन्धि थी। यशवन्तराव अपनी हार को सहन न कर सका। इन्दौर वापस आकर वह नई तोपें ढलवा रहा था और सेना का फिर से संगठन करने में लगा था। शासन में भी वह सुधार करना चाहता था। पर इतने ही में उसका दिमाग ठिकाने न रहा और वह पागल हो गया। बन्दूक की नली फटने से उसकी एक आँख जाती रही थी, इसी लिए वह 'एकचक्षुहौला' के नाम से प्रसिद्ध था। मालकम लिखता है कि उसकी शिक्षा अच्छी हुई थी। वह फारसी समझ सकता था, पर लिख न सकता था। मराठी लिखने का उसको अच्छा अभ्यास था, हिसाब में भी वह बड़ा चतुर था। घोड़े की सवारी और भाला चलाने में वह अद्वितीय था। उसकी योग्यता के अनुसार उसका माहस भी था। आवश्यकता पड़ने पर वह किसी बात में हिचकता न था। वह एक वीर योद्धा था, पर शासन की उसमें योग्यता न थी। वह मराठा युद्ध-प्रणाली के सहारे भारतवर्ष में फिर से मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था।<sup>१</sup> यदि वह नीतिज्ञ हुआ होता और गिन्धिया तथा भोंसला के साथ मिलकर युद्ध करता, तो मराठा साम्राज्य का इतना शीघ्र पतन न होता।

**निजाम और पेगवा—**वालें यद्यपि हस्तक्षेप न करने की नीति का पक्षपाती था, पर जब मतलब का प्रश्न आ जाता था, तब वह भी न चूकता था। निजाम अपने दीवान मीरआलम को निकालकर उसकी जगह पर राजा महीपतराम को रखना चाहता था। मीरआलम कहने को तो निजाम का



दीवान था, पर वास्तव में वह अंगरेजों का नाकर था। निजाम की इच्छा के विरुद्ध वह दीवान बनाया गया था और उसको बराबर रुपया दिया जाता था। निजाम के दीवान के अपने हाथ में रखना अंगरेजों की नीति थी। शन्त में राजा चन्द्रूलाल नायब दीवान बनाया गया, जो बराबर अंगरेजों का कहना करता रहा और भोग-विलास में फूँकने के लिए निजाम को भी काफी रुपया देता रहा।<sup>१</sup> महायुक्त सन्धियों से देगी राजाओं को यही शासन की स्वतंत्रता दी गई थी।

कम्पनी के सचालक ब्रेमीन की सन्धि को भी, जिसके कारण मराठा युद्ध हुआ था, बदलना चाहते थे। यह सन्धि वालों की मलाह से हुई थी, इसका बदलना वह सहन न कर सकता था। परन्तु प्रकट रूप से अपने स्वामियों की आज्ञा का विरोध करने की अपेक्षा उसने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि स्वयं पेशवा सन्धि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था।<sup>२</sup> यह बात सत्य नहीं जान पड़ती। सन्धि होने के बाद से ही वह स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी तरफ से जो चाहे कह दिया जाता था, अपने विचार प्रकट करने की उसके स्वतंत्रता ही कब दी जाती थी ?

**विल्लौर का उपद्रव**—टीपू के बेटे और रिश्तेदार विल्लौर में नजरबन्द रहते थे। जुलाई सन् १८०६ में यहाँ एक बड़ा उपद्रव हो गया। मदरास के गवर्नर विलियम बेंटिक की अनुमति से स्थानीय सेनापति ने एक आज्ञा निकाल दी कि सिपाहियों को एक नये ढंग की पगड़ी बाँधनी पड़ेगी, दाढ़ी मूँछ भी एक खास ढंग से बनवानी पड़ेगी और माथे पर तिलक या अन्य कोई धार्मिक चिह्न न लगाया जायगा। इस 'भूखता की आज्ञा' से सारी सेना में सनसनी फैल गई और सिपाही समझने लगे कि उनको ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने किले पर कूँजा कर लिया और कुछ अंगरेजों को मार डाला। अर्काट से एक अंगरेजी सेना आ गई और

१ ग्रिविल, हिस्ट्री ऑफ़ दि डेकन, जि० २, पृ० १४६-४७।

२ मालकम, हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, जि० १, पृ० ३८१-८३।

उपद्रव शीघ्र ही शान्त हो गया। सिपाहियों को बड़ा कड़ा ढड़ दिया गया और टीप के बेटे कलकत्ता भेज दिये गये। वास्तव में उनका कोई दोष था या



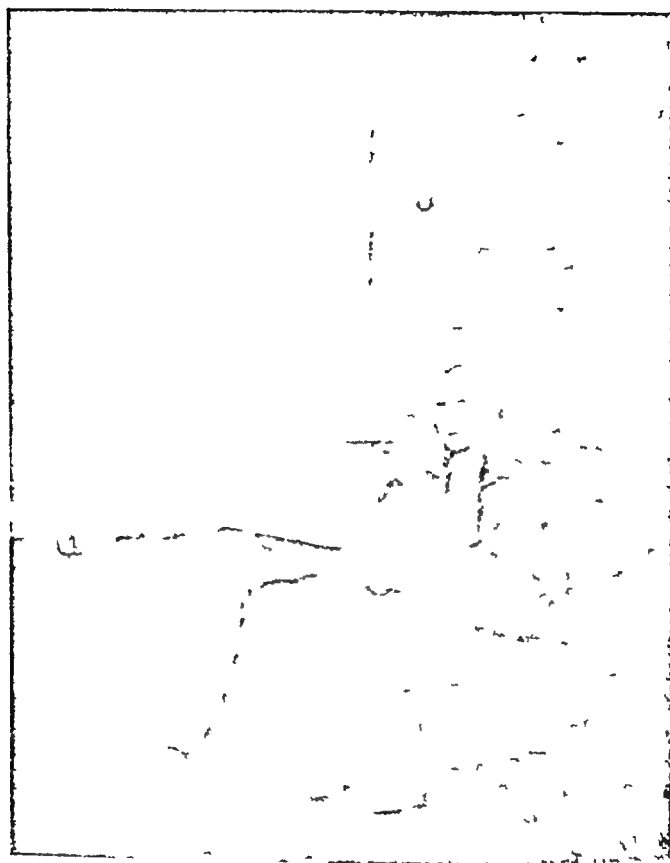
### मदरास के सिपाही

नहीं, इसकी पूरी तरह से जांच तक नहीं की गई। इस पर संचालकों ने मदरास के सेनापति तथा गवर्नर दोनों को वापस बुला लिया।

वालर्ने ने खर्च घटाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, इसी लिए कम्पनी को कुछ लाभ भी होने लगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह "सबसे नीच गवर्नर-जनरल" था। उसके समय में सिन्धिया और होलकर के साथ जो सन्धिया की गई, उनसे "ब्रिटिश शान" पर धब्बा लग गया। वह नीच था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु उसकी नीचता इन सन्धियों के करने में न थी, इसका पता उसके दूसरे ही कामों में मिलता है। वह देशी राज्यों को आपस में लड़ाने का बराबर प्रयत्न किया करता था। मालकम लिखता है कि वह कुछ भूमि देकर के भी मछेरी और भरतपुर के साथ सन्धिया तोड़ देना चाहता था।<sup>१</sup> मेटकाफ का तो यहाँ तक कहना है कि गवर्नर-जनरल की राय में देशी राज्यों के झगड़े ही में ब्रिटिश शासन की दृढ़ता थी, इसी लिए वह जान-बूझकर इन झगड़ों को

१ मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जि० १, पृ० ३७३।

बढ़ाया करता था।<sup>१</sup> अपने मामियों को प्रमत्त रखने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था।



लार्ड मिंटो

लार्ड मिंटो—संचालक बालों को ही गवर्नर-जनरल रखना चाहते परन्तु इंग्लैंड की सरकार एक दूसरे ही व्यक्ति को चाहती थी। अन्त

---

<sup>१</sup> जान के, सेलेक्शम फ्रॉम दि पेपर्स ऑफ मेडकाफ, पृ० ७।

दोनो की राय से, सन् १८०७ में 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' का सभापति लार्ड मिटो गवर्नर-जनरल बनाया गया और वार्ले मद्रास का गवर्नर बना दिया गया। मिटो वर्क का मित्र था, हेस्टिग्स पर अभियोग चलाने में भी उसने भाग लिया था, परन्तु फ्राम की राज्य-क्रान्ति से उसके विचारों में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था।

**महाराजा रणजीतसिंह**—रणजीतसिंह का जन्म सन् १७८० में हुआ था। उसका पिता महानसिंह 'सुकर चकिया' नामक मिसल का मुख्य सरदार था। रणजीतसिंह बचपन से ही अपने पिता के साथ लड़ाइयों पर जाया करता था। अपने पिता के मरने पर वह बराबर लड़ता रहा और १७९९ में उसने कई एक मिसलों को दबा लिया। सन् १७९९ में जर्माशाह ने उसको लाहोर का राजा बना दिया। लाहोर सिखों का मुख्य स्थान था, सन् १७९७ में इसको जर्माशाह ने छीन लिया था। सन् १८०२ में रणजीतसिंह ने श्रमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अब वह एक स्वतंत्र राजा हो गया और उसके नाम के सिक्के चलने लगे। रणजीतसिंह की उन्नति ने सिख मिसलों की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। कई एक मिसलों का एक बड़ा राज्य बन गया और उसके भाग्य का निपटारा लाहोर के राजा के हाथ में आ गया।

**खालसा दल**—रणजीतसिंह के पहले मिसलों की सेनाएँ अलग अलग थीं, इनका आपस ही में युद्ध हुआ करता था। परन्तु रणजीतसिंह ने इन सबको मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की। मराठों की तरह उसने भी मिसलों की युद्धप्रणाली को छोड़ दिया और सेना को कवायद सिखलाने के लिए कई एक यूरोपियन अफसरों को नौकर रखा। इनमें सब से मुख्य बेचुरा था, यह महाराजा की 'फौज ग्यास' का सेनापति था। रणजीतसिंह का इस पर बहुत विश्वास था। उसने इसको लाहोर का 'काजी' और 'हाकिम' भी बना दिया था। सिखों की सेना में भी घोड़सवार की अपेक्षा पैदल पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इस पैदल सेना में ज्यादातर 'अफाली' थे, जो गदा लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। तीस तीस मील का

धावा यह पैदल सेना एक दिन में लगाया करती थी। दीवान मोहकमचन्द प्रधान सेनापति था। उसके अधीन कई प्रसिद्ध सिख सरदार थे। तोपखाना का अध्यक्ष इलाहीवरण नाम का एक मुसलमान था। सिपाही अंगरेजी ढंग की वर्दी पहनते थे। सेना में भर्ती होने का सिंगो को ऐसा चाव था कि रणजीतसिंह को सिपाहियों का कभी अभाव न रहता था। इसी विनाल सेना के सहारे वह अपने राज्य की सीमा को बराबर बढ़ाया करता था।

**अमृतसर की सन्धि**—सिन्धिया के साथ जब युद्ध हो रहा था, तभी से अंगरेज सिंगो को अपने पक्ष में मिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। रणजीतसिंह ने पञ्जाब में होलकर का पीछा करने के लिए भी अंगरेजी सेना को आज्ञा दे दी थी। इस समय उसके राज्य का प्रारम्भ ही था, ऐसी दशा में वह अंगरेजों से कोई झगडा न करना चाहता था। परन्तु अब एक ऐसा प्रश्न उपस्थित हो गया, जिसके कारण उसको अंगरेजों का सामना करना पड़ा। सतलज और जमुना के बीच का देश पहले नाम मात्र को सिन्धिया के अधीन था। इसमें कई एक छोटे छोटे सिख राज्य भी थे, जिनमें मुरथ पटियाला, नाभा और फिन्द, 'फुलकिया मिसल' के राज्य थे। इन सबके राजा एक ही घराने के थे और बराबर आपस में लडा करते थे। सन् १८०६ में अपने चचा फिन्द के राजा के बुलाने पर रणजीतसिंह अपनी सेना लेकर पहुँच गया। लुधियाना पर उसका अधिकार हो गया और वह धीरे धीरे इस ओर भी अपना राज्य बढ़ाने लगा।

इस पर इन राजाओं ने अंगरेजों से सहायता माँगी। लार्ड मिंटो ने हस्तक्षेप करने का यह अच्छा अवसर देखा। इधर फारस और अफगानिस्तान होकर फ्रांसीसियों के आक्रमण की खबर उड़ रही थी। यह भी एक बहाना मिल गया। रणजीतसिंह से कहा गया कि सिन्धिया पर विजय पाने से यह प्रदेश अंगरेजों के अधीन हो गया, उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ऐसी दशा में सेना लेकर रणजीतसिंह को सतलज नदी के उस पार चला जाना चाहिए। उसको समझाने का काम मेडकाफ को सौंपा गया। साथ साथ लुधियाने की ओर अंगरेजी सेना भी भेज दी गई। रणजीतसिंह ने

पहले तो बहुत विरोध किया, वह लड़ने तक के लिए तैयारी करने लगा, परन्तु अपने एक मंत्री अजीजुद्दीन के बहुत समझाने पर उसने सन्धि करना स्वीकार



### अमृतसर

कर लिया। मन् १८०६ में अमृतसर की सन्धि हो गई। सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। इसके उत्तर तथा पश्चिम में रणजीत-सिंह को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई और इसके दक्षिण का देश अंगरेजों के अधीन मान लिया गया। इसके बाद से रणजीतसिंह अपने जीवन भर अंगरेजों से बराबर मित्रता का व्यवहार करता रहा।

**सीमाओं की रक्षा—**भारतवर्ष में कुछ शान्ति होने के कारण मिंटो का ध्यान अधिकतर राज्य की सीमाओं को सुरक्षित बनाने की ओर था। जब उसके पता लगा कि फ्रांस में एक दूत फारस भेजा गया है, तब उसने भी मालकम को फिर से फारस भेजा। बेलेजली के समय में यह एक बार फारस जा चुका था। तभी अफ़गानिस्तान की सीमा पर जर्माणाह को अरम्माये रखने के लिए फारस के शाह को कुछ रुपया देने का भी वचन दिया गया था। डूधर इंग्लैंड-सरकार का भी एक दूत तेहरान पहुँच गया। शाह ने

उसको फ्रांसीसियों की सहायता न करने का वचन दे दिया। उसके सामने मालकम की कोई पूछ न हुई और वह वापस लौट आया। मिंटो इय प्रबन्ध में सन्तुष्ट न था। उसने मालकम को दूसरी बार फिर से भेजा, परन्तु कोई लाभ न हुआ। सन् १८१० में लौटने पर मालकम अपने राजनामचे में लिखता है कि “भूट, कपट और पटुयंत्रों” में मेरा पिंड छुटा।” जिम डग में उसको फारम में काम करना पड़ा था, उसका पता हमी से लगता है।

इसी उद्देश्य से एल्फिंस्टन काबुल भेजा गया, परन्तु उसे पेगावर ही में पता लगा कि अमीर शाहशुजा अफगानिस्तान में निकाल दिया गया है। यहीं अमीर के मंत्रियों से उसकी भेंट हुई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि फ्रांसीसियों के विरुद्ध हममें सहायता चाहते हो, तो शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। एल्फिंस्टन के पास इसका कुछ उत्तर न था। अफगानिस्तान में झगडा बढ़ाये रखने के लिए फारम को रुपया दिया जा रहा था, काबुल पर आक्रमण करने के लिए रणजीतसिंह को स्वतंत्रता दे दी गई थी, तिस पर भी अफगानिस्तान के साथ मित्रता की सन्धि का प्रस्ताव किया जा रहा था। इस अवसर पर एक लाभ अवश्य हुआ, एल्फिंस्टन को कई एक सरदारों से अफगानिस्तान की बहुत सी बातों का पता लग गया।

सिन्ध के अमीरों के साथ भी फ्रांसीसियों के विरुद्ध एक सन्धि की गई। फ्रांसीसियों का जो कुछ भय था, वह तो था ही, पर सिन्ध में हस्तक्षेप करने का यह अच्छा अवसर मिल गया। इस तरह लार्ड मिंटो की नीति से चार स्वतंत्र राज्यों में अंगरेजों का पैर जमने लगा।

**समुद्री युद्ध**—मिंटो ने केवल स्थल से ही भारत पर आक्रमण करने के मार्गों को नहीं रोका, बल्कि उसने समुद्र की ओर से भी किसी के आने की सम्भावना नहीं रखी। भारतवर्ष के निकट दो ऐसे स्थान थे, जहाँ से आक्रमण होने की आशका थी। एक तो मारिशस और उसके निकटवर्ती टापू, जो

फ्रांसीसियों के अधीन थे और दूसरे जावा तथा मसाला के टापू, जो उच्च लोगों के पास थे। मारिगम से फ्रांसीसी अंगरेजों के व्यापार को बड़ी हानि पहुँचाया करते थे। दस वर्ष में उन्होंने लगभग ३० लाख रुपये का नुकसान किया था। मसाला के टापूओं पर अंगरेजों की पहले ही से दृष्टि थी। सन् १८१० में एक जहाजी बेड़ा भेजकर फ्रांसीसी टापू जीत लिये गये। उसी समय गवर्नर-जनरल ने स्वयं जाकर जावा तथा मसाला के टापूओं पर भी अधिकार कर लिया। सन् १८११ में वह जावा से लिखता है कि “गुडहोप अन्तरीप से लेकर हार्न अन्तरीप तक ब्रिटिश जाति का कोई शत्रु या सामना करनेवाला नहीं रह गया”। फ्रांस और हालैंड के साथ सन्धि हो जाने पर सब टापू वापस कर दिये गये, केवल मारिगम रख लिया गया। यही “मिर्च के टापू” के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भारतवर्ष से कुली भेजे जाते हैं। यहाँ ऊख की खेती होती है और कुलियों से बड़ी निर्दयता के साथ काम लिया जाता है।

**कृष्णाकुमारी का आत्मवलिदान**—इस समय राजपूताने की बड़ी गौचनीय दशा थी। अंगरेजों ने रक्षा का विश्वास दिलाकर राजाओं का साथ छोड़ दिया था। हेलकर सबसे मनमाना रूपया वसूल कर रहा था। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बड़े झगड़े चल रहे थे। इनका मुख्य कारण उदयपुर के महाराणा की लड़की कृष्णाकुमारी थी। जयपुर तथा जोधपुर दोनों के राजा उसके साथ विवाह करना चाहते थे और हेलकर की सहायता माँग रहे थे। इस पर अमीरख़ा ने राजकुमारी को मरवा डालने की महाराणा को सलाह दी। उस वीर बालिका ने सब झगड़ों को मिटाने के लिए महर्षि विष-पान कर लिया।

**ईसाई मत का प्रचार**—वेल्लेजली की नीति से पादरियों का उत्साह बढ़ गया था और भारत में ईसाई मत के प्रचार का प्रयत्न किया जा रहा था। मिंटो के भारत आने पर पता लगा कि श्रीरामपुर के ‘मिशन’ से कई एक किताबें देगी भाषाओं में निकाली गई हैं, जिनमें हिन्दू और मुसलमानों के धर्मों पर अनुचित आक्षेप किये गये हैं। मिंटो ने ऐसी किताबों का द्वापना बन्द





भारतवासियों की शिक्षा के लिए पहले-पहल एक लाख रुपया सालाना मजूर किया गया। नेपोलियन की नीति से यूरोप में अंगरेजों का व्यापार चौपट हो जाने के कारण इंग्लैंड के बहुत से व्यापारी अपना माल भारत में भेजना चाहते थे। उनका कहना था कि कम्पनी को अब राज्य मिल गया है, इसलिए व्यापार का ठेका उसके हाथ में रहना ठीक नहीं है। इस पर बहुत बहस हुई और अन्त में भारत के व्यापार का द्वार सब अंगरेजों के लिए खोल दिया गया। ईसाई मत के प्रचार के लिए लाइसेंस लेकर पादरियों को भारतवर्ष जाने की अनुमति दे दी गई। कलकत्ते में

एक 'विशप' और चार पादरी भी नियुक्त कर दिये गये, जिनका चेतन भारतवर्ष की आय से देना निश्चित हुआ। सन् १७६३ के आज्ञापत्र में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारत में राज्य-वृद्धि के लिए युद्ध करना "इस राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा तथा नीति के विरुद्ध है"। परन्तु इस नये आज्ञापत्र में इसके दोहराने की आवश्यकता नहीं समझी गई।



लार्ड हेस्टिंग्स

लार्ड हेस्टिंग्स—यह पहले 'थर्ल' आफ मोयरा' के नर  
था। इस समय इसकी अवस्था ५६ वर्ष की थी। का १८११।

यह भी स्वतंत्रता के आन्दोलन को दबाने के लिए अमरीका गया था। इंग्लैंड के युवराज का यह बड़ा घनिष्ठ मित्र था और उसके साथ पड़कर अपनी बहुत सी सम्पत्ति उड़ा चुका था। उम्मी की गिफारिश से, लार्ड मिंटो का बिना कुछ ध्यान किये हुए, यह भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल और सेनापति बना दिया गया। जब यह भारतवर्ष पहुँचा तब इसको “भात ऐमे कगडे जान पडे जिनमे युद्ध की सम्भावना थी।” इनमें सत्रमे पहला कगडा नैपाल राज्य के साथ था।

**नैपाल का राज्य**—इस राज्य में पहले राजपूत गामन करते थे, परन्तु सन् १७६८ से गोरगो का अधिकार हो गया था। सतलज नदी से लेकर भूटान तक हिमालय की दक्षिणी पहाड़ियों में यह राज्य फैला हुआ था। यही एक ऐसा राज्य रह गया था, जिसमें मुसलमान न पहुँच सके थे और जहाँ प्राचीन हिन्दू ढंग से शासन होता था। उत्तर में इसका चीन के साम्राज्य से सम्बन्ध था। दक्षिण का डालू भाग, जो तराई के नाम से प्रसिद्ध है, अवध के राज्य से मिला हुआ था। सन् १७६५ में एक अंगरेजी सेना ने तराई में घुसने का प्रयत्न किया था, परन्तु गोरगो ने इसको निकाल बाहर किया था। सन् १७९१ में कार्नेवालिस ने कर्नल कर्कपैट्रिक को भेजकर नैपाल के साथ एक व्यापारिक सन्धि की थी। इस राज्य का वर्णन करते हुए कर्कपैट्रिक लिखता है कि यहाँ परम्परा से चली आई हुई शासन-व्यवस्था इतनी दृढ़ हो गई थी कि किसी स्वेच्छाचारी राजा का उसके विरुद्ध जाना एक प्रकार से असम्भव था। शासन का कुल भार प्रधान सचिव के हाथ में रहता था। न्याय विभाग का अध्यक्ष ‘धर्माधिकारी’ कहलाता था। इस विभाग का ऐसा उत्तम प्रबन्ध था कि चोरी का कहीं नाम तक न सुनाई देता था। यहाँ से भारत का माल तिब्बत और चीन जाता था। व्यर्थ की शान में बहुत रुपया न फूँका जाता था, इसी लिए खजाने में खूब जितने ब्रह्मसंस्कृत विद्या का अच्छा प्रचार था। वृत्त की छाल से, जो ‘कागजी’ की कि कम्पोंती थी, कागज बनता था। माटर्गोव ‘नैपाल का बनारस’ समझा गया। शासन के केवल एक पुस्तकालय में उस समय भी १५ हजार से अधिक

ग्रन्थ थे। कर्कपैट्रिक सैनिक रहस्यों का भी पता लगाना चाहता था, परन्तु इसमें उसको सफलता नहीं हुई।<sup>१</sup>

**गोरखों का युद्ध**—वेलेजली के समय में गोरखपुर का जिला कम्पनी के हाथ में आ जाने से उसके राज्य की सीमा नैपाल की तराई तक पहुँच गई। इस सीमा पर बराबर झगडा हुआ करता था। दोनों ओर से भूमि दवाने का प्रयत्न किया जाता था। इन दिनों ज्यौराज और बुटवल के गाँवों पर झगडा था। कहा जाता है कि गोरखों ने इनको दबा लिया था। पहले समझौते से मामला निपटाने का प्रयत्न किया गया जिसमें सफलता न होने पर अंगरेजों की एक सेना ने कई स्थानों पर अधिकार कर लिया। गोरखों ने इस समय तो विरोध नहीं किया पर बाद में अंगरेजी पुलिस के कुछ सिपाहियों को मार डाला। इसी पर गवर्नर-जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी।

अंगरेजों की ओर से चार स्थानों पर आक्रमण करने का प्रबन्ध किया गया। इसके लिए ३४ हजार सेना एकत्र की गई। परन्तु गोरखों से लडना सहज न था। नैपाल पहाडी देश है, गोरखा वीरता में भी किसी से कम नहीं है। उनकी सेना इस समय १२ हजार से अधिक न थी, तब भी उन्होंने अंगरेजों को अच्छी तरह छका दिया। बलभद्रसिंह ने केवल ६०० गोरखों को लेकर जनरल जिलेस्पी को हरा दिया और उसको युद्ध में मार डाला। विल्सन लिखता है कि इस युद्ध में जिलेस्पी के बहुत उत्तेजित करने पर भी गोरों की पलटन आगे न बढ़ रही थी और अंगरेजी अफसर हताश हो रहे थे। लड़ाई में इस तरह असफल होते देखकर फूट फैलाने की नीति से काम लिया गया। नैपाल के सरहद्दी राजाओं को, जो गोरखों के शासन से सन्तुष्ट न थे, मिलाने का प्रयत्न किया गया। पश्चिम में हिन्दूर के राजा की सहायता से कर्नल आक्टरलोनी आगे बढ़ने लगा, पूर्व में शिकिम का राजा मिला लिया गया और एक सेना कमाऊँ की तरफ से भी घुस पड़ी। इस पर सन्धि की

---

<sup>१</sup> कर्कपैट्रिक, अकाउंट ऑफ दि किंगडम ऑफ नैपाल, सन् १८११।

वातचीत होने लगी। गोरखों को ६०० मील की सीमा की रचा करनी थी, सरहद्दी राजा उनके साथ न थे, जल के मुख्य मुख्य स्थानों पर अंगरेजों ने अधिकार कर लिया था। अंगरेज भी तग आ गये थे, उन्हें पहाड़ी युद्ध का अभ्यास न था, इसलिए दोनों सन्धि चाहते थे।

**मिर्गौली की सन्धि**—सन् १८१६ में मिर्गौली नामक स्थान पर सन्धि हो गई। इनसे अंगरेजों को कमाऊँ, गढ़वाल तथा तराई का बहुत कुछ भाग मिल गया। यह प्रदेश मिल जाने से देहरादून, ममूरी, नैनीताल तथा अलमोड़ा अंगरेजों के अधिकार में आ गये। इस समय तक अंगरेजों के पास कोई पहाड़ी स्थान न था। इनके मनोरम दृश्य और स्वच्छ जल-वायु का बड़ा भारी लालच था। बहुत से अंगरेज इन सुन्दर तथा रमणीक पहाड़ियों में बगना चाहते थे। जान पड़ता है, शायद इसी लिए यह लड़ाई लड़ी गई थी, श्योराज और दुदवल का झगडा तो साधारण था। गोरखों ने अपनी इच्छा कि विरुद्ध अंगरेज रेजीडेंट को भी रखना स्वीकार कर लिया। उस समय से दोनों राज्यों में मित्रता का सम्बन्ध है। अंगरेजों ने गोरखों के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान लिया है। वे उनके वीरोचित गुणों का आदर करते हैं। अंगरेजों सेना में उनकी कई एक पदवें हैं। सिंगही-विद्रोह के समय पर गोरखों ने अंगरेजों का पूरा साथ दिया और सन् १८१४ के यूरोपीय महायुद्ध में भी ये बड़ी वीरता से लड़े। ये स्वभाव से ही वीर, साहसी और बड़े स्वामिभक्त होने हैं। इन भोले-भाले वीरों से अब दूसरों की स्वतंत्रता अपहरण करने का काम लिया जाता है।

नेपाल राज्य को बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के किसी अन्य राज्य से सम्बन्ध जाड़ने या किसी यूरोपियन को नौकर रखने का अधिकार नहीं है। इस दृष्टि से वह अंगरेजों के अधीन है। पर शासन में उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। रेजीडेंट को किंचित् भी हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं है। नेपालियों से जो कुछ मिलना था, वह मिल चुका था, पहाड़ों की विकट घाटियों में कुछ रखा न था। गोरखों का मान रखने से उनकी अमूल्य सहायता मिलती थी। ऐसा न होता तो वहाँ के शासन में भी, किसी न किसी बहाने, हस्तक्षेप

अवश्य किया जाता। बिना विरोध आज्ञा के नेपाल में कोई जाने नहीं पाता है। गोरखा को विदेशियों पर बड़ा सन्देह रहता है। किसी राजनैतिक सकट के समय पर इनके सरदारों की एक सभा एकत्र होती है। सन् १८४६ में कई भागों के कारण इस सभा ने तत्कालीन महाराजा को गद्दी से उतार दिया था।<sup>१</sup> तभी जंगबहादुर प्रधान सचिव बनाया गया। सन् १८५० में वह इंग्लैंड गया और वहाँ से लौटने पर उसने शासन में कई सुधार किये। सन् १८५७ के गदर में उसने अँगरेजों का साथ दिया। सन् १८२८ में दासता की प्रथा, जो बहुत दिनों से नेपाल में प्रचलित थी, उठा दी गई।

**पिंडारियों का दमन**—दक्षिण के कुछ पठानों ने अपना पेशा लडना-भिडना बना रखा था। राज्यों के परस्पर युद्ध में ये बराबर भाग लिया करते थे और शत्रुओं को लूटकर अपना काम चलाते थे। औरंगजेब के समय में इन्होंने शिवाजी का साथ दिया था और मुगल सेना को खूब लूटा था। नसरु नाम का इनका एक सरदार शिवाजी की सेना का जमादार था। इसी के वंशज गाजीउद्दीन की सहायता से पेशवा बाजीराव पहले ने मालवा पर आक्रमण किया था। तभी से ये लोग मालवा में बस गये थे। कुछ हिन्दुओं के शामिल हो जाने से इनका दल बहुत बढ़ गया था। इनमें धर्म या जाति का कुछ भी भेद न था। लडना इनका मुख्य काम था, तलवार और भाला इनके अस्त्र थे। घोड़े की सवारी में ये बड़े निपुण होते थे। एक दिन में चालीस चालीस, पचास पचास मील का धावा लगाते थे। ये सबके सब पिंडारी कहलाते थे। यह नाम कैसे पड़ा, इस पर मतभेद है। मालकम का कहना है कि ये 'पिंड' नाम की गराव बहुत पिया करते थे, इसी लिए पिंडारी कहलाते थे।

इनकी सेनाएँ बन गई थीं, जो हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहती थीं। उनको वेतन देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वे केवल शत्रु को

लूटने की आजा चाहती थीं। सिन्धिया और होलकर दोनों पिंडारियों से सहायता लेते थे। इसलिए इनके दो दल बन गये थे, जो 'सिन्धियाशाही' और 'होलकरशाही' के नाम से प्रसिद्ध थे। पिंडू ने मराठा युद्ध में आर्थर वेलेजली भी पिंडारियों से सहायता लेना चाहता था। शत्रुओं को ये खूब लूटते थे और उनके साथ कभी कभी निर्दयता का भी व्यवहार करते थे, इसमें सन्देह नहीं है। पर केवल लूटना ही इनका पेशा न था जैसा कि अंगरेज इतिहासकारों का कहना है। मालकूम लिखता है कि होलकर की सेना में इनका पडाव अलग रहता था और चार आना रोज के हिमाय से इनको भत्ता मिलता था। इसके अतिरिक्त अपने दृष्टियों और बैलों पर नाज तथा लकड़ी लाद करके भी ये लोग कुछ कमा लेते थे। जब लूटने की आजा मिलनी थी तब यह भत्ता बन्द कर दिया जाता था। विल्सन का कहना है कि सिन्धिया और होलकर ने नर्मदा के निकट इनको जागीरें दे रखी थीं, जहाँ ये शान्ति के समय में रहते और लडाई छिड़ने पर अपने मालिकों का साथ देते थे।

वेलेजली की नीति से इनकी सत्ता बहुत बढ गई थी। निजाम, टीपू तथा मराठों के बहाने से बेकाम सिपाही इनमें शामिल हो गये थे। आर्थर वेलेजली ने गवर्नर-जनरल को तभी सचेत किया था, परन्तु तब इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इन दिनों करीमख़ा, वामिल-मुहम्मद और चीनू इनके मुख्य सरदार थे। सिन्धिया के राज्य में करीमख़ा तथा चीनू की जागीरें थीं और ये दोनों नवाब कहलाते थे। इन दिनों मालगा, राजपूताना और दक्षिण में पिंडारी ऊधम मचाये हुए थे। कर्नल टाड ने राजपूताने में इनके अत्याचारों का बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में वर्णन किया है। इधर कुछ दल बिहार की सीमा तक पहुँच गये थे और कुछ निजाम के राज्य में लूट-पाट मचाये हुए थे। मई १८१६ में जब निजाम की अंगरेजी सेना ने इन पर आक्रमण किया तब ये उत्तरी सरकार के जिले पर दूट पडे। इस पर 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' की अनुमति से लार्ड हेस्टिंग्स ने इनका दमन करना निश्चित कर लिया।

अंगरेज इतिहासकारों ही के मतानुसार इनकी संख्या ३० हजार से अधिक न थी। पर इनके दमन करने के लिए १ लाख २० हजार सेना एकत्र की गई, जिसमें १३ हजार गोरे सिपाही थे। पहले नये समझौते करके मराठों की शक्ति अच्छी तरह जकड़ दी गई, जिसमें उनसे पिंडारियों को किसी प्रकार की सहायता न मिले। फिर यह सेना पिंडारियों पर दूट पड़ी। इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए उनमें दम ही कितना था? क़रीमख़ां ने हथियार डाल दिये, उसको गोरखपुर के जिले में एक जागीर दे दी गई। बासिल-मुहम्मद ने निराश होकर आत्मघात कर लिया। चौतू कुछ दिनों तक लड़ता रहा, पर जंगल में एक चीते ने उसको खा डाला। इनकी सेनाएँ छिन्न-भिन्न हो गईं और सैनिक अन्य कामों में लग गये। इस तरह सन् १८१८ में पिंडारियों का अन्त हो गया।

**मराठों का भय**—पिंडारियों को दमन करने के लिए जैसी कुछ तैयारी की गई थी, उसे देखकर मराठे चिन्तित हो रहे थे। सर जान के लिखता है कि इस अवसर पर चारों ओर से जिस तरह सेना उमड़ रही थी, उससे यही जान पड़ता था कि घेरकर मराठा राजाओं का शिकार किया जायगा। उनका यह सोचना कि “फिरगी अब काफी विश्वास कर चुके हैं, वे फिर से घोर युद्ध के लिए कसरत रहे हैं और अपनी सारी सैनिक शक्ति को एकत्र करके इस बार भूमि पर से देशी राजाओं का नाम मिटा देना चाहते हैं,” स्वाभाविक था।<sup>१</sup> इतनी भारी सेना के आगे बढ़ने से वे डर रहे थे। उनको भय था कि अन्त में इसका वार मराठों पर अवश्य होगा। उनका यह सन्देह निराधार न था। पिंडारियों पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप मराठा युद्ध की सम्भावना की चर्चा उन दिनों सरकारी कागजात में बड़े विस्तार के साथ हो रही थी। कैम्पिल भवन में राजनीतिज्ञ बड़ी गम्भीरता से इस पर बहस कर रहे थे। मराठा राजाओं को पूर्ण रूप से अधीन बना लेने पर सेटकॉफ़ जोर दे रहा था। उसका कहना था कि यदि पिंडारी-युद्ध में मराठे पूरा साथ न दें या



किसी प्रकार की बाधा डाले तो, शत्रु समझकर, उन पर आक्रमण कर देना चाहिए और उनके राज्यों को थोड़ा बहुत छीन लेना चाहिए। इसमें युद्ध का खर्च भी चल जायगा और अधिक सेना रखने के लिए काफी रुपया भी मिल जायगा।<sup>१</sup> इन वाक्यों में पिंडारी-युद्ध का वामनविक्रम उद्देश्य स्पष्ट प्रकट हो रहा है। के लिखता है कि ऐसी दशा में भी यदि मराठों के साथ युद्ध न हुआ होता तो आश्चर्य था। जिस तरह भावी भय के लिए तैयारी करने का हमें अधिकार था उसी तरह उनको भी था। यदि उनकी तैयारी को, जिन्हें हमसे कहीं अधिक भय की आशका थी, हम चिड़ोह या मूर्खता कहते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वार्थ से हम अन्धे हो रहे थे। जब हमारी तोपें भरी हुई हैं और हाथ में पलीना सुलग रहा है, तब निस्सन्देह हम इस बात की आशा नहीं कर सकते कि अन्य राज्य अपनी चढी हुई तोपों को उतार लेंगे।<sup>२</sup>

मराठों से इस समय कोई ऐसा भय न था। ब्रिटिश सरकार की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि मनरो की राय में अब देशी राज्यों के किसी गुट से उसे कोई डर नहीं था।<sup>३</sup> परन्तु अँगरेजों की नीति अब पलट चुकी थी। वास्तव में नेपाल का युद्ध नीति के परिवर्तन की घोषणा थी। वीर नेपोलियन, जिसके नाम से अँगरेज कांपते थे, कम्पनी के अधीन सेट हेलेना के टापू में पड़ा सड़ रहा था। उसके साथ लड़ने में इंग्लैंड की जो चूति हुई थी, उसकी किसी न किसी तरह पूर्ति करनी थी। पिंडारियों के दमन के बहाने में मराठों की राजनीति में हस्तक्षेप करने का लार्ड हेस्टिंग्स को अच्छा अवसर मिल गया। भारत आते ही उसने निश्चित कर लिया था कि ब्रिटिश सरकार को 'सर्वोच्च' बना देना चाहिए और देशी राजाओं को नाम से भले ही नहीं पर वास्तव में उसके 'जागीरदार' बनाकर रखना चाहिए।<sup>४</sup>

१ जान के, लाइफ ऑफ मेटकाफ, जि० १, पृ० ४३७।

२ जान के, लाइफ ऑफ सर जान मालकम, जि० २, पृ० १८९-९०।

३ ग्लोब, लाइफ ऑफ मनरो, पृ० २४६, २५०।

४ लॉर्ड हेस्टिंग्स, प्राइवेट जर्नल, (पाणिनि आफिस संस्करण) पृ० ३०।

**भोंसलाओं की अवनति—**मार्च सन् १८१६ में राघोजी भोंसला

की मृत्यु हो गई। नागपुर का यह अन्तिम स्वतंत्र राजा था। इसका पुत्र, जो अन्धा था, नाम मात्र के लिए राजा मान लिया गया, परन्तु शासन किसके हाथ में रहे, इस पर झगडा चल पडा। घुमने के लिए अँगरेजों को यह अच्छा अवसर मिल गया। लार्ड हेस्टिंग्स लिखता है कि “राघोजी भोंसला की अचानक मृत्यु से मैं उस कार्य को कर सका जिसके लिए बारह वर्ष से बराबर प्रयत्न किया जा रहा था।” इस मामले में तरह तरह की चालें चली गईं और घूम से काम लिया गया।<sup>१</sup> राघोजी का भतीजा अप्पा साहब अँगरेजों की सहायता से राजा का संरक्षक बन गया। उसने गुप्त रीति से अँगरेजों के साथ सहायक सन्धि कर ली। जब तक नागपुर में अँगरेजी सेना पहुँच न गई, इसका किमी को पता भी न लगा। मालकम लिखता है कि इस सन्धि का समाचार मिलने पर रनिवास तक में कोलाहल मच गया। “मराठा-मंडल की शक्ति पर यह भीषण आघात हुआ”।<sup>२</sup>

फरवरी सन् १८१७ में नये राजा वाला साहब की भी मृत्यु हो गई, इस पर अप्पा साहब राजा बना दिया गया। अब स्वयं अप्पा साहब को अँगरेजों का हस्तक्षेप असह्य होने लगा। राज्य की आमदनी के एक तिहाई भाग में भी अधिक केवल सेना का खर्च मँगा जा रहा था और मंत्रियों की नियुक्ति में भी बाधा डाली जा रही थी। भोंसला मराठा-मंडल का सेनापति माना जाता था, इसी लिए गद्दी पर बैठते समय पेशवा के यहाँ से खिलत आई थी। यह बात अँगरेजों को बहुत खटकी, क्योंकि एक तो इन दिनों पेशवा से उनकी चल रही थी, दूसरे मराठा-मंडल के अस्तित्व को जतानेवाले किसी रीति-रिवाज को वे मानने के लिए तैयार न थे। अप्पा साहब को हाथ में रखने के लिए रेजीडेंट ने अँगरेजी सेना को नागपुर बुला भेजा।<sup>३</sup> अप्पा साहब

१ लार्ड हेस्टिंग्स, प्राइवेट जर्नल, पृ० २५४।

२ मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वि० १, पृ० ४९४-९५।

३ वही, पृ० ५०५।

की सेना इस अपमान को सहन न कर सकी और उसने सीतावल्दी की छावनी पर आक्रमण कर दिया, पर सफलता न हुई। अन्धा साहव ने फिर समझौता कर लिया, जिसमें सेना का प्रवन्ध और मुख्य गढ़ अंगरेजों के हाथ में आ गये। इस पर भी अंगरेजों को सन्तोष न हुआ। अब कहा जाने लगा कि वह सेना को भडका रहा है और बाजीराव से पत्र-व्यवहार कर रहा है। इतने दिनों बाद वाला साहव की मृत्यु का ढोप भी उसी के मध्ये मढ़ा जाने लगा। रेजीडेंट की आज्ञा से वह गिरफ्तार करके इलाहाबाद भेज दिया गया, जहाँ से वह भाग निकला। कुछ दिनों तक वह रणजीतसिंह के दरबार में रहा। वहाँ से हटाये जाने पर वह जोधपुर चला गया, जहाँ के राजा ने उसे अंगरेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। जून सन् १८१८ में रावोजी का नाती, जो बालक था, नाम मात्र के लिए राजा बना दिया गया। कुल शासन रेजीडेंट के निरीक्षण में होने लगा। नर्मदा नदी के उत्तर का प्रदेश, जिसमें सागर का जिला है, सेना का सर्च चलाने के लिए ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इस तरह आधुनिक 'मध्यप्रान्त' की नींव पड़ी।

**सिन्धिया के साथ नई सन्धि**—इस समय तक सिन्धिया की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट न हुई थी। पिछली सन्धि में अंगरेजों ने यह वचन दिया था कि राजपूत राज्यों के साथ उसका जो सम्बन्ध है, उसमें वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेंगे। उसे निर्बल बनाने के लिए किसी न किसी तरह इस शर्त को बदलना था। अब उस पर यह अपराध लगाया गया कि वह गुप्त रीति से पिंडारियों की सहायता कर रहा है और अंगरेजों के विरुद्ध नेपाल के राजा से भी सम्बन्ध जोड़ना चाहता है। इसी बात पर पिंडारियों को दमन करने के लिए जो सेना तैयार की गई थी, उसे लेकर स्वयं गवर्नर-जनरल ने सिन्धिया को इस तरह घेर लिया कि मजबूर होकर उसे अंगरेजों की सब शर्तें माननी पड़ीं। उसके दो मुख्य किले जमानत में ले लिये गये और राजपूत राज्यों के साथ सन्धिया करने के लिए अंगरेजों को स्वतंत्रता मिल गई। लार्ड हेस्टिंग्स लिखता है कि मैंने सिन्धिया को ऐसा जकड़ दिया है कि अब

विश्वासघात के लिए उसमें दम नहीं रह गया। इस सन्धि से “वास्तव में मराठों का पतन हो गया”।<sup>१</sup>

**होलकर के राज्य की दुर्दशा**—इस राज्य का कोई देखनेवाला न था। अमीरखा, जिस पर यशवन्तराव को बड़ा भरोसा था, उसके जीवन-काल से ही विश्वासघात कर रहा था। इस समय तो अँगरेजों ने होलकर के राज्य का ही एक भाग (टोक) देकर उसको अपने पक्ष में मिला लिया था। नेलन नाम का एक अँगरेज अपने इतिहास में लिखता है कि “होलकर के राज्य की एकता नष्ट करने के लिए अमीरखा और अँगरेज जो चालें चल रहे थे, वे हमारे राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठास्पद नहीं। उनके सम्बन्ध में, दरबार के सभी आदमी, राज्य के सभी दल, अँगरेजों के पक्ष में या उनके विरुद्ध और एक दूसरे के प्रतिकूल पड़्यत्र रच रहे थे। भूड, धोखेबाजी, अपहरण, वध, हत्या, लूट, विद्रोह और परस्पर के युद्ध से वह राज्य, जिस पर सुप्रसिद्ध होलकर कभी शासन करता था, छिन्न-भिन्न और कलुषित हो रहा था”।<sup>२</sup> रानी तुलसीबाई मार डाली जा चुकी थी। ऐसी दशा में भी यह सन्देह किया गया कि इस राज्य से भी पिंडारियों को सहायता मिल रही थी। दिसम्बर सन् १८१७ में महीदपुर में होलकर की सेना चारों ओर से घेर ली गई। बड़ी घोर लड़ाई हुई जिसमें अँगरेजों के बहुत से सैनिक मारे गये। रोशनबेग के तोपखाना ने बड़ा काम किया, परन्तु इतने ही में अष्टदुलगाफूर खाँ, जो होलकर का एक मुख्य सेनानायक था, अँगरेजों से मिल गया। इन्हीं के मिश्रद्वियों ने रानी तुलसीबाई का वध किया था। इस विश्वासघात के लिए उसके वंशजों को जावरा की जागीर दी गई।<sup>३</sup> जनवरी सन् १८१८ में सन्धि हो गई, तब से होलकर राज्य भी अँगरेजों के अधीन हो गया।

१ लाट हेस्टिंग्स, प्राइवेट जर्नल, पृ० ३०९।

२ नेलन, ब्रिटिश एम्पायर, जि० २, पृ० ५२१।

३ लुतफुल्ला, आटोबायोग्राफी, पृ० १०३-१०४।

**पेशवाओं का अन्त**—बाजीराव अपने को बड़ा नीति-निपुण समझता था, पर अंगरेजों से कूटनीति में पार पाना सहज न था। पिछले मराठा युद्ध के समय से ही अंगरेजों ने धूम देकर उसके मंत्रियों को फोड़ रखा था।<sup>१</sup> इन दिनों उसके दरबार में एल्फिन्स्टन रेजीडेंट था। पेशवा पर उसकी बड़ी कड़ी निगाह रहती थी। बाजीराव लिखता है कि वह किस दिन क्या खाता था, इसका भी पता रेजीडेंट को रहता था। इन्हीं दिनों गंगाधर शास्त्री, जो बड़ोदा राज्य का कुछ हिस्सा भीगडा निपटाने के लिए पूना आया था, मार डाला गया। रेजीडेंट का कहना था कि यह कार्य पेशवा की राय से उसके मंत्री ज्यम्बरजी द्वारा किया गया। ज्यम्बरजी अंगरेजों का बड़ा विरोधी था। रेजीडेंट के बहुत दवाने पर पेशवा ने उसको अंगरेजों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे एक किले में कैद कर दिया। थोड़े दिन बाद वह किले में भाग निकला। रेजीडेंट की राय में इसमें भी पेशवा की साजिश थी। उसको यह भी मन्देह था कि पेशवा गुप्त रीति से युद्ध की तैयारी कर रहा था। इस पर गवर्नर-जनरल ने घोषणा कर दी कि बाजीराव 'शत्रु' है। अंगरेजी सेना भी पूना की ओर बढ़ने लगी। बबडार बाजीराव ने सन् १८१७ में नई सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके अनुसार मराठा-मंडल नष्ट कर दिया गया। अन्य मराठा राज्यों पर पेशवा का कोई अधिकार न रहा और दंड स्वरूप उसे रायगढ़ तथा पुरन्दर के किले और मालवा तथा उत्तरी भारत के सब इलाके अंगरेजों को दे देने पड़े। लार्ड हेस्टिंग्स ने भी माना है कि ये शर्तें बड़ी कड़ी थीं। पर उसका कहना है कि यदि बाजीराव को गद्दी पर बिठलाये रखना या और अपनी रक्षा का भी प्रबन्ध करना था, तो उसे इस तरह से "पगु बना देने" के अतिरिक्त और कोई उपाय न था।<sup>२</sup> यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाजीराव के गुप्त भाव चाहे जो कुछ रहे हों, इस समय तक उसने बेसीन की सन्धि को किसी तरह

१ वेलिंगटन, टेसपैचेज़, पृ० २७३-७६।

२ लार्ड हेस्टिंग्स, प्राइवेट जर्नल, पृ० २९१।

भग नहीं किया था। शासन में भी वह थोड़े बहुत सुधार कर रहा था। इसको इतिहासकार मालकम ने भी माना है।<sup>१</sup>

इस नई सन्धि के अपमान को भी यदि बाजीराव चुपचाप सहन कर लेता तो आश्चर्य था। परन्तु अब यह बात उसके हाथ की न थी। पेशवा की गद्दी का इस तरह अपमान देखकर उसकी सेना उत्तेजित हो रही थी। मुख्य सरदार गोखले, जो स्वयं पहले अंगरेजों का पक्षपाती था, उनकी ज्यादाती देखकर बिगड़ रहा था। इन दिनों कुछ अंगरेजी सेना पिंडारियों के साथ लड़ने के लिए बाहर गई हुई थी। अक्सर पाकर गोखले ने नवम्बर सन् १८१७ में किरकी (खडकी) की छावनी पर आक्रमण कर दिया। मालकम के कथनानुसार पेशवा इस समय भी पहले अपनी तरफ से चार न करना चाहता था, परन्तु गोखले ने ऐसे स्वामी की बात न सुनना ही उचित समझा। रेजीडेंट्स में आग लगाकर पेशवा की सेना ने घोर युद्ध किया, परन्तु अंगरेजी सेना अधिक आ जाने से उसे पीछे हटना पड़ा और पूना पर अंगरेजों का फिर से धिकार हो गया। बाजीराव भाग निकला।



बापू गोखले

गोखले ने बराबर युद्ध जारी रखा, अन्त में वह बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए मारा गया। पेशवा का दल बढ़ रहा था। जिसके पूर्वजों ने “मलावार से लेकर लाहोर” तक भगवा झंडा फहराया था, उसकी गद्दी का

इस तरह नष्ट होना मराठा सम्राट् सहन न कर सकते थे। इस भाव को दवाने के लिए मैसूरवाली चाल चली गई। शिवाजी के वंशज सतारा के राजा को पेशवा का बहुत सा राज्य देने की घोषणा की गई। इस चाल का भी कोई प्रभाव न पड़ा, अंगरेजों की नीति में बराबर अग्रगण्य फैलने लगा। परन्तु बाजीराव न इस अवसर पर भी अपनी कायरता का परिचय दिया। उसने अपने को अंगरेजी सेनाध्यक्ष मालकम के हवाले कर दिया, जिसने उसको २ लाख रुपये साल की पेगन देकर बिट्टर भेज दिया, जहाँ वह बहुत दिनों तक जीवित रहा।

बाजीराव को इतनी बड़ी पेगन देना गवर्नर-जनरल की राय में उचित न था। अंगरेज इतिहासकारों का कहना है कि पेशवा के साथ बड़ी उदारता की गई। परन्तु वास्तव में बात कुछ और ही थी। मालकम, जिसको



दूसरा बाजीराव

भी उसका साथ देने का विचार कर रहा था। मैसूर से लेकर मालवा तक सारा देश उसके लिए चिन्तित हो रहा था। पेशवा अपनी सेना के साथ असीरगढ़ की ओर बढ़ रहा था, जिसका बर्सात में जीतना कठिन था। ऐसी

तत्कालीन स्थिति का सबसे अधिक ज्ञान था और जिसने पेशवा को गद्दी छोड़ देने के लिए आठ लाख रुपये सालाना देने का लालच देकर राजी किया था, लिखता है कि पेशवा के पास इस समय भी चार पाँच हजार घोड़सवार बाकी थे, जो कुछ दिन विश्राम करके, फिर से लड़ने के लिए तैयार थे। उसके पास इतनी ही पैदल सेना थी, जिसमें बहुत से श्रव लोग थे। “हम लोगों की दृष्टि में उसकी दशा चाहे जितनी गिरी हुई हो, पर उसके नाम से सहस्रा सैनिक एकत्र हो रहे थे।” सिन्धिया

दशा में किसी न किसी तरह समझा-बुझाकर बाजीराव को हाथ में लाने के सिवा और कोई उपाय न था ।<sup>१</sup>

बाजीराव के प्रति जो राजभक्ति दिखाई गई, उसके योग्य वह न था । उसमें व्यक्तिगत माहम का सर्वथा अभाव था, केवल धूर्तता में वह बड़ा निपुण था । संस्कृत का वह अच्छा विद्वान् था और पंडितों का सदा आदर करता था । जवान का वह ऐसा मीठा था कि उसका सभी पर प्रभाव पड़ता था और उसके भावों का जानना कठिन हो जाता था । वह बड़ा व्यसनी और आलसी था, इसी लिए गंगा के तट पर आठ लाख रुपया मालाना से आनन्द करने के सामने उसको पेशवाओं का नाम मिटाने में भी संकोच नहीं हुआ ।

**पेशवाइ शासन**—पेशवाओं के समय में शिवाजी की राज्य-व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था । इन दिनों मराठों का साम्राज्य कई एक राज्यों का समूह था । इन राज्यों को शासन की स्वतंत्रता थी, पर तब भी इन सब की शासन-पद्धति में बहुत कुछ समानता थी । गाँव का मुखिया पटेल कहलाता था । इसका मुख्य काम लगान वसूल करना होता था । इसके नीचे एक 'कुलकर्णी' रहता था, जो प्रायः ब्राह्मण होता था । इसको गाँव का कुल हिसाब रखना पड़ता था । पटेल की ही अध्यक्षता में गाँव का काम करनेवाले पेशेवर रहते थे ।<sup>२</sup> इन सब का सालियाना देना होता था, जो गाँव की आमदनी से ही मिलता था । पटेलों की निगरानी के लिए सूबेदार और सर सूबेदार रहते थे, जिनके ऊपर राज्य के दीवान और मंत्री होते थे । पटेलों से रुपया वसूल करने के लिए कभी कभी सूबेदार अपने नौकर रखते थे, जो मामलतदार और तहसीलदार कहलाते थे । शिवाजी के समय में मालगुजारी के लिए मलिक अम्बर का चलाया हुआ बन्दोबस्त था । बालाजी बाजीराव ने फिर से पैमा-

१ मालकम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जि० १, पृ० ५२१-२३ ।

२ बहई, लेहार, धोवी, नाई, कुम्हार, सोनार, पुजारी, भिस्ती, मोची, रस्मी बटनेवाला, चाँकीदार और मुहा ये गाँव के 'बारह बलुते' कहलाते थे ।



यश कराकर कई माल के लिए नया बन्दोबस्त किया था, जिसमें गाँवों की मालगुजारी बहुत बढ़ गई थी। दूसरे बाजीराव ने अंगरेजों की देखा-देखी ठेके की प्रथा चला दी थी, जिसमें प्रजा पर अत्याचार होने लग गया था।

पूना के न्यायाधीश के पद पर चार शास्त्री काम करते थे। न्यायाधीश राम-शास्त्री की योग्यता प्रसिद्ध थी। प्रान्तों में इसी ढंग की छोटी छोटी अदालतें थी। इनके अतिरिक्त पटेल, मामलतदार और तहसीलदारों को भी फौजदारी तथा दीवानी के कुछ अधिकार रहते थे। परन्तु अधिकतर न्याय पचायतों द्वारा होता था। उनका फैसला मान्य न होने पर सरकारी अदालतों में अपील होती थी। दीवानी में स्मृति ग्रन्थों से कानून का काम लिया जाता था, पर अधिकतर देश, कुल तथा गाँव के रीति-रिवाजों ही पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राजनैतिक अपराधों को छोड़कर अन्य अपराधों के लिए ठंड की व्यवस्था बहुत कठोर न थी। प्राणदण्ड तो बहुत ही कम दिया जाता था। जेल का अच्छा प्रबन्ध रहता था। कैदियों को बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती थी और उनका अपमान कभी न किया जाता था। अपराधियों के साथ ययाशक्ति सौम्य व्यवहार किया जाता था।

जमीन के लगान के सिवा और भी बहुत से कर लिये जाते थे। परन्तु इनके वसूल करने में देनेवालों की स्थिति का बराबर ध्यान रखा जाता था।<sup>१</sup> पेशेवरों से जो कर लिया जाता था, वह 'मोहतरफा' कहलाता था। व्यापार पर चुगी लगती थी, जो 'जकात' के नाम से प्रसिद्ध थी। लोकोपयोगी व्यापार पर 'जकात' माफ कर दी जाती थी। बिना माफी के परवाने के पेशवा तक के माल पर जकात ली जाती थी। विदेशियों को बिना रोक-टोक के व्यापार करने की आज्ञा थी और उन्हें सब तरह की सुविधाएँ दी जाती थीं। अनेक स्थानों पर सरकारी दुकानें रहती थीं, जिनके द्वारा विशेष वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। इन दुकानों से किसानों को कभी कभी कर्ज भी दिया जाता था। नये बाजार और हाट बसाने की और पेशवाओं

का बड़ा ध्यान रहता था। खाने-पीने की चीजें बहुत सस्ती विक्रिती थी।<sup>१</sup> खेती की उन्नति के लिए भी प्रयत्न किया जाता था। पड़ती ज़मीन को तोड़कर चैनी बनाने के लिए किसानों को धन दिया जाता था और बहुत दिनों तक लगान वसूल न किया जाता था। दुर्भिक्ष या युद्ध के समय पर भी किसानों के साथ खास रियायत की जाती थी। सिंचाई के लिए नहरें और बड़े बड़े तालाब खोदवाये जाते थे। खेतों को रहन या बय करने का अधिकार किसानों को न था।

उन दिनों गाँवों का जीवन ऐसा था कि गाँववाले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध आप ही कर लेते थे। इसलिए राज्य को इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता न रहती थी। पर तब भी गरीबों के लिए चिकित्सालय खोलना, उनको अन्न देना, धर्मशाले और मन्दिर बनवाना, सभी हिन्दू राजा अपना कर्तव्य समझते थे। राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबन्ध न था, यह कार्य माधारणतः गाँव के शिक्षकों द्वारा ही होता था। बड़े बड़े पंडितों को राज्य से दक्षिणा अवश्य मिलती थी। गाँवों की उन्नति के लिए आजकल की तरह न कोई अलग विभाग ही था और न उसके लिए अलग धन ही रखा जाता था। उनकी जो कुछ आमदनी होती थी, उसमें से इन कार्यों के लिए कुछ भाग अलग कर दिया जाता था। बाहरी आक्रमण से उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य था।

गाँव की रखवाली वहाँ का चौकीदार ही कर लेता था। विशेष अवसरों पर सरकार की ओर से इसका प्रबन्ध किया जाता था। तहसीलदार की मातृ-हृती में पहरेदार और सवार पुलिस का काम करते थे। बड़े बड़े नगरों में कोतवाल भी रहते थे, जिन्हें वहाँ का सब हाल लिखकर रखना पड़ता था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में पूना की पुलिस बड़ी अच्छी समझी जाती थी।<sup>२</sup>

१ माधवराव के समय में चावल एक रुपया चार आना मन, गेहूँ दो रुपया मन और घा एक रुपये का टेंड या दो सेर विकता था। पेशवाओं की टायरी, जि० २, पृ० ३११-१४।

२ कॉम्बिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, जि० ५, पृ० ३९३।

हिन्दुओं के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने का पेशवाओं को अधिकार था। मुसलमानों के हाथ में पड़कर जिनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था, उनकी शुद्धि कर ली जाती थी।<sup>१</sup> बाजीराव ने मती प्रथा बन्द कर दी थी। अन्य मतावलम्बियों को पूरी स्वतंत्रता थी। उनकी बराबर रक्षा की जाती थी। गांवों में मुसलमानों के लिए मुज्जा का सालियाना बंधा रहता था। पुर्नगालियों के गिरजाघरों को भी सहायता मिलती थी। बहुत से इलाकों में शराब बनाने की मनाही थी, केवल यूरोपियन लोगों को भट्टी चढ़ाने की आज्ञा मिलती थी, उनको भी साधारण जनता में उसके बेचने का अधिकार न रहता था। बेगार और गुलामी की भी चाल थी, पर गुलामों के साथ निर्दयता का व्यवहार न होता था।

आवश्यकता पड़ने पर सरकार को साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था। पेशवा लोग बहुत कर्ज लिया करते थे। निजी खर्च और दरबारी खर्च बढ़ा हुआ न था। मुगल बादशाहों की नकल करने में पेशवाओं का भी बहुत खर्च होता था। सिक्के अनेक प्रकार के चलते थे, जिनके बदलने में बड़ा लगता था और प्रायः बहुत झगडा होता था।

फडनवीस की अध्यक्षता में पूना में पेशवा का 'हज़ूर दफ्तर' रहता था, जिसमें २०० कारकुन काम करते थे। इसमें सभी विषयों के कागजात रहते थे। आजकल यह दफ्तर पूना के इनाम कमीशन के अधिकार में है। 'डेकन वर्नाक्युलर ट्रांसलेशन सोसायटी' की ओर से इन कागजातों की कई एक जिल्दें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें सेना, जहाजी वेडा, जमीन की पैमायश, गांवों के झगडे, कर्मचारियों और जागीरदारों के दुराचार तथा छलकपट, पुलिस और जेल की व्यवस्था, सरकारी डाक, वैद्यक्रिया, शस्त्रक्रिया, ऋण, टकसाल, व्यापार, सामाजिक जीवन, बाजारदर तथा मजदूरी और उत्सव तथा अन्य बहुत सी बातों का बड़ा रोचक वर्णन दिया हुआ है।

नाना फडनवीस के समय तक सब व्यवस्था अच्छे ढंग से चलती रही। पेशवा माधवराव बल्लाल के जीवनकाल में बड़े बड़े सरदारों को भी इसमें

<sup>१</sup> पेशवाओं की टायरी, जि० ३, पृ० २१५, २१९।

विरुद्ध जाने का साहस न होता था। सिन्धिया और होलकर ने कई इलाकों से जबरदस्ती 'घास दाना' वसूल कर लिया था, जिसके लिए उनको पेशवा की डाट सुननी पड़ी थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार के निर्बल होने पर यह व्यवस्था भी बिगड़ गई। बाजीराव के समय में तो किसी की सुनवाई ही न होती थी। घासीराम कोतवाल का अत्याचार प्रसिद्ध था। दूसरे यह व्यवस्था केवल महाराष्ट्र देश के लिए ही थी। मराठों ने जो और बहुत सा देश जीत लिया था, वहाँ न तो किसी प्रकार का सुधार ही किया गया था और न प्रजा के हित की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया था। उन प्रान्तों में केवल रुपया वसूल किया जाता था। यही कारण था कि उन्होंने अन्त में मराठों का साथ नहीं दिया।

इस शासनव्यवस्था में बहुत से दोष भी थे। अधिकारी स्वेच्छाचारी होते थे, उनके निरीक्षण का अधिक प्रबन्ध न रहता था। आजकल की बहुत सी सुविधाएँ उन दिनों न थीं। यह सब होते हुए भी यह व्यवस्था 'निन्दनीय' नहीं कही जा सकती, जैसा कि मुख्य अँगरेज इतिहासकारों का मत है। इसमें जो दोष थे, उनसे तत्कालीन यूरोप के बहुत से राज्य भी मुक्त न थे।

**मराठों का पतन**—पेशवाओं के अन्त के साथ ही साथ मराठों का भी वान्धव में पतन हो गया। अन्य मराठा राज्य अँगरेजों के अधीन हो गये। गायकवाड, होलकर और सिन्धिया के राज्य अब भी हैं। भोंसला का बचा-खुचा राज्य डलहौजी के समय में हड़प कर लिया गया। युद्ध में हारने के कुछ कारणों का वर्णन पहले किया जा चुका है, पर सबसे मुख्य बात इस समय आपस की फूट थी। शिवाजी के जीवनकाल में देशभक्ति का जो भाव उदय हुआ था, वह अब अस्त हो चुका था। पेशवाओं के समय में मराठों का साम्राज्य जागीरों का एक समूह बन गया था, जिसको एकता में बाँधनेवाला कोई दृढ़ बन्धन न था। नाना फडनवीस के साथ नीति बिटा हो गई थी। इस समय कोई योग्य नेता न रह गया था। संसार में क्या हो रहा है, इसका कुछ भी ज्ञान तत्कालीन मराठा राजाओं को न था।

अंगरेजों का राज्य स्थापित हो जाने से भारतवर्ष का सम्बन्ध यूरोप की राजनीति से हो गया था। उसी की चाल के साथ साथ भारतवर्ष में अंगरेजों की नीति बदलती थी। अमरीका स्वतंत्र हो गया था। यूरोप में इन दिनों फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति का जोर था। परन्तु मराठा राजाओं को इनकी खबर तक न थी। भूगोल और इतिहास तो वे जानते ही न थे। इस सम्बन्ध में दूतों को पेरिस भेजकर टीपू ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। शिवाजी के समय में मराठों के जीवन में जो सादगी थी, वह भी इस समय लुप्त हो गई थी और उसके स्थान पर कई एक दुर्गुण आ गये थे। अंगरेजों की गूढ़ नीति, उनका रहन-सहन, उनकी सभी बातें मराठों के लिए नई थीं, जिनको जानने का उन्होंने कभी प्रयत्न तक न किया था। एक ओर आपस की फूट, यह अज्ञानता, उदासीनता तथा शिथिलता थी और दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता, अद्भुत संगठन, सब बातों के जानने की उत्सुकता, कुटिल नीति, अदम्य उत्साह तथा बुद्धि की प्रखरता थी। ऐसी दशा में परिणाम वही हो सकता था, जो वास्तव में हुआ।

**अवध के शाह—**सन् १८१४ में नवाब सादतअली की मृत्यु हो गई। हेबर लिखता है कि वह एक योग्य शासक था, उसने सीमाओं को सुरक्षित बना दिया, राज्य की आमदनी बड़ा दी और वह खजाने में बहुत सा धन छोड़ गया। वजीर हकीम मेहदी ने शासन में कई एक सुधार किये। उसके समय में प्रजा सन्तुष्ट थी। वह अंगरेजों को शासन में बहुत हस्तक्षेप न करने देता था। उसके बाद उसका लड़का गाजीउद्दीन गद्दी पर बैठा। इन दिनों कर्नल बेली रेजीडेंट था। वह नवाब की हर एक बात में हस्तक्षेप करता था। उसके विषय में स्वयं लार्ड हेस्टिंग्स लिखता है कि "वह छोटी छोटी बातों में भी नवाब को दबाता था, बिना सूचना दिये हुए उसके महल में घुस पड़ता था, अपने आदमियों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दिलवाता था, जो नवाब की सब बातों का उसको पता देते थे और सबसे भारी बात तो यह थी कि वह नवाब के साथ सदा शासक की भाषा का प्रयोग करता था, जिससे प्रजा और घरवालों की दृष्टि में नवाब का बड़ा अपमान होता

था"।<sup>१</sup> गोरखा युद्ध के समय पर नवाब ने कम्पनी को ढो करोड़ रुपया कर्ज दिया था। शासन में अंगरेजों के हस्तक्षेप से प्रजा में भी बहुत अशान्ति फैल रही थी। प्राचीन रीति-रिवाजों का नये प्रबन्ध में कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता था। इन सब बातों का विचार करके गवर्नर जनरल ने कर्नल ब्रेली को रेजीडेंट के पद से हटा दिया और शासन में नवाब को कुछ स्वतंत्रता भी दे दी।

इस समय तक अवध के नवाब मुगल सम्राट् के वजीर कहलाते थे, परन्तु अब लार्ड हेस्टिंग्स की सलाह से गाजीउद्दीन हैदर ने 'अवध के शाह' की उपाधि धारण की। इससे अवध का कम्पनी के साथ जो सम्बन्ध था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भोले नवाब को प्रसन्न करने के लिए यह केवल एक खेलवाड ही नहीं था, बल्कि लार्ड हेस्टिंग्स की इसमें भी नीति थी। वह नवाब के इस कार्य से मुसलमानों में फूट फैलाना चाहता था। इसको उसने अपने एक पत्र में स्पष्ट स्वीकार किया है।<sup>२</sup> इस समय तक उत्तरी भारत के मुसलमानों में दिल्ली सम्राट् के नाम का सम्मान था, परन्तु अब अवध के मुसलमानों का दल ही अलग हो गया। साथ ही साथ सबको यह भी दिखला दिया गया कि कम्पनी को भी बादशाह बनाने का अधिकार है। इस तरह मुगल सम्राट् का खुले तौर पर अपमान किया गया। अब दीवानी के दिन च्यतीत हो चुके थे, वह कम्पनी का वेतनभोगी था, फिर उसके नाम के मान रखने की आवश्यकता ही क्या थी ?

गोरखा युद्ध के समय पर जो रुपया लिया गया था, उसके बदले में खैरी-गढ और तराई का कुछ भाग अवध को दिया गया। सन् १८२५ में उससे डेढ़ करोड़ रुपया फिर कर्ज लिया गया। इस तरह अवध का खजाना कम्पनी की सहायता के लिए खाली किया जाता था और कुप्रबन्ध का दोष शासकों के मथे मढा जाता था। गाजीउद्दीन तालुकदारों की मालगुजारी बढ़ाना

१ लार्ड हेस्टिंग्स, प्राइवेट जर्नल, पृ० ९७।

२ मालकम, हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, वि० १, पृ० ५३६।

चाहता था, यह उसका अन्याय बतलाया जाता था। पाटडी हेवर लिखता है कि गाजीउद्दीन बराबर कहा करता था कि कम्पनी की मित्रता पर भरोसा करना ही मेरी सब कठिनाइयों का मुख्य कारण है। उस पर विश्वास करके मैंने अपनी सेना हटा दी, इसीलिए अब मुझे सैनिक सहायता के लिए कम्पनी को इतना रुपया देना पड़ता है। यदि यह रुपया बच जाता, तो मैं अपनी प्रजा का कुछ हित कर सकता।<sup>१</sup> गाजीउद्दीन अबध का अन्तिम शासक था, जिसको प्रजा का कुछ ध्यान था। उसके बाद भोग-विलास ही वहाँ के शासकों का मुख्य काम रह गया।

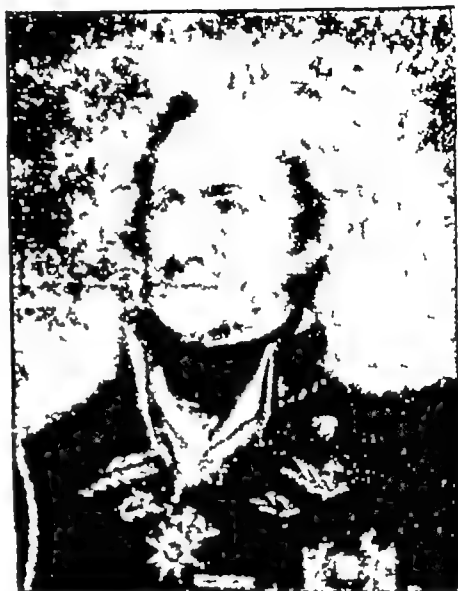
**शासन-प्रबन्ध**—लार्ड हेस्टिंग्स के समय में शासन में भी कुछ परिवर्तन किये गये। इन दिनों अंगरेजी अदालतें अन्याय और अत्याचार के लिए बदनाम हो रही थी। एल्फिंस्टन लिखता है कि अदालतों के भय से लोग गांव छोड़कर भाग जाते थे।<sup>२</sup> जिनका मुख्य काम न्याय था, उनसे इतना भय हो रहा था। अदालतों के सुधारने का कुछ प्रबन्ध किया गया और उनकी सख्या बढ़ा दी गई। इनमें कुछ हिन्दुस्तानी भी रखे गये। कर्न-वालिस के समय से कलेक्टर के हाथ में केवल माल-विभाग ही रह गया था, अब उसको न्याय के अधिकार फिर से दिये गये। उड़ीसा में कर इतना बढ़ा हुआ था कि बड़े उपद्रव हो रहे थे। उसको शान्त करने के लिए एक कमिश्नर रखा गया, जिसको जनता के रीति-रिवाजों का ध्यान रखने की ताकीद दी गई। आगरा प्रान्त में नया बन्दोबस्त करने के लिए फिर से पैमायश शुरू की गई। लार्ड हेस्टिंग्स के सौभाग्य से उसको बड़े योग्य अफसर मिल गये थे, जिनकी सहायता से वह शान्ति स्थापित कर सका।

**सर टामस मनरो**—यह मदरास का गवर्नर था। वेल्लेजली के समय में टीपू से जो राज्य छीना गया था, उसका बन्दोबस्त इसी ने किया।

१ हेवर, नैरेटिव ऑफ ए जरनी, जि० २, पृ० ८६-८७।

२ कोलब्रुक, लाइफ ऑफ एल्फिंस्टन, जि० २, पृ० १३१।

था। यह लार्ड कार्नवालिस के जमीन्दारी बन्दोबस्त का पक्षपाती न था। इसने मदरास में रयतवारी बन्दोबस्त ही जारी रखा। इसका मत था कि प्राचीन समय से भारत-वर्ष में यही बन्दोबस्त था। इसके अनुसार किसानों से सरकारी तहसीलदारों द्वारा लगान वसूल किया जाता है। जब तक किसान बराबर लगान अदा करता रहता है, वह बेदखल नहीं किया जा सकता। अपने खेतों को रहन-वस करने का भी उसको कुछ अधिकार रहता है। छोटे बड़े सभी किसानों को एक ही तरह के अधिकार प्राप्त रहते हैं। इस बन्दोबस्त से सभी लाभ हो सकता है, जब तहसीलदारों को किसानों के हित का बराबर



टामस मनरो

ध्यान रहे, जिसकी सदा आशा नहीं की जा सकती। यह दोष मनरो के समय में ही दिखलाई देने लगा था और उसको कई एक तहसीलदार तथा कलेक्टरों की अच्छी तरह से खबर लेनी पड़ी थी। मनरो ने जो लगान बाँधा था, वह भी बहुत ज्यादा था। सन् १८५५ में उसके प्रबन्ध में बहुत कुछ परिवर्तन किये गये, तब से मदरास प्रान्त में यह ढँग अच्छी तरह चल रहा है। मनरो पंचायतों का बड़ा पक्षपाती था। उसके बहुत अनुरोध करने पर मदरास में जजों के साथ पंचायतों को विठलाने का प्रबन्ध किया गया। परन्तु 'जूरी' के ढँग की पंचायतों का देश में रिवाज न था, इसलिए विशेष सफलता न हुई।



हिन्दुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे न देना उसकी राय में बड़ी भूल थी। वह लिखता है कि जब तक हिन्दुस्तानियों को प्रतिष्ठित पद देकर उनकी उनकी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं दिलाया जायगा, तब तक उनके चरित्र में सुधार करने की आशा व्यर्थ है। ऐसा न होने ही के कारण अंगरेजों के अधीन प्रान्तों में रहनेवाले हिन्दुस्तानी “सबसे अधिक गिरे हुए हैं।” केवल भारतवर्ष के ही लोग घूम नहीं खाते हैं, प्रत्युत सब देशों का यही हाल है। उस शिक्षा के लिए उत्साह ही क्या हो सकता है, जिसके प्राप्त करने पर केवल लेखक का पद मिल सकता है? उसका कहना था कि यदि इंग्लैंड में इसी ढंग से कोई विदेशी शासन करने लगे, तो थोड़े ही काल में वहाँ की भी वही दशा हो जायगी, जो भारत की है। केवल अंगरेजों द्वारा शासन करना नीति और न्याय देना के विरुद्ध है। दासता में रहने से राष्ट्रीयता के गुणों का ह्रास हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य केवल सार्वजनिक जीवन ही में नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी गिर जाता है। इसमें तो यही अच्छा होता कि अंगरेज भारतवर्ष को एक-दम छोड़ देते। यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो हिन्दुस्तानियों को शासन में पूरा हिस्सा देना चाहिए।<sup>१</sup>

**माउंट स्टुआर्ट एलफिंस्टन**—पेशवा से जो राज्य छीना गया, उसको पहले बंगाल सरकार के अधीन रखने का विचार था, पर अन्त में वह बम्बई प्रान्त में मिला दिया गया और एलफिंस्टन, जो पेशवा के यहाँ रेजीडेंट था, बम्बई का गवर्नर बनाया गया। वह अच्छी तरह जानता था कि जनता के लिए पूना का प्रभुत्व भूलना सहज नहीं है, इसीलिए वह बराबर उसके भावों का ध्यान रखता था। उसने वहाँ एक-दम से कोई नया प्रबन्ध नहीं किया। सरदारों के न्यायाधिकार छीने नहीं गये, कलेक्टरों को दीवानी मामलात में यथासम्भव पचायतो द्वारा निर्णय कराने का आदेश किया गया। यह प्रबन्ध अंगरेजी अदालतों को पसन्द न था। सन् १८२३ में

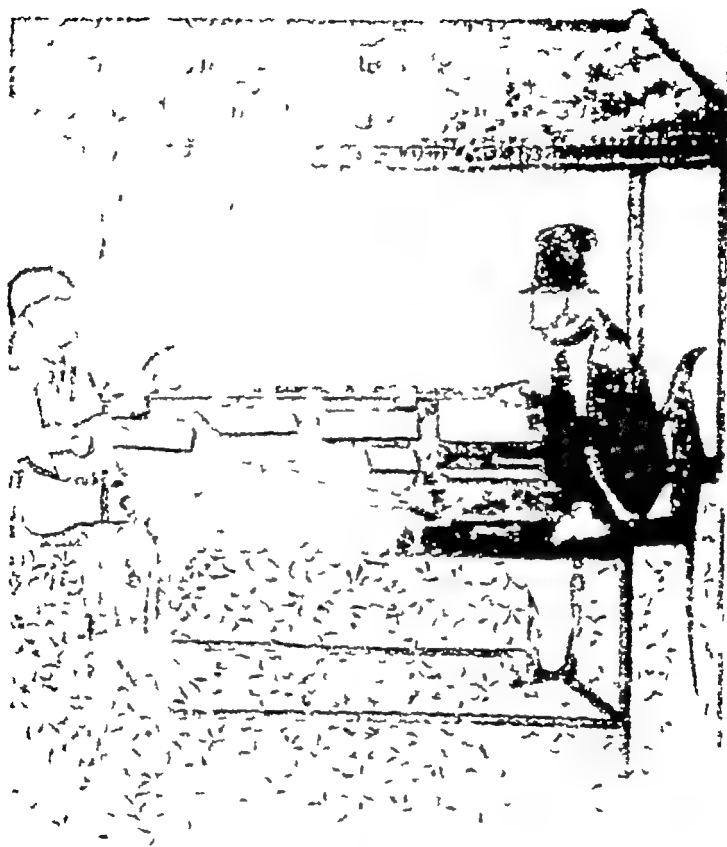
१ अर्बुथोट, सेलेक्शंस फ्रॉम दि मिनिट्स ऑफ सर टामस मनरो, पृ०

बम्बई में 'सुप्रीमकोर्ट' स्थापित हो गया था, वह अपनी अधिकार-सीमा बढ़ाना चाहता था। इसलिए थोड़े समय में अंगरेजी अदालतें खुल गईं और महाराष्ट्र देश से भी पचायतों का लोप हो गया। माल-गुजारी के लिए बाजीराव का चलाया हुआ ठेकेदारी का ढँग उठा दिया गया और मद्रास की तरह यहाँ भी, कुछ फेर-फार के साथ, रैयतवारी बन्दोबस्त किया गया। बाजीराव के पहले भी ऐसा ही प्रबन्ध था। बन्दोबस्त को स्थायी करने के लिए सन् १८२५ में पैमायश प्रारम्भ की गई। पटेलों से पुलिस के अधिकार ले लिये गये और कलेक्टर की अध्यक्षता में सवार तथा पैटल पुलिस रखी गई। इतिहासकार किकेड लिखता है कि बहुत दिनों तक इस नई पुलिस के अफसरो को वह योग्यता प्राप्त नहीं हुई, जो पेशवाओं के समय में प्राप्त थी। एल्-फिस्टन को फारसी का अच्छा ज्ञान था। उसने भारतवर्ष का एक अच्छा इतिहास लिखा है।

**सर जान मालकम**—एल्फिस्टन के बाद सर जान मालकम बम्बई का गवर्नर हुआ। यह भी बहुत दिनों से भारतवर्ष में काम करता था। लार्ड मिंटो के समय में यह फारस भी गया था। देशी राजाओं के स्वभाव को यह खूब पहचानता था और उनसे सहज ही में अपना मतलब निकाल लेता था। बाजीराव को इस पर बड़ा विश्वास था। इमने भी भारतवर्ष का एक अच्छा इतिहास लिखा है। मध्य भारत पर भी इसका एक अच्छा ग्रन्थ है, जिसमें बहुत सी तत्कालीन बातों का बटा रोचक वर्णन है।

**कर्नल जेम्स टाड**—राजपूताना के सम्बन्ध में टाड साहब का नाम प्रसिद्ध है। इसी की सहायता में राजपूत राजाओं के साथ सन्धियाँ हुई थीं। मराठों के विरुद्ध इमने राजपूतों को अच्छी तरह भड़काया था। राजपूतों के लिए इसके हृदय में मत्सा आदर था। इसने बड़े परिश्रम और खोज के साथ राजपूताने के मुख्य राज्यों का इतिहास लिखा है, जो "टाड राज-

स्थान" के नाम से प्रसिद्ध है। बिना इस ग्रन्थ के हमको राजपूतों की बहुत सी बातों का पता ही न चलना।



जैन पंडित और कर्नेल टाड

**लार्ड हेस्टिंग्स का इस्तीफा**—हैदराबाद में पामर कम्पनी महांजी का काम करती थी। निजाम पर उसका बहुत कर्जा हो गया था। धीरे-धीरे कर्नाटक के नवाबवाला हाल निजाम का भी हो रहा था। इस कम्पनी

के एक हिस्सेदार से हेस्टिंग्स का भी कुछ सम्बन्ध था। कहा जाता है कि इसी लिए वह इस मामले में चुप रहता था। सचालको को यह बात पसन्द न आई। इस पर जनवरी सन् १८२३ में उसने इस्तीफा दे दिया। नौ वर्ष के शासन-काल में उसने बहुत कुछ किया। भारतवर्ष की उत्तरी सीमा को उसने हिमालय तक पहुँचा दिया, पिडारियो की बला को दबा दिया और मराठा-मंडल को तोड़-फोड़कर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। कम्पनी के राज्य में उसने बहुत सी भूमि बड़ा दी। इन सब कामों के लिए सचालको से उसको ८० हजार पौंड मिले। उसकी तुलना वारेन हेस्टिंग्स या वेलेजली से नहीं की जा सकती। उसमें न उतनी चतुरता ही थी और न उतनी योग्यता ही। शासन में उसको जो कुछ सफलता हुई, वह योग्य अफसरों के कारण हुई। यह बात अवश्य है कि भारतवर्ष में उसने ब्रिटिश सरकार को “वास्तव में सर्वोच्च” बना दिया, जैसा कि उसका उद्देश्य था।

**विलायती माल—**इस समय तक भारतवर्ष केवल ‘कृषिप्रधान’ देश न बना था। इस समय की दशा का वर्णन करते हुए मनरो का कहना था कि सभी आवश्यक वस्तुएँ यूरोप की अपेक्षा भारतवर्ष में कहीं सस्ती और अच्छी बनती हैं। इनमें सूती तथा रेशमी कपड़े, चमड़ा, कागज, लोहे तथा पीतल के वर्तन और खेती के औजार मुख्य हैं। मोटे ऊनी कपड़े, बहुत अच्छे तो नहीं, पर सस्ते अवश्य होते हैं। बढ़िया कम्बल, हमारे कम्बलों से कहीं अधिक गरम और टिकाऊ होते हैं। भारतवर्ष के लोग वैसे ही व्यापारी हैं, जैसे कि हम लोग। उनके जितने पवित्र स्थान और तीर्थ हैं, वास्तव में वे मेले हैं, जहाँ सब तरह का माल बिकता है। भारतवर्ष में धर्म और व्यापार एक साथ चलते हैं। व्यापार की ओर हिन्दुस्तानियों की प्रवृत्ति देखकर ऐसा जान पड़ता है कि अंगरेजों को वहाँ का व्यापार छोड़ना पड़ेगा। एक बात यह भी है कि हिन्दुस्तानियों का रहन-सहन इतना सादा और कम-खर्च है कि कोई यूरोपियन उनका मुकाबला नहीं कर सकता।<sup>१</sup>

सन् १८१० में पार्लामेंट की कमेटी के मामले कहा गया था कि यदि भारतवर्ष का माल इंग्लैंड में बेचा जाय तो वहाँ के बने हुए माल में ५० से ६० सैकड़ा कमीशन और लाभ के साथ बिक सकता है। मिलरने के 'ओरियंटल कामर्स' नामक ग्रन्थ में भी इस समय की व्यापारिक स्थिति का अच्छा वर्णन मिलता है। डाक्टर बुकानन के 'जर्नल' में दिये हुए विवरण से पता लगता है कि केवल पटना, गाहागढ़, भागलपुर और गोरखपुर के जिलों में, जिनकी आबादी ८३६३१४४ थी, ८१५५०६ लोग कताई का काम करते थे। साल भर में ५३१८१०७ रुपये का मृत काता जाता था। इन जिलों में ४३६६३ करघे चलते थे, जिनमें ५४२७६०१ रुपये माल का कपड़ा बनता था।<sup>१</sup> दक्षिण भारत की भी यही दशा थी। मैसूर में ब्राह्मणों को छोड़कर सभी जाति की स्त्रियाँ कताई का काम करती थीं। केवल मदरास में ५३ लाख रुपये से अधिक का माल बाहर जाना था।<sup>२</sup> इस तरह कताई-बुनाई भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय था।

इस व्यवसाय को चौपट करने का बराबर प्रयत्न हो रहा था। विदेशीय व्यापार को अपने हाथ में न रखकर हिन्दुस्तानियों ने बड़ी भूल की थी। इंग्लैंड ने इससे पूरा लाभ उठाया। अब वहाँ भारत से जानेवाले माल पर ७० से ८० सैकड़ा तक चुगी बढ़ा दी गई और भारत में विलायती माल पर एकदम से चुगी घटा दी गई। विल्सन लिखता है कि यदि ऐसा न किया जाता तो भाक के जोर से भी पेमली और मैक्वेस्टर के मिल न चल पाते। भारतवर्ष में भी विलायती कपड़े के प्रचार करने का भरपूर प्रयत्न किया गया। देश की अन्य कलाओं को भी नष्ट करने में कोई कसर न रखी गई। बेलेजली के समय तक बंगाल में जहाज खूब बनते थे।<sup>३</sup> बम्बई के बने हुए जहाज लन्दन या लिवरपूल के जहाजों से किसी तरह घटिया न होते थे।<sup>४</sup> अब इस बात का

१ पुन्ताम्बेकर और वरदाचारी, हाथ की कताई-बुनाई, (हिन्दी) पृ० ८५।

२ बुकानन, जर्नी क्रॉम मदरास यू मैसूर, कनाडा पेंड मलाबार, सन् १८०७।

३ बेलेजली, डेसपैचेज, स० ओयन, पृ० ७०५।

४ हेवर, जर्नल, जि० २, पृ० ३८०।

प्रयत्न किया गया कि भारतीय जहाजों पर अंगरेज व्यापारी माल न लादा करें। इससे इम कला को भी बड़ा धक्का पहुँचा। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि भारत की मुख्य कलाएँ नष्ट होने लगीं और विलायती माल की खपत बढ़ने लगी। बने हुए माल के बजाय कच्चा माल अधिक बाहर जाने लगा और भारतवर्ष 'आद्योगिक' से 'कृषिप्रधान' देश बनने लगा।

**आर्थिक जीवन**—इंग्लैंड की नीति का देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा विकट प्रभाव पड़ा। कपड़े की कला से बहुतों का निर्वाह होता था। औरत मर्द सभी इसमें काम करते थे। खेती के साथ साथ यह काम हो सकता था। कताई से स्त्रियों को आजकल की दर से दस बीस रुपया साल तक मिल जाता था। इसी तरह प्रति कर्घा २३ से ५३ रुपया तक लाभ होता था। पूरी मेहनत करनेवाले जुलाहे तो साल भर में आजकल की दर से पाँच सौ रुपये में भी अधिक कमा लेते थे।<sup>१</sup> उन दिनों सब चीजों का भाव भी मस्ता था। उस समय की दर से गोहूँ और चावल रुपये का मन भर मिलता था।<sup>२</sup> बुकानन लिखता है कि बहुत अच्छे ढंग से रहनेवाले पाँच आदमियों के कुटुम्ब के खाना-खुराक में ३३५ और कपड़े में २१० रुपया साल खर्च होता था। सबसे गरीब लोगों के इतने बड़े कुटुम्ब का खाने के लिए २१ और पहनने के लिए अठ्ठाई रुपये में ही काम चल जाता था।<sup>३</sup> परन्तु एक और तो कपड़े का व्यापार नष्ट होने लगा और दूसरी ओर लगान ऐसा बढ़ा दिया गया कि खेती में भी अधिक लाभ न रह गया। फल यह हुआ कि बेचारी जनता हर तरह से पिसने लगी। बुकानन का कहना है कि गोरखपुर की दशा नवाबों के समय से भी गईं बीती थी। जहाँ पहले खेती होती थी, वहाँ जमीन ऊसर पड़ी थी। मदराम का इलाका, जो पचास वर्ष

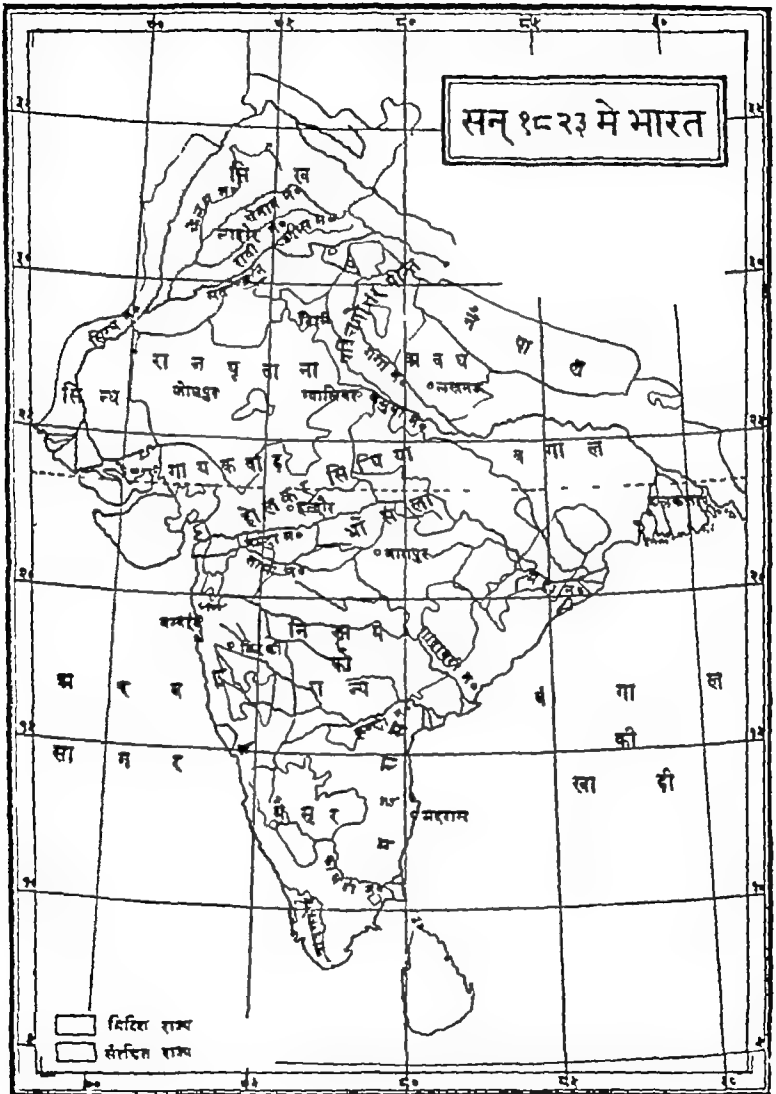
१ हाथ की कताई-बुनाई, पृ० ८६, ८७।

२ मिल्बर्न, ओरियंटल कामर्स, मन् १८१३, जि० २, पृ० १५७।

३ हाथ की कताई-बुनाई, पृ० ८९।



# सन् १८२३ मे भारत





## परिच्छेद १०

### सुधार और शिक्षा

जान ऐडम और अखबार—लार्ड हेस्टिंग्स के चले जाने पर, मात महीने तक, कौंसिल का बड़ा मेम्बर जान ऐडम गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रहा। इसने 'कलकत्ता जरनल' नामक अँगरेज़ी पत्र के सम्पादक को, सरकारी अफसरों की तीव्र आलोचना करने के कारण, पकड़वा कर ज़बर-दस्ती इंग्लैंड भेजवा दिया। भारतवर्ष में सबसे पहला अँगरेज़ी पत्र सन् १७८० में निकला था। वारेन हेस्टिंग्स की स्त्री पर आरोप करने के कारण इसके सम्पादक को बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। लार्ड कार्नवालिस के समय में भी एक सम्पादक को देश-निष्कासन का दंड दिया गया था। लार्ड वेलेजली और मिटो की भी समाचारपत्रों पर बड़ी तीव्र दृष्टि रहती थी। लार्ड हेस्टिंग्स सरकारी कार्यों की विचारपूर्ण आलोचना के विरुद्ध न था, इसी लिए उसके समय में समाचारपत्रों को कुछ स्वतंत्रता मिल गई थी। सन् १८१८ से 'समाचार दर्पण' नाम का एक बँगला साप्ताहिक पत्र भी निकलने लगा था। इस समय तक भारतवासियों का छापाखाना की ओर ध्यान ही न गया था। पहले-पहल पादड़ियों ने कुछ पुस्तकें छपवाई थीं। 'समाचार दर्पण' भी मार्शमैन नाम के एक पादड़ी का ही निकाला हुआ था। जान ऐडम को लार्ड हेस्टिंग्स की नीति पसन्द न थी। उसने यह नियम बना दिया कि बिना सरकारी लाइसेंस लिये हुए किसी को अखबार छापने का अधिकार नहीं है।

लार्ड एमहर्स्ट—अगस्त सन् १८२३ में इंग्लैंड से लार्ड एमहर्स्ट गवर्नर-जनरल नियुक्त होकर आ गया। चीन में यह कुछ समय तक दूत रह

चुका था। इतने दिनों की लड़ाई से मंचालको की नीति में फिर परिवर्तन हो रहा था। उनका कोई निश्चित मिद्धान्त न था, उन्हें केवल रुपये की चिन्ता



एमहर्स्ट

रहती थी। यदि युद्ध से बराबर लाभ होता रहे, तो उसमें कोई दोष न था, पर ज्योंही खर्च बढ़ने लगता था, उसको बन्द कर देने की पुकार मच जाती थी। लार्ड एमहर्स्ट से यह आशा थी कि उसके समय में कोई युद्ध न होगा, पर उसकी नीति ने कम्पनी को ऐसे युद्ध में भिड़ा दिया, जिसका खर्च गत पंडारी तथा मराठा युद्धों से कई गुना अधिक था, जो बराबर दो वर्ष तक चलता रहा और जिसमें विजय होने पर भी ब्रिटिश सरकार की बहुत कुछ हानि हुई।

**बर्मा का राज्य**—जिस समय ब्रिगेज बंगाल में लड़ रहे थे, उन्हीं दिनों, सन् १७६० के लगभग, अलोम्पा नामक एक सरदार ने बर्मा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। वह पहले एक साधारण मनुष्य था, परन्तु उसने थोड़े ही दिनों में अपनी बुद्धि और बाहु-बल से सारे बर्मा को एक बना दिया। वह अधिकतर शावा नगर में रहता था। उसके वंशजों ने राज्य का और भी अधिक विस्तार किया। पहले पीग पर अधिकार करके सन् १७६६ में स्याम राज्य से टेनासरिम छीन लिया गया। सन् १७८४ में अराकान भी जीत लिया गया। यह पहले एक स्वतंत्र राज्य था और इसकी सीमा पश्चिम में ढाका तक थी। सन् १८१३ में बर्मा के राजा ने मनीपुर पर अधिकार कर लिया और सन् १८२२ में उसने आसाम जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह बर्मा का राज्य बंगाल की पूर्वोत्तर सीमा तक पहुँच गया।

**पहला युद्ध**—यह सीमा स्पष्ट न होने के कारण दोनों राज्यों में बहुत दिनों से झगडा चला आता था। अराकान के बहुत से निवासी भागकर अंगरेजों के राज्य में चटगांव के समीप बस गये थे। ये लोग बराबर अराकान की सीमा पर लूट-मार किया करते थे। इनके एक सरदार ने इन दिनों बड़ा ऊधम मचा रखा था। अराकान का बर्मी हाकिम इन लोगों को निकाल बाहर करने के लिए अंगरेजों से बराबर अनुरोध करता था, परन्तु ये लोग उसकी एक भी न सुनते थे और इधर-उधर की बातें ही में टाला करते थे। उसके गठ्ठे में इस स्थान पर “आग और बारूद” दोनों एकत्र हो रहे थे। समझौते से यह प्रश्न हल होते हुए न देखकर बर्मियों ने चटगांव के निकट शाहपुरी नाम के टापू पर अधिकार कर लिया। उनका कहना था कि यह टापू बर्मा राज्य का है। चटगांव और ढाका पर भी वे अपना हक दिखलाने लगे, क्योंकि किसी समय ये स्थान अराकान राज्य में शामिल थे।

दूसरी ओर आसाम में भी झगडे चल रहे थे। वहाँ कई एक छोटे छोटे राज्य थे, जो आपस में लडा करते थे। बर्मा के आधिपत्य से वे सन्तुष्ट न थे। मनीपुर के राज्य का सन् १७६२ से अंगरेजों के साथ सम्बन्ध था। दो तीन और राजा भी अंगरेजों की सहायता से बर्मियों को निकालना चाहते थे। इसके लिए अंगरेजों की कुछ सेना उधर पहुँच चुकी थी और कचार के राजा से सन्धि की बातचीत हो रही थी। बर्मियों की सेना भी दो तरफ से आगे बढ़ रही थी। विक्रमपुर के निकट दोनों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें बर्मी ऐसी वीरता में लडे कि अंगरेजी गिपाहियों को पीछे हटना पडा।<sup>१</sup> इस पर फरवरी सन् १८२४ में युद्ध की घोषणा कर दी गई। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि बर्मियों ने अंगरेजों पर कोई आक्रमण नहा किया था। वे कचार की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके साथ अंगरेजों की इस समय तक सन्धि न हुई थी।

बर्मा के राजा ने महावन्दूला की अध्यक्षता में एक सेना बगाल पर आक्रमण करने के लिए भी भेजी। रामू के निकट अंगरेजी सेना के साथ

<sup>१</sup> लॉरी, अवर बर्मीज वार्म, सन् १८८५, पृ० २१।

इसका युद्ध हुआ, जिसमें कप्तान नोटन मारा गया और अँगरेजी सेना भाग निकली। इस पर फ़्लकते में हलचल मच गया और अँगरेजों को बड़ा भय होने लगा। परन्तु इन ही में समुद्र के मार्ग से एक अँगरेजी सेना रंगून पहुँच गई। इस पर महाबन्दूला वापस बुला लिया गया। गवर्नर-जनरल को बाध ले जाने के लिए वह सेना की जज़ीरे लाया था, लेकिन उसको गाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि सैनिक दृष्टि से यह भूल की गई। उधर आम्बाम में भी कूटनीति में काम लिया गया और देशी राजाओं को अपने पक्ष में मिलाकर बर्मियों को वहाँ से हटाया गया।

**वारिकपुर का विद्रोह**—इस युद्ध के बीच ही में कलकत्ता के निकट वारिकपुर में एक बड़ा उपद्रव हो गया। यहाँ पर हिन्दुस्तानी सेना की एक बड़ी छावनी थी। उन दिनों बंगाल के हिन्दुस्तानी सैनिकों को कई एक शिकायतें थीं। बम्बई और मदरास के सिपाहियों से उनको भत्ता कम मिलता था। गोरों के लिए तम्बू लग जाते थे और उनका सामान लाट ले चलने का



वारिकपुर की कोठी

सब प्रबन्ध कर दिया जाता था, पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों के कष्ट का कुछ भी ध्यान न रखा जाता था। रहने के लिए सूपड़े तक उन्हें स्वयं ही बनाने पड़ते

ये। बर्मा में युद्ध छिड़ने पर समुद्र के मार्ग से बंगाल की सेना को रंगून भेजना निश्चित किया गया था। इस सेना में बहुत से कुलीन थे, जो समुद्र-यात्रा निषिद्ध मानते थे। कुछ लोग अलग अलग अपने वर्तन ले जाना चाहते थे, जिनके डोने के लिए अफसर कोई प्रबन्ध नहीं कर रहे थे। उनकी इन सब शिकायतों पर कुछ भी ध्यान न दिया गया और कहा गया कि वे आज्ञा न मानकर विद्रोह करना चाहते हैं। कलकत्ता से गोरी सेना बुलाकर उनको घेर लिया गया और पहली नवम्बर सन् १८२४ को कवायद करने से इनकार करने पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई। इसमें बहुत से सिपाही मारे गये। कई एक नेताओं को फासी दी गई और बहुतों को जेल में रखकर सड़क पीटने का काम दिया गया। समझाने-बुझाने से ही यह उपद्रव शान्त हो सकता था। सिपाहियों की शिकायतों में बहुत कुछ सत्यता थी। किसी तरह की हानि पहुँचाना उनका उद्देश्य न था। पास की ही कोठी में लार्ड एम-हर्स्ट ठहरा हुआ था। यदि वे लोग चाहते तो उस पर आक्रमण कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी जो बन्दूकें मिलीं, वे सब खाली थीं। ऐसी दशा में पहले उन पर गोली चलाना और फिर कठोर दंड देना उचित नहीं कहा जा सकता। अन्य सैनिकों पर भी इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। बर्मा युद्ध की अश्वफलता और इसका समाचार मिलने पर सचालकों ने एमहर्स्ट को वापस बुलाना निश्चित कर लिया, परन्तु यह पता लगने पर कि इसमें गवर्नर-जनरल का अधिक डोप नहीं था, ऐसा नहीं किया गया।

**बर्मा में युद्ध—**बंगाल में सेना को रंगून भेजने का विचार छोड़ दिया गया और सर आर्चीबाल्ड कैम्पबेल की अध्यक्षता में मदरास से सेना भेजी गई। इस सेना ने मई महीने में रंगून पर अधिकार कर लिया, परन्तु यहाँ इसमें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। बर्मियों ने सारा देश उजाड़ कर दिया था, रमद का कोई प्रबन्ध न था, बरसात शुरू हो गई थी, नदियाँ भरी हुई थीं, अंगरेजों को देश का अधिक ज्ञान न था और बीमारी भी फैल रही थी। ऐसी दशा में बहुत दिनों तक अंगरेजी सेना पड़ी रही। इतने में बंगाल से

महाबन्धूला भी आ पहुँचा और अच्छी तरह से युद्ध प्रारम्भ हो गया। रंगून से कुछ दूरी पर हमने अपने पडाव को बड़े यत्न से सुरक्षित बना रखा था।



एक अंगरेज लिखता है कि हम सम्बन्ध में हमकी योग्यता किसी वैज्ञानिक इंजीनियर से कम नहीं थी। यहाँ पर अचानक गोली लग जाने से हमकी मृत्यु हो गई। महाबन्धूला बड़ा योग्य और वीर मेना पति था।<sup>१</sup> यदि वह जीवित रहता तो अंगरेजों के लिए हम युद्ध में विजय पाना सहज नहीं था। इधर अंगरेजी सेना ने अराकान और टेनासरिम पर अधि-कार कर लिया। महाबन्धूला के मरने पर कैम्पबेल ने आगे बढ़कर प्रोम नगर भी जीत लिया।

बर्मियों का जंगी मच्चान

इस पर सन्धि की बातचीत होने लगी।

**यांडबू की सन्धि**—फरवरी सन् १८२६ को यांडबू नामक स्थान पर सन्धि हो गई। अंगरेजों को आसाम, अराकान और टेनासरिम के सारे मिल गये। आसाम में कचार, जयन्तिया और मनीपुर के राज्य बर्मा के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गये। अंगरेजों को लडाई का खर्च भी मिला और

<sup>१</sup> स्नॉडग्र्यास, नैरोटिव आफ दि बर्मीज वार, सन् १८२७, पृ० १७५-७६।

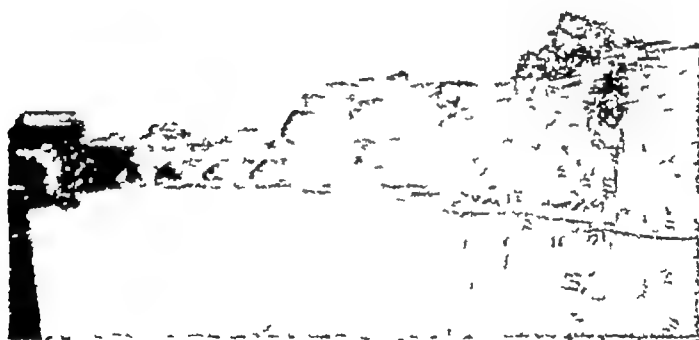
वर्मा के राजा ने अपने दरबार में अंगरेज रेजीडेंट भी रखना स्वीकार किया।  
वर्मियों के हाथ से बहुत सा समुद्र-तट निम्नल गया और बंगाल की पूर्वीय



सन्धि-सम्मेलन

सीमा सुरक्षित हो गई। इस युद्ध में वर्मा बड़ी वीरता से लड़े, उनके दूत  
मराठा राजाओं तक पहुँचना चाहते थे और भारतवासियों के साथ मिलकर

धा और आक्टरलोनी, जो सेना लेकर भरतपुर की ओर बढ़ रहा था, वापस बुला लिया गया था। 'गुप्त कमेटी' का भी कहना था कि हमारी शक्ति की वृद्धि से अन्य राज्यों के घरेलू मामलात में हस्तक्षेप करने का हमारा अधिकार भी बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं माना जा सकता। परन्तु मेटकाफ की दलीलों में पढ़कर गवर्नर-जनरल को अपना मत बदलना पड़ा। उसका कहना था कि सन्धियों द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं, इसका कोई प्रश्न नहीं है। "माधारण शान्ति, नियम और अधिकारों के सर्वोच्च संरक्षक" होने के कारण बालक को गद्दी पर बिठलाये रखना, हमारा कर्तव्य है।<sup>१</sup> इस पर "समझा-बुझाकर" या "बलात्" इस कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा दे दी गई।



### भरतपुर का किला

मेटकाफ से, जिसका भरतपुर की पिछली हार के सम्बन्ध में मत दिखलाया जा चुका है, यह आज्ञा करना व्यर्थ था कि वह "समझा-बुझाकर" अपना काम निकालेगा। दिसम्बर सन् १८२५ में २५ हजार सेना के साथ भरतपुर घेर लिया गया। इस घार लार्ड कम्बरमियर सेनापति था। सबसे पहले उस झील पर, जहाँ से किले के चारों ओर की खाई में पानी आता था, अधिकार



राजा, नागपुर के भोमला, यहाँ तक कि सिंहासनच्युत पेशवा भी न छोड़ा गया। लार्ड एमहर्स्ट, इतिहासकार स्मिथ के शब्दों में, गवर्नर-जनरल के उच्च पद के योग्य न था, इस पर उसका नियुक्त करना भूल थी। परन्तु तब भी बर्मा और भरतपुर के युद्ध में विजय के लिए पार्लामेंट की ओर से उसको बधाई दी गई और 'शर्ल' की उपाधि प्रदान की गई।

दौलतराव सिन्धिया की मृत्यु—सन् १८२७ में दौलतराव सिन्धिया की मृत्यु हो गई। तीस वर्ष तक उसके नाम से भारतवर्ष के

इतिहास में हलचल मचा रहा। किसी समय सारे उत्तरी भारत में उसका आतंक था, दिल्ली का बादशाह उसके हाथ में था, राज-पूत राजा उसके चौथ देते थे, पेशवा पर उसका पूरा अधिकार था और दोआब, बुंदेलखंड तथा मालवा के अधिक भाग में उसका राज्य था। रेजीडेंट मेजर स्टिवार्ट के शब्दों में उसकी समझ में किसी प्रकार की



दौलतराव सिन्धिया

कमी न थी। उसका स्वभाव नम्र और मीठा था, परन्तु इससे उसके

गवर्नर-जनरल बना दिया गया। जुलाई सन् १८२८ में वह कलकत्ता पहुँचा। तब तक कौंसिल का सदस्य बटरवर्थ वेली गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रहा।

**शासनसुधार**—पन्चसे पहले आर्थिक दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया गया। इन दिनों खर्च और आमदनी में एक करोड़ रुपया साल का अन्तर पड़ रहा था। सैनिकों को शान्ति के समय में भी आधा भत्ता मिलता था। अन्य विभागों के अफसरों को भी बड़े बड़े वेतन मिलते थे। संचालकों की आज्ञा से सैनिकों का भत्ता बन्द कर दिया गया, कुछ सेना भी घटा दी गई और अन्य विभागों में भी वेतन कम कर दिया गया। इस पर अंगरेजों में बड़ा असन्तोष फैला और बेटे क को बहुत कुछ बुरा-भला सुनना पड़ा। खर्च घटाने के साथ साथ आमदनी बढ़ाने का भी प्रयत्न किया गया। आगरा प्रान्त में जमीन्दारों के साथ तीस वर्ष के लिए बन्दोबस्त किया गया और इलाहाबाद में मालविभाग का बड़ा दफ्तर 'बोर्ड ऑफ रेविन्यू' खोला गया। इस प्रबन्ध में प्रान्त की मालगुजारी बहुत बढ़ गई। मालवा की अफीम करार्ची होकर चीन को जाती थी और वहाँ कम्पनी की बगालवाली अफीम से गस्ती विकती थी, जिसमें कम्पनी को बड़ा घाटा होता था। बेंटिंक ने यह नियम बना दिया कि मालवा की सब अफीम बम्बई होकर कम्पनी द्वारा चीन जाया करे। इससे मालवा के राज्यों और अफीम के काश्तकारों को बड़ा घाटा हुआ, पर कम्पनी का काम बन गया। बहुत से लोगों के पास 'लाखिराज' अर्थात् कर न देनेवाले इलाके थे। इनमें से कुछ लोगों के मरने पर, कोई लडका न होने के कारण, उनके इलाके जव्त कर लिये गये और 'लाखिराज' इलाकों के उत्तराधिकार का निर्णय कलेक्टर के हाथ में छोड़ दिया गया। जान मालकम लिखता है कि यदि ऐमा करना था तो इलाके देना ही व्यर्थ था। इन जव्तियों से कम्पनी की आमदनी अवश्य बढ़ गई, पर साथ ही साथ कितने ही बड़े बड़े हिन्दुस्तानी घराने नष्ट हो गये।

न्याय के प्रबन्ध में भी कुछ परिवर्तन किया गया। बहुत से मुकदमों में पिछले पड़े हुए थे, अंगरेज जजों को रखने में बड़ा खर्च पड़ता था। इसलिए हिन्दु-

यात्रियों को अपनी बातों में फुसला लेते थे और जंगल में या किसी एकान्त स्थान में पहुँचने पर गले में रुमाल का फन्दा डालकर उनको मार डालते थे और सब माल-असबाब छीन लेते थे। फाँसी लगाने में ये बड़े निपुण होते थे, इनका वार कभी खाली नहीं जाता था, इसी लिए ये 'फाँसीगर' भी कहलाते थे। इनके सब काम गुप्त होते थे। लाखों तक इस ढँग से छिपा दी जाती थीं कि किसी को कुछ भी पता न लगता था। ये सभी जगह बने रहते थे और आवश्यकतानुसार भेप बदला करते थे। इनके किसी किसी दल में ३०० से भी अधिक मनुष्य रहते थे। ये काली का पूजन करते थे और लडकों को अपने दलों में भर्ती किया करते थे। ये प्रायः स्त्रियों को न मारते थे।

मुसलमानों के समय में भी ये बड़ा उधम मचाया करते थे। कहा जाता है कि अकबर ने केवल इटावा के जिले में पाँच सौ ठगों को फाँसी लटकवा दिया था। औरंगजेब ने भी बहुतों को प्राणदण्ड दिया था। इधर राजनैतिक अशान्ति के कारण इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। बहुत से बेकार सिपाही इनमें शामिल हो गये थे। कुछ जमीन्दार और व्यापारी भी इनकी गुप्त रीति से मदद करते थे और लूट का माल लेते थे। इनके दमन करने का काम कर्नल स्लीमैन को सौंपा गया। उसको फिरंगिया नाम के एक मुखविर से इनकी सब गुप्त बातों का पता लग गया। चारों ओर से इनकी खोज होने लगी, प्राण बचाने के लिए बहुत से मुखविर हो गये और ६ वर्ष में लगभग ३२६६ ठग पकड़ लिये गये। इनमें बहुतों को फाँसी लगाई गई और बहुत से कालेपानी भेज दिये गये। मुखविर जव्वलपुर में रख दिये गये और उनके लडकों को खेती-बारी सिखलाने का प्रबंध कर दिया गया।

**सती-प्रथा का अन्त**—सती का अर्थ वाम्त्व में पतिभक्ता स्त्री है। पति की सहगामिनी बनने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ उसके मरने पर चिता में जलकर प्राण त्याग देती थीं। इसी लिए इस तरह जल मरने का नाम 'सती होना' पड़ गया। प्राचीन समय से भारत में स्त्रियाँ बराबर सती हुआ करती थीं। परन्तु प्रत्येक स्त्री के लिए सती होना आवश्यक है, ऐसा किसी धर्म-शास्त्र में उल्लेख नहीं है। सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर रहता था।

देने के अतिरिक्त, कोई उपाय न था। सन् १८१८ में अमेले कलकत्ता प्रान्त में २४४ सतिरिया हुई थीं। स्वयं हिन्दुओं में इसके विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ ठाकुर इसके रोकने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे।

लार्ड वेंटिक को यह अच्छा अवसर मिल गया। उसने इस विषय की पूरी जांच करवाई, बड़े बड़े अफसरों से सलाह ली, निजामत अदालत का मत लिया और इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी सेना तथा पुलिस की राय जानने का भी प्रयत्न किया। जब उसको यह मालूम हो गया कि अधिकांश लोगों का मत इस प्रथा के विरुद्ध है, तब उसने इसके लिए कानून बनाना निश्चित कर लिया। परन्तु बहुतों को सन्देह था कि कानून बनाने से बड़ा उपद्रव मचेगा। कुछ लोगों की राय में सेना में विद्रोह हो जाने का भय था। स्वयं राजा राममोहन राय का भी ऐसा ही अनुमान था। परन्तु सन् १८२६ में गवर्नर-जनरल ने बंगाल में इस प्रथा के वन्द करने का कानून पार कर दिया। इस पर कोई उपद्रव नहीं हुआ, इसी से सिद्ध है कि जनता इसके वन्द करने ही के पक्ष में थी। कुछ बगालियों ने इस कानून को तोड़ने के लिए पार्लामेंट को लिखा और मुकदमे चलाये, परन्तु राममोहन राय की सहायता से यह आन्दोलन थोड़े ही दिनों में शान्त हो गया। सन् १८३० में बम्बई और मद्रास प्रान्तों में भी यह कानून पार कर दिया गया। इस सम्बन्ध में लार्ड वेंटिक का साहस सराहनीय है। जो स्त्री पति की सहगामिनी बनना निश्चित कर लेती है, उसको रोकनेवाला अब भी कोई नहीं है। कानून और पुलिस होते हुए भी वह किसी न किसी तरह आत्म-श्लिष्टान कर ही देती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस कानून में उन महत्त्वो स्त्रियों की रक्षा हो गई, जिनका उनकी इच्छा के विरुद्ध बलिदान कर दिया जाता था।

**देशी राज्य**—इनके सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की कोई निश्चित नीति न थी। जिस नीति से अपना काम बनता था, उसी का किसी न किसी तरह समर्थन किया जाने लगता था। कहने के लिए तो वेंटिक 'हम्सलेप न

लडका न था, इसलिए "प्रजा की इच्छा" से कुर्ग अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया।<sup>१</sup> यहाँ बहुत से अंगरेज बस गये हैं, जो काफी की खेती कराते हैं। यहाँ का शासन एक कमिश्नर के हाथ में है, जो मैसूर के रेजीडेंट की निगरानी में काम करता है। पदच्युत राजा बनारस भेज दिया गया। सन् १८५० में इंग्लैंड जाकर उसने कम्पनी पर दावा किया, परन्तु वह खारिज हो गया। उसकी लडकी ने ईसाई होकर एक अंगरेज से शादी कर ली।

कहने के लिए निजाम के साथ बराबरी का सम्बन्ध था। इस समय तक उसको पत्र लिखने में कम्पनी अपने लिए 'न्याजमन्द' (कृपापात्र) शब्द का प्रयोग करती थी। पर तब भी उसके शासन में हर तरह से बाधाएँ डाली जाती थीं। सहायक सेना के अतिरिक्त उसको एक अपनी सेना भी रखनी पड़ती थी, जिसके सब्र अफसर अंगरेज होते थे। इनको केवल भत्ते में १४ लाख रुपया साल दिया जाता था। चार्ल्स मेटकाफ का कहना था कि हम उसके राज्य में ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो किसी सन्धि के अनुसार उचित नहीं कहा जा सकता। हमने एक ऐसे आदमी (राजा चन्दूलाल) को दीवान बना दिया है, जो हमारी सहायता के कारण राज्य का शासक बन बैठा है और अपने स्वामी की कुछ भी पर्वाह नहीं करता है। ऐसी दशा में शासन के दोषों के लिए हम निजाम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वास्तव में उनके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि उनके दूर करने का उपाय हमारे हाथ में है।<sup>२</sup> बेंटिक ने निजाम के साथ पत्र-व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग उठा दिया, जिनमें निजाम का बड़प्पन जाहिर होता था। परन्तु राज्य की दशा सुधारने की ओर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उल्टे निजाम और उसके दीवान को राज्य बरवाद करने की स्वतंत्रता दे दी।

१ इस अवसर पर कुर्ग-निवासियों ने राज्य के एक भाग में गावेष न होने देने का ब्रिटिश सरकार से वचन ले लिया। हॉलर, ए गार्ट हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इटिया, पृ० ५३४।

२ प्रिविल, हिस्ट्री ऑफ़ दि टेकन, जि० २, पृ० १७६-७९।

बर्मा-युद्ध के समय पर आसाम के कई एक राज्यों से सन्धियाँ की गई थीं। इनमें कचार, जयन्तिया और मनीपुर के राज्य मुख्य थे। कचार के राजा के मरने पर, कोई लड़का न होने के कारण, उसका राज्य 'प्रजा की इच्छा' से जब्त कर लिया गया। जयन्तिया के राजा पर भी बहुत से अपराध लगाये गये। कहा गया कि उसके राज्य में तीन चार अँगरेज मार डाले गये हैं। मार्च सन् १८३५ में उसका राज्य भी ले लिया गया। इन राज्यों की शासन-व्यवस्था ऐसी बुरी न थी। जयन्तिया में बड़े बड़े मामलों के निर्णय में राजमाता, मंत्री और बड़े बड़े सरदारों की राय लेना राजा के लिए आवश्यक था।

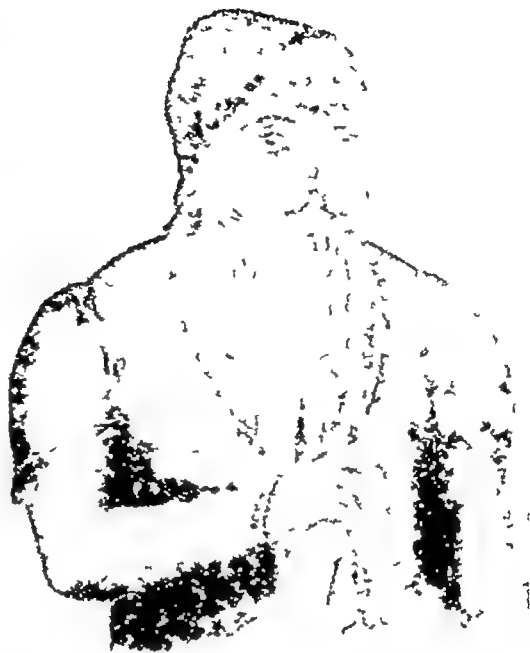
**रूस का भय**—फ़ासीसियों के भय के कारण मराठों का राज्य हड़प कर लिया गया। अब कहा जाने लगा कि हेरात और कन्दहार होकर रूस भारत पर आक्रमण करना चाहता है। उससे रक्षा करने के लिए पंजाब, सिन्ध और अफगानिस्तान में अँगरेजी शक्ति दृढ़ करना आवश्यक है। इसी नीति के अनुसार सिन्ध के अमीरों को एक व्यापारिक सन्धि करने के लिए मजबूर किया गया, पर वास्तव में इसका उद्देश्य राजनैतिक था। तब भी इसमें लिखा गया कि दोनों पक्ष "एक दूसरे के राज्य पर लालच की दृष्टि कभी न डालेंगे।" इस समय तक अँगरेजों को सिन्ध नदी का अधिक ज्ञान न था, इसके लिए भी एक चाल चली गई। गाँटी और घोडे के उपहार महाराजा रणजीतसिंह को इस नदी के मार्ग से भेजे गये। सीधे-साधे अमीरों को इस चाल का पता भी न लगा। इसके अतिरिक्त रणजीतसिंह के दबाव के कारण वे कुछ कह भी न सकते थे। अफगानिस्तान से भागे हुए शाहशुजा को भी दोस्तमुहम्मद से राज्य छीनने के लिए बर्माहित किया गया। इसी के कारण आगे चलकर अफगानिस्तान से युद्ध हुआ। रणजीतसिंह से भी घनिष्ठ मित्रता करने का प्रयत्न किया गया। उन दिनों उम्र मार्ग से रूसियों का आना एक प्रकार से असम्भव सा था, पर कहा यह जाता था कि "भारतवर्ष में हम लोग बारूद की नली पर बैठे हैं, न जाने किस दिन वह फूट पड़े।" इसलिए पहले ही से प्रवन्ध कर लेना उचित है।

**सिखों का राज्य**—इतने दिनों में महाराजा रणजीतसिंह ने अपने राज्य को बहुत बड़ा लिया था। दस वर्ष तक घोर युद्ध करके उसने सन् १८१६ में मुलतान ले लिया। यहाँ का नवाब मुजफ्फरगढ़ की वीरता से लड़ता हुआ मारा गया। सन् १८१६ में उसने काश्मीर भी जीत लिया, इसमें उसका राज्य दुगुना हो गया। अहमदशाह दुर्रानी के समय से यहाँ अफगानियों का राज्य था। महाराज की बहुत दिनों में इस पर दृष्टि लगी हुई थी। सन् १८२६ के लगभग काँगड़ा का राजपूत राज्य भी ले लिया गया। पंजाब के जितने छोटे छोटे मुसलमान राज्य थे, उन सबको उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। सन् १८२० में उसके राज्य की सीमा सतलज से लेकर सिन्ध नदी तक पहुँच गई। सन् १८२३ में उसने पेशावर पर भी अधिकार कर लिया। हजारों पहले ही में उसको मिल गया था। इस पर पश्चिमोत्तर सीमा के मुसलमानों ने 'जिहाद' छेड़ दी। कई वर्षों तक बराबर युद्ध होता रहा। दो एक नामी सिख सरदार काम आये, परन्तु अन्त में हरीमिह नलवा की विजय हुई। सन् १८३३ में ग़ाहशुजा ने पेशावर पर रणजीतसिंह का अधिकार मान लिया। यह काबुल से निकाल दिया गया था, और रणजीतसिंह की शरण में रहता था। इसी से रणजीतसिंह को प्रसिद्ध 'कोहनूर' हीरा मिला था। हरीमिह नलवा पेशावर का सेनापति बनाया गया। सन् १८३५ में खैबर घाटी की रक्षा के लिए उसने जमरूद में एक दुर्ग बनवाया। काबुल से दोस्तमुहम्मद ने इस पर दो बार आक्रमण किया, परन्तु हरीसिंह ने बड़ी वीरता से इसकी रक्षा की। दूसरे आक्रमण में वह स्वयं मारा गया, पर लाहौर से सिख सेना ने आकर अफगानियों को भगा दिया।

**ब्रिटिश और रणजीतसिंह**—सिखों के इस राज्य-विस्तार से अंगरेजों को बड़ा भय हो रहा था। अब वे किसी न किसी तरह सिन्ध नदी को अपनी पश्चिमोत्तर सीमा बनाने के लिए चिन्तित हो रहे थे। इसी लिए सिन्ध के अमीरों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा रहा था। सन् १८०६ की सन्धि से अंगरेजों को सतलज के पश्चिम और पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी,

तब भी सिन्ध पर उसका अधिकार न जमने पावे, इसके लिए बराबर प्रयत्न किया जा रहा था। साथ ही साथ उसके सन्देह को दूर रखने के लिए मित्रता भी बढ़ाई जा रही थी। सन् १८३१ में

मतलज नदी के तट पर रुपुर में लार्ड ब्रेंटिक ने उसके साथ भेंट की। इस अवसर पर दोनों ओर से एक दूसरे को अपनी अपनी सैनिक शक्ति दिखलाने का प्रयत्न किया गया। इंग्लैंड के राजा चौथे विलियम ने रणजीतसिंह को पत्र लिखा और अंगरेजी घोड़े उपहार में भेजे। यह मुलाकात राजनैतिक दृष्टि से खाली न थी। दूसरे माल एक व्यापारिक सन्धि की गई और



रणजीतसिंह

गाहशुजा की सहायता करने के लिए भी उसमें कहा गया। अंगरेजों की नीति को वह समझता था। वह जानता था कि सिन्ध और अफगानिस्तान की ओर से भी उसके राज्य को घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु केवल सन्देह के कारण अंगरेजों की प्रबल शक्ति से वह वैर न करना चाहता था, इसी लिए वह चुप रहा।

**कम्पनी का आज्ञापत्र**—सन् १८३३ में कम्पनी का आज्ञापत्र फिर दोहराया गया। सन् १८२६ से ही एक कमेटी द्वारा जांच हो रही थी।





ही शिक्षा अधिक होती थी। साथ ही साथ जन साधारण की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए भी कुछ प्रबन्ध था। बड़े बड़े गाँवों और नगरों में इसके लिए पाठशाला और मकतब थे, जिनमें किसान तथा व्यापारियों के लड़कों को लिखना-पढ़ना सिखलाया जाता था। ऐडम लिखता है कि बंगाल में केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बहुत से कायस्थ तथा शूद्र भी पढ़ाते थे। “अज्ञत जातियों” के भी बहुत से लड़के पढ़ाये जाते थे। लड़कों को पढ़ने के पहले लिखना सिखलाया जाता था, जो आधुनिक ‘माटसोरी सिस्टम’ का मुख्य सिद्धान्त है। डाक्टर गेंड्रूजवेल को स्कूलों में ‘मॉनीटर’ रखने के ढंग का पता भारत की पाठशालाओं से ही चला था।<sup>१</sup> उन दिनों राज्यों में कोई ‘शिक्षा-विभाग’ न थे, यह बात ठीक है, परन्तु जैसा कुछ समाज का संगठन था, उसमें इसकी कोई आवश्यकता ही न थी। हर एक गाँव में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध रहता था। गाँववाले प्रायः इसको स्वयं ही कर लेते थे, राज्य का उससे कोई विशेष सम्बन्ध न रहता था। मन्दिर तथा मसजिदों में ही पढ़ाई हुआ करती थी। शिक्षकों का पालन गाँववाले ही करते थे। कहीं कहीं जमीन्दार या धनी व्यापारी भी अपनी बैठकों में पाठशालाएँ खोल देते थे। तीर्थों के बड़े बड़े विद्यापीठों को राज्यों की ओर से सहायता मिलती थी और विद्वानों के लिए दक्षिणा का प्रबन्ध रहता था। इन विद्यालयों के अतिरिक्त घरों पर भी पढ़ाई होती थी। स्त्रियों की शिक्षा के लिए विद्यालय न थे, पर बहुत सी स्त्रियों को घर पर थोड़ी बहुत शिक्षा अवश्य दी जाती थी।

अंगरेज़ी शासन से गाँवों का प्राचीन संगठन और देशी राज्य दोनों नष्ट हो रहे थे। इसलिए देश की सभी बातों में बाधाएँ पड़ रही थीं, पर तब भी इस समय तक शिक्षा का प्रबन्ध था। गाँव के शिक्षकों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए सन् १८१४ के एक ‘खरीते’ में कम्पनी के संचालक लिखते हैं कि

इसके नेता प्रिमेप भाई और डाक्टर होरेस विल्सन थे। दूसरा दल अंगरेजी भाषा के पक्ष में था, जिसके लिए मैकाले, मेटकाफ और राममोहन राय आन्दोलन कर रहे थे। मैकाले, जिसको किसी पूर्वीय भाषा के एक अक्षर तक का ज्ञान नहीं था, सारे पूर्वीय साहित्य की हँसी उड़ा रहा था। उसकी राय में भारतवर्ष और अरब का कुल साहित्य यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भर भी नहीं था। उसका कहना था कि हिन्दुओं की ज्योतिष पर अंगरेज लड़कियों को हँसी आयेगी। इतिहास और भूगोल का तो कुछ कहना ही नहीं है। पुराणों में राजाओं की हजारों वर्ष की आयु लिखी हुई है और क्षीरसागरो का वर्णन है। ऐसी शिक्षा में धन खर्च करना व्यर्थ है। अंगरेजी शासकों की भाषा है, व्यापार उन्हीं के द्वारा होता है, वह ज्ञान का भांडार है। इसलिए अंगरेजी भाषा द्वारा ही शिक्षा होना आवश्यक है। अन्त में उसी के मत की विजय हुई और मार्च सन् १८३५ में गवर्नर-जनरल ने अपनी कौंसिल में यह निश्चित किया कि भारतवासियों में “यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी दशा में शिक्षा के लिए जो धन है उसका सबसे अच्छा उपयोग केवल अंगरेजी शिक्षा में ही हो सकता है।”

**अंगरेजी शिक्षा का प्रभाव**—कहा जाता है कि लार्ड वेंटिंक ने भारतवर्ष के साथ यह बड़ा भारी उपकार किया, उसने देश को अज्ञानता के अन्धकार से बचा लिया। पर वास्तव में उन दिनों इसका उद्देश्य दूसरा ही था। उस समय छोटे छोटे ओहदों पर अंगरेजी पढ़े हिन्दुस्तानियों की बड़ी आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त भारतवासियों पर पाश्चात्य मभ्यता का आतंक जमाना था। अंगरेजी शिक्षा से कम्पनी के लेखकों की कमी न रही और अंगरेजी पढ़े हुए लोग बहुत सी बातों को भूलकर अपनी मभ्यता को तुच्छ समझने लगे। मैकाले ने तभी लिखा था कि इसमें एक भी मृत्तिपूजक वाकी न रह जायगा। इस तरह राजनैतिक विजय के साथ साथ मानसिक विजय का भी प्रारम्भ हो गया। पहले बहुत दिनों तक इस शिक्षा का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा।

इसके नेता प्रिसेप भाई और डाक्टर होरेस विल्सन थे। दूसरा दल अंगरेजी भाषा के पक्ष में था, जिसके लिए मैकाले, मेटकाफ और राममोहन राय आन्दोलन कर रहे थे। मैकाले, जिमको किसी पूर्वीय भाषा के एक अच्छे तक का ज्ञान नहीं था, सारे पूर्वीय साहित्य की हँसी उड़ा रहा था। उसकी राय में भारतवर्ष और अरब का कुल साहित्य यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भर भी नहीं था। उसका कहना था कि हिन्दुओं की ज्योतिष पर अंगरेज लड़कियों को हँसी आयेगी। इतिहास और भूगोल का तो कुछ कहना ही नहीं है। पुराणों में राजाओं की हजारों वर्ष की आयु लिखी हुई है और चौरसागरो का वर्णन है। ऐसी शिक्षा में धन खर्च करना व्यर्थ है। अंगरेजी शासकों की भाषा है, व्यापार उसी के द्वारा होता है, वह ज्ञान का भांडार है। इसलिए अंगरेजी भाषा द्वारा ही शिक्षा होना आवश्यक है। अन्त में उसी के मत की विजय हुई और मार्च सन् १८३५ में गवर्नर-जनरल ने अपनी कौंसिल में यह निश्चित किया कि भारतवासियों में “यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी दशा में शिक्षा के लिए जो धन है उसका सबसे अच्छा उपयोग केवल अंगरेजी शिक्षा में ही हो सकता है।”

**अंगरेजी शिक्षा का प्रभाव**—कहा जाता है कि लार्ड बेंटिंक ने भारतवर्ष के साथ यह बड़ा भारी उपकार किया, उसने देश को अज्ञानता के अन्धकार से बचा लिया। पर वास्तव में उन दिनों इसका उद्देश्य दूसरा ही था। उस समय छोटे छोटे ओहदों पर अंगरेजी पढ़े हिन्दुस्तानियों की बड़ी आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त भारतवासियों पर पाश्चात्य सभ्यता का आतंक जमाना था। अंगरेजी शिक्षा से कम्पनी को लेखकों की कमी न रही और अंगरेजी पढ़े हुए लोग बहुत सी बातों को भूलकर अपनी सभ्यता को तुच्छ समझने लगे। मैकाले ने तभी लिखा था कि इससे एक भी मूर्तिपूजक बाकी न रह जायगा। इस तरह राजनैतिक विजय के साथ साथ मानसिक विजय का भी प्रारम्भ हो गया। पहले बहुत दिनों तक इस शिक्षा का प्रभाव अच्छा नहीं पटा।

है' इस सिद्धान्त को वह कभी न भूला। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उसको प्रजाहित का भी कुछ ध्यान था। इन दिनों सारे देश में गान्धि थी, युद्ध का कोई भय न था, इसलिए वह कुछ सुधार कर सकता था। मती-प्रथा के रोकने में उसने अवश्य साहस दिखाया, पर इससे अँगरेजों का कुछ बनता बिगड़ता न था। प्रायः वह ऐसी भाषा का प्रयोग करता था, जिससे जान पड़े कि उसको सदा प्रजा की चिन्ता रहती थी। लार्ड वेलेजली भी ऐसा ही करता था। यह गुण प्रायः सभी अँगरेज राजनीतिज्ञों में पाया जाता है। अफगान-युद्ध का बीज रूसी के समय में बोया गया, जिसका उसके जाने के बाद ही भयंकर परिणाम हुआ।

**राजा राममोहन राय**—यदि उस समय कोई भारतवासी था, जो देश की नई परिस्थिति को समझ सका था, तो वह राजा राममोहन राय था। संस्कृत, अरबी तथा फारसी का वह बड़ा पंडित था। हिब्रू, ग्रीक, लटिन तथा अँगरेजी का भी उसके अच्छा ज्ञान था। सूफी मत तथा वेदान्त का उस पर बड़ा



राजा राममोहन राय

प्रभाव पड़ा था। तिब्बत जाकर उसने बौद्धधर्म का भी अध्ययन किया था। अँगरेजों से उसका बड़ा मेल था और वह उनका रहन-सहन भी पसन्द

करता था। हिन्दू धर्म के पापंडवाद और कुलीनता का वह घोर शत्रु था। अपनी भावज को सती होते देखकर, उसने इस प्रथा को बन्द करवाने का प्रण कर लिया था। स्त्रियों को वह शिचा देकर स्वतंत्र करना चाहता था। समाचारपत्रों और सभाओं द्वारा उसने बड़ा आन्दोलन मचा रखा था। कट्टर हिन्दू और ईसाई दोनों ने उसके मार्ग में बाधा डालने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वह बराबर उठा रहा। सन् १८३० में दिल्ली सम्राट् का वकील बनकर वह इंग्लैंड गया, वही सन् १८३३ में उसका देहान्त हो गया।

**ब्रह्मसमाज**—उन दिनों भारतवर्ष में ईसाई मत के प्रचार के लिए बड़े जोरों से प्रयत्न हो रहा था। अंगरेजी शिचा मिलने पर हिन्दूधर्म की कुरीतियों को देखकर कुछ लोगों की उस ओर प्रवृत्ति हो जाती थी। राम-मोहन राय को इसका अनुभव हो रहा था। वह हिन्दूधर्म में सुधार करना चाहता था। साथ ही साथ वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देकर मत-मतान्तरों के झगड़ों को हटाना चाहता और हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाइयों को एक करना चाहता था। इसी उद्देश्य से सन् १८२६ में उसने 'ब्रह्मसमाज' स्थापित किया। इसमें तीनों धर्मों के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का समावेश किया गया और सब भेद भाव दूर कर दिये गये। नवयुवकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और थोड़े ही दिनों में इसके सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। राममोहन राय के बाद इसमें भी कई एक दल हो गये और केशवचन्द्र सेन ने समय से इसके एक दल पर पाश्चात्य रहन-सहन का बड़ा प्रभाव पड़ गया। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस समाज ने वही काम किया, जो पन्द्रहवीं शताब्दी में गुरु नानक के सिख सम्प्रदाय ने किया था।

**सर चार्ल्स मैटकाफ़**—लार्ड वेंटिक के चले जाने पर मैटकाफ़ कुछ दिनों तक गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रहा। ऐडम के समय में प्रेस का मुँह बन्द करने के लिए जो नियम बनाये गये थे, उन सबको इसने रद्द कर दिया और समाचारपत्रों को बहुत कुछ स्वतंत्रता दे दी। वेंटिक

भी समाचारपत्रों की स्वतंत्रता का पक्षपाती था, पर एंडेम के नियमों को रद्द करने का उसको साहस

न हुआ था। मेटकाफ ने इस सम्बन्ध में किसी की भी पर्वाह न की। उसका यह कार्य सचालको को पसन्द न आया। उसी को गवर्नर-जनरल बनाये रखने की बातचीत थी, वह छोड़ दी गई और वह मदरास का गवर्नर तक न बनाया गया। नये गवर्नर-जनरल आक्लेड के आ जाने पर वह इस्तीफा देकर वापस चला गया।



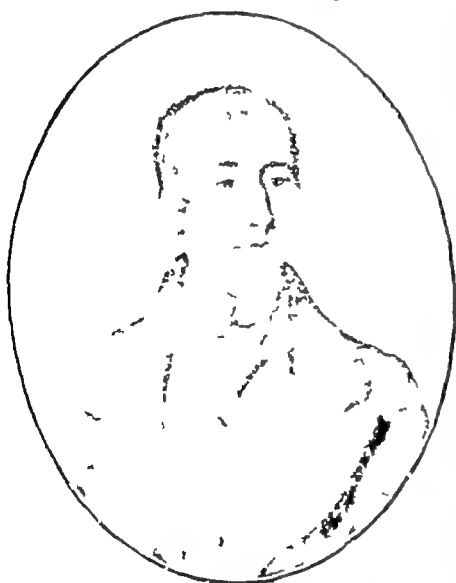
चार्ल्स मेटकाफ

कुछ दिनों तक वह पश्चिमोत्तर प्रान्त का लैफ्टिनेंट-गवर्नर भी रहा था। वह एक योग्य शासक था और ३८ वर्ष तक हमने भारतवर्ष में काम किया था।

## परिच्छेद ११

### पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा

लार्ड आकलेड—मार्च सन् १८३६ में लार्ड आम्लेड गवर्नर-जनरल होकर भारतवर्ष पहुँचा। उसने लार्ड वेंटिक की नीति का ही



आकलेड

अनुकरण करना निश्चित किया। उसके समय में बम्बई और मद्रास में डाक्टरी कालेज खोले गये। जिन विद्यालयों में अँगरेजी भाषा की पढाई नहीं होती थी, उनको भी कुछ सहायता देना निश्चित किया गया और प्रारम्भिक शिक्षा देशी भाषाओं में देने के लिए प्रवन्ध किया गया। इस तरह वेंटिक की शिक्षा-नीति की भूलों का कुछ सुधार किया गया। इस समय तक यूरोपियन लोग दीवानी के मुकदमों की अपील 'सुप्रीम कोर्ट' में करते थे। यह इंग्लैंड सरकार की अदालत थी।

अब कानूनी मेम्बर मैकाले ने यह प्रस्ताव किया कि सब अपीलों कम्पनी की 'सदर दीवानी अदालत' में हुआ करें। कलकत्ता के गोरे व्यापारियों को यह बात बड़ी खटकी। जो अदालत काले आदमियों का निर्णय करती थी, वह भला गोरे आदमियों के निर्णय के योग्य कैसे हो सकती थी? इस 'काले कानून' के विरुद्ध बड़ा धोर आन्दोलन किया गया और मैकाले को बहुत कुछ बुरा-



भला कहा गया, परन्तु वह अपनी बात पर डटा रहा। अन्त में यह कानून पाम हो गया।

**पश्चिमोत्तर प्रान्त का दुर्भिक्ष**—सन् १८३७ में उत्तरी भारत में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। कहा जाता है कि इसमें आठ लाख आदमी मर गये। सरकार की ओर से सहायता करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें ३८ लाख रुपया खर्च हुआ। जल का कष्ट दूर करने के लिए गंगाजी से एक नहर निकालने का भी विचार किया गया और उसकी नाप शुरू कर दी गई।

**देसी राज्य**—सन् १८३७ में नसीरुद्दीन हैदर के मरने पर अवध में पादशाह बेगम ने कुछ उपद्रव किया। वह अपने पोते मुन्नाजान को गद्दी पर बिठलाना चाहती थी, परन्तु रेजिडेंट ने दोनों को कैद करके चुनार भेज दिया और नसीरुद्दीन के चचा मुहम्मदअली को मसनद पर बिठला दिया। इसके साथ एक नई सन्धि की गई, जिससे फौज बढ़ा दी गई और यह निश्चित किया गया कि यदि किसी जिले का प्रबन्ध ठीक न होगा तो उसमें शासन के लिए अंगरेज अफसर रख दिया जायगा, जो कुल हिसाब सम्झाया करेगा। अवध के साथ यह बड़ी ज्यादाती थी। लार्ड वेलेजली के समय में उसकी रक्षा का पूरा भार ग्रहण किया गया था और आधा राज्य लेकर यह स्पष्ट कह दिया गया था कि फिर अधिक रुपया न मांगा जायगा, तब भी उस पर १६ लाख रुपये साल का नया बोझ लाद दिया गया। सचालको ने भी इसके अनुचित समझकर मजूर नहीं किया। इस पर मुहम्मदअली को केवल इतना ही लिख दिया कि उससे अब रुपया न लिया जायगा। कप्तान बर्ड का कहना है कि मुहम्मदअली ने शासन प्रबन्ध ठीक करने का प्रयत्न किया और ऐंती तथा व्यापार की वृद्धि की ओर भी ध्यान दिया।<sup>१</sup>

हैदराबाद से सहायक सेना हटाने का विचार किया गया, क्योंकि इसके खर्च के लिए राज्य का काफी भाग मिल चुका था और निजाम से कहा गया कि वह अपनी सेना से ही शासन का प्रबन्ध करे। इस सेना के अंगरेज

अफ़सरो को उसे ३८ लाख रुपया माल वेतन देना पड़ता था। इस तरह हस्तक्षेप न करने की नीति का दिखलावा करके उससे रुपया लिया जाने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस पर कर्ज बढ़ने लगा।<sup>१</sup> सन् १८४२ में कर्नूल के नवाब पर बहुत से दोष लगाये गये और उसका राज्य छीनकर कर्नूल का जिला बना दिया गया। सन् १८१६ में मतारा के राजा के साथ बड़ी उदारता दिखलाई गई थी और उसको पेशवा के राज्य का कुछ भाग दिया गया था। अब कहा जाने लगा कि राजा प्रतापसिंह अंगरेजों के विरुद्ध पुर्तगालियों से बातचीत कर रहा है, नागपुर के भागे हुए राजा अप्पा साहब को बुलाना चाहता है और सेना को भड़का रहा है। उसके शासन में भी बहुत से दोष दिखलाये गये। सन् १८३६ में वह गद्दी से उतार कर बनारस भेज दिया गया और उसका भाई राजा बना दिया गया। प्रतापसिंह एक योग्य शासक था। वह अंगरेजों के हाथ का खिलौना बनकर न रहना चाहता था। यही उसका अपराध था। उसके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया गया।<sup>२</sup> हरीराव होलकर को भी धमकी दी गई कि यदि वह गवर्नर-जनरल के आज्ञानुसार शासन का प्रबन्ध न करेगा, तो उसका भी राज्य छीन लिया जायगा।

**रूस की समस्या—**लार्ड मिंटो के समय में फारस के साथ परस्पर रक्षा की सन्धि की गई थी, पर जब रूस ने फारस को ढबाना शुरू किया, तब अंगरेजों ने सहायता देने से इनकार कर दिया। रूस से बचने के लिए फारस के शाह को कुछ रुपया देकर सन्धि की वह शर्त ही हटा दी गई।<sup>३</sup> अफ़गानिस्तान की सीमा पर उपद्रव मचाये रखने के लिए फारस से मित्रता की गई थी, वह मतलब अब सिद्ध हो चुका था, इसलिए फारस को प्रमत्त रखने की विशेष आवश्यकता न थी। इस नीति का परिणाम यह

१ मित्रिल, हिस्ट्री ऑफ़ दि टेकन, जि० २, पृ० १७८।

२ एम्, स्टोरी ऑफ़ मराठा।

३ ट्रायल, लाउ आकाल्ट (रूलम् ऑफ़ इंडिया मिरिज) पृ० ३८-३०।

हुआ कि फारम ने रूस के साथ मेल कर लिया और उसकी सहायता से अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हेरात का घेरा डाल दिया। इस पर इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ घबरा उठे। उन्होंने समझा कि यह तो भारत पर आक्रमण करने की तैयारी हो रही है। पर वास्तव में यह भय निराधार था, क्योंकि अफगानिस्तान अंगरेजी राज्य से बिल्कुल अलग था। दोनों के बीच में पंजाब, भावलपुर, सिन्ध और राजपूताना के राज्य थे, जिनको लॉर्ड कार्नवालिस अंगरेजों के राज्य पर किपी का आक्रमण करना सम्भव न था। इसका कुछ भी ध्यान न किया गया और हेरात को “भारत की पश्चिमोत्तर सीमा का द्वार” मानकर अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करना निश्चित कर लिया गया। लॉर्ड आकलेड ने बिना अधिक सोच-विचार के इसी नीति पर काम करना प्रारम्भ कर दिया।

**अफगानिस्तान में हस्तक्षेप**—सन् १८०६ में अहमदशाह दुर्रानी का पोता शाहशुजा काबुल से निकाल दिया गया। कई वर्षों तक वहाँ आपस में बहुत झगडा चलता रहा। अन्त में सन् १८२६ से दोस्तमुहम्मदखान, जो एक वारकजई सरदार था, राज्य करने लगा। शाहशुजा पहले महाराजा रणजीतसिंह की निगरानी में रहा, फिर अंगरेजों की शरण में आकर लुधियाना में रहने लगा। यहाँ उसको पेंशन भी दी जाने लगी। इस बला को पालने की कोई आवश्यकता न थी, पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिए यह अच्छा उपाय मिल गया और उसके लिए भारत के खजाने का रुपया खर्च किया जाने लगा। लॉर्ड आकलेड के आने पर बर्न्स नाम का एक अंगरेज व्यापारिक मन्त्रि करने के लिए काबुल भेजा गया, पर वास्तव में इसका उद्देश्य राजनैतिक था। उन दिनों अफगानिस्तान के साथ कोई व्यापार न था। बर्न्स स्वयं लिखता है कि वह केवल रंग-ढंग देखने के लिए वहाँ गया था। परन्तु दोस्तमुहम्मद को फाँसना सहज न था, वह भी बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था और बड़ी योग्यता के साथ उठड़ काबुलियों पर शासन कर रहा था। उसने कहा कि जब तक रणजीतसिंह से उसको पेशावर नहीं मिला दिया जायगा, तब तक कोई मन्त्रि नहा हो सकती। इसके उत्तर में

उमसे कहा गया कि अन्य स्वतंत्र राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना ब्रिटिश सरकार का नियम नहीं है। अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से रणजीत

सिंह को रोकने का अवश्य प्रयत्न किया जायगा। दोस्तमुहम्मद के दरबार में इंग्लैंड का बड़ा मजाक उड़ाया गया, क्योंकि सिखों के आक्रमण की कोई सम्भावना न थी।<sup>१</sup>

इन्हीं दिनों रूस का भी एक दूत काबुल पहुँच गया और दोस्तमुहम्मद के भाई, जो कन्दहार में थे, फारम से मिल करने की बातचीत करने लगे। दोस्तमुहम्मद अंगरेजों से वैर न करना चाहता था। लार्ड आर्लेड के आने पर उसने लिखा था कि “आप मुझे और मेरे राज्य को अपना ही समझें।” बर्न्स भी उसकी योग्यता देखकर गवर्नर जन-

बर्न्स

रल को बराबर लिख रहा था कि उसके साथ मित्रता रखने ही में लाभ है। परन्तु लार्ड आर्लेड पर उसके सेक्रेटरी मकनाडन और कालविन का रंग जमा हुआ था। इन दोनों की सलाह से बर्न्स की बात न मानकर शाहशुजा को गद्दी पर बिठलाना निश्चित किया गया। दोस्तमुहम्मद ऐसे चतुर शासक से पार पाना सहज न था, पर शाहशुजा कम्पनी का वेतनभोगी ही था, इसलिए उसके समय में खूब मनमानी हो सकती थी।

**युद्ध की घोषणा**—अंगरेजों से निराश होकर दोस्तमुहम्मद ने रूसी दूत की ओर ध्यान दिया। उसकी शत्रुता का यह अच्छा प्रमाण मिल

गया और युद्ध का प्रबन्ध होने लगा। मैकनाटन रणजीतसिंह के पास लाहोर भेजा गया। महाराजा का स्वास्थ्य इन दिनों बिल्कुल बिगड़ चुका था और उसकी अवस्था भी बहुत हो चुकी थी। पहले उसको इस बेमतलब के युद्ध में पड़ने में सकोच हुआ। वह जानता था कि काबुल में अंगरेजों का पैर जमाना उसके राज्य के लिए हितकर न होगा। पर जब उसने देखा कि अंगरेज बिना उसकी सहायता के भी शाहशुजा को गद्दी पर बिठलाने के लिए तुल्य हुए हैं, तब उसने साथ देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद शाहशुजा समझा-बुझाकर राजी किया गया। उसको भी इस नीति की सफलता में बड़ा सन्देह था। वह जानता था कि अभिमानी अफगान विदेशियों का हस्तक्षेप कभी सहन न करेंगे। इस बात को उसने अच्छी तरह से स्पष्ट भी कर दिया था। इतने ही में फारस के शाह ने हेरात का घेरा उठा लिया और काबुल से रूसी दूत भी बिना किसी सफलता के विदा हो गया। इस तरह युद्ध के जो दो मुख्य कारण ये जाते रहे, पर तब भी शिमला से अकतूबर मन् १८३८ में युद्ध की घोषणा कर दी गई। इसमें कौंसिल से भी परामर्श नहीं किया गया।

इस घोषणा तथा पार्लामेंट के सामने जो कागजात रखे गये उनमें बहुत सी बातें बना-बुनाकर लिख दी गईं। कहा गया कि दोस्तमुहम्मद हमारे पुराने मित्र रणजीतसिंह पर सहसा आक्रमण करनेवाला है और वह पेशावर छीनना चाहता है। शाहशुजा अफगानिस्तान में बड़ा लोक-प्रिय है और सब लोग उसी को गद्दी पर बिठलाना चाहते हैं। गवर्नर-जनरल की नीति बहुतों के समझ में न आ रही थी। लार्ड वेल्लेजली को ऐसे देश पर, जिनमें सिवा "चट्टान, बालू और बरफ" के कुछ भी नहीं है, अधिकार करने के विचार पर हँसी आ रही थी। वेल्लिंगटन का मत था कि एक बार सिन्ध नदी पार करके फिर अफगानिस्तान से पिछे छुटाना मुश्किल हो जायगा। लार्ड वेंटिक को आश्चर्य हो रहा था कि शान्तिप्रिय लार्ड आरुन्डेल ने युद्ध कैसे छेड़ दिया। भारत के प्रधान सेनापति फेन का कहना था कि भारतवर्ष में जो चाहें कर लो पर पश्चिम की ओर बढ़ना ठीक नहीं है।

मेटकाफ पहले ही से सिन्ध नदी पार करने की नीति के विरुद्ध था। उसका मत था कि यह जान-बूझकर भारतवर्ष की ओर रुमियों का ध्यान आकर्षित करना है। कम्पनी के संचालक भी इसके विरुद्ध थे। पर लार्ड आक्लेड को इन सबकी परवाह न थी। इंग्लैंड-सरकार उसका साथ दे रही थी, भारत की सेना युद्ध के लिए आतुर हो रही थी।

पहले शाहशुजा और सिलो को केवल आर्थिक सहायता देने का विचार था, अब उनके साथ अंगरेजी सेना भी भेजना निश्चित किया गया। फीरोजपुर में लार्ड आक्लेड और रणजीतसिंह की बड़े बूमधाम के साथ भेट हुई और बगाल तथा बम्बई की सेनाओं को काबुल की ओर बढ़ने की आज्ञा दे दी गई। पजाब होकर अंगरेजी सेना जाने के लिए रणजीतसिंह की अनुमति न मिल सकती थी, इसलिए यह सेना सिन्ध होकर भेजी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिन्ध की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया गया।

सिन्ध के साथ पहले जो व्यापारिक सन्धि की गई थी, उसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि सिन्ध नदी के द्वारा कोई सेना न जायगी और सिन्ध में कोई अंगरेज न बसने पावेगा। पर अब सिन्ध नदी के मार्ग से सेना भेजी गई और शिकारपुर तथा बखर पर भी जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया। अमीरों पर बहुत से अपराध लगाये गये, उन्हें राज्य छीन लेने का भय दिखाया गया और सन् १८३६ में एक नई सन्धि की गई, जिसके अनुसार ३ लाख रुपया सालाना सेना का खर्च देने के लिए अमीरों को मजबूर किया गया। भावलपुर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया।

**पटली विजय**—मार्ग में सेना को बड़ा कष्ट हुआ। रसद का कोई प्रबन्ध न था, पानी की भी बड़ी कमी थी। परन्तु बोलन होती हुई जैसे-तैसे यह सेना खन्डहार पहुँची। वहाँ से गजनी पर अधिकार कर लिया गया। यह समाचार मिलने पर दोस्तमुहम्मद काबुल से भाग निकला और अगस्त सन् १८३६ में शाहशुजा गद्दी पर बिठला दिया गया। उसका नगर-प्रवेश एक "मानर्मा जलम" जान पड़ता था, किसी ने भी उसका स्वागत नहीं किया। इस विजय के लिए इंग्लैंड-सरकार ने गवर्नर-जनरल और उसके अफसरों की

बड़ी प्रशंसा की। इस मामले में दोस्तमुहम्मद के साथ पूरा अन्याय किया गया। स्वयं मैकनाटन ने भी इसको माना है। वह लिखता है कि हमने दोस्तमुहम्मद को, जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं था, अपनी नीति का शिकार बनाकर निकाल दिया।<sup>१</sup>

युद्ध की घोषणा में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि शाहशुजा को गद्दी पर बिठलाकर अंगरेजी सेना बापम चली आयगी, पर तब भी दस हजार सेना अफगानिस्तान में छोड़ दी गई। मैकनाटन शाहशुजा के दरबार में अंगरेजों का दूत बनाया गया, वर्न्स भी साथ ही था। इन दोनों ने अमीर के हर एक काम में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया।



शाहशुजा

अंगरेज अफसरों की सलाह से गामन होने लगा और गोरे मिपाही पुलिस का काम करने लगे। भारत का खजाना अफगानियों को सन्तुष्ट रखने के लिए लुटाया जाने लगा। सिखों को भी नाराज कर दिया गया। उनसे पेशावर छीन लेने का प्रयत्न किया जाने लगा और उन पर बहुत से अपराध लगाये जाने लगे। दोस्तमुहम्मद भी अंगरेजों की शरण में आ गया और वह शाहशुजा की जगह पर भारत में रहने लगा। अब अंगरेजों ने समझ लिया कि उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं रही और वे मनमानी करने लगे।

**भीषण बदला—**अफगानिस्तान भारतवर्ष न था। वहाँ के निवासी “काफिर फिरगियो” का हस्तक्षेप सहन न कर सके। दोस्तमुहम्मद के बेटे

अकबरशा की अध्यक्षता में वे सब के सब बिगड पड़े। इधर अंगरेज अफसर आपस ही में लड रहे थे, बहुत से दुराचरण में पड़े थे कोई भी किमी की न सुनता था। सैनिक व्यवस्था बिगड रही थी। सुरक्षित किला छोडकर खुले मैदान में छावनी पडी थी। शाहशुजा बराबर सचेत कर रहा था, पर उसकी कौन सुनता था? रमद की बडी कमी थी, वेढव ठड पड रही थी, खजाना भी खाली था। इतने ही में दूसरी नवम्बर सन् १८४१ को बर्नो मार डाला गया, तब भी मैकनाटन की आँखें न खुली और रजा का कोई भी प्रबन्ध न किया गया।

विद्रोहियों का जोर बढ़ता गया। कोई उपाय न देखकर मैकनाटन ने अफगानिस्तान खाली कर देना स्वीकार कर लिया और दोस्तमुहम्मद

को भी वापस भेज देने के लिए

राजी हो गया। इस पर अक-

बरशा ने अंगरेजों की रक्षा करने

का वचन दे दिया। परन्तु मैक-

नाटन अपनी बात पर कायम न

रहा। वह छिपे छिपे अपने

मुशी मोहनलाल द्वारा अकबर-

शा के साथियों को फोडने लगा।

पहले अकबरशा को इसका

विश्वास न हुआ, परन्तु उसने

एक चाल से सब बातों का पता

लगा लिया और मैकनाटन को

मुलाकात करने के लिए बुलाया।

वह मैकनाटन को केवल कैद

करना चाहता था, परन्तु मैक-

नाटन की बातों से उसमें क्रोध आ गया। इतने ही में किसी ने कहा कि अंगरेजी सेना आ रही है। इस पर उसने मैकनाटन को गोली से मार



अकबरशा



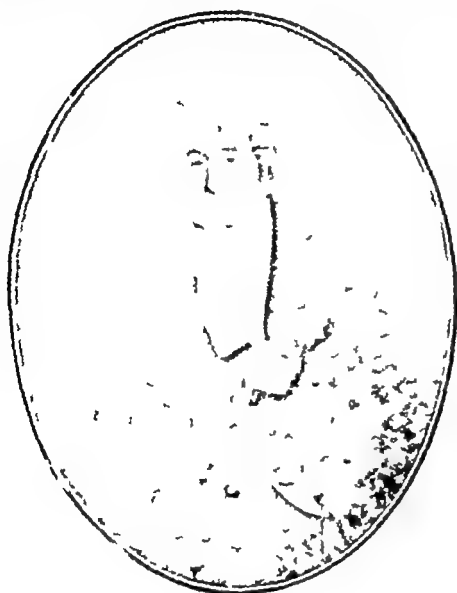
दिया।<sup>१</sup> इसके बाद ता० १ जनवरी सन् १८४२ को जैसे-तैसे समझौता करके, तोप, बन्दूक, गोली, बारूद सब सामान छोड़-छाड़कर अंगरेजी सेना काबुल से निकल भागी। बाल-बच्चे, स्त्रियाँ और नौकर-चाकर सब मिलाकर इस सेना में १६५०० मनुष्य थे। इनमें से ता० १३ जनवरी को केवल डाक्टर ब्राडन बचकर जलालाबाद पहुँचा। बहुत से शीत और मार्ग के कष्ट से मर गये। बहुतों को, अकबरखा के मना करने पर भी, सीमा पर के उड़ड़ अफगानियों ने पहाड़ों के तग रास्तों में मार डाला। कई एक अफसर कैद कर लिये गये, बाल-बच्चे तथा स्त्रियाँ अकबरखा की निगरानी में छोड़ दी गई। इस तरह काबुल की अंगरेजी सेना का अन्त हो गया।

**आकलैंड का दोष**—इस युद्ध के लिए लार्ड आकलैंड को बहुत कुछ दोष दिया गया है, पर वह केवल इंग्लैंड-सरकार की आज्ञा का पालन कर रहा था। वास्तव में इसका बीज लार्ड वेंटिंग, जिसको अब आकलैंड की नीति पर आश्चर्य हो रहा था, बो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि लार्ड आकलैंड में स्वतंत्र विचार की शक्ति न थी, वह अपने मंत्रियों के हाथ में था। पर इसमें हमका या हमके सलाहकारों ही का क्या दोष था? वे लार्ड वेल्लेजली और हेमिंग्स के बताये हुए मार्ग पर चल रहे थे। यदि भारतवर्ष के स्वतंत्र राज्यों में हस्तक्षेप करना अनुचित न था, तो सिन्ध नदी पार उसी नीति के अनुसरण करने में क्या दोष था? लोकमत की कुछ भी पर्वाह न करके अयोग्य शासक का पद लेना, हमके राज्य में अपनी सेना रखकर शासन में हस्तक्षेप करना और अन्त में हमके मरते सब दोषों को मढ़कर राज्य छीन लेना अंगरेजों की मुख्य नीति रही है। लार्ड आकलैंड और उसके सलाहकार इसी नीति पर चल रहे थे। यदि उनकी कोई भूल थी, तो इतनी ही कि उन्होंने अफगानिस्तान को भी भारतवर्ष समझ लिया था। सफलता होने में लार्ड आकलैंड की भी गणना साम्राज्य के निर्माण करनेवालों में हुई हाती, इसमें सन्देह नहीं है।

<sup>१</sup> जान के, दि वार इन अफगानिस्तान, जि० ०, पृ० १६४। ट्राटर, आकलैंड, पृ० १८६।

**लार्ड एलिनबरा**—फरवरी सन् १८४२ में आकलैंड वापस चला गया और एलिनबरा गवर्नर-जनरल होकर आया। यह तीन बार 'बोर्ड

ऑफ कंट्रोल' का सभापति रह चुका था। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की इम पर बड़ी कृपा थी। अफगान-युद्ध की नीति का यह घोर विरोधी था। इमी लिए संचालको ने इसको भागतवर्ष भेजा था। इम युद्ध में पानी की तरह घन खर्च हो रहा था और कोई अन्त न दिखलाई देता था। एलिनबरा पहले काबुल पर "एक सप्ताह" भर के लिए भी अधिकार करके अंगरेजी सेना की लज्जा मिटाना चाहता था। पर जब उसको गजनी छिन जाने का समाचार मिला, तब उसने अफगानिस्तान एकदम खाली कर देने



एलिनबरा

की आज्ञा दे दी। अकबरसा के हाथ में बहुत से अंगरेज कैदी थे, उनका भी उमने कोई खयाल नहीं किया। यह बात अंगरेज अफसरों को बहुत सटकी। तब उमने जनरल पोलक और नाट को, जो अफगानिस्तान में थे, लिख दिया कि जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। इतिहासकार स्मिथ लिखता है कि इस तरह एलिनबरा ने अपनी जिम्मेदारी टाल दी। एलिनबरा का अपने समर्थन में कहना है कि उमने स्थानीय अफसरों को केवल स्वतंत्रता दे दी।<sup>१</sup>

**युद्ध की समाप्ति**—जनरल पोलक ने जलालाबाद की रक्षा की थी और जनरल नाट कन्दहार में डटा पडा था। अब ये दोनों काबुल की ओर

<sup>१</sup> ना, शिया अटर लाट एलिनबरा।

बड़े। सिखों को जलालाबाद देने का लालच दिया गया और उनको खूब धार्मिक जोश दिलाया गया। पहले गजनी पर अधिकार कर लिया गया और वर्हा का किला तथा नगर नष्ट कर दिया गया। सितम्बर सन् १८४२ में काबुल पर भी अधिकार हो गया। वर्हा के निरपराध दूकानदारों को लूटकर और दो मस्जिदें तथा चार बाजारें, जो “एशिया में अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध थीं,” नष्ट करके हार का बदला लिया गया।<sup>१</sup> जिन्होंने अंगरेजों की दुर्दशा की थी, उनका कुछ भी करते न देन पड़ा। उल्टे उनको बहुत सा रुपया देकर कैदियों को छुड़ाया गया। अकबरगढ़ा को, जिसने अंगरेज कैदियों को बड़ी अच्छी तरह रखा था, पकड़े जाने पर मैकनाटन की हत्या का दंड देने की आज्ञा दी। अब उसी से समझौता किया गया और अफगानिस्तान खाली करके दोस्त मुहम्मद को वापस कर देने का वचन दिया गया। शाहशुजा को अपने प्राण बचाकर अंगरेजों की सहायता में राज्य करने का फल पहले ही मिल चुका था। अफगानिस्तान में रहने का अब अंगरेजों का माहम न था।



दोस्तमुहम्मद

### सोमनाथ का फाटक—

कहा जाता है कि महमूद सोमनाथ के मन्दिर में लगा हुआ चन्दन का फाटक गजनी ले गया था और यह वर्हा उसके सक्करे में लगा था। लार्ड एलिनवरा ने उस फाटक को भाग्यवर्ष लाने की आज्ञा दी, पर

<sup>१</sup> जान के, दि वार इन अफगानिस्तान, जि० २, पृ० ६३८-३९।

जो फाटक लाया गया वह दूसरा ही था। इतने दिनों की भूली हुई बात का स्मरण दिलाकर भारतवर्ष में हिन्दू और मुसलमानों के परस्पर भेदभाव को जागृत करने का यह प्रयत्न किया गया। लार्ड एलिनबरा इसको बड़ी धूमधाम से सोमनाथ ले जाना चाहता था, परन्तु इंग्लैंड में इसका बड़ा विरोध किया गया। इस पर यह विचार छोड़ दिया गया। यह फाटक आजकल आगरा के किले में पड़ा हुआ सब रहा है। अफगानिस्तान में लौटी हुई सेना का फीरोजपुर में बड़े समारोह के साथ स्वागत करने का प्रयत्न किया गया। लार्ड एलिनबरा इसमें दोस्तमुहम्मद को भी शामिल करना चाहता था। उस अभिमानी शासक पर इसका प्रभाव क्या होता, जब यह पता चला, तब यह विचार भी छोड़ दिया गया। स्वागत के लिए महीने से हाथियों को मलामी करना सिपलाया गया था, पर ठीक समय पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिसमें नारा मजा किरकिरा हो गया। नाममात्र की विजय का इस अपमान-सूचक ढंग से मनाया जाना बहुतों ने पसन्द नहीं किया।

**सिन्ध का शिकार**—इस युद्ध में बहुत सा धन खर्च हुआ था, जिसकी पूर्ति करनी थी। अंगरेजों की बदनामी भी बहुत हुई थी, उसको किसी न किसी तरह मिटाना था। इसी लिए अब सिन्ध का शिकार करना निश्चित किया गया। इसमें एक यह भी लाभ देखा गया कि सिन्ध नदी पर, जो अरबों के शब्दों में “दिल्ली की खाई” थी, अधिकार हो जाने से पंजाब को भी दराने का अवसर मिल जायगा। सिन्ध के साथ पहले ही से अन्याय किया गया था। यहाँ बिलोचियों का राज्य था, जिनमें हैदराबाद, मीरपुर और रैरपुर के मुख्य घराने थे, जो अमीर कहलाते थे। सन् १८०६ में इनसे केवल फार्मीसियों को अलग रखने के लिए कहा गया था। सन् १८३१ में इनकी इच्छा के विरुद्ध रणजीतसिंह को उपहार ले जाने का बहाना करके बर्मे सिन्ध नदी के मार्ग से लाहौर भेजा गया। तभी एक बिलोची ने कह दिया था कि “जब अब हो चुका, अंगरेजों ने हमारे देश के मार्ग को देख लिया।” परन्तु अंगरेजों के विवाय दिलाने पर कि सिन्ध नदी से सिवा व्यापार के और कोई सैनिक लाभ न उठाया जायगा, अमीरों ने व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी।

सन् १८३८ में शाहशुजा और रणजीतसिंह के साथ जो समझौता किया गया, उसमें सिन्ध का कुछ भी ध्यान न रखा गया और उन दोनों को सिन्ध से २० लाख रुपया दिलवा देने का वचन दे दिया गया। सन् १८३६ में पिछली सन्धि के विरुद्ध सिन्ध नदी से अफगानिस्तान सेना भेज दी गई, बक्खर पर अधिकार कर लिया गया और ३ लाख रुपया साल सेना का खर्च भी अमीरों के मत्थे मढ़ दिया गया। उनसे कहा गया कि आवश्यकता के लिए कोई नियम नहीं है। समय पड़ने पर मित्रों की सहायता करनी चाहिए। इस पर मीर नूरमुहम्मद ने ठीक ही कहा कि अंगरेजों के “मित्र” शब्द का अर्थ उसकी समझ में कभी न आयागा।<sup>१</sup> अफगानिस्तान में अंगरेजों पर विपत्ति पड़ने के समय में ये अमीर बराबर उनकी सहायता करते रहे थे। पर इसका भी कुछ विचार न किया गया और सर चार्ल्स नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि बनाकर सिन्ध भेजा गया, जो हर एक बात में हस्तक्षेप करने लगा।

**मियानी का युद्ध**—अमीरों पर तरह तरह के दोष लगाये गये और एक नई सन्धि करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। इसके अनुसार सैनिक खर्च के लिए कुछ स्थान ले लिये गये और सिन्ध में अंगरेजों का सिक्रा चला दिया गया। जिन स्थानों के लेने की बातचीत थी, सन्धि पर हस्ताक्षर होने के पहले ही उन पर अधिकार कर लिया गया और अमीरों को डराने के लिए इमामगढ़ का प्रसिद्ध किला नष्ट कर डाला गया। अमीरों ने सन्धि पर तो हस्ताक्षर कर दिये परन्तु यह स्पष्ट कह दिया कि उहड़ विलोची इस अपमान को सहन न कर सकेंगे। उनकी वे जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस घटना के तीसरे ही दिन कुछ विलोचियों ने विगड़कर रेजीडेंसी पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या था, तीन हजार सेना लेकर नेपियर पहुँच गया। अमीरों की बाईस हजार सेना थी, विलोची बड़ी वीरता से लड़े, पर तब भी उनकी हार हुई। रिचर्ड वर्टन लिखता है कि यदि कभी इसकी जाँच की जाय कि गुप्त रीति

<sup>१</sup> उतकुल्ला, आटोबायग्रैफी, मन् १८५७, पृ० २९५।

मे कितना रुपया उनके अफसरों को दिया गया तो अंगरेजों की विजय के कारणों का पता लग सकता है।<sup>१</sup> लूट में कोई कसर न रखी गई। इसमें से ७० हजार पौंड नेपियर को मिले। विलोचियों के विद्रोह में अमीरों का कितना दोष था, इसकी पूरी जाँच भी नहीं की गई और वे गिरफ्तार करके बम्बई भेज दिये गये। सिन्ध अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया और चाल्म्स नेपियर वहाँ का शासक बना दिया गया।

इस तरह सिन्ध ले लेने का अंगरेजों को कोई अधिकार न था, इसको स्वयं नेपियर ने भी स्वीकार किया है। वह लिखता है कि “हमें सिन्ध लेने का कोई अधिकार नहीं है, तब भी हम ऐसा करेंगे” क्योंकि यह “बड़ा लाभ-दायक” होगा। इसमें “धूर्तता” की गई, इसको भी मानने की “धृष्टता” उसने मी है।<sup>२</sup> मचालको का भी ऐसा ही मत था। परन्तु यह सब होते हुए भी सिन्ध को लौटालने के लिए कोई भी तैयार न था। इस जबरदस्ती के समर्थन में कहा जाता है कि अन्ततः इससे वहाँ की प्रजा का लाभ ही हुआ। यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मामले में अंगरेजों का उद्देश्य काबुल की लज्जा मिटाना न था। कई कारणों से सिन्ध को अंगरेजी राज्य में मिला लेना अनिवार्य हो गया था<sup>३</sup>।

**ग्वालियर का भगड़ा**—सिन्धिया इस समय भी “थोड़ा बहुत स्वतंत्र था।” उसके साथ कोई सहायक सिन्ध न थी और न उसके राज्य की गणना अधीन राज्यों में थी। मेजर क्लोज के शब्दों में “वह स्वाधीन था,” उसके साथ “कई एक सिन्धिया थी, पर उनसे उसकी स्वतंत्रता नष्ट न होती थी।” यह स्वतंत्रता गवर्नर-जनरल की आँखों में पटक रही थी। सिन्धिया के पास इस समय भी ४० हजार अच्छी सेना थी। गवर्नर-जनरल की राय में, सतलज नदी से थोड़ी दूर पर, जहाँ सिखों की ७० हजार सेना “विजय”

१ लार्ड ऑफ गिबट वटन, पृ० १४१। वसु, जि० ५, पृ० १०५।

२ लार्ड ऑफ जनरल नेपियर, जि० २, पृ० २१८।

३ कॉन्ट्रिबुटि डिस्ट्री आफ सन्धिया, जि० ५, पृ० ५३८-३९।

के मद में मस्त” और “लडाई तथा लूट के लिए उत्सुक” पड़ी थी, हम सेना का रहना उचित न था। इस तरह उसकी दृष्टि पंजाब और ग्वालियर दोनों ही पर थी। ग्वालियर की शक्ति नष्ट करने का एक अच्छा अवसर मिल गया।

सन् १८४३ में जकोजी सिन्धिया की मृत्यु हो गई और एक नौ वर्ष का बालक गोद लेकर गद्दी पर बिठलाया गया। एलिनबरा ने दबाव डालकर मामा साहब को उसका संरक्षक बनवा दिया, पर ग्वालियरवालों ने थोड़े ही दिनों में उसे निकाल बाहर किया और दादा खासगीवाला को संरक्षक चुना। दरबारियों की इस धृष्टता को अभिमानी एलिनबरा सहन न कर सका। नये संरक्षक पर कितने ही अपराध लगाये गये। रेजीडेंट को गवर्नर-जनरल का यह अकारण हस्तक्षेप बहुत पसन्द न था, इसलिए वह अपने पद से हटा दिया गया और कर्नल स्लीमैन रेजीडेंट बनाया गया। अधिक दबाव डालने पर दरबार ने दादा साहब को भी गवर्नर-जनरल के हवाले कर दिया, पर तब भी वह सेना लेकर, चम्बल पार उतर आया। सिन्धिया की सेना ने इसको अपने राज्य पर आक्रमण समझा। महाराजपुर और पनियर नामक दो स्थानों पर एक ही दिन युद्ध हुआ। ऐसे युद्धों में जो परिणाम होता था वही हुआ। इन दिनों सिन्ध के सम्वन्ध में एलिनबरा की नीति की तीव्र आलोचना हो रही थी। यदि ऐसा न होता, तो गायद सिन्धिया का राज्य भी ले लिया जाता। अन्त में गवर्नर-जनरल ने “दया करके” राज्य वापस कर दिया। नई सिन्ध में जो कुछ स्वतंत्रता थी, वह सब जाती रही और सेना भी तोड़ दी गई।

**पंजाब पर दृष्टि**—एलिनबरा की पंजाब पर पूरी दृष्टि थी। रण-जीतसिंह के मरने से वहाँ की दशा विगड़ रही थी। सिखों को जलालाबाद देकर वह उनकी सेना को पश्चिम की ओर हटाना चाहता था। काबुल की तरफ बटने के लिए भी वह उनको भटका रहा था। अपने पत्रों में वह लिखता है कि पंजाब मेरे पैरों तले है, पर अभी समय नहीं आया है। वहाँ आपस की फूट से वही हो रहा है जो हम चाहते हैं। यदि सन् १८४५

तक का मुझे समय मिल गया, तो फिर किसी बात का भय नहीं है।<sup>१</sup> इन वाक्यों से स्पष्ट है कि यदि वह भारतवर्ष में रह जाता तो उसी के समय में सिखों के साथ भी युद्ध छिड़ जाता।

**अन्य राज्य—**निजाम की आर्थिक दशा बहुत बिगड़ रही थी, उसको कर्ज देकर उसके हाथ से भी शासन ले लेने की बातचीत हो रही थी। दूसरी ओर अवध के शाह से दस लाख कर्ज लिया जा रहा था। जान पड़ता था कि अवध का खजाना कम्पनी ही का माल था। बेचारा शाह अंगरेजी पुस्तकों के अनुवाद में लगा था, जिनके लिए उसकी प्रशम्भा की जा रही थी। राजाओं के कोई सन्तान न होने के कारण बुट्टेलखंड के दो छोटे छोटे राज्य जव्त कर लिये गये। बेचारे दिल्ली के बादशाह को नजर देने की प्रथा बन्द कर दी गई। एलिनबरा उसको कुटुम्ब सहित महल से निकालकर महल को गवर्नर-जनरल का निवास स्थान बनाना चाहता था। उसकी राय में सम्राट् का पद इंग्लैंड के शासकों को मिलना चाहिए था।

**एलिनबरा की नीति—**लार्ड एलिनबरा “एशिया में शान्ति स्थापित करने” आया था। वह भारतवर्ष का दूसरा “अक्रबर” बनना चाहता था। उसका कहना था कि जनता को ब्रिटिश सरकार से कुछ भी प्रेम नहीं है। उसने प्रजाहित के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं किया। बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही हैं, मन्दिर टूट रहे हैं और देशी नरेशों के मान का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी उदारता का परिचय मिले। हम केवल सेना के बल पर शासन कर रहे हैं। मैं अंगरेजी राज्य को जनता के हृदय में स्थापित करना चाहता हूँ और मैं इसका कर सकता हूँ। जिस तरह अक्रबर की सरकार टूट गयी, मैं उसी तरह ब्रिटिश सरकार को भी टूट बना सकता हूँ। ‘परन्तु नम मुझे अक्रबर की तरह काम करना पड़ेगा न कि आर्कलैंड की तरह’।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> उसका नाम बर्लिंगटन का नाम पत्र, वसु, जि० ५, पृ० १४१-४६।

<sup>२</sup> ला, रटिया नम लार्ड एलिनबरा, पृ० ६४।



इन शब्दों और उसके कार्यों में कितना अन्तर था ? परन्तु इनसे उन दिनों भी सरकार के प्रति जो भाव था, वह अवश्य प्रकट हो रहा है ।

सन् १८३३ के एक भाषण में एलिनबरा का कहना था कि राजनैतिक तथा सैनिक शक्ति हिन्दुस्तानियों के हाथ में न देने ही से भारत में हमारा नाज्जाय्य स्थापित रह सकता है । इसका ध्यान रखते हुए प्रजाहित के लिए जो कुछ बन पड़े करना चाहिए । वास्तव में इसी नीति के अनुसार शासन करने का प्रयत्न किया गया । सन् १८४३ में टाम्पता की प्रथा उठा दी गई । सरकार की ओर से लाटरी डालकर रुपया इकट्ठा करने की रीति भी बन्द कर दी गई । शासन के भिन्न भिन्न विभाग सेक्रेटरियों में बाँट दिये गये और एक 'ग्रैमदमन्य' भी नियुक्त किया गया । पुलिस की दशा भी सुधारी गई और धानेदारों का वेतन कुछ बढ़ा दिया गया ।

कम्पनी के संचालक उसकी नीति से सन्तुष्ट न थे । नौकरी के मामलों में वह उनकी न सुनता था । लार्ड वेल्लेजली की तरह वह भी उनका निरादर करता था । उसे बड़ा अभिमान था और वह बिना सोचे-विचारे बड़ी शान के धोपणा-पत्र निकाला करता था, जिनका प्रभाव अच्छा न पड़ता था । लार्ड वेल्लेजली और वेलिंगटन उसके बड़े सलाहकार थे । उनकी राय में गवर्नर-जनरल के पद के लिए उससे बढकर इंग्लैंड में कोई योग्य न था । रानी विक्टोरिया का भी यही मत था । तब भी सन् १८४४ में संचालकों ने उसके वापस बुला लिया । उनके इस कार्य से रानी विक्टोरिया बहुत रूष्ट हो गई ।

**लार्ड हार्डिंज**—एलिनबरा के स्थान पर सर हेनरी हार्डिंज गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया । नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन की लड़ाइयों में उसने बड़ी वीरता और चतुरता दिखाई थी । बीस वर्ष से वह पार्लामेंट का मध्यस्थ था और युद्ध-सचिव के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुका था । लार्ड एलिनबरा की राय में “दो वर्ष के युद्ध से सर्वत्र शान्ति विराज रही थी ।” पर तब भी पञ्जाब की दशा देखते हुए इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों को युद्ध की आशंका हो रही थी । इसी लिए गवर्नर-जनरल के पद पर हार्डिंज सा रण-

चतुर सैनिक नियुक्त किया गया। इंग्लैंड में चलते समय संचालकों की ओर से कहा गया कि "ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन न्यायपूर्ण, नम्र तथा



हार्डिज

शान्तिप्रद होना चाहिए, परन्तु समय पड़ने पर उसकी शक्ति का प्रभुत्व शत्रुों के दम में अवश्य स्थापित रहना चाहिए।" युद्धप्रिय सैनिक के लिए भावी नीति का इतना इशारा काफी था।

**रणजीतसिंह की मृत्यु**—सन् १८३६ में 'पंजाबकेशरी' महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु हो गई। यद्यपि वह पढा-लिखा नहीं था, पर तब भी वह बड़ा योग्य शासक था। उसकी स्मरण-शक्ति विलक्षण थी। हर एक बात जानने की उसको उत्सुकता रहती थी। वह बड़ा वीर और साहसी था, किसी बात में उसकी हिम्मत कभी न हारती थी। घोड़े की सवारी और तलवार चलाने में वह बड़ा निपुण था। अच्छे अच्छे घोड़ों के रखने का उसको बड़ा शौक था। रणनीति में भी वह चतुर था, उसका सामना करना सहज काम न था। उसका अधिकांश जीवन युद्ध में ही व्यतीत हुआ था, पर तब भी उसमें कठोरता न थी। अपने शत्रुओं में भी वह वीरता का आदर करता था। उसके उदार व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते थे। अपना मतलब सिद्ध करने में वह किसी उपाय से न चूकता था। उसका दरबार बड़ी गान का था, पर वह स्वयं सादे ढंग से रहता था। तलवार को ही वह अपना सबसे अच्छा आभूषण समझता था। उसके चेहरे पर गीतला के दाग थे, एक आख भी नहीं थी, परन्तु उसकी "आकृति सुडौल, माथा बिगाल और कंधे चौड़े" थे। जब वह घोड़े पर निकलता था, उसमें विचित्र-वीर-रस का आवेग दिखलाई देता था।

**सिरख-शासन**—खालसा की मुख्य मभा 'गुरुमाता' का अन्त सन् १८०५ में ही हो गया था। राज्य का कुल शासन महाराजा की इच्छा पर निर्भर था। राज्य की आमदनी लगभग ढाई करोड़ रुपये थी। हर एक जिले में एक 'कारदार' रहता था, जो कर वसूल करता था। प्रजा से, पैदावार के पाँचवे हिस्से में कुछ अधिक, लगान में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के कर लिये जाते थे। जागीरदारों का 'खिराज' देना पड़ता था। कारदारों को न्याय के भी अधिकार रहते थे। दीवानी और फौजदारी की अलग अलग अदालतें नहीं। बहुत से अपराधों में प्रायः दुस्मान का डंड दिया जाता था। महाराजा की राय में अपराधियों को जेल में रचना फजूलखर्ची थी। बड़े बड़े अपराधों में शग-भंग का डंड दिया जाता था। मक्कारी अफसरों पर महाराजा की बड़ी तीव्र दृष्टि रहती थी।



**पंजाब की दुर्दशा**—रणजीतसिंह के मरते ही सारी शासन व्यवस्था बिगड़ गई। दरबार के बड़े बड़े सरदारों को, जो उसके सामने भय से कांपते थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का अवसर मिल गया और सेना बेकाबू हो गई। केवल राजा की योग्यता और शक्ति पर निर्भर रहनेवाले राज्यों में यही बड़ा भारी दोष है। उसके हटते ही पतन प्रारम्भ हो जाता है। बराबर वैसे ही राजा होते जायें, यह सम्भव नहीं है। एक इतिहासकार ने ठीक लिखा है कि यदि भारतवर्ष में अकबर सरीखे ही बादशाह बराबर शासन करते, तो आज भी अंगरेज वैसे ही व्यापारी बने होते, जैसे कि वे तब थे।

माल भर के भीतर ही रणजीतसिंह के बेटे खड्गसिंह और पोते नावनिहालसिंह का भी अन्त हो गया। नावनिहालसिंह बड़ा वीर युवक था। सेना पर भी उसका बड़ा प्रभाव था, अफगान-युद्ध में वही सेनापति था। अंगरेजों की नीति को वह खूब समझता था। इन दिनों दरबार में दो बड़े बड़े दल थे, एक और मुख्य सिन्धन-बालिया सरदार थे और दूसरी और जम्मू के ध्यानसिंह, गुलाबसिंह तथा सुवेतसिंह तीनों भाई थे। कुछ दिनों तक खड्गसिंह की रानी चंडिकुंवरि राज्य करती रही। अन्त में जम्मूवालों की विजय हुई और गेरसिंह, जो रणजीतसिंह का दूसरा लड़का माना जाता था, गद्दी पर बिठलाया गया। इस समय राज्य की ऐसी शोचनीय दशा हो गई थी कि अंगरेजों से भी सहायता मांगी गई, पर उन्होंने परस्पर की कलह जारी रहने ही में अपना हित देखा और रणजीतसिंह की मित्रता का कुछ भी ध्यान न करके, हस्तक्षेप करने में इनकार कर दिया। सन् १८४३ में गेरसिंह मार डाला गया और प्रधान सचिव ध्यानसिंह का भी अन्त हो गया। यह बड़ा महत्वाकांक्षी, साहसी, योग्य, समझदार और नीतिनिपुण सचिव था। सुवेतसिंह की भी मृत्यु हो गई। तीनों भाइयों में केवल गुलाबसिंह बाकी रह गया। इसी साल ८ वर्ष का बालक दिलीपसिंह गद्दी पर बिठलाया गया और उसकी माता रानी किन्दन राज्य का काम देखने लगी।

कहने के लिए तो दिलीपसिंह और उसके मरदार राज्य करते थे, पर वास्तव में सारी शक्ति सेना के हाथ में थी। रणजीतसिंह के बाद से इसकी

संख्या बहुत बढ़ गई थी। इंग्लैंड का यह में रखने के लिए नावनिहालमिह और जेरमिह के समय में सैनिकों का वेतन भी बहुत बढ़ा दिया गया था। अब कोई ऐसा योग्य सरदार न था, जिसकी आज्ञा का मारी सेना पालन करती। हर एक कम्पनी की अलग अलग पचायते बनी हुई थी। पंचों का निर्वाचन सैनिक ही करते थे, इन्हीं पचायतों द्वारा कुल सेना का शासन होता था। कभी कभी यह सब पचायतों एक साथ मिलकर परामर्श करती थी और उनका निश्चय खालसा का निश्चय माना जाता था। इस संगठन में सेना की एकता, जो सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है, नष्ट हो गई थी और कई एक दल बन गये थे, जिन्हें सरदार लोग अपने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयत्न किया करते थे। ऐसी दशा में खालसा की न तो कोई निश्चित नीति थी और न जटिल प्रश्नों पर पूरी तरह विचार ही होता था। परन्तु जो सरदार अपनी मनमानी करना चाहते थे, उनके मार्ग में इस सेना से बड़ी बाधा पड़ती थी। इन दिनों तेजसिंह प्रधान सेनापति था और कुटिल लालमिह वजीर था, जिसका महारानी पर बड़ा प्रभाव था। गुलाबमिह दूर ही से यह सब दशा देख रहा था। परन्तु सेना के कारण इन तीनों की दाल न चलने पाती थी, इसी लिए किसी न किसी तरह सेना की शक्ति को नष्ट करके ये तीनों अपनी मनमानी करना चाहते थे।

**सिखों का पहला युद्ध**—सिखों की यह दशा देखकर अंगरेज अपनी सीमा पर बराबर सेना बढ़ा रहे थे। हार्डिज के समय में इसकी संख्या लगभग ४५ हजार तक पहुँच गई। फीरोजपुर में एक नई छावनी भी बना दी गई। अंगरेजों का कहना था कि यह सब तैयारी केवल अपनी रक्षा की दृष्टि से की जा रही थी। दूसरी ओर सिखों को भय था कि उनके राज्य पर आक्रमण के लिए यह सब प्रबन्ध हो रहा था। इस भय के कई एक कारण भी थे। अंगरेजों राज्य के विस्तार का इतिहास उनसे छिपा न था। “आत्म-रक्षा” के श्रवण को भी वे अच्छी तरह समझते थे। अंगरेजों के व्यवहार से भी उनके इस भय की पुष्टि हो रही थी। अफगान-युद्ध में सहायता देने का बदला, शाहशुजा को पेशावर बंदिन के लिए उत्प्राहित करने में दिया गया

था। सतलज नदी के इस पार के कुछ राज्यों को अंगरेजों ने अपने अतीत मान लिया था। कुछ सिख सैनिक लाहौर जाने के लिए फीरोजपुर के निकट सतलज नदी पार करके अंगरेजी राज्य में आ गये थे। यह बिना आज्ञा के "सीमोल्लघन" समझकर उन पर गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई थी। इसी तरह कुछ सिपाही लुटेरों को पकड़ने के लिए सिन्ध चले गये थे। इस पर सर चार्ल्स नेपियर ने उधर की सीमा पर सेना एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया था। सिखों को यह मुलतान की तरफ से चढ़ाई करने की चाल दिखलाई पड़ रही थी।<sup>१</sup> इस परम्पर अचेर्यास की स्थिति में तेजसिंह, लालसिंह और गुलाबसिंह का अपना दृष्ट्य सिद्ध करने का अच्छा अवसर मिल गया। वीरता और देशभक्ति सिखों के स्वाभाविक गुण हैं। इन दोनों को पूरी तरह उत्तेजित करके जब मनिको से पूँछा गया कि क्या वे खालसा पर किरंगियों का अधिकार सहन कर सकेंगे, तब सबने एक स्वर से उत्तर दिया कि जीते जी वे गोविन्दसिंह का राज्य नाट न होने देंगे और अंगरेजों पर स्वयं आक्रमण करके उनको परास्त करेंगे। महाराजा रणजीतसिंह की समाधि पर यह निश्चय करके दिसम्बर सन् १८४२ में सिख सेना सतलज नदी पार करके फीरोजपुर के निकट आ डटी।

इस पर गवर्नर-जनरल हार्डिंज ने भी युद्ध की घोषणा कर दी और सतलज नदी के इस पार के राज्यों को अंगरेजी राज्य में मिला लेने की आज्ञा दे दी। सिख-इतिहास के लेखक कनिंघम का कहना है कि सन्धि की शर्तों का तोड़कर युद्ध का प्रारम्भ पहले सिखों ने किया, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि कई वर्षों से अंगरेज जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, उसमें भी शान्ति स्थापित रहने की अधिक सम्भावना नहीं थी। इसलिए उस युद्ध के सम्बन्ध में, जिसको वे तुच्छ समझते थे, जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे और जिसमें वे जानते थे कि उन्हीं की वृद्धि होगी, व सर्वथा निर्दोष नहीं कहे जा सकते।<sup>२</sup>

<sup>१</sup> कनिंघम, हिस्ट्री ऑफ द सिख, स० गैरेट, पृ० २७५-८७।

<sup>२</sup> वही पृ० २८६-८७।

**मुदकी और फीरोजगढ़**—अंगरेजों को इस समय तक मित्रों की वीरता का पता न था। वे समझे बैठे थे कि बात की बात में वे उनको परास्त कर देंगे। यद्यपि युद्ध में अंगरेजों ही की विजय हुई, पर उनका यह भ्रम शीघ्र ही दूर हो गया। ता० १८ डिसेम्बर को मुदकी नामक स्थान पर पहली लड़ाई हुई। लालसिंह जो सेना का अध्यक्ष बनकर आया था, अंगरेजों से पहले ही से मिला था। वह युद्ध के समय पर मैदान में हट गया। प्रधान सेनापति तेजसिंह की भी वही दशा थी। परिणाम यह हुआ कि सिखों को मैदान छोड़ना पड़ा। ता० २१ डिसेम्बर को फीरोजगढ़ में दूसरी लड़ाई हुई। इसमें अंगरेजों के छक्के छूट गये। गोला बारूद समाप्त हो गई, वे फीरोजपुर की तरफ हटने ही वाले थे कि इतने में तेजसिंह स्वयं पीछे हट गया। इस लड़ाई में बहुत से अंगरेज अफ-सर मारे गये, परन्तु सिख सेना फिर सतलज के उम पार चली गई। जनवरी मन् १८४६ में लुधियाना के निकट एक दल ने अंगरेजों पर फिर आक्रमण किया। अंगरेज सिपाहियों ने इसको रोकना अवश्य, पर वे इतने थके हुए थे और उनका साहस इतना टूटा हुआ था कि वे पीछे हटने लगे। इतने पर भी सिखों ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि “वे बिना ऐसे नेता के थे, जो अंगरेजों को पराजित देखना चाहता हो।” इस अवसर पर बहुत सा लूट का माल मित्रों के हाथ आया और अंगरेजों के बहुत से सिपाही भी गिरफ्तार हुए। इसमें सिखों की हिम्मत बढ़ गई।

**अलीवाल और सोवराँ**—इस समय तक गुलाबसिंह जम्मू से ही यह रंग देख रहा था। अब वह भी लाहौर आकर सेना को और बढ़ावा देने लगा, पर स्वयं रणक्षेत्र में जाने का अवसर बड़ी चतुरता से टालता रहा। जनवरी मन् १८४६ के अन्त में सिख सेना फिर सतलज पार करके आ गई, पर अलीवाल के युद्ध में इसको फिर हारना पड़ा। इस पर गुलाबसिंह ने यन्त्रि की बातचीत प्रारम्भ कर दी और अंगरेजों से भिड़ने के लिए सेना को भी बुरा-भला कहा। परन्तु अब गवर्नर-जनरल ने लाहौर पर विजय-पताका फहराना निश्चित कर लिया था, इसलिए वह सिख सेना के तोड़ देने की



गर्त चाहता था। यह बात गुलाबसिंह की शक्ति के बाहर थी। इसलिए उसकी राय में यह तय पाया कि “अंगरेज सिख सेना पर आक्रमण करे। हार होने पर दरबार उसका साथ छोड़ दे, सतलज पर कोई रोक टोक न की जाय और विजेताओं के लिए राजधानी का मार्ग खुला छोड़ दिया जाय।” इति-हामकार कनिंघम के शब्दों में “इस चतुर नीति और निर्लज्ज विश्वासघात की दशा में सोवराव का युद्ध हुआ”।<sup>१</sup>

लड़ने के लिए सैनिकों के हृदय में साहस था, भुजाओं में बल था, केवल एक नता की कमी थी, जो सबको जोश दिलाकर हर एक बात का ठीक ठीक प्रबन्ध कर सकती। पहले ही बार में तेजसिंह भाग निकला, केवल वृद्ध ग्रामसिंह सेना को ललकारता हुआ रणक्षेत्र में डटा रहा, जहाँ लड़ते लड़ते वह मारा गया। मजदूर होकर सिख सेना पीछे हटने लगी। उधर सतलज नदी का बांध टूटा हुआ था, इस पर बहुत से सिपाही नदी में कूद पड़े। ऐसी दशा में भी उन पर गोलावारी की गई। थोड़े ही समय में नदी रक्त से लाल हो गई पर एक सैनिक ने भी शरण की भिन्ना नहीं मानी। इस तरह मित्रों का पहला युद्ध समाप्त हुआ। इसमें जितने अंगरेज अफसर मारे गये, उनमें किसी युद्ध में काम न आये थे।

**लाहौर की सन्धि**—अंगरेजी सेना ने सतलज नदी पार करके कसूर व किले पर अधिकार कर लिया। गुलाबसिंह भी युवक दिलीप को साथ लेकर आ गया। लाहौर पहुँचकर ता० ६ मार्च को सन्धि हो गई। सतलज और व्यास नदियों के बीच की भूमि सिखों से ले ली गई, डेढ़ करोड़ रुपये वड भी माँगा गया और सेना की संख्या घटा दी गई। युद्ध में जिन तोपों

<sup>१</sup> कनिंघम, हिस्ट्री, पृ० ३०९। इस स्पष्ट बात को लिखने के कारण कनिंघम ‘पोलिटिकल विभाग’ में हटा दिया गया और पनाब से भूपाल बदल दिया गया। वह साठ वर्ष तक पनाब में रहा था, इन लड़ाइयों में भी मौजूद था। उसका कहना था कि मैंने पूरी जाँच करके ऐसा लिखा है।

से काम लिया गया था, वे भी छीन ली गईं। गुलाबसिंह जम्मू का स्वतंत्र महाराजा मान लिया गया। लालसिंह वजीर बनाया गया और माल भर



गुलाबसिंह

के लिए कुछ अंगरेजी सेना लाहौर में छोड़ दी गई। ढंड का रुपया वसूल न होने पर हजाग और काश्मीर के इलाके ले लिये गये और ३५ लाख रुपये में काश्मीर गुलाबसिंह के हाथ बेच दिया गया। सन्धि में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि “ब्रिटिश सरकार लाहौर राज्य के शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करेगी।”

आर्थिक तथा सैनिक कठिनाइयों के कारण पंजाब का अंगरेजी राज्य में मिलाया जाना उचित न समझा गया। उस समय इसका राजनैतिक प्रभाव भी अच्छा नहीं

पड़ता, इसका भी ध्यान रखा गया। इसी लिए राज्य का बहुत सा भाग लेकर, सेना घटाकर और गुलाबसिंह को स्वतंत्र बनाकर मालसा पगु बना दिया गया। काश्मीर की भी रक्षा का कोई उपाय न था, रुपये की बड़ी आवश्यकता थी, इसी लिए वह भी गुलाबसिंह को दिया गया। इस मनोरम देश को इस तरह दे देने के लिए बाद में अंगरेजों को बड़ा पछतावा हुआ। काश्मीर पर अधिकार करने में गुलाबसिंह को कुछ कठिनाई हुई, कांगड़ा कोट भी बिना तोपों का भय दिखलाये हुए अंगरेजों को न मिला। इसके लिए लालसिंह दोषी ठहराया गया। उसकी जागीर छीन ली गई और वह पैद करके अंगरेजी राज्य में भेज दिया गया। विश्वासघात का यही फल होता है। ता० १६ दिसम्बर सन् १८४६ में लाहौर दरबार के कहने पर दूसरी

बन्ध की गई। महारानी के सब अधिकार छीन लिये गये और उसके डेढ़ लाख रुपया साल की पेशन दी गई। लाहौर दरबार में अंगरेज रेजिडेंट रख दिया गया, जिसको “सब विभागों के संचालन करने के पूरे अधिकार” दे दिये गये। उसकी निगरानी में काम करने के लिए आठ सरदारों की एक कौमिल बना दी गई। मुख्य मुख्य गढ़ों में अंगरेजी सेना रख दी गई और उसके खर्च के लिए दरबार से २२ लाख रुपया साल लेना निश्चित हुआ। दिलीपसिंह के बालिग होने तक आठ वर्ष के लिए यह प्रबन्ध किया गया। अंगरेजों ने इस बात का विश्वास दिलाया कि वे राज्य में “शान्ति स्थापित रखने” का प्रयत्न करेंगे और “जनता के भावों तथा राष्ट्रीय सस्थाओं” का बराबर ध्यान रखेंगे।

**हार्डिज का शासन**—युद्ध में लगे रहने पर भी हार्डिज ने शासन का अच्छा प्रबन्ध किया। उसी के समय में रेल की पैमायश शुरू की गई और गगाननहर का काम जोरों से चलाया गया। देशी राज्यों को सती-प्रथा बन्द करने के लिए कहा गया और जंगलियों में ‘नरबलि’ रोकने का भी पूरा प्रयत्न किया गया। नमक पर महसूल कम कर दिया गया। रविवार को नातील मनाने का भी नियम बनाया गया। खर्च कम करने के लिए सेना की मर्यादा भी कुछ घटा दी गई। मित्रों पर विजय पाने के लिए उसको लार्ड की सहायता दी गई। जनवरी सन् १८४८ में वह इंग्लैंड वापस चला गया। चलते समय उसका विश्वास था कि “सात वर्ष तक भारतवर्ष में फिर बन्दूक चलाने की आवश्यकता न पड़ेगी।”



श्रार सदा नीति से काम लेता था। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह छुट्टी लेकर लार्ड हार्डिज के साथ ही इंग्लैंड चला गया और उसकी जगह पर करी रेजीडेंट बनाया गया। इसने सब जगह अंगरेज अफसर भर दिये, जो हर एक काम में अपनी मनमानी करने लगे। कर्नल स्लीमैन को भय था कि इसका परिणाम वही होगा, जो काबुल में हुआ था। परन्तु उसकी इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह के हस्तक्षेप से सिखों में बड़ा असन्तोष फैलने लगा। अंगरेज अफसरों ने मुसलमानों को पुरानी बातों का स्मरण दिलाकर सिखों के विरुद्ध भड़काने का भी प्रयत्न किया।<sup>१</sup> पेशावर की तरफ बहुत से मुसलमान बिगड़ पड़े और नाजिम छत्रसिंह को शासन करना असम्भव हो गया। ये सब बातें सिखों को असह्य हो रही थीं और धीरे धीरे अगान्ति की आग सुलग रही थी।

**मुलतान का विद्रोह**—रणजीतसिंह के समय में सावनमल मुलतान का दीवान था। उसने नहरें खोदवाकर वहाँ के बहुत से रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया था। उसके बाद मूलराज दीवान बनाया गया। इस अवसर पर उसने एक करोड़ रुपया नजराना और कुल पिछला हिसाब मांगा गया। इन सब बातों से तंग आकर मूलराज ने अपने पद से इस्तीफा दे देने का विचार प्रकट किया। इस पर दो अंगरेज अफसरों के साथ एक सिख सरदार नया दीवान बनाकर भेजा गया। मूलराज ने मुलतान उसके हवाले कर दिया, पर कुछ सिपाही बिगड़ गये और उन्होंने अंगरेज अफसरों को मार डाला। मुलतान की सेना घटा देने का नये दीवान को हुक्म हुआ था। सिपाहियों के बिगड़ने का, बहुत सम्भव है, यही कारण रहा है। अपनी वचत का कोई उपाय न देखकर और सिपाहियों के दबाव में पड़कर मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया।<sup>२</sup> यदि अंगरेजी सेना पहुँच जाती, तो यह विद्रोह गायब ही शान्त हो जाता, क्योंकि मूलराज के पास अधिक सेना नहीं, पर ऐसा

<sup>१</sup> पञ्जाब पेपर्स, सन् १८४९, पृ० ३००।

<sup>२</sup> एटवर्ट, ए डयर ऑन दि पञ्जाब फ़ाटियर, जि० २, पृ० ५१।

लिया। उसकी सहायता से छत्रसिंह अटक छीनकर लाहोर की तरफ बढ़ने लगा। मुलतान से गेरसिंह भी उसी ओर आ रहा था। ऐसी दशा में अंगरेजों ने मुलतान का घेरा छोड़कर गेरसिंह का पीछा किया। ता० १३ जनवरी सन् १८४६ को चिलियानवाला में दोनों सेनाओं का सामना हुआ। इसमें बहुत से अंगरेज अफसर मारे गये और उनकी चार तोपें छीन ली गईं। सिखों का भी बहुत नुकसान हुआ, पर अन्त में दोनों दलों ने अपनी विजय मानी। स्वयं लार्ड डलहौजी की राय में अंगरेजों की विजय केवल दिखलाने भर की थी, वास्तव में उनकी दशा बड़ी नाजुक हो रही थी।<sup>१</sup> इस युद्ध का समाचार इंग्लैंड पहुँचने पर लार्ड गफ को सेनापति के पद से हटाने की आज्ञा दे दी गई। परन्तु नये सेनापति सिन्धविजयी सर चार्ल्स नेपियर के आने के पहले ही ता० २१ फरवरी को गुजरात की लडाई में उसने सिखों का अन्त कर दिया।

मुलतान इसके पहले ही अंगरेजों के हाथ में आ गया था, इस अवसर पर उनकी कुल सेना एकत्रित थी। छत्रसिंह के आ जाने से मिर्खा मेना की भी संख्या बढ़ गई थी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुछ काल तक वेढव गोलावारी हुई। डलहौजी के शब्दों में सिख “सिंहों की तरह लड़े” पर अन्त में अंगरेजी तोपों के सामने उनको हार माननी पड़ी। ता० १२ मार्च को रावलपिंठी में सिख सरदारों ने हथियार डाल दिये। इस अवसर पर एक वृद्ध सरदार ने आँखों में आँसू भरकर ठीक कहा कि “आज रणजीतसिंह मर गया।”

**पंजावपतन**—अगस्त सन् १८४८ में ही डलहौजी ने यह राय कायम कर ली थी कि बिना सिखों की शक्ति नष्ट किये हुए और पंजाव को ब्रिटिश राज्य में मिलाये हुए, शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। उसका विश्वास था कि सिखों के साथ कभी मित्रता नहीं रह सकती। इंग्लैंड सरकार का मत था कि पंजाव की “अधीनता पूरी होनी चाहिए, पर यदि

<sup>१</sup> डलहौजी, प्राइवेट लेटर्स, स० वेयर्ट, पृ० ४४।

सन्धन न था और उसने उनके ढवाने का भी प्रयत्न किया था। संरक्षक की हमियत से इन विद्रोहों को शान्त करना ब्रिटिश सरकार का कर्तव्य था। अंतरेजी सेना के पंजाब पहुँचने पर ता० ८ नवम्बर सन् १८४८ के घोषणा-पत्र में यह कहा भी गया था कि “विद्रोहियों को ढड देने” और लाहोर दरबार के “विरुद्ध शस्त्र उठानेवालों को ढवाने” के लिए हम पंजाब में आये हैं। परन्तु तब भी अन्त में दिल्लीपसिंह निकाल दिया गया, उसके राज्य पर अधि-कार कर लिया गया और कोहनूर हीरा छीन लिया गया। लडलो लिखता है कि इस तरह सब कुछ अपहरण करके दिल्लीपसिंह की “रक्षा” की गई।<sup>१</sup>

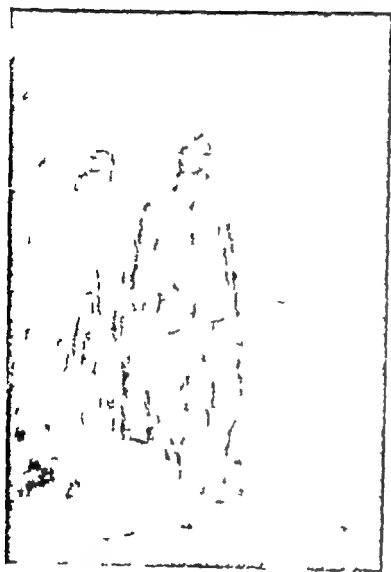
लार्ड डलहौजी ने इस सन्धन में अपनी नीति का बड़े जोरों से समर्थन किया है। वह सचालको को लिखता है कि लाहोर दरबार ने पिछली सन्धि की शर्तों का पालन नहीं किया था। सैनिक खर्च के लिए २२ लाख रुपया माल तय हुआ था, जिसमें से “एक रुपया तक” नहीं दिया गया था। विद्रोहों के ढवाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। ये विद्रोह लाहोर दरबार के विरुद्ध न थे, पर वास्तव में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे। “ब्रिटिश शक्ति का नाश” सिखों ने निश्चित कर लिया था। उनकी स्वतंत्रता में सारे देश का भय था। ऐसी दशा में मैंने जो कुछ किया, “राज्य के प्रति अपना कर्तव्य समझकर शुद्ध चित्त से किया।” उसके न्यायसंगत तथा आवश्यक होने में मुझे जरा भी मन्देह नहीं है।<sup>२</sup> इवांस वेल की राय में यह समर्थन “नतिक दृष्टि से तुच्छ” और उम उदार राष्ट्र के लिए, जो “भारत तथा पूर्व के सामन आदर्श रखने का दावा करता है, सर्वथा अयोग्य है।” उसने सप्रमाण पिट्ट किया है कि सैनिक खर्च के हिसाब में १३५६६३७ रुपया जमा किया गया था। विद्रोहों में अधिकांश सिख सरदार शामिल न थे और लाहोर दरबार ने यथाशक्ति उनके ढवाने का प्रयत्न किया था। अन्तिम सन्धिपत्र पर कैम्ब्रिज के मेम्बरों को डरा धमकाकर हस्ताक्षर कराये

१ लटलो, ब्रिटिश इटिया, जि० २, पृ० १६६।

२ जर्नाल, डलहौजीज ऐडमिनिस्ट्रेशन, जि० १, पृ० २०५-९।

गये थे। लार्ड डलहौजी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि और आर्थिक लाभ था।<sup>१</sup>

बालक दिलीपसिंह अपने कुटुम्बियों और देवनामियों से अलग करके एक अँगरेज की निगरानी में फतहगढ़ में रख दिया गया, जिसका फल यह



कैदी मूलराज

हुआ कि वह थोड़े ही समय में ईसाई हो गया<sup>२</sup> और इंग्लैंड चला गया। वहाँ से वह फिर कभी स्वदेश न लौटने पाया। इंग्लैंड में उसके वंशज अब भी मौजूद हैं। अँगरेजों के अत्याचार से पीड़ित होकर उसकी माता चुनारगढ़ से भागकर नेपाल चली गई। उसका बहुत सा जेवर जप्त कर लिया गया और पेशन बन्द कर दी गई। दीवान मूलराज को फाँसी का हुक्म हुआ। लार्ड डलहौजी उसको 'कालेपानी' भेजना चाहता था, जिसका उसे 'मृत्यु से भी बड़कर भय' था। परन्तु गवर्नर-जनरल

की यह इच्छा पूर्ण होने के पहले ही मूलराज का अन्त हो गया। अँगरेज वैदियों को सिख सरदारों के हाथ से छुड़ाना था, इसलिए पहले उनके साथ दया का बर्ताव करने का वचन दिया गया, पर जब अँगरेज कैदी लूट आये, तब

<sup>१</sup> स्वामि वेल्, प्रेसक्वेशन ऑफ दि पनाव।

<sup>२</sup> इस अवसर पर लार्ड डलहौजी ने दिलीपसिंह को एक वाइविल भेंट की, जिस पर लिखा हुआ था कि इस पवित्र ग्रन्थ में उसको जो कुछ मिलेगा, वह दुनियाँ के राज्यों ने कदा बड़का है। दिलीपसिंह एंड दि गवर्नमेंट, मन् १८८४, पृ० ८५।



सरदारों पर बहुत से अपराध लगाये गये और वे सबके सब इलाहाबाद भेज दिये गये। इस तरह रणजीतसिंह के, जिसने अंगरेजों का बराबर साथ दिया था, राज्य और वंश का भारतवर्ष में अन्त हो गया।

**नया प्रबन्ध**—हेनरी लारेंस की उदार नीति से डलहौजी चिढ़ा हुआ था। वीर शत्रुओं के प्रति उसकी महानुभूति डलहौजी को पसन्द न थी। इसी लिए पंजाब का शासन हेनरी लारेंस को न दिया गया। उसके लिए चार सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया, जिसके निरीक्षण का काम गवर्नर-जनरल ने स्वयं अपने हाथ में रखा। सबसे पहले “हथियार छीनकर जनता की युद्धप्रवृत्ति दबा दी गई।” सालसा दल तोड़ दिया गया और बहुत से सिपाही, दूसरों की स्वतंत्रता अपहरण करने के लिए, अंगरेजी सेना में भरती कर लिये गये। विद्रोही सरदारों की जागीरें छीनकर उन्हें हर तरह से दबा दिया गया। इन उपायों द्वारा ‘पंजाब बोर्ड’ को तीन ही वर्ष में यह कहने का अवसर मिला कि “हाल में मिलाये हुए राज्य में जैसी पूर्ण शान्ति है भारतवर्ष के अन्य किसी भाग में नहीं है।”

कुल पंजाब बहुत से जिलों में बाँट दिया गया, जिनमें अंगरेज कमिश्नर रख दिये गये। इनमें बहुत से सैनिक अफसर थे। इनको न्याय के सत्र अधिवार दे दिये गये। यहाँ बगाल के कानून-कायदे जारी नहीं किये गये। मजिस्ट्रेटों को देश के रीति-रिवाजों का ध्यान रखकर न्याय करने की स्वतंत्रता दे दी गई। बहुत से कर उठा दिये गये और खेती की उन्नति के लिए नहरों का प्रबन्ध किया गया। व्यापार की ओर भी ध्यान दिया गया और कई नए मण्डल बनवाई गई। सन् १८५५ में शिक्षाविभाग स्थापित किया गया और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए धोटे से स्कूल खोले गये।

सन् १८५३ में बोर्ड तोड़ दिया गया और हेनरी लारेंस का भाई जान लारेंस, जो प्रायः लार्ड डलहौजी से सहमत रहता था, पंजाब का चीफ कमिश्नर बना दिया गया। शान्ति स्थापित रखने के लिए ५० हजार सेना रखा गई। पश्चिमोत्तर सीमा पर, जो अब सिन्ध नदी पार कर गई थी, रक्षा का पूर्ण प्रबन्ध कर दिया गया। लार्ड डलहौजी का यह “प्यारा प्रान्त” था।

इसमें उसने चुन-चुनकर योग्य अफसरों को शासन करने के लिए रखा था। इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब में शान्ति स्थापित हो गई, गेती तथा व्यापार की उन्नति हुई, न्याय की दशा सुधर गई और शिक्षा का प्रचार हुआ। पर साथ ही साथ उसका सच्चा जीवन नष्ट हो गया।

**बर्मा का दूसरा युद्ध**—पिछली सन्धि से आवा दरबार में अंगरेज रेजीडेंट रखना निश्चित हुआ था और बर्मा सरकार ने अंगरेज व्यापारियों को सब तरह की सुविधाएँ देने का भी वचन दिया था। परन्तु वहाँ रेजीडेंट की मनमानी न चल पाती थी, इसलिए सन् १८४० के बाद से कोई रेजीडेंट नियुक्त नहीं किया गया था। अब रंगून में अंगरेज व्यापारियों पर अत्याचार की शिकायतें आने लगीं। अंगरेजों की ही प्रजा के आदिमियों द्वारा अभियोग लाने पर रंगून के बर्मा गवर्नर ने दो व्यापारी जहाजों के कप्तानों को कुछ दिन तक निगरानी में रखकर उन पर ६ सौ रुपया जुर्माना कर दिया। बर्मा सरकार का यह बड़ा भारी अन्याय माना गया और हजार हरजाना वसूल करने के लिए तीन जंगी जहाजों के साथ जहाजी सेना का एक अफसर भेज दिया गया। बर्मा स्वतंत्र राज्य था, ब्रिटिश प्रजा के अभियोग लाने पर ही कप्तानों को दंड दिया गया था, समझौते से मामला तय हो सकता था, फिर जंगी अफसरों को, जो लार्ड डलहौजी के शब्दों में बातचीत ही में “भभक” उठते थे, भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

अंगरेजों के कहने पर बर्मा सरकार ने रंगून के उस गवर्नर को, जिसने दंड दिया था, हटा दिया और एक नया गवर्नर भेजा। उससे भी अंगरेजों की न पटी। एक दिन वह सो रहा था, इसलिए उसके पहरेदारों ने अंगरेज अफसरों को मुलाकात करन से कुछ काल के लिए रूक में रोक लिया। यह अपमान अंगरेज अफसर महन न कर सके। उन्होंने बर्मा सरकार का एक जहाज पकड़ लिया और नदियों के मार्ग को रोकने की आज्ञा दे दी। यह झूल की गई, इसको डलहौजी ने भी माना है। पर तब भी उसने बर्मा के राजा को एक बड़ा कटा पत्र लिख दिया, जिसमें बहुत सा हरजाना माँगा गया, माफी माँगने के लिए कहा गया और युद्ध की धमकी दी गई। ‘वोर्ड’

‘आफ कंट्रोल’ के सभापति की राय में भी पत्र की भाषा बड़ी तीव्र थी। पर डलहौजी का मत था कि हिन्दुरतानी राजा और खासकर बर्मा के शासक सीधी सीधी बात से डीर नहीं रहते।<sup>१</sup> इस पत्र के उत्तर की बिना प्रतीक्षा किये हुए ही युद्ध करना निश्चित कर लिया गया।

बर्मा में युद्ध की कोई तैयारी न थी, यहाँ पहले ही से सय प्रबन्ध था। बात की बात में अंगरेजी सेनाएँ बर्मा पहुँच गईं। मर्तवान पर अधिकार कर लिया गया, रगून का मन्दिर भी छीन लिया गया और अंगरेजी सेना प्रेमस तक पहुँच गई। बर्मा दरबार सन्धि करने के लिए राजी न था। इस पर कुल दक्षिणी बर्मा अर्थात् पीगू प्रान्त अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया। ईंग्लैंड-सरकार कुल बर्मा के फिक में थी, पर डलहौजी की राय में इसके लिए समय नहीं आया था। इस प्रान्त के निकल जाने से बर्मियों के हाथ समुद्र-तट जाता रहा, कुमारी अन्तरीप से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक गाल की खाड़ी के कुल तट पर अंगरेजों का अधिकार हो गया। सन् १८५२ के अन्त में लार्ड डलहौजी लिखता है कि “केवल ईश्वर जानता है कि युद्ध की आवश्यकता को दूर करने की मेरी कितनी प्रबल इच्छा थी।” रगून घटनाओं से इसका समर्थन नहीं होता। ईंग्लैंड के लोकप्रिय नेता लावटन ने इस युद्ध की पोल अच्छी तरह खोली है।<sup>२</sup> उसका पूछना था कि दो अंगरेजों के अपमान के लिए युद्ध में भारत का खजाना क्यों लुटाया गया? इसमें भारत की निर्धन प्रजा का क्या लाभ हुआ? एक हजार रुपये से दस लाख तक हरजाना माँगना कहाँ तक उचित था? लार्ड डलहौजी का कहना था कि जब पीगू से आसमानी होने लगोगी, तब ब्रिटिश राष्ट्र इन सब बातों को भूल जायगा।<sup>३</sup>

<sup>१</sup> लीवानर, डलहौजी, जि० १, पृ० ४०१।

<sup>२</sup> लावटन, हाऊ वार्म आर गाट अप इन इण्डिया ?

<sup>३</sup> मार्शमन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जि० ३, पृ० ३७५।

**पीगू का शासन**—पंजाब की तरह पीगू छीनने को भी वाफायद बनाने के लिए बर्मा दरबार से सन्धि करने का प्रयत्न किया गया, पर सफलता न हुई। बर्मा राजदूत कलकत्ता आये। उनका कहना था कि यदि शान्ति स्थापित करना है, तो जीता हुआ देश लौटा देना चाहिए। इसके उत्तर में कहा गया कि “जब तक सूर्य में प्रकाश है ऐसा नहीं किया जायगा, युद्ध का दोष बर्मियों के मत्थे है।” अँगरेजी दूत आवा भी भेजे गये, पर कुछ तत्त्व न निकला। एक लाभ अवश्य हुआ, दरबार की बहुत सी बातों का पता लग गया और कई एक अफसर भी अपने पक्ष में मिला लिये गये। रगून पीगू की राजधानी बनाया गया और वहाँ भी पंजाब की तरह शासन का प्रबन्ध किया गया। लार्ड डलहौजी स्वयं वहाँ चार बार गया। पीगू पर अधिकार हो जाने से पूर्विय देशों के लकड़ी और चावल का बहुत सा व्यापार अँगरेजों के हाथ में आ गया। डकैतियों के रोकने, तार लगाने तथा सड़के बनवाने का प्रबन्ध किया गया और शिक्षा के लिए कुछ स्कूल भी खोले गये।

**देशी राज्यों का अपहरण**—लार्ड आकलैंड के समय में ही इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने यह निश्चित कर लिया था कि अवसर मिलने पर देशी राज्यों को छीन लेने से चूकना न चाहिए।<sup>१</sup> ‘वोर्ड आफ कंट्रोल’ के अध्यक्ष हावहाउस ने डलहौजी को भी इस नीति का इशारा कर दिया था।<sup>२</sup> इसी उद्देश्य से अब यह दिखलाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि देशी राज्यों से भारत का कितना अहित हो रहा था। स्वयं डलहौजी का मत था कि छोटे छोटे राज्यों से झगड़ो ही की अधिक सम्भावना है। उनका अन्त कर देने से सरकारी खजाने को भी लाभ होगा और उन राज्यों में भी एक ही ढंग की शासन-व्यवस्था हो जायगी, जिससे वहाँ के लोगों का बड़ा हित होगा।<sup>३</sup> ‘सुप्रीम काउन्सिल’ के एक मेम्बर की राय थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के बीच बीच में देशी

१ जॉन रिग्न, मेम्बॉयर, पृ० २७०। वमु, जि० ५, पृ० २१८।

२ लीवार्नेर, टर्म्स, जि० २, पृ० १५०।

३ इंडिया अन्डर डलहौजी एन्ड कनिंग, पृ० २७।

राज्यों के होने से साधारण सुधार के कार्यों में बड़ी अड़चन पड़ती है। ब्रिटिश भारत में जितना देश है, उस पर शासनाधिकार हो जाने ही में जनता का सबसे अधिक हित है।<sup>१</sup> सेनापति नेपियर का कहना था कि एक भी देशी राजा को न छोड़ना चाहिए।<sup>२</sup> इस तरह देशी राज्यों के प्रति इंग्लैंड-सरकार, गवर्नर-जनरल और उसके मलाहकारों की नीति निश्चित थी। इसको काम में लाने के लिए एक विचित्र सिद्धान्त का सहारा लिया गया। पुत्र न होने पर हिन्दुओं में गोद लेने की प्रथा है। राजाओं को इसके लिए, जिस शक्ति के वे अधीन होते थे, उसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। यह एक साधारण नियम था। इसमें कोई विशेष अड़चन न डाली जाती थी और नजराना लेकर यह आज्ञा प्रायः सभी राजाओं को दे दी जाती थी। अब इसका यह अर्थ लगाया गया कि गोद लेने की आज्ञा देना या न देना ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर निर्भर है। यदि किसी राजा को यह आज्ञा नहीं मिली है, तो उसके मरने पर उसका राज्य सरकार की सम्पत्ति है। उसने और किसी का हक नहीं है। एक साधारण नियम का यह मनमाना अर्थ था। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर जार्ज क्लार्क की राय में मुसलमानों या मराठों के शासनकाल में कोई राज्य इन तरह जव्त नहीं किया गया था।

सन् १८३४ में ही सचालको ने यह निश्चित कर लिया था कि जहाँ तक सम्भव हो गोद लेने की आज्ञा न देने चाहिए। सन् १८४१ में ब्रिटिश सरकार ने भी यह मत स्थिर कर लिया था कि ऐसे राज्य हाथ में आ जाने से छोड़ने न चाहिए। इसी के अनुसार कोलाश और माडची की रियासतें पहले ही जव्त हो चुकी थीं। अब डलहौजी ने अधीन राज्यों के सम्बन्ध में इसको अपना मुख्य सिद्धान्त मान लिया और कई एक हिन्दू राज्यों को जव्त कर लिया। उसकी राय में हिन्दू राज्यों की तीन श्रेणियाँ थीं। एक तो म्हादीन राज्य, दूसर ऐसे राज्य जो ब्रिटिश सरकार को मुगल सम्राट् या पेशवा के

<sup>१</sup> सतारा पेपर्स, सन १८०९, पृ० ८७।

<sup>२</sup> एडर, डलहौजी (रूलर्स ऑफ़ इण्डिया मिरीज) पृ० २७।



हित था। इसलिए इनके सम्बन्ध में वह 'हस्तक्षेप न करने की नीति' का पक्ष अनुयायी बन गया था। उसका स्पष्ट कहना था कि "स्वतंत्र देशी राज्यों के पुनरुद्धार" का हमने बीड़ा नहीं उठाया है।<sup>१</sup> 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के अध्यक्ष लार्ड ब्राउटन को पूरा विश्वास था कि "पाँच मिनट" का भी समय मिलने पर डलहौजी अवध और हैदराबाद के शासकों का, जो ब्रिटिश साम्राज्य को कलंकित कर रहे हैं, अन्त कर देगा।<sup>२</sup>

**सतारा**—लार्ड डलहौजी के भारतवर्ष पहुँचने के कुछ ही दिन बाद, दिसम्बर सन् १८४७ में 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' की ओर से हायहाउस उसको सतारा के विषय में लिखता है कि "मैंने सुना है कि राजा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। बहुत सम्भव है कि उसके राज्य के भाग्य का निर्णय हमें गीब्र ही करना पड़े। मेरी पक्की राय है कि बिना पुत्र के इस राजा के मरने पर गोद लेने की आज्ञा न दी जाय और यह छोटा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाय। यदि मेरी अध्यक्षता में यह प्रश्न आया, तो मैं ऐसा ही करने के लिए कोई बात उठा न रखूँगा।"<sup>३</sup> सन् १८४८ में राजा के मरने पर उसका राज्य ले लिया गया। मरते समय उसने जिस लड़के को गोद लिया था, उसका राज्य पर कोई अधिकार न माना गया। लार्ड डलहौजी लिखता है कि सन् १८१६ में इस राज्य को स्थापित करने की भले ही आवश्यकता रही हो, पर अब मराठों का भय न होने से, इसके रखने की कोई जरूरत नहीं थी। यह 'जिला बहुत उपजाऊ है और आमदनी भी बढ़नेवाली' है। इसको ले लेने से हमारे सैनिक प्रबन्ध तथा शासन में सुगमता हो जायगी और आमदनी भी बढ़ जायगी।

सन् १८१६ में सतारा के राजा के साथ जो सन्धि हुई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि उसके "वारिसों तथा उत्तराधिकारियों" का राज्य पर "बराबर

१ प्रिविल, हिस्ट्री ऑफ टेकन, जि० २, पृ० २०३।

२ लाबानर, डलहौजी, जि० २, पृ० ३१५।

३ यहाँ, पृ० १५८।

कब्जा" बना रहेगा। बम्बई के गवर्नर सर जार्ज क्लार्क का मत था कि ऐसी दशा में राज्य को जूट करना किसी तरह उचित न था। रेजीडेंट फ्रेरे का कहना था कि किसी अदालत के सामने राजा के वारिस अपना हक साबित कर सकते थे। सतारा का शासन भी ऐसा बुरा न था। प्रतापसिंह के समय में तो राज्य की बड़ी अच्छी दशा थी। परन्तु दो लाख पैड साल की आमदनी के सामने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। अर्नाल्ड लिखता है कि सरकार के मन्त्रों पर कलक का यह ऐसा टीका लगा, जो कभी मिट नहा सकता।

**नागपुर**—दिसम्बर सन् १८५३ में नागपुर के राजा की मृत्यु हो गई। उसके भी कोई सन्तान न थी, इसलिए उसका भी राज्य ले लिया गया। नागपुर के राज्य का वही पद था, जो सिन्धिया और होलकर के राज्यों का था। परन्तु इसके उत्तर में कहा गया कि अपना साहब के भागने पर राज्य अंगरेजों के हाथ में आ गया था और उन्होंने अपनी तरफ से राजा को गद्दी पर बिठलाया था। सन् १८२६ की सन्धि से राज्य "ब्रिटिश सरकार की दया पर" निर्भर था और "महाराजा की मर्मान्त जिसे चाहे देने" का उसे अधिकार था। ऐसी दशा में नागपुर की भी गणना अधीन राज्यों में थी। विधवा रानी ने एक बालक गोद लिया था, उसका कोई हक न माना गया। कहा गया कि पिछले राजा ने बड़ा अत्याचार किया था। वह "न्याय को बेचने-वाला, शराबी और व्यसनी" था, फिर ब्रिटिश सरकार को यह कैसे विश्वास हो सकती थी कि नया राजा उसी की नकल नहीं करेगा? नागपुर की प्रजा के हित की दृष्टि से सरकार इस अवसर को छोड़ नहीं सकती।

ब्राम्बर में मुख्य कारण, जैसा कि लीवानर ने लिखा है, नागपुर का भौगोलिक और राजनैतिक महत्व था। डलहौजी का ध्यान था कि इस राज्य को मिला लेने से ८० हजार वर्ग मील भूमि पर अधिकार हो जायगा, ४० लाख रुपये माल की आमदनी बढ़ जायगी और इधर उधर का राज्य एक में मिल जायगा। कलकत्ता से बम्बई जाने के लिए मार्ग भी साफ हो जायगा। इस तरह "नागपुर पर अधिकार हो जाने से हमारी सैनिक शक्ति एक में मिल



जायगी, हमारे व्यापार का क्षेत्र बढ़ जायगा और हमारा शासन भी अच्छी तरह बढ़े जायगा।”<sup>१</sup> इंग्लैंड-सरकार का भी यही मत था और डलहौजी को बराबर इसके सम्बन्ध में लिखा जा रहा था। राज्य का अन्त हो जाने पर दरबार की सब सम्पत्ति नीलाम कर दी गई। सर जान के का कहना है कि सामान लेने में रानियों के साथ बहुत ज्यादती की गई। नीलाम की कुछ ग्रामदानी ने भोसला परिवार की रक्षा के लिए एक ‘भोसलाफंड’ खोल दिया गया। इनमें सरकार की कोई उदारता नहीं थी। उस सम्पत्ति पर तो भोसला के कुटुम्बियों का सब तरह से अधिकार ही था।

**भोसला-शासन**—तत्कालीन अन्य राज्यों के शासन की तरह भोसलाओं का शासन में भी बहुत से दोष थे। पर तब भी राज्य की दशा ऐसी शोचनीय नहीं थी, जमी कि बतलाई जाती है। वह बात रिचर्ड जेकिस के, जो बहुत दिनों तक नागपुर दरबार में रेजीडेंट रहा था, दिये हुए विवरण से स्पष्ट है। वह लिखता है कि जनोजी भोसला के समय में न्याय ठीक ढंग से होता था। फौजदारी अपराध बहुत कम होते थे और प्राणदण्ड शासन ही कभी दिया जाता था। राजदानी ग्रामदानी खूब थी और प्रजा सुख से रहती थी। सेना और बड़े अफसरों का वेतन ठीक समय में बिना कुछ बढ़ाये हुए दिया जाता था। राजा अपने बराबर समझता था और दरबार में कभी कभी वह स्वयं उठकर मिलता था। राघोजी के समय में ‘मजुमदार’ या दीवान राज्य का सबसे मुख्य अफसर होता था। उसके फटनवीस के हाथ में कुल हिमाय-किताब और दफ्तर रहता था। नगर के बड़े बड़े साहूकारों को भी दरबार में स्थान दिया जाता था और समय समय पर उनमें मलाहली जाती थी। उनमें से एक ‘नगर-नायक’ होता था, जो व्यापार का निरीक्षण करता था और राज्य के लिए आवश्यकता होने पर ऋण का प्रबन्ध करता था।

यहां भी दक्षिण की तरह हर एक गांव में एक पटेल रहता था, जिसके पास गांव के अन्य कर्मचारी काम करते थे। लगान के अतिरिक्त भी बहुत

<sup>१</sup> लार्डार्न, डलहौजी, जि० २, पृ० १७८-७९।

से कर लिये जाने थे। पटेलों पर निगरानी रखने के लिए मूवेदार लोग डोंग करते थे। पटेलों को न्याय और पुलिस के भी कुछ अधिकार रहने थे। डीवानों मामले पचायतों द्वारा तय किये जाने थे। पंचों को चुनने में जानि-पॉनि का भेद न माना जाता था। प्रायः योग्य और प्रतिष्ठित लोग ही चुने जाते थे। बड़ी बड़ी पचायतों में कुल कार्यवाही लीमी जाती थी। गवाहों का बड़ा ध्यान रखा जाता था और किसी प्रकार का हम्नजेप न होने पाता था। फौजदारी की अन्तिम अपील राजदरबार में होती थी। स्त्रियों और ब्राह्मणों को प्राण-दंड नहीं दिया जाता था। सन् १७६० तक राज्य की अच्छी दशा थी। वेलेजली के मराठा-युद्ध के बाद से कुछ अत्याचार अवश्य प्रारम्भ हो गया था।

हर एक जिले में वहाँ के लिए काफी खपडा बनता था। नागपुर में बुनाई का अच्छा काम होना था। बगाल के ढँग के डोरिया और चारगाने बनाये जाते थे। सन् १८०३ में रावोजी ने बहुत से जुलाहों को जैनागढ़ और बरहानपुर से लाकर बसाया था। सबसे अधिक खादी बनती थी, जो तम्बू, कनात और साधारण आदमियों के पहनने के काम में आती थी। बारह आने से लेकर तीन रुपये तक का एक धान बिकता था। सन् १८०३ तक यह खादी बरार होकर बम्बई और अरब तक जाती थी। धोतिया, साडी, लुगी और हमाल भी बहुत बनते थे। सन् १८१७ से कपड़े का बनना मन्दा पड़ गया। मेनाश्री के तोड़ देने से कपड़े की खपत कम हो गई। साल में १४ लाख रुपये का कपडा केवल पूना जाता था। पेशवा का दरबार नष्ट हो जाने से यह बन्द हो गया, पर तब भी बाजीराव के खर्च के लिए कपडा बराबर बिकर जाता रहा। हुडी-पर्व का काम मारवाड़ियों के हाथ में था, जो जैक्स के शब्दों में “बड़े बुद्धिमान्, व्यापारचतुर और ईमानदार होते हैं।” शिक्षा का प्रचार ब्राह्मणों में अधिक था। गुलामी की कम चाल थी। हर एक चीज का भाव मन्दा था। धी रुपये का तीन चार सेर, आटा ३७ सेर और चावल २५ सेर बिकता था। यदि सन् १८२७ तक, जब का यह विवरण है, ऐसी दशा थी, तो फिर

पचीस ही वर्ष में कौन सा और क्यों ऐसा परिवर्तन हो गया, जिसके कारण डल-होजी को प्रजा पर दया करके नागपुर कम्पनी के राज्य में मिला लेना पड़ा ?

नागपुर की गई-बीती अवस्था में भी अन्तिम रेजीडेंट मैमेल को मानना पड़ा है कि शासन के सिद्धान्त चाहे जो कुछ हो, राज्य की दशा अच्छी थी ।<sup>१</sup> मर रिचर्ड टेम्पल भी, जो बाद को चीफ कमिश्नर हुआ, लिखता है कि भोसला घराने के मराठा राजाओं द्वारा नागपुर के शासन के बारे में मेरा अच्छा गयाल है । उसमें कई एक अच्छी बातें थीं ।<sup>२</sup>

**भाँसी**—यह मराठों के अधीन थी और यहाँ का शासक पेशवा का सूबेदार कहलाता था । सन् १८१७ में पेशवा का राज्य नष्ट होने पर सूबेदार रामचन्द्रराव ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली । सन् १८३० में उसको राजा की उपाधि दी गई । सन् १८३५ में उसकी मृत्यु होने पर उसका चचा गद्दी पर बिठला दिया गया । जिस लड़के को उसने गोद लिया था, उसका हक न माना गया । कारण यह था कि गद्दी के लिए चार हकदार लड़-भिड़ रहे थे । गोद लेने के सम्बन्ध में भी बहुतों को मन्देह था । इसी लिए जो सबसे योग्य समझा गया और जिसका पक्ष सबसे प्रबल था, वही गद्दी का अधिकारी मान लिया गया । सन् १८५३ में जो राजा मर गया, उसके भी कोई सन्तान नहीं थी । मरने के एक दिन पहले उसने एक बालक को गोद लिया था । लार्ड डलहौजी ने उसको नहीं माना और रानी को पेंशन देकर भाँसी का राज्य जप्त कर लिया गया । डलहौजी का कहना था कि भाँसी नीमरे दर्जे का राज्य था । दत्तक पुत्र का अधिकार न मानने का सन् १८३५ का प्रमाण मौजूद था और वहाँ के राजा किसी योग्य न थे । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाँसी अंगरेजों की दी हुई जागीर न थी । हम पर रामचन्द्रराव तथा उसके “वारिसों” का अधिकार उन्होंने “मर्दा के लिए” मान लिया था । सन् १८३५ में गोद लेने का अधिकार था या नहीं,

<sup>१</sup> वरार पेपर्स, सन् १८५८, पृ० २६ ।

<sup>२</sup> ब्रिटिश एट नटिव मिस्टर्स, जन १८६८, पृ० ६९ ।

इस पर कोई विचार नहीं किया गया था। जिसका पन्ना मस्ये प्रबल था, वही राजा मान लिया गया था। वहा के शासन में प्रजा मन्तुष्ट थी। राज्य का काम चलाने के लिए रानी “मर्षया योग्य” थी।<sup>१</sup> परन्तु भाँसी का राज्य “ब्रिटिश जिलो के बीच में” था, इसलिए डलहौजी की राय में उस पर अधिकार कर लेना ही “नीतियुक्त” था।

**निजाम और वरार**—सहायक सेना के अतिरिक्त निजाम को ४० लाख रुपया साल के खर्च में एक दूसरी सेना रखनी पड़ती थी, इसका उल्लेख किया जा चुका है। किसी सन्धि के अनुसार शान्ति के समय में इस सेना का रखना आवश्यक न था। पर तब भी यह सेना तोड़ी न जाती थी। इसका परिणाम यह हो रहा था कि निजाम पर सरकारी कर्ज बढ़ रहा था। लार्ड हेस्टिंग्स के शब्दों में “यह सेना, जो वेतन देना था, उसकी अपने आपनी थी।” रेजीडेंट फ्रेजर की राय में, इस सेना का रखना “अपने लिए वैसा ही लज्जाजनक था, जैसा कि निजाम के लिए हानिकारक।” रेजीडेंट लो इससे “निष्ठुरता” समझता था, जिसके कारण निजाम का सजाना खाली हो रहा था। उसका कहना था कि जिस सेना का खर्च हम बराबर २८ वर्ष से ले रहे हैं, किसी सन्धि के अनुसार, उसका निजाम से “एक रुपया” भी लेने का “हमें अधिकार नहीं है।” सन् १८४८ में डलहौजी ने भी स्वीकार किया कि इस मामले में ब्रिटिश सरकार निर्दोष नहीं है।<sup>२</sup>

इतने पर भी यह सेना घटाई नहीं गई। उल्टे कुल कर्ज, जो बढ़ते बढ़ते ६४ लाख तक पहुँच गया था, फौरन श्रदा करने के लिए निजाम को उड़ी तीव्र भाषा में लिखा गया और कहा गया कि भारत-सरकार की “शक्ति तुम्हें जब चाहें पड़दलित कर सकती है”। बेचारे निजाम ने अपने जवाहरात गिरग्री रत्नफर जेमे तैय्ये पहली किस्त श्रदा की। बाकी जवाहरात को वह एक बैक में, जो टूनी के लिए कायम किया गया था, बन्धक रखकर ४० लाख रुपया देना चाहता था, पर गवर्नर-जनरल की आज्ञा से वह बक तोट दिया गया।

<sup>१</sup> मार्चन, स्ट्रियन एन्वायर, पृ० २, पृ० ५६-५७।

<sup>२</sup> प्रिन्सिपल, मिस्ट्री ऑफ़ हि इंडिया, पृ० २, पृ० १९५-१९७।

आवकारी के हिसाब में निजाम का ४० लाख रुपया अंगरेजों के पास निम्नलता था। वह भी मुजरा नहीं दिया गया और निजाम से कुल रुपये की अर्द्ध के लिए राज्य का कुछ भाग दे देने के लिए कहा गया। गवर्नर-जनरल की इस ज्यादती के कारण रेजीडेंट फ्रेजर का रहना मुश्किल हो गया। निजाम और उसके वजीर के आनाकानी करने पर मैनिक्र वल के प्रयोग की धमकी दी गई और सन् १८५३ में एक सन्धिपत्र पर, जिसके अनुसार बरार अंगरेजों के पास बन्धक रख दिया गया, निजाम के हस्ताक्षर करा लिये गये।<sup>१</sup>

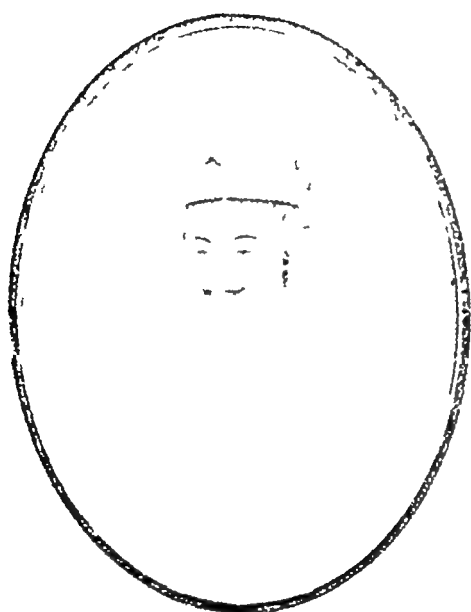
दलहोजी की राय में निजाम के साथ बड़ी 'उदारता और नम्रता' का व्यवहार किया गया। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की "ईमानदारी" और "क्षमता" में किसी का मन्देह नहीं हो सकता। इस प्रबन्ध से 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' के अध्यक्ष चार्ल्स वुड को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी राय में यदि कोई भूल हुई तो इतनी ही कि निजाम को कुल हिमायत समझाने और वचन वापस कर देने का वचन दे दिया गया।<sup>२</sup> बरार रुई की गैती के लिए प्रसिद्ध है। यह निजाम को फिर कभी वापस न किया गया। बरार और नागपुर ले लेने के सम्बन्ध में एक अंगरेज ने ठीक कहा था कि "इन दिनों न्याय के कान में रुई ऐसी थी।"

**अवध राज्य का अन्त**—मुहम्मदअली के मरने पर उसके लड़के अमजदअली ने पांच वर्ष तक राज्य किया। उसमें शासन की विशेष योग्यता न थी, पर तब भी ७७ हजार रुपया माल के खर्च में रेजीडेंट की निगरानी में सीमा पर की पुलिस ठीक की गई। गिग-युद्ध के समय पर उसने भी ब्रिटिश सरकार की बड़ी सहायता की। उसका बाद सन् १८८७ में वाजिद-अली शाह गद्दी पर बैठा। दो वर्ष में शासन ठीक करने के लिए उसके चनाबती दी गई। इस पर सन् १८४८ में रेजीडेंट तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त व लपिटेन्ट-गवर्नर की राय से अवध के कुछ मरहटी जिलों में ब्रिटिश शासन-

<sup>१</sup> मिडिल, हिस्ट्री ऑफ़ डिडेकन, जि० , पृ० २०६--१।

<sup>२</sup> लीगनर, जि० २, पृ० १२०।

व्यवस्था चलाने के लिए एक योजना तैयार की गई। परन्तु फलकृता से उसके लिए मजूरी नहीं मिली। वहा तो कुछ और ही तैयारियाँ हो रही



वाजिदग़ली शाह

पर विचार करनेवाली कमेटी भी बैठनेवाली है। इसी लिए, मेरी राय में, पेड को हिलाकर इस फल का गिराना सचालको को पसन्द न आयगा।<sup>१</sup> ता० २१ अक्टूबर सन् १८५३ के पत्र में 'बोर्ड आफ कंट्रोल' का अध्यक्ष चार्ल्स बुड लिखता है कि यदि पीगू छीनने की आवश्यकता न पड़ी होती, तो मुझे अवध के ले लेने में कुछ भी सकोच न होता। हाल में या कुछ दिनों बाद वह तो हमें लेना ही पड़ेगा। "अथ केवल समय, अवसर और बहाने का है।"

थीं। डलहौजी ने पहले ही से यह राय कायम कर ली थी कि अवध के शासन में सुधार होने की सम्भावना नहीं है। वहाँ "बहुत कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे।"<sup>१</sup> अवध के सम्बन्ध में ता० ३० जुलाई सन् १८५३ के एक पत्र में वह लिखता है कि यह फल किसी दिन हमारे मुँह में अवश्य गिरेगा। यह बहुत दिनों से पक रहा है। परन्तु इस समय राज्यों के ज्वल करने के विरुद्ध कुछ ग्रान्दोलन हो रहा है। इसके अतिरिक्त कम्पनी के आज्ञापत्र

१ टर्कोयटी इन एन्सेल्मिस, पृ० १००-१११।

२ एल्हाता, प्राइवेट लेटर्स, पृ० ६०।

इन दिनों “हटप करने की प्रवृत्ति” का दिखालाना बहुत वांछित नहीं जान पड़ता है। इसलिए “अपनी जागीर” पर अधिकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ।<sup>१</sup> इन वाक्यों से अवध के प्रति गवर्नर-जनरल तथा इंग्लैंड-सरकार के जो भाव थे, स्पष्ट है। उसके जवत करने में कभी केवल दो बातों की थी। एक तो बहाना और दूसरे इंग्लैंड की जनता का समर्थन।

मई १८५३ में कम्पनी के शासन की जांच समाप्त हो गई और उसको नया आजापत्र मिल गया। इसलिए इंग्लैंड के लोकमत का अधिक भय न रहा, अब केवल बहाने की बात रह गई। शासन ठीक न होने का बहाना बना बनाया था। इसके लिए अवध के शासकों को प्रत्येक गवर्नर-जनरल द्वारा चेतावनी देता आ रहा था। हाल ही में रेजीडेंट स्लीमैन का दौरा समाप्त हुआ था। प्रजा कैसी पीड़ित थी, उस पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे थे, इसका उसने जो वर्णन किया था, उससे बढ़कर अवध के शासन की तीव्र आलोचना क्या हो सकती थी? यदि वास्तव में ये सब बातें ठीक थी, तो भी यह प्रश्न होता है कि उन सबको दूर करने का क्या एक मात्र उपाय अवध का अंगरेजी राज्य में मिला लेना ही था? नव्य स्लीमैन इसको मानने के लिए तैयार न था। उसकी राय में शासन का भार एक बोर्ड के हाथ में दे देना काम चल सकता था। इसमें शाह को भी आपत्ति नहीं थी। सर एनरी लॉरेन्स का भी ऐसा ही मत था। उसका कहना था कि शासन के दोषों का दूर करने की “श्रृंखला हमारे हाथ में है।” यदि “कोई अपना धन नष्ट करता है, या प्रजा को पीटा पहुँचाता है, तो भी उसको लूट लेने का हमें अधिकार नहीं है। उसका धन बिना अपनी जेब में रखा हुआ हम प्रजा की रक्षा और सहायता कर सकते हैं। यदि हमें अवध की चिन्ता है, तो जहाँ तक सम्भव हो शासन वर्ग के निवासियों ही के हाथ में छोड़ देना चाहिए और वहाँ का एक रुपया भी कम्पनी के खजाने में न लेना चाहिए।”

<sup>१</sup> लाबानर, एल्हाजी नि० २, पृ० ३१६।

<sup>२</sup> एनरी लॉरेन्स, एमेन पृ० १००-३०।

सन् १८३७ की सन्धि से डलहौजी ऐसी प्रवृत्ति का मकत था। परन्तु इसके अनुसार बादशाह को सारा हिमाचल समझाना पड़ता और शासन ठीक हो जाने पर अवध वापस कर देना पड़ता। गायद इन्हीं लिए उसका कहना था कि यह सन्धि रह हो गई। इसको संचालको ने मजूर नहीं किया था, यह बात ठीक है। परन्तु अवध के बादशाह को इसकी सूचना कभी नहीं दी गई थी। बाद में लार्ड हार्डिज ने इसी सन्धि पर जोर दिया था। ऐसी दशा में यह सन्धि रह नहीं मानी जा सकती थी।<sup>१</sup> परन्तु डलहौजी का उद्देश्य ही दूसरा था। इसी लिए वह सन् १८०९ की सन्धि पर जोर दे रहा था, जिसमें नवाब को यह वचन दिया गया था कि अवध का “शासन उसके अफसरों द्वारा होगा।” डलहौजी का कहना था कि ऐसी दशा में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता था? पर वास्तव में अवध में कई एक अंगरेज अफसर इस समय भी काम कर रहे थे। हेनरी लारेंस लिखता है कि छोटी छोटी बातों में बराबर हस्तक्षेप किया जाता था, पर जब कोई महत्त्व का प्रश्न आ जाता था, तब अवश्य हाथ सींच लिया जाता था। अवध की दशा बिगड़ने देने ही में ब्रिटिश सरकार का काम बनता था, इसी लिए उसके सुधारने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही थी। केवल वसूली दी जा रही थी।

गवर्नर-जनरल की ज्यादाती के कारण स्लीमैन को लखनऊ छोड़ना पड़ा। उसका कहना था कि डलहौजी और उसके सलाहकार इन दिनों अवध को अंगरेजी राज्य में मिला लेने के पक्ष में हैं, जिसका परिणाम यह होगा कि वहाँ मजदूर तथा उच्च श्रेणी के लोग नष्ट हो जायेंगे। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा न करने का परिणाम हमारे ही लिए भयकर होगा। “हडप करने की नीति” से देशवासियों में भय के भाव दिग्विस्तार हो रहे हैं। आन्दोलनकारियों के लिए यह अच्छा अवसर मिल रहा है। मैं सन्धियों का पूर्ण रूप से पालन चाहता हूँ। चाहे वे काले मुखवाले से की गई हों या गोरे मुखवाले से। अवध को



जन्म करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना “‘वेईमानी और लज्जा’ की बात होगी। यदि हम प्रजा को बराबर कसतें जायेंगे, तो उस पर जेमा कुछ गामन हो रहा है, उसमें अच्छा न होगा।” “यदि हम अवध या हमके किसी भी भाग को छीन लेंगे, तो भारतवर्ष में हमारे नाम पर, जिसका मूल्य दर्जेनो अवध से अधिक है, धब्बा लगेगा।”<sup>१</sup>

परन्तु डलहौजी की राय निश्चित थी। उसने एक चाल सोच रखी थी। पेशवा नबीकार करके कुल शासन अंगरेजों के हाथ में दे देने के लिए वह वाजिदअली से प्रस्ताव करना चाहता था। उसने सोचा था कि यदि यह प्रस्ताव नबीकार कर लिया गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। पर यदि ऐसा न किया गया तो वह अवध के साथ सब सम्बन्ध तोड़ देगा और वहाँ से सेना तथा अफसरों को हटा लेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अवध भर में उपद्रव मच जायगा और अंगरेजों से छेड़-छाड़ होने लगेगी। तब फिर अवध पर आक्रमण करके भी उसको छीन लेने में किसी को आपत्ति न होगी।<sup>२</sup> उसका कहना था कि सन् १८०१ की सन्धि के अनुसार अवध व गामन में कोई सुधार नहीं किया गया था। इसलिए हमके गामन नष्ट तोड़ देने में कोई दोष न था। उस सन्धि पर अधिक जोर देने का यही मुख्य कारण था। नाम मात्र के शासकों को मानने से कोई लाभ नहीं है, यह लार्ड डलहौजी का सिद्धान्त था। पर अब वह स्वयं इसमें हट रहा था। अंगरेज इतिहासकारों का कहना है कि इसी में अवध के शाही घराने व प्रति हमकी महानुभूति प्रकट हो रही है। परन्तु वास्तव में वह केवल एक ‘बहाना’ ढूँढ़ रहा था। यदि सचमुच हमकी महानुभूति होती, तो स्लीमैन तथा हनरी लारेंस की राय मानकर केवल गामन-व्यवस्था ठीक कर दी गई, होती और अवध की आमदनी कम्पनी की जेब में न रखी जाती।

<sup>१</sup> स्मॉर्निन, अवध, जि० १, भूमिका, पृ० २१-२२।

<sup>२</sup> वही, जि० २, पृ० ३७९।

<sup>३</sup> लारेंस डलहौजी, पृ० ३२३।

इस चाल के चलने का काम नये रेजीडेंट आउट्रम को सौंपा गया। चुपके चुपके सब सैनिक प्रवन्ध कर लिया गया, हनुमान गढ़ी के उपद्रव को शान्त करने के ब्रह्माने सेना एकत्र कर ली गई और अधिकार मिल जाने पर कौन कौन अफसर कहाँ रहेगा, यह सब भी तय कर लिया गया। इतन ही में इंग्लैंड से भी जैसा उचित जान पड़े वैसा करने के लिए मजूरी आ गई। अब किसी प्रकार की बाधा न रही। फरवरी सन् १८५६ में, सैनिक बल प्रयोग करने की धमकी देने पर भी वाजिदअली शाह ने अपमानजनक सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस पर एक घोषणा द्वारा अवध औरंगजेबी राज्य में मिला लिया गया और वाजिदअली शाह को पेंशन दे दी गई। थोड़े दिनों बाद वह कलकत्ता भेज दिया गया। इस तरह अवध औरंगजेबी के हाथ में आ गया। लार्ड डलहौजी अपनी डायरी में लिखता है कि अवध के ऐसे शासन को, जिसमें करोड़ों आदमियों को पीड़ा पहुँच रही थी, कुछ काल अधिक बनाये रखने में सहायता देने में ईश्वर और मनुष्य की दृष्टि में ब्रिटिश सरकार दोषी ठहराई जाती। इस भाव को हृदय में लेकर और परम शक्तिशाली ईश्वर की अनुकम्पा पर विश्वास रखकर मैंने इस कर्तव्य को, बड़े सोच-विचार तथा सहानुभूति, परन्तु शान्ति और बिना किसी सन्देह के साथ किया।<sup>१</sup>

**नवाबी शासन—**शुजाउल्ला के समय में देश की जैसी कुछ दशा थी, दिखलाई जा चुकी है। आसफुद्दौला के समय से औरंगजेबी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, वैसे ही दशा भी बिगड़ने लगी। सन् १७८४ में इसको वारेन हेस्टिंग्स ने भी माना है। सादतअली के समय में दशा फिर कुछ सुधरी। सन् १८१८ में लार्ड हेस्टिंग्स गाजीउद्दीन को विश्वास दिलाता है कि खेती की अच्छी दशा, जनसंख्या की वृद्धि और प्रजा का “सुख तथा आराम” देखकर बड़ा सन्तोष हो रहा है। सन् १८२४ में हेबर लिखता है कि अवध की आबादी और खेती की अच्छी दशा देखकर

आश्चर्य हो रहा था।<sup>१</sup> मन् १८३६ में आकलेड मुहम्मदअली गाह को लिखता है कि “जब से आप गद्दी पर बैठे हैं, पिछली दशा को देखते हुए राज्य में बहुत कुछ सुधार हुआ है।” सर हेनरी लारेस का कहना है कि अवध के शासकों से जैसी कुछ आशा थी, उससे वे कहीं अच्छे थे। वे कभी कभी क्रूर अवश्य पर झूठे कभी नहीं हुए।

‘हुजूर तहसील’ को छोड़कर अवध का राज्य बहुत से इलाकों और चकलों में बँटा हुआ था। यहाँ के तालुकेदार और जमीन्दार बहुत कुछ स्वतंत्र थे। वे प्रायः आपस में लड़ा करते थे और सब तरह से अपनी रियायतें बढ़ाने का प्रयत्न किया करते थे। उनमें सरकारी मालगुजारी वसूल करना मुश्किल हो जाता था। परन्तु प्रजा के साथ इनमें से बहुतों का व्यवहार अच्छा था। इसको स्लीमैन ने भी माना है। गाहगज के विषय में वह लिखता है कि यहाँ “काश्तकार धनी तथा मनुष्य है।” उनको कभी धोखा नहीं दिया जाता है। चोर, डाकू, उठंड पड़ोसी और सबसे अधिक ‘गाही फौज’ से उनकी रक्षा की जाती है। गावों में अच्छे अच्छे किसानों को बसाने का प्रयत्न किया जाता है। हर एक गाव में झोपड़े के सामने फुलवाड़ी है। देश एक “हरा-भरा बगीचा” सा जान पड़ता है। सरहद्दी ऋगड पटवारी और कानूनगो की महायता से पचायतो द्वारा नियंता लिये जाते हैं। छोटे बड़े सभी किसानों को जो वचन दिया जाता है, उसका जमीन्दार पालन करते हैं और किसान भी अपना लगान बराबर देने हैं। दुर्भिक्ष या किमी आपत्ति के समय में उनके साथ स्वामि रियायत की जाती है।<sup>२</sup> इस तरह नवाबी शासन ठीक न हान पर भी अवध के कई भागों में प्रजा का पालन होता था।

मन् १८३१ में यात्रा करनेवाली एक महिला लिखती है कि अवध की प्रजा ब्रिटिश शासन के सुख में भाग लेने के लिए किसी तरह राजी नहीं है। अपनी व राज्य में रहनेवालों से अवध-निवासी कहीं अधिक धनी, मोटे और

<sup>१</sup> हवर, जर्नल, जि० २, पृ० ४९।

<sup>२</sup> स्लीमैन, अवध, जि० १, पृ० १५०-६८।

प्रसन्नचित्त हैं।<sup>१</sup> स्लीमैन लिखता है कि सन् १८०१ में अवध का जो भाग ले लिया गया था, उसमें जमीन्दार और रईमों की श्रेणी नष्ट कर दी गई थी। उनकी आमदनी का बहुत सा हिस्सा हर नये बन्दोबस्त में ले लिया जाता था। अत्याचार, मारपीट और लडाई-झगड़े होने पर भी अवधनिवासी अंगरेजी जिले में रहना पसन्द न करते थे। हमारी अदालतों के कानून-कायदे, न्याय करनेवालों के “घमंड और बेपरवाही” तथा वकीलों के “लालच और गुस्ताखी” से वे बहुत डरते थे।<sup>२</sup> एडवर्ड्स लिखता है कि “जब हमने अवध लिया वह धनी, आबाद और व्यापारी देश था। इन बातों में हमारे साम्राज्य के बहुत से भागों से उसकी अच्छी तरह तुलना की जा सकती थी।”<sup>३</sup>

यदि अवध में जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित न होने तथा ग्रामों के अत्याचार के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसमें अधिकांश सत्य भी हो, तो उसके लिए अंगरेज ही अधिक जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। सेना उनके हाथ में थी, वे शासन की हर एक बात में हस्तक्षेप करते थे। देश-रक्षा की जिम्मेदारी से अलग होकर भोग-विलास में समय बिताना नवाबों के लिए स्वाभाविक था। यदि वे कभी सुधार की चेष्टा भी करते थे, तो उसमें भी अड़चनें डाली जाती थीं। हेनरी लारस की राय में जैसी कुछ व्यवस्था थी उसमें कोई वजीर अपने स्वामी और रेजीडेंट को एक साथ प्रसन्न न रख सकता था और ऐसे रेजीडेंट का मिलना मुश्किल था, जो केवल “प्रजा और राजा के हित” का ध्यान रखकर निरर्थक हस्तक्षेप से अपने को अलग रखता। इसी लिए शासन में बड़ी बाधाएँ पड़ती थी।

**मुग़ल बादशाह**—लार्ड डलहौजी की राय में नाम मात्र के नवाब और राजाओं को रखने की कोई आवश्यकता न थी। सब शक्ति छीनकर बड़े बड़े नाम देना उनकी हँसी उड़ाना था। इनमें सबसे मुख्य दिल्ली का

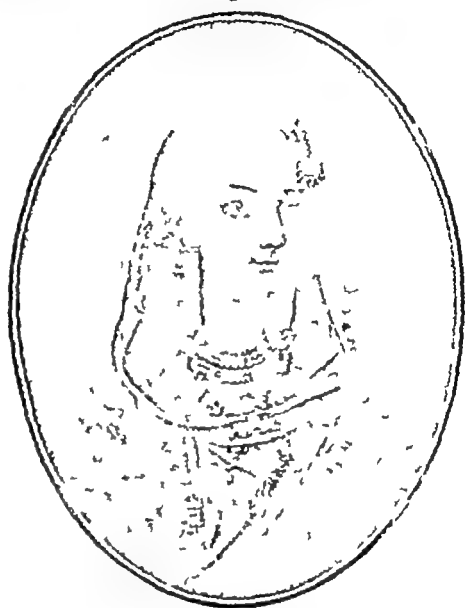
१ मिमेज फेन पाक, वाटरिंगम आफ ए पिलग्रिम।

२ स्लीमैन, अवध, नि० १, पृ० १६८-६९।

३ एडवर्ड्स, हेनरी लारस, नि० २, पृ० २८०।

बादशाह था। लार्ड डलहौजी बहादुरशाह के मरने के बाद में तमूर के घराने में मन्नाट् की उपाधि को हटा देना चाहता था। परन्तु उसी समय ब्रान को मन्नालको ने स्वीकार नहीं किया।

बहादुरशाह अपनी छोटी बेगम जीनतमहल के लडके को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। परन्तु डलहौजी ने एक बड़े लटके को उत्तराधिकारी मान लिया और समय यह वादा करा लिया कि बहादुरशाह के मरने पर दिल्ली का महल खाली कर दिया जायगा। रसल लिखता है कि गाँधी घराने के लोग नजरबन्द रखे जा रहे थे। न उनकी पूरी आर्थिक सहायता की जाती थी और न उन्हें सरकारी नोकरीया हा दी जाती थीं। उनक लिए “उचिन महत्त्वाकांक्षा” का दर्वाजा बन्द था। ऐसी रूढ़ि में जब उनका समय “आलस्य, नीचता तथा भोग-विलास” में व्यतीत होता था, तब उनकी निन्दा की जाती थी और यह दिखालाया जाना जाता कि वे कितन पतित हैं।



जीनतमहल

अन्य नवाब और राजा—कर्नाटक के नवाब का राज्य पहले ही हान लिया गया था। सन् १८५५ में मुहम्मदगास के मरने पर उसके उत्तराधिकारी को नवाब की उपाधि नहीं दी गई और पेशन भी हटा दी गई। कहा गया कि सन् १८०९ की सन्धि तत्कालीन नवाब के साथ व्यक्तिगत बनिय था। हममें उसके उत्तराधिकारियों का कोई उल्लेख न था। यदि ऐसा था तो हमें बाद में और नवाब क्यों मान गये? इसके उत्तर में कहा

गया कि तब बात दूसरी थी, अब उस नीति में काम लेने की आवश्यकता न थी।<sup>१</sup> इन दिनों नवाब के वंशज 'अर्काट के शाहजादे' कहलाते हैं। सन् १८५५ में तंजोर के राजा शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके केवल दो लड़कियाँ थीं। उसका कोई चारिम न माना गया, पेंशन बन्द कर दी गई और कुटुम्ब के गुजारा का प्रबन्ध कर दिया गया। रानियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उनकी निजी सम्पत्ति भी छीन ली गई, परन्तु यह डलहौजी के चले जाने के बाद की बात है। तंजोर के राजाओं ने हस्तलिखित ग्रन्थों का अच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर में अब भी मौजूद है। सन् १८५१ में पेंशनवाजीराव के मरने पर, उसको ८ लाख रुपये साल की जो पेंशन दी जाती थी, बन्द कर दी गई और नाना साहब को, जिसे उसने गोद लिया था, केवल बिठूर की जागीर दी गई। कहा गया कि पेंशन व्यक्तिगत थी, इसके अतिरिक्त बाजीराव बहुत सा धन छोड़ गया है। नाना साहब ने एक प्रार्थनापत्र इंग्लैंड भेजा, जिसमें उसने दिखलाया कि यह पेंशन राज्य छीनने के बदले में दी गई थी। धन एकत्र हो जाने से पेंशन का हक नहीं मारा जाता। पर वहाँ से भी कोरा जवाब मिला।

**काबुल और क़िलात**—पश्चिमोत्तर सीमा की रक्षा करने के लिए अफगानिस्तान के अमीर दोस्तमुहम्मद से मित्रता की सन्धि कर ली गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के राज्य में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। विलोचिस्तान की तरफ से किसी के आक्रमण का भय न रहे, इसलिए क़िलात के 'खान' से भी सन्धि की गई। इस सन्धि से अंगरेजों को विलोचिस्तान में सेना रखने और व्यापार करने के अधिकार मिल गये। उस तरफ लूट-पाट में रक्षा करने के लिए क़िलात के 'खान' और उसके उत्तराधिकारियों का १० हजार रुपये साल की सहायता देने का भी वचन दिया गया।

**शासनप्रबन्ध**—डलहौजी के समय में भारतवर्ष का बहुत सा भाग अंगरेजी राज्य में मिल गया, इसलिए अब शासनप्रबन्ध में कुछ परिवर्तन

करना आवश्यक हो गया। इस समय तक बंगाल का गायन गवर्नर-जनरल के हाथ ही में था, परन्तु उसका काम अधिक बढ़ जान के कारण सन् १८५३ में बंगाल प्रान्त के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट-गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। पंजाब, बर्मा, अवध और नागपुर ब्रिलकुल स्वतंत्र प्रान्त नहीं बनाये गये। इनमें चीफ कमिश्नर रख दिये गये जो गवर्नर-जनरल के अधीन थे। ये प्रान्त हाल ही में लिये गये थे। इनको शान्त रखने के लिए ऐसे गायन की आवश्यकता थी, जिसमें प्रचलित रीति-रिवाजों में बहुत परिवर्तन भी न हो। और सरकार का काम भी शीघ्रता और सुगमता से निपटना जाय। इसी लिए यहाँ बंगाल के सब कानून-कायदे नहीं चलाये गये। जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में, जो 'डिप्युटी कमिश्नर' कहलाने लगे, न्याय, पुलिस और माल के सब अधिकार दे दिये गये।

बंगाल की अपेक्षा नये प्रान्तों में सेना का रखना अधिक आवश्यक समझा गया। उत्तरी भारत में मेरठ में सेना की मुख्य छावनी बनाई गई। पंजाब में एक अलग सेना रखी गई और गोरखों की भी कई एक पलटने बनाई गई। इस समय उत्तरी भारत में अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता थी, इसलिए शिमला में भारत-सरकार के रहने का प्रयत्न किया गया।

**रेल**—सन् १८४१ में ही भारतवर्ष में रेल चलाने का विचार हो रहा था। अब साम्राज्य का विस्तार हो जाने में, एक स्थान में दूसरे स्थान में सेना गात्र ले जाने के लिए, रेलों की बड़ी आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी। सरकार इसके लिए धन लगाने को तैयार न थी। टलहोजी ने घाटा पूरा करने का वचन देकर भारतवर्ष में रेल चलाने के लिए अंगरेजी कम्पनियों को राजी किया। सन् १८५३ में बम्बई के निकट, 'ग्रेट इंडियन पेनिशुलर' (जी० आई० पी०) रेलवे कम्पनी ने पहले-पहल रेल चलाई। इसी की गामाँ खानदेश और नागपुर की तरफ बढ़ाई गई। 'ईस्ट इंडियन रेलवे' (ई० आई० थार०) कम्पनी ने पहले कलकत्ता से रानीगंज तक रेल चलाई। फिर कलकत्ता से इलाहाबाद होते हुए दिल्ली तक इसी कम्पनी की रेल चल गई। इस तरह लार्ड डलहोजी के समय में ही 'मदराम रेलवे' (एम०

आर० ) और 'बम्बई बडोदा मेटल इंडिया' ( बी० बी० मी० आई० ) रेलवे कम्पनियों भी स्थापित हो गईं ।

सेना की सुविधा के अतिरिक्त रेलों के चलाने में डलहौजी को इंग्लैंड के व्यापार का भी ध्यान था । वह लिखता है कि इंग्लैंड को रुई की बड़ी आवश्यकता है । भारतवर्ष में यह अच्छे किम्म की और सूख पैदा होती है । यदि समुद्र के बन्दरगाहों तक इसके पहुँचाने का प्रबन्ध किया जा सके, तो इंग्लैंड की यह आवश्यकता दूर हो सकती है । साथ ही साथ यह भी ग्याल था कि रेलों से भारतवर्ष के दूर दूर के स्थानों में यूरोप की बनी हुई चीजों की खपत बढ़ जायगी ।<sup>१</sup> इस तरह सैनिक सुविधा और इंग्लैंड की व्यापारिक उन्नति की दृष्टि से भारतवर्ष में पहले-पहल रेलें चलाई गईं ।

**तार—**इसी उद्देश्य से तारों का भी प्रबन्ध किया गया । सन् १८५० में कलकत्ता के निकट पहला तार लगाया गया । भारतवर्ष में तार लगाना सहज काम न था । बड़े बिकट जंगल, नदी, नाले और पहाड़ों के होने से तार के खम्भों के गाड़ने में बड़ी मुश्किलें पड़ती थी । बन्दर तार तोड़ डालते थे और जंगली जानवर खम्भों को गिरा देते थे । डलहौजी के समय में बड़े परिश्रम के साथ यह काम पूरा किया गया । सिपाहीविद्रोह के समय पर तार अंगरेजों के बड़े काम आया । क्षण भर में समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँच जाता था, सिपाही मुँह ताकते रह जाते थे । लार्ड डलहौजी ने भारतवर्ष में अंगरेजी साम्राज्य को "लोहे की पटरियों और तारों से जकड़" दिया । हटर लिखता है कि सन् १८५७ के विद्रोह में रेल और तार हजारों आदमियों के बराबर थे । रेल और तारों ही द्वारा भारतवर्ष अब भी सैनिक रीति से हाथ में है ।

**डाक—**डलहौजी के पहले डाक का कोई ठीक प्रबन्ध न था । स्थान की दूरी और पत्र के वजन के हिसाब से महसूल लिया जाता था । पत्र देने पर डाकिया महसूल वसूल करता था, जिसमें बड़े झगड़े होते थे । गाँवों में तो पत्र



कभी पहुँचते ही न थे। लार्ड डलहौजी ने जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया और सन् १८५३ में आधे तोले के वजन का आधा आना महसूल नारे भारतवर्ष के लिए निश्चित कर दिया। महसूल वसूल करने के आगटे न घटने के लिए टिकटें चला दी गई। लार्ड डलहौजी के समय में ही साठे सात में के लगभग डाकखाने खोले गये। रेल, तार और डाक से आगे चलकर जनता को भी बहुत लाभ हुआ। समय तथा दूरी की कठिनाइया जाती रहीं और भारत धीरे धीरे एकता की ओर बढ़ने लगा।

**नहर और सड़के**—गंगा की नहर, जो बहुत दिनों से खुद रही थी, लार्ड डलहौजी के समय में पूरी हो गई। उसमें उत्तरी भारत में गिँचाई के लिए सुविधा हो गई। पंजाब में भी बारी दोआब नहर से बहुत लाभ हुआ। दक्षिण में गोदावरी के पानी से भी खेती को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया गया। कई एक नदरें बनवाई गई और ऐसे कार्यों की देख-भाल के लिए 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' कायम किया गया।

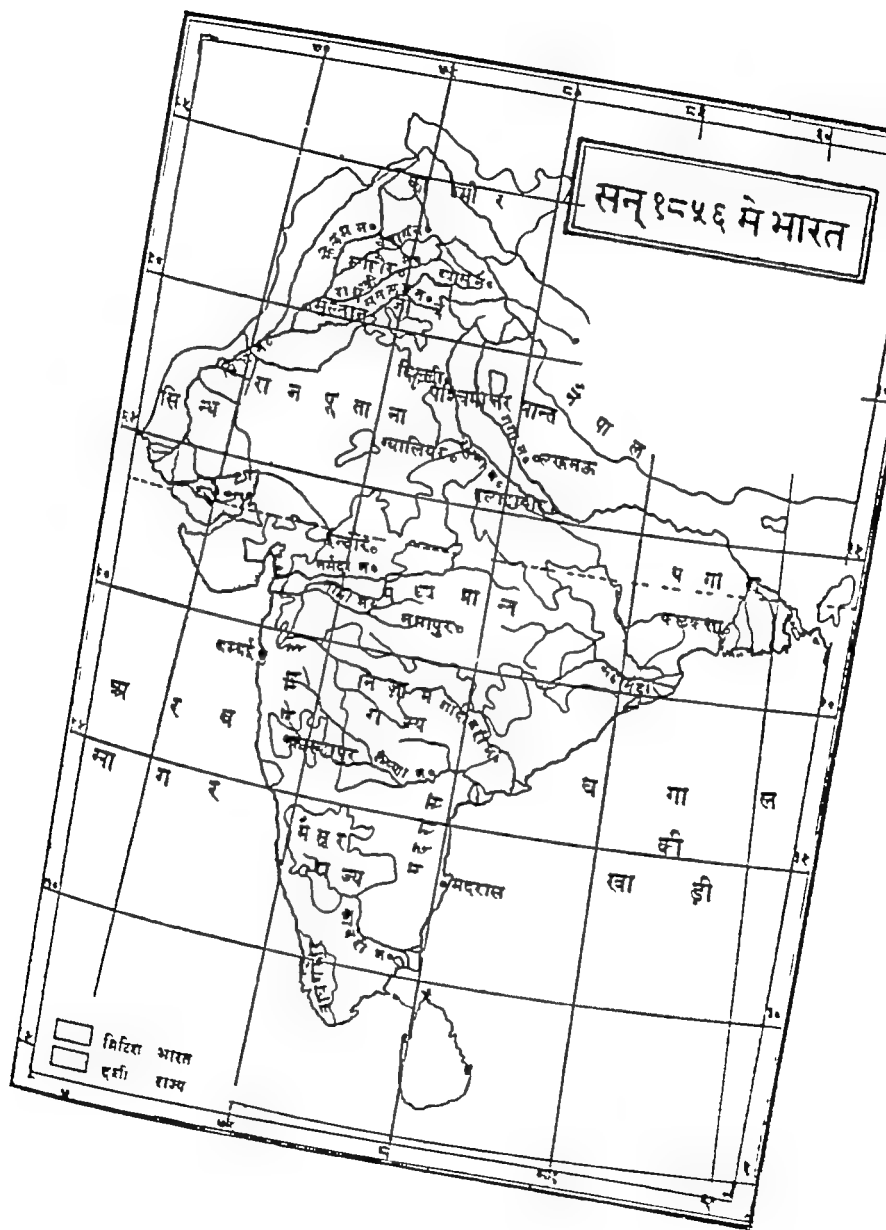
**शिक्षा और व्यापार**—नर चार्ल्स वुड की सलाह से अंग देशी भाषाओं पर अधिक जोर दिया जाने लगा। गाँवों की पाठशालाओं और मदतियों को सरकारी सहायता देने और उनके निरीक्षण करने का प्रयत्न किया गया। बड़े बड़े गाँवों में प्रारम्भिक स्कूल और जिलों में हाई स्कूल खोले गये। तीनों प्रान्तों में इजीनियरिंग की पढाई का भी कुछ प्रयत्न किया गया। लार्ड डलहौजी के समय में भारत में श्रंगरेजों का व्यापार भी बहुत बढ़ गया। सन् १८४८ में देश से जितनी रई बाहर जाती थी, सन् १८५६ में उसमें दुगुनी से भी अधिक जाने लगी। गल्ला तिगुना जाने लगा और मृत्ती कपडा तथा अन्य विलायती चीजों का आना दुगुने से भी अधिक हो गया।<sup>१</sup> इस व्यापार की वृद्धि से भारत को लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होान लगी।

**कम्पनी का अन्तिम आज्ञापत्र**—सन् १८५३ में कम्पनी के आज्ञापत्र व सम्बन्ध में पार्लामेंट ने फिर कानून पास किया। भारत का शासन

नाम मात्र के लिए इस समय भी कम्पनी के हाथ में था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, केवल इस बार कोई श्रवधि निश्चित नहीं की गई। गवर्नर-जनरल की 'लेजिस्लेटिव कौंसिल' (व्यवस्थापक सभा) के मेम्बरो की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें बम्बई, मद्रास और पश्चिमोत्तर प्रान्त से भी एक एक मेम्बर लिया गया। इस तरह पहले-पहल इसको केवल बंगाल प्रान्त की श्रपेक्षा भारत साम्राज्य की कौंसिल बनाने का प्रयत्न किया गया। लार्ड डलहौजी इसमें एक हिन्दुस्तानी मेम्बर भी रखना चाहता था, परन्तु इंग्लैंड-सरकार ने इसको स्वीकार न किया। इस कौंसिल में पार्लामेंट की नकल की जाती थी। यह बात इंग्लैंड-सरकार को पसन्द न थी। सर चार्ल्स बुड इसको 'भारतवर्ष की पार्लामेंट' न मानता था।

**डलहौजी का चरित्र**—मार्च सन् १८५६ में डलहौजी वापस चला गया। वह बड़ा परिश्रमी गवर्नर-जनरल था। सबेरे नौ बजे से लेकर पांच बजे शाम तक बराबर दिमागी काम किया करता था। इंग्लैंड से आने पर ही उसका स्वास्थ्य बराबर था, भारतवर्ष में अधिक परिश्रम करने से वह और भी बिगड़ गया। उसके एक मित्र ने हँसी में लिखा था कि रूस के जार और डलहौजी ये ही दो स्वेच्छाचारी शामक बाकी रह गये हैं।<sup>१</sup> इसमें बहुत कुछ सत्यता थी। वह जो राय कायम कर लेता था, उसमें किसी की न सुनता था। हेनरी लारेंस और स्लीमैन ऐसे अनुभवी अफसरों की राय का भी उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता था। सेनापति चार्ल्स नेपियर से तो बराबर झगडा हुआ करता था। उसने स्वयं माना है कि वह दूसरों के साथ मिलकर काम न कर सकता था। वह प्रायः कड़ी और कभी कभी अनुचित भाषा का प्रयोग कर बैठता था। दूसरों के सम्मान और प्रतिष्ठा का उसको बहुत कम ध्यान रहता था, जिसकी वजह से, जिनका उससे मतभेद होता था, वे और भी असन्तुष्ट रहते थे। थर्नाल्ट की राय में उसने आधुनिक भारत की नींव डाल दी। हटर का मत है कि उसने साम्राज्य और देश को एक बना दिया। यह चाहे जो कुछ हो, देशी

सन् १८५६ मे भारत





नरेशों के प्रति उसकी नीति और व्यवहार की प्रशंसा नहीं की जा सकती। आगे चलकर वह नीति भारत-सरकार को छोड़नी ही पड़ी। उसके लोभोपयोगी कार्यों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से बहुतों की योजना उसके आने के पहले ही तैयार हो चुकी थी, उसने उनको पूरा अवश्य कर दिया। जिस काम को वह हाथ में लेता था, उसको करके छोड़ता था, यह हममें बड़ा भारी गुण था। लार्ड डलहौजी ने जो कुछ किया, वह अपने देश के लिए किया। हमकी सेवा में वह अपने जीवन को भी तुच्छ समझता था। जिस साम्राज्य की लार्ड क्लाइव ने नींव डाली थी, जिसको वारेन हेस्टिंग्स ने दृढ़ बनाया था, विलेजली तथा लार्ड हेस्टिंग्स के समय में जिसकी वृद्धि हुई थी, लार्ड डलहौजी ने उसको पूरा कर दिया।

जिमने सदा अंगरेजों का साथ दिया था, यह धारणा हा रही थी कि किसी राज्य का वचना सम्भव नहीं है। सबको यह भय हो रहा था कि किसी न किसी बहाने से धीरे धीरे सभी राज्य ले लिये जायेंगे। मराठों में पञ्चा का अन्त हो ही चुका था, सतारा और नागपुर लेकर शिवाजी और भागला के घराने भी नष्ट कर दिये गये थे। रणजीतसिंह का राज्य तो जड़ में हा खाद दिया गया था। मुसलमानों में मुहम्मदशली के वंश का कनाटक के नवाब कहलाने तक की अनुमति नहीं दी गई थी, निजाम के अंगरेजों से लिया गया था और अवध के राज्य का तो एक-दम में ही अन्त कर दिया गया था। दिल्ली में बृद्ध मुगल सम्राट् बहादुरशाह का अपन पूना के महलों में भी रहना मुश्किल हो गया था।

जिम डग से यह नीति काम में लाई जा रही थी उसमें अशान्ति और भी बढ़ रही थी। इन राजाओं तथा नवाबों के आभूषण, जवाहरात, तारी और घाट बाजारों में नीलाम किये जा रहे थे। रानियों और वेगम का पुरी दशा थी। सतारा, कनाटक तथा अवध और नाना साहय के दून डैंगल नष्ट हो रहे थे पर कहीं किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस तरह निराशा होकर इनमें से कुछ लोग बदला लेने का अवसर ताक रहे थे।

**सामाजिक परिवर्तन**—कई एक देशी राज्यों में नष्ट हो जाने का समाज में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा था। बहुत से बड़े बड़े आदमी बस्तर में मर रहे थे। अंगरेजों के यहाँ उनके लिए नौकरियों का दरवाजा बन्द था। अमला और सिपाहियों की तो कुछ गिनती ही न थी, इनके लिए कहीं भी टिकाना न था। नये दन्देधर्म में प्राचीन बड़े बड़े घरानों का कुछ भी ध्यान नहीं किया जा रहा था। बंगाल में ब्रिटिश के समय से ही 'लासिबराज' जायदाद जवन जा रही थी। बम्बई में सनदों की जाँच करने के लिए 'इनाम कमाशन' लगा हुआ था, जो छोटी बड़ी मिलाकर २० हजार जायदादों और जागीरों का बँटव कर चुका था। अवध में तालुकेदारों के साथ भी यही व्यवहार किया जा रहा था। जिन इलाकों पर इनका पुष्टों से अधिकार चला आ रहा था, वे भी नन्द या आग कोई ऐसा ही सवृत न होने के कारण, छीन जा रहे थे।

दीवानी अदालतों की डिक्रियो से जायदादे नीलाम हो रही थीं और जमीन्दार तबाह हो रहे थे।

अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों का सामाजिक सम्बन्ध टूट रहा था, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। अंगरेज हिन्दुस्तानियों को असभ्य और हिन्दुस्तानी अंगरेजों को अपने धर्म का विरोधी समझ रहे थे। दोनों की बहुत सी बातें एक दूसरे की समझ में न आ रही थीं और न उनके समझने का कोई प्रयत्न ही किया जा रहा था। शिवा से यह भेदभाव दूर नहीं हो रहा था। अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग हर एक बात में अंगरेजों की नकल कर रहे थे और अपने देश की सभी बातों को तिस्कार की दृष्टि से देखते थे। बहुत से बेपड़े हिन्दुस्तानी रेल और तार को 'जादू' समझे बैठे थे और उनसे भय करते थे। पाश्चात्य सभ्यता की बहुत सी बातों के आ जाने से भारतवर्ष के सामाजिक जीवन में, जो सहस्रों वर्ष से एक ही ढंग से चला आ रहा था, बड़ा उथल-पुथल मच रहा था।

**धार्मिक उत्तेजना**—भारतवर्ष में हर एक बात का सम्बन्ध धर्म से है। अंगरेज जिनको सामाजिक परिवर्तन समझ रहे थे, हिन्दुस्तानी उनको अपने धर्म पर आघात मान रहे थे। सती-प्रथा का बन्द करना धर्म में हस्तक्षेप समझा जा रहा था। विधवा-विवाह को जायज मानने के लिए हाल ही में एक कानून पास हुआ था। बहु-स्त्री-विवाह को रोकने के लिए भी कानून बनाने पर विचार हो रहा था। इस समय तक धर्म-परिवर्तन करने से पैतृक सम्पत्ति में हक मारा जाता था, अब यह नियम भी उड़ा दिया गया था। ये सब बातें जन-साधारण को खटक रही थीं। इनके अतिरिक्त सबसे भारी बात तो यह थी कि इन दिनों ईसाई मत के प्रचार पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। लार्ड पामरस्टन तक भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों को "उच्च और श्रेष्ठ" मत में लाने का स्वप्न देख रहा था। सरकारी स्कूलों में बाइबिल की शिक्षा अनिवार्य करने के लिए आन्दोलन हो रहा था। पादरी लोग हिन्दू और मुसलमान धर्मों की हँसी उड़ा रहे थे। वारिकपुर के मैट्रिक अफसर खुले तौर पर सिपाहियों को ईसाई मत का उपदेश दे रहे थे। सरकार की ओर से इनको रोकने की कोई चेष्टा नहीं की जा

८५ नेता गिरफ्तार कर लिये गये और उनको दस दस वर्ष की कड़ी कैद की सजा दी गई। ता० ६ को परेड पर उनकी बर्दिया छीनकर उन्हें सब तरह से अपमानित किया गया। अपने अपमानित साथियों के ललकारने पर सब सिपाही बिगड पडे। जो अंगरेज जहाँ मिल गया, वही मार डाला गया, छावनी में आग लगा दी गई, जेल का फाटक तोडकर कैदी निकाल लिये गये और सबके मंत्र दिल्ली की ओर बढ़ चले।

विद्रोह की आग भभक उठी। दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक मुख्य मुख्य स्थानों पर सिपाही बिगड पडे। अंगरेजों से जो असन्तुष्ट हो रहे थे, उनको बदला लेने का अच्छा अवसर मिल गया और उनमें से कुछ लोग सिपाहियों के साथ हो गये। इस तरह एक नैतिक विद्रोह को राजनैतिक स्वरूप मिल गया।

**दिल्ली**—मेरठ में विद्रोही सिपाही दूसरे ही दिन दिल्ली पहुँच गये। यहाँ गोरों की कोई सेना न थी और शहर सिपाहियों के हाथ में था। ये मंत्र विद्रोहियों में मिल गये, अंगरेज अफसर मार डाले गये और बृद्ध बहादुरशाह को फिर से तख्त पर बिठलाकर मुगल साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। बहादुरशाह के महल को विद्रोहियों ने चारों ओर से घेर लिया था, उनका खाना देने के सिवा उमके लिए अपनी रक्षा का कोई दूसरा उपाय न था। राज्यों के व्यवहार में उमके कुटुम्बी पहले ही से असन्तुष्ट थे। फारम की प्रारम्भ में उनको भटकाने का बराबर प्रयत्न हो रहा था। बहादुरशाह के विरोध करने भी सिपाहियों ने क्रोध में आकर कई एक अंगरेजों को उनके घर में भेजा कि अहित मार डाला। दिल्ली में एक बड़ा भारी बारूदगाना जाति पानि के ज़िम्मे सिपाही लेना चाहते थे। पर कुछ साहसी अंगरेज गन्ध भारी अपने जीवन की कुछ भी पर्वाह न करके उसमें आग लगा दी, जिसमें बहादुरशाह जल-भुनकर मर गये। दिल्ली छिन जाने से अंगरेजों के बाँत पर बड़ा धक्का लगा और सारे पश्चिमोत्तर प्रान्त में उपद्रव मच गया। यह समाचार पंजाब पहुँचने पर सर जान लार्से ने लाहौर के सिपाहियों को तैयार छीन लिये और बड़ी सक्ती के साथ वहाँ के उपद्रवियों को दंड दिया।



अमृतसर के डिप्युटी कमिश्नर कूपर ने, एक अंगरेज़ अफसर को मार डालने के अपराध में, पैदल सेना की २६ वीं पल्टन के २८२ सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से २३७ सिपाही बिना किसी अभियोग के गोली से मार दिये गये। बच करते करते एक गोली चलानेवाला बेहोश हो गया। बाकी ४५, जो एक कोठरी में बन्द थे, भय, अम और दम बुटने के कारण आपसी मार मार गये। इस तरह सो वर्ष बाद कलकत्ते की काल कोठरी का बदला चुक गया। इन सबकी लाशें उजनाला के एक अन्धे कुएँ में झोंक दी गईं।<sup>१</sup> इस पल्टन के बचे-खुचे सिपाही लाहोर में तोपदम कर दिये गये। मार्टिन लिखता है कि दो अंगरेजों के बच के अपराध में पाँच सौ आदमियों के प्राण लेना ऐसा बदला है, जिसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता।<sup>२</sup> जान लारेंस ने इस तरह पंजाब को शान्त करके गोरों की सेना को निकल्मन की अव्यवस्था में दिल्ली भेजा।

इसके पहले पंजाब और मेरठ की कुछ सेना जून में बदलीसराय के युद्ध में विद्रोहियों को हरा चुकी थी और दिल्ली को घेरे हुए पड़ी थी। निकल्मन की सेना आ जाने पर अच्छी तरह से युद्ध छिड़ गया। मितम्बर में पंजाब से तोपें भी आ गईं और शहर का काश्मीरी ढवाँजा उड़ा दिया गया। चार पाँच दिन तक घोर युद्ध करके अंगरेजों ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस युद्ध में लगभग १५०० गोरों मौतों का शिकार हो गये और वीर निकल्मन मारा गया। विजय के बाद 'बिजन' बोल दिया गया, शहर लूट लिया गया, निरपराध नागरिकों की भिन्न मांगों पर भी गोली से मार दिये गये, भय में कांपते हुए बुड़्डे काट डाले गये।<sup>३</sup> 'टाइम्स' पत्र के सवाददाता के शब्दों में शाहजहाँ की दिल्ली में नादिरशाह के बाद से ऐसा भीषण दृश्य देखने में न आया था। इतिहासकार मार्टिन ने मर्मस्पर्शी शब्दों में इसका वर्णन किया है।<sup>४</sup>

१ कूपर, काउन्सिलर इन दि पन्ना, पृ० १६८-७४।

२ मार्टिन, इंडियन एम्पायर, जि० २, पृ० ४२८।

३ टोम्स, इंडियन स्ट्रुटिनी, पृ० ३८१।

४ मार्टिन, इंडियन एम्पायर, जि० २, पृ० ४४५-६०।

बृद्ध बहादुरशाह न प्राणरक्षा का वचन मिलने पर अपने को अंगरेजों के हवाले कर दिया। चिढ़ोही कहीं छुड़ा न लेवे, इस भय से उसके लडके, बिना इस

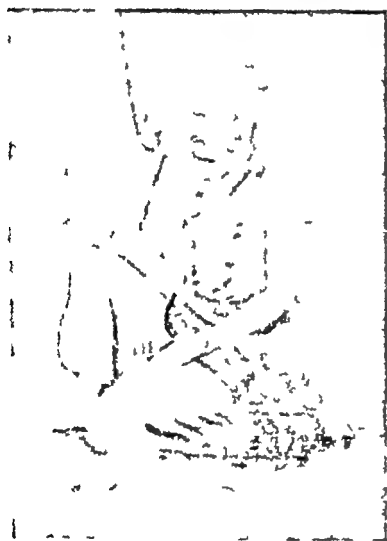


### बहादुरशाह की गिरफ्तारी

रात की जाँच किये हुए कि उनका कोई अपराध था या नहीं, गोली मार दिये गये। इतिहासकार मैलेसन का कहना है कि कोई ऐसा भय न था, इस तरह उनकी हत्या करना अनुचित था।<sup>१</sup> इतिहासकार हॉम्स का भी ऐसा ही मत है।<sup>२</sup> मुगल सम्राट् बहादुरशाह पर जनवरी सन् १८५८ में अभियाग चलाया गया। अपराधी सिद्ध होने पर वह ग़ुन भेज दिया गया, जहाँ सन् १८६२ में ८७ वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह मुगल सम्राटों का अन्त हो गया।

दिल्ली हाथ में आ जाने से अंगरेजों की फिरधाक जम गई और सब जगह उनकी विजय होने लगी। सन् १८५८ में दिल्ली पंजाब में मिला दी गई।

**कानपुर**—यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बिठूर में नाना साहब रहता था, जिसको बाजीराव ने गोद लिया था। जान के लिखना है कि वह सीधा-साधा प्रमिद्ध था और मद्रास और कम्पनी की बात मानने के लिए तैयार रहता था। बाजीराव की पेशन के सम्बन्ध में वह बराबर लिखा-पढ़ी कर रहा था, पर कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी में वह चिढ़ा हुआ था। कहा जाता है कि वह औरंगजेबों के विरुद्ध पड़ोस रच रहा था। इसी



नाना साहब

शत्रुओं का सामना किया। अन्त में नाना साहब से रत्ता का वचन मिलने पर, उन सबने हथियार डाल दिये और गंगा के मार्ग से वे इलाहाबाद जाने

उद्देश्य से बिठूर के पहले वह लखनऊ तथा दिल्ली गया था और रजवाड़ों में पत्र-व्यवहार कर रहा था। लखनऊ के मार्टिन गवियर का तो यहाँ तक कहना है कि उसके दूत ने, जो इंग्लैंड गया था, रुमियो से भी बातचीत की थी।<sup>१</sup>

जून में कानपुर के सिपाहियों ने भी बिठूर कर दिया और वे भी सबके सब दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। परन्तु नाना साहब के कहने पर वे सब कानपुर फिर लौट पड़े।<sup>२</sup> तीन सप्ताह तक औरंगजेबों ने बड़े साहस और धैर्य के साथ

<sup>१</sup> के और मैलेसन, शटेयन म्युटिनी, जि० १, पृ० ४५४।

<sup>२</sup> नात्या टोपे का कहना है कि सिपाहियों ने जबरदस्ती नाना साहब को अपने साथ ले लिया और कानपुर को तरफ लौट पड़े। के और मैलेसन, जि० २, पृ० २२४।

के लिए तैयार हो गये। नाना साहब की ओर से नावों का प्रबन्ध कर दिया गया। परन्तु जब वे अपने बाल-बच्चे और स्त्रियों सहित नावों पर बैठ गये तब घाट पर से सिपाहियों ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। नावों में आग लगा दी गई और अँगरेजों का वध किया जाने लगा। शरण में आये हुए शत्रुओं के साथ ऐसा व्यवहार सर्वथा निन्दनीय है। नाना साहब को यह समाचार मिलने पर उसने बालकों तथा स्त्रियों की रक्षा करने के लिए तुरन्त ही आज्ञा भेज दी।<sup>१</sup> बच्चे हुए अँगरेज कानपुर में रख दिये गये और नाना साहब विदूर चला गया, जहाँ बड़ी धूमधाम के साथ वह पेगवा बनाया गया।

उसने अपनी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया, उल्टे कानपुर आकर अपना अमूल्य समय नाचरंग में नष्ट कर दिया। कानपुर के हत्याकांड का समाचार मिलने पर इलाहाबाद से हैदराबाद और नील की अभ्युत्थता में गोरी सेनाएँ कानपुर की ओर चल पड़ीं। मार्ग में फतेहपुर, जो सिपाहियों के हाथ में आ गया था, विध्वंस कर दिया गया। गावों में आग लगा दी गई, जिनमें कितने ही बच्चे तथा स्त्रियाँ जलकर मर गईं और सब सम्पत्ति लूट ली गई।<sup>२</sup> नाना साहब के मित्राही अँगरेजी सेना को रोक न सका। उसके बड़न का समाचार पहुँचते ही कानपुर में घबराहट फैल गई। इस उत्तेजना के समय में दो सौ से अधिक अँगरेज स्त्रियों और बाल-बच्चों का, जा बाघीघर में रख दिये गये थे, वध कर डाला गया और उनकी लाशें एक अन्धे कुएँ में फेंक दी गई। कहा जाता है कि यह अमानुषिक कार्य नाना के दुष्ट सलाहकार अजीमुल्ला और एक मुसलमान स्त्री के कहने से किया गया था। एक भी सैनिक इस तरह की हत्या करने के लिए राजी न हुआ था। यह चाहे जो कुछ हो, इसमें सन्देह नहीं कि भारतवर्ष के नाम पर यह ध्वसा लग गया।

नाना साहब अँगरेजों का सामना न कर सका, वह छिपकर भाग निकला। इलाहाबाद में कानपुर पर अँगरेजों का फिर से अधिकार हो गया। विदूर में नाना

का और सेलेमन, इण्डियन म्यूजिकी, जि० ३, पृ० २०८।

वही, पृ० २७७-७८।

साहब का महल नष्ट कर दिया गया और सत्र सम्पत्ति लूट ली गई। उन्मत्त गोरे सिपाहियों ने भरपूर चटला लिया। सेनापति नील ने अपने कार्यों से यह दिखला दिया कि निर्दयता और कठोरता में अंगरेज भी किसी से कम नहीं हैं। उसके हाथ में जो कोई हिन्दुस्तानी सिपाही पड़ गया, उसी में उसने वेत लगा लगाकर बीबीवर का मृत्यु नाफ करवाया और अन्त में उसको फाँसी लटकवा दिया। वह न्याय लिखता है कि मैं हिन्दुस्तानियों को ऐसी कड़ो सजा देना चाहता था, जिससे उनके भावों को अधिक से अधिक आघात पहुँचे और जिसको वे सदा स्मरण रखें।<sup>१</sup>

**लाखनऊ**—अबध का राज्य लेने के लिए चाहे जो कारण रहे हों, पर जिस ढंग से वहाँ के शासन का प्रबन्ध किया गया, जान के लिखता है कि उससे, वहाँ की प्रजा में, जो सदा अंगरेजों का हित चाहती थी, असन्तोष के बीज बो दिये गये। 'छत्र मजिल' में, जो बादशाहों का खान महल था, गोरो का डेरा जम गया और साल भर तक उनके कुटुम्बियों को पेशने नहीं दी गई। शाही घराने के इस अपमान से प्रजा उनके अत्याचारों को भूलकर उनसे सहानुभूति दिखलाने लगी। जो लोग दरबार के आश्रित थे, उनकी रोजी जाती रही। जिन लोगों का महलों में पालन पोषण हुआ था, उनको रात में सड़कों पर भीख मागने की नौबत आ गई। शाही सिपाहियों को कोई पूँछनेवाला न रहा, वे अपने अपने घर जाकर अंगरेजों के अत्याचारों का वर्णन करके असन्तोष फैलाने लगे। बहुत से तालुकदारों के इलाके छीन लिये गये और उनकी स्थिति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। जिन कारीगरों का दरबार से गुजर होता था, उनका रोजगार नष्ट हो गया। व्यापार की सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया गया और किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया। बहुत सी इमारतें तह दी गईं और रईमों को अपमानित किया गया। इस तरह सभी श्रेणी के लोगों को असन्तुष्ट कर दिया गया।

<sup>१</sup> के और मलेसन, इण्डियन स्टुडिनी, जि० २, पृ० २०८-३००।

इस दशा को सुधारने के लिए सर हेनरी लारेमन, जिमसे लार्ड कैनिंग न अवध का चीफ कमिश्नर बनाकर भेजा था, बहुत कुछ प्रयत्न किया। परन्तु अब अगान्ति पूर्ण रूप से फेल चुकी थी और उसका



### लखनऊ की रेजीडेंसी

बदला सहज न था। यहाँ भी कारतूत का भगडा चल रहा था। मेरठ में विद्रोह होने के साथ ही साथ लखनऊ में भी उपद्रव मच गया। हेनरी लारेमन विद्रोहियों को शान्त करने में सफल न हुआ। कई एक अंगरेज अफसर मार डाले गये और वाजिदअली का एक दस वर्ष का लटका नवाब दजीर बना दिया गया। रेजीडेंसी का विद्रोहियों ने घेर लिया। मुट्ठी भर अंगरेजों ने घटे साहस के साथ विद्रोहियों का बहुत दिनों तक सामना किया। इसी बीच में एक गोला गिरन से सर हेनरी लारेमन की मृत्यु हो गई। वह बड़ा उदार-दय, दयानु और योग्य अफसर था। डलहाजी की नीति उसको पसन्द न थी। सभी राज्यों की रक्षा के लिए उसने बराबर प्रयत्न किया था।

लखनऊ के विद्रोह का समाचार फैलते ही अवध के सभी जिलों में ऊधम मच गया। पहले तो तालुकदार लोग चुप रहे, पर जब लार्ड कैनिंग ने उनके इलाकों को जब्त करने की घोषणा कर दी, तब उनमें से बहुतों ने सिपाहियों का साथ दिया। विद्रोहियों का सबसे अधिक जोर लखनऊ में था। कई बाग श्रींगरेजों ने इसको लेने के लिए प्रयत्न किया, पर कामयाबी न हुई। नील तथा और कई एक सैनिक अफसर मारे गये। बड़ी मुश्किल में मार्च मन् १८५८ में सेनापति लार्ड क्लाइड ने लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया। कैम्बर बाग लूट लिया गया और कई दिनों तक बराबर मारकाट जारी रही।<sup>१</sup> जो 'काला आदमी' हाथ में पड़ गया, वही गोली में मार दिया गया, या किसी पेड़ में फाँसी लटका दिया गया।<sup>२</sup> अवध के विद्रोह को शान्त करने में श्रींगरेजों को, नेपाल के राणा जगबहादुर की अध्वर्यता में, गोरखों से बड़ी सहायता मिली।

**बरेली**—रहेलखंड में विद्रोह का प्रारम्भ बरेली से हुआ। मई मन् १८५७ के अन्त में यहाँ के सिपाही विगड पड़े और मुसलमान जनता उनके साथ हो गई। हाफिज रहमतखा का पोता नवाब नाजिम बना दिया गया जो साल भर तक बरेली पर अधिकार जमाये रहा। मुसलमानों ने इसको धर्म-युद्ध मान लिया और कटने मरने के लिए 'गाजियो' का एक दल बन गया, जो बड़ी वीरता से लड़ा। रहेलखंड में अहमदुल्ला नामक फैजाबाद के एक मौलवी ने बहुत जोर बाँधा। लखनऊ में भी उसी ने ऊधम मचाया था। वह कट्टर मुसलमान था और उसके घमंड का कोई ठिकाना न था। पर साथ ही साथ सिटन के शब्दों में "वह बड़ा योग्य, साहसी और दृढ़ विचार का मनुष्य था, विद्रोहियों में वह सबसे अच्छा सैनिक था।" उसने शाहजहाँपुर में दो बार सेनापति कैम्पबेल को हराया। पुथार्वा के राजा ने उसे मरवा डाला। मैलेसन लिखता है कि

<sup>१</sup> रमल, टायरा, जि० १, पृ० ३३१।

<sup>२</sup> मनेटी, अप अमग दि पंडीन, पृ० १९५-९६।

“वह सच्चा देशभक्त था। निरपराधियों के बंध में उसने अपनी तलवार को क्लकित न किया था और न कभी उसने किसी ऐसे बंध का समर्थन ही किया था। उन विद्रोहियों के साथ, जिन्होंने उसके देश पर अधिकार कर लिया था, वह वीरता, सम्मान और दृढ़ता के साथ मैदान में लड़ा था। उसकी स्मृति सभी जातियों के बीच तथा सच्चे हृदयवालों के लिए प्रादुर्णीय है।”<sup>१</sup> बरेली पर मई सन् १८५८ में ही अंगरेजों का अधिकार हो गया था। मौलवी के मरते मरते रहेलखंड के अन्य स्थान भी अंगरेजों के हाथ में आ गये।

**विहार—**विद्रोह का समाचार मिलने पर पटना में धर-पकड़ शुरू कर दी गई। मेजर होम्स ने अपनी आज्ञा से सिंगौली के आस पास जंगी कानून जारी कर दिया। केवल सन्देश के कारण कुछ आदमियों को फांसी दे दी गई और बहुत से जेल में ठूस दिए गये। इन बातों से विहार में भी बड़ा असन्तोष फैल गया और दीनापुर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जगदीशपुर का ८० वर्ष का बूढ़ा जमीन्दार कुंवरसिंह उनका नेता बन गया। मालगुजारी के सम्बन्ध में उसके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी। विद्रोहियों का साथ देने के लिए पहले वह तैयार न था। परन्तु पटना के कमिश्नर का उस पर भी सन्देश हुआ, तब उस वीर राजपूत ने फांसी पर लटकने की प्रेरणा युक्त सं प्राण देना ही उचित समझा।<sup>२</sup> विद्रोहियों के साथ उसने आग का घेर लिया। परन्तु इलाहाबाद से एक अंगरेजी सेना के आ जाने पर उसका हटना पड़ा। जगदीशपुर की इमारतें नष्ट कर डाली गईं।<sup>३</sup> कुंवरसिंह का बनवाया हुआ मन्दिर भी न छोटा गया।<sup>४</sup> विहार में निरन्तर उसने आजमगढ़ के निकट अंगरेजों के एक ठल की अच्छी व्यव



ली। परन्तु जब अँगरेजों की अधिक सेना आ गई, तब वह बिहार लौट आया। यहाँ उसने अँगरेजों के एक दल को हरा दिया और जगदीशपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। इसके बाद ही युद्ध में आहत होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अँगरेज इतिहासकारों ने भी उसकी वीरता की प्रशंसा की है।

**भाँसी**—मध्य भारत और बुंदेलखंड को शान्त करने में अँगरेजों को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। जून सन् १८५७ में भाँसी के सिपाहियों ने बिगड़कर कई एक अँगरेजों को मार डाला और राजा गंगाधरराव की विधवा लक्ष्मीबाई को भाँसी की गद्दी पर बिठला दिया। अँगरेजों की हत्या से उसका कोई सम्बन्ध था, यह सिद्ध नहीं होता।<sup>१</sup> उसके साथ बहुत कुछ अनुचित व्यवहार होने पर भी, वह बिद्रोहियों में शामिल न होना चाहती थी। सिपाहियों के दबाव के कारण उसे उनकी बात माननी पड़ी। नौ महीने तक वह भाँसी का शासन बड़ी चतुरता से करती रही। मार्च सन् १८५८ में सर ह्यूरोज़ ने भाँसी पर आक्रमण कर दिया। रानी बड़ी वीरता से लड़ी, पर अन्त में उसको किला छोड़ना पड़ा। उसके हटते ही भाँसी में भयानक 'बिजन' बोल दिया गया। कहा जाता है कि इस अवसर पर पाँच हजार आदमियों का वध किया गया।<sup>२</sup> बिना किसी अपराध के, केवल लूट के लालच से, अमृतराव की जागीर किरवी, जिसकी गद्दी पर एक नौ वर्ष का बालक था, छीन ली गई।<sup>३</sup>

रानी लक्ष्मीबाई ने भाँसी से निकलकर तात्या टोपे के साथ, जो उसकी सहायता के लिए आ रहा था, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। महाराज जयाजी राव निन्धिया की सेना बिगड़ गई और वह भागकर आगरा चला

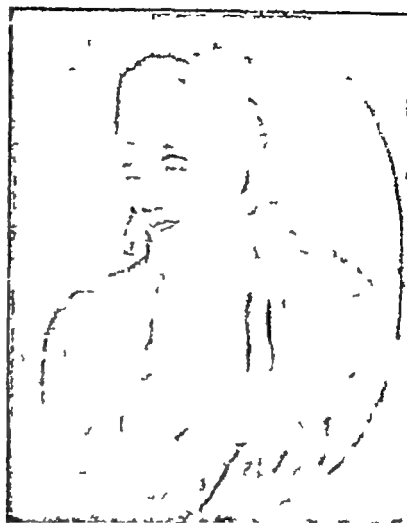
१ होम्स, इंडियन म्युटिनी, पृ० ४९३। महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, भाग १४, पृ० १७।

२ मार्टिन, इंडियन एम्पायर, जि० २, पृ० ४८५।

३ के और मैलेसन, जि० ५, पृ० १८१।

गया। ग्वालियर का शासन रावसाहब को दिया गया, जो भोग-विलास में पड़ गया। कालपी जीतकर जून में छारोज ग्वालियर पहुँच गया।

रानी ने मरठाना भेष धारण करके फिर उसका सामना किया। दिन भर घोर युद्ध के बाद विजय की आशा न देखकर उसने मैदान छोड़ दिया। एक नाले के पास उसका घोड़ा रुक गया। कई एक गोरे आ पहुँचे, उसने अकेले ही उनका मुकाबला किया। अन्त में वह घायल होकर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। सेनापति सर एड्रोज की राय में विद्रोहियों के नेताओं में वह सबसे अधिक “योग्य और वीर” थी। मलेसन लिखता है कि अँगरेजों की नजर में रानी का चाहें जो कुछ दोष हो, पर भारतवासी मरठा उसे अद्भुत तथा गौरव की दृष्टि से देखेंगे और सरकार पर यह दोष लगायेंगे कि उसने रानी के साथ अन्याय किया।<sup>१</sup>



लक्ष्मीबाई

**नात्या टोपे**—यह नाना साहब का सेनापति था। ग्वालियर में भाग-बर यह कई महीने तक राजपूताना, बुंदेलखंड और मालवा में घूमता रहा। अँगरेजों के बहुत बड़ प्रयत्न करने पर भी यह उनके हाथ न आया। अन्त में ग्वाल्दिया के एक स्वार्थी जागीरदार ने विश्वासघात करके उसका अँगरेजों के हवाले कर दिया। जंगी अदालत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का इम पर अपराध लगाया गया और फाँसी का दंड दिया

<sup>१</sup> क और मलेसन, जि० ५, पृ० १७५।



कि बनारस से लडके तक फासी पर लटका दिये गये थे। इलाहाबाद में निरपराध जनता का बिना किसी सफ़ा के वध किया गया था। वहाँ से चलते समय नील ने गाव के गाव जलाकर साफ कर दिये थे।<sup>१</sup> कम्पनेल का कहना है कि नील न जिस निर्दयता से लोगों का वध करवाया था वसा हिन्दुस्तानियों ने भी नहीं किया था।<sup>२</sup> निरुत्सव अग्रिक स अग्रिक वेदना देनेवाले प्राण्डड का समर्थन कर रहा था। हर एक जगह विजय के बाद 'विजय बोल दिया जाता था, जिसमें कितने ही ब्रेकमूर आदमी आर आरतों की हत्या होती थी। दिल्ली आर पञाब की घटनाओं का उल्लेख किया जा चुका है। सिपाहियों की कठोरता का वर्णन करनेवाले कृपर न ही लिखा है कि "यदि कानपुर का कुशा ह तो उमर साध रजनाला का भी कुशा है।" म्वर लार्ड कनिंग न माना है कि सिपाहियों के साथ साथ कितने ही निरपराध वच्चों, स्त्रियों तथा बुढ़ों तन का वध किया गया था। वह लिखता है कि बिना पूरी जाच किए हुए फासी लटका देने स आर गांवों को लूटने तथा जला देने स जा लोग सरकार का साथ देना चाहते थे, वे भी उत्तेजित हा गये थे।<sup>३</sup> बहुत सी अटालता की कारवायों का लार्ड कनिंग ने इस भय से प्रकाशित न किया था कि उनमें 'ममार म हमारे दशवासियों का घोर अपमान होगा।'<sup>४</sup>

यदि कुछ उन्मत्त सिपाहियों न श्रीगरेज खियों आर वच्चों का वध कर डाला था, तो अधिकांश जनता ने उनकी रक्षा भा की थी। जिस समय दिल्ली, कानपुर आर फासी में श्रीगरेजों की हत्याएँ हा रही थीं, उम्मी समय बहुत स गानों पर दया, महानुभूति आर करुणा के उदाहरण भी घट रह थे। बहुत

<sup>१</sup> कै. ऑर नलेसन, जि० २, पृ० २०२-०८। होमर, पृ० २०२-०८।

<sup>२</sup> कै. ऑर नलेसन, जि० २, पृ० २८०।

<sup>३</sup> कै. ऑर नलेसन, जि० २, पृ० २००।

<sup>४</sup> कनिंग, पैनिंग (रलम ऑफ इंडिया मिनिस्टर) पृ० २०३।

से हिन्दुस्तानियों ने अपनी जान हथेली पर लेकर अंगरेजों को अपने घर में छिपाया था। कितने ही भारतवासियों ने पद पद पर केवल मनुष्यत्व और दया के नाते अंगरेजों की सहायता की थी। कमिश्नर ग्रियेड लिखता है कि “दिल्ली से जितने भागे हुए अंगरेज आये, उन सबने स्वीकार किया कि अनेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें आश्रय दिया और उनके साथ भला बर्ताव किया। एक सन्यासी को जमुना में बहता हुआ एक अंगरेज बचा मिला, उसे बड़ मेरठ ले आया। जब हम उसको इनाम देने लगे उसने न लिया और कहा कि अगर मुझे कुछ देना ही है, तो रास्ते पर एक कुआ खोदवा दे।” कुछ दरिद्र मजदूरों ने घायल डाक्टर बुड की रक्षा की थी।<sup>१</sup> कितनी ही हिन्दुस्तानी आयाश्रों ने अंगरेज बच्चों की जाने बचाई और उनका इस कठिन अवसर पर अपनी सन्तानों से बढ़कर लालन-पालन किया।

यदि इस भयंकर समय में दरिद्र ग्रामवासी, मजदूर, बनी, राजा, रईम सभी दर्जों के भारतवासियों ने अंगरेजों की सहायता न की होती, तो उनका वचना मुश्किल था। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इस अवसर पर अंगरेजों ने भी अपने अद्भुत साहस, धैर्य, वीरता और स्वदेशभक्ति का परिचय दिया। सच बात तो यह है कि दोनों ओर से दैवी और आसुरी दोनों ही गुणों का प्रदर्शन किया गया।

यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास में ‘गदर’ के नाम से प्रसिद्ध है। पजाब के चीफ कमिश्नर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमात्र कारण कारतूस का झगडा था, पर मैलेसन इसको अंगरेजों की “बदनियती” बतलाता है। वह लिखता है कि अंगरेजों ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, अफगान-युद्ध के बाद से सिपाहियों की शिकायतें नहीं सुनी गईं, सन्धिघोष के विरुद्ध देशी राज्य छीन लिये गये और नये शासन-प्रबन्ध में प्रजा के रीति-रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया।<sup>२</sup> लार्ड डलहौजी के समय में ही

<sup>१</sup> मार्टिन, इंडियन एम्पायर, पृ० १६९।

<sup>२</sup> के और मैलेसन, वि० ५, पृ० २७९-९०।

अगान्ति की बाखुद एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारतृय की चित्तगारी पड़ गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिक विद्रोह जान्त हो गये थे, यह भी जान्त हो जाता।

**असफलता के कारण—**फार्मी की रानी को छोड़कर गिराहियो का कोई योग्य नेता न था। उनमें हिस्मत, उत्साह और शक्ति की कमी न थी, पर मोचनवाला मस्तिष्क न था। पहले से विद्रोह का कोई उद्देश्य या कार्यक्रम निश्चित न था। एक ओर बहादुरशाह सम्राट् और दूसरी ओर नाना साहब पेशवा बनाया जा रहा था। अंगरेजों को निरालाकर किस प्रकार पानन होगा, इस ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया था। हिन्दू और मुसलमानों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। धन की चिन्ता कमी थी और सगठन की ओर तो किसी का ध्यान ही न था। विद्रोह के कुछ दिन पहले गाँवों में चपात्या और रियालों में कमल घुमाये जा रहे थे। नाना साहब लगनठ और दिल्ली के चक्रर लगा रहा था। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विद्रोह के लिए पड़्यंत्र रचा गया था। यदि ऐसा हा भी तब भी मानना पड़ेगा कि इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गई थी। यदि एक ही दिन सारे देश में विद्रोह हो जाता, तो अंगरेजों के लिए उसका दबाना असम्भव था।

विद्रोह देशव्यापी न था। इसका नयन अधिक जोर पञ्जाब, पश्चिमोत्तर प्रान्त, रतेलखण्ड, अवध नर्मदा तथा चम्बल के बीच के प्रदेश और बिहार तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में था। सिन्ध के नपियर ने फिर उठान योग्य हो न स्या था। राजपूताना का हासला बहुत दिनों से पस्त था, दूसरे सर नाना साहब की नीति ने भी उसके भुलावे में डाल दिया था। नर्मदा के दक्षिण में बालापुर को छोड़कर अन्य कहीं विशेष उपद्रव नहीं हुआ। सत्य और पूर्वी बंगाल शान्त रहा। पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा के स्वतंत्र राज्य अफगानिस्तान और नेपाल अंगरेजों के मित्र बन रहे।

प्रायः सभी देशी राज्यों ने अंगरेजों का साथ दिया। इनकी सैनिक शक्ति पहले से ही नष्ट कर दी गई थी। ऐसी दशा में असन्तुष्ट होते हुए भी, अपने-अपने-अपने का ध्यान करके, सिवा चुप रहने के इनके लिए कोई और उपाय न

था। सिन्धिया को उसके दीवान दिनकरराव ने यमका-बुझाकर राजभक्त बनाये रखा। यदि वह बिगड़ जाता तो अन्य मराठा राज्य भी उसके साथ हो जाते। जनरल डनिस के शब्दों में “उसकी राजभक्ति ने अंगरेजों के लिए हिन्दुस्तान बचा लिया।” इसी तरह निजाम को सर गालारजग ने राजभक्त बनाये रखा और मुसलमान उपद्रवियों को कठिन ढड़ देकर हैदराबाद में उपद्रव को भड़कने न दिया। विद्रोह के इतिहासकार होम्स का कहना है कि इसके लिए अंगरेजों को सालारजंग का मद्दा कृतज्ञ रहना चाहिए। मिस और गोरखा सैनिकों ने अंगरेजों की पूरी सहायता की, इनको लूट का सूत्र लालच दिया गया था। दिल्ली लूटने की मिसों को बहुत दिनों में अभिलाषा थी, यही बात अवध के सम्बन्ध में गोरखों के लिए थी। सर जान लारेंस लिखता है कि यदि पंजाब ने साथ न दिया होता, तो हम कहीं के भी न होते।

लार्ड कैनिंग ने इस कठिन अवसर पर बड़ी बुद्धिमत्ता से काम किया। यह बात ठीक है कि यदि उसने अशान्ति के चिह्नों को देखकर पहले से परा प्रस्थान किया होता, तो विद्रोह इतना जोर न पकड़ता। परन्तु साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारतवर्ष आये हुए उसको थोड़ा ही दिन हुआ था। उसे देश की स्थिति का पूरा ज्ञान न था, दूसरे अशान्ति की वीज उसके आने के पहले ही बोये जा चुके थे। बड़ी उत्तेजना के समय में भी उसने अपने को शान्त रखा। यदि वह निकल्सन ऐसे अफसरों के कटने में आ जाता, जो स्त्रियों और बच्चों को जला देने तथा विद्रोहियों की साल सलाह लेने के लिए कानून बना देने पर जोर दे रहे थे, तो निस्सन्देह अशान्ति बढ़ जाती। अंगरेजों के बहुत कुछ आन्दोलन करने पर भी उसने बगाल की जमीन कानून जारी नहीं किया और निर्मूल घटनाओं को प्रकाशित करके उत्तेजना बढ़ानेवाले समाचारपत्रों का मुँह बन्द कर दिया। उसकी न्याय और दया की नीति को बहुत से अंगरेजों ने पसन्द नहीं किया, पर इसमें सन्देह नहीं कि इसका जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा।

**कम्पनी का अन्त**—विद्रोह का समाचार मिलने पर सन् १८५८ ही इंग्लैंड में इस बात पर विचार हो रहा था कि भारत का शासन इंग्लैंड





## परिच्छेद १४

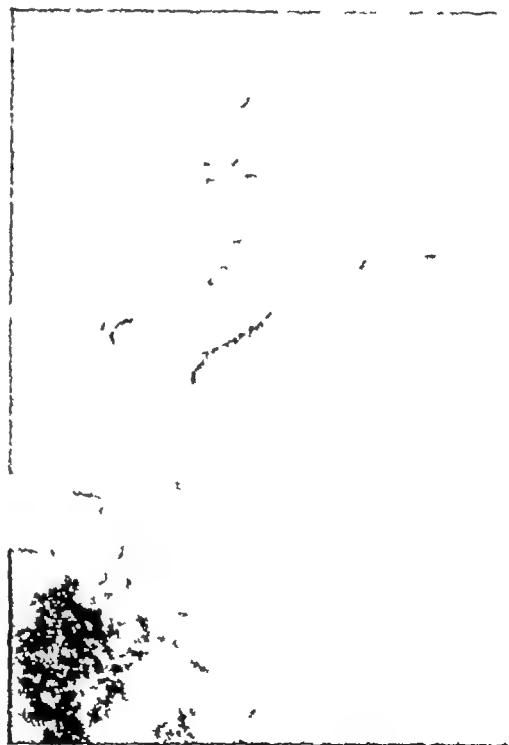
### ब्रिटिश छत्र की छाया

रानी विक्टोरिया का घोषणापत्र—नई शासन-प्रवस्था का प्रारम्भ इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के एक घोषणापत्र से किया गया। इसका अन्वयिदा तैयार कराने में

स्वयं विक्टोरिया ने योग दिया और इसमें “उदारता, दया और धार्मिक सहिष्णुता” के भावों को दिखलाने के लिए आदेश किया।

पहली नवम्बर सन् १८५८ को इलाहाबाद में बड़ी धूमधाम से एक दरबार किया गया, जिसमें लार्ड बनिगन, जो भारतवर्ष का

पहला वाइसराय (राजप्रतिनिधि) बनाया गया, इस घोषणापत्र को पढ़कर सुनाया। इसमें कम्पनी व सब कर्मचारियों का उनका स्थान पर बहाल करत हुए और देशी नरेशों का मान्यता की रक्षा तथा



रानी विक्टोरिया

“निःशर्का के पालन करने का विश्वास दिलाने हुए, रानी विक्टोरिया की ओर

से कहा गया कि इस समय भारत में जितना मेरा राज्य है, मैं उसे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। “मैं देगी नरेशों के अधिकारों और मानमर्यादा को अपने ही अधिकारों और मानमर्यादा के समान समझूँगी।

“राजधर्म पालन करने के लिए जिस तरह मैं अपनी अन्यान्य प्रजाओं से प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, वैसे ही भारत की प्रजा के निरुद्ध भी प्रतिज्ञाबद्ध रहूँगी। सर्वशक्तिमान् परमात्मा की दया से मैं उन प्रतिज्ञाओं का भरमरु यथारीति पालन करूँगी।

“इसारे धर्म पर मेरा दृढ़ विश्वास है। इसके आश्रय में मुझे जो शान्ति मिली है, उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हुए, मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि अपने धर्म को प्रजा से मनवाने के लिए न मेरी इच्छा है और न मुझे अधिकार है। मैं अपनी यह राजकीय इच्छा प्रकट करती हूँ कि कोई व्यक्ति, अपने धार्मिक विश्वास या रीतियों के कारण, न किसी तरह अनुगृहीत किया जाय और न किसी तरह सताया या छेड़ा जाय। सबकी निष्पक्ष भाव और समान रूप से कानून द्वारा रक्षा की जाय। जो मेरे अधीन शासनार्थ में नियुक्त है, उन्हें मैं आज्ञा देती हूँ कि वे मेरी किसी प्रजा के धर्म या द्वासना में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यदि वे ऐसा करेंगे, तो मेरी अत्यन्त अप्रसन्नता के पात्र होंगे।

“मेरी यह भी इच्छा है कि यथासम्भव मेरी प्रजा को, वह चाहे किसी जाति या किसी धर्म की माननेवाली हो, अपनी विद्या, योग्यता और सचरित्रता के कारण, सरकार के अधीन जिस किसी काम के करने योग्य हो, वह काम उसको बिना किसी पक्षपात के दिया जाय।

“भारतवासियों को अपने पूर्वजों से जो जमीनें मिली हैं, उनके लिए उनमें कितनी माया और ममता होगी, इसको मैं अच्छी तरह समझती हूँ और उसका आदर करती हूँ। इन सब जमीनों पर जिसका जैसा और जितना अधिकार है, उसकी मैं रक्षा करना चाहती हूँ, पर उन्हें नियमानुसार लगाया हुआ कर देना होगा। मेरी इच्छा है कि कानून बनाते समय तथा कानूनों को व्यवहार में लाते समय भारत के प्राचीन स्वत्व और रीति-रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाय।”

विद्रोहियों के साथ दया का व्यवहार करने का वचन देते हुए घोषणापत्र के अन्त में कहा गया कि “ईश्वर की कृपा से जब शान्ति फिर से स्थापित हो जायगी, तब भारत की कलाओं को बचाने, लोकप्रयोगी कार्यों और सुधारों की ओर अधिक ध्यान देने तथा भारत की प्रजा के उपकार के लिए काम करने की मेरी परम इच्छा है। इसकी समृद्धि में मैं अपनी शक्ति, इसके अन्तोप में मैं अपनी रक्षा और इसकी कृतज्ञता में मैं अपना सर्वस्व बड़ा पुरस्कार समझूँगी।”

यह घोषणापत्र भारत का ‘अधिकारपत्र’ माना गया है। इस सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो यह कबे समय पर प्रकाशित किया गया था और दूसरे इसके उच्च भावों से व्यवहार में कहा तक काम लिया गया। घोषणापत्रों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध फ्रीमन की राय है कि हमें कूट की भरमार होती है। विक्टोरिया के उच्च आदर्श और प्रजाप्रेम पर विनी को नन्देह नहीं हो सकता, पर साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड की शासन-व्यवस्था में नीति का काम में लाना मंत्रियों के हाथ में है, न कि राजा के। सर जेम्स स्टिफन का मत है कि यह घोषणापत्र केवल दरबार में पढ़कर सुनाये जाने के लिए था। यह कोई नव्वि न थी जिसमें अनुसार काम करने के लिए अगरेजों पर विनी प्रसार की जिम्मेदारी हो। जिन उद्देश्य से यह घोषणापत्र प्रकाशित किया गया, वह अल्प समय में ही भारत की भोली-भाली जनता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

**देशी राज्य—**सन् १८५६ में राजाओं के सम्बन्ध में भी एक नया लेन-बा प्रथिभार मान लिया गया। इन तरह राज्यों के बड़े भारी सम्बन्धों को गये वा कारण दूर कर दिया गया। लार्ड डलहौजी के समय में जिन नीतियों का अनुसरण किया गया था उसका त्याग देना ही इस बात का सर्वप्रथम प्रमाण है कि उसमें विनी भारी भूल की गई थी। विद्रोह के समय में सरकार की सहायता करने के बदले में निजाम पर जो दबाव था, वह भाग्य पर दिया गया। अवध की सीमा का कुछ जंगली भाग नेपाल को दे दिया गया। बिन्दिया, गायकवाट, भूपाल की बंगम और कई एक राजपूत राजाओं को

थोड़ी थोड़ी भूमि दी गई और बहुतों का खिराज घटा दिया गया। राजाओं, तालुकदारों और जमीन्दारों में विपत्ति के समय में किननी सहायता मिल सकती है, लार्ड कैनिंग इसको अच्छी तरह जानता था। इसी लिए जहाँ तक हो सका उसने इन सबको सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया। विद्रोह शान्त हो जाने पर उसने अवध के तालुकदारों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, जिन्होंने उसके नाम से लखनऊ में 'कैनिंग कालेन' स्थापित किया।

**सैनिक संगठन**—साम्राज्य की रक्षा के लिए सेना का फिर से अच्छी तरह संगठन किया गया। कम्पनी और इंग्लैंड-सरकार की सेनाओं में जो भेद था, उठा दिया गया और दोनों सेनाएँ एक कर दी गईं। विद्रोह में जैसी कुछ स्थिति हो गई थी, भविष्य में उसमें बचन के लिए यह नियम बना दिया गया कि तोपखाने में हिन्दुस्तानी भरती न किये जायँ और जितनी मिया-हियो की सख्या हो, कम से कम उससे आधे गोरे अवश्य रखे जायँ। डल-हौजी के समय में गोरी सेना की सख्या ४५ हजार थी, अब यह बढ़ाकर ७० हजार कर दी गई। इसी के अनुसार हिन्दुस्तानी सेना की सख्या १३,५००० रखी गई। आवश्यकतानुसार इस सख्या में घटा-बढ़ी होती रहती है। सेना की सख्या बढ़ जाने से खर्च भी बहुत बढ़ गया।

**आर्थिक सुधार**—दो तीन वर्ष विद्रोह रहने के कारण सरकार को बहुत घाटा हुआ था, कर्ज की रकम दुगुनी हो गई थी और सालाना खर्च पूरा न पड़ता था। इस दशा को सुधारने के लिए इंग्लैंड से जेम्स विल्सन बुलाया गया। उसके समय में व्यापार, आमदनी और तमाखू पर टैक्स लगा दिये गये। चाय, सन तथा जूट पर, जो भारतवर्ष से बाहर जाते थे, महसूल उठा दिया गया और बाहर से आनेवाले माल पर चुगी कम कर दी गई। इस तरह आर्थिक कष्ट के समय पर भी इंग्लैंड के व्यापार का ध्यान रखा गया। सन् १८६० में मिलन की मृत्यु हो जाने पर सैम्युएल लैंग अर्थ-सदस्य बनाया गया। इसके समय में सेना और शासन के खर्च को कुछ घटाने का प्रयत्न किया गया और नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया। इन उपायों

ये हर साल जो कमी पड़ती थी, पूरी हो गई और कुछ बचत भी होने लगी। इन बचत से भारत की दरिद्र जनता का कोई उपकार नहीं किया गया, पर मेम्बरों के साल पर चुगी और घटा दी गई। इसी समय से प्रान्तीय सरकारों को कुछ आर्थिक स्वतंत्रता देने का प्रयत्न किया गया और कांग्रेस का विकास भी चलाया गया।

**शासनप्रबन्ध**—सन् १८६१ में 'इंडियन कॉमिल ऐक्ट' पास किया गया। इसके अनुसार वाइसराय की 'एक्जीक्यूटिव कॉमिल' (कार्यकारिणी समिति) के सदस्यों की संख्या पाँच कर दी गई। शासन के भिन्न भिन्न विभाग इन सदस्यों को सौंप दिये गये, जिसमें हर एक बात पर विचार करने के लिए कॉमिल की मीटिंग करने की आवश्यकता न पड़े। वाइसराय की अनुपस्थिति में काम चलाने के लिए कॉमिल के सबसे बड़े मेम्बर को महापति मानने का नियम बना दिया गया। कानून बनाने के लिए वाइसराय की 'लेजिस्लेटिव कॉमिल' (व्यवस्थापक सभा) के गैरसरकारी मेम्बर नामजद करने का भी अधिकार दे दिया गया, जिससे कुछ भारतवासियों को मेम्बर बनने का अवसर मिला। सरकारी मेम्बरों की संख्या अधिक होने से उनमें प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। बम्बई और मद्रास की कॉमिलों में कानून बनाने के अधिकार सन् १८३३ में ले लिये गये थे, अब उनमें ये अधिकार फिर से दिये गये। बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रान्त में भी आवश्यकता होने से कॉमिलें स्थापित करने की व्यवस्था की गई।

'सुप्रीम कोर्ट' तथा 'मदर अदालतों' का भेद उठा दिया गया और उनकी जगह पर बलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 'हाईकोर्ट' स्थापित कर दिये गये। मकाल के समय से कानूनों का जो संग्रह तैयार हो रहा था, अब स्वीकार कर लिया गया और सारे भारतवर्ष में जायजा दीवानी, तालीम-ए-मिन्द और जज्ता फाजदारी जारी कर दिये गये। बंगाल में वास्तविकता को धार धार दखल करके घटा तग किया जाता था। इसलिए सन् १८६६ में बंगाल दिवार, पागुरा और मध्यप्रान्त के लिए यह कानून बना दिया गया कि वार्षिक रूप से किमी खेत को जोतने से वास्तविकता का उसमें मौलुमी हक मान लिया

जायगा। भारतवर्ष भर में इस्मरारी बन्दोबस्त जारी करने का भी विचार था, पर कई कारणों से ऐसा नहीं किया गया। सन् १८५८ में सर चार्ल्स वुड की रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा का प्रयत्न हो ही रहा था। अब उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया और सन् १८५७ में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 'यूनिवर्सिटिया' ( विश्वविद्यालय ) स्थापित की गईं।

**नील और चाय की खेती**—भारतवर्ष में अंगरेजों के बसाने के प्रश्न पर बहुत दिनों से विचार हो रहा था और इसके लिए उन्हें लालच भी दिये जा रहे थे। सन् १८५० में आसाम और नीलगिरि की पहाड़ियों में चाय और काफी की खेती करने के लिए कुछ युरोपियन आबाद हुए। इन लोगों को बहुत सी ज़मीनें मामूली लगान पर दे दी गईं। इसी तरह नील की खेती कराने के लिए बंगाल में भी बहुत से अंगरेज बसाये गये। विद्रोह के बाद इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा था। कहा जाता था कि हिमालय की पहाड़ियों में अंगरेजों के आबाद हो जाने से रूसियों के आने का भय न रहेगा और भारतवर्ष में साम्राज्य की जड़ भी मजबूत हो जायगी। इसकी जाँच करने के लिए सन् १८५८ में पार्लियामेंट की एक कमेटी भी नियुक्त की गई थी। ये युरोपियन गरीब किसानों पर अत्याचार करते थे और उनमें जबर-दस्ती नील की खेती करवाते थे।<sup>१</sup> सन् १८६० में यह मामला इतना बढ़ गया कि इसकी सरकार की ओर से जाँच कराई गई और जबरदस्ती नील की खेती कराने से उन्हें रोका गया। कुलियों पर अब भी ये लोग बड़ा अत्याचार करते हैं।

**लार्ड एलगिन**—सन् १८६२ में लार्ड कैनिंग वापस चला गया। चिन्ता और परिश्रम के कारण उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। इंग्लैंड पहुँचने के दोपहर ही दिन बाद वह मर गया। विद्रोह के ऐसे कठिन समय पर

---

१ दीनानन्दु मिश्र ने, अपने 'नील दर्पण' नामक नाटक में, इन अत्याचारों को बहुत अच्छी तरह चित्रित किया है। इसके अंगरेजी अनुवाद में अंगरेज लोग बहुत निंदे और प्रेक्षक अनुवादकों को जेल भुगतनी पड़ी।

उमन बड़े धैर्य से काम लिया। उसकी उदार नीति से कुछ अंगरेज बहुत नट्ठा नटे थे, पर अन्त में सबको उसकी योग्यता माननी पड़ी। उसके स्थान पर लार्ड एलगिन वाइसराय बनाया गया। यह पहले कनाडा में गवर्नर-जनरल और चीन में राजदूत रह चुका था। साल ही भर बाद नवम्बर मन् १८६३ में, पनात्र के धर्मशाला नामक स्थान पर, इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना हुई। पश्चिमोत्तर सीमा पर बहारी मुसलमानों ने बड़ा उपद्रव किया। इसको शान्त करन में अंगरेजी सना को बड़ी प्रतिभादर्शिता उठानी पड़ी।

**सर जान लारेंस**—पश्चिमोत्तर सीमा पर अगान्ति होने के कारण

गवर्नर-जनरल का पद

सर जान लारेंस को

दिया गया। पहले

यह पञ्जाब का चीफ

कमिश्नर रह चुका

था। गन्तव्य के समय में

भी इसने बड़ा काम

किया था। पश्चि-

मात्तर सीमा-सम्बन्धी

विषयों का इसको

बड़ा ज्ञान था।

भारतवर्ष में वापस

जान के बाद में इंग्लैंड

में यह नई स्थापित

‘ए. इटिया बैग्निल’

काम करता था।

सर सर लार्ड डल-

हौसी की नीति का



सर जान लारेंस

पक्षपाती था, पर विद्रोह के समय में हमने अपना मत बदल दिया था। अब लार्ड कैनिंग की तरह हमकी राय में भी देशी राज्यों को बनाये रखना आवश्यक था।

**भूटान की लड़ाई**—सन् १८२६ में आगाम पर अधिकार हो जाने से अँगरेजी राज्य की सीमा भूटान से मिल गई थी। इस सीमा पर भूटानी प्रायः लूट-मार किया करते थे। सन् १८६३ में इन झगड़ों को तय करने के लिए एक अँगरेज अफसर भेजा गया। भूटानियों ने उसका बड़ा अपमान किया और उससे एक सन्धि पर हस्ताक्षर करवा लिये, जिसमें आगाम में आने के लिए पहाड़ी मार्गों पर जो 'द्वार' कहलाते हैं, भूटानियों का अधिकार मान लिया गया। भारत-सरकार ने इस सन्धि को मानने से इनकार कर दिया और अँगरेज क़ैदियों को वापस करने के लिए भूटान को लिख भेजा। कोई उत्तर न मिलने पर युद्ध छिड़ गया। सन् १८६५ में भूटानियों ने देवनगिरि से अँगरेजी सेना को भगा दिया और दो तोपें छीन लीं। परन्तु अँगरेजों की अधिक सेना आ जाने के कारण अन्त में भूटानियों को हार मानकर सन्धि स्वीकार करनी पड़ी। उनमें 'बारह द्वार' ले लिये गये और उनके बदले में उन्हें कुछ रुपया सालाना देने का वचन दिया गया।

**अफ़ग़ानिस्तान**—सन् १८६३ में अमीर दोस्तमुहम्मद की मृत्यु हो गई। विद्रोह के समय में यदि वह चाहता तो अँगरेजों से पेशावर छीन सकता था, परन्तु ऐसा न करके उसने उनके साथ बराबर मित्रता का व्यवहार किया। उसके १६ लड़के थे, इनमें से चार पाँच गद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे। जान लारेंस का यह मत था कि जो गद्दी पर बैठे उसके साथ मित्रता रखकर आपस के झगड़ों में किसी तरह का हस्तक्षेप न करना चाहिए। इस नीति के अनुसार शेरअली या उसका भाई अफ़जल, जो गद्दी पर बैठ जाता था, वही अमीर मान लिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि सब झगड़ों से बचने के लिए अँगरेजों के हक में यह बड़ी अच्छी नीति थी, परन्तु अफ़ग़ानिस्तानवालों का



इसमें अय्यन्तुष्ट होना स्वाभाविक था। पहले जेरमनी को मित्रता का विचार दिलाया गया, पर उसको हटाकर जब अफजल गद्दी पर बैठ गया, तब उसने अंग्रेजों का पत्र भेजा गया। इस पर सेंट अफगान सरकार का कहना था कि किसी जाति का अंगरेजों से पार पाना मुश्किल है। इस पत्र में अंगरेजों की यह इच्छा मालूम पड़ती है कि हम सब आपस ही में फट सकें। यदि जेरमनी जानता तो इसको भी उन्होंने ऐसा ही पत्र लिखा होता। इसी तरह जेरमनी का कहना था कि अंगरेज अपने मतलब के मित्रों और किसी बात को नहीं देखते। वे हमसे ताका करते हैं, जिसको वे सबसे जबरन पाने हैं। हमी क मित्र बन जाते हैं।<sup>१</sup>

मध्य एशिया में धीरे धीरे रूस दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। इससे अफगानिस्तान की समस्या और भी जटिल हो गई थी। कुछ लोगो की राय थी कि रूस को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ नई सन्धि हानी चाहिए, पर जान लारेंस इसकी आवश्यकता न समझता था। उसका कहना था कि हमी तथा अंगरेजी साम्राज्यों की प्रभाव-सीमा रूस से ही मिलकर निर्धारित होनी चाहिए। मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बढ़ जाना से फंड भय नहीं था। उससे बता दें जंगली मनुष्यों से कुछ सभ्यता आ जायगी। इसी लिए रूस को सरकार को, प्रार्थना करने पर भी, भारत-सरकार की ओर से सेंट सभायता नहीं दी गई। जान लारेंस की राय से अफगानिस्तान की ओर से भारतवर्ष की रक्षा का सबसे अच्छा उपाय यही था कि उसके ऊपर से न पड़ा भार, सीमा पर काफी सेना रखी जाय और भारतवर्ष के राजाओं का अनुष्ठान रखा जाय। लार्ड लिटन के समय तक सरकार की यही नीति रहा।

**उर्दू का अकाल—**सन् १८६५ में उर्दू का सेंट नदर पाल पड़ा, जिसमें लाखों आदमी मर गये। बंगाल-सरकार का भार से रक्षा की रक्षा के लिए पहले से कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया। यदि



राजकुमारों के लिए अजमेर में 'मेयो कालेज' खोला गया। लाहौर और राजकोट में भी ऐसे ही कालेज स्थापित किये गये। इनमें राजकुमारों को अंगरेज शिक्षकों के साथ मिल-जुलकर रहने और पाश्चात्य आचार-विचार सिखलाने का प्रवन्ध किया गया। राष्ट्रीयता की दृष्टि से इन सस्थाओं का प्रभाव राज्यों के भावी शासकों पर अच्छा नहीं पड़ रहा है। बचपन से ही उन्हें पाश्चात्य ढंग के रहन-सहन की शिक्षा मिलने लगती है। "शासन की जिम्मेदारी" का समझना तो दूर रहा, बड़े होने पर बहुतों को यूरोप में हवा खाने का चस्का लग जाता है।

**शेरअली से भेंट—**मार्च १८६९ में अफगानिस्तान के अमीर शेरअली के साथ अम्बाला में लार्ड मेयो की भेंट हुई। शेरअली एक ऐसी सन्धि चाहता था, जिससे अंगरेज उसको साल में कुछ रकमा दिया करें और आवश्यकता पड़ने पर सेना से उसकी सहायता करें। लार्ड मेयो ने यह तो स्वीकार नहीं किया, पर उसने इस ढंग से काम लिया कि अमीर अंगरेजों की नीति से अच्छी तरह सन्तुष्ट होकर अफगानिस्तान वापस गया। जान लारेंस की नीति से अमीर को जो सन्देह उत्पन्न हो गया था, वह इस भेंट से दूर हो गया। लार्ड मेयो भी उसी नीति का अनुयायी था, पर वह लारेंस की अपेक्षा अधिक नीतिनिपुण था। इसी लिए अमीर को उसने, अपने को बिना किसी प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध किये हुए, अंगरेजों की मित्रता का विश्वास दिला दिया। इस भेंट का अमीर पर बहुत प्रभाव पड़ा। अफगानिस्तान जाकर, उसने शासन में अंगरेजी ढंग के कई एक सुधार किये। उसने कठोर ढङ्गे को उठा दिया, पुलिस को ठीक किया, न्यायालय तथा डाक-घर खोले और शासन में सहायता करने के लिए तेरह मेम्बरों की एक कौमिल भी बनाई।

भारत की सीमाओं को सुगन्धित रखने के लिए लार्ड मेयो का मत था कि उसको सुदृढ़ तथा मित्रता का भाव रखनेवाले, स्वतंत्र राज्यों से घेर देना चाहिए। अपने हित का ध्यान रखकर वे सदा हमारा साथ देंगे, फिर हमें किसी का भय नहीं रहेगा। अम्बाला-सम्मेलन के सम्बन्ध में उसका कहना था

कि इसमें मध्य एशिया के राज्यों में अंगरेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। तब यदि लोगों को यह समझा सकें कि वास्तव में हमारी नीति हमसे न रुकन तथा शान्ति स्थापित रखने की है और इस समय एशिया में केवल हमारा ही एक ऐसा राज्य है, जो किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहता, तो हम शक्ति की इस पराकाष्ठा पर पहुँच जायेंगे, जो हमें पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी।<sup>१</sup> पश्चिम, उत्तर और पूर्व की सीमाओं के राज्यों के साथ हमने इसी नीति में काम लिया। रुस के साथ भी लार्ड मेयो ने समझौता कर लिया। आक्रमण नदी के दक्षिण तक अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा मान ली गई और उदयगंगा पर भी श्रीमौर का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। लार्ड मेयो की राय थी कि अंगरेजों की शक्ति इतनी बढ़ है कि उसे रुस से कोई भय नहीं है। मध्य एशिया में रुस के साथ छेड़बानी करने की अपेक्षा हमसे मित्रता करना ही अच्छा है।

**आर्थिक प्रवन्ध—**सर जान लारेन्स के समय में सरकार का मानना कि चर्च पूरा न पड़ता था इसलिए कर्ज भी बहुत बढ़ गया था। उसका दूर धरन के लिए लार्ड मेयो ने सर्वे घटाने और आमदनी बढ़ाने का प्रवन्ध किया। उन दिनों 'पब्लिक वर्क्स' विभाग में खूब खर्चा हो रहा था। टर्नापियर लागू कौड़े काम अपनी निगाह से न देखते थे। लार्ड मेयो ने इस विभाग का सर्वे को घटा दिया। इस समय तक बंगाल की अपेक्षा बम्बई और मद्रास में नमक-कर कुछ कम था, इन दोनों प्रान्तों में यह कर बढ़ा दिया गया। 'हन्स टक्स' (आय-कर) की दर भी बढ़ा दी गई। अर्थविभाग में पैसा-किताब ठीक रखने का प्रवन्ध किया गया। इस समय तक भारतीय सरकारों को बिना भारत सरकार की आज्ञा के खर्च करने का अधिकार था। हर साल उन्हें अपना 'बजट' बनाकर भेजना पड़ता था और ब्याज मंजूर होना जान पर उसी के अनुसार खर्च करना पड़ता था। सामन्ती देश-का खर्च करना अर्थशास्त्र का आधारण सिद्धान्त है परन्तु इस प्रवन्ध में उनका

भी पालन न होता था। कुल ग्रामदानी भारत-सरकार की थी, प्रान्तीय सरकारों को उसका कुछ भी ध्यान न रहता था, उन्हें केवल अपने स्वर्च में मनलग था। इसके लिए जो रकम मजूर होती थी, उसमें यदि कुछ बच रहता था तो उसको भारत-सरकार ले लेती थी। ऐसी दशा में किरायात में स्वर्च करने की ओर प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी न जाता था। हर एक सरकार अपना बजट खूब बढ़ा-चढ़ाकर भेजती थी, जो स्वयं अधिक लिखा-पढ़ी करती थी, उसी को सबसे बड़ी रकम भी मिलती थी। इसमें शासन में भी बड़ी बाधा पड़ती थी, कभी कभी तो जरूरी रकमों को भी भारत-सरकार स्वीकार न करती थी।

इस दशा को सुधारने के लिए लार्ड मेयो ने प्रान्तों के लिए सालाना रकम निश्चित कर दी और यह नियम बना दिया कि जिस प्रान्त की जो बचत हो, वह उसी के काम में आये और हर पांचवें साल, किस प्रान्त का कितना मिलना चाहिए, इसकी जांच की जाय। इस रकम को खर्च करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया और जेल, रजिस्ट्री, पुलिस, शिक्षा तथा सड़क और सरकारी इमारतों का काम उन्हीं को सौंप दिया गया। इन सुधारों से प्रान्तीय सरकारों में जिम्मेदारी का भाव आ गया और वे समस्त वृक्षर काम करने लगीं। इस तरह कुछ काम बँट जाने से भारत-सरकार को भी सारे देश से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों पर विचार करने का समय मिल गया।

खेती और व्यापार की उन्नति करने के लिए लार्ड मेयो के समय में एक नया विभाग खोला गया। कई एक नई नहरे खोदवाई गईं और रेल की नई लाइनें खोली गईं। बाटे का भय न होने के कारण रेलवे कम्पनियां मनमाना स्वर्च करती थी और नई लाइनें खोलने में सरकार की सैनिक तथा राजनैतिक सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान न देती थी। इन दोषों को दूर करने के लिए लार्ड मेयो ने सरकारी रेलें खोलने की व्यवस्था की। उसके सुधारों का परिणाम यह हुआ कि भारत-सरकार को हर साल बचाव घाटा के कुछ बचत होने लगी।

**लार्ड मेयो की मृत्यु**—लार्ड मेयो को जेलों की दगा मुधारने की पूरी

चिन्ता थी। उसका कहना था कि उनमें कंदियों की रक्षा करना है न कि उन्हें मार डालना है। शासन-प्रबन्ध ठीक करने के लिए सन १८७० में वह अइमन द्वीप, नार्थ काले पानी के अपराधी रखे जाते हैं, देखने गया। वहाँ नाव पर सवार होने समय एक पठान कैदी ने उसको मार डाला। मेयो बड़ा डसाही शासक था अपने मिष्टाचार से वह सबको प्रसन्न रखता था। उसके शासनकाल में भारत-वर्ष में पूर्ण शान्ति रही। इंग्लैंड से नये बाइसराय लार्ड नार्थब्रुक के आन तक गवर्नर-जनरल के पद पर मदरास का गवर्नर नेपियर काम करता रहा।

**लार्ड नार्थब्रुक**—सन् १८७२ में लार्ड नार्थब्रुक भारतवर्ष पंजा। वह इंग्लैंड के बड़े धनी घराने का था और युद्धविभाग में कुछ दिन काम कर चुका था। वह बहुत मोच-विचारकर चलता था और पट्टे पत्र विचार का शासक था। उसमें दूसरों को अपनी ओर आश्रित रखने की शक्ति का अभाव था, यही कारण था कि बहुत से मामों में उसमें चञ्चलता नाली थी। अपनी नीति के सम्बन्ध में वह न्यत्र लिखता है कि 'अनुगति' 'दिया वो उठा देना और अनावश्यक सानून उनाने को रोक देना मेरा उद्देश्य रहा है।' हर एक बात में निरर्थक हस्तक्षेप करना उस पर बन्द पड़ता था। "ज्या बुरा है उसे चलने दो यही उसकी नीति थी।" यद्यपि दिया था "देना" उसने अपनी नीति का उद्देश्य बतलाया है, पर भारत की नीति चला के सम्बन्ध में उसमें इसमें काम नहीं लिया। 'इनकम टैक्स' का दान स धन व्यापारी, जमीन्दार और भारत में बसनेवाले अंगरेजों का ही भोग हुआ। भारत की आर्थिक दगा का ज्ञान रखनेवाले सर रिचर्ड टेम्सिल बार सर जान की बात थी कि यदि टैक्स उठाना ही है, तो नफ़ा-नफ़ा माफ कर देना चाहिए जिसमें बित्तों ही दरिद्रों का उपकार होगा। भारतमन्त्रि की भी पूरी राय थी। परन्तु लार्ड नार्थब्रुक अपनी ही बात पर डटा रहा।

**नवतत्र व्यापार**—इन दिनों इंग्लैंड में 'नवतत्र व्यापार' के विचारों की धूम थी। कहा जाता था कि व्यापार की वस्तुओं पर कर न

१८७०, नार्थब्रुक, पृ० ६०, १२० ।

लगाने से वे सस्ती पड़ेगी, जिससे सारे मंगार का लाभ होगा। इसी सिद्धान्त के अनुसार बाहर से आनेवाले माल पर चुगी उठाई जा रही थी। सन् १८६६ में स्वेज़ की नहर का मार्ग खुल जाने से भारतवर्ष के साथ इंग्लैंड का व्यापार बहुत बढ़ गया था। सन् १८६० तक भारतवर्ष में बाहर से आनेवाले माल पर १० सैकड़ा और बाहर जानेवाले माल पर ३ सैकड़ा चुगी लगती थी। सन् १८६४ में बाहर से आनेवाले माल पर चुगी घटाकर साढ़े सात सैकड़ा कर दी गई थी। सन् १८७५ में लार्ड नार्थमुक ने इसको घटाकर पाँच ही सैकड़ा कर दिया। तेल, चावल, नील तथा लाख को छोड़कर बाहर जानेवाले सब माल पर चुगी उठा दी गई। इसका फल यह हुआ कि भारतवर्ष से कच्चा माल तथा अन्न खूब बाहर जाने लगा और बना हुआ माल यूरोप से भारतवर्ष भी खूब आने लगा। मैनेस्टर के बने हुए कपड़े पर इंग्लैंड-सरकार पाँच सैकड़ा चुगी भी माफ कर देना चाहती थी, पर नार्थमुक इसके लिए राजी न हुआ। उसकी राय थी कि भारत-सरकार को आम-दनी की इस घटी का पूरा करना मुश्किल हो जायगा। इंग्लैंड ऐसे देश के लिए, जिसकी औद्योगिक कलाएँ पूरी उन्नति कर चुकी हैं और जिसका जीवन व्यापार ही पर निर्भर है, 'स्वतंत्र व्यापार' का सिद्धान्त ठीक है, परन्तु भारतवर्ष ऐसे देश के लिए जहाँ की सब कलाएँ चौपट कर दी गई हैं और जिसका खेती ही केवल आधार बना दी गई है, यह सिद्धान्त हितकर नहीं माना जा सकता। इससे उसका अन्न तथा कच्चा माल बाहर चला जाता है और विलायती माल सस्ता पड़ने से किसी उद्योग के लिए भी उत्साह नहीं मिलता है।

**मल्हारराव गायकवाड़**—सन् १८७५ में मल्हारराव गायकवाड़ वडोदा की गद्दी से उतार दिया गया। कहा जाता है कि वह अंगरेज रेजीडेंट को ज़हर देना चाहता था। इसकी जाँच करने के लिए, ग्वालियर और जयपुर के महाराजा, निजाम के वज़ीर, इन्दौर के दीवान और तीन अंगरेज अफसरों का एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन के सब हिन्दुस्तानी मेम्बरों ने महाराजा को निर्दोष पाया। इस पर यह अभियोग छोड़कर भारतमन्त्रि की सलाह से कहा गया कि उसके राज्य का प्रबन्ध का

आर चेतावनी देने पर भी ठीक ठीक नहीं हो रहा है, और वह गद्दी से उतार दिया गया। डलहौजी की नीति के अनुसार उसके राज्य का अपहरण नहीं किया गया। दल्लिक राजघराने का एक बालक गद्दी पर बिठला दिया गया और सर माधवराव दीवान बनाया गया, जिसके समय में राज्य की बहुत कुछ उन्नति हुई।

**युवराज का आगमन**—सन् १८७५ में इंग्लैंड के युवराज एडवर्ड ने भारत-भ्रमण किया। देश भर में बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया गया। भारतवर्ष में राज्य का स्वरूप राजा है। उसके लिए भारतवासियों के हृदय में सदा आदर रहता है। कम्पनी का शासन साधारण जनता की समझ में न आता था। बहुतेका तो अनुमान था कि कम्पनी किमी रानी का नाम था, जो इंग्लैंड में रहती थी। वे उसको 'कम्पनी जहाँ' कहा करते थे। मुगल बादशाहों के बाद में सारे देश पर शासन करनेवाले घराने के राजकुमार को देखते ही उन्हें फिर अवसर प्राप्त हुआ। देशी नरेशों ने अपनी राजभक्ति का परिचय दिया। उनके साथ अंगरेज अफसरों का उदंड व्यवहार देखकर एडवर्ड को बड़ा आनन्द हुआ और उसने इस सम्बन्ध में अपनी माता को लिखा। 'इस पतानुभूति में इंग्लैंड के राजघराने के साथ देशी नरेशों का सम्बन्ध टूट हो गया। एडवर्ड के बाद में प्रत्येक युवराज के भारतवर्ष आने की चाल पट गई।

**नार्थब्रुक का इस्तीफा**—सन् १८७३ में रमियो ने सच्य एशिया में राजा पर अधिकार कर लिया। इससे घबड़ाकर अफगानिस्तान के अमीर एरशली ने अंगरेजों के साथ अपना सम्बन्ध टूट बनाने के लिए एक दूत मिमला भेजा, परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ। इस समय तक अफगानिस्तान के प्रति इंग्लैंड तथा भारत-सरकार की वही नीति थी जिसका प्रयोग लार्ड कनिंग और सर जान लारेस के समय में हुआ था। लार्ड मैन्रो ने भी चतुरता से बिना कोई सन्धि किये हुए भी अमीर को अपना मित्र बनाया था, पर लार्ड नार्थब्रुक ने यह बात नहीं की। रमियो के विरुद्ध अंगरेजों ने आक्रामकता का कोई वचन न मिलने पर अमीर कुछ स्पष्ट हो गया। इससे अफगानिस्तान का कोई वचन न मिलने पर अमीर कुछ स्पष्ट हो गया। इससे अफगानिस्तान का कोई वचन न मिलने पर अमीर कुछ स्पष्ट हो गया। इससे अफगानिस्तान का कोई वचन न मिलने पर अमीर कुछ स्पष्ट हो गया।



बड़े लडके या कृत्रिम को कैद कर दिया था। इस सम्बन्ध में लार्ड नार्थवुक ने एक कड़ा पत्र लिखकर उसको और भी चिढ़ा दिया। इतने ही में इंग्लैंड की सरकार दूसरे दल की हो गई और उसने राय दी कि गेरशली में अपने दम्पार में अंगरेज रेजीडेंट रखने के लिए कहा जाय। लार्ड नार्थवुक इस बात पर राजी न हुआ। उसने भारतसचिव सालिमवरी को लिख भेजा कि अमीर पर मन्देह करना ठीक नहीं है। परन्तु भारतसचिव अपनी ही बात पर डटा रहा। इस तरह दोनों में मतभेद होने के कारण लार्ड नार्थवुक मई १८७६ में इन्फा टेक इंग्लैंड लौट गया। चलते समय वह भारतसचिव को सचेत कर गया कि अमीर की इच्छा के विरुद्ध अंगरेज रेजीडेंट रखने का परिणाम यह होगा कि गीत्र ही

अफगानिस्तान से युद्ध करना पड़ेगा। उसकी यह बात सच निकली।

### लार्ड लिटन—

अप्रैल सन् १८७६ में लार्ड लिटन वाइसराय होकर कलकत्ता पहुँचा। अंगरेजी भाषा का वह एक अच्छा विद्वान् और सुयोग्य लेखक था। बोलने का भी उसे सूत्र अभ्यास था। परन्तु शासन का कोई विशेष अनुभव न था। इसी लिए वाइसराय के उच्च पद पर उसकी नियुक्ति से बहुतों को आश्चर्य हो रहा था।

अपनी नीतिज्ञता का परि

चय वह कई दरबारों में अवश्य दे चुका था। इंग्लैंड के प्रधान सचिव लार्ड

लार्ड लिटन



ब्रेकमफील्ड की राय में इस समय मध्य एशिया की जटिल समस्या को सुलझाने के लिए एक नीतिज्ञ की ही आवश्यकता थी। इसी लिए लार्ड लिटन वाइसराय बनाकर भेजा गया।

**दिल्ली दरबार—**अब ब्रिटिशों ने एक छोटे से द्वीप इंग्लैंड की ही रानी न थी रुम को छोड़कर सारे यूरोप के बराबर, सागर से लेकर हिमालय तक भारत पर अपना आधिपत्य था। बड़े बड़े राजा, महाराजा और नवाब अपने पक्ष में थे। ऐसी दशा में उनके नई उपाधि देने के प्रश्न पर कुछ दिनों में विचार आ गया था। सन् १८७६ में पार्लामेंट की रायने उनके 'कमरहिन्द' की उपाधि दी गई। जनवरी सन् १८७७ में दिल्ली में एक बड़ा भारी दरबार किया गया, जिसमें राजा महाराजाओं ने उनके भारत की सम्राज्ञी स्वीकार किया।

**दक्षिण में अकाल—**जिस समय दिल्ली में यह आनन्द मनाया जा रहा था दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ रहा था। कहा जाता है कि इसमें लाखों मनुष्य जिना अन्न के भूखे मर गये। मध्यप्रान्त और पश्चिमोत्तर प्रान्त में भी अन्न की कमी थी। लार्ड लिटन ने उस वर्ष को दूर कर दिया और कुछ प्रयत्न अवश्य किया। अकाल-पीड़ितों में जो लोग काम करने योग्य थे उनका काम किसी काम में लगाया और बाकी लोगों में अन्न तथा रसदा दे दिया। मदरास में इस धन के खर्च में बड़ा गोलमाल हो रहा था, लार्ड लिटन ने स्वयं जाकर वहाँ प्रबन्ध ठीक किया। सर रिचर्ड स्टुर्टी की प्रयत्नता में अकाल-पीड़ितों की खूब जाच की गई और भविष्य में पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए कुछ रकमा अलग रखना तथा एक नया बर लगाना निर्दिष्ट किया गया। जिन जिलों में अकाल से बड़ी हानि हुई थी, वहाँ नये आरम्भ करने का प्रबन्ध किया गया।

**आर्थिक प्रबन्ध—**सन् १८७६ में लार्ड लिटन ने पश्चिमोत्तर प्रान्त में पिटनेट-गवर्नर सर जान स्टुर्टी को प्रयत्नता बनाया। इसमें मदरास की भी प्रबन्ध ठीक किया। इस समय तब जिन जिन प्रान्तों में उनकी दरभारा थी और देशी राज्यों से सुरावर नमन आता था। इसको देखते हैं

लिए ग्रटक से लेकर महानदी तक इंट-पत्थर और कटीले चूनों की एक दीवाल सी बना दी गई थी, जो 'चुगी की लाइन' कहलाती थी। चारह हजार कर्मचारी इसकी देख-रेख रखते थे और बिना चुगी का नमक बुझने न देने थे। इस ढंग से खर्च अधिक पड़ता था, काम भी पूरा न होता था और कर्मचारी घूस खाते थे। जान स्ट्रैची ने यह भद्दा प्रबन्ध उठा दिया और जिन राज्यों में नमक बनता था, उन्हें कुछ रुपया देकर, उनमें नमक का कुल अधिकार अपने हाथ में ले लिया।

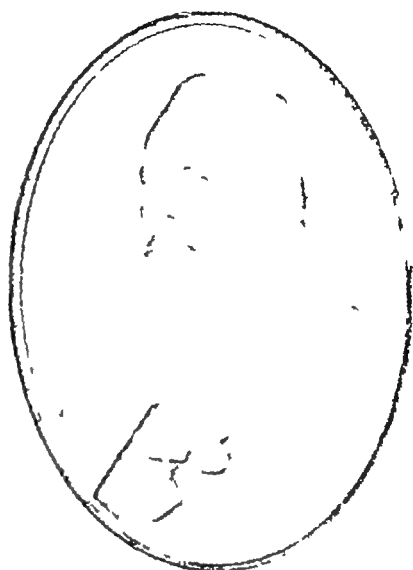
स्वतंत्र व्यापार के नाम पर लकाशायर के कपड़ा बनानेवालों की फिर से सहायता की गई। सन् १८७७ में पार्लामेंट ने यह प्रस्ताव पास किया कि भारतवर्ष में विलायती कपड़े पर चुगी लगाना "उचित व्यापार-नीति" के विरुद्ध है, इसलिए उसको उठा देना चाहिए। गवर्नर-जनरल की कौंसिल के तीन सदस्यों ने केवल सरकारी ग्रामदनी की दृष्टि से इसका विरोध किया, पर लार्ड लिटन ने, कौंसिल के अधिकांश मत को न मानकर, सन् १८७६ में सूती मोटे कपड़े पर से चुगी उठा दी। प्रान्तों के खर्चों के लिए इस समय तक भारत सरकार के खजाने से रुपया दिया जाता था, सर जान स्ट्रैची की सलाह से अब यह नियम बना दिया गया कि उन्हें ग्रामदनी का कुछ भाग दे दिया जाय। इस तरह प्रान्तीय सरकारों को जिम्मेदार और स्वतंत्र बनाने के लिए जिस सिद्धान्त का प्रारम्भ लार्ड मेयो के समय में हुआ था, उसकी वृद्धि की गई।

**अलीगढ़ कालेज**—इस समय तक मुसलमानों में अँगरेजी शिक्षा का प्रचार अधिक नहीं हो रहा था, पर अँगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दुओं की संख्या बराबर बढ़ रही थी और उन्हें सरकारी नौकरियाँ भी मिल रही थीं। लार्ड मेयो के समय में मुसलमानों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबन्ध किया गया था, अब सर सैयद अहमद के सराहनीय उद्योग से 'अलीगढ़ कालेज' खोला गया। इसके लिए हिन्दू और मुसलमान दोनों ने ही चन्दा दिया। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया। यद्यपि वह तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन के पक्ष में

न था, पर भारतवर्ष के हित के लिए वह हिन्दू और मुसलमानों की एकता को नितान्त आवश्यक समझता था। उसका कहना था कि “हिन्दू और मुसलमान भारतवर्ष की दो प्रांति हैं।”

### वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट—

सरकार की नीति से जनता में धीरे धीरे अन्तर्गत फल रहा था। रूप से साध जगता कुछ व्यवहार किया जा रहा था इसकी हिन्दुस्तानी समाचार पत्रों में बड़ी तीव्र आलोचना की जा रही थी। इस पर मनु १८७८ में लार्ड लिटन ने यह धारणा बना दिया कि देशी भाषाओं में प्रकाशित होनेवाले समाचारपत्रों में सम्पादकों को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वे कोई ऐसी बात न



सर लार्ड लिटन

लिखें, जिससे सरकार के प्रति या भिन्न भिन्न जाति तथा धर्मवालों में परस्पर द्वेष पड़े। इस कानून से देशी भाषाओं के समाचारपत्रों का स्वातंत्र्य कम हुआ। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया, परन्तु लार्ड लिटन ने विरोध की नहीं सुनी।

उसको भय था कि अँगरेज दूत की रक्षा करना बड़ा मुश्किल होगा। यह बात ठीक भी थी, उन दिनों काबुल में खूबसे खड़ रही थी कि रूस और इंग्लैंड दोनों अफगानिस्तान को आपस में बाँट खाना चाहते हैं। लार्ड लिटन की दृष्टि में अँगरेजों का यह अपमान किया गया। मन् १८७६ में किलात के खान से उसने कपेटा ले लिया। पहले अफगान-युद्ध में यहाँ से मेना गई थी। इससे अमीर को युद्ध का सन्देह होने लगा। जनवरी मन् १८७७ में उसका दूत सैयद नूरमुहम्मद सन्धि की शर्तें तय करने के लिए पेशावर आया। उसका कहना था कि “अँगरेज राष्ट्र बली है और उसकी शक्ति भी बहुत है। अफगान लोग उसका सामना नहीं कर सकने, परन्तु वे स्वेच्छाचारी तथा स्वतंत्र हैं और उनकी दृष्टि में जीवन की अपेक्षा सम्मान का मूल्य अधिक है।” ऐसी दशा में अँगरेज रेजीडेंट रखना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा करना बड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त अँगरेज हर एक बात पर निगाह रखते हैं। इस सम्बन्ध में उसने स्पष्ट कह दिया कि “हमें आपका विश्वास नहीं है। हमें भय है कि हमारे सम्बन्ध की सब बातें लिखी जायँगी और किसी दिन उन्हीं से हमारे विरुद्ध काम लिया जायगा।”

नूरमुहम्मद की ये बातें लार्ड लिटन की समझ में न आईं। उसको यह सलाह दी जा रही थी कि काबुल और किलात ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में यह बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी शक्ति बहुत बड़ी-बड़ी है, हम खूब सम्य भी हैं और वे हमारे मुकाबले में कमजोर तथा आधे जंगली हैं।<sup>१</sup> नूरमुहम्मद की मृत्यु हो जाने पर दूसरे अफगान दूत के आने की बिना प्रतीक्षा किये हुए ही लार्ड लिटन ने सन्धि का प्रयत्न छोड़ दिया और लार्ड आफ़्लैंड की तरह पेशावर की बातचीत का मनमाना वर्णन इंग्लैंड लिए भेजा। उसने पश्चिमोत्तर सीमा की जातियों को भी भड़काने का प्रयत्न किया और गुप्त रीति से महाराजा काश्मीर को समझा-बुझाकर गिलगिट में कुछ अँगरेजी मेना भेज दी। सीमा पर के अफसरों ने लार्ड लिटन को सचेत भी किया कि इस ढंग से शेरशली के साथ कोई समझौता न होगा। पर उसने

<sup>१</sup> रॉबर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया, पृ० ४३७।

किन्ती की भी न सुनी। वह “अफगान शक्ति को मजोर और कीर गारे  
दिन्न-भिन्न करने पर तुला हुआ था, जेसा कि उमन म्मग म्मीफार म्मिया ह।

इधर तुर्किस्तान के सम्बन्ध में रूस और इंग्लेड की आपस में कुछ  
प्रयत्न हो गई थी। इमलिण्ड इंग्लेड को रुमियो का फिर बड़ा भर  
हा रहा था। इतने ही में ताशकन्द में एक रूसी अफगार शक्ति की  
तरफ दटा। अमीर ने समझा-बुझाकर उसको लाटालन का बड़ा प्रयत्न  
किया। परन्तु रूस ने उसको गद्दी में उतार देने की धमकी दी, इन पर



दर्रा सैवर के अफ्रीदियो को धूम दे दिलाकर चेम्बर्लैन अलीमजिद तक पहुँच गया। वहाँ उसको अफगान गिपाहियो ने बिना अमीर की आज्ञा पाये हुए आगे बढ़ने से रोक दिया, इस पर वह पेशावर लौट आया। लार्ड लिटन की राय में अंगरेजी दूत को यह “जबरदस्ती निकाल देना” था। इसके लिए अमीर से माफी माँगने को कहा गया, तब उसने दूत को काबुल आने की अनुमति दे दी। लार्ड लिटन को इतने पर भी सन्तोष न हुआ और अफगानिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी गई।

इस युद्ध के सम्बन्ध में ‘लिवरल’ दल के नेता ग्लैडस्टन का कहना था कि सन् १८३८ में हमने भूल से अफगानिस्तान के साथ लड़ाई की थी। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है और चूमा के योग्य भी है। परन्तु दूसरी बार बिना किसी समर्थन के फिर हम वैसी ही भूल कर रहे हैं। सब तरह की चेतावनी मिलते हुए भी हम उस भूल को दोहरा रहे हैं। सन् १८४१ में हमारी सेना पर जो विपत्ति पड़ी थी, वह भी फिर कहीं दोहरा न जाय ?

**गडमक की सन्धि**—अंगरेजी सेना ने तीन ओर से अफगानिस्तान में प्रवेश किया। जनरल राबर्ट्स कुर्रम की घाटी से काबुल की तरफ बढ़ा। अफगान लोगो ने अंगरेजों का सामना नहीं किया। कहीं से सहायता न मिलने पर गेरअली रूस भाग गया, वहीं १८७६ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके लड़के यकूबखां ने अंगरेजों के साथ सन्धि कर ली, जिसके अनुसार अफगानिस्तान की विदेशी नीति में उसने अंगरेजों की सलाह लेना और काबुल में अंगरेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। कुर्रम की घाटी अंगरेजों के अधिकार में आ गई और उन्होंने बाहरी आक्रमण से अमीर की रक्षा करने और ६ लाख रुपया मालाना देने का वचन दिया। लार्ड लिटन की नीति की विजय हुई। इंग्लैंड के प्रधान सचिव वेक्सफील्ड की राय में “भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक तथा समुचित सीमा” स्थापित हो गई।

परन्तु यह सन्धि अधिक दिनों तक कायम न रही। अंगरेज रेजिडेंट डेवेनरी, काबुल पहुँचने के कुछ ही दिन बाद मार डाला गया। लार्ड लिटन लिखता है कि “नीति का जाला, जो बड़ी चतुरता और धैर्य के साथ

हुना गया था, महमूदा दूट गया। पिछले युद्ध में मैं न जिन बातों के ख्याल के लिए प्रयत्न किया था, अन्त में वही हुआ।” फिर ये युद्ध छेड़ा गया, यारूज अंगरेजों की गरज से आ गया और काबुल पर अंगरेजों का अधिकार था गया। रजाहेट की हत्या से कोई दोष न होते हुए भी यारूजिया कद कदके भारतवर्ष भेज दिया गया और उसकी जगह पर गेरअली का एक भतीजा अब्दुरहमान काबुल का शमीर बनाया गया। कन्दहार और हरात पर दूसरे यारूजिया का अधिकार मान लिया गया। इस तरह लार्ड लिटन का अफगानिस्तान में विजय करने का उद्देश्य सफल हुआ।



## परिच्छेद १५

### राष्ट्रीयता का जन्म

लार्ड रिपन—वाइसराय के पद पर नियुक्त होने के समय लार्ड रिपन की अवस्था ५३ वर्ष की थी। 'रोमन कैथलिक' होने के कारण उसको वाइस-



रिपन

राय बनाने का इंग्लैंड में बड़ा विरोध किया गया, परन्तु 'लिवरल सरकार' की दृष्टि में लार्ड लिटन की नीति से जो चर्चा हुई थी, उसकी पूर्ति करने के लिए वह सर्वथा उपयुक्त था। भारतवर्ष पहुँचने पर उसके सामने सबसे मुख्य प्रश्न अफगानिस्तान का था। उसकी राय में रूस के आक्रमण का बहाना करके लार्ड लिटन अफगानिस्तान को अंगरेजी राज्य में मिला लेना चाहता था। वह लिखता है कि लार्ड लिटन की दृष्टि काश्मीर पर भी थी और उस 'चाद' को भी छीन लेने का प्रयत्न हो रहा था।<sup>१</sup>

इंग्लैंड-सरकार ने लार्ड लिटन की इस नीति को बिल्कुल बदल देना निश्चित कर लिया था। भारतमन्त्री लार्ड हार्डिंगटन भारतवर्ष की रक्षा के लिए अफगानिस्तान के राज्य को सुदृढ़ बनाये रखना आवश्यक समझता था।

अमीर अब्दुर्रहमान—लार्ड लिटन की नीति में अफगानिस्तान वि-  
भिन्न प्रार निर्वहल हो गया था । अब्दुर्रहमान केवल काबुल का शासक था  
परान पर अंग्रेजों का एक लडका अय्यूबशाह राज्य कर रहा था । कन्दहार  
एक दूसरे ही सरदार के पास था । इस तरह अफगानिस्तान में तीन स्वतंत्र  
शासक थे । अंगरेजों सेना को हटाने के पहले ही इन तीनों में युद्ध छिड़ गया ।  
अय्यूबशाह ने सेवान्त में अंगरेजों सेना को हरा दिया । इस युद्ध में लगभग  
एक हजार अंगरेज मारे गये । इस हार का बदला जनरल गार्डन ने  
कन्दहार में लिया । अय्यूबशाह हारकर फेरान लौट गया । अब अंगरेजों  
पना था अफगानिस्तान में रहना उचित न समझा गया था । सन् १८८१ में  
बाल्ख और कन्दहार जीत लिया, परन्तु इस बार बिना अंगरेजों की सहायता के  
। अब्दुर्रहमान ने हमसे हराकर फारस भाग दिया था । कन्दहार तथा  
गान पर अधिकार कर लिया । कन्दहार के शासक के साथ अंगरेजों की  
लिया, परन्तु हमको समझा-बुझाकर अंगरेजों ने भारत पर हमला किया ।  
इस तरह अब्दुर्रहमान पर अफगानिस्तान का अमीर बन गया ।

समय से मेसूर का शासन बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। टीवण को मलाह देने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सभा भी बन गई है और राज्य की बराबर उन्नति हो रही है।

**देशी समाचारपत्रों की स्वाधीनता**—इंग्लैंड की 'लिविंग्गटन मगर' की दृष्टि में लार्ड लिटन के 'वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट' से देशी भाषाओं में छपनेवाले समाचारपत्रों के साथ बड़ा अन्याय किया गया था। इस सम्बन्ध में पार्लामेंट में भी चर्चा चल रही थी और प्रधान सचिव ग्लेडस्टन इसके रह करने के लिए चिन्तित था। परन्तु वाइसराय की कौन्सिल में इस समय भी बहुत से लार्ड लिटन की नीति के समर्थक थे, इसलिए लार्ड रिपन को इस "वृक्षित कानून" के रह करने में बड़ी चतुरता से काम लेना पड़ा।

**स्थानीय स्वशासन**—अंगरेजी शिक्षा, रेल, तार, डाक और समाचारपत्रों से धीरे धीरे भारतवर्ष के विचारों में बड़ा परिवर्तन हो रहा था। जिस ढंग से इस समय भारतवर्ष का शासन किया जा रहा था, लार्ड रिपन की राय में अब वैसा करना अधिक दिनों तक सम्भव न था। उसका मत था कि यथासम्भव भारतवासियों को शासनप्रबन्ध में कुछ भाग देना चाहिए। इसी उद्देश्य से उसने स्थानीय स्वशासन स्थापित करने का प्रबन्ध किया। इसके अनुसार जिलों और तहसीलों में बोर्ड स्थापित किये गये और उनको देहातो की सफाई, शिक्षा का प्रबन्ध और सड़कें बनाने का काम सौंपा गया। खर्च के लिए वहाँ की ग्रामदानी का कुछ भाग उन्हें दे दिया गया। नामजद करने की अपेक्षा मेंबरों को चुनने पर अधिक जोर दिया गया। जिला या 'डिस्ट्रिक्ट बोर्ड' के सम्बन्ध में लार्ड रिपन की राय थी कि जहाँ तक सम्भव हो इसमें "बड़े साहब" का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए। ऐसा न करने से शासन की शिक्षा देने का उद्देश्य नष्ट हो जायगा और केवल जिलाअफसर की आज्ञा का पालन होने लगेगा। तहसील, तालुका या 'लोकल बोर्ड' को स्थापित करके वह गाँवों की प्राचीन स्वशासन-व्यवस्था को फिर से जागृत करना चाहता था। इस सम्बन्ध में उसका कहना था कि मेरा उद्देश्य अंगरेजी सलाहों के प्रचार करने का नहीं है। हमने देशी स्वशासन

परन्तु वो बहुत कुछ नष्ट कर डाला है, पर तब भी देश के बहुत से भागों में यह थोड़ी बहुत हम समय भी मौजूद है। इसी के आधार पर मैं स्वतंत्रता संग्राम की हमारा को खड़ा करना चाहता हूँ।<sup>१</sup> परन्तु हमारा वह उद्देश्य सफल न हो सका। गांधी के प्राचीन संगठन को अंगरेजी शासन ने दबाने का प्रयत्न कर डाला था। इसके पुनरुद्धार के लिए अंग्रेजों ने एक योजना तैयार की थी।

शहरों में म्युनिसिपलिटियों के अधिकार बढ़ा दिये गये और जनता द्वारा सरकार के चुन जाने का प्रयत्न किया गया। कलकत्ता बम्बई और मद्रास में पहले से ही ऐसा होता था, परन्तु अब यह अधिकार भी शीघ्र ही अन्य भागों का भी मिल गया। लार्ड रिपन की राय थी कि जहाँ तक सम्भव हो म्युनिसिपल बोर्डों का अधिकार सरकारी होना चाहिए, परन्तु बहुत दिनों तक ऐसा न हो सका। जिलों और शहरों में बोर्डों के स्थापित होना तो सामान्य और सर्वोच्च के प्रयत्न में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। पहले यह बहुत प्रमुख भारत-सरकार के हाथ में था। लार्ड मेयो के समय में प्रांतीय सरकारों को, इसमें कुछ भाग दिया गया था, अब कुछ भाग दिया गया था भी मिल गया। इस तरह धीरे धीरे जिम्मेदारी हममें बँट गई।

हिन्दुस्तानियों को “वाते करने और काम करने” के भेद का पता लग सकेगा।<sup>१</sup> कुछ दिनों तक इन बोर्डों का काम ठीक ठीक न चला, पर वह इसमें निगम नहीं हुआ। उसकी राय में इनके स्थापित करने का मंत्र में बड़ा भारी लाभ यह था कि जनता की “राजनीति और शासन में शिक्षा” हो रही थी।

**आर्थिक सुधार**—लार्ड रिपन भी स्वतंत्र व्यापार-नीति का पनपाती था। सन् १८८२ में उसने नमक, शराब और अस्त्र-गन्ध द्रव्यों की मर विलायती माल पर चुगी उठा दी। इसमें विलायत के व्यापारियों का ही अधिकतर लाभ हुआ। पर साथ ही साथ उसको भारत की दृष्टि जनता का भी ध्यान रहा और उसने नमक-कर बढ़ा दिया। देश भर में इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी करने की बहुत दिनों से बात चल रही थी। इसके विरोधियों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार का नुकसान होगा। खेती में जो कुछ आमदनी बढ़ेगी, उसमें सरकार को कोई हिस्सा न मिलेगा। बीस तीस वर्ष का बन्दोबस्त कर देने से खेती में उन्नति करने का काफी समय भी मिल जाता है और सरकार की भी कोई हानि नहीं होती है। इसके प्रतिकूल इस्तमरारी बन्दोबस्त के समर्थकों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार को बार बार बन्दोबस्त का खर्च न उठाना पड़ेगा, अपने लाभ की दृष्टि से खेती की उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा और प्रजा की दशा अच्छी होने से अन्य कर्तों द्वारा सरकार की हानि भी पूरी हो जायगी। कुछ लोगों का तो कहना था कि इस्तमरारी बन्दोबस्त हो जाने से अफाँलो की अधिक सम्भावना न रहेगी, क्योंकि जनता का ध्यान खेती की ओर अधिक जायगा। यह बात भले ही ठीक न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि जमीन का लगान बहुत ज्यादा लिया जाता था। सन् १८७६ में विलियम हटर का कहना था कि दक्षिण में किसानों को इतना भी नहीं बचता कि वे साल भर तक अपने कुटुम्ब का पालन कर सकें। सन् १८८१ में लार्ड नार्थब्रुक ने भी माना था कि “जमीन का लगान बहुत ज्यादा लिया जाता है।”

सन् १८६० में हंगेलेड-सरकार ने इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था, परन्तु इस सम्बन्ध में भारत-सरकार में प्रसार लिम्बा-पड़ी होती रही। लार्ड मेयो न इसका बड़ा विरोध किया। अन्त में सन् १८८३ में यह विचार त्याग दिया गया। लार्ड रिपन की राय थी कि जिन जिलों की पूरी पैमायश करके मालगुजारी बांधी गई है, उन्हें यह प्रचन दे देना चाहिए कि सिवा दाम बढ़ जान के मोरे को छोटकर और कमी दाद हुआफा न किया जायगा। इस तरह एक प्रकार में न्यायी बन्दोबस्त भी टा जायगा और सरकार की कोई हानि भी नहीं होगी। परन्तु भारतसचिव न इसी इस राय को नहीं माना। लार्ड रिपन न कियाता की दगा मुशान था भी प्रयत्न किया। बंगाल और अवध में जमीन्दार मिलाना या बार बार बदल करके तंग किया करते थे। इनके हक का मरायी प्रान के लिए अत दा वानुन पेश किये, परन्तु इसके समय में ये पाव न हो सक। अत-वागमाना में काम करनेवालों की रक्षा के लिए भी हमन प्रदन्त किया और वन वानुन बना दिया कि लटकों में ना घटा गेज न प्रतिक वान न किया जाय।

पेशा, सभी बातों का उल्लेख किया गया। तब से हर दसवें वर्ष यह गणना होती है। इसकी रिपोर्टें से देश की बहुत सी बातों का पता चलता है।

**इंडियन सिविल सर्विस**—सन् १८३३ के आज़ापत्र तथा सन् १८५८ में महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र में, भारतवासियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का जातिभेद न रखा जायगा। परन्तु वास्तव में जितने बड़े बड़े ओहदे थे, उन पर अंगरेज ही रखे जाते थे। भारतवासियों को जो वचन दिये गये थे, उनका मनमाना अर्थ लगाया जाता था। कहा जाता था कि सब छोटी छोटी नौकरियाँ हिन्दुस्तानियों के ही हाथ में हैं, सरकारी नौकरियों में अंगरेजों की अपेक्षा उनकी संख्या कहीं अधिक है, इस तरह प्रतिज्ञाओं का पालन हो रहा है। सिविल सर्विस के कुछ पदों पर भारतवासियों को नियुक्त करने के नियम बनाने के लिए सन् १८७० में इंग्लैंड से भारत-सरकार को लिखा गया था, परन्तु उसने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सन् १८७८ में लार्ड लिटन ने 'स्टेट्यूटरी सिविल सर्विस' नाम की एक श्रेणी खोली, जिसमें प्रान्तीय सरकार की सिफारिश पर बड़े घराने के लोगो को रखना निश्चित किया गया। लार्ड लिटन का मत था कि "उन प्रतिज्ञाओं को, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है और जो वास्तव में बिना सोच-समझे कर दी गई हैं, अधिक स्पष्ट कर देना चाहिए। उनको नियमों से भले ही जकड़ दिया जाय, पर आवश्यक सीमाओं के अन्तर्गत उन्हें सत्य बनाना चाहिए।"

इस तरह लार्ड रिपन के आने पर सिविल सर्विस में घुसने के दो तरीके थे। एक तो लार्ड लिटन के बनाये हुए नियमों द्वारा नामजदगी से और दूसरे 'सिविल सर्विस परीक्षा' द्वारा, जो इंग्लैंड में होती थी। नामजदगी में शिक्षा और योग्यता की अपेक्षा सामाजिक पद पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मध्य श्रेणी के उच्च शिक्षा-प्राप्त लोगों के साथ यह बड़ा अन्याय होता था। इसी लिए लार्ड रिपन इसको पसन्द न करता था। परीक्षा के लिए पहले २१ वर्ष की अवस्था का नियम था, लार्ड लिटन के समय में १६ वर्ष की अवस्था का नियम कर दिया गया था। यह नियम भी भारतवासियों

को परीक्षा में अलग रखने के उद्देश्य में ही बनाया गया था। लार्ड रिपन इस परीक्षा में बैठने में भारतवासियों को एकदम रोक देना चाहता था। लार्ड रिपन का तो यहाँ तक कहना है कि उसको "उच्च शिक्षा-प्राप्त भारत-वासियों में घृणा थी।" लार्ड रिपन २१ वर्ष की अवस्था में फिर निग्रह मानना चाहता था। सिविल सर्विस की परीक्षा भारतवर्ष में भी हुई थी, उसकी यह भी इच्छा थी। परन्तु वह एक एम सगट में पढ़ गया कि इस सम्बन्ध में वह कुछ भी न कर सका। उसकी पूरी शक्ति न इनका पार विरोध किया।

**इल्लवर्ट बिल**—इस समय तक बम्बई, मद्रास और सन्ध्या का

छात्र अथवा स्थानों के हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेट और जजों को सिविल नगर अभियुक्त का एकदम करन का अधिकार नहीं था। अब यह हिन्दुस्तानी सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके आ गया और यह जज की जिला मजिस्ट्रेट होनेवाले थे। कुछ हिन्दुस्तानी 'समान जज' के पास भी पहुँचनेवाले थे। पद में अंगरेजों के समान होते हुए भी इनका एक विशेषता नहीं उचित न जान पड़ता था। महाराजा ज्योतीन्द्रमोहन टाटा ने सरकार को यह भी लेजिस्लेटिव कौंसिल में इस प्रश्न को उठाया। लार्ड रिपन भी न्याय के मामला में जातिभेद रखना बिल्कुल अनुचित समझता था। इसी विचार के कारण ही इस भेद को उठाने के लिए सरकार की छोर में बान्ना मन्त्रि इल्लवर्ट ने एक बिल पेश किया। इसमें अंगरेजों की कोई हानि न हो, परन्तु भी इनके न समानाचार विरोध किया। वाइसरॉय का खुले तौर पर सम्मान किया गया। सरकारी अफसरों के अतिरिक्त अन्य अंगरेजों ने इसके साथ जना उठा लिया। अंगरेज अक्सर जाँच से बाहर हो गये। 'द ग्लोब' ने लिखा कि 'भारतवर्ष में यदि किसी को अधिकार है, तो वे अंगरेज के भारत-वासियों को कोई अधिकार नहीं हैं।' "इस तरह हिन्दुस्तानियों का स्वयं पर



बिठलाना” भारतवर्ष में रहनेवाले गोरे सहन न कर सके और उन्होंने गोरी सेना को भी भड़काने का प्रयत्न किया।

लार्ड रिपन को कभी सन्देह न था कि इम वान पर इतना धीर आन्दोलन उठेगा। यदि वह ऐसा जानता तो शायद इम प्रश्न को उठाता ही नहीं। पर एक बार ऐसा प्रस्ताव करके उसे वापस लेने में, रिपन की राय में, भारतवासियों को यह दिखलाना था कि महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र में की हुई प्रतिज्ञाओं में कुछ तत्त्व नहीं हैं। परन्तु यह आन्दोलन बढ़ता ही गया और अन्त में लार्ड रिपन को भी इसके आगे सिर झुकाना पड़ा। कलकत्ता की सड़को पर उपद्रव होने की नौबत देखकर लार्ड रिपन ने समझौता कर लिया। गोरे अभियुक्तों को ‘जूरी’ की सहायता से, जिसमें आधे अंगरेज या अमरीकन हों, मुकदमा कराने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह देखने के लिए तो जातिभेद उठा दिया गया, क्योंकि जूरी की सहायता से मुकदमा करने का अधिकार हिन्दुस्तानी और अंगरेज जजों को समान रूप से दे दिया गया। पर वास्तव में यह भेद बना रहा, क्योंकि हिन्दुस्तानियों को जूरी की सहायता से मुकदमा कराने का कोई अधिकार न दिया गया।

**उदार नीति**—लार्ड रिपन इंडिया काउंसिल के हस्तक्षेप को पसन्द न करता था। उसका कहना था कि “भारतवर्ष को लिबरल सरकार से लाभ ही क्या हो सकता है, यदि वह हाथ-पैर बांधकर कुछ ऐसे बड़बूत आदमियों के हवाले कर दिया जाय, जिनकी शक्तियां बुढ़ापे से नष्ट हो गई हैं, जिन्हें बिना किसी जिम्मेदारी के अच्छी तनखावे मिलती हैं और जिनको उन लोगों के प्रस्तावों की आलोचना करने तथा उनके काम में बाधा डालने में आनन्द आता है, जिन्हें भारतवर्ष की वास्तविक दशा का पूरा ज्ञान है और जिनके ऊपर देश का अच्छा शासन करने की पूरी जिम्मेदारी है ?” भारतवर्ष की आमदनी से इंग्लैंड का लाभ उठाना वह अनुचित समझता था। सन् १८८२ में विद्रोह शान्त करने के लिए भारतवर्ष से जो सेना

मिन्न भेंजी गई थी, उसका स्वर्च प्रधान मन्त्रि ग्लैडस्टन भारतवर्ष में लेना चाहता था, क्योंकि उसकी राय में इंग्लैंड पर काफी द्रोह था और मिन्न को शान्त स्वर्च से स्वेज की नहर सुरक्षित रह सकता थी। इस पर लाइ रिपन ने भारतमन्त्रि को लिखा कि इंग्लैंड में पालमिट है इवलि, प्रतिक रूपया मानन में भय होता है। भारतवर्ष पर “अनाद्वय द्रोह” लाइ इन में कोई पूछनेवाला नहीं है, इसी लिए ऐसा किया जा रहा है। मरी राय में यह न्याय नहीं बल्कि मन्त्रिमंडल की ग्यारह जरूरी है। लिम्ल डल का नेता होकर ग्लैडस्टन इसका समर्थन कर रहा था लाइ रिपन को इसका बड़ा दुःख था। अन्त में उसकी बात मानकर इंग्लैंड सरकार ने आधा स्वर्च देना स्वीकार किया।”

भारतवर्ष की रक्षा के सम्बन्ध में उसका मत था कि यह के शासन का अंग निर्मल है। यह बात ठीक है कि जनता में अमान्यता मान्यता हमारे विरुद्ध भटका सकते हैं। इसको दशक या मनुष्य रूप में मान्यता कि देश का शासन उत्तम रीति से किया जाय और यदि नहीं तो देश भर में उन्नति के चिह्न दिखलाई दे राह, जगता में शासन-विचार में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। स्थिति निम्न-वैत दली गति में, परन्तु यदि बुद्धि और साहस से काम लिया जाय, तो हमसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। येते दिनों के “न्याय और सत्यपूर्ण शासन” से हमारा प्रभाव जनता के हृदय पर जम जायगा और उसका हम पर विश्वास बढ़ा देगा। शासन में सन्तोष बट जायगा। ऐसा करने से अफगानिस्तान की सीमाओं पर सत्ता रखन की अपेक्षा हम रूसियों के आक्रमण से भारतवर्ष की रक्षा कर सकेंगे।”

लाइ रिपन का कहना था कि भारत-सरकार के मानने से निर्मल है। एक तो उनकी नीति है, जिन्होंने समाचारपत्रों के सम्बन्ध में

है, शिवा की उन्नति की है, अधिक सग्या में भारतवासियों को सब तरह की नौकरियाँ दी हैं और जिन्होंने म्मशामन की वृद्धि का समर्थन किया है। दूसरी नीति उन लोगों की है, जो समाचारपत्रों की म्मनत्रता का तिरस्कार करते हैं, जो शिवा की उन्नति से डरते हैं और जिन्हें शासन में भारतवासियों को जरा सा भी भाग देने में जलन होती है। “इन दो नीतियों में से हमें चुनना पड़ेगा। एक का अर्थ उन्नति और दूसरी का अर्थ दमन है। लार्ड लिटन ने दूसरी को और मैंने पहली नीति को चुना।”<sup>१</sup>

**लार्ड रिपन का इस्तीफा**—सन् १८८४ में लार्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया। जहाँ तक वन पड़ा उसने भारतवर्ष का हित करने के लिए बराबर प्रयत्न किया। हर एक बात में उसको भारतवासियों का ध्यान रहता था और शासन में वह किसी प्रकार का जातिभेद पसन्द न करता था। इसके लिए उसको अपने देशवासियों के मुख से बहुत सी बुरी-भली बातें भी सुननी पड़ीं। चलते समय भारतवासियों ने अपनी कृतज्ञता का पूरा परिचय दिया। जगह जगह पर उसको मानपत्र दिये गये और मीलों तक लायों आदमियों ने जयध्वनि से उसकी बिदाई की। कुछ अँगरेज इतिहासकारों का कहना है कि उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं। सम्भव है यह ठीक हो, पर जैसा कि असेंकाइन पेरी ने लिखा है, उसमें “दिल था, जिसका हिन्दुस्तानी सबसे अधिक आदर करते हैं।” सर कालविन का विश्वास था कि लार्ड रिपन का भारतवासियों के हृदय पर इतना अधिक प्रभाव था कि वह जो चाहे कर सकता था। पंजाब के सर साहबदयाल ने ठीक कहा था कि लार्ड रिपन सहस्रों सैनिकों के बराबर है, क्योंकि भारतवासियों का उस पर विश्वास है और वे उसको चाहते हैं। यदि भारतवर्ष में कभी अँगरेजों पर विपत्ति पड़े, तो उन्हें लार्ड रिपन को भेजना चाहिए।<sup>२</sup>

१ उक्त, लार्ड रिपन, जि० २, पृ० ९४।

२ वही, पृ० १६५-६६।

“मेरा देश एक बेचारे बरूरे की तरह है, जिन पर भालू (रूस) और गेर (इंग्लैंड) दोनों की निगाहे जमी हुई हैं। उसका डेग्वर ही रक्षक है।” इसी लिए वह पजडेह छोड़ देने के लिए भी राजी हो गया। इस पर रूस से समझौते की बातचीत होने लगी।

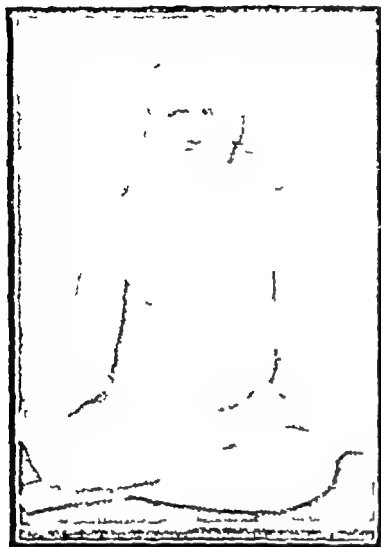
लार्ड डफरिन ने भी बड़ी चतुरता से काम लिया। उसने अमीर का बड़ा सम्मान किया और उसको रुपये तथा अस्त्र-गद्य की सहायता देकर काबुल वापस भेज दिया। अमीर किसी प्रकार की सैनिक सहायता न चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इसमें फिर झगडा होगा। लार्ड डफरिन कुछ इजीनियरों को भेजना चाहता था, परन्तु अमीर ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। लार्ड डफरिन भी सेना भेजने के लिए उससे न था, यदि अमीर चाहता तो उसको सेना भेजनी पड़ती, क्योंकि बाहरी आक्रमण से अफगानिस्तान की रक्षा करने का लार्ड रिपन वचन दे चुका था। परन्तु इसका अवसर न आया। सन् १८८७ में रूस से समझौता हो गया और पजडेह पर उसका अधिकार मान लिया गया। इस घटना का भारतवर्ष पर यह प्रभाव पड़ा कि उसके खजाने का बहुत सा रुपया युद्ध की तैयारी में उड़ गया और सेना की संख्या बढ़ गई।

**बर्मा का तीसरा युद्ध**—सन् १८७६ में बर्मा के राजा थीवा के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर अंगरेजी राजदूत वापस बुला लिया गया था। तब से बर्मा में अंगरेजों को पूरी व्यापारिक सुविधाएँ नहीं मिल रही थी और व्यापारी लोग बर्मा को भी अंगरेजी राज्य में मिला लेने के लिए कह रहे थे। थीवा जर्मनी, इटली और फ्रांस से सन्धि की बातचीत कर रहा था। सन् १८८५ में एक फ्रांसीसी राजदूत भी मंडाले आया था और एक बैंक स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा था। बर्मा दरबार में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व अंगरेजों को खटक रहा था और वे लडाई का कोई न कोई बहाना ढूँढ रहे थे। इन्हीं दिनों एक अंगरेजी व्यापारिक कम्पनी पर थीवा ने २३ लाख रुपया जुरमाना कर दिया। यह अच्छा बहाना मिल गया। रगून में दस हजार सेना एकत्र करके थीवा को इस मामले की अंगरेज पंचो द्वारा जांच

दस ही दिन में युद्ध समाप्त हो गया। बर्मियों ने युद्ध की कोई तैयारी न की थी, उन पर सहसा आक्रमण कर दिया गया था। जनवरी सन् १८८६ में उत्तरी बर्मा भी अँगरेजी राज्य में मिला लिया गया और थीवा केंद्र करके भारतवर्ष भेज दिया गया, जहाँ खागिरि में वह बहुत दिनों तक जीवित रहा। इस तरह विजय तो हो गई पर बर्मा को गान्त करने में बहुत समय लगा। चार पाँच वर्षों तक बहुत से लुटेरे बड़ा उपद्रव मचाते रहे, पर धीरे धीरे गान्ति स्थापित हो गई और अँगरेजी शासन चल पड़ा। इतिहासकार राबर्ट्स की राय में बर्मा के साथ “जबरदस्ती और निष्ठुरता” का व्यवहार किया गया। यह मानते हुए भी कि थीवा अत्याचारी था, उसके राज्य को छीन लेने का भारत-सरकार को कौन सा अधिकार था? वह स्वतंत्र शासक था और चाहे जिसके साथ सन्धि कर सकता था। फ्रांसीसियों का ‘इंडो-चैना’ भी उसके राज्य से मिला हुआ था। यदि उसके कहने पर फ्रांसीसी अपना प्रभाव वहाँ जमा रहे थे, तो फिर अँगरेजों को जलन क्यों होती थी? जैसा हक अँगरेजों का था वैसा ही फ्रांसीसियों का, इसमें बिगडने की कौन सी बात थी? परन्तु स्वार्थ के आगे न्याय की कौन सुनता है? निर्बल पर सबल का सभी अधिकार रहता है। दक्षिणी बर्मा से उत्तरी बर्मा अधिक उपजाऊ है, वहाँ खूब धन कमाने की सम्भावना थी। युद्ध छिडने के पहले ही लार्ड डफरिन ने लिखा था कि यदि फ्रांसीसी उत्तरी बर्मा में अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करे तो उसको बिना किसी संकोच के अँगरेजी राज्य में मिला लेना चाहिए।<sup>१</sup>

**देशी राज्य—**सन् १८८६ में ग्वालियर का किला सिन्धिया को वापस कर दिया गया। काश्मीर के शासन में रेजीडेंट प्लाउडन बहुत हस्तक्षेप करता था। सन् १८८८ में लार्ड डफरिन ने उसको वापस बुला लिया। वाइस-राय के इन कार्यों का देशी राज्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जब रूस के साथ युद्ध छिडनेवाला था, तब बहुत से राज्यों ने सहायता करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। समय पड़ने पर सरकार की सहायता करने के लिए बड़े बड़े

स्थान पर इसकी शाखाएँ खुल गईं। बहुत से हिन्दुओं को इसने ईमाई और मुसलमान होने से बचाया। समाजसुधार की ओर इसने विशेष ध्यान



स्वामी दयानन्द

न्यूयार्क नगर में मैडम ब्लैवट्स्की और कर्नेल अलकाट ने 'थियोसोफिकल सोसायटी' स्थापित की। इस सोसायटी ने सब धर्मों की एकता और सत्यता पर जोर दिया। स्वामी दयानन्द जी के आमंत्रित करने पर सन् १८७६ में ये दोनों भारतवर्ष आये। इन्होंने प्राच्य शास्त्रों की महत्ता दिखलाते हुए यह बतलाया कि भारतवर्ष का उद्धार उसी के विचारों द्वारा हो सकता है। इस सोसायटी का मुख्य कार्यालय मदरास के निकट अदयार में स्थापित हुआ। सन् १८६३ में मिसेज वेसेट के आ जाने से इसका ज़ोर बहुत बढ़ गया। अंगरेज़ी पढ़े हुए लोगों को भी, जो पाश्चात्य सभ्यता पर सुग्ध हो रहे थे, यह ज्ञात होने लगा कि उनके देश की प्राचीन सभ्यता और आचार-विचारों में भी कुछ तत्त्व हैं। इस सोसायटी ने समाजसुधार और शिक्षा को भी अपनाया और तत्कालीन शिक्षा को "धर्म तथा राष्ट्रीयता के भावों के विरुद्ध" बतलाया।

दिया और विधवा-विवाह का प्रचार किया। प्राचीन ढंग से शिक्षा देने के लिए इसने गुरुकुल स्थापित किये। उत्तरी भारत में इसने वही काम किया, जो ब्रह्मसमाज ने बंगाल में किया। केवल भेद इतना ही था कि ब्रह्मसमाज ने पाश्चात्य ढंग को अपनाया, परन्तु यह पूरा भारतीय बना रहा। इस समय भी समाजसुधार और शिक्षा के लिए आर्य-समाज बहुत कुछ कर रहा है। इसके प्रचारक उपनिवेगों तक में पहुँच गये हैं।

### थियोसोफिकल सोसायटी—

जिस साल भारतवर्ष में आर्यसमाज स्थापित हुआ, उसी साल अमरीका के



के आध्यात्मिक विचारों की उन्नति को सिद्ध कर दिया और देश के सामने समाजसेवा का आदर्श रखा। इस तरह भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के भावों का उदय हुआ।<sup>१</sup>

**इंडियन नेशनल कांग्रेस**—इन विचारों का राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ रहा था। अपने पूर्व गौरव का पता लगने पर राजनैतिक पराधीनता खटक रही थी। पाश्चात्य राष्ट्रों के इतिहास के अध्ययन में आगे खुल रही थी। समाचारपत्रों की संख्या बढ़ रही थी और उनमें धीरे धीरे लोकमत जाग्रत हो रहा था। कुछ उदार-हृदय अंगरेज भी भारतवासियों को उत्साहित कर रहे थे। जब से भारत का अंगरेजों से सम्बन्ध हुआ था, तभी से बराबर कुछ अंगरेज ऐसे अवश्य रहे हैं, जिन्हें अपने देश के साथ साथ भारतवर्ष के हित का भी ध्यान रहा है। फ्रांसिस, बर्क, मालक्रम, मनरो, हेनरी लारेंस ऐसे लोगों का स्थान स्थान पर उल्लेख किया जा चुका है। इन दिनों जान ब्राइट भारत-सरकार की तीव्र शब्दों में आलोचना कर रहा था। भारतवर्ष का बराबर पक्ष लेने के कारण पार्लामेंट में हेनरी फास्ट, 'भारतीय सदस्य' के नाम से प्रसिद्ध था। इलवर्ट विल के झगड़े से चार्ल्स ब्रैंडला भी भारतीय प्रश्नों में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था। भारतवर्ष में भी कुछ अंगरेज अफसर भारतवासियों की सहायता करने के लिए चिन्तित थे। सिपाही-विद्रोह के समय से इटावा के कलेक्टर ह्यूम साहब बड़े लोकप्रिय हो गये थे। बंगाल में सर हेनरी काटन और बम्बई में सर विलियम वेडरबर्न अपने उदार विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। कई एक सुशिक्षित भारतवासी देश की तत्कालीन स्थिति का अनुभव कर रहे थे। इनमें बम्बई के दादाभाई नौरोजी, फीरोजशाह मेहता, जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे तथा काशी नाथ त्र्यम्बक तेलंग, बंगाल के बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा आनन्दमोहन बोस, बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह, मदरास के माननीय सुब्रह्मण्य



राष्ट्रीय सभा बन गई। कांग्रेस का इतिहास वामन में भारतवर्ष के स्वतंत्रता युद्ध का इतिहास है।

**डफरिन की नीति**—सन् १८८८ में लार्ड डफरिन इस्तीफा देकर वापस चला गया। भारतवर्ष आने पर उसने इस बात को देख-लाने का प्रयत्न किया था कि वह लार्ड रिपन की नीति का अनुकरण करना चाहता है। अन्त तक वह यही कहता भी रहा, पर दोनो की नीति में बड़ा अन्तर था। लार्ड रिपन की नीति से असन्तुष्ट अंगरेजों को सन्तुष्ट करने का उसे सब से अधिक ध्यान था। शासन में शिक्षित भारतवासियों के सहयोग की आवश्यकता को वह समझता था और उसने कौन्सिलों के सुधार के लिए भारतसचिव को लिखा भी था, पर कांग्रेस की नीति और उसके कार्यक्रम को वह पसन्द न करता था। कांग्रेस को राजनैतिक संस्था बनाने की सलाह देने में उसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि सरकार को उसके द्वारा देश की जनता के मन का पता लगता रहे। उसकी राय थी कि थोड़ा-बहुत सुधार करके दस पन्द्रह वर्ष के लिए “सार्वजनिक सभाओं और उत्तेजित करनेवाली वक्तृताओं को बन्द कर देना चाहिए।” वह भारतवर्ष को प्रतिनिधि-शासन के योग्य न समझता था। उसका मत था कि “इंग्लैंड को अपना शासनाधिकार कभी न छोड़ना चाहिए।”<sup>१</sup>

**लार्ड लैसडौन**—सन् १८८८ में लार्ड लैसडौन वाइसराय नियुक्त किया गया। यह भी कनाडा का गवर्नर-जनरल रह चुका था और कुछ दिनों तक भारतवर्ष का उपसचिव भी रहा था। वाइसराय पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परन्तु लैसडौन भारतवर्ष में ६ वर्ष के लगभग रहा।

**सीमाओं की रक्षा**—अफगानिस्तान और भारतवर्ष की सीमाओं के बीच २५००० वर्ग मील के लगभग पहाड़ी भूमि है। इसके दक्षिण में बिलोचिस्तान और उत्तर में चितराल है। इन्हीं पहाड़ियों में से अफगानिस्तान

राष्ट्रीय सभा बन गई। कांग्रेस का इतिहास वामन में भारतवर्ष के स्वतंत्रता-युद्ध का इतिहास है।

**डफरिन की नीति**—सन् १८८८ में लार्ड डफरिन इन्तीफा देकर वापस चला गया। भारतवर्ष आने पर उसने हम बात को दिखलाने का प्रयत्न किया था कि वह लार्ड रिपन की नीति का अनुकरण करना चाहता है। अन्त तक वह यही कहना भी रहा, पर डेनो की नीति में बड़ा अन्तर था। लार्ड रिपन की नीति से असन्तुष्ट अंगरेजों को सन्तुष्ट करने का उसे सब से अधिक ध्यान था। शासन में शिक्षित भारतवासियों के सहयोग की आवश्यकता को वह समझता था और उसने कौंसिलों के सुधार के लिए भारतसचिव को लिखा भी था, पर कांग्रेस की नीति और उसके कार्यक्रम को वह पसन्द न करता था। कांग्रेस को राजनैतिक संस्था बनाने की मलाह देने में उसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि सरकार को उसके द्वारा देश की जनता के मन का पता लगता रहे। उसकी राय थी कि थोड़ा-बहुत सुधार करके दस पन्द्रह वर्ष के लिए “सार्वजनिक सभाओं और उत्तेजित करनेवाली वक्तृताओं को बन्द कर देना चाहिए।” वह भारतवर्ष को प्रतिनिधि-शासन के योग्य न समझता था। उसका मत था कि “इंग्लैंड को अपना शासनाधिकार कभी न छोड़ना चाहिए।”<sup>१</sup>

**लार्ड लैंसडौन**—सन् १८८८ में लार्ड लैंसडौन वाइसराय नियुक्त किया गया। यह भी कनाडा का गवर्नर-जनरल रह चुका था और कुछ दिनों तक भारतवर्ष का उपसचिव भी रहा था। वाइसराय पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परन्तु लैंसडौन भारतवर्ष में ६ वर्ष के लगभग रहा।

**सीमाओं की रक्षा**—अफगानिस्तान और भारतवर्ष की सीमाओं के बीच २५००० वर्ग मील के लगभग पहाड़ी भूमि है। इसके दक्षिण में ब्रिलो-चिम्तान और उत्तर में चितराल है। इन्हीं पहाड़ियों में से अफगानिस्तान

जाने जाने के मार्ग है। यहाँ के निवासी नाममात्र के लिए अमीर की अधीनता स्वीकार करते थे, पर वास्तव में वे स्वतंत्र थे। ये लोग भारतवर्ष की पश्चिमोत्तर सीमा पर बराबर लूट-पाट किया करते थे। इनके सम्बन्ध में भारत-सरकार की क्या नीति होना चाहिए, यह कुछ निश्चित न था। एक दल 'आगे बढ़ने की नीति' के पक्ष में था। उसका कहना था कि रेलें चलाकर और चौकियाँ कायम करके अफगानिस्तान की सीमा तक पहुँच जाना चाहिए। इसके प्रतिकूल दूसरा दल था, जो गिन्ध नदी की सीमा से ही सन्तुष्ट रहना चाहता था। इसका कहना था कि इन पहाड़ी जातियों को दबाये रखने में बड़ा खर्च पड़ता है और अफगानिस्तान के अमीर को भी भारत-सरकार की नीयत पर सन्देह होता है।

लार्ड लैमडौन के समय में 'आगे बढ़ने की नीति' के अनुसार गिलगिट पर अधिकार जमाने का प्रयत्न हो रहा था। उसके व्यवहार से भी अमीर अब्दुर्रहमान चिढ़ा हुआ था। वाइसराय के "आदेशपूर्ण" पत्रों को, जिनमें शासनप्रबन्ध ठीक करने के लिए उसको लिखा जाता था, वह पसन्द न करता था। सन् १८६२ में एक अँगरेज दूत चित्तराल भेजा गया। इससे अमीर का सन्देह और भी बढ़ गया। परन्तु सर हेनरी मार्टिंजर डुराड की चतुरता से अमीर का भ्रम दूर हो गया और अँगरेजों के साथ मित्रता का सम्बन्ध हो गया। डुराड अपने साथ किसी सरञ्जक को भी नहीं ले गया, जिसमें अफगानिस्तान-निवासियों को किसी प्रकार का सन्देह न हो। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। सीमा के बहुत से झगड़े तय हो गये और अमीर को जो मालाना रकम दी जाती थी, वह बढ़ा दी गई। कुछ भूमि भी अमीर को दी गई, जिनके बदले में उसने सीमा पर बसनेवाले अफ्रीदी, बजीरी तथा अन्य जातियों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। अमीर इंग्लैंड की नीति का खूब सम्मत्ता था। उसका कहना था कि मित्रता दिखलाते हुए भी इंग्लैंड अपने मतलब से कभी नहीं चूकता। जो कुछ रुख ने लिया है, उसमें भी अधिक इस मित्र ने लिया है।

**काश्मीर**—महाराजा गुलाबसिंह के लड़के महाराजा रणवीरसिंह को इस बात का बराबर भय था कि किसी दिन काश्मीर अँगरेजी राज्य में अवश्य

मिला लिया जायगा। वह कहा करता था कि उसके एक ओर रूस, दूसरी ओर अफगानिस्तान और तीसरी ओर अंगरेज हैं। इनके बीच में पड़कर उसका राज्य अवश्य पिसेगा। लार्ड रिपन ने लिखा ही था कि लार्ड लिटन इस चाँद को अंगरेजी राज्य में मिलाने का प्रयत्न कर रहा था। परन्तु रणवीरसिंह के समय में अंगरेजों की दाल न गल सकी। सन् १८८५ में उसके मरने पर प्रतापसिंह गद्दी पर बैठा। उसमें उतनी योग्यता और दृढ़ता न थी। उसके गद्दी पर बैठते ही पहला काम यह किया गया कि काश्मीर दरबार में अंगरेज रेजीडेंट रख दिया गया। गुलाबसिंह के साथ जो सन्धि हुई थी, उसमें रेजीडेंट रखने की कोई बात भी न थी। महाराजा प्रतापसिंह ने इसका विरोध भी किया, पर उसकी कुछ भी न सुनी गई। रेजीडेंट प्लाउडन ने शासन की हर एक बात में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर सन् १८८८ में लार्ड डफरिन ने उसको दूसरी जगह बदल दिया।

पर तब भी महाराजा प्रतापसिंह को चैन नहीं लेने दिया गया। सन् १८८६ में उस पर अंगरेजों के विरुद्ध रूस से पत्र-व्यवहार करने, प्रजा पर अत्याचार करने तथा भोग-विलास में राज्य का खजाना उड़ाने के अपराध लगाये गये और उससे एक पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये गये, जिसके अनुसार उसने कुल शासन कुछ सरदार तथा अंगरेज अफसरों की एक कौंसिल को सौंप दिया। उस पर जो अपराध लगाये गये, उनकी कभी जांच नहीं की गई। महाराजा प्रतापसिंह का कहना था कि उसने रूस से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया था, शासन में भी वह बहुत से सुधार करना चाहता था, परन्तु रेजीडेंट के हस्तक्षेप के कारण कुछ न हो सका। उसके शासन से प्रजा को कोई शिकायत न थी, न उसके अत्याचार ही का कोई प्रमाण बतलाया गया। शिकायत करना तो दूर रहा, जम्मू के डोगरों का कहना था कि अंगरेज रेजीडेंट की आज्ञा पर चलनेवाली कौंसिल के इनामों से अपने राजा द्वारा लूटा जाना कहीं अच्छा है। मिस्टर विनगेट ने भी, जिसकी राय से भारत-सरकार ने अपना मत स्थिर किया था, माना है कि महाराजा दरिद्रों पर सदा दया करता था, जमीन के मामलों में बड़ी दिलचस्पी लेता था और अफसरों के

अत्याचारों से काश्तकारों की रक्षा करता था। सन् १८८८ में स्वयं लार्ड डफरिन ने लिखा था कि “सुधार के सम्बन्ध में बहुत कुछ उन्नति की गई है।” ऐसी दशा में प्रजा पर अत्याचार का अपराध सिद्ध नहीं होता। खजाने से अपने खर्चों के लिए वह एक बँधी रकम लेता था। उसका बहुत सा रुपया काश्मीर की सैर करनेवाले अँगरेज अफसरों की खातिरदारी में उड़ता था।

काश्मीर पर अँगरेजों की जैसी कुछ दृष्टि थी, सो तो थी ही, परन्तु इस समय मुख्य बात यह थी कि उन्हें गिलगिट पर अधिकार करने की आवश्यकता थी। यह काश्मीर के अधीन था। उन दिनों मध्य एशिया में यह एक नैतिक महत्त्व का स्थान था। सन् १८६० में चार्ल्स ब्रैडला ने काश्मीर के मामले की जाँच कराने के लिए पार्लामेंट में प्रयत्न किया पर कोई फल नहीं हुआ। सन् १९०५ में न जाने क्या सोचकर महाराजा प्रताप-सिंह को फिर से शासनाधिकार दिये गये।<sup>१</sup>

**मनीपुर**—सन् १८६१ में आसाम की सीमा पर कचार के पूर्व, मनीपुर ही रियासत में गद्दी के लिए झगडा हुआ। भारत-सरकार ने वहाँ के सेनापति को निकाल दिया। इस पर उसने वगावत कर दी और कुछ अफसरों को धाँगे से मार डाला। अन्त में वह और उसके साथी पकड़े गये और उन्हें फाँसी का दंड दिया गया। मनीपुर अँगरेजी राज्य में नहीं मिलाया गया। गद्दी पर एक लड़का बिठला दिया गया। अँगरेज अफसर वसी के नाम से शासन करते रहे। सन् १९०७ में उसको पूरे अधिकार दे दिये गये।

**सिक्का**—भारतवर्ष में बहुत दिनों से चाँदी का सिक्का काम में लाया जाता है और इंग्लैंड में सोने का सिक्का चलता है। भारतवर्ष को बहुत सा रुपया इंग्लैंड भेजना पड़ता है, परन्तु वहाँ चाँदी का सिक्का न होने के कारण वह रुपया सोने के सिक्कों में देना पड़ता है। पहले एक रुपया पाँच का आठवाँ हिस्सा, यानी २ शिलिंग ६ पेंस के बराबर माना जाता था। सन् १८७० से यह पाँच का दसवाँ हिस्सा अर्थात् २ शिलिंग के बराबर माना

जाने लगा। इधर कई कारणों से चांदी बहुत मम्मी हो गई, जिसका फल यह हुआ कि सन् १८६२ में रुपये का भाव घट कर १ शिलिंग १ पेस ही रह गया। इसका भारत की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसको अब पहले से बहुत अधिक रुपया देना पड़ने लग गया। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत-सरकार ने फिर से इनकम टैक्स लगा दिया और नमक-कर बढ़ा दिया। जब इतने से भी पूरा न पड़ा, तब रुपये का मूल्य १ शिलिंग ४ पेस निर्धारित कर दिया गया, सरकारी खजानों में 'सावरेन' भी लिये जाने लगे और आगे चलकर भारतवर्ष में सोने का मुद्रा चलाने की दृष्टि से टकरालों में अधिक रुपया ढालना बन्द कर दिया गया।

**कौंसिलों का सुधार**—लार्ड डफरिन के समय से कौंसिलों के सुधार पर विचार हो रहा था। उसकी बहुत सी बातें मान ली गईं और सन् १८६२ में 'इंडियन कौंसिल ऐक्ट' पास किया गया, जिसके अनुसार भारतीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। म्यूनिसिपलिटियां, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और यूनिवर्सिटियों को लेजिस्लेटिव कौंसिलों में अपने प्रतिनिधियों के भेजने का अधिकार दिया गया। इस तरह प्रतिनिधियों के चुनने के सिद्धान्त का प्रारम्भ किया गया। पर उस समय तक कौंसिलों में सरकारी मेम्बरों की ही अधिकता रखी गई। 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल' में मेम्बरों को प्रश्न पूछने और सालाना बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। गिञ्चित समाज इन सुधारों से सन्तुष्ट न हुआ। कांग्रेस का मत था कि इनसे "कौंसिलों में भेजने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता को न मिला।" इसलिए उसने इसको स्वीकार करते हुए आन्दोलन जारी रखना निश्चित किया।

**पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन**—सरकारी नौकरियों की जांच करने के लिए सन् १८८७ में एक कमीशन नियुक्त किया गया था। सन् १८९१ में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसने नौकरियों की भारतीय, प्रान्तीय और मातहतों के तीन श्रेणियां बनाई और यह निश्चित किया कि इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास करनेवालों को केवल भारतीय श्रेणी की नौकरियां दी जायें।

करे और बाकी दो श्रेणियों में यथासम्भव हिन्दुस्तानी रखे जाया करे। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को भी पूरे तौर पर नहीं माना। इस पर कांग्रेस ने बड़ा असन्तोष प्रकट किया और इस सम्बन्ध में श्री दादाभाई नौरोजी द्वारा, जो पार्लामेंट के मेम्बर चुन लिये गये थे, एक प्रार्थनापत्र भेजना निश्चित किया। सन् १८६३ में पार्लामेंट ने सिविल सर्विस की परीक्षा भारतवर्ष में भी करने की इच्छा प्रकट की। मद्रास को छोड़कर सभी प्रान्तीय सरकारों ने इसका बड़ा विरोध किया। इसलिए कोई कानून पास न किया गया और पार्लामेंट का प्रस्ताव यों ही रह गया।

**दूसरा लार्ड एलगिन**—सन् १८६४ में लार्ड एलगिन वाइसराय नियुक्त किया गया। यह पहले लार्ड एलगिन का, जो सन् १८६२-६३ में गवर्नर-जनरल रह चुका था, लडका था। यह किसी बड़े ओहदे पर नहीं रहा था और न इसको शासन का ही अधिक अनुभव था। इसमें कोई विशेष योग्यता भी नहीं थी और यह भारतवर्ष में रहनेवाले अफसरों के कहने ही पर अधिकतर चलता था।

**चितराल और तीराह**—हिन्दूकुश के दक्षिण में चितराल एक छोटी सी रियासत है। सन् १८६५ में यहाँ की गद्दी के लिए झगडा हुआ और विद्रोहियों ने अँगरेजी चौकी को घेर लिया। इस पर अँगरेजी सेना ने बढ़कर चितराल पर अधिकार कर लिया। लार्ड एलगिन चितराल को छोड़ना न चाहता था। इंग्लैंड की लिबरल सरकार की राय थी कि वहाँ से सेना वापस बुला लेनी चाहिए। इस पर लिखा-पढ़ी हो ही रही थी कि इतने में इंग्लैंड की सरकार बदल गई और नई सरकार ने एलगिन की बात मानकर चितराल में अँगरेजी राज्य तक सड़क बनाने और उम पर चौकियाँ स्थापित करने की आज्ञा दे दी। माले और एसक्विथ की राय में चितरालियों के साथ यह विस्वाम्वात किया गया। इसके उत्तर में भारतमन्त्रि का कहना था कि चितराली युद्ध करने पर रاض थे, ऐसी दशा में चितराल पर नैतिक अधिकार अपना आवश्यक था।

चितराल के मामले का सरहद्दी जातियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्हें अँगरेजों की नीति पर सन्देह होने लगा। मड़के बनाना और चौकियों को कायम करना उन्हें पसन्द न आया। इसके अतिरिक्त इन दिनों तुर्कों के सुल्तान का, जिनको सब मुसलमान अपना 'खलीफा' मानते थे, बराबर अपमान करने के कारण ईसाइयों से मुसलमान चिढ़े हुए थे और मुल्ला लोग सरहद्दी अफगानों को 'जिहाद' का उपदेश दे रहे थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सन् १८६७ में कई एक सरहद्दी जातियाँ बिगड़ पड़ीं। स्वात निवासियों ने अँगरेजी चौकियों पर धावा कर दिया, काबुल नदी के उत्तर में रहनेवाले महमन्द लोगों ने पेशावर तक लूटमार मचा दी। अफ्रीदियों ने सिख सिपाहियों को मार डाला और खैबर के दर्रे को रोक दिया। इस उपद्रव को शान्त करने के लिए दो सेनाएँ भेजी गईं। एक ने महमन्द लोगों को हराया और दूसरी ने पेशावर के दक्षिण-पश्चिम तीराह की घाटी में अफ्रीदियों को दबाया। इसमें अँगरेजों को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। अफ्रीदी बड़ी वीरता से लड़े। सन् १८८६ में उन्होंने हार मान ली। इस युद्ध में भारत-सरकार को देशी राज्यों की 'साम्राज्य-सेवा सेना' से बड़ी सहायता मिली।

रूस से सन्धि हो जाने के कारण पामीर के पर्वतों में दोनों साम्राज्यों की सीमाएँ निश्चित हो गईं। अफगानिस्तान की सीमा भी निर्धारित हो गई और पूर्व में बर्मा तथा चीन के बीच की सीमा भी तय हो गई। इस तरह लार्ड एलगिन के समय में सीमाओं का प्रश्न कुछ काल के लिए हल हो गया।

**प्लेग और अकाल—**भारतवर्ष में पहले भी प्लेग हो चुका था। जहाँगीर बादशाह ने अपनी 'तुजक जहाँगीरी' में इस 'बवा' का उल्लेख किया है और लिखा है कि यह रोग चूहों से फैलता है। सन् १८६६ में बम्बई शहर में यह रोग बड़े जोरों से फैल गया। कहा जाता है कि यह चीन से आया था। शहर से लगभग चार लाख मनुष्य भाग निकले। यह रोग अन्य स्थानों में न फैलने पावे, इसके लिए बड़ा प्रबन्ध किया गया। मकानों की सफाई और रोगियों को अलग रखने के लिए बड़े कड़े नियम बनाये गये और जनता की आराम-तकलीफ तथा उसके भावों का ध्यान न रखकर इनसे काम



लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता में बड़ा असन्तोष फैल गया और पूना में दो अँगरेज अफसर मार डाले गये। इस पर सरकार ने नाटू भाइये को, बिना अभियोग चलाये हुए, निर्वासित कर दिया और अपने पत्र 'केसरी' में तीव्र लेख लिखने के कारण श्री बाल गंगाधर तिलक को जेल भेज दिया। अशिक्षित जनता को यह भ्रम हो गया था कि प्लेग के कीड़ों को सरकार फैलाती है। सन् १८६८ में सरकार को भी अपनी भूल का पता लग गया। उसने अधिक हस्तक्षेप न करना ही उचित समझा और नियमों को बहुत कुछ बदल दिया। धीरे धीरे प्लेग सभी प्रान्तों में फैल गया और सन् १९०३ के अन्त तक इसमें २० लाख आदमी मर गये। अब प्लेग का उतना प्रकोप नहीं है, पर तब भी हर साल लाखों आदमी इसके कलेवा बन जाते हैं।

इसी समय पश्चिमोत्तर प्रान्त, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। पश्चिमोत्तर प्रान्त में अकालपीडित मनुष्यों के लिए लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर एंटनी मैकडानेल ने सराहनीय प्रयत्न किया। सन् १८६८ में अकाल से बचने के साधन बतलाने के लिए फिर एक कमीशन नियुक्त किया गया। अकालों के सम्बन्ध में कांग्रेस का मत था कि भारतवर्ष का बहुत सा धन हर साल विलायत चला जाता है। अँगरेज अफसरों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देन और सेना रखने में खूब रुपया बढ़ाया जाता है। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि जनता बराबर दरिद्र होती जाती है। यही कारण है कि दुर्भिक्ष के समय में कष्ट इतना अधिक बढ़ जाता है। इसको निवारण करने के लिए खर्च घटाना चाहिए, रुपया जोड़ना चाहिए और दूगी कलाशों को, जो नष्ट कर दी गई है, फिर से जाग्रत करना चाहिए।<sup>१</sup>

**कपड़े पर चुंगी**—सिक्के के ऋण के कारण, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, भारत-सरकार को जिन साल लार्ड एलगिन आया बड़ा पाटा उठाना पड़ा। इसको पूरा करने के लिए सूती कपड़े को छोड़कर बाहर से धानवाले माल पर पाँच सैंकड़ा फिर चुंगी लगा दी गई। साल के अन्त

१ सन् १८९६ की कांग्रेस का प्रस्ताव।

मे यह चुगी कपड़े पर भी ली जाने लगी। इस पर मैनेस्टर और लंका-शायर के कपड़े के व्यापारियों ने बड़ा गोर-गुल मचाया। तब भारत-सरकार ने उनको शान्त करने के लिए भारत के कारखानों में बने हुए कपड़े पर भी उतनी ही चुगी लगा दी। सरकार की यह बड़ी जबरदस्ती थी। इसके विरुद्ध भारत में भी आन्दोलन होने लगा। सन् १८६६ में देशी और विलायती दोनों कपड़ों पर चुगी घटाकर साढ़े तीन सैकड़ा कर दी गई। मैनेस्टर के लाभ के लिए देशी माल पर चुगी लगाने का भारतवर्ष बराबर विरोध करता रहा।

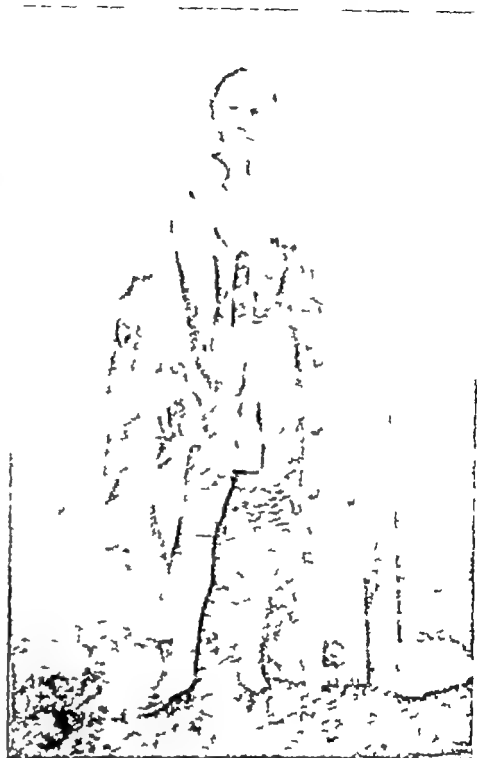
**अफीम का व्यापार**—अफीम पर सरकार का डेका है। इसका बहुत सा भाग चीन जाता है। सन् १८४२ में अफीम के ही कारण चीन से युद्ध हो गया था। इस व्यापार से सरकार का बड़ा लाभ होता है। कुछ लोगों के मत में अफीम ऐसी हानिकारक वस्तु के प्रचार से लाभ उठाना सरकार के लिए उचित नहीं था। इसकी जाँच करने के लिए सन् १८६३ में एक कमीशन नियुक्त हुआ। इसकी राय थी कि अफीम से कोई विशेष हानि नहीं होती, इसलिए आम्दनी के खयाल से भारत-सरकार को यह व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह चीन का पीछा नहीं छोड़ा गया। बहुत झगड़ों के बाद यह तय हुआ कि सन् १९०८ से चीन में अफीम का भेजना धीरे धीरे कम कर दिया जाय।

**सैनिक प्रवन्ध**—इस समय तक बंगाल, बम्बई और मद्रास की सेनाएँ अलग अलग रहती थीं और उनके सेनापति भी अलग अलग होते थे। परन्तु सन् १८७६ से इन तीनों सेनाओं को मिलाकर एक सेनापति रखने के प्रश्न पर विचार हो रहा था। सन् १८६५ में यह प्रवन्ध स्वीकार कर लिया गया और भारत की कुल सेना का एक सेनापति बना दिया गया। इस सुधार से सेना का प्रान्तीय भेद जाता रहा और उसमें एकता के भाव का संचार हुआ।

**लार्ड कर्जन**—सन् १८६६ में लार्ड कर्जन वाइसराय बनाया गया। भारतवर्ष के वाइसराय बनने की बचपन से ही इसको बड़ी आकांक्षा थी।

इस पद पर नियुक्त होने के पहले वह चार बार भारतवर्ष आ चुका था और एशिया के प्राय सभी देशों का भ्रमण कर चुका था। फारम के ग्राह, अफगानिस्तान के अमीर, कोरिया तथा जपान के बादशाहों से उसका परिचय था और पूर्वीय राजनीति का उसको अच्छा ज्ञान था।

इस सम्बन्ध में उसने तीन पुस्तकें भी लिखी थीं। इन दिनों पश्चिमोत्तर सीमा का प्रश्न फिर जटिल हो रहा था। ऐसी दशा में उस विषय के एक पूर्ण ज्ञाता का वाइसराय के पद पर नियुक्त किया जाना आवश्यक समझा जाता था। इस समय लार्ड कर्जन की अवस्था ४० वर्ष की भी नहीं, पर तब भी उसकी योग्यता का परिचय सारे देश का मिल चुका था। भाषण की उसमें विचित्र शक्ति थी,



लार्ड कर्जन

कल्पना की उसमें कमी नहीं। हर एक बात उसकी समझ में गीघ्र ही आ जाती थी। उसका प्रवन्ध ऐसा होता था कि कोई कसर बाकी न रह जाती थी। वह बड़ा परिश्रमी था, उसके नीचे काम करनेवालों को उसका साथ देना मुश्किल हो जाता था। अपने आगे वह किसी की भी न सुनता था। ब्रिटिश साम्राज्य का उसको बड़ा अभिमान था। भारतवर्ष ऐसे विशाल देश पर वह शासन करने आया है, इसका उसे बराबर ध्यान रहता था।

भारतवर्ष की राजनीति से भी वह अनभिज्ञ न था। दो वर्ष तक वह उपसचिव के पद पर काम कर चुका था। सन् १८६० का 'इंडियन कैमिल ऐक्ट' पार्लामेंट की कामस सभा में उसी ने पेश किया था। भारतवर्ष को वह "ब्रिटिश साम्राज्य का केन्द्र" समझता था। इंग्लैंड में चलते समय उसने कहा था कि चाइसराय के पद को मैं महर्षि स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भारतवर्ष, उसके निवासी, उसके इतिहास, उसके शासन, उसके जीवन तथा उसकी सभ्यता के मनोग्राही रहस्यों से प्रेम करता हूँ।<sup>१</sup> लार्ड कर्जन के इन शब्दों से भारतवासियों को भी उससे बहुत कुछ आशा हो रही थी और चौदहवीं कांग्रेस ने, सहानुभूतिसूचक शब्दों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उसके स्वागत का प्रस्ताव पारित किया था।

**अकाल—**भारतवासियों के लिए लार्ड कर्जन के शासन का प्रारम्भ अकाल से हुआ। सन् १९०० में फिर बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। इस बार गुजरात में इसका बड़ा प्रकोप रहा। सन् १९०१ में सर ऐंटनी मैकडोनेल की अध्यक्षता में फिर एक कमीशन नियुक्त किया गया, पर कांग्रेस के बताये हुए उपायों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि जहाँ तक सम्भव हो देश भर में इस्तरकारी बन्दोबस्त कर देना चाहिए, लगान घटा देना चाहिए, अंगरेज अफसरों के वेतन में हर साल करोड़ों रुपया विलायत जाता है, उसको कम करने के लिए हिन्दुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे देना चाहिए और देशी कारखानों की रक्षा तथा कलाओं को उत्साह प्रदान करना चाहिए।

**पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त—**लार्ड कर्जन 'आगे बढ़ने की नीति' का अनुयायी था। इंग्लैंड में बहुतों को सन्देह था कि उसके समय में सीमा पर लड़ाई छिड़ेगी और रूस से भी वैर होगा। परन्तु उसने ऐसी नीति से काम लिया कि सन् १९०१ में महसूदी वजीरियों को दवाने के लिए एक छोटी सी लड़ाई के सिवा, दस वर्ष तक सीमा पर शान्ति रही। लार्ड

<sup>१</sup> रीनाल्डसे, लार्ड कर्जन, जि० १, पृ० ३१५।

पुलिन के समय में दस बारह हजार सेना भिन्न भिन्न स्थानों में रख दी गई थी। लार्ड कर्जन ने इसमें की बहुतसी सेना को वापस बुला लिया और अंगरेज अफसरो की अध्यक्षता में वहाँ के निवासियों को अस्त्र-शस्त्र देकर रक्षा का भार सौंप दिया। इस समय तक सीमा पर के जिलों का शासन पंजाब-सरकार के हाथ में था। सन् १९०१ में इनका 'पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त' के नाम से एक अलग प्रान्त बना दिया गया। नाम में कोई गड़बड़ न हो इसलिए 'पश्चिमोत्तर प्रान्त' का नाम 'संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध' रख दिया गया।

**अफ़ग़ानिस्तान**—सन् १९०१ में अमीर अब्दुर्रहमान की मृत्यु हो गई। लार्ड कर्जन के साथ उसका पहले से परिचय था और वह कर्जन की नीति से सन्तुष्ट था। यद्यपि अंगरेजों की नीति पर उसे अधिक विश्वास नहीं था, पर तब भी अपने हित के लिए वह उनकी मित्रता आवश्यक समझता था। उसका लटका अमीर हवीबुल्ला गद्दी पर बैठा। उसके साथ भी अंगरेज नई सन्धि करना चाहते थे, पर उसने इसको स्वीकार न किया। उसकी राय में पिछली सन्धि अफ़ग़ानिस्तान राज्य के साथ हुई थी। वह अमीर अब्दुर्रहमान के साथ व्यक्तिगत सन्धि न थी। ऐसी दशा में उसके बदलने की कोई आवश्यकता न थी। इस पर दो तीन वर्ष तक दोनों सरकारों में कोई समझौता न रहा और अमीर हवीबुल्ला ने, भारत-सरकार से जो सालाना रुपया मिलता था, वह भी न लिया। सन् १९०४ में एक अंगरेज दूत फिर अफ़ग़ानिस्तान भेजा गया, नई सन्धि पर जोर देना छोड़ दिया गया और हवीबुल्ला की 'शाह' की उपाधि मान ली गई। इस पर दोनों राज्यों में फिर मित्रता स्थापित हो गई और हवीबुल्ला ने भारत-सरकार से जो रुपया वाकी था ले लिया।

**फ़ारस की खाड़ी**—सत्रहवीं शताब्दी में अंगरेजों ने फ़ारस की खाड़ी को व्यापार के लिए सुरक्षित बनाया था। सन् १८५३ में अन्य राज्यों के जहाज भी यहाँ से आने-जाने लगे थे, पर अंगरेज इसके तटों पर किसी अन्य राज्य का अधिकार पसन्द न करते थे। यह बात इन राज्यों को खटकती थी और धीरे धीरे फ्रांस, रूस, जर्मनी और तुर्की इसके तटों पर जहाजों के स्टेशन बनाकर



रूस की सहायता के लिए एक सेना भेज दी गई। तिब्बतवाले आधुनिक शस्त्र-सम्पत्तियों से सुसज्जित सेना का सामना न कर सके और अंगरेज वहाँ की राजधानी लहामा में पहुँच गये। इस पर सन्धि हो गई, जिसके अनुसार ७५ लाख रुपया दंड मँगाया गया, जमानत के लिए कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया गया, और अंगरेजों को व्यापारिक सुविधाएँ देने तथा प्रतिनिधि रखने के लिए तिब्बत-सरकार को मजबूर किया गया। उससे यह वचन भी लिया गया कि भविष्य में वह किसी अन्य राज्य से सम्बन्ध न रखेगी।

इंग्लैंड-सरकार की इच्छा के विरुद्ध यह सन्धि की गई थी। तिब्बत के किसी भाग पर अधिकार न करने का वह रूस को वचन दे चुकी थी। लार्ड कर्जन के विरोध करते रहने पर भी उसने सन्धि की शर्तों को बदल दिया और दंड की रकम को घटाकर २५ लाख कर दिया। तीन वर्ष के बाद अधिकृत प्रदेश को खाली कर देने का वचन दिया और प्रतिनिधि रखने का विचार छोड़ दिया। एक दल का कहना है कि लार्ड कर्जन ने रूस की गुप्त चालों का श्रुत कर दिया। इसके प्रतिकूल दूसरे दल का मत है कि एरु स्वतंत्र पर निर्भर राज्य को अकारण दबाना अनुचित था। यह बात ठीक है कि सिवा लार्ड कर्जन के इससे अंगरेजों का कोई लाभ नहीं हुआ, तिब्बत पर चीन का अधिकार पक्का हो गया और बैठे-बिठाये भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर एक झगड़ा पैदा हो गया। इस झगड़े में भारतवर्ष का खजाना बेकार लुटाया गया। सन् १८५८ में यह कहा गया था कि भारतवर्ष की आसानी सिवा उस पर आक्रमण रोकने के और किसी दशा में उसकी सीमाओं के बाहर न खर्च की जायगी, परन्तु इस समय इसका कुछ भी ध्यान न रखा गया। कायेम ने सरकार की इस नीति का विरोध किया।

**वरार का झगड़ा**—सन् १८५३ में निजाम के साथ वरार के सम्बन्ध में सन्धि की गई थी, उसमें यह कहा गया था कि निजाम को कुल हिमाचल वरार समझाया जायगा और जो वचन होगी दी जाय करेगी। वरार की आसानी से ७ हजार सेना का खर्च चलाना और ४८ लाख रुपये का खर्च निपटाना निश्चित किया गया था। शासन का खर्च स्पष्ट नहीं किया

गया था पर यह कह दिया गया था कि दो लाख रुपया साल से अधिक न होगा। सन् १८५३ तक सेना का खर्च ४० लाख रुपया साल होता था, यह घटाकर २४ लाख कर दिया गया, पर सेना की संख्या में कोई कमी या प्रबन्ध में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई। यदि यह रकम पहले ही घटा दी गई होती, जिसके करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं थी, तो इतने कज की नौबत ही न आती, परन्तु वैसा नहीं किया गया। सन् १८५७ के गदर में अंगरेजों की सहायता करने के बदले में कर्ज माफ कर दिया गया। सेना का खर्च घट जाने से जो बचत हुई, उसका तथा आवकारी का जय निजाम ने पिछला हिस्सा मर्गा, तब उसके जिम्मे ४४ लाख की दो रकम और दिखला दी गई, जिनका इसके पहले कभी जिक्र तक नहीं किया गया था। सन् १८६० में जो नई सन्धि की गई, उसमें से हिसाब समझाने की शर्त ही निकाल दी गई।

शासन का खर्च बढ़ाकर चौगुना कर दिया गया। इस पर सन् १९०० में इलाहाबाद के अंगरेजी समाचारपत्र 'पायनियर' का लिखना था कि "पहले हमने कर्ज के बदले में जायदाद देने के लिए निजाम पर जोर दिया, बाद को यह कर्ज फर्जी साबित हुआ। २५ सैकड़ा से अधिक शासन में खर्च न करने और सालाना बचत निजाम को देने का हमने वचन दिया। इस पर विश्वास करके निजाम ने हिसाब मर्गना छोड़ दिया और हमको शासन की स्वतंत्रता दे दी। हमने इसका (अनुचित) लाभ उठाकर केवल शासन का खर्च ४३ सैकड़ा कर दिया।" यह बात ठीक है कि इस शासन से बरार का भी लाभ हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि खर्च खुले हाथ से किया गया। सन् १९०२ में लार्ड कर्जन निजाम महबूबअलीखा से एकान्त में मिला और उससे यह स्वीकार करवा लिया कि २५ लाख रुपया सालाना देने पर अंगरेजों को बरार सदा के लिए दे दिया जाय। इस प्रबन्ध से बेचारे निजाम की ही हानि हुई, क्योंकि सेना टूट जाने से बरार की बचत ५० लाख साल से भी अधिक हो गई।



निजाम के वजीर नवाब सर सालारजंग के समय में हैदराबाद की बहुत कुछ वृद्धि हुई। मालगुजारी के ठेके उठा दिये गये, पुलिस का प्रबन्ध ठीक किया गया, नई अदालतें स्थापित की गई, स्कूल तथा कालेज खोले गये और प्रजा की दशा सुधारने की ओर अधिक ध्यान दिया गया। हैदराबाद राज्य में हिन्दुओं की संख्या अधिक है, पर यहाँ कभी पक्षपात से काम नहीं लिया गया। इन दिनों भी वजीर के पद पर एक हिन्दू राजा है।

**दिल्ली दरबार और देशी राज्य**—जनवरी सन् १६०१ में, ८२ वर्ष की अवस्था में, महारानी विक्टोरिया का देहान्त हो गया। ६४ वर्ष तक

उसने राज्य किया। उसको अपनी भारतीय प्रजा से भी प्रेम था। देश भर में उसके मरने का शोक मनाया गया। उसका लडका सातवां एडवर्ड गद्दी पर बैठा। सन् १६०३ में दिल्ली में भी एक बड़ा भारी दरबार किया गया। भारतवर्ष पिछले दुर्भिक्ष के कष्ट से इस समय तक मुक्त न हो पाया था, पर इसका कुछ भी ध्यान न रखा गया और लाखों रुपया 'तमांगे' में उड़ाया गया। इस साल की कांग्रेस के महापति श्री लालमोहन घोष ने कहा था कि जितना दरबार में रुपया फूँका गया, उन्नीस लाखों लोगों की प्राण बच गये होते। इन दरबार में देशी नरेशों के सम्मान का कुछ भी ध्यान न रखा गया। इन पर



सातवां एडवर्ड

सातवां एडवर्ड

लार्ड कर्जन की बड़ी कड़ी निगाह रहती थी। उसने एक आज्ञा प्रकाशित करवा दी थी कि भारत-सरकार की बिना अनुमति के कोई राजा यूरोप न जाय।<sup>१</sup>

**कृषि और व्यापार**—पंजाब में महाजन लोग अधिक व्यापार पर रुपया देकर किसानों की जमीनें छीन लेने थे। उनकी रक्षा के लिए सन् १९०० में यह नियम बना दिया गया कि कर्ज में किसी काश्तकार की जमीन न छीनी जाय। सन् १९०२ में मालगुजारी के प्रश्न की भी फिर से जांच की गई। लार्ड कर्जन ने इस बात को दिखलाने की चेष्टा की कि अकालों का कारण मालगुजारी या लगान की अधिकता नहीं है। पर साथ ही साथ उसने यह भी निश्चय किया कि फ़सल खराब होने पर कुछ माफी देनी चाहिए या कुछ काल तक लगान वसूल न करना चाहिए। किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए 'कोऑपरेटिव सोसाइटियों' (सहयोग-समितियों) के खोलने का प्रबन्ध किया गया और खेती की देखभाल करने के लिए 'कृषि-विभाग' स्थापित किया गया। व्यापार की निगरानी करने के लिए वाइसराय की कौंसिल का एक मेम्बर और बढ़ाया गया।

**प्राचीन स्मारक-रक्षा**—भारतवर्ष में बहुत सी हिन्दूकालीन इमारतें तो नष्ट हो ही चुकी थीं, मुगल साम्राज्य तथा बड़े बड़े देशी राज्यों का अन्त हो जाने से मध्यकालीन इमारतों की भी वही दशा हो रही थी। फ़तहपुर सीकरी के विशाल भवनों में भालू और भेड़िये निवास करते थे। संसार की सुन्दर इमारतों के ताज—ताजमहल—की शोचनीय दशा थी। बहुत सी इमारतों को तोड़-फोड़कर सरकारी दफ्तर बना लिये गये थे। लार्ड कैनिंग ने इस और अवश्य कुछ ध्यान दिया था, पर इस समय तक भारत-सरकार इनकी रक्षा के लिए अपने को जिम्मेदार न मानती थी। लार्ड कर्जन के समय में इनकी रक्षा तथा मरम्मत करने के लिए एक खास कानून बनाया गया और इसके लिए एक नया विभाग स्थापित किया गया, जो 'आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेंट' कहलाता है। इस विभाग ने बड़ी खोज की है और अनेक ऐतिहासिक विषयों

पर नया प्रकाश डाला है। निस्सन्देह प्राचीन सभ्यता के चिह्नों की रक्षा करके लार्ड कर्जन ने भारत का बड़ा उपकार किया।

**उच्च शिक्षा**—सन् १९०१ में शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए गिमला में एक सम्मेलन किया गया। इसमें एक भी हिन्दुस्तानी नहीं बुलाया गया। यद्यपि लार्ड कर्जन का कहना था कि “मैं जब से भारतवर्ष आया हूँ, किसी बात का गुप्त रखना मेरी नीति नहीं रही,” पर तब भी इस सम्मेलन की कार्यवाही गुप्त रखी गई। इसके बाद एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसमें भी पहले कोई हिन्दुस्तानी मेम्बर नहीं रखा गया। समाचारपत्रों में बड़ा विरोध होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सर गुरुदास बनर्जी का नाम शामिल कर लिया गया। पाँच ही महीने में इस कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। इसकी राय थी कि सरकारी सहायता पानेवाले छोटे छोटे कालेजों में शिक्षा दीक नहीं होनी। इन कालेजों में कानून पढ़ाने के दर्जे न रखने चाहिए, इसके लिए एक कालेज अलग खोलना चाहिए। कालेजों में फीस बढ़ा देनी चाहिए, उनके निरीक्षण के लिए इसपेक्टर रखने चाहिए और यूनिवर्सिटियों का प्रबन्ध करनेवाले ‘सिनेट’ तथा ‘मिंडिकेट’ का ऐसा संगठन करना चाहिए कि जिसमें उन पर सरकार की पूरी देख-रेख रह सके।

इसी रिपोर्ट के आधार पर सन् १९०४ में ‘यूनिवर्सिटीज ऐक्ट’ पास किया गया। कमीशन का उद्देश्य “शिक्षा का सुधार” बतलाया गया था, पर वास्तव में जैसा कि कमीशन ने स्वयं स्वीकार किया था, इसने यूनिवर्सिटियों पर सरकार का अधिकार बढ़ा दिया और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को संकुचित बना दिया। उच्च शिक्षा में जिस लोकमत की जागृति हो रही थी, वह लार्ड कर्जन को पसन्द न था। उसका कहना था कि इससे हिन्दुस्तानी पाश्चात्य सभ्यता के बंधन कोरे गठ्ठों को सीख जाते हैं, पर उनके भावों को नहीं समझते। सार्वजनिक थियेटरों में सबसे अधिक भाग लेने के कारण वकील सरकार की भाषों में खटक रहे थे। इसी लिए कानून पढ़ाने की सुविधाओं को हटा कर उनकी संख्या कम करने का प्रयत्न किया गया। सर गुरुदास बनर्जी ने कमीशन की विफारिशों में अपना मतभेद प्रकट किया। काग्रेस की राय थी

कि इस नये कानून से यूनिवर्सिटियों की “स्वतंत्रता नष्ट हो गई और वे सरकार का एक विभाग बन गईं।”

**बंग-विच्छेद**—गाम्यन की दृष्टि में उस समय का बंगाल प्रान्त एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर के लिए बहुत बड़ा था। सारे प्रान्त पर पूरा निरीक्षण न हो पाता था। इसी लिए कुछ दिनों में उसके दो टुकड़े करने का विचार किया जा रहा था। पहले यह सोचा गया कि पूर्वीय बंगाल अर्थात् चटगांव, ढाका तथा मैमनसिंह के जिले आसाम में मिला दिये जायें। बाद को लार्ड कर्जन ने गुप्त रीति से यह निश्चित किया कि उत्तरी बंगाल के कुछ जिले भी इसी के साथ मिला दिये जायें। ये सब जिले बंगाल के अंग हैं। उनकी भाषा, सभ्यता और संस्कृति एक है, इसका कुछ भी ध्यान न रखा गया। मई

१९०५ में ‘आसाम और पूर्वीय बंगाल’ का नया प्रान्त बना दिया गया और उसके शासन के लिए एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर रखा दिया गया। ढाका उस प्रान्त की राजधानी बनाया गया।

**स्वदेशी और**

**वायकाट**—इसके विरुद्ध बंगाल में घोर आन्दोलन मच गया। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व देशसेवा के लिए अर्पण कर दिया था, इसके मुख्य नेता हुए। पहले सरकार से प्रार्थना

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

की गई, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तब अंगरेजों पर जोर डालने के लिए

स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विलायती वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा की गई। इसमें देश के प्रायः सभी प्रान्तों ने बंगाल का साथ दिया। सर्वत्र स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार का प्रबन्ध होने लगा और आन्दोलन में एक नया जीवन आ गया। कांग्रेस ने भी 'स्वदेशी और बायकाट' की नीति को मान लिया और देश भर में एक विचित्र जागृति हो गई। कई एक नये कारखाने खुल गये, समाचारपत्रों में निर्भीकता आ गई, अशिक्षित समाज में भी देश की चर्चा होने लगी, एकता का भाव बढ़ने लगा और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का सचमुच जन्म हो गया।

शासन की सुविधा के लिए कई उपाय थे, जिनमें बंगाल की जनता को कोई आपत्ति न हो सकती थी। मदरास और बम्बई की तरह यहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहायता करने के लिए एक्जीक्यूटिव कौंसिल स्थापित की जा सकती थी या बिहार तथा उड़ीसा के जिले अलग किये जा सकते थे, जैसा कि बाद में किया गया, पर इन दिनों सरकार की नीति ही दूसरी थी। कलकत्ता के नेताओं का सारे प्रान्त पर प्रभाव पड़ रहा था। लार्ड कर्जन इसको अच्छा न समझता था। 'स्टेट्समैन' पत्र के एक भूतपूर्व सम्पादक की राय में बंगालियों की मयुक्त शक्ति तथा कलकत्ते के राजनैतिक प्राधान्य का नष्ट करना और हिन्दुओं को दबाये रखने के लिए मुसलमानों के जोर को बढ़ाना बिल्कुल सही विचार के मुख्य उद्देश्य थे। पूर्वीय बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसलिए यह दिखलाने की चेष्टा की गई कि इस प्रबन्ध में मुसलमानों के हित का विशेष ध्यान रखा गया है। देशव्यापी आन्दोलन बनावटी बतलाया गया और उसके दबाने का संकल्प कर लिया गया। नभाएँ तोड़ दी गईं, 'बन्दे मातरम्' चिल्लाना अपराध बना दिया गया, नेताओं पर अभियोग चलाये गये और बहुतों को जेल का दंड दिया गया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि आन्दोलन और भी जोर पकड़ गया।

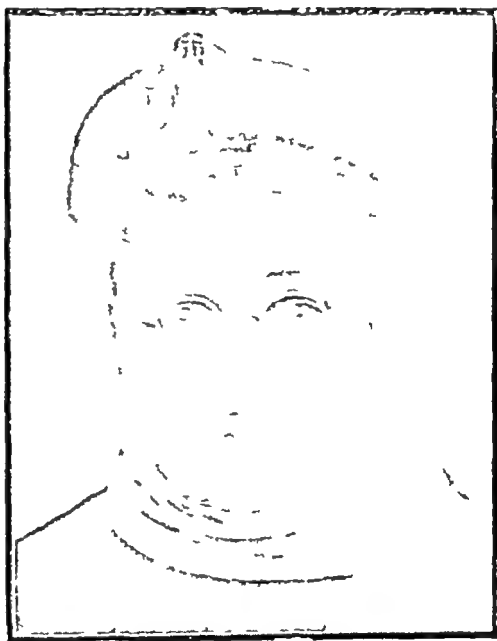
**किचनर से मतभेद**—प्रधान सेनापति प्रायः वाइसराय की कौमिलता सम्मर भी होता था, पर सेना का 'शासनविभाग' कौंसिल के एक साधारण सेन्यर के हाथ में रहता था, जो एक सैनिक ही हुआ करता था। सेना

के शासन-सम्बन्धी मामलों में वाइसराय को यही सलाह देना था और प्रधान सेनापति के सब प्रस्ताव इसी के द्वारा वाइसराय के पास जाते थे। लार्ड किचनर की राय में, जो इन दिनों भारत का प्रधान सेनापति था, इस तरह सैनिक प्रबन्ध के हर एक काम में बड़ी देर लगती थी और वाद-विवाद बढ़ जाता था। इसलिए वह इस विभाग को प्रधान सेनापति की अध्यक्षता में ही रखना चाहता था। लार्ड कर्जन और उसकी कौंसिल दोनों इस राय के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि ऐसा करने से प्रधान सेनापति का अधिकार बहुत बढ़ जायगा, वाइसराय को, जिसे प्रायः सैनिक मामलों का विशेष ज्ञान नहीं रहता, स्वतंत्र सलाह न मिल सकेगी और उसको प्रधान सेनापति की सब बातें माननी पड़ेंगी। इसके उत्तर में लार्ड किचनर का कहना था कि हर एक बात के मानने या न मानने का वाइसराय को सदा अधिकार है। फिर ऐसी दशा में प्रधान सेनापति के होते हुए सेना का शासन एक माध्यम सैनिक के हाथ में देना उचित नहीं जान पड़ता।

**लार्ड कर्जन का इस्तीफा**—इस मामले में भारतसचिव ने जो निर्णय किया, वह लार्ड कर्जन को पसन्द न आया और उसने सन् १९०५ में इस्तीफा दे दिया। उसके पद की अवधि सन् १९०४ ही में समाप्त हो गई थी, पर वह दूसरी बार पाँच वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। इस बीच में, जब वह ६ महीने के लिए इंग्लैंड गया था, तब उसके स्थान पर मदरास के गवर्नर लार्ड एमथिल ने काम किया था। इसमें सन्देह नहीं कि लार्ड कर्जन बड़ा प्रतिभाशाली मनुष्य था। हर एक बात पर वह अपनी छाप लगाना चाहता था। अपने सिद्धान्तों के अनुसार वह कार्यापलट करना चाहता था। वह लार्ड वेलेजली और डलहौजी के ढग का गवर्नर-जनरल था, जिन्होंने भारतवर्ष का नक्शा बदल दिया था। लार्ड कर्जन के लिए जीतने को कुछ बाकी न रह गया था, उसने बंगाल के टुकड़े करके ही ऐसा किया। महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र की प्रतिज्ञाओं का पालन करना उसकी राय में असम्भव था। वह अपने को भारत की दीन जनता का संरक्षक मानता था, देश के नेताओं पर उसको विश्वास न था और भारतीय शिक्षित

समाज को वह तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। उसका कहना था कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में मृत्यु का अधिक सम्मान है, पूर्व में कपट की ही मात्रा अधिक है, पूर्विय कूटनीति संसार में प्रसिद्ध है।<sup>१</sup>

वह भारतवर्ष का शासन अंगरेजों के लिए 'ईश्वरदत्त' मानता था। उसका विश्वास था कि सत्य के लिए लड़ना, अपूर्णता, अन्याय तथा नीचता का तिरस्कार करना, प्रशंसा, खुशामद या निन्दा की, जिनकी भारतवर्ष में कमी नहीं है, कभी परवाह न करना, ईश्वर ने यह काम सौंपा है, ऐसा समझ कर, न्याय, सुख, समृद्धि, नतिक सम्मान, स्वदेशभक्ति, मानसिक उन्नति और कर्तव्य-परायणता के भावों का करोड़ों भारतवासियों में यथाशक्ति प्रचार करना ही भारतवर्ष में अंगरेजों के रहने का समर्थन है। उसका कहना था कि इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रहस्य नहीं रहा, इसका निर्णय भारतवर्ष ही करेगा।<sup>२</sup>



भारतवर्ष ने जो निर्णय किया, वह सन् १९०५ की कांग्रेस के सभापति स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण गोखले के गण्डे से प्रकट है। गोखले

गोपाल कृष्ण गोखले

का कहना था कि भारतवर्ष के इतिहास में लार्ड कर्जन के शासन की तुलना

<sup>१</sup> कल्कत्ता कनवोकेशन ऐंटेम।

<sup>२</sup> गोनारटो, लार्ड कर्जन, जि० २, पृ० ४२४।

औरगजेब के शासन से हो सकती है। उसने भी शासन को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत बनाने का प्रयत्न किया था। उद्देश्य की दृढ़ता, कर्तव्य का भाव, काम करने की विचित्र शक्ति, अविश्वास और दमन की नीति में आग्रह उसमें भी ऐसा ही था। लार्ड कर्जन की सबसे अधिक प्रशंसा करनेवाले भी इस बात को मानने के लिए तैयार न होंगे कि उसने भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की नींव को दृढ़ बना दिया। “उसके लिए भारतवर्ष ऐसा देश था, जिसमें अंगरेज कुल शक्ति सदा अपने हाथ में रखकर केवल कर्तव्य ही का बखान किया करे। उसकी राय में भारतवासियों के लिए शासित होना ही केवल काम था, अन्य कोई आकांक्षा रखना पाप था।”

यह बात ठीक है कि अविश्वास तथा दमन की नीति से स्वदेशप्रेम और राष्ट्रीयता के भावों को उत्तेजना देने के लिए भारतवर्ष लार्ड कर्जन का अवश्य कृतज्ञ रहेगा।

---



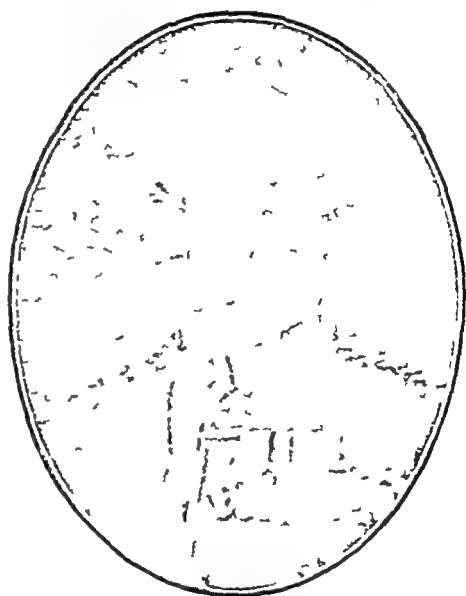
## परिच्छेद १६

### राजनैतिक सुधार

**लार्ड मिंटो**—लार्ड कर्जन के इस्तीफा देने पर लार्ड मिंटो वाइसराय नियुक्त किया गया। यह पहले लार्ड मिंटो का, जो सन् १८०६ में गवर्नर-जनरल होकर आया था, वंशज था और कनाडा का गवर्नर-जनरल रह चुका था। लार्ड कर्जन ने देश की स्थिति बड़ी नाजुक बना दी थी, जिसके कारण लार्ड मिंटो का बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं।

### अमीर हवीबुल्ला—

सन् १९०७ में अफगानिस्तान का अमीर हवीबुल्ला भारतवर्ष आया। लार्ड कर्जन उसको दिल्ली के दरबार में बुलाना चाहता था, परन्तु वह लार्ड कर्जन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, इसलिए हमन आने में इनकार कर दिया था। लार्ड मिंटो ने आगरा में



लार्ड मिंटो

उसका बड़ी धूम-धाम से स्वागत किया। वाइसराय के व्यवहार में वह बहुत मनुष्ट होकर वापस गया। हिन्दुओं का ध्यान रखकर बकरीद के समय पर त्यन दिल्ली में गोवध न होना दिया। सन् १९०७ में इंग्लैंड का रुम में सम्मोदा हो गया, जिससे दोनो साम्राज्यों ने अफगानिस्तान, पारस की खाटी

और तिब्बत के सम्बन्ध में अपनी नीति स्थिर कर ली। यह समझौता हवी-बुल्ला को पसन्द न आया, पर तब भी उसने भारत-सरकार के साथ मित्रता का व्यवहार न छोड़ा। सन् १९०८ में सीमा पर जंग जकाखेल अफ़्रीकियों ने फिर से उपद्रव किया, तब भी उसने उनका पक्ष न लिया। सीमा प्रदेश पर अधिकार करने की बात फिर चल पड़ी, परन्तु भारत-सचिव ने स्पष्ट शब्दों में इसको रोक दिया।

**मुसलिम लीग**—कांग्रेस में बहुत कम मुसलमान शामिल हुए थे, अँगरेजी शिक्षा का बहुत प्रचार न होने के कारण अधिकांश मुसलमानों का ध्यान देश की स्थिति की ओर न गया था। राष्ट्रीय आन्दोलन को जोर पकड़ते देखकर सन् १९०६ में कुछ नेताओं ने मुसलमानों के राजनैतिक स्वतंत्रों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस के ढंग पर 'मुसलिम लीग' की स्थापना की। मुसलमानों के कुछ प्रतिनिधि वाइसराय से भी मिले और उन्होंने यह दिखलाया कि मुसलमानों ने सदा अँगरेजों का साथ दिया है, इसलिए उनकी सत्या का खयाल न करके उनके राजनैतिक महत्त्व का बराबर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि कौंसिलों में जाने के लिए मुसलमान प्रतिनिधि केवल मुसलमानों द्वारा ही चुने जायँ। लार्ड मिंटो ने इस बात का ध्यान रखने का वचन दिया।

**कांग्रेस में मतभेद**—सन् १९०६ की कांग्रेस के सभापति बयोबुद्ध गहू नौरोजी ने 'स्वाज्य' अर्थात् उपनिवेशों के ढंग का शासन राजनैतिक आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बनलाया। इसका प्रारम्भ सरकार किस ढंग से कर सकती है, इसके लिए कांग्रेस ने कई एक सुधार बतलाये। परन्तु इसके बाद से ही कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया। सरकार की दमन-नीति के कारण एक दल का, जिसके नेता श्री बाल गंगाधर तिलक थे, सरकार पर सविस्तर विचार जाता रहा। इस दल का कहना था कि कांग्रेस को 'प्रार्थना-नीति' छोड़कर अधिक माहस से काम लेना चाहिए। सन् १९०७ में सूरत में इन दोनों दलों में बड़ा झगडा हो गया। 'नरम' और 'गरम' दल अलग-अलग

अलग हो गये। पहले दल के नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले, सर फीरोजशाह मेहता और बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे। कांग्रेस में नरम दलवालों की संख्या अधिक थी, इन्होंने 'आपनिवेशिक स्वराज्य' कांग्रेस का ध्येय माना और कानूनी उपायों द्वारा उसे प्राप्त करना निश्चित किया। साथ ही साथ यह भी नियम बना दिया कि जा लोग कांग्रेस के ध्येय और नियमों को मानने की लिखित प्रतिज्ञा करेंगे वे ही उसके सेम्बर हो सकेंगे। इस पर गरम दलवालों ने कांग्रेस छोड़ दी। तब से सन् १९१६ तक उस पर नरम दलवालों ही का अधिकार रहा।

**क्रान्तिकारी दल—**इन दिनों देश भर में घोर राजनैतिक अशान्ति थी। इसके कई एक कारण थे। लार्ड कर्जन की नीति से सारा देश असन्तुष्ट था अकाल और प्लेग से जनता पीड़ित थी, देश में धन का अभाव था, व्यापार चोपट हो गया था और पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी बढ़ रही थी। बहुत से अँगरेज अफसर दूरदर्शिता से काम न ले रहे थे, पूर्वीय बंगाल में नये लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर बैमफील्ड फुलर का शासन असह्य हो रहा था। सन् १९०५ में जापान ने रूस को परास्त किया था, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा था और नवयुवकों में बड़ी उत्तेजना फैल रही थी। इन्हीं दिनों सरकार की नीति में हताश होकर कुछ नवयुवकों का एक ऐसा दल स्थापित हो गया, जिसने सरकार का नष्ट करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। कई एक स्थानों में इसकी गुप्त समितियाँ बन गईं और अँगरेजों पर बम फेंके जाने लगे। एक मजिस्ट्रेट के धोखे मुजफ्फरपुर में बम लगाने से दो अँगरेज महिलाओं का प्राण गये। इसी तरह जहाँ-तहाँ और भी कई एक हत्याएँ हुईं।

**दमन का जोर—**इस अवसर पर सरकार ने भी बड़ी कड़ाई से काम लिया। गुप्त समितियों को ढूँढ निकालना और सच्चे अपराधियों को पकड़ना महज काम न था, इसलिए गरम दल के नेता ही, जिनका इस आन्दोलन में कुछ भी सम्बन्ध न था, सरकार के क्रोध का अधिकतर शिकार बने। पहले मना में विद्रोह फैलाने के सन्देह पर, बिना किसी प्रकार की जाँच किये हुए, सन् १८९८ के एक कानून के अनुसार, पंजाब से श्री लाला

लाजपतराय और अजीतसिंह निर्वाचित कर दिये गये। फिर 'केमरी' में सरकार के विरुद्ध तीव्र लेख लिखने के कारण श्री बाल गंगाधर तिलक



पर अभियोग चलाया गया और ६ वर्ष के लिए कैद करके उन्हें मडाले भेज दिया गया। बंगाल का उपद्रव शान्त करने के लिए ६ प्रतिष्ठित नेता भी, सन् १८९८ के कानून के अनुसार, निर्वासित कर दिये गये।

विस्फोटक पदार्थों का रखना या बेंचना अपराध बना दिया गया। समाचारपत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई। उनके लिए जमानत जमा करने का नियम बना दिया गया। राजनैतिक अभियोगों को जल्दी निपटाने

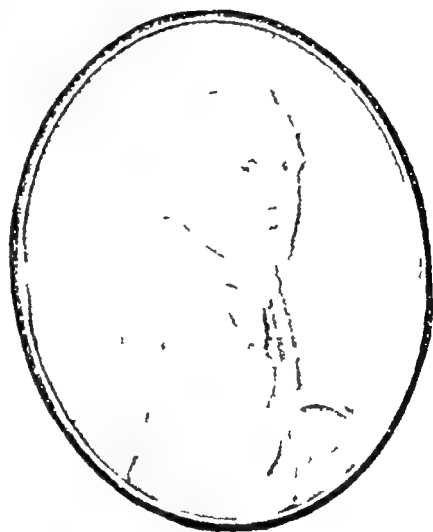
बाल गंगाधर तिलक

के लिए ज़ाबता फौजदारी का संशोधन किया गया और सरकार को, जहाँ उचित समझे, सभाएँ रोक देने का अधिकार दिया गया।

**सातवें एडवर्ड का घोषणापत्र**—सन् १९०८ में भारतवर्ष पर इंग्लैंड के राजाओं को राज्य करते हुए ५० वर्ष पूरे हुए, इसलिए इस अवसर पर सम्राट् की ओर से एक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। जोधपुर के दरबार में बाइसराय ने इसको पढ़कर सुनाया। इसमें महारानी विक्टोरिया की प्रतिज्ञाएँ दोहराई गईं, इतने वर्ष के शासन पर सन्तोष प्रकट

किया गया और प्रजाहित के लिए जो कुछ भारत-सरकार ने किया था, उसकी बड़ी प्रशंसा की गई। इसमें यह भी कहा गया कि जिम्मेदार बड़ी बड़ी नौकरियों के सम्बन्ध में जातिगत भेद मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है और प्रतिनिधि संस्थाओं के सिद्धान्त की वृद्धि के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

**जान मार्ले की नीति**—इन दिनों भारतसचिव के पद पर इंग्लैंड का सुप्रसिद्ध विद्वान् जान मार्ले काम करता था। वह भारत-सरकार की दमन-नीति को पसन्द न करता था। यह उसके उदार सिद्धान्तों के विरुद्ध थी। पर तब भी शासन की दृष्टि से, जहाँ तक बन पड़ा, उसने वाइसराय का साथ दिया। जब कभी वह देखता कि भारत-सरकार बहुत आगे बढ़ रही है, तब वह उसके रोकने का प्रयत्न करता था। बिना जाँच किये हुए नेताओं का निर्वासित करना उसे बहुत ग्वटकता था। “जंगी कानून” के नाम से उसके “रोकटो ग्वट हो जाते थे।” उसका विश्वास था कि “यदि सुधारों से



जान मार्ले

(ब्रिटिश) राज्य की रक्षा नहीं हो सकती, तो फिर किसी से नहीं हो सकती।” परन्तु इन सुधारों से उसका अभिप्राय भारतवर्ष को कभी स्वराज्य देना का न था। वह केवल शिक्षित भारतवासियों को शासन में कुछ भाग देना चाहता था। उसकी राय थी कि जहाँ तक सम्भव हो नरम ढलवाला को अपने पक्ष में मिलाये रखना चाहिए। वह गोखले के साथ बराबर परामर्श किया करता था।

**मार्ले-मिटो सुधार**—लार्ड मिटो भी जब से भारतवर्ष आया था सुधारों की आवश्यकता प्रतीत कर रहा था। उसने समझ लिया था कि देश की स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब “आंग्ल बन्द रखने” से काम न चलेगा, भारतवासियों को कुछ अधिकार अवश्य देने पड़ेंगे। इस पर विचार करने के लिए उसने एक कमेटी भी नियुक्त की थी। वह एक हिन्दु-स्तानी को अपनी ‘एक्जीक्युटिव कौंसिल’ का मेम्बर बनाना चाहता था, इसी का उसके कौंसिलवाले विरोध कर रहे थे। जातिगत भेद मिटाने की घोषणा करनेवाले स्वयं सम्राट् एडवर्ड भी इसके विरुद्ध थे। तीन वर्ष तक सुधारों के सम्बन्ध में वाइसराय की भारतमन्त्रि में लिखा-पढ़ी होती रही। अन्त में दो भारतवासी ‘इंडिया कौंसिल’ के मेम्बर बनाये गये और फलकत्ता हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर तथा ‘ऐडवोकेट जनरल’ सर सत्येन्द्रप्रमन्नभट्ट वाइसराय की कौंसिल के ‘कानूनी मेम्बर’ बनाये गये। सन् १९०९ में पार्लामेंट से सुधारबिल भी पास हो गया। इसके अनुसार लेजिस्लेटिव कौंसिलों के मेम्बरों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रान्तीय कौंसिलों में गैरसरकारी मेम्बरों की कुछ अधिकता रखी गई। बम्बई तथा मद्रास की एक्जीक्युटिव कौंसिलों के मेम्बरों की भी संख्या बढ़ा दी गई और उनमें एक हिन्दुस्तानी मेम्बर रखने की व्यवस्था की गई। अन्य प्रान्तों में भारतमन्त्रि की अनुमति से एक्जीक्युटिव कौंसिलें स्थापित करने का अधिकार वाइसराय को दिया गया। लेजिस्लेटिव कौंसिलों में मेम्बरों का प्रस्ताव पेश करने, बजट पर पूरी तरह बहस करने और एक ही विषय पर कई एक प्रश्न पूछने के अधिकार दिये गये। मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार भी मिल गया।

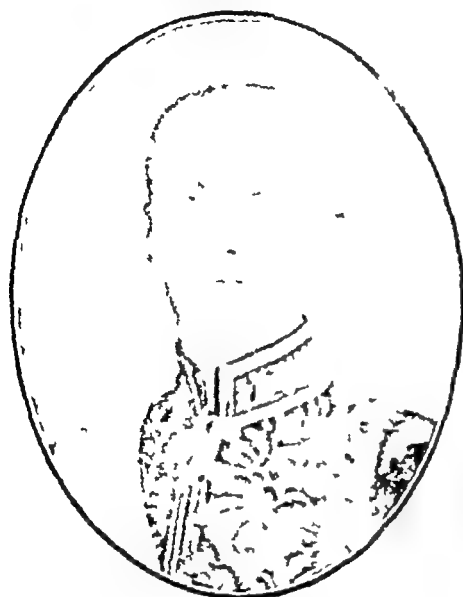
सम्प्रदायों के अनुसार निर्वाचन-क्षेत्र बनाने के सिद्धान्त को कांग्रेस ने पसन्द न किया। इसमें हिन्दू और मुसलमानों का भेद-भाव बढ गया। मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने के अतिरिक्त हिन्दुओं के साथ भी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस ने इसको गैरमुसलमान प्रजा के साथ “अन्याय” बतलाया। सुधारों के सम्बन्ध में जो नियम

बनाये गये, उनसे उनका क्षेत्र और भी संकुचित कर दिया गया। किसी प्रतिनिधि को न चुने जाने की आज्ञा देने का अधिकार वाइसराय को दे दिया गया। गरम दल के नेताओं को कौंसिलों से अलग रखने की दृष्टि में यह नियम बनाया गया। प्रान्तीय कौंसिलों में नाम भर के लिए गैरसरकारी मेम्बरो की अधिकता रखी गई, पर वास्तव में सरकार के अधिकार ज्यों के त्यों बने रहे। कांग्रेस का कहना था कि इन नियमों में “शिक्षित समाज के प्रति सरकार का अविश्वास” स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। इनमें सुधारों में जो कुछ बल था, वह भी नष्ट हो गया। इन सुधारों में स्वेच्छाचारी और प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्तों को मिलाने की चेष्टा की गई, जो सर्वथा अयम्भव है।

**मिटो की नीति**—लार्ड मिटो क सामने बड़ी कठिन समस्या थी। एक ओर तो राजनैतिक अशान्ति से घबड़ाकर अंगरेज अफसर दमन पर जोर दे रहे थे और दूसरी ओर भारत का शिक्षित समाज सुधारों के लिए आतुर हो रहा था। इन दोनों को मन्तुष्ट रखने के लिए लार्ड मिटो ने “दमन और सुधार” की नीति का अवलम्बन किया। दोनों ओर के उग्र आन्दोलनकारियों की बात को न मानकर उसने मध्य के मार्ग पर चलना निश्चिन किया। दो चार अंगरेजों की हत्याओं से घबड़ाकर उसने अपना धर्म्य न छोड़ा और वह चुपचाप अपनी नीति से काम लेता रहा। नई कोमिल द्वारा समाचारपत्र-सम्बन्धी कानून पास हो जाने पर, जब उसने देख लिया कि गरम दल सरकार का पूरा साथ दे रहा है, तब उसने निर्वागिन नताओं को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। देशी राजाओं से उसने बहुत मेल पका किया। भारत के शासन में वह उन्हें भी कुछ भाग देना चाहता था। इसके लिए उसने उनकी एक समिति बनाने का प्रस्ताव किया था। राजनैतिक आन्दोलन को दवाने के सम्बन्ध में भी उसने बड़े बड़े राजाओं से गय मांगी थी।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> वूकन, लार्ड मिटो।

**लार्ड हार्डिंज**—सन् १८१० में लार्ड मिंटो वापस चला गया और उसके स्थान पर लार्ड हार्डिंज वाइसराय बनाया गया। पहले लार्ड किचनर



लार्ड हार्डिंज

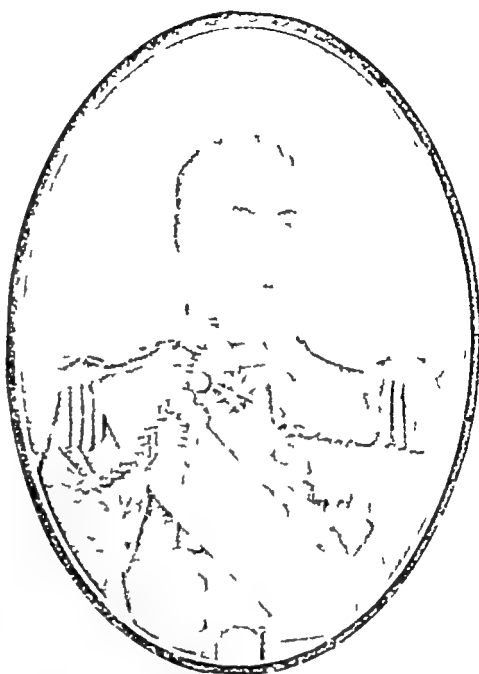
को वाइसराय बनाने की बात-चीत थी, परन्तु जान माले हमके पन में न था। लार्ड हार्डिंज का भारतवर्ष में पुराना सम्बन्ध था। सन् १८४४ में हमी का दादा गवर्नर-जनरल होकर आया था, जिसके समय में पहला सिख-युद्ध हुआ था। मिंटो के सुधारों से राजनैतिक अगान्ति दूर न हुई थी, बंगाल का आन्दोलन चल रहा था। माले ने बंगाल के विच्छेद को अनुचित मानते हुए भी उसे रद्द न किया था। उसका कहना था कि अब यह

तय हो चुका। इससे असन्तोष बढ़ रहा था।

**सम्राट् का आगमन**—सन् १८१० में सातवें एडवर्ड की मृत्यु हो गई और उसका लड़का पाँचवाँ जार्ज गद्दी पर बैठा। युवराज की हैसियत से यह पहले भारतवर्ष आ चुका था। सन् १८११ में अपने मंत्रियों की सलाह से सम्राज्ञी सहित यह फिर भारतवर्ष आया, जहाँ दिल्ली में बड़े समारोह के साथ इसका राज्याभिषेक किया गया। इसके पहले इंग्लैंड का कोई राजा भारतवर्ष न आया था। भारतवासी स्वभाव से ही राजभक्त है, सम्राट् का भारतवर्ष में भी राज्याभिषेक कराकर लार्ड हार्डिंज ने अपनी नीति-निपुणता का परिचय दिया। इस अवसर पर कई एक बड़े महत्त्व की घोषणाएँ की गईं। लार्ड कर्जन का किया हुआ बग-विच्छेद रद्द कर दिया गया। बंगाल के जो जिले अलग किये गये थे फिर उसमें मिला दिये गये



श्रीर शासन के लिए एक्जीक्युटिव कौंसिल सहित एक गवर्नर रख दिया गया। आसाम फिर चीफ कमिश्नर के अधीन रह गया और लेफ्टिनेंट-गवर्नर के अधीन बिहार तथा उड़ीसा का एक नया प्रान्त बना दिया गया। भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली कर दी गई। 'विक्टोरिया क्रॉस' नामक विख्यात पदक लडाई में पराक्रम दिखलानेवाले भारत-वानियों को भी देने का नियम कर दिया गया। गद्दी पर बैठते समय देशी राजाओं से नजराना लेने की प्रथा उठा दी गई। बहुत से कट्टी छेड़ दिये गये, पचास रुपये से कम वेतनवाले कर्मचारियों को एक महीने का अधिक वेतन इनाम में दिया गया और पचास लाख रुपया शिर्चा के लिए दान किया गया।



पॉर्चर्वे जार्ज

बंगाल के विच्छेद का रह होना कर्जन के ढल को बढा खटका। राजधानी का परिवर्तन भारत में, विशेषकर कलकत्ता में, रहनेवाले अंगरेजों को पसन्द न आया। शासन-सम्बन्धी परिवर्तन का अधिकार केवल पार्लामेंट को है, इसलिए जब ये प्रस्ताव पार्लामेंट में पेश हुए तब लार्ड कर्जन को अपने हृदय के उद्गार निकालने का अवसर मिला। इन दोनों बातों को गुप्त रखकर, बिना पार्लामेंट की मलाह लिये हुए, सम्राट् के मुख से उनकी घोषणा कराने के लिए उमन मंत्रियों की निन्दा की। इसमें सन्देह नहीं कि इस अवसर

पर यह बिलकुल नया ढंग निकाला गया था, यन्त्राट् के मुग्न में निकली हुई वातो में हर-फेर करना उचित न जान पड़ता था, ऐसी दशा में इन पर वाद-विवाद व्यर्थ था। बंगाल के विच्छेद को रद्द करने के सम्बन्ध में लार्ड कर्जन ने कहा कि इससे मुसलमान रुष्ट हो जायेंगे। बंगालियों का “बनावटी आन्दोलन” शान्त हो गया था, ऐसी दशा में इसकी कोई आवश्यकता न थी। दिल्ली को उसने “साम्राज्यो का कवरिमान” बतलाया और कहा कि वहाँ राजधानी बनाने में बड़ा खर्च पड़ेगा।

दिल्ली को राजधानी बनाने के पक्ष में भारत-सर्वकार का कहना था कि यह नगर ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही, प्राचीन स्मृतियों के कारण, इसको बड़े आदर की दृष्टि में देखते हैं। यह शिमला के निकट और भारतवर्ष के मध्य में भी है। यहाँ रेल की कई लाइने मिलती हैं और जलवायु भी अच्छा है। कलकत्ता भारतवर्ष के एक कोने में है, समुद्र-तट पर अब राजधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त बंगाल में अब गवर्नर रहेगा, उसका और वाइसराय का एक ही स्थान पर रहना ठीक नहीं जान पड़ता। यह सब ठीक होते हुए यह अवश्य मानना पड़ेगा कि नई राजधानी के बनाने में बहुत धन फँका गया। जितना तत्परीना हुआ था, उससे बहुत अधिक रुपया खर्च हो चुका है, परन्तु इस साल तक काम समाप्त नहीं हुआ है।

**दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह**—सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में कुछ अंगरेज और डच अफ्रिका पहुँचे। इन दोनों ने वहाँ के हवशियों को दबाकर बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया। नैटाल प्रदेश में गन्ना, चाय और काफी की खेती में बराबर काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। पहले हवशियों को फँसाने का प्रयत्न किया गया, उसमें सफलता न होने पर भारत-सरकार को लिखा गया। भारतवर्ष में भूखे मरनेवालों की कमी न थी। सन् १८४० से हिन्दुस्तानी मजदूरों का वहाँ जाना प्रारम्भ हो गया। इनमें पाँच वर्ष तक काम करने के लिए एक ऐग्रीमेंट (इकरारनामा) लिखा जाने लगा। मजदूरों में यह ‘गिरमिट’ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, इसी लिए

पेग्रीमेंटवाले मजदूर 'गिरमिटिया' कहलाने लगे। नेटाल में इनकी आवादी बढ़ने पर कुछ हिन्दुस्तानी व्यापारी भी पहुँच गये। थोड़े ही दिनों में उनका व्यापार खूब चल पड़ा। हवशी और डच लोगों से, जिन्हें अँगरेज वृणा की दृष्टि से देखते थे, हिन्दुस्तानियों की पटने लगी और वे सब रियामतों में पहुँच गये। अपनी मितव्ययता और परिश्रम से उन्होंने धन जमा कर लिया और जमीनें खरीद लीं। हिन्दुस्तानियों की यह बढ़ती गोरों को खटकने लगी और वे उनको तंग करने लगे। मुक्त हुए कुलियो से २१ पौंड साल का कर मांगा जाने लगा। अच्छी अच्छी ज़मीनें छोन ली गई और राजनैतिक अधिकार भी रह करने का प्रयत्न होने लगा। सन् १८६६ में डच लोगों का, जो 'बोअर' के नाम से प्रसिद्ध है, अँगरेजों से घोर युद्ध हुआ। इसमें साम्राज्य के नाते से हिन्दुस्तानियों ने अँगरेजों का पूरा साथ दिया। इसका भी कुछ ध्यान न करके उनका हर तरह से अपमान किया गया। सन् १८६३ में वहां श्री मोहनदास कर्मचन्द गान्धी बैरिस्टरी कर रहे थे। उनके उद्योग से प्रवासी हिन्दुस्तानियों में आत्म-सम्मान और एकता के भाव जागृत हुए। गान्धीजी न कई अनुचित नियमों का घोर विरोध किया, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा और तरह तरह के कष्ट भोगने पड़े।

सन् १८९३ में वहाँ एक नया कानून पेश किया गया। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि हिन्दुस्तानी मजदूर वहाँ के निवासी न समझे जायेंगे और स्वदेश जाने पर उन्हें लौटने का अधिकार न होगा। प्रो. स्टेट की रियासत में व्यापार या खेती-वारी न करने की प्रतिज्ञा करने पर वहाँ जाने की आज्ञा दी जायगी, जिस धर्म में बहु-स्त्री-विवाह की प्रथा है, उस धर्म के अनुसार किया हुआ विवाह अप्रामाणिक माना जायगा और प्रत्येक हिन्दुस्तानी को अपना विवाह अदालत में जाकर रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। इसका घोर विरोध किया गया। लगभग १५०० हिन्दुस्तानियों ने गान्धीजी की अध्यक्षता में सत्याग्रह प्रारम्भ किया। यह समाचार मिलने पर भारतवर्ष में भी बड़ा अमन्तोष फैला। परन्तु इस अवसर पर लार्ड हार्डिज ने बड़े माहम नाम लिया। उसने मद्रास के भाषण में अफ्रिका के इस नये कानून को

“अन्यायपूर्ण” बतलाया, सत्याग्रहियों के प्रति महानुभूति प्रकट की और अफ्रिका की सरकार से जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का अनुरोध किया। इस बात को वहाँ की सरकार ने मान लिया और मयफो जेल से छोड़ दिया। प्रवासी हिन्दुस्तानियों के पक्ष का समर्थन करने के लिए गोखले भी अफ्रिका गये। अन्त में समझौता हो गया, जिससे वहाँ के हिन्दुस्तानियों की दशा कुछ सुधर गई।



मदनमोहन मालवीय

आधुनिक साहित्य और विज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन और उनमें अन्वेषण करना, ऐसी वैज्ञानिक, आर्थिक तथा व्यापारिक विद्याओं का काम में लाने योग्य शिक्षा के साथ फैलाना, जिनसे देश की सम्पत्ति बढ़े, और धर्म तथा सदाचार की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को चरित्रवान् बनाना इस विश्व-विद्यालय के मुख्य उद्देश्य है। ‘सेंट्रल हिन्दू-कालेज’, जिसको मिसेज़ वेसेंट ने अपने कुछ मित्रों की सहायता से सन् १८९८ में स्थापित किया था, इसका पहला कालेज हुआ। सन् १९२६ तक विश्वविद्यालय के लिए १ करोड़ २१ लाख

### काशी-हिन्दू-विश्व-

विद्यालय—सन् १९१६

में श्री पंडित मदनमोहन मालवीय के उद्योग से काशी में हिन्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना हुई। हिन्दू-शास्त्रों और संस्कृत-साहित्य की शिक्षा द्वारा हिन्दुओं के सर्वोत्तम विचारों तथा उनकी गौरवमयी प्राचीन सभ्यता के प्रसिद्ध गुणों की रक्षा और उनका प्रचार करना,

रुपया जमा हो गया। सभी श्रेणी के लोगों ने इसमें चन्दा दिया और सरकार ने भी सहायता की। यह अखिल भारतीय सस्था है। इसमें सभी प्रान्तों के



### हिन्दू विश्वविद्यालय ( विज्ञान-विभाग )

यत्र शिक्षा पाते हैं। हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य जातियों के छात्र भी इसमें बिना किसी रोक-टोक के पढ़ सकते हैं।

**यूरोपीय महायुद्ध**—सन् १९१४ में यूरोप में बला भीषण युद्ध छिट गया। इसके जटिल राजनैतिक कारणों की विवेचना यहां नहीं हो सकती, इतना ही कहना काफी है कि इसकी नैयारियां बहुत दिनों से हो रही थी। यूरोप के भिन्न भिन्न राज्य एक दूसरे में जल रहे थे और इनके दो मुख्य गुट बन गये थे। आस्ट्रिया, जर्मनी तथा इटली एक ओर थे और दूसरी ओर फ्रांस, रूस तथा इंग्लैंड के राज्य थे। जून सन् १९१४ में आस्ट्रिया का युव-

राज ऑस्ट्रिया से मार डाला गया। इसका दोष सर्बिया के मध्ये मढ़कर आस्ट्रिया ने उस पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर रूस सर्बिया की सहायता के लिए खड़ा हो गया। इस पर जर्मनी ने रूस और फ्रांस से युद्ध छेड़ दिया। इंग्लैंड इस समय तक अलग था। मनु १८७१ में जर्मनी और इंग्लैंड दोनों वेलजियम की रक्षा का वचन दे चुके थे, पर जब इस मन्धि को “एक कागज का टुकड़ा” मानकर जर्मनी की सेना वेलजियम होकर फ्रांस की ओर बढ़ने लगी, तब इंग्लैंड भी फ्रांस और रूस के साथ, जर्मनी और आस्ट्रिया के विरुद्ध, युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी के साथ तुर्कों के मिल जाने से एशिया में भी युद्ध छिड़ गया।

इस अवसर पर सारे भारतवर्ष ने अंगरेजों का साथ दिया। राजा, महाराजा और नवाबों ने धन से सरकार की सहायता की और अपनी सेनाएँ युद्ध में भेजीं। कई एक राजाओं ने स्वयं युद्ध में भाग लिया। जनता ने भी सरकार की सहायता करने में कोई बात उठा न रखी। तुर्कों के सुलतान मुसलमानों के खलीफा थे। उसके विरुद्ध ग़ल्ले उड़ाने पर भी राजभक्त मुसलमानों ने सरकार का साथ न छोड़ा। इस समय भारतवर्ष अंगरेज सैनिकों से बिलकुल खाली सा हो गया था, पर तब भी कहीं किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। बड़े कठिन अवसर पर भारत के वीर सिपाहियों ने फ्रांस जाकर ईंग्रिज, न्यूशपल और लू की लड़ाइयों में जर्मनी के भयंकर आक्रमण को रोका। इन लड़ाइयों से युद्ध का रंग ही बदल गया।

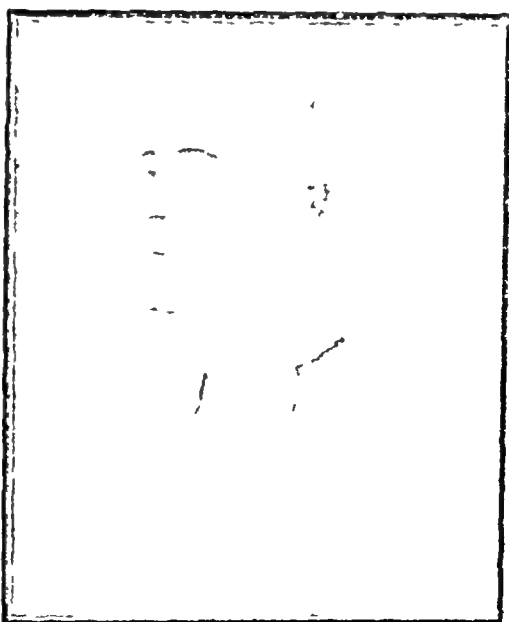
मेसोपोटामिया (इराक) की लड़ाइयों में भी भारतीय सेना ने बड़ी मदद की। मराठों की पल्टन ने बसरा जीत लिया। परन्तु टानशेड की सेना को बगदाद की घड़ाई में हार माननी पड़ी। इसमें रसद और चिकित्सा का ठीक प्रबन्ध न होने के कारण सेना को बड़ा कष्ट हुआ। इसकी जाँच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने भारत सरकार की बड़े तीव्र शब्दों में आलोचना की। माटेग्यू ने उसकी शासनव्यवस्था को “हठी, कठोर तथा असामयिक” बतलाया। लार्ड किचनर की बात मानकर सेना का शासन-विभाग, प्रधान सेनापति के अधीन रखने के कारण, इस प्रबन्ध में बड़ी शसु-

विधायें हुईं । सन् १९१७ में बगदाद पर अंगरेजों का अधिकार हो गया । इतन ही में पैनेस्टाइन ( फिलस्तीन ) होकर जनरल एलेनबी की सेना, जिसमें अधिकांश हिन्दुस्तानी सिपाही थे, था गई और उसने जस्मेलम और दमस्क के विख्यात नगरों को जीत लिया । अंगरेजों की इन विजयों से तुर्की के गलीफा की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई । यह युद्ध चार वर्ष तक बराबर चलता रहा । जर्मनी के व्यवहार से अग्रन्तुष्ट होकर अमरीका भी 'मित्र राष्ट्रों' की श्रेणी से युद्ध में शामिल हो गया । इटली, यूनान और जापान ने भी उनका साथ दिया । राज्य-क्रान्ति हो जाने के कारण रूस युद्ध से अलग हो गया था, जर्मनी में भी इसके लक्षण दिखलाई पड़ रहे थे । विजय की कोई आशा न देखकर जर्मन सम्राट् म्पर विलियम हालेड भाग गया और जर्मनी ने हार स्वीकार कर ली । सन्

१९१९ में सन्धि हो गई । इस सन्धि-पत्र पर भारत की ओर से महाराजा वीकानेर और लार्ड रिड ने हस्ताक्षर किये ।

**लार्ड चेम्सफर्ड—**

लार्ड हार्डिज के शासन में भारतवासी बहुत सन्तुष्ट थे । सन् १९१२ में दिल्ली की चादनी चौक में उस पर बम भी फेंका गया, पर उसने इसका कुछ भी खयाल नहीं किया । सन् १९१४ में उसकी अवधि समाप्त होने पर कांग्रेस ने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अवधि बढ़ाने का



**चेम्सफर्ड**

प्रस्ताव पास किया । इन दिनों लड़ाई की दशा बड़ी नाजुक थी, इसलिए





का प्रान्तीय सरकारों पर अधिकार ज्यों का त्यों बना रहा। कैमिलो में नामजद और सरकारी मस्त्रों की सहायता से सरकार की ही जीत होती रही, जिससे प्रतिनिधियों को इनकी निरर्थकता का पूरा अनुभव हो गया। लार्ड मिटो के समय में पास किये हुए दमन-सम्बन्धी कानूनों के कारण भी बड़ा असन्तोष था। लार्ड हार्डिज पर बम फेंके जाने के बाद राजनैतिक पट्टियों के सम्बन्ध में जावता फौजदारी के नियम और भी कड़े बना दिये गये थे। "विश्वास में विश्वास उत्पन्न होता है" कैमिलो में यह बराबर कहते रहने पर भी प्रतिनिधियों की कुछ सुनवाई नहीं होती थी। जिम्मेदार पदों पर हिन्दुस्तानियों को नियुक्त करने की ओर भी अधिक ध्यान न दिया जाता था। 'गोरे और काले' का भेद भी बना था। बिना लाइसेंस के भारतवासियों को हथियार रखने की आज्ञा न थी। अपने देश की रक्षा में उन्हें कोई भाग न दिया जाता था। सैनिक बाल्टियर बनने तक का उन्हें अधिकार न था। उपनिवेगों में उनके साथ बड़ा अनुचित व्यवहार किया जाता था।

इन्हीं कारणों से युद्ध के समय में भी राजनैतिक आन्दोलन बन्द न हुआ था, बल्कि युद्ध छिड़ने से इसमें एक नया जीवन आ गया था। प्रजातन्त्र के लिए समार को सुरक्षित बनाना, स्वेच्छाचारी शासन को नष्ट करना और छोटे राष्ट्रों की रक्षा करना, युद्ध के उद्देश्य बनलाये जाते थे। अमरीका के राष्ट्रपति विल्मन न "आत्मनिर्णय" के सिद्धान्त को समार के भावी राजनैतिक प्रबन्ध का आधार बतलाया था। ऐसी दशा में भारतवासियों के लिए यह आशा करना स्वाभाविक था कि जिन सिद्धान्तों के लिए अंगरेज यूरोप में लड़ रहे थे, उनके लाभ में वे भारतवर्ष को, जिसने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना धन लुटाया और रक्त बहाया है, वंचित न रखेंगे। 'युद्ध-समिति' और 'साम्राज्य-सम्मेलन' में भारतीय प्रतिनिधियों के बुलाये जाने से, यह आशा और भी पक्की हो रही थी। भारतवर्ष के राजनैतिक जीवन पर रूस की सामंजसिक राज्यक्रान्ति का भी, जिसने जार के स्वेच्छाचारी शासन को समूल नष्ट कर डाला था, प्रभाव पड़ रहा था। युद्ध के समय की कठिनाइयों में रूस वृत्त के लिए एक 'गठर पार्टी' बन गई थी। मिमेज एनी वेमेट

भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों से परामर्श किया। लार्ड चेम्सफर्ड के साथ भारत की मुख्य समस्याओं के प्रतिनिधियों तथा नताग्रो से भी वह मिला। देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसने राजाओं से भेट की और सुधार सम्बन्धी अपने प्रस्तावों को उसने एक रिपोर्ट के स्वरूप में पार्लामेंट के सामने पेश किया। सन् १९१८ में उसने सर मत्थेन्द्रप्रसन्नमिश्र को, जिसे 'लार्ड' की उपाधि दी गई भारत का उपसचिव बनाया। माटेग्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट पर दो वर्ष तक विचार होता रहा। इसके प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारतवर्ष में फिर राजनैतिक मतभेद हो गया। नरम दलवालों ने इसके मुख्य सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया, परन्तु कांग्रेस ने, जिसमें थोड़े गरम दलवालों की अधिकता थी, "निराशा और असन्तोष" प्रकट किया। मुख्य मुख्य दलों के प्रतिनिधि इंग्लैंड गये और उन्होंने पार्लामेंट की कमेटी के सामने अपने विचार प्रकट किये। कुछ हेर-फेर के बाद सन् १९१९ में सुधार-कानून पास हो गया, जिसमें भारतवर्ष की शासनव्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया।

**भारतसचिव और इंडिया कांसिल**—भारतवर्ष के शासन के लिए पार्लामेंट के प्रति भारतसचिव जिम्मेदार मान लिया गया और उसका वेतन इंग्लैंड के स्वज्ञान से दिया जाने लगा। शासन का कुल निरीक्षण उसी के हाथ में है। भारत-सरकार को बराबर उसकी मलाह लेनी पड़ती है। उसकी अधिकार-सीमा इतनी बड़ी हुई है कि भारत-सरकार को बहुत कम स्वतन्त्रता रह जाती है। इंडिया कांसिल का मुख्य काम भारतसचिव को मलाह देना रह गया। इसमें हिन्दुस्तानी मेम्बरों की संख्या दो से तीन बढ़ी गई। कांग्रेस पहले से ही इस कांसिल के तोट देने पर जोर दे रही थी, परन्तु इसका कुछ भी ध्यान नहीं किया गया। इसमें अधिकतर भारत में लाटे हुए सिविलियन होते हैं, जो हर एक बात को निपट्ट दृष्टि से नहीं देखते। हिन्दुस्तानी मेम्बरों को भारतसचिव ही नामजद करना पड़ा। प्रायः ऐसा अवसर आ जाता है, जब इनमें से कोई भी इंग्लैंड में परामर्श नहीं रहता।

**भारत-सरकार**—गवर्नर-जनरल की एक्जीक्युटिव कौंसिल के हिन्दु-स्तानी मेम्बरो की संख्या भी बढ़ाकर तीन कर दी गई। इसके मेम्बर राजाजा द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और इसका सभापति गवर्नर-जनरल होता है। इसके मेम्बरो के हाथ में शासन के भिन्न भिन्न विभाग रहते हैं। कानून बनाने के लिए 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल' के स्थान पर दो सभाएँ कर दी गईं, एक 'लेजिस्लेटिव असेम्बली' ( बड़े व्यवस्थापक सभा ) और दूसरी 'कौंसिल ऑफ स्टेट' ( राज्यपरिषद )। लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बरो की संख्या १४३ है, जिसमें १०३ निर्वाचित और बाकी सरकारी अफसर तथा नामजद मेम्बर होते हैं। निर्वाचित मेम्बरो में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव जनता द्वारा होता है। 'कौंसिल ऑफ स्टेट' के मेम्बरो की संख्या ६० है, जिनमें ३४ निर्वाचित मेम्बर होते हैं। परन्तु इनके निर्वाचन के ऐसे नियम रखे गये हैं, जिनके कारण बड़े बड़े जमीन्दार और धनी लोग ही अधिक चुने जाते हैं। गवर्नर-जनरल उन दो सभाओं में से न किसी का मेम्बर ही होता है और न सभापति। लेजिस्लेटिव असेम्बली का सभापति मेम्बरो द्वारा चुना जाता है, पर कौंसिल ऑफ स्टेट के सभापति को सरकार नियुक्त करती है। लेजिस्लेटिव असेम्बली की अवधि साधारणतः तीन वर्ष की होती है और कौंसिल ऑफ स्टेट का हर पांचवें वर्ष चुनाव होता है।

कानून बनाने के लिए किसी प्रस्ताव का दोनो सभाओं द्वारा पास होना और गवर्नर-जनरल द्वारा उसका मजूर होना आवश्यक है। दोनो सभाओं में मतभेद होने पर एक साथ वाद-विवाद हो सकता है। बजट के कुछ भाग में कमी-वर्गी करने का भी इन सभाओं को अधिकार है, पर इसका अधिक भाग ऐसा है, जिसमें सेना का खर्च, धन तथा और कई ऐसी रकमें रहती हैं, जिन पर केवल ब्रह्म हो सकती है, पर कोई कमी नहीं की जा सकती। सरकारी कर्ज, भारतवर्ष की आमदनी, सैनिक प्रबन्ध तथा देशी या बाहरी राज्यों के प्रति सम्बन्ध के विषय में इन सभाओं को कुछ भी अधिकार नहीं है। गवर्नर-जनरल इन सभाओं को स्थगित, भंग तथा आमंत्रित कर सकता है।

हं और उनमें आवश्यकता होने पर भाषण भी कर सकता हूं। किसी बिल को गवर्नर-जनरल "ब्रिटिश भारत की शान्ति, रक्षा तथा हित" की दृष्टि में सभाओं की इच्छा के विरुद्ध भी पास या रद्द कर सकता है। बजट में सम्बन्ध में भी उसको इसी तरह के अधिकार हैं। वह या उसकी काँग्रेस के सेन्सर भारत की व्यवस्थापक सभाओं के प्रति जिम्मेदार नहीं है। ये सभाएँ केवल आलोचना कर सकती हैं, जिसमें इतना लाभ अवश्य होता है कि लोकमत प्रकट हो जाता है, अन्यथा इनकी अधिकार-सीमा बहुत संकुचित है। काँग्रेस आफ स्टेट का ऐसा संगठन किया गया है कि वह बराबर सरकार का नाथ देती है। लेजिस्लेटिव असेम्बली को गवर्नर-जनरल अपने विशेषाधिकार के अकुश में बराबर दबाये रख सकता है।

**प्रान्तीय सरकार—**बम्बई, मदरास और बंगाल में तो गवर्नर ये ही अब अन्य बड़े बड़े प्रान्तों के लेफ्टिनेंट-गवर्नर भी गवर्नर बना दिये गये और उनकी सहायता के लिए एक्जीक्युटिव कांसिलें स्थापित कर दी गई, जिनमें एक या दो हिन्दुस्तानी सेन्सर रखने की व्यवस्था भी रखी गई। इनके प्रतिरिक्त लेजिस्लेटिव कांसिलों के चुने हुए सेन्सरों में से दो या तीन सत्री नियुक्त करने का अधिकार भी प्रान्तीय गवर्नरों को दिया गया। प्रान्त का शासन, सत्रियों तथा एक्जीक्युटिव काँग्रेस के सेन्सरों में बांट दिया गया। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग तथा अन्य छोटे छोटे विभागों का भार सत्रियों को सौंपा गया और न्याय, शान्ति-स्थापन, पुलिस, दम तथा ग्रामद्वी की विभागों पर एक्जीक्युटिव काँग्रेस को अधिकार दिया गया। इस तरह शासन के दो विभाग कर दिये गये, इसी लिए यह व्यवस्था 'डायर्का' अर्थात् 'दाहरी शासन-व्यवस्था' के नाम से प्रसिद्ध है। सत्री काँग्रेस के प्रति जिम्मेदार समझे जाते हैं और उनका वेतन इसी के द्वारा स्वीकार होता है। कांसिलों के सेन्सरों की संख्या घटा दी गई और उनमें निर्वाचित सेन्सरों का अधिकार रखी गई। प्रान्तीय गवर्नरों को भी विशेषाधिकार दिये गये।

भारतीय और प्रान्तीय सरकारों की अधिकार-सीमाओं को निश्चित करने का भी प्रयत्न किया गया। देश-रक्षा, परराष्ट्र-सम्बन्ध, व्यापार-नानि, सिद्धा,

तार, डाक तथा अन्य ऐसे विभागों पर भारत-सरकार का अधिकार बना रहा। परन्तु स्थानीय विषय, जैसे न्याय, गामन, म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का प्रबन्ध, सफाई, खेती और शिक्षा ऐसे विषय प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिये गये। आमदनी का भी बटवारा किया गया। मालगुजारी, आवकारी, सिचाई और स्टाम्प की आमदनी प्रान्तीय सरकारों को दे दी गई और इनकम टैक्स, नमक, अफीम तथा रेलों की आमदनी भारत-सरकार के पास रह गई। इतने से भारत-सरकार का खर्च पूरा न पड़ता था, इसलिए प्रान्तों द्वारा उसे एक सालाना रकम देने का नियम बनाया गया। इससे प्रान्तों ने बड़ा विरोध किया। प्रान्तीय सरकारों को कर्ज लेने और कुछ टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया गया। भारत-सरकार का प्रान्तीय सरकारों पर इस समय भी बहुत अधिकार है। हर एक कानून के लिए गवर्नर-जनरल की मंजूरी आवश्यक है।

इस प्रबन्ध से खर्च बहुत बढ़ गया। मंत्रियों को केवल खर्चवाले विभाग दिये गये। रुपये के लिए उन्हें गवर्नर का मुँह ताकना पड़ता है। अध्यक्ष एक्जीक्यूटिव कांसिल का ही मेम्बर होता है। इसके मेम्बरों के हाथ में जो विभाग रहते हैं, वे 'रिजर्व्ड' (रक्षित) कहलाते हैं। इनके खर्च में यदि लेजिस्लेटिव कांसिल कोई कमी करे, तो उसके मानने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं है, पर यह बात मंत्रियों के विभाग के सम्बन्ध में, जो 'ट्रांसफर्ड' (हस्तान्तरित) कहलाते हैं, नहीं है। कांसिल में जिस दल की अधिकता हो, उसी से मंत्रियों को चुनना चाहिए, तभी वे कांसिल के विश्वासपात्र बन सकेंगे और अपनी नीति को काम में ला सकेंगे। परन्तु ऐसा करने का कोई नियम नहीं है, गवर्नर जिस दल से चाहता है मंत्री चुन लेता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मंत्रियों को अपना काम चलाने के लिए सरकारी तथा नाम-जद मेम्बरों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।

**निर्वाचन**—पहले प्रान्तीय कांसिलों के मेम्बरों का निर्वाचन, म्युनि-सिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा होता था और भारतीय कांसिल में प्रान्तीय कांसिलों से प्रतिनिधि जाते थे। अब इन मेम्बरों का

निर्वाचन जनता के हाथ में आ गया। परन्तु सम्पत्ति को आधार मानकर निर्वाचकों के लिए ऐसे नियम बनाये गये कि सैकड़ों पीछे दो आदमियों को भी वोट देने का अधिकार मुश्किल से मिला। स्त्रियाँ को वोट देने का अधिकार देना या उन्हें प्रतिनिधि बनाना कौंसिलों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। हिन्दू और मुसलमानों के सम्बन्ध में लखनऊ का समझौता स्वीकार कर लिया गया और यूरोपियन तथा सिखों को भी अपने प्रतिनिधि अलग अलग चुनने का अधिकार दे दिया गया। माटेग्यू साम्प्रदायिक निर्वाचन के सिद्धान्त को पसन्द न करता था। उसका कहना था कि इसमें नागरिकता के भाव की अपेक्षा पक्षपात बढ़ जाता है। परन्तु सन् १९०६ में मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग चुनने का अधिकार दिया जा चुका था, इसलिए उसको यह स्वीकार करना पड़ा।

**नरेन्द्रमंडल**—देशी राजा और नवाबों का भी एक मंडल बनाया गया, जो 'चेम्बर ऑफ प्रिंसेज' कहलाता है। इसका सभापति वाइसराय होता है। यह देशी राज्य-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करता है और वाइसराय को सलाह देता है। इसके सगठन से बड़े बड़े राज्य सन्तुष्ट नहीं हैं। हैदराबाद, मसूर तथा अन्य कई एक बड़े राज्य इसमें इस समय तक शामिल नहीं हुए हैं।

**पार्लामेंट का अधिकार**—इस नये कानून की भूमिका में भारतवर्ष पर पार्लामेंट का पूर्ण अधिकार स्पष्ट कर दिया गया और यह भी नियम बनाया गया कि हर दसवें वर्ष एक कमीशन द्वारा शासन की जांच की जाय और पर इसकी रिपोर्ट के अनुसार परिवर्तन किये जायें। आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को, जिस पर युद्ध में इतना जोर दिया गया था, यह सर्वथा प्रतिकूल है। इस कानून के अनुसार भारत के भाग्य का निर्णय उसके नहीं बल्कि पार्लामेंट के हाथ में है।

**सुधारों का प्रारम्भ**—सन् १९१६ के अन्त में सम्राट् की ओर से एक घोषणापत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सुधारों के लिए मजबूरी दत्त हुए। यह बताया गया कि भारतवर्ष को यथासम्भव सभी सुख देने का प्रयत्न किया जाय, परन्तु उसके हित की रक्षा और उसके शासन के चलाने का अधिकार

वहाँ के निवासियों को इस समय तक नहीं दिया गया था, जिसके बिना किसी देश की उन्नति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती।” उसी का प्रारम्भ अब इन सुधारों से किया जाता है और आशा की जाती है कि सरकारी आफिस और प्रजा के नेता, दाना मिलकर इनको सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। नई समस्याओं को खोलने के लिए पहले युवराज आनवाला था, परन्तु बाद में सन् १९०१ में सम्राट् का चचा ज्यू ऑफ कनाट आया। इसने दिल्ली में राजकीय मन्देश पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि वर्षों से मन्देश और राजभक्त भारतवासी अपनी मातृभूमि के लिए ‘साम्राज्य’ का स्वप्न देख रहे थे, उसके लिए अब अवसर दिया जा रहा है। ज्यू ने अपने भाषण में ब्रिटिशों के साथ यह बतलाया कि भारतवर्ष में शासन का आधार “बल और भय” नहीं है। बाइसराय के शब्दों में उसने यह भी कहा कि “स्वेच्छाचारी शासन का सिद्धान्त” अब त्याग दिया गया। सन् १९१६ में अमृतसर की कांग्रेस ने सुधारों के प्रति अपना असन्तोष प्रकट किया। इस पर नरम दलवाले कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने अपनी दूसरी सभा स्थापित की, जो “नेशनल लिबरल फेडरेशन” के नाम से प्रसिद्ध हुई। सन् १९२० में नई कोसिलों का पहला चुनाव हुआ, जिसमें समझौते के कारण कांग्रेस ने कोई भाग न लिया। नरम दलवालों ने सरकार का साथ दिया और उनके कई एक नेता भिन्न भिन्न प्रान्तों में मंत्री बनाये गये। लार्ड सिंह बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किये गये।

**रोलट-बिल-सत्याग्रह**—युद्ध के समय क्रान्तिकारी कार्यों को रोकने के लिए ‘भारत-रक्षा-कानून’ बनाया गया था। सरकार ने राजनैतिक आन्दोलन को दबाने के लिए इसके प्रयोग न करने का वचन दिया था, पर तब भी कई बार इसका दुरुपयोग किया गया। इसी के अनुसार ‘होमरूल आन्दोलन’ को दबाने का प्रयत्न किया गया। युद्ध में असाधारण सहायता और नये सुधारों की घोषणा से यह आशा थी कि युद्ध के साथ साथ साधारण स्वतंत्रता में वापस डालनेवाले इस कानून का भी अन्त कर दिया जायगा। परन्तु ऐसा न करके सरकार ने इंग्लैंड के जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में

हम प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसने गुप्त रीति में जांच करके यह निश्चित किया कि भारतवर्ष में इस समय भी बहुत से क्रान्तिकारी मौजूद हैं इसलिए बिना किसी ऐसे कानून के हिया का रोकना सम्भव है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कॉमिल में दो कानून पेश किये, जिनमें पुलिस को बहुत अधिकार दिये गये और राजविद्रोह-मन्त्रन्धी मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए नियम बनाये गये। गान्धीजी ने इनको “न्याय तथा स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के विरुद्ध और मनुष्यों के उन प्रारम्भिक अधिकारों के जिन पर जनसमाज तथा राज्य अवलम्बित हैं नष्ट करनेवाला” बतलाया और इनके विरुद्ध सत्याग्रह करना निश्चित किया। सत्याग्रह की प्रतिज्ञा में कहा गया कि हम लोग इन तथा अन्य ऐसे ही कानूनों को न मानेंगे और हम सड़के में “धर्मपूर्वक सत्य का आश्रय ग्रहण करके किसी के जीवन या सम्पत्ति पर आघात न करेंगे।” इसी सम्बन्ध में ता० ६ अप्रैल सन् १९१६ को देश भर में हड़ताल मनाई गई। दिल्ली में ता० ३० मार्च को ही हड़ताल मनाई गई, वहाँ कुछ दंगा होने पर गोलिया चलाई गई। सड़कें में आते हुए गान्धीजी गिरफ्तार करके वापस कर दिये गये। यह समाचार मिलने पर अहमदाबाद तथा उसके आस-पास कई स्थानों में कुछ स्पष्टवृत्त हुआ।

**पंजाब में अशान्ति**—यूरोप के युद्ध में केवल पंजाब में ३६०००० पढ़ा भेजे गये। इनके भरती करने में बहुत सख्ती में काम लिया गया। सन् १९१८ में दिल्ली की ‘युद्ध-सभा’ के बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट-गवर्नर पर माइकेल ओडायर ने स्वर्य कहा था कि “हमें मेना के लिए दो लाख आत्मी चाहिए, सम्भव हों तो रजामन्त्री से, नहीं तो जबरदस्ती से।” व्यवहार में इसी नीति से काम लिया गया और जनता के साथ बहुत जबरदस्ती की गई। इसी तरह लटार्ड के लिए कर्ज लेने में भी ज्यादती की गई। कुछ सप्ताहों के कारण भी जनता में बड़ा असन्तोष था। तुर्की के प्रति ग्लेड की नीति से सुगममान भी असन्तुष्ट थे। इतने ही में गान्धीजी का सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। इस पर ओडायर ने राष्ट्रीय पत्रों का



पंजाब में आना बन्द कर दिया और कई एक नेताओं की भर्त्सना की। शिष्टि नेताओं के प्रति उसका व्यवहार बहुत अनुचित होता था, अपने निन्दनीय आचरणों के कारण, कैमिल में एक बार उसे माफी मागनी पड़ी थी। सुधारों के साथ भी उसकी सहानुभूति न थी। ता० ६ अप्रैल की हड़ताल में कोई उपद्रव न होने पर भी उसने बहुत चिड़कर अमृतसर के कुछ नेताओं को निर्वासित कर दिया और गान्धीजी को पंजाब आने में रोक दिया।

**भीषण हत्याकांड**—उसके इन कार्यों से अमृतसर में बड़ी उत्तेजना फैल गई। नेताओं को छुड़ाने की प्रार्थना करने के लिए एक बड़ा भारी जलूस डिप्युटी कमिश्नर के बंगले की तरफ चल पड़ा। इन लोगों के पास कोई हथियार न थे, पर तब भी इन पर गोली चलाई गई, जिसका फल यह हुआ कि कुछ लोगों का घैर्य जाता रहा और उपद्रव मच गया। कई एक अंगरेज मार डाले गये, एक बैंक का गोदाम लूट लिया गया और टाउनहाल में आग लगा दी गई। इस गड़बड़ में बदमाशों को अपना काम बनाने का अच्छा अवसर मिल गया। इन थोड़े मनुष्यों के उपद्रव पर, जिन्हें शान्त नागरिक नहीं रोक सकते थे, समस्त नागरिकों को डंड देना निश्चित कर लिया गया। जनरल डायर की आज्ञा से ४ मनुष्यों का जमाव गैरकानूनी बना दिया गया, परन्तु इसकी पूरी तरह से मुनादी नहीं की गई। ता० १३ अप्रैल को तीसरे पहर जलियानवाला बाग में एक सभा हो रही थी। यह बैसाखी का दिन था, जब अमृतसर में यात्रियों की खूब भीड़ होती है। सभा में लगभग २० हजार आदिमियों की भीड़ थी, स्थान घिरा हुआ था, जिसमें केवल एक मुख्य रास्ता था। सभा का समाचार मिलने पर जनरल डायर ६० सैनिक और २ मशीनगन लेकर वहाँ पहुँच गया। उसने “तीस सेकेंड” में अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और गोली चलाने की आज्ञा दे दी। भीड़ के भागने पर भी गोली चलाना बन्द नहीं किया गया। जनरल डायर का कहना था कि “मैं इसे पूरा तितर-बितर होने तक गोली चलाते रहना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यदि मैंने थोड़ी गोलीयाँ चलाई होती तो यह मेरी भूल होती।”

इसमें लगभग एक हजार निरपराध मनुष्यों की जाने गई और बहुत न घायल हुए, जिनकी सेवा, शुश्रूषा और चिकित्सा का कोई उचित प्रबन्ध न किया गया।<sup>१</sup> पंजाब के पाँच जिलों में जंगी कानून जारी कर दिया गया। कितने ही नेता निर्वासित कर दिये गये, शान्त नागरिकों को हर तरह से अपमानित और पीड़ित किया गया। पेट के बल रेंगने का ढंढ दिया गया और हर एक अंगरेज को सलाम करने का नियम बनाया गया। पंजाब की इन घटनाओं से देश भर में रोष फैल गया और सरकार की कठोर नीति की वड़े तीव्र शब्दों में आलोचना की गई। कांग्रेस की ओर से जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसने सर माइकेल ओडायर की नीति को पंजाब के अमन्तोप का मुख्य कारण बतलाया और जनरल डायर की कठोरता का वर्णन करते हुए, उसे ढंढ देने का अनुरोध किया। वाइसराय लार्ड चेम्सफर्ड की उदारमनता पर भी उसने खेद प्रकट किया और उसको वापस बुला लेने की सलाह दी। हटर की अध्यक्षता में जाँच करने के लिए सरकार की ओर से भी एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसके सामने जनरल डायर ने स्वीकार किया कि जलियानवाला की फायरो में भय उत्पन्न करके वह “नैतिक प्रभाव” डालना चाहता था। कमेटी के अंगरेज सदस्यों ने, जिनकी सख्ता अप्रिय थी, राजनैतिक अन्डोलन को अशान्ति का मुख्य कारण बतलाया। उनकी राय में पंजाब में राज-विद्रोह की स्थिति थी, जिसके दमन के लिए जंगी कानून आवश्यक था, पर फौजी अफसरों ने कुछ अनुचित उपायों में काम लिया और जनरल डायर ने जलियानवाला में ज्यादती की। कमेटी के हिन्दुस्तानी सदस्यों की राय में जंगी कानून जारी करनेवाली स्थिति न थी और अशान्ति के मुख्य कारण वे ही थे, जिन्हें कांग्रेस कमेटी ने बतलाया था।

भारत-सरकार ने हटर कमेटी के अंगरेज सदस्यों की राय मानकर जंगी कानून बंद बायों की निन्दा की और जनरल डायर के व्यवहार को कठोर तथा

<sup>१</sup> सरकार ने मरे हुए लोगों की सख्या पहले २९१ और बाद में ३७९ या कुछ कम मानी।



से सरकारी उपाधियाँ त्याग दी जायँ, अवैतनिक पदों से हस्तीफा दे दिया जाय, सरकारी दरबार तथा अन्य इत्येवों में जाना छोड़ दिया जाय, सरकारी या सर-कार से सहायता पानेवाले स्कूल तथा कालेजों से लड़के हटा लिये जायँ, उनकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्कूल खोले जायँ, धीरे धीरे सरकारी अदालतों में जाना छोड़ दिया जाय और उनकी जगह पर पचायतों नियुक्त की जायँ । नई कांसिलों के निर्वाचन में कोई भाग न लिया जाय और सूत की कताई तथा कपट की दुहाई का खूब प्रचार किया जाय । दिसम्बर में नागपुर की कांग्रेस में इसका समर्थन किया गया और इसको अहिंसात्मक बनाये रखन पर बड़ा जोर दिया गया । कांग्रेस का संगठन भी ठीक किया गया । बराबर काम चलान के लिए एक 'कार्यकारिणी समिति' (वर्किंग कमेटी) नियुक्त की गई और "न्याययुक्त तथा शान्त उपायों द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति" कांग्रेस का ध्येय बनाया गया ।

अगस्त सन् १९२० में लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई । उनकी मृति में 'तिलक स्वराज्य कोष' स्थापित किया गया और देश भर में अमर्याद आन्दोलन बड़े जोरों से चल पड़ा । हजारों विद्यार्थियों ने सरकार से सम्बन्ध रखनवाली नस्थाओं में पढ़ना छोड़ दिया । पढाई के लिए कई एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हो गये । कांसिलों के बहिष्कार में भी बड़ी सफलता प्राप्त हुई । लिबरल नेताओं को छोड़कर, जो अमर्याद की नीति से सहमत न थे, अन्य कोई राष्ट्रीय नेता नई कांसिलों में न गया । सहर राष्ट्रीय पोगाक हो गया और चर्चा का प्रचार फिर से प्रारम्भ हुआ । अमर्यादों के नेताओं ने देश भर में भ्रमण किया, गाँवों तक में कांग्रेस की शाखाएँ स्थापित हो गईं, हिन्दू और मुसलमान परस्पर के भेद को भूल गये और मारे देश में एक विचित्र जागृति हो गई ।

**लार्ड रीडिंग**—अप्रैल सन् १९२१ में लार्ड रीडिंग वाइसराय होकर आया । यह इंग्लैंड का प्रधान न्यायाधीश रह चुका था, जिसने कारण बताया था कि उसके समय में न्याय होगा । लार्ड रीडिंग भी आते ही न्यायवादी बन गया और मुख्य मुख्य नेताओं से मिला, जिसका अच्छा प्रभाव

दसके आने के पहले ही सरकार की दमन-नीति प्राग्गम हो गई थी। मयुक्त प्रान्त में असहयोग आन्दोलन क्रान्तिकारी बतला दिया गया था, बिहार में स्वयंसेवकों पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा था। जगह जगह सरकार की अफसरो द्वारा 'अमन सभाएँ' स्थापित की जा रही थीं और उनमें सब तरह के असहयोगियों को बदनाम करने का प्रयत्न किया जा रहा था। अब और भी बड़ाई से काम लिया जाने लगा। जहाँ कहीं उपद्रव हुआ उसके लिए असहयोगी ही अपराधी ठहराये गये। हजारों असहयोगी, बड़े बड़े नेताओं सहित, जिनसे कभी विद्रोह की आशका नहीं की जा सकती थी, जेल में डूँब दिये गये।

**मोपला-विद्रोह**—इतने ही में मदरास के मलाबार प्रान्त में मोपला-विद्रोह ठूठ खड़ा हुआ। मलाबार में वसे हुए अरब लोग मोपला कहलाते हैं। ये कट्टर मुसलमान हैं और इनमें शिक्षा का भी प्रचार नहीं है। यहाँ के जमीन्दारों और कायतकारों में बहुत दिनों से झगड़ा था। खिलाफत आन्दोलन भी चल पड़ा था, पर इनको इसके वास्तविक अर्थ का पता न था। कुछ उपद्रव होने पर कलेक्टर की आज्ञा से एक मसजिद घेर ली गई और नेताओं का मलाबार जाना रोक दिया गया। इस पर ये लोग जाश में आकर दिगट पड़े। कुछ अंगरेज अफसर मार डाले गये और 'खिलाफत राज्य' स्थापित किया गया। यहाँ हिन्दुओं के साथ बड़ा अत्याचार किया गया, बहुत से हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बना डाले गये और उनके मन्दिर नाष्ट डाले गये। सरकार ने सेना भेज कर उपद्रव शान्त किया और जमीन कानून जारी कर दिया। बहुत से मोपला कैद करके निर्वासित कर दिये गये। सौ केंदी मालगाड़ी के एक डब्बे में भर दिये गये, जिनमें से ६६ हम घटन के कारण मर गये। मोपलाओं को उत्तेजित करने का अपराध भी असहयोगियों के मथे मट दिया गया।

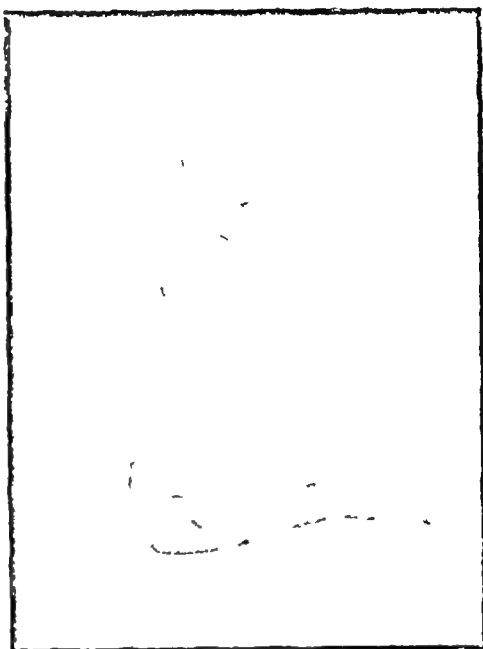
**चौरीचौरा**—गान्धीजी के बहुत प्रयत्न करने पर भी आन्दोलन अहिंसामय न रह सका। इसके कई एक कारण थे। सबसे मुख्य बात

तो यह है कि सविनय अवज्ञा की सफलता के लिए बड़े अ-यात्म-बल, आत्म-संयम, धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता है। सबमें इन गुणों का होना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त हम आन्दोलन को बढ़ाना करने के लिए सरकार की ओर से सभी तरह के उपायों में काम लिया जा रहा था। बंदियों को भी अपना मनलव सिद्ध करने का अच्छा अवसर मिल गया था और उनकी वजह से जगह जगह उपद्रव हो रहे थे। गिलाफन का झगडा चल ही रहा था। अहिंसात्मक उपायों में सफलता की कोई आशा न देखकर कुछ मुसलमान नेता भी असन्तुष्ट हो रहे थे। सरकार की दमन-नीति के कारण जनता की उत्तेजना बहुत बढ़ गई थी और उसका फायदा में रखना नेताओं के लिए असम्भव हो रहा था। कई जगह उपद्रव हो चुके थे, पर फरवरी सन् १९२२ में गोरखपुर के जिले में एक बड़ी भारी दुर्घटना हो गई। चौरीचौरा के धाने में आग लगा दी गई और धानेदार तथा सिपाही सब मिलाकर २२ आदमी मार डाले गये।

**बारडोली-निर्णय**—इस दुर्घटना से गान्धीजी की आँखें खुल गई और उन्हें विश्वास हो गया कि देश सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। बारडोली में, जहाँ सत्याग्रह के लिए बड़े जोरो से तैयारी हो रही थी, 'कांग्रेस वर्किंग कमेटी' की एक बैठक की गई, जिसमें सविनय अवज्ञा स्थगित करके, खहर के प्रचार, अछूतों के उद्धार, मादक वस्तुओं के निषेध, राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पचायतों को स्थापित करने और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर अधिक जोर देना निश्चित किया गया। कई नेताओं की राय में ऐसा निर्णय करके बड़ी भूल की गई, देश की जागृति से पूरा लाभ न उठाया गया, पहले धमकी देकर फिर सविनय अवज्ञा छोड़ देने का प्रभाव जनता पर अच्छा न पड़ा और उसकी हिम्मत टूट गई। गान्धीजी का कहना था कि बिना सविनय अवज्ञा की योग्यता के उसका प्रारम्भ करना हानिकारक है। सबसे पहले 'सत्य और अहिंसा' के सिद्धान्तों को अपने जीवन में लाना चाहिए। अपनी आत्मा की अपेक्षा संसार के सामने झुका बनना लाखों दर्जा अच्छा है।

महात्माजी की इस जटिल उक्ति को साधारण जनता समझ न सकी, जिसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे उनका प्रभाव कम पड़ने लगा। सरकार

बहुत दिनों में उन्हें ढंड देन का विचार कर रही थी, परन्तु अमहयोग आन्दोलन के जोर और गान्धीजी की लोकप्रियता के कारण उनकी हिम्मत न पड़ती थी।<sup>१</sup> अब उनके अच्छा अक्सर मिल गया और उसने कुछ तीव्र लेखों के कारण मार्च सन् १९२० में गान्धीजी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने की आज्ञा दे दी। उन पर सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करने और उसे नष्ट करने की चेष्टा करने का अपराध लगाया गया। उत्तर



महात्मा गान्धी

में गान्धीजी का कहना था कि जिस सरकार ने भारत को दरिद्र बना दिया है, जिसके धानों में उसकी लूट हो रही है और जिसके शासन ने उसको पुरुषार्थहीन बना दिया है, उस सरकार के प्रति किसी को भी स्नेह नहीं हो सकता। इस पर उन्हें ६ साल की सखी कैद का दंड दिया गया। जेल जाने समय महात्माजी देण के लिए बेंचल 'खहर' का संदेश छोड़ गये। अमहयोग आन्दोलन धीरे धीरे टटा पट रहा था, ऐसे समय पर उन्हें जेल भेजकर जनता पर बेंचल आतंक जमाने का प्रयत्न किया गया।

<sup>१</sup> गटिया इन १९०१-००, पृ० १०७।

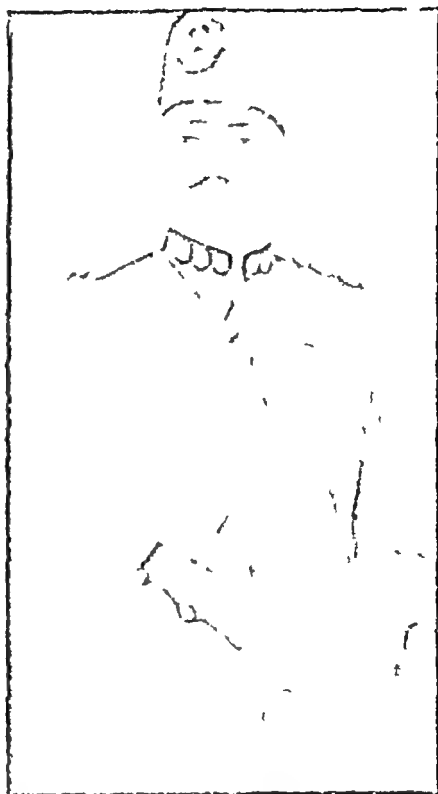
**असहयोग का प्रभाव**—जिम उद्देश्य के लिए असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, वह प्राप्त न हो सका, यह बात ठीक है, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस आन्दोलन से देश का बड़ा लाभ हुआ। जनता में निर्भीकता आ गई, जेलों का भय जाता रहा, सरकार की सच्ची नीति का मन्त्रोपपात लग गया, गाँवों तक में स्वराज्य की चर्चा होने लगी, गरीबों की सहायता के लिए खदर का साधन मिल गया, अछूतों की दुर्दशा की ओर मन्त्रोपपात ध्यान आकर्षित हो गया, कई एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हो गये और देश भर को स्वावलम्बन का पाठ मिल गया। महात्माजी के आध्यात्मिक जीवन का भी कुछ लोगो पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन का काया-पलट ही हो गया।

**माटेग्यू का इस्तीफा**—भारतसचिव माटेग्यू की नीति तत्कालीन इंग्लैंड-सरकार को पसन्द न थी। नये सुधारों से भारत के गवर्निलियन भी खुब चिढ़े हुए थे और उनका पक्ष पार्लामेंट में लिया जा रहा था। फरवरी, सन् १९२२ में उसकी नीति की पार्लामेंट में बड़ी तीव्र आलोचना की गई। गान्धीजी को गिरफ्तार न करने का भी उस पर दबाव लगाया गया। प्रधान सचिव लायड जार्ज ने अपने एक भाषण में यह कहते हुए कि भारत में कभी प्रजातन्त्र शासन नहीं रहा, इंडियन सिविल सर्विस को भारतवर्ष का “फौलादी ढाँचा” बतलाया। इतने ही में माटेग्यू को भारतसचिव के पद से हटाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। खिलाफत आन्दोलन का जोर बढ़ते देखकर भारत-सरकार ने तुर्की के साथ सन्धि की जो सन्धि हुई थी, उसको बदलने के लिए माटेग्यू को एक तार भेजा था। मुसलमानों को शान्त करने के लिए माटेग्यू ने मन्त्रि-मंडल से बिना पूछे हुए इस तार को प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी। मुसलमानों को असहयोग आन्दोलन से हटाकर अपने पक्ष में मिलाने की दृष्टि से ही इस तार के प्रकाशन में इतनी शीघ्रता की गई थी। मन्त्रि-मंडल ने माटेग्यू के इस कार्य को अनुचित समझा, इस पर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके थोड़े ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक उससे वन पड़ा वह बराबर भारतवर्ष के हित के लिए प्रयत्न करता रहा।



**तीसरा अफ़ग़ान-युद्ध**—फरवरी मन् १९१९ में अमीर हवीबुल्ला मार डाला गया। उसके बड़े लड़के ने अपने चचा के पक्ष में गद्दी का

अधिकार त्याग दिया। इस पर नमरुल्ला अमीर हो गया। परन्तु हवीबुल्ला का तीसरा लड़का अमानुल्ला इसको सहन न कर सका। उसे सन्देह था कि उसके पिता का वध नमरुल्ला ने ही कराया है। अमानुल्ला को सेना बहुत चाहनी थी। इसकी सहायता से वह अपने बड़े भाई और चचा को केंद्र करके अमीर बन गया। भारतवर्ष की अगान्ति में अमीर अमानुल्ला ने अफ़ग़ानिस्तान का पूरी तरह स्वतंत्र बनाने का अच्छा अवसर देखा। काबुल में बालगेंविक रूस और तुर्की का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर अंगरेजों को भी बड़ी चिन्ता हो



अमानुल्ला

रहा थी। अमीर की सेना भारत-वर्ष की तरफ बढ़ते देखकर युद्ध छेड़ दिया गया। इसमें अफ़ग़ान सेनापति जादिरग़ा ने बड़ी चतुरता से काम लिया। परन्तु अधिक दिनों तक अंगरेजों का नामना न किया जा सका। हवाई जहाज जलालाबाद और काबुल पहुँच गये। इस पर लड़ाई बन्द करके सन्धि की बात-चीत होने लगी। नवम्बर मन् १९२१ में दोनों राज्यों में सन्धि हो गई। इसके अनुसार अफ़ग़ानिस्तान पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया गया और उसे स्वयंसेवक बन्द

कर दिया गया। वहाँ के शासक अब 'ग्रामीर' के बजाय 'शाह' कहलाने लगे। इस सम्बन्ध में हबीबुल्ला के समय में ही झगडा चल रहा था।

सन् १६२७ में अमानुल्ला भारतवर्ष होता हुआ युगोप गया। सब जगह उसका खूब स्वागत किया गया। वहाँ से लौटकर उमने बहुत से सुधार किये। शासन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय सभा स्थापित की गई, पर्दा उठा दिया गया, बहु-स्त्री-विवाह की प्रथा रोक दी गई और मुल्लाओं का जोर दबा दिया गया। पाश्चात्य ढंग की शिक्षा तथा सभ्यता का देश में प्रचार करने का प्रबन्ध किया गया। इन उग्र सुधारों के लिए देश तैयार न था। गर्व अधिक बढ़ जाने से कई एक नये कर लगा दिये गये, जिससे प्रजा में असन्तोष फैल गया। सेना का वेतन बाकी पडा हुआ था, इसलिए वह भी असन्तुष्ट थी। सन् १६२८ के अन्त में शिनवारियों का भीषण विद्रोह उठ खडा हुआ। बच्चा सका हबीबुल्ला के नाम से बादशाह बन गया और अमानुल्ला कन्दहार भाग गया। साल भर तक देश में अराजकता फैली रही। इतने ही में फारस से नादिरशा आ गया। सफलता की कोई आशा न देखकर अमानुल्ला इटली चला गया। उसका हिन्दू प्रजा के साथ बडा अच्छा व्यवहार था। वह एशियाई राष्ट्रों का एक सघ स्थापित करना चाहता था। नादिरशा ने बड़ी चतुरता से देश को अपने पक्ष में करके काबुल पर अधिकार कर लिया। सन् १६२९ के अन्त में वह बादशाह बन गया और हबीबुल्ला मार डाला गया। नादिरशाह योग्य शासक जान पड़ता है। वह बड़े सोच विचार के साथ चल रहा है।

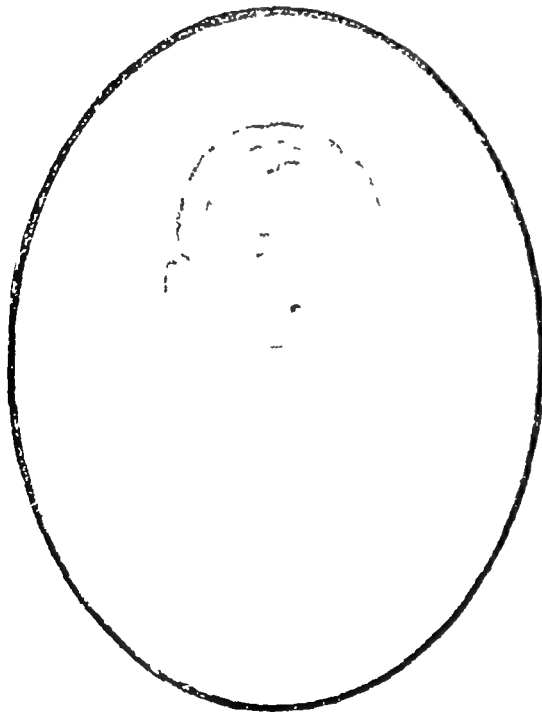
**अकाली आन्दोलन**—सिखों के बहुत से गुरुद्वारे हिन्दू महन्तों के हाथ में थे, जिनका प्रबन्ध ठीक ठीक न होता था। इनको सुधारने के लिए एक आन्दोलन चल पडा, जिसमें 'अकालियों' ने बहुत भाग लिया। इस सम्बन्ध में सरकार का प्रस्ताव पसन्द न आने पर इन लोगों ने सत्याग्रह द्वारा अपना उद्देश्य प्राप्त करना निश्चित किया। सन् १६२० के अन्त में 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी' नियुक्त हुई, जिसके आदेशानुसार सिखों ने गुरुद्वारों पर कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया। फरवरी सन् १६२१ में ननकाना के महन्त ने १३० अकालियों को मरवा डाला, जिसकी वजह से सिखों में बडा हलचल

मच गया। सिखों की शिकायतें ठीक थीं, अदालतों द्वारा उनका दूर हाना एक तरह से असम्भव था, ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य था कि वह बीच में पड़कर झगड़ों को निपटवा देती, परन्तु ऐसा न करके इस आन्दोलन का भी दमन प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १६२२ के अन्त में 'गुरु के वाग' में अपना अधिकार जतान के लिए, अकाली लकड़ी काटना चाहत थे। यहाँ का गुरुद्वारा इस समय भी महन्त के अधिकार में था। उनकी रत्ना के लिए पुलिस पहुँच गई इस पर अकालियों ने अपने जत्थे भेजना शुरू कर दिया। ऊँची धूप में पुलिस के डंडों की मार सहकर भी ये जत्थे शान्त रहे। अन्त में धाग का ठेका एक दूसरे मज्जन को देकर यह मामला शान्त किया गया।

इतने ही में सरकार के विरुद्ध अकालियों को एक और शिकायत का माफ़ा मिल गया। नाभा और पटियाला के राज्यों में आपस का कुछ झगड़ा था, जिसमें सरकार ने महाराजा नाभा को दोषी पाया। इस पर सन् १६२३ में महाराजा न गद्दी छोड़ दी, जिस पर उसका लड़का बिठला दिया गया और राज्य का शासन भारत-सरकार की निगरानी में होने लगा। अकालियों की राय में महाराजा के साथ यह अन्याय किया गया। इसलिए वे महाराजा का फिर न गद्दी पर बिठलान के लिए आन्दोलन करने लगे। जुलाई सन् १६२३ में नाभा राज्य के जायतों गुरुद्वारा में उनकी एक सभा तोड़ दी गई। परन्तु इसमें अकाली डरे नहीं, उनके जत्थे बराबर मोर्चे पर पहुँचते रहें। इस पर अक्टूबर में सरकार ने 'गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी' को गैरकानूनी ठहराकर सब मेम्बरों को गिरफ्तार कर लिया। कमेटी फिर से संगठित हो गई और पाँच महीने तक २५ आदमियों का एक जत्था राजाना जाकर गिरफ्तार होता रहा। जनवरी सन् १६२४ में अमृतसर से ५०० आदमियों का एक 'शहीदी जत्था' पैदल खाना हुआ, जिसमें कनाडा और शघाई से भी बहुत से मिव आकर शामिल हुए। मार्ग में इसके साथ बहुत भीटभाड़ हो गई। जायतों पहुँचने पर नाभा-सरकार की ओर से गोली चलाई गई, जिसमें बहुतों के प्राण गये। दूसरी प्रबन्धक कमेटी के मेम्बर भी गिरफ्तार किये गये और 'कृपाण' धारण कानून-विरुद्ध ठहरा दिया गया।

सरकार का बहुत कुछ सैनिक बल मित्रों पर निर्भर है। अधिक दिनों तक उनको अमनुष्ट रखना उचित न था। इंग्लिश सरकार ने कोई उपाय न देखकर अन्त में समझौता करना निश्चित किया। जुलाई सन् १९०५ में, पंजाब कौन्सिल में 'गुरुद्वारा कानून' पास किया गया, जिसके अनुसार यथासम्भव गुरुद्वारों का प्रबन्ध मित्रों के हाथ में दे दिया गया। मिस्र कैदी भी धीरे धीरे छोड़ दिये गये। इस आन्दोलन में ३० हजार मिस्र गिरफ्तार किये गये, ८०० के प्राण गये, दो हजार घायल हुए और १५ लाख रुपया जुरमाना में वसूल किया गया।<sup>१</sup> पर तब भी मित्र बराबर शान्त रहे और उन्होंने इस बात को

दिखाया दिया कि व्यवहार में भी गान्धीजी का सत्याग्रह असम्भव नहीं है।



चित्तरंजन दास

**स्वराज्य दल-**  
गान्धीजी के जेल जान से अमहयोग आन्दोलन और भी गिथिल पड़ गया। उनके बतलाये हुए कार्यक्रम पर अधिकांश जनता को श्रद्धा न थी और उसके लिए कुछ भी काम न हो रहा था। विद्यार्थी धीरे-धीरे फिर सरकारी स्कूल और कालेजों में वापस जा रहे थे, राष्ट्रीय संस्थाएँ टूट रही थीं, सड़क का प्रचार कम पड़ रहा था, हिन्दू और मुसलमानों में भी

<sup>१</sup> शडियन क्वार्टरली रजिस्टर, कलकत्ता, सन् १०२५, जि० १, पृ० ९०।

कागड़ा प्रारम्भ हो गया था। इस पर कांग्रेस की ओर से 'सविनय अवज्ञा कमेटी' नियुक्त की गई, जिनमें देश भर में भ्रमण करके उस समय की स्थिति में सविनय अवज्ञा को सर्वथा असम्भव बतलाया और कैमिलो में जाने की सलाह दी। इसके कुछ दिनों पहले से ही असहयोग के कई एक नेताओं की यह राय हो रही थी कि कैमिलो में न जाकर भूल की गई। कहा जाता था कि लिस्बन के मिल जाने से सरकार और भी दृढ़ हो गई थी और अपनी मनमानी कर रही थी। इस भूल को सुधारन के लिए मन् १९०२ की गया कांग्रेस में 'स्वराज्य दल' स्थापित किया गया, जिनमें कैमिलो में जाकर सरकार के हर एक काम में बाधा डालना निश्चित किया। श्री चित्तरजन दाम, जिन्होंने असहयोग के समय पर वेंगिस्त्री छोड़ दी थी और जेल जा चुके थे, इस दल के नेता बनाये गये।

कांग्रेस में इस समय भी महात्माजी के नाम का बड़ा प्रभाव था। उसमें इस दल को अपना स्थान नहीं दिया। इस दल की नीति असहयोग के सिद्धान्तों के विरुद्ध थी। कैमिल-बहिष्कार ही असहयोग का एक अंग मानी रह गया था, वह भी इस नीति में नष्ट हो रहा था। इस पर कांग्रेस में दो दल हो गये, एक तो कैमिलवादियों का और दूसरा उन कट्टर असहयोगियों का, जो अपनी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन न चाहते थे। इसी लिए यह दल 'अपरिवर्तनवादियों' का नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों दलों में बहुत दिनों तक कागड़ा चलता रहा। स्वराज्य दलवाले कम संख्या में होते हुए भी कांग्रेस का अपना मत में लाने के लिए बराबर प्रयत्न करते रहे। बीमार पड़ने के कारण फरवरी मन् १९२४ में सरकार ने गान्धीजी को छोड़ दिया। मन् १९२६ के निर्वाचन में सफलता हाथ में स्वराज्य दल का प्रभाव बहुत बढ़ गया। गान्धीजी ने भी देखा कि कैमिलो का बहिष्कार अब सम्भव नहीं है। इस पर उन्होंने राजनीति से अपना हाथ ही खींच लिया और हिन्दू-मुसलमानों की एकता, प्रवृत्तों के उद्धार तथा सब से अधिक गहर के प्रचार पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। खेद महाना और सूत कातना कांग्रेस के सम्परा के लिए अनिवार्य कर दिया गया। सफलता न हाथ में सूत कातने

का नियम उठा दिया गया, सड़क पहनना इस समय भी आवश्यक है। कताई का प्रचार करने के लिए गान्धीजी ने एक 'अखिल भारतीय चर्मा मव' स्थापित किया। इसका व्यापारिक ढंग पर बड़ा अच्छा काम चल रहा है और यह कांग्रेस का एक श्रग भी है। सन् १९०५ में कांग्रेस ने स्वराज्य दल की नीति को मान लिया।

सन् १९२३ के निर्वाचन में स्वराज्य दल को अच्छी सफलता हुई। यदि इस अवसर पर कांग्रेस ने इसका साथ दिया होता तो बहुत सम्भव था कि इस दल की पूरी विजय हुई होती, पर तब भी अस्मेश्वली में इसकी प्रधानता रही और प्रान्तीय कौंसिलों में बंगाल तथा मध्यप्रान्त में स्वराज्य दल के लोग सबसे अधिक संख्या में चुने गये। इन दोनों कौंसिलों में मंत्रियों का नियुक्त होना असम्भव कर दिया गया। बंगाल में दास की नीति-निपुणता के कारण सरकार को कई बार हार खानी पड़ी। मध्यप्रान्त में मंत्रियों के विभाग अन्ततः एकजीक्युटिव कौंसिल के मेम्बरों को ही सौंप दिये गये। अस्मेश्वली में भी स्वराज्य दल ने अपनी धाक जमा दी। असहयोग के दमन में सरकार का साथ देने के कारण इस निर्वाचन में लिबरलों की पूरी हार हुई थी। अन्य दल भी सरकार की नीति से सन्तुष्ट न थे। देशी नरेशों की समाचार-पत्रों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए एक कानून गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार से पास कर दिया गया था। इसी तरह पूरा विरोध करते रहने पर भी नमक-कर बढ़ा दिया गया था। इस असन्तोष से स्वराज्य दल ने सूर लाभ उठाया। उसने अन्य दलों से मिलकर सरकारी बजट नामंजूर कर दिया, जो गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार से पास किया गया।

परन्तु अन्य दलों के साथ यह मेल स्थायी न हुआ, जिसकी वजह से स्वराज्य दल को फिर अधिक सफलता न हुई। उसकी नीति में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, हर एक काम में बाधा डालना छोड़ दिया गया और प्रजाहित के कार्यों में सरकार का साथ भी दिया जाने लगा। सन् १९२४ में दास की मृत्यु हो जाने से और भी धक्का लगा और हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े का भी प्रभाव पड़ा। नीति में परिवर्तन होने के कारण लोकप्रियता घट गई, आपस

में ही मतभेद हो गया, कुछ महाराष्ट्र नेता सरकारी पदों को स्वीकार करने के पक्ष में भी हो गये। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि सन् १९२६ के निर्वाचन में कांग्रेस के प्रयत्न करने पर भी इस दल में अधिक सफलता नहीं हुई। असेम्बली में इस दल के सदस्यों की संख्या लगभग उतनी ही रही और बगाल तथा मदरास में कुछ अधिकता रही। इस द्वार मंत्रियों को नियुक्त न करने देने का प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हुआ।

**खिलाफत का अन्त**—सन् १९२४ में, तुर्की में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो गया। सुलतान गद्दी से उतार दिया गया और मुम्ताफा कमाल पाशा राष्ट्रपति बनाया गया। इसके पहले ही लोमान की सन्धि हो गई थी, जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों ने तुर्की की स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। तुर्की का यह कार्य भारतीय मुसलमानों को पसन्द न आया। खिलाफत की प्राचीन संस्था को बनाये रखने के लिए प्रयत्न भी किया गया, पर कोई सफलता न हुई। इस तरह खिलाफत का झगड़ा आप ही आप शान्त हो गया, पर तब भी मुसलमानों की कई एक शिकायतें बनी रहीं। उनके कुछ पवित्र स्थानों पर, नई सन्धियों के अनुसार, अन्य राष्ट्रों का अधिकार हो गया। अरब में बहावी सुलतान इब्नसऊद की विजय के कारण यह समस्या और भी जटिल हो गई।

**हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा**—खिलाफत के अन्त के साथ साथ प्रमहयोग के दिनों में हिन्दू-मुसलमानों में जो एकता स्थापित हुई थी, वह भी नष्ट हो गई। सन् १९२३ में दोनों का भेदभाव बहुत बढ़ गया और सन् १९२४ में महारनपुर के जिले में मुहर्रम के समय पर बड़ा भारी दंगा फैला गया। उत्तरी भारत के अन्य कई स्थानों में भी बहुत से दंगे हुए। इसके फल भी कहीं एक साथ दंगे हो जाते थे, पर डर इनके बढ़ जाने के कई एक कारण थे। प्रमहयोग एक राजनैतिक आन्दोलन था, इसके साथ खिलाफत का सम्बन्ध जोड़ देने से धार्मिक भाव पैदा हो गया। नये स्थानों में परस्पर के भेदभाव को मिटाने की कोई चेष्टा नहीं की गई।

कौंसिलों में दोनों के प्रतिनिधि अलग अलग चुने ही जाने थे, अब म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी इसी नियम से काम लिया जाने लगा और सरकारी नौकरियाँ देने में भी हिन्दू-मुसलमानों का ग्याल होने लगा। जो हिन्दू पहले मुसलमान हो गये थे उन्हें शुद्ध कर्म के लिए आन्दोलन चल पड़ा और हिन्दू-समाज को सुसंगठित बनाने के लिए 'हिन्दू महासभा' स्थापित हो गई। मुसलमानों में भी 'तजीम और तखलीफ' के लिए आन्दोलन होने लगा। धार्मिक प्रचार तथा सामाजिक संगठन का दोनों को समान अधिकार है, पर इनमें राजनैतिक रंग ला दिया गया। इसी तरह केवल राजनैतिक प्रश्नों में भी धर्म और जाति के भावों का समावेश कर दिया गया। गोश्व का झगडा पहले ही से था, हिन्दू सदा से इसका विरोध करते रहे, अब मुसलमानों ने मसजिदों के सामने बाजा बजाने पर आपत्ति करना प्रारम्भ कर दिया। इन भेद-भावों को उत्तेजित करने में कुछ लोगों को आनन्द आने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि देशभर में दोनों जातियों में परस्पर का अविश्वास उत्पन्न हो गया और लड़ाई-झगड़े तथा दंगा-फसाद होने लगे।

सितम्बर सन् १९२४ में सीमा प्रान्त के कोहाट नगर में बड़ा उपद्रव हो गया। एक साधारण झगड़े पर सरहद्दी मुसलमानों ने नगर के हिन्दू मुहल्लों में आग लगा दी, दूकानें लूट लीं और कुछ लोगों को मार डाला। बहुत से हिन्दू कोहाट छोड़कर रावलपिंडी भाग आये। गुलबर्गा और लखनऊ में भी उपद्रव हुए। कोहाट के पूरे समाचार मिलने पर गान्धीजी ने दिल्ली में २१ दिन का उपवास किया। इसी समय दिल्ली में 'एकता सम्मेलन' हुआ, जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी और सिखों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देते हुए यह निश्चित किया कि जहाँ जैसी रीति है उसी के अनुसार, बिना किसी का दिल दुखाये हुए, काम करना चाहिए। परन्तु इसके निर्णयों पर काम नहीं किया गया। कांग्रेस भी इन झगड़ों को निपटाने का कई बार प्रयत्न किया, पर तब भी कुछ हुआ। झगडा बराबर बढ़ता ही गया और दोनों ओर से ज्यादातिया हो रही। सरकार की कोई निश्चित नीति न रही और उसने दोनों के अधिकार



जाना था। इस व्यापार के कारण थोड़े ही दिनों में वेनिस मालामाल हो गया। सन् १४५३ में तुर्क लोगों की विजय के कारण इस मार्ग में भी बाधा पड़ने लगी, और यूरोप-निवासियों को भारतवर्ष आने-जान के लिए एक नया मार्ग ढूँढ़ निकालने की चिन्ता होने लगी।

### नया मार्ग—यूनान

लोगों के समय से ही अनुमान था कि अफ्रीका उस भारतवर्ष जाने का एक समुद्र मार्ग है, परन्तु इसका तिर को ठीक ठीक पता न था स्पेन के राजा की आज्ञा 'मेने की चिड़िया' भारतवर्ष को ढूँढ़ने ढूँढ़ने, सन् १४९२ में जिनेआ निवासी कोलम्बस अमरीका जा पहुँचा। इस धुन में जान बेंचो न्यूफाउन्डले पहुँच गया। अन्त में इस ढूँढ़ निकालने का श्रेय पुर्तगा को ही प्राप्त हुआ। पन्द्रह शताब्दी के समय से ही यहाँ निवासी इसकी खोज में लगे हुए थे। राजकुमार हेनरी सागर जीवन इसी में हथा था। सन् १५



वास्कोडुगासा

डियाज नाम का एक पुर्तगाली अफ्रीका के एक दक्खि



की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न भी नहीं किया। सन् १९२६ में गुरुकुल कांगड़ी के स्थापक स्वामी श्रीद्वानन्दजी का बध कर डाला गया। इलाहाबाद और कलकत्ता में भी बड़े उपद्रव हुए। सन् १९२८ के अन्त से ये झगड़े धीरे धीरे शान्त होने लगे। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। ये झगड़े प्रायः ब्रिटिश भारत में ही होते हैं, देशी राज्यों में ऐसे झगड़े बहुत कम होते हैं।

**सुधारों की उपयोगिता**—असहयोग के दिनों में नई कमिनों में प्रजा के प्रतिनिधियों का कुछ ध्यान रखा गया। उनके कहने पर न्याय तथा गणों के सम्बन्ध में गोरे-काले का भेद उठाने, कुछ दमनकारी कानूनों को रद्द करने और समाचारपत्रों को अधिक स्वतंत्रता देने का प्रयत्न किया गया। मदन-राम और मयूक्त प्रान्त में मंत्रियों के साथ मिलकर चलने की भी चेष्टा की गई। परन्तु असहयोग का जोर टूटा हो जाने तथा माटेग्यू के हटने पर सरकार की नीति फिर बदल गई। असेम्बली में 'देशी नरेश-रक्षक कानून' प्रतिनिधियों के विरोध करते रहने पर भी गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार में पाव कर दिया गया और नमक-कर बढ़ा दिया गया। प्रान्तीय सरकारों में लिबरल डल के मंत्रियों को काम करना असम्भव कर दिया गया और उनको मजदूर होकर हमीया देना पड़ा। इंग्लैंड की मजदूर सरकार के शासनकाल में भी, जिसमें भारतवर्ष को बहुत कुछ आशा थी, बगाल में क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए एक कठोर कानून (बगाल आर्डिनेंस) पास कर दिया गया। इसके अनुसार किसी पर ऐसे पड्यत्रों में भाग लेने का सन्देह होने ही में बिना अभि-याग चलाये हुए, उसको जेल में रखने या निर्वासित करने का अधिकार बगाल-सरकार को मिल गया। सभी जगह विशेषाधिकारों से काम लिया जाने लगा। सरकार की इन कार्यवाहियों से, जो उसका साथ देना चाहते थे, उन्हें भी यह भागित हो गया कि सुधारों से सरकार के रवेच्छाचारी शासन का अन्त नहीं हुआ जैसा कि ड्यूक ऑफ कनाट के भाषण में कहा गया था।

पहली असेम्बली के कहने पर सरकार ने भारतसचिव को यह लिखना निर्धार कर लिया था कि असेम्बली की राय से सन् १९३० के पहले ही सुधारों की फिर से जांच करना आवश्यक है। परन्तु दूसरी असेम्बली

ने, जिसमें स्वराज्य दलवालो की अधिकता थी, यह प्रस्ताव पास किया कि भारत की शासन-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सरकार और प्रजा के प्रतिनिधियों का एक मिश्रित सम्मेलन ( गवर्नर टेबल कान्फ्रेंस ) होना चाहिए। इसका स्वीकार करना तो दूर रहा, सन् १९१७ की विज्ञप्ति का भी इस अवसर पर मनमाना अर्थ लगाया गया। सरकार का कहना था कि विज्ञप्ति में 'उत्तरदायी शासन' का वचन दिया गया है, जिसका अर्थ 'श्रौपनिवेशिक स्वराज्य' नहीं है। अन्ततः सुधार-कानून के अन्तर्गत और क्या परिवर्तन हो सकते हैं, केवल इस पर विचार करने के लिए सन् १९०४ में मुडीमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई।

इस कमेटी के सामने जो गवाहियाँ हुईं, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि दोहरी शासन-व्यवस्था केवल असफल ही नहीं हुई, बल्कि भविष्य में भी उसमें देश के हित की कोई आशा नहीं है। गवर्नर और उसकी एक्जीक्युटिव, कौंसिल मंत्रियों के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। बहुत से प्रान्तों में मंत्रियों की मिश्रित जिम्मेदारी नहीं है, हर एक मंत्री अलग अलग जिम्मेदार माना जाता है। जिस ढंग से विषयों का विभाग किया गया है, वैसा होना असम्भव है। शासन के सभी विभागों का एक दूसरे से सम्बन्ध है, इसलिए कुल शासन की एक ही जिम्मेदारी हो सकती है। अर्थ-विभाग एक्जीक्युटिव कौंसिल के मेम्बर के हाथ में रहने से मंत्रियों के काम में बड़ी बाधा पड़ती है और भारतसचिव तथा गवर्नर का मंत्रियों पर, जो जनता के प्रति जिम्मेदार समझे जाते हैं, पूरा अधिकार रहता है। इस कमेटी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें अधिकांश मेम्बरों ने यह राय दी कि राजनैतिक अशान्ति के कारण नई शासन-व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं उठाया गया। सुधार-कानून के अन्तर्गत रहकर ही, कुछ फेर-फार करने से लाभ हो सकता है। इसके विरुद्ध कमेटी के तीन हिन्दुस्तानी मेम्बरों की राय थी कि दोहरी शासन-व्यवस्था से हित की सम्भावना नहीं है, इसलिए 'रायल कमीशन' द्वारा फिर से जांच कराना चाहिए और इस व्यवस्था का अन्त ही कर देना चाहिए।

## परिच्छेद १७

### औपनिवेशिक स्वराज्य

**लार्ड अरविन**—सन् १९२६ में पार्लामेंट ने यह नियम बना दिया कि गवर्नर-जनरल प्रधान सेनापति, गवर्नर तथा एक्जीक्युटिव कांसिल के मेम्बर भी छुट्टी ले सकते हैं। इस पर लार्ड रीडिंग तीन महीने की छुट्टी लेकर भारतसचिव से परामर्श करने के लिए इंग्लैंड गया। उसके स्थान पर बंगाल का गवर्नर लार्ड लिटन काम करता रहा। वहाँ से उसके लौटने पर मालूम हुआ कि कृषि की उन्नति के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक रायल कमीशन नियुक्त होनेवाला है। लार्ड रीडिंग की अवधि समाप्त होने पर लार्ड अरविन वाइसराय बनाया गया। यह सर चार्ल्स बुड का पोता है, जो पहले भारतसचिव था और जिसने देशी राज्यों के प्रति लार्ड डलहौजी की नीति को बढ़ाया था। इसी के समय में



लार्ड अरविन

भारतभूत गिच्छा की ओर भी अधिक ध्यान दिया गया था। लार्ड अरविन

को खेती में बड़ी दिलचस्पी है और आप अपनी शिष्टता तथा मादगी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं ।

**भारत और साम्राज्य**—गत यूरोपीय महायुद्ध के समय में साम्राज्य-सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर कई एक भारतीय नेताओं के जाने का फल यह हुआ कि उन्हें उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को अपनी बात समझाने का अवसर मिला गया, जिसके कारण बहुत से भ्रम दूर हो गये । कनाडा और आस्ट्रेलिया में हिन्दुस्तानियों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार होने लगा, परन्तु दक्षिण अफ्रीका पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा । गान्धीजी के साथ जो समझौता हुआ था, सन् १९१९ से उसके विरुद्ध फिर काम होने लगा । कई बार कुलियों को निकालने तथा प्रवासी हिन्दुस्तानियों के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न किया गया । इस पर भारत में फिर अमनतोष बढ़ने लगा । परस्पर का भ्रम दूर करने के लिए सन् १९२६ में भारत-सरकार ने एक डेप्यूटेशन ( प्रतिनिधि मंडल ) दक्षिण अफ्रीका भेजा, वहाँ से भी एक डेप्यूटेशन भारत आया । इस तरह आपस में फिर समझौता हो गया । दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों की, जिनकी संख्या डेढ़ लाख से भी अधिक है, देख-भाल करने के लिए वहाँ भारत का एक 'एजेंट' ( प्रतिनिधि ) रखना निश्चित हुआ और इस पद पर श्रीनिवास शास्त्री नियुक्त किये गये । इस समय भी वहाँ के हिन्दुस्तानियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है । पूर्व अफ्रीका में भी, विशेष कर कीनिया में, हिन्दुस्तानियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है । साम्राज्य के सभी भागों में अपनी अधीनता के कारण भारत को अपमान सहना पड़ता है ।

**राष्ट्रसंघ**—जब साम्राज्य के भीतर ही उसकी यह दशा है, तब फिर संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों में उसका मान ही क्या हो सकता है ? आज कल सब से भारी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'राष्ट्रसंघ' ( लीग ऑफ नेशंस ) है, जो महायुद्ध के पश्चात्, संसार में शान्ति स्थापित रखने के लिए स्थापित किया गया था । भारत भी इस संघ का सदस्य है और उसका रक्षक चलाने के लिए हर साल

एक बड़ी रकम देता है। परन्तु उसमें जाने के लिए प्रतिनिधि सरकार द्वारा चुने जाते हैं। मन् १९२८ तक इन प्रतिनिधियों का नेता कोई अंगरेज ही होता था, परन्तु मन् १९२९ में वाइसरॉय की कैबिनेट का एक हिन्दुस्तानी मंत्री पहली बार नेता बनाया गया।

**सीमाओं का प्रश्न**—मन् १९१९ में अफगान-युद्ध की चर्चा सुनकर सीमा पर के वजीरी और महसूदियों ने फिर उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर सेना भेजकर उन्हें दवाने का प्रयत्न किया गया और यह निश्चित किया गया कि रुपया तथा हथियार देकर रक्षा का भार उन्हीं लोगों के हाथ में सौंपने की नीति से काम न चलेगा, वजीरमान में सेना रखनी पड़ेगी और रेल तथा मटको को जमरूढ़ के आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। दो वर्ष तक यह उपद्रव जारी रहा, जिसको शान्त करने में बड़ा धन फँका गया और बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न पड़ीं। मन् १९२१ के अन्त में सेना हटा ली गई और रक्षा का भार फिर 'खाम्सादारी' को सौंप दिया गया। इस सीमा-प्रदेश के सम्बन्ध में इस समय भी दो मत चल रहे हैं, एक दल 'आगे बढ़ने की नीति' का पक्षपाती है। दूसरे दल का कहना है कि इसमें बड़ा खर्च पड़ता है, इसलिए यहाँ लड़के बनाकर सेना की चौकियाँ स्थापित कर देनी चाहिए और जहाँ तक सम्भव हो यहाँ पर बसनेवाली जातियों को अपने पक्ष में मिलाये रखना चाहिए। भारत सरकार आवश्यकतानुसार दोनों नीतियों से काम ले रही है, जिसमें खूब धन उड़ रहा है।

इस सीमा पर के निवासी पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के जिले में बड़ा उद्यम मचाया करते हैं। मन् १९१९-२० में इनके ६११ धावे हुए, जिन में ३०० आदमियों के प्राण गये और ३० लाख की सम्पत्ति लुट गई। इन्हीं की वजह से इस प्रान्त की राजनैतिक उन्नति में बड़ी बाधा पड़ रही है। लार्ड वर्जन के समय से यह प्रान्त भारत-सरकार के अधीन है। एक दल का कहना है कि इस प्रान्त में भी सुधार-योजना के अनुसार शासन होना चाहिए, पर दूसरे दल की राय है कि सीमा-प्रदेश भारत-सरकार की निगरानी में रखना ही ठीक है, इस प्रान्त के कुछ जिले को पंजाब में मिला देना चाहिए, जिसमें

सुधारों से वहाँ के निवासी भी लाभ उठा सके। इस सम्बन्ध में भी हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न आ गया। सीमा प्रान्त में मुसलमानों की संख्या अधिक है, इसी लिए उसकी स्वतंत्रता से कुछ हिन्दुओं को भय हो रहा है, परन्तु अधिकांश हिन्दू नेताओं को इसमें विशेष आपत्ति नहीं है। इस पर अभी विचार हो रहा है।

उत्तर की सीमा पर कोई ऐसा भय नहीं है। उम और हिमालय की दीवाल खड़ी है। उसके बाद तिब्बत है, जिसके साथ मित्रता का सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त उसकी ऐसी दशा भी नहीं है कि वह भारत की ओर निगाह उठा सके। नेपाल के साथ एक नई सन्धि हो गई है, जिसमें उसने सीमा पर निगरानी रखने का वचन दिया है। इसके बदले में भारत-सरकार की ओर से उसे कई एक व्यापारिक सुविधाएँ दी गई हैं। पूर्व की ओर चीन की अनिश्चित राजनैतिक स्थिति के कारण बर्मा की सीमा पर सेना बढ़ाई जा रही है। कुछ वर्षों से बर्मा में उसे भारत से अलग करने के प्रश्न पर आन्दोलन हो रहा है। कहा जाता है कि बर्मियों का धर्म, उनकी जाति, भाषा तथा संस्कृति हिन्दुस्तानियों से भिन्न है, इसलिए भारत के साथ रहने में उनका हित नहीं है। इसके अतिरिक्त बर्मा में हिन्दुस्तानी उन्हें बहुत दबाये हुए हैं। इस आन्दोलन में सरकार की ओर से बर्मियों को उत्साहित किया जा रहा है।

**देशरक्षा**—गत मेसेपोटामिया और अफगान-युद्ध में भारतीय सेना का कुप्रबन्ध देखकर सन् १९१६ में, लार्ड एशर की अध्यक्षता में, सेना का संगठन ठीक करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई अक्टूबर सन् १९२० में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कई एक सुधारों का बतलाते हुए इसने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि भारतीय सेना साम्राज्य की सेना का एक श्रंग है, इसलिए इसकी नीति का संचालन इंग्लैंड के युद्ध-विभाग के हाथ में होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेम्बली ने इस सिद्धान्त को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि भारतीय सेना का मुख्य कर्तव्य भारत की रक्षा है, उसका पूरा प्रबन्ध भारत-सरकार के हाथ में रहना चाहिए और यथासम्भव स्वदेश-रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिए भारतवर्ष से बाहर उस सेना



में काम न लेना चाहिए। साथ ही साथ उसने यह प्रस्ताव भी पास किया कि जल, स्थल, और वायु तीनों प्रकार की सैन्याओं में बिना किसी जातिभेद के हिन्दुस्तानियों को भरती करना चाहिए, हर साल बड़ बड़ ज़ोहदों पर २५ फी मदी हिन्दुस्तानी 'शाही कमीशन' द्वारा नियुक्त करना चाहिए<sup>१</sup> और हिन्दुस्तानियों को सैनिक शिक्षा देने के लिए स्थानीय सेना (टेरिटोरियल फोर्स) का संगठन ऐसा होना चाहिए, जिसमें हिन्दुस्तानी स्वदेश-रक्षा में भाग ले सकें और अंगरेजी सेना की भी अधिक आवश्यकता न रहे, जिसमें बड़ा धन खर्च होता है।

असेम्बली के बहुत जोर देने पर 'सहायक सेना' (आक्जिलियरी फोर्स), जिसमें केवल यूरोपियन होते हैं और 'स्थानीय सेना' (टेरिटोरियल फोर्स) के कुछ भेदों को मिटाने का प्रयत्न किया गया। विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा के लिए छोटे छोटे दल बनाये गये और देहरादून में एक सैनिक कालेज खोला गया। यहाँ की पढाई समाप्त करने पर इंग्लैंड के 'सैंडहर्स्ट कालेज' में भरती होने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें हिन्दुस्तानियों के लिए दरज रखी जाती है। 'शाही कमीशन' के सम्बन्ध में यह निश्चित किया गया कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों के आठ दलों में धीरे धीरे सब अफसर हिन्दुस्तानी कर दिये जायें। इसी में लगभग २५ वर्ष लग जायेंगे। यदि इसी तरह सेना को राष्ट्रीय बनाने का प्रयत्न किया गया, तो इसमें सैंडहर्स्ट वर्ष लगेंगे। 'सैंडहर्स्ट कालेज' में शिक्षा पाने पर प्रायः 'शाही कमीशन' मिलता है। असेम्बली के बहुत कहने पर भारत में एक ऐसे कालेज के स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जनरल स्पीन की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इसने सन् १९३३ में कालेज खोलने

१ भारतीय सेना में दो प्रकार के अफसर होते हैं, एक तो 'वाइसराय के कमीशन' द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और दूसरे जो 'किंग या शाह कमीशन' द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। 'शाही कमीशन' के अफसरों का पद उँचा होता है और उनके अधिकार भी बहुत होते हैं। यूरोपीय महायुद्ध के पहले किमा हिन्दुस्तानी को 'शाही कमीशन' न मिलता था।

और तब तक सेंडहर्स्ट में हिन्दुस्तानियों के लिए जगहे बढाने की मत्ताह दी, परन्तु इस और विशेष ध्यान न देकर भारत-सरकार 'आठ ढलवाली योजना' ही पर डटी है ।

भारत के पास कोई जहाजी सेना नहीं है । सन् १८२६ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक ऐसी सेना बनाई थी, परन्तु मिपाही विद्रोह के बाद वह तोड दी गई । तब से भारत के मागर-तट की रक्षा इंग्लेड की जहाजी सेना द्वारा होती है । इसके लिए हर साल इंग्लेड को एक बडी रकम दी जाती है । सन् १८६२ से भारत के पास कुछ जहाजों का एक छेडा ब्रेडा है, जो 'रायल इंडियन मैरीन' कहलाता है । सन् १९०६-२७ में इसी से भारत की जहाजी सेना ( इंडियन नेवी ) बनाने का प्रयत्न किया गया । इसमें कुछ हिन्दुस्तानियों के भरती करने का वचन दिया गया, परन्तु साथ ही साथ यह शर्त लगाई गई कि आवश्यकता पडने पर इसमें साम्राज्य की रक्षा का काम लिया जायगा । असेम्बली ने इसको स्वीकार न किया, इस पर यह विचार छोड दिया गया । इंडियन मैरीन के तीन जहाज जंगी बना दिये गये और कुछ हिन्दुस्तानियों को जहाजों शिक्का देने का प्रबन्ध किया गया । सरकार के पास 'रायल एयर फोर्स' के कुछ हवाई जहाज भी है ।

स्वदेशरक्षा का भार अपने हाथ में न होने से हिन्दुस्तानी पूर्ण रूप से अँगरेजों के अधीन है । एक और तो उनकी सैनिक शिक्का का कोई यथेष्ट प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है और दूसरी और यह कहा जाता है कि स्वदेश-रक्षा के लिए अयोग्य होने के कारण, वे स्वराज्य के योग्य नहीं हैं । भारत में सेना का बडा खर्च है । सन् १९२१-२२ में यह ६५ करोड रुपया तक पहुँच गया था । इचक्रेप कमेटी के कहने पर इसमें कुछ कमी की गई, परन्तु तब भी यह ५५ करोड रुपया है । इस तरह भारत का सैनिक खर्च आमदनी का ४२ सैकडा है, जितना किसी देश में नहीं है ।

**व्यापार**—यूरोपीय महायुद्ध के समय में व्यापार की बडी अनिश्चित अवस्था रही । इन दिने जापान ने खूब लाभ उठाया । बाहर से आने-वाली चीजों का भाव बहुत बढ़ गया, यह दशा युद्ध के बाद भी कई साल

तक बनी रही। भारत को बहुत सा बना हुआ माल बाहर से मँगाना पड़ता है। ६६ करोड़ रुपये माल का तो केवल कपड़ा ही आता है। पिछले दस वर्षों में लगभग ७ अरब रुपये का माल बाहर से आया। महायुद्ध के बाद विलायती कपड़े पर चुगी बढ़ा दी गई। भारत के सम्बन्ध में स्वतंत्र व्यापार के प्रश्न की जाँच करने के लिए सन् १९२१ में एक कमीशन नियुक्त हुआ, जिसकी सिफारिशों के अनुसार सन् १९२२ में 'टेरिफ बोर्ड' स्थापित किया गया। देश की किस औद्योगिक कला को सरकारी रक्षा और सहायता की आवश्यकता है, यह निश्चित करना इस बोर्ड का मुख्य काम है। सन् १९२४ में इस बोर्ड के कहने पर बाहर से आनेवाली लोहे की कुछ चीजों पर चुगी बढ़ा दी गई और रेलों का सामान बनाने के लिए जमशेदपुर में टाटा के लोहे के कारखाने को आर्थिक सहायता दी गई। सन् १९२६ में भारतवर्ष में घने हुए कपड़े पर जो चुगी ली जाती थी, वह सन् १९२६ में उठा दी गई।

देश की औद्योगिक कलाओं की उन्नति की ओर भी कुछ ध्यान दिया गया। सन् १९२१ में इसके लिए भारत-सरकार का एक अलग विभाग गला गया। प्रान्तों में यह विभाग मंत्रियों के हाथ में है। लोकमत के जोर से सरकार थोड़ा-बहुत प्रयत्न इस ओर अवश्य कर रही है, पर उससे यह अधिक ध्यान इंग्लैंड के लाभ का ही रहता है। साम्राज्य में बनी हुई चीजों का ही साम्राज्य के सब देशों में व्यवहार किया जाय इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। इस तरह इंग्लैंड का माल भारत के मध्ये मटा जा रहा है, जिसका फल यह होता है कि भारतवर्ष को कभी कभी मँहगी चीजें मिलनी पड़ती हैं, पर इंग्लैंड का व्यापार बढ़ता है और वर्षों की बेकारी खतरा है। महायुद्ध के बाद से इस समय तक भारत की व्यापारिक दशा सुधर नहीं पाई है। प्रधान नेताओं का मत है कि इसका मुख्य कारण सरकार की आर्थिक नीति है, पर सरकार का कहना है कि इसका सम्बन्ध अन्य कारणों की गति से है।

खेती—लार्ड थ्रविन के आने पर 'कृषि कमीशन' नियुक्त हुआ। १९२२ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें इसने पृथा के कृषि-

कालेज को विस्तृत बनाकर कृषि-सम्बन्धी योज के लिए अधिक सुविधाएँ देने की सलाह दी। इसने यह भी बतलाया कि कृषि-विभाग में केवल भारतवासियों को रखने से काम न चलेगा, विशेषज्ञों को बाहर से लाना चाहिए और किसानों को खेती की उचित शिक्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए। लगान की अधिकता के कारण बेचारे किसान पैसे जाते हैं, इसकी श्रांति कुछ भी ध्यान न दिया गया और न मालगुजारी के प्रश्न पर ही विचार किया गया। इस कमीशन की सिफारिशों से किसानों की दशा कुछ भी नहीं सुधरी। अब बाहर से अन्न भी आना प्रारम्भ हो गया है, इसी से खेती की दशा का पता चलता है।

**आर्थिक प्रबन्ध**—खर्च बहुत बढ़ जाने के कारण महायुद्ध के बाद कई एक टैक्स बढ़ा दिये गये। कई साल तक सरकार को बड़ा घाटा होता रहा और कर्ज बढ़ता गया। सन् १९०४ में आमदनी और खर्च का हिसाब बराबर हो गया। सुधारों के समय से प्रान्तों को हर साल एक रकम भारत-सरकार को देनी पड़ती थी, जिसमें उनके काम में बड़ी बाधा पड़ती थी। भारत-सरकार के बजट में बचत होने पर सन् १९२८-२९ में यह प्रबन्ध तोड़ दिया गया। चाँदी की कमी होने के कारण युद्ध के समय में एक एक रुपये के नोट चला दिये गये थे। इनसे जनता को बड़ी असुविधा होती थी। बाद में इनका छापना बन्द कर दिया गया। जनता के विरोध करते रहने पर भी सन् १९२३ में नमक-कर फिर बढ़ा दिया गया। खर्च में कमी करने के लिए सन् १९२२ में लार्ड इचकेप की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसकी सिफारिशों के अनुसार सेना तथा अन्य विभागों में खर्च कुछ घटाया गया। परन्तु भारतीय नौकरियों में अगरेज युवकों की अधिक रूचि पैदा करने की दृष्टि से सन् १९२४ में 'ली कमीशन' ने तनखाहें तथा भत्ता बढ़ा देने की सलाह दी, जिसका फल यह हुआ कि भारत पर एक करोड़ रुपया साल का बोझ और लड़ गया।

ईस्ट इंडियन और ग्रेट इंडियन पेनिशुला रेलवे कम्पनियों के ठेकों की अवधि समाप्त होने पर सरकार ने उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। सन् १९२४ में रेलों का बजट भी अलग कर दिया गया और उनका प्रबन्ध एक 'रेल'

गोर्डे' को मँप दिया गया। तार और डाक के विभागों को भी व्यापारिक ढंग पर चलाने का प्रयत्न किया गया। भारतवर्ष को हर साल एक बड़ी भारी रकम विलायत भेजनी पड़ती है, इसने बहुत न्यायकारी मामान खरीदा जाता है और अफसरों की तनखाहे तथा पेंशने दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार का लेन देन भी रहता है। इसी लिए पाँडु और रुपये की कीमत दर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सन् १९०६-०७ में सरकार ने १ मिलि ग पेंस रुपये की दर निश्चित कर दी। इस निर्णय में सरकार को अवश्य कुछ बचत हुई, पर बाहर माल भेजने में देश का बड़ा नुकसान होने लगा। 'एकमर्चेज' ( विनिमय ) और 'करंसी' ( मुद्रा ) के सम्बन्ध में सरकार की मनमानी नीति के कारण भारत को करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ता है।

इन दिनों भारत की आर्थिक दशा बड़ी जोचनीय हो रही है। सन् १९२६ तक हम पर विलायती कर्ज ४ अरब से भी अधिक हो गया, जो आदमी पीछे ४२ रुपया पड़ता है। इसके सूद तथा 'होम चार्जेज' के नाम से अन्य गर्जे व लिए हमें प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपया इंग्लैंड भेजना पड़ता है। विलायती पूँजी तो भारत में इतनी खपी हुई है कि हमका अनुमान करना उठिन है। इन सब रकमों के कारण देश इंग्लैंड के पास बन्धक सा हो रहा है। जनता पर हमलों का इतना बोझ लद गया है कि उसको पेट भर खाने तर का ठिकाना नहीं है। भारत में आदमी पीछे प्रति दिन दो आने से अधिक की आमदनी का आसत नहीं है।

**शिक्षा**—सन् १९१७ में 'क्लकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन' नियुक्त हुआ। दो वर्ष तक देश में भ्रमण करने के बाद सन् १९१९ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसने भारतीय शिक्षा के सभी प्रश्नों पर विचार किया। इसकी राय थी कि स्कूलों से निकलनेवाले हर एक विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालयों में उच्चता सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में कालेजों में 'इटरमीडियेट' के दर्जे के बालक स्कूलों में मिला देने चाहिए और उनमें शिक्षा का ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए, जिसमें उनमें निकलने पर विद्यार्थियों को जीवन-निर्वाह में सहायता मिल सके। इन 'इटरमीडियेट कालेजों' का निरीक्षण एक बोर्ड के

हाथ में रखना चाहिए। विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कमीशन का कहना था कि उनका मुख्य कर्तव्य "जीवन को हर तरह में उन्नत बनाना" है। दूर दूर के कालेजों को एक विश्वविद्यालय में रखने का फल यह होता है कि उसका काम केवल परीक्षा लेना रह जाता है। इसलिए हमने मलाह दी कि ऐसे छोटे छोटे विश्वविद्यालय बनाने चाहिए, जिनमें विद्यार्थी निवास कर सकें और अध्यापकों के साथ रहकर पूरा लाभ उठा सकें।

इसी ढंग पर सन् १९२०-२१ में ढाका तथा लखनऊ में नये विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये। 'अलीगढ़ कालेज' भी 'मुसलिम विश्वविद्यालय' बन गया, इसमें मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया। आगे चलकर इलाहाबाद के विश्वविद्यालय का भी नये ढंग पर संगठन किया गया और दिल्ली, पटना, नागपुर, रगून, आन्ध्रप्रान्त तथा आगरा में, कहीं नये और कहीं पुराने ढंग के, विश्वविद्यालय स्थापित किये गये। राजा अन्नामलै चेट्टि ने ३५ लाख रुपया शिक्षा के लिए दान किया, इसलिए उनके नाम से चिटम्बरम (मदरास) में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।

सुधारों के समय से प्रान्तों में शिक्षा-विभाग मंत्रियों के हाथ में आ गया। तब से प्रारम्भिक शिक्षा की ओर कुछ विशेष ध्यान दिया गया। कई एक जैहरो की म्युनीसिपलिटियों ने इसको मुफ्त तथा अनिवार्य बना दिया, परन्तु धनभाव के कारण विशेष उन्नति न हो सकी। अनुभव से यह भी पता लगा कि केवल साहित्य की शिक्षा से अधिक लाभ नहीं है। इसलिए सभी श्रेणियों में वैज्ञानिक, औद्योगिक, व्यापारिक तथा खेती की शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। देशी भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कुछ प्रयत्न किया गया। अभी भारत में शिक्षा का बड़ा अभाव है। सन् १९२१ की मनुष्यगणना से पता लगता है कि ब्रिटिश भारत में हजार मर्द पीछे केवल १२२ और हजार औरतों पीछे केवल १८ औरतें पढ़ी-लिखी हैं। अंगरेजी पढ़े हुए लोगों की संख्या तो नाममात्र के लिए है। देश की अशिक्षता दूर करने के लिए सरकार से २० करोड़ रुपया साल भी खर्च नहीं किया जाता, पर वेकास सेना रखने में ५५ करोड़ फूँका जाता है।

**समाज-सुधार**—गिजा के साथ साथ जनता का ध्यान धीरे धीरे समाज-सुधार की ओर आकर्षित होने लगा। ब्रह्मसमाज तथा आर्य समाज पहले ही से इस ओर काम कर रहे थे। कुछ वर्षों से कांग्रेस के साथ 'समाज-सुधार सम्मेलन' भी होत लगे। अग्रहयोग के समय में अछूतों द्वारा ओर मादक वस्तुओं के बहिष्कार पर अधिक जोर दिया जान लगा। हिन्दू महा-सभा ने भी समाज-सुधार को अपनाया। सती-प्रथा बन्द करने के बाद में धार्मिक उदासीनता की नीति का सहारा लेकर सरकार इन मामला में चुन रहा। परन्तु सुधारों के समय में जनता के प्रतिनिधियों ने इसी इस मानता का थोटा-बहुत भग किया। सन् १९०५ में 'महामात्रय' १० वर्ष में बढ़ा कर १३ वर्ष कर दिया गया। इसमें आर बढ़ान के लिए प्रयत्न हा रहा है। सन् १९२६ में 'बालविवाह-निषेध कानून' पास किया गया। इसके अनुसार अप्रैल सन् १९३० के बाद से १४ वर्ष में कम की लड़की आर १८ वर्ष में कम की लड़के का विवाह अपराध बना दिया गया। सभी धर्मा में मादक वस्तुओं का निषेध है, पर तब भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। इनके व्यवसाय से सरकार की उठी आमदनी जाती है, जिसका दोहन के लिए वह तैयार नहीं है। पिछले ७० वर्षों में केवल शराब में सरकारी आमदनी १ करोड़ से २५ करोड़ रुपये पहुँच गई। शराब पीन का व्यसन मिना घट गया, इसी में जान पड़ रहा है।

**साइमन कमीशन**—सुधार-कानून में प्रति दसवें वर्ष शासन-व्यवस्था की जांच करने का नियम रखा गया था। सन् १९०१ ही में अमरावती ने अवधि समाप्त होने के पहले ही जांच करान का प्रस्ताव पास किया था। मुर्सीमेन कमेटी के तान मेंबरों ने भी यही सलाह दी थी। 'लिवरल फेडरेशन' भी बराबर यही कह रहा था। परन्तु इस बात की कुछ भी सुनवाई नहीं की गई। सन् १९२७ में आप ही आप कमीशन नियुक्त करने की घोषणा कर दी गई। सन् १९३० के पहले ही जांच करान का कारण यह बतलाया गया कि जिसमें सबका सरकार के भावों का पता जाय ओर सन्देश दूर होकर शान्ति स्थापित हो जाय। इसमें पार्लामेंट

के लिबरल ( उदार ) दल में एक, लेबर ( मजदूर ) में दो और कजर्वेटिव ( अनुदार ) दल से चार मेम्बर लिये गये । लिबरल दल के प्रसिद्ध वैरिस्टर सर जान माइमन इसके अध्यक्ष बनाये गये ।

इस कमीशन में एक भी भारतवासी न रखा गया । इसके कई एक कारण बतलाये गये । कहा गया कि भारतवर्ष के शासन का अधिकार पार्लामेंट को है, इसलिए पार्लामेंट के मेम्बर ही उसके शासनसम्बन्धी प्रश्नों का ठीक ठीक विचार कर सकते हैं और वन्हीं की गय पार्लामेंट को भी अधिक मान्य होगी । इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में जातिगत झगड़े चल रहे हैं, किस किस जाति के नेता कमीशन के मेम्बर बनाये जायँ, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है । कमीशन के मेम्बरों की संख्या अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में निष्पक्ष विचार की भी बड़ी आवश्यकता है, जिसकी भारतीय नेताओं से, जो राजनैतिक आन्दोलन में भाग ले रहे हैं, आशा करना व्यर्थ है । हिन्दुस्तानियों के सन्तोष के लिए यह निश्चित किया गया कि भारतीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों की कमेटियाँ बना दी जायँ, जो जाँच करने में कमीशन की सहायता करें ।

सारे देश ने इसको अपना घोर अपमान समझा । कांग्रेस तो पहले ही से पार्लामेंट के अधिकार को स्वीकार न करती थी । उसका मत है कि 'आत्म-निर्णय' के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष के भाग्य का निर्णय भारतवासियों के हाथ में ही होना चाहिए । लिबरल दलवाले भी कमीशन में एक भी हिन्दुस्तानी न रखना सहन न कर सके और सबने मिलकर इस कमीशन का बहिष्कार करना निश्चित किया । ता० ३ फरवरी सन् १९२८ को, जिस दिन इस कमीशन ने भारत-भूमि पर पैर रखा, देशभर में हड़ताल मनाई गई । लेजिस्लेटिव असेम्बली और मद्रास, मध्यप्रान्त तथा युक्तप्रान्त की कौंसिलों ने कमीशन पर अपना अविश्वास प्रकट किया । उसकी सहायता करने के लिए जो भारतीय तथा प्रान्तीय कमेटियाँ बनाई गईं, उनके चुनाव में जनता के अधिकांश प्रतिनिधियों ने कोई भाग नहीं लिया । पहली जाँच के बाद नवम्बर में यह कमीशन फिर भारतवर्ष आया । इस बार भी जहाँ जहाँ यह गया हड़-

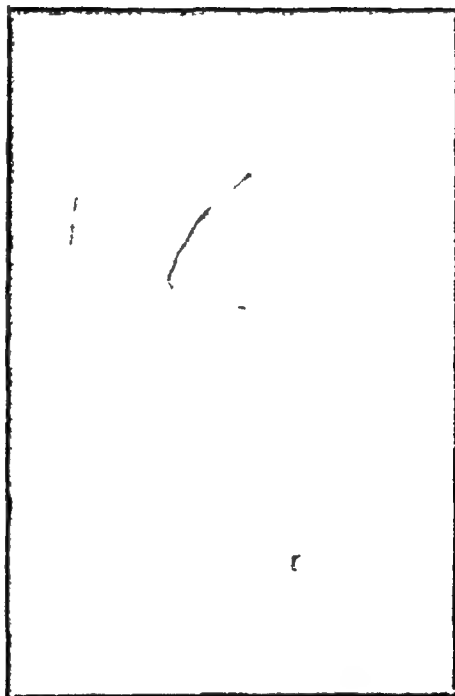


ताल मनाई गई और इसका बहिष्कार किया गया। काले भंडों के जलूस और "लैट जाओ" की ध्वनि से सर्वत्र इसका स्वागत किया गया। कई जगह ऐसे जलूसों पर पुलिस के डंडे चले। लाहौर में लाला लाजपत राय को चोट आई। इसके एक ही महीने बाद, सम्भवत इसी बात के कारण, उनका देहान्त हो गया। उनका मारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत हुआ था।

उनकी स्थापित की हुई 'मर्वेंट्स ग्रोफ दि पीपुल मोसायटी' (लोक-संवक समिति) है, जो अदृष्टोद्धार के लिए बड़ा काम कर रही है।

### सर्वदल सम्मेलन—

सन् १९२० में कांग्रेस का ध्येय 'स्वराज्य' था। इसमें "यदि सम्भव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं तो उसके बाहर" दोनों भाव आ जाते थे। परन्तु अगहयोग के समय से ही एक दल का यह भावित हो रहा था कि साम्राज्य में रखर भारत का हित नहीं है इसी लिए वह पूर्ण स्वतंत्रता पर जोर दे रहा था। गाइडन



लाला लाजपत राय

वर्माण की नियुक्ति से स्पष्ट होकर सन् १९२७ में कांग्रेस ने ध्येय में बिना कुछ परिवर्तन किये हुए 'पूर्ण स्वतंत्रता' को अपना अन्तिम दृष्ट्य मान लिया, पर साथ ही साथ स्वराज्य की परिभाषा पर विचार करने के लिए देश के प्रधान राजनैतिक दलों की एक कमेटी बनाना निश्चित किया। श्री पटित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस

योजना पर विचार करने के लिए देश की राजनैतिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक, आयोगिक तथा अन्य मुख्य मुख्य मस्याओं के प्रतिनिधियों का 'मर्वडल-मम्मेलन' किया गया। परन्तु इसमें भी मुसलमानों के साथ समझौता न हो सका। गान्धीजी के बहुत जोर देने पर कांग्रेस ने यह निश्चित किया कि यदि माल भर में 'नेहरू योजना' के अनुसार श्रीपनिर्वेशिक स्वराज्य दे दिया जाय तब तो वह स्वीकार किया जाय पर यदि ऐसा न हो तो फिर से अग्रहयोग प्रारम्भ किया जाय।

**देशी राज्य—**भारत की ७ लाख वर्गमील भूमि इस समय भी देशी नरेशों के अधीन है। इसमें १०० बड़े और ४५० छोटे छोटे राज्य हैं, जिनकी आबादी ७ करोड़ है। कई एक राज्यों में इधर बहुत कुछ उन्नति हुई है। इनमें मेमूर, त्रावणकोर और बड़ोदा मुख्य हैं। इनमें शिना के प्रचार तथा बलाओं की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है और शासन में प्रजा के प्रतिनिधियों को भी कुछ भाग दिया गया है। बड़ोदा में प्रारम्भिक शिना अनिवार्य और मुफ्त है। राजपूताने में वीकानर भी अन्द्री उन्नति कर रहा है। परन्तु अधिकांश राज्यों में इस समय भी मनमानी शासन-व्यवस्था चल रही है। प्रजा के प्रति राजाओं का जिम्मेदार न होना इसका मुख्य कारण है। बाहरी आक्रमण तथा भीतरी विद्रोह के भय से पहले राजाओं को प्रजा का दायर ध्यान रखना पड़ता था, परन्तु अब दोनों से रक्षा करने के लिए ब्रिटिश सना मौजूद है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुतों को अपनी जिम्मेदारी का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है।

**बटलर कमेटी—**पिछले १० वर्षों में कई कारणों से भारत-सरकार का इन राज्यों में हस्तक्षेप करना पड़ा। इनमें नाभा, इन्दौर तथा भरतपुर व राज्यों में शासनाधिकार ले लिये गये। निजाम से भी बड़ी लिखा-पट्टी हुई, जिसमें लार्ड रीडिंग ने स्पष्ट कह दिया कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य पूर्ण रूप से है। उसके साथ किसी राज्य की दायरी नहीं हो सकती। इस पर देशी राज्यों के साथ भारत-सरकार का क्या सम्बन्ध है और मन्त्रियों तथा

अग्रन्तोप प्रकट किया और 'पूर्ण आधिपत्य' के निद्वान्त का साफ जट्टो में विरोध किया। "दलीमवी गताब्दी के प्रारम्भ से ही भारत में पूर्ण ब्रिटिश आधिपत्य रहा है", कमेटी के इस मत को मडल के अध्यक्ष महाराजा पटियाला ने ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं माना।

**मजदूर-संघ**—गत महायुद्ध के समय से भारत के रूल-कारवानों में काम करनेवाले मजदूरों में भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर तथा अन्य व्यापारिक केन्द्रों में उनके संघ स्थापित हो गये। सन् १९२६ में 'ट्रेड यूनियन बिल' (मजदूर-संघ कानून) पास किया गया, जिसके द्वारा ऐसे संघों को स्थापित करने का अधिकार मान लिया गया और उनके संगठन तथा रजिस्ट्री कराने के नियम बनाये गये। मजदूर लोग हड़तालों द्वारा अपनी पिछाईयों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने लगे। एक दूसरे को प्रति सहानुभूति दिखलाने के लिए सभी कारखानों में हड़ताल होने लगी और उनमें रेलों के कर्मचारी भी शामिल होन लगे। हड़तालों को घटने देखकर सन् १९२६ में सरकार ने 'ट्रेड्स डिम्यूट बिल' (व्यवसायी कगहा कानून) पास किया। इससे मजदूर-संघों की उहुन कुछ म्यतप्रता नष्ट हो गई और हड़तालों के सम्बन्ध में बड़े कठिन नियम बना दिये गये। कगहा निपटाने के लिए पचायतों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। मजदूरों की स्थिति पर विचार करने के लिए ह्रीटली की अध्ययनता में एक समान नियुक्त हुआ है।

**किसानों का एका**—असहयोग के समय से किसानों में भी जागृति हो गई। जमीन्दारों के अत्याचारों से बचने के लिए उत्तरी भारत में 'एका आन्दोलन' चल पड़ा। दक्षिण में भी धीरे धीरे उनका संगठन होने लगा। पारटोली में बिना पूरी जांच किये हुए लगान बढ़ा दिया गया। इस पर सन् १९२८ में वर्धा के किसानों ने सत्याग्रह किया। सरकार की ओर से बड़े अत्याचार किये गये, तब भी वे शान्त रहे। अन्त में उनकी बात मानकर जांच करने के लिए सरकार का एक कमेटी नियुक्त करनी पड़ी, जिसने सरकारी तत्व-



की श्रार यह प्रकट किया कि शीघ्र ही ऐसों नियम बनाये जायेंगे, जिनमें श्रमिकों को ऐसों काया में बाधा डालन का अधिकार न रहे। जिस दिन श्री पटेल अपनी व्यवस्था देनवाले थे, उसी दिन अमेम्बली में एक बम फेका गया, जिसमें बड़ी मनमनी मच गई। उधर लाहोर में कई लोगों पर सरकार के विरुद्ध पट्टेयत्र रचने का मुकदमा चल रहा था। जेल में व्यवहार ठीक न होने के कारण अभियुक्तों ने अनशन प्रारम्भ कर दिया। इनमें ६३ दिन आठ यतीन्द्रनाथ दाम की मृत्यु हो गई। इसी तरह बर्मा में भी पुंगी विजय की मृत्यु हो गई। इसका फल यह हुआ कि जेलों में अभियुक्तों के प्रति व्यवहार की गंभीर जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया और उसमें कुछ सुधार किया गया।

**श्रीपनिवेशिक स्वराज्य**—सन् १९२६ में इंग्लैंड का गायन फिर मजदूर दल के हाथ में आ गया और श्री वेजट्ट डेन भारतमन्त्रि के पद पर नियुक्त किये गये। पहली मजदूर सरकार का भारत के साथ अनुदार व्यवहार और साइमन कमीशन की नियुक्ति में मजदूर दल के सहयोग के कारण भारतवासियों को नई मजदूर सरकार से कोई आशा न थी। साइमन कमीशन के पूर्ण विहिष्कार, नेहरू योजना के सम्बन्ध में देश के मुख्य राजनैतिक दलों की एकता और स्वतंत्रता के आन्दोलन को बढता हुआ देखकर वाइसराय लार्ड आरविन की आंखें खुल गई। मजदूर सरकार से परामर्श करने के लिए वे इंग्लैंड गये। वहाँ न लॉटकर ता० ३१ अक्टूबर



वेजट्ट डेन

सन् १९२६ को उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि

मीने को गलत बतलाया। अकालियों की तरह बारडोली के किसानों ने भी यह दिखला दिया कि यदि पूर्ण रूप से सगठन किया जाय तो व्यावहारिक दृष्टि से भी सत्याग्रह से सफलता प्राप्त करना असम्भव नहीं है।

**पब्लिक सेफ्टी बिल**—ब्रोलगेविक शासन में रूस का कायापालट ही हो गया। इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ने लगा। साम्प्रदायिक झगड़ें और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता देश के युवकों को खटकने लगी और उसे नष्ट करने के लिए 'युवक-सत्र' स्थापित होने लगे। इन सब आन्दोलनों में सरकार को रूस के कम्युनिस्ट (वर्गवादी) लोगों का हाथ दिखलाई देने लगा। इस पर दमन-चक्र फिर चल पड़ा। अहिंसात्मक आन्दोलन की असफलता से कुछ युवकों की प्रवृत्ति भी बदल रही थी, सरकार की दमन-नीति से वे और भी उत्तेजित हो गये। लाहौर में दिनधाड़े पुलिस कमिश्नर गार्ड्स की हत्या की गई। अन्य कई स्थानों में भी पुलिस को पड़्यंत्रों का पता चला। सन् १९२८ में सरकार ने 'पब्लिक सेफ्टी बिल' (जनता-रक्षक कानून) पेश किया। इसका आशय यह था कि यदि किसी विदेशी पर भारत-सरकार को यह सन्देह हो कि वह वर्गवादी सिद्धान्त फैला रहा है, तो वह बिना किसी मुकदमा के निर्वासित कर दिया जाय। असेम्बली ने इसको राष्ट्रीय आन्दोलन पर आक्रमण समझकर नामंजूर कर दिया।

इतने ही में सरकार ने मजदूर तथा किसान आन्दोलन के कुछ नेताओं और तीन अँगरेजों पर मेरठ में एक मुकदमा चला दिया कि वे लोग रूस के 'कम्युनिस्ट' दल की सहायता से भारत में सम्राट् के विरुद्ध पड़्यंत्र रच रहे हैं। इसी के बाद सन् १९२९ में 'पब्लिक सेफ्टी बिल' फिर पेश किया गया। इस पर असेम्बली के अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि इस बिल का बहुत कुछ सम्बन्ध मेरठ के मामले से है, जो अदालत के विचाराधीन है। ऐसी दशा में इस बिल पर पूरी बहस नहीं हो सकती, इसलिए इसका पेश करना ठीक नहीं है। अध्यक्ष पटेल की इस व्यवस्था में सरकार बड़े चक्कर में पड़ गई। इस पर वाइसराय ने अपनी विशेष आज्ञा द्वारा उस कानून को ६ महीने के लिए जारी कर दिया। अपने भाषण में उन्होंने अध्यक्ष की व्यवस्था की आलोचना

की और यह प्रकट किया कि शीघ्र ही ऐसे नियम बनाये जायेंगे, जिनमें अध्वक्ष को ऐसे कार्यों में बाधा डालने का अधिकार न रहे। जिस दिन श्री पटेल अपनी व्यवस्था देनेवाले थे, उसी दिन असेम्बली में एक बम फेंका गया, जिसमें बड़ी मनसूनी मच गई। उधर लाहौर में कई लोगों पर सरकार के विरुद्ध पट्टे रचने का मुकदमा चल रहा था। जेल में व्यवहार ठीक न होने के कारण अभियुक्तों ने अनशन प्रारम्भ कर दिया। इनमें ६३ दिन बाद यतीन्द्र-नाथ दास की मृत्यु हो गई। इसी तरह बर्मा में भी पुंगी विजय की मृत्यु हो गई। इसका फल यह हुआ कि जेलों में अभियुक्तों के प्रति व्यवहार की और जनता तथा सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया और उसमें कुछ सुधार किया गया।

**श्रीपनिवेशिक स्वराज्य**—सन् १९२६ में इंग्लैंड का शासन फिर मजदूर दल के हाथ में आ गया और श्री वेजवुड वैन भारतसचिव के पद पर नियुक्त किये गये। पहली मजदूर सरकार का भारत के साथ अनुदार व्यवहार और साइमन कमीशन की नियुक्ति में मजदूर दल के सहयोग के कारण भारतवासियों को नई मजदूर सरकार से कोई आशा न थी। साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार, नेहरू योजना के सम्बन्ध में देश के मुख्य राजनैतिक दलों की एकता और स्वतंत्रता के आन्दोलन को बढ़ता हुआ देखकर वाइसराय लार्ड अरविन की आँखें खुल गईं। मजदूर सरकार से परामर्श करने के लिए वे इंग्लैंड गये। वहाँ स लौटकर ता० ३१ अक्टूबर सन् १९२६ को उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि



वेजवुड वैन

सन् १९१७ की विज्ञप्ति में 'उत्तरदायी शासन' देने के लिए वचन दिया गया था, उसका अर्थ 'श्रौपनिवेशिक स्वराज्य' है। देशी राज्यों का प्रश्न भारतीय शासन-व्यवस्था से बिलकुल अलग नहीं है। इसलिए सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था पर विचार करने के लिए सरकार, ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शीघ्र ही लन्दन में किया जायगा।

इस पर देश के मुख्य मुख्य नेताओं ने दिल्ली में एक वक्तव्य प्रकाशित किया। इसमें कहा गया कि सम्मेलन (राउड टेबल कान्फरेस) की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि शासन में उदार नीति से काम लिया जाय और राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि श्रौपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर ही सम्मेलन में शासन-व्यवस्था पर विचार किया जाय। परन्तु इसके बाद पार्लामेंट में राइमराय की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में जो बहस हुई, उससे कांग्रेस के नेताओं को ब्रिटिश सरकार की नीति पर सन्देह होने लगा।

**पूर्ण स्वराज्य**—दिसम्बर सन् १९२६ में लाहौर में कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। इसके कुछ दिन पहले ही दिल्ली के निश्चित वाइसराय की ट्रेन के नीचे बम रखकर उनके प्राण लेने का प्रयत्न किया गया। परन्तु सौभाग्यवश किसी को चोट नहीं आई। इस तरह अहिंसा-वादी भारत की लाज रह गई। कांग्रेस ने इस पर खेद प्रकट किया और वाइसराय के प्रति सहानुभूति दिखलाई। गत कलकत्ता कांग्रेस के निर्णय के अनुसार हमने निश्चित किया कि 'पूर्ण स्वराज्य' कांग्रेस का ध्येय है, जिसको प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह प्रारम्भ करना चाहिए। कब और किस रूप में सत्याग्रह किया जाय इसके निर्णय का अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (अल इंडिया कांग्रेस कमेटी) को दिया गया। साथ ही साथ यह भी निश्चित किया गया कि कैमिलों के बहिष्कार में असहयोग फिर से प्रारम्भ किया जाय। अन्य दलों के साथ कांग्रेस की जो एकता हो रही थी वह इस निर्णय में नष्ट हो गई। लिबरलों ने कान्फरेंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसी नेतारी के लिए फिर से एक सर्वदल सम्मेलन करना निश्चित।



किया। उनका कहना है कि वाइसराय, भारतसचिव तथा मजदूर सरकार की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उन पर विश्वास करके कान्फरेंस में शरीक होना चाहिए। पहले से शर्तें रखना ठीक नहीं है।

लाहोर कांग्रेस के आदेशानुसार ता० २६ जनवरी सन् १९३० को देश भर में 'पूर्ण स्वराज्य-दिवस' मनाया गया। इस दिन प्रायः सभी नगरों में मभाएँ की गईं, जिनमें एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा गया कि "भारत की अंगरेज सरकार ने हिन्दुस्तानियों को न केवल उनकी स्वाधीनता से वंचित कर दिया है बल्कि वह जनता के शोषण के आधार पर ही बनी है और उसने हिन्दुस्तान को आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए हिन्दुस्तान को अवश्य ब्रिटिश सम्बन्ध त्यागकर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए।" इसके अन्त में विश्वास दिलाया गया कि "यदि हम ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना छोड़ दें और उत्तेजना का कारण उपस्थित होने पर भी उपद्रव न करें तो इस अमानुषिक शासन का अन्त निश्चित है।"

---

## परिच्छेद १८

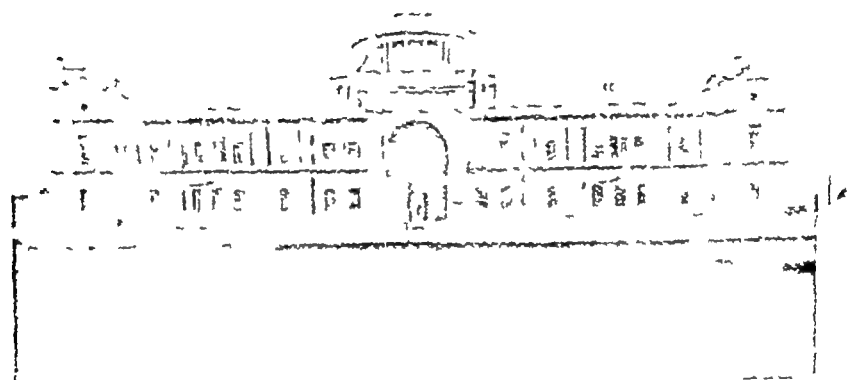
### कला और साहित्य

**ललित कलाएँ**—भारत की मुख्य उपयोगी कलाओं का जिस तरह नाश हुआ, दिखलाया जा चुका है। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता के कारण इस काल में ललित कलाओं की भी अवनति हो गई। मुगल बादशाहों की मरनकता में इन कलाओं की बड़ी उन्नति हुई थी। उनके पतन होने के थोड़े ही वर्षों बाद देश में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ, जिसने इनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी दशा में इन कलाओं ने देशी राज्यों में आश्रय लिया, परन्तु राजाओं का यूरोप जाना-आना प्रारम्भ हो जाने पर इनको प्रायः पूर्णतः भी हटना पड़ा। सस्ती और तडक-भड़कवाली विलायती चीजों के मुलावे में जनता भी पड़ गई। इस तरह भारतीय ललित कलाओं के नष्ट होने की नीव तैयार हो गई। परन्तु इनने ही में राष्ट्रीयता की जागृति प्रारम्भ हुई, जिसने इन कलाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। भारत का शासन जब से ब्रिटिश राजाओं के अधीन हुआ, तब से सरकार ने भी इस ओर कुछ ध्यान दिया। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा लाहौर में 'आर्ट्स स्कूल' (कलाविद्यालय) स्थापित किये गये। परन्तु इनमें बहुत दिनों तक भारतीय कलाओं के पुनरुद्धार का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सरकारी प्रदर्शनीयों में विलायती चीजों की ही भरमार होती रही। अभी हाल तक विश्वविद्यालयों की पढाई में कलाओं को कोई स्थान न था। जनता की इस ओर प्रवृत्ति देखकर सरकार को भी कुछ न कुछ करना पड़ता है, परन्तु अधिकांश विदेशी अफसर न भारतीय ललित कलाओं के मन्त्रे भावों को समझने हैं और न उनकी उन्नति के लिए कोई प्रयत्न ही करते हैं। इस तरह ये कलाएँ सरकारी संरक्षकता से, जो उनकी उन्नति के लिए नितान्त आवश्यक हैं, वास्तव में वंचित ही हैं।

**स्थापत्य**—सुन्दर इमारतें बनाने की कला बड़े महत्त्व की है। इसमें कई एक मुख्य उपयोगी तथा ललित कलाओं का समावेश हो जाता है। भारत की यह कला किसी समय बड़ी उन्नत अवस्था में थी। प्राचीन तथा मुगल काल की सुन्दर इमारतों को देखकर अब भी लोग दंग रह जाते हैं। परन्तु ब्रिटिश काल में इसका भी हास हो गया। पहले-पहल जो अंगरेज आये थे वे हिन्दुस्तानी दंग की इमारतों में ही रहते थे। सूरत में उस समय के बने हुए अंगरेजों के मकबरे बिलकुल मुसलमानी दंग के हैं। परन्तु जब अंगरेजों ने मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई को बसाया, तब इनमें इंग्लैंड के नवकालीन प्रचलित भेदे दंग की इमारतों का अनुकरण किया गया। कम्पनी के व्यापारियों को तब इसका कुछ भी ध्यान न था कि आगे चलकर देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटिश आधिपत्य के साथ-साथ जब इन नगरों का राजनैतिक महत्त्व बढ़ गया, तब जनता तथा राजा-महाराजाओं की दृष्टि में यहाँ की इमारतें आदर्श बन गईं और इन्हीं की नकल होने लगी। सबसे पहले मुर्शिदाबाद तथा लखनऊ के नवाबों ने इस दंग की इमारतें बनवाना प्रारम्भ किया। ऐसी इमारतों में रहना आधुनिक सभ्यता का चिह्न समझा जाने लगा और जगह-जगह इनका प्रचार हो गया। 'मुहकमा नामीरात' (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) खोलकर सरकार ने सार्वजनिक इमारतों का ठेका अपने हाथ में ले लिया। यह विभाग अंगरेज इंजीनियरों को मापा गया, जिन्हें भारतीय स्थापत्य का कुछ भी ज्ञान न था। इंजीनियरिंग के कालेजों में भी इस भारतीय कला की पढाई के लिए कोई प्रवन्ध न किया गया। उस समय के इंजीनियर भारत में भी कोई ऐसी कला है इसको मानने के लिए तैयार न थे। इस विभाग ने देगी स्थापत्य की परम्परा का बिना कुछ ध्यान किये हुए इमारतें बना डालीं। कलकत्ता आर्ट्स स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष हंवेल् के शब्दों में इसके बनाये हुए कालेज सिपाहियों की रोक में जान पड़ते हैं।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> हंवेल्, एमेज़ आन इटियन आर्ट, इटस्टी ऐट एजुकेशन।

इधर बहुत धन फूँककर कलकत्ता में 'विक्टोरिया मेमोरियल हाल' (विक्टोरिया स्मारक भवन) बनाया गया है। लार्ड कर्जन इसके सुन्दरता



### विक्टोरिया मेमोरियल हाल

में 'तान' के सदृश बनवाना चाहता था, परन्तु उसके साथ तुलना में यह तुच्छ जान पड़ता है। जिस समय दिल्ली को फिर से राजधानी बनाने की घोषणा की गई, तब मन्त्रों ने यह आशा हुई कि इसकी नई इमारतों के बनाने में हिन्दुस्तानी मिश्रियों की अपनी कारीगरी दिखलाने का अवसर दिया जायगा। परन्तु उनका निर्माण भी अंगरेज इंजीनियरों को सौंपा गया। इनके बनाने में १८ करोड़ से अधिक रुपया फूँका गया, पर तब भी मुगल काल की इमारतों से सामने ये भट्ठी जान पड़ती है। डाक्टर जेम्स कजिम की राय में इनके बनाने में मालिकाना तथा खूबना से तो काम ही नहीं लिया गया है। मेमोरियल के दायर और बायलभवन "कैदगाने" से जान पड़ते हैं। ये स्मारकें अधिकतर 'इटालियन टग' की बनाई गई हैं। वहीं कहीं जाली

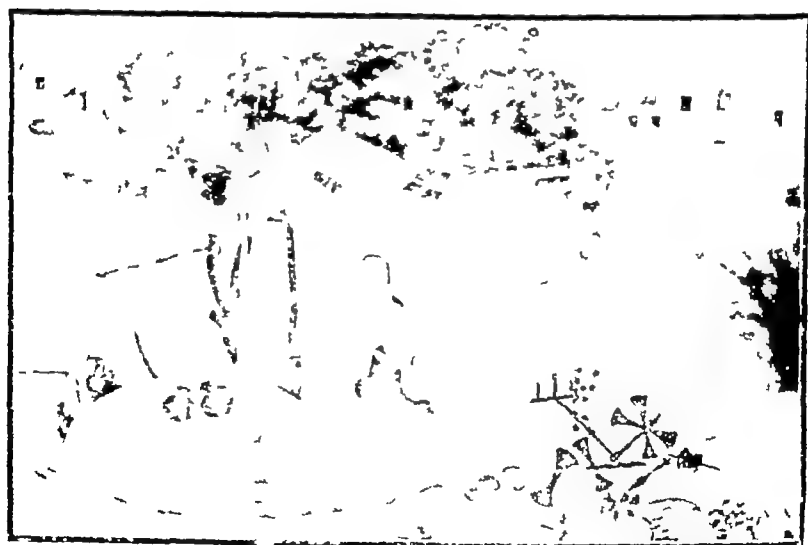
छुज्जा तथा छतरी देकर इनमें हिन्दुस्तानीपन लान का प्रयत्न किया गया है। वाइसराय के भवन में, जो अभी बनकर तैयार हुआ हैं, इस ओर कुछ विशेष ध्यान दिया गया है।

फर्ग्युसन के शब्दों में भारत में यह कला अब भी जीवित है। उसका कहना है कि मैंने स्थापत्य के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो कुछ हिन्दुस्तानी मिस्त्रियों से सीखा, उसका मुझे उस विषय की सब किताबें पढ़ ज्ञान पर भी पता न चला था। बनारस के घाट, मथुरा के मन्दिर, जयपुर नगर तथा बहुत से राजवाडों की कई एक इमारतें ब्रिटिशकाल ही की बनी हुई हैं, जिनमें हिन्दुस्तानी मिस्त्रियों की कारीगरी का नमूना दिखलाई देता है। इस समय भी कहीं कहीं एक आध इमारत इस ढंग की बन जाती हैं। मजबूती में इनका मुकाबला करना सहज नहीं है। परन्तु सरकार, राजा, रईमों तथा अधिकांश जनता की उदासीनता के कारण यह कला धीरे धीरे नष्ट हो रही है। प्रायः कहा जाता है कि यह आधुनिक आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विदेशी कला के सिद्धान्तों को अपने ढंग पर ले आने का हिन्दुस्तानियों में सदा से एक बड़ा गुण रहा है। आजकल इमारत का खाका खींचनेवाले और उसके बनानेवाले भिन्न भिन्न होते हैं। परन्तु मध्यकालीन यूरोप की तरह भारत में ये दोनों काम मिस्त्री के ही हाथ में रहते थे। इस तरह ईवेल की राय में उसको इमारतों के बनाने में अपने भावों को प्रकट करने का अवसर मिलता था। परन्तु अब वह सुन्दर इमारतों की कल्पना करने के अयोग्य समझा जाता है और उसे केवल दूसरों के खींचे हुए नकशा के ढंग की इमारतें बनाने का काम दिया जाता है, जिनमें उसे अपनी कल्पना-शक्ति के दिखलाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता।

**चित्रकारी**—सत्रहवीं शताब्दी में चित्रकारी के दो मुख्य ढंग थे, जहाँ 'मुगल कलम' और 'राजपूत या हिन्दू कलम' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 'मुगल कलम' की उत्पत्ति अकबर के समय में हुई थी। इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के छोटे छोटे चित्र, दरवार तथा शिकार के दृश्य और फूल-पत्ते तथा

पशु-पक्षियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। जहाँ तक सम्भव हो इनकी पूरी नकल करने का प्रयत्न किया जाता था। इस तरह इस कलम का मुख्य लक्षण 'स्वाभाविकता' था। मुगल साम्राज्य का पतन होने पर दिल्ली के बहुत से चित्रकार लखनऊ चले गये। कुछ लोग बिहार तथा बंगाल में भी आबाद हो गये। बहुत से अंगरेज इन चित्रकारों में अपने ढंग की तस्वीरे बनवाने लगे, जिसका फल यह हुआ कि इन पर पाश्चात्य चित्रकारी का प्रभाव पड़ने लगा। इस समय के बन हुए लखनऊ के प्रायः सभी चित्र इसी मिश्रित ढंग के हैं। बंगाल और अवध की नवाबियों के अन्त के साथ इस कला का भी लोप हो गया।

मुगल कलम के साथ साथ उत्तरी भारत के हिन्दू राज्यों में एक दूसरी ही चित्रकला की उन्नति हो रही थी। इसका बहुत कुछ सम्बन्ध भारत की



सुदामा की कुटी ( राजपूत कलम )

प्राचीन चित्रकला में था। इसमें पौराणिक तथा जनसाधारण के जीवन के दृश्य दिखाने का बड़ा प्रयत्न किया जाता था। इसका मुख्य केन्द्र जयपुर

था। यह 'राजस्थानी' या 'राजपूत कलम' के नाम से प्रसिद्ध है।<sup>१</sup> मुगल दरबारों में भी इन चित्रों की मांग थी, इसलिए बहुत से चित्रकार दिल्ली, आगरा तथा लाहौर में आवादी हो गये थे। मुगलों का पतन होने पर इनको पंजाब की छोटी छोटी पहाड़ी राज्यों में आश्रय मिला। इनमें काँगड़ा इम चित्रकला का मुख्य केन्द्र हुआ। इस तरह 'काँगड़ा' या 'पहाड़ी कलम' का प्रचार हुआ। राजा संसारचन्द्र के समय में इसकी बड़ी उन्नति हुई। टिहरी (गढ़वाल) तथा बुंदेलखंड के राज्यों में भी इसका प्रचार हुआ। गढ़वाली चित्रकारों में मोलाराम, माणकू और चैतू का बड़ा नाम है। पहाड़ी चित्रकार राजाओं के छोटे छोटे चित्र भी बड़े सुन्दर बनाने लगे और उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के कई शहरों में उनकी माँग होने लगी। महाराजा रणजीतसिंह के दरबार में भी कई एक पहाड़ी चित्रकार रहते थे। इनमें कपूरसिंह बड़ा प्रसिद्ध था। पंजाब पर अँगरेजों का अधिकार हो जाने से इन लोगों का भी आश्रय जाता रहा। सन् १८०५ के भीषण भूकम्प ने तो काँगड़ा नगर और वहाँ के बचे-बचूचे चित्रकारों का अन्त ही कर दिया।

दक्षिण में हैदराबाद मुसलमान चित्रकारों का केन्द्र था। तजोर और मैसूर में हिन्दू चित्रकारों का आश्रय मिलता था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त में उत्तरी भारत के कई एक चित्रकार तजोर के राजा सरफोजी के दरबार में पहुँच गये थे। तजोर के अन्तिम राजा शिवाजी के समय (१८३३-४६) में इन चित्रकारों के १८ घराने थे। ये लोग हाथीदाँत और लकड़ी पर भी काम करते थे। इनके बनाये हुए राजाओं के पूरे कद के तैलचित्र तजोर के दरबार-भवन में इस समय भी देखने को मिलते हैं। मैसूर में राजा कृष्णराज वाडयार के समय में इम कला की अच्छी उन्नति

१ डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी ने इसको 'राजपूत कलम' का नाम दिया है, परन्तु

२। नानालाल चमनलाल मेहता की राय में इसको 'हिन्दू कलम' कहना ठीक है।

३। राज इन इण्डियन पेंटिंग, पृ० ५।

हुई। सन् १८३८ के बाद से वहाँ भी इसका लोप हो गया।<sup>१</sup> लन्दन के 'ब्रिटिश म्यूजियम' और ब्रोम्टन में भारत के प्राचीन चित्रों के सबसे बड़े संग्रह हैं। भारत में भी इनके संग्रह करने की ओर कुछ ध्यान दिया जा रहा है।

बंगाल में श्री अन्नोन्दनाथ ठाकुर तथा उनके कुछ साथियों की अध्यक्षता में इस कला के प्राचीन सिद्धान्तों को फिर से काम में लाने का प्रयत्न हो रहा है। इनकी राय में भारत की इस कला पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ना ठीक नहीं है। इसके प्रतिकूल कुछ लोगों का मत है कि विदेशी चित्रकारी के सिद्धान्तों का भी अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी दृष्टि से कई एक चित्रकार विलायती तैल तथा जलचित्रों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

**संगीत**—मुहम्मदशाह ( १७१९ ) अन्तिम मुगल बादशाह था, जिसके दरबार में गवैयों का मान होता था। आदरग और सादरग की वीणा प्रसिद्ध थी। इन्हीं दिनों शोरी ने हिन्दुस्तानी गाने में 'टप्पे' का बड़ा प्रचार किया। मुगल साम्राज्य का पतन होने पर यह कला भी देशी नरेशों के दरबारों में रह गई। अंगरेज तो बहुत दिनों तक हिन्दुस्तानी गाने को विलकुल जगती गाना ही समझते रहे। उनमें पहले-पहल सर विलियम जोन्स, विलियम आम्ले, कप्तान डे और विल्ड ने इसकी खूबियों को समझा। सन् १८१३ में पटना के रईस मुहम्मदरिजा ने 'नगमाते आसफी' लिखा, जिसका उत्तरी भारत के संगीत पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसके रागलक्षणों का हिन्दुस्तानी गाने में बहुत प्रचार है। इन्हीं दिनों जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह ने एक 'संगीत सम्मेलन' किया, जिसके प्रयत्न से 'संगीतसार' की रचना हुई। सन् १८४२ में कृष्णानन्द व्यास ने कलकत्ते से 'संगीतरागकल्पद्रुम' नामक हिन्दी गीतों का एक अच्छा संग्रह प्रकाशित करवाया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में सर सुरीन्द्रमोहन ठाकुर ने संगीत का बृहत् इतिहास तथा अन्य कई एक उपयोगी पुस्तकें निकाली।

<sup>१</sup> ब्राउन, इटियन पेंटिंग ( हेरिटेज ऑफ इटाली मिरान )।



दक्षिण में तंजोर के राजा तुलजाजी (१७६३-१७८७) का दरबार गवैयो का केन्द्र था। स्वयं तुलजाजी को संगीत में बड़ी योग्यता थी। उसका 'संगीत-नारामृतम्' नामक ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध है। त्यागराज (१८००-१८५०) तंजोर ही का रहनेवाला था, जिसके कीर्तने का दक्षिण में बहुत प्रचार ह। पट्टाल गोविन्द का भी दक्षिण में बड़ा नाम है। कोचिन और त्रावणकोर के राजाओं की संगीत में बड़ी रुचि थी। पेरुमाल महाराज की रचनाएँ संस्कृत, तामिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी और हिन्दुस्तानी में भी मिलती हैं।<sup>१</sup>

पिछले बीस-पच्चीस वर्षों में संगीत की ओर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्य मुख्य नगरों में 'संगीत-समाज' स्थापित हो गये। सन् १९१६ में महाराजा बडोदा की अध्यक्षता में 'अखिल भारतीय संगीत-सम्मेलन' हुआ। सन् १९१९ में 'अखिल भारतीय संगीत-परिषद्' (आल इंडिया म्यूजिक एकेडेमी) की स्थापना हुई। सन् १९२७ में प्रान्तीय सरकार की ओर से लखनऊ में 'मैरिस संगीत-विद्यालय' खोला गया। अब बहुत से स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में संगीत की शिक्षा का प्रबन्ध हो गया है। नाट्यकला में 'यात्राओं' तथा 'रास-मंडलियों' का स्थान थियेट्रो ने लिया। पारसी कम्पनियों में बहुत दिनों तक पाश्चात्य थियेट्रों की भद्दी नकल की गई। पर शिक्षा के साथ साथ जनता की रुचि में परिवर्तन हुआ और इस कला के सुधार का भी प्रयत्न होने लगा। बंगाल तथा महाराष्ट्र ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। थोड़े दिनों से व्यवसायी नाटक कम्पनियों के खेले में भी कुछ सुधार हो रहा है, पर वारतव में इस समय तक भारत में राष्ट्रीय गमक का अभाव ही है।

**साहित्य**—देश के साहित्य की उन्नति की ओर ब्रिटिश सरकार केवल उदासीन ही नहीं रही, बल्कि अँगरेजी भाषा का प्रचार करके उसने उसके मार्ग में रूपावटें डालीं। परन्तु जनता उसको भूल न सकी। इस काल में संस्कृत साहित्य की कोई वृद्धि नहीं हुई पर उसका पुनरुद्धार अवश्य हुआ।

बौद्धकाल के बाद से भारतीय विचारों का अन्य देशों में प्रचार बन्द ही सा हो गया था, पर यूरोप के साथ सम्बन्ध हो जाने से यह मिलमिला फिर जारी हो गया। यूरोप के, खासकर जर्मनी के, कई एक विद्वानों ने संस्कृत के सभी विषयों का अध्ययन प्रारम्भ किया। बड़े बड़े शहरों में इसके लिए समितियाँ स्थापित हो गईं और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में संस्कृत को स्थान दिया गया। सभी विषयों के संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद और उनकी विद्वत्तापूर्ण आलोचनाएँ प्रकाशित होने लगीं। मैक्समूलर ऐसे विद्वानों का भारत सदा कृतज्ञ रहेगा। भारत में भी नये ढंग पर संस्कृत का अध्ययन प्रारम्भ हो गया। मसूर, ब्रायणकोर, बडौदा तथा काश्मीर दरबारों की ओर से वहाँ के पुस्तकालयों में हस्तलिखित ग्रन्थ विद्वानों द्वारा सम्पादित करवाकर प्रकाशित किये जाने लगे। काशी, कलकत्ता, पूना तथा अन्य स्थानों में भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ काम हो रहा है और प्रति वर्ष बहुत से अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित हो जाते हैं।

ब्रिटिश काल सबसे अधिक देश की आधुनिक भाषाओं की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। प्रायः इन सभी भाषाओं में गद्य की रचना इसी काल में प्रारम्भ हुई। पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा और इन भाषाओं के साहित्य को देश-काल के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया। द्वापेयाने का साधन मिल जाने से इनकी उन्नति में बड़ी सुगमता हो गई। पत्र-पत्रिकाओं का एक नया मार्ग खुल गया। प्रायः सभी विषयों पर अब इन भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं।

**हिन्दी**—भारत में अंगरेजी राज्य के आरम्भकाल में हिन्दी साहित्य के आधुनिक अभ्युदय का आरम्भ होता है। यो तो हिन्दी गद्य के कुछ नमूने तब भाषा के एक याव प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलते हैं, पर सबसे पुराना आधुनिक हिन्दी गद्य का जो मुख्य ग्रन्थ प्राप्त हुआ है, वह मुशी सदासुखलाल का किया हुआ भागवत का स्वच्छन्द अनुवाद 'सुरसागर' है। इसमें पंडितों तथा साधु-मन्तों में प्रचलित भाषा के शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया गया है। इसके अनन्तर मुशी इशाउल्लाहा ने 'रानी केतकी की कहानी' लिखी। इसमें "हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले" इसका उन्होंने बड़ा

प्रयत्न किया। इसकी भाषा सरल और सुन्दर है, पर पद्यों की रचना उर्दू ढंग की है। इसी लिए कुछ लोग इसे हिन्दी का नमूना न मानकर उर्दू का पुराना नमूना मानते हैं। सन् १८०० के लगभग कलकत्ते में हिन्दी गद्य के कुछ ग्रन्थों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसमें श्रीरामपुर के मिशनरियों ने भी योग दिया। डाक्टर गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में 'फोर्ट विलियम कालेज' में भी इस सम्बन्ध में कुछ काम हुआ। यहाँ के लल्लूलालजी ने 'प्रेमसागर' की रचना की और सदल मिश्र ने 'नसिकेतोपाख्यान' लिखा। इनमें लल्लूलालजी की अपेक्षा सदल मिश्र की भाषा अधिक पुष्ट और सुन्दर है, पर एक में प्रजभाषा का और दूसरे में पूर्वी भाषा का पुट स्पष्ट देख पड़ता है।

उत्तर भारत में अँगरेजी राज्य के स्थापित होने पर यहाँ की दरबारी भाषा के स्थान पर राज-काज की भाषा उर्दू मानी गई। मुसलमान हिन्दी को कोई भाषा मानने के लिए तैयार न थे। उनका कहना था कि जब राज-काज की भाषा उर्दू है, तब उसी में सब प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। राजा शिवप्रसाद ने इस मत का विरोध किया और उद्योग करके हिन्दी की पढाई को भी शिक्षाक्रम में स्वीकार कराया। पर साथ ही साथ समय की प्रगति के अनुकूल ऐसी भाषा का स्वरूप खड़ा किया जो देवनागरी और फारसी अक्षरों में सुगमता से लिखी जा सके। इस भाषा में प्रायः फारसी शब्दों की अधिकता होती थी। राजा लक्ष्मणसिंह तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र इस मत के विरोधी थे और भारतीय संस्कृति की परम्परा से अपने को अलग करने के लिए तयार न थे। उन्होंने हिन्दी को ऐसा रूप दिया जिसमें स्वदेशी शब्दों की अधिकता थी। शब्दों की इस विभिन्नता को छोड़कर हिन्दी और उर्दू के ढाँचे में उस समय कोई अन्तर न था। पीछे चलकर उर्दू फारसी की और अधिक झुकी और हिन्दी ने संस्कृत का आश्रय लिया।<sup>१</sup>

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का प्रभाव हिन्दी भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने भाषा को "चलता, मधुर और स्वच्छ" बना दिया। वास्तव में वे वर्तमान हिन्दी गद्य के प्रवर्तक हैं। साथ ही साथ उन्होंने

साहित्य को भी नवीन मार्ग दिखलाया। नई शिक्षा के प्रभाव से देश की विचारधारा में बड़ा परिवर्तन हो रहा था। समाज-सुधार तथा देशभक्ति की नई उमंगें उठ रही थीं। उन्होंने साहित्य को देश-काल के अनुकूल बना



भारतेंदु हरिश्चन्द्र

दिया। बंगाल की नवीन साहित्यिक प्रगति का भी उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने हिन्दी साहित्य की भी उसी ढंग पर उन्नति करने का प्रयत्न किया। उनके जीवनकाल में ही पंडित बदरीनारायण चौधरी, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अम्बिकादत्त व्यास और लाला श्रीनिवासदास ऐसे लेखकों और कवियों का एक मंडल तैयार हो गया, जो उनके अस्त हो जाने पर भी हिन्दी साहित्य के इस नये विकास में, बहुत कुछ काम करता रहा। अनेक प्रकार के

गद्य, प्रबन्ध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे।<sup>१</sup>

ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में प्राचीन शैली के भी कई एक प्रसिद्ध कवि हुए। इनमें पद्माकर भट्ट का नाम मुख्य है। मराठा तथा राजपूत दरबारों में इनका बड़ा मान था। 'रीतिकाल' के कवियों में इनका स्थान 'सर्वश्रेष्ठ' माना गया है। अलीमुद्दीन खाँ (प्रीतम) और सैयद गुलामनबी (रसलीन) ऐसे सुसलमान भी इन दिनों हिन्दी में कविता करते थे। गद्य के विकासकाल में भी कविता की प्राचीन परम्परा बहुत दिनों तक चलती रही, परन्तु भारतेंदु के समय

से इसकी धारा ने भी एक नया रंग धारण किया। केवल भक्ति और शृंगार रस में हटकर इसका सम्बन्ध प्रतिदिन के जीवन से हो गया। भारतेन्दु और उनके सहयोगी लेखकों ने देशकाल के अनुकूल नये नये विषयों की ओर ध्यान दिया, पर उन्होंने व्रजभाषा की परम्परा को नहीं छोड़ा। उनकी कविताएँ व्रजभाषा में प्रचलित छन्दों में ही हुआ करती थीं। भारतेन्दुजी के न रहने के कुछ ही दिनों बाद इस सम्बन्ध में भी नये विचार उत्पन्न हुए। गद्य एक भाषा में लिखा जाय और पद्य दूसरी भाषा में यह बात खटकने लगी। इसका फल यह हुआ कि खड़ी बोली में भी कविता होने लगी। यह प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। कुछ दिनों से अन्यानुप्रास-रहित अथवा अतुकान्त कविता की भी चाल चल पड़ी।

सन् १९०३ में 'काशी नागरीप्रचारिणी सभा' की स्थापना हुई, तब से हिन्दी की उन्नति के लिए संगठित रूप से काम होने लगा। नाटक, उपन्यास, इतिहास, निबन्ध, समालोचना तथा वैज्ञानिक विषयों पर पुस्तकें और सुन्दर पत्र-पत्रिकाएँ बड़ी संख्या में प्रकाशित होने लगीं। कुछ दिनों तक तो अनुवादों की भरमार रही पर अब उच्च कोटि के मौलिक ग्रन्थ भी निकलने लगे हैं। विश्वविद्यालयों की ऊँची से ऊँची परीक्षाओं में भी हिन्दी को स्थान मिल गया है। जब से महात्मा गान्धी ने इन्दौर में 'हिन्दी साहित्य-सम्मेलन' के सभापति का आसन ग्रहण किया, तब से उस संस्था द्वारा आसाम और मदराम ऐसे प्रान्तों में भी हिन्दी के प्रचार का प्रबन्ध हो रहा है, जिसकी सफलता से आशा होती है कि किसी दिन हिन्दी भिन्न प्रान्तों के परस्पर व्यवहार की भाषा होकर राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित होगी।

उर्दू—जो बात संस्कृत के सम्बन्ध में कही गई है वही अरबी तथा फारसी के सम्बन्ध में कही जा सकती है। इन भाषाओं के प्राचीन ग्रन्थों के अच्छे-बुरे संस्करण भारत में प्रकाशित होने लगे, जिनका प्रचार अफगानिस्तान, ईरान तथा अन्य मुसलमानी राज्यों में हो रहा है। 'मदरमनुल ग़ालिया' कलकत्ता, 'दरललूलूम' देवबन्द (सहारनपुर) और 'नदवतुल उलमा' लखनऊ ऐसे विद्यालयों में अरबी तथा फारसी के अध्ययन का अच्छा

प्रबन्ध है। इनमें भारत से बाहर के भी छात्र शिक्षा पाते हैं। परन्तु ब्रिटिशकाल उर्दू की उन्नति के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके कवियों का मुख्य केन्द्र दिल्ली था। मुगल बादशाहों की अवनत अवस्था में भी दर्द, सोज और सौदा ऐसे कवियों ने कुछ काल तक उनके दरबार में अपनी सुन्दर रचनाओं द्वारा बड़ी कीर्ति प्राप्त की। दर्द ने उर्दू कविता को 'भापा दोहरो' के प्रभाव से मुक्त किया और अपने उच्च सूफी विचारों से इसको गम्भीर बना दिया। सोज ने गजलो में अच्छा नाम पैदा किया। सौदा ने भी हिन्दी शब्दों की बड़ी काट-छाँट की, पर उसने हिन्दी साहित्य से उर्दू का नाता एकदम तोड़ नहीं दिया। उसकी रचनाओं में कहीं कहीं अर्जुन की वीरता और कृष्ण की लीलाओं का भी उल्लेख मिलता है। उर्दू काव्य में उसने 'कमीदा' और हास्यरस की रचनाओं का प्रचार किया। मीरतकी की भी प्रसिद्धि पहले-पहल दिल्ली ही में हुई। उर्दू गजलो का यह 'शेख सादी' माना जाता है। इना को उर्दू तथा हिन्दी दोनों में कविता का अभ्यास था। अन्तिम मुगल बादशाह बहादुरशाह (जफर) स्वयं एक अच्छा कवि था। उसके समय में गालिव और जोक ऐसे कवियों से दिल्ली दरबार साहित्य की दृष्टि ने अन्तिम बार जगमगा उठा। जोक ने उर्दू भाषा को स्वच्छ बनाया और कमीदा तथा गजल में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की। गालिव बड़े उच्च कोटि का विद्वान् और कवि था। वह फारसी तथा उर्दू दोनों में कविता करता था। उसकी रचनाएँ उच्च विचारों से पूर्ण तथा मौलिक हैं। कहीं कहीं उनमें हास्यरस का भी आनन्द आ जाता है। उर्दू के गद्य और पद्य दोनों में उसको उच्च स्थान प्राप्त है।

मुगल बादशाहों की दशा विगडने पर दिल्ली के बहुत से कवियों ने लखनऊ के नवाबों के यहाँ आश्रय लिया। आगे चलकर यहाँ नासिप और आतिश ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। लखनऊ में 'मर्सियो' का बड़ा प्रचार हुआ। इनमें कहीं कहीं बड़े मर्मस्पर्शी भाव प्रकट किये गये हैं। उर्दू साहित्य को गन्दा करनेवाली 'रेखनी' कविता का प्रचार लखनऊ के व्यसनी दरबार में ही अधिक हुआ। अन्तिम मुगल बादशाह वाजिदअली (अक़्बर) की भी

कविता का बड़ा शौक था। लखनऊ के बाद उत्तरी भारत में उर्दू के कवियों का रामपुर केन्द्र बन गया। अँगरेजी शिक्षा का काफी प्रभाव पड़ने पर उर्दू कविता की गति-विधि भी बदलने लगी। केवल शृंगाररस को छोड़कर इसका भी प्रवाह समाज और देश की ओर हो गया। आजाद और हाली के साथ उर्दू साहित्य में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। कवियों की प्रवृत्ति नये विषयों की ओर हुई और गजलों का स्थान 'मुसद्दस' तथा 'मसनवियों' ने लिया।<sup>१</sup>

उर्दू गद्य की उन्नति पहले-पहल कलकत्ता के 'फोर्ट विलियम कालेज' में हुई। डाक्टर गिलक्राइस्ट ने कई एक योग्य विद्वानों को एकत्र करके कुछ पुस्तकें लिखवाईं। सन् १८३५ से अदालती भाषा हो जाने के कारण उत्तरी भारत में उर्दू का बड़ा प्रचार हो गया। बाद में लखनऊ से भी गद्य-साहित्य निकलना प्रारम्भ हो गया। इसमें मिर्जा रजवश्रली बेग ने अच्छा नाम पैदा किया। आजाद और गालिव ने भी गद्य की उन्नति में भाग लिया। मर सैयदअहमद ने अखबारी भाषा का प्रचार किया। आजकल अलीगढ़, भूपाल और हैदराबाद उर्दू साहित्य के मुख्य केन्द्र हैं। अलीगढ़ में 'मुसलिम विश्वविद्यालय' स्थापित हो जाने से इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हैदराबाद के 'उस्मानिया यूनिवर्सिटी' में उर्दू ही शिक्षा का माध्यम है। औरंगाबाद में 'अजुमन तरक्की उर्दू' अच्छा साहित्य प्रकाशित कर रही है। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि पहले हिन्दी और उर्दू में कोई विशेष भेद न था, परन्तु कुछ काल से दोनों में बड़ा भेद हो गया। अब थोड़े दिनों से दोनों के क्लिष्ट शब्दों को निकालकर साधारण बोलचाल की 'हिन्दुस्तानी' भाषा के प्रचार का प्रयत्न हो रहा है। इलाहाबाद में प्रान्तीय सरकार द्वारा स्थापित 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' इस ओर विशेष ध्यान दे रही है।

**बंगला**—सत्रहवीं शताब्दी के अन्त से बंगला में संस्कृत शब्दों का अधिकता से प्रयोग होने लगा। इसी समय में अलाउल नाम के एक मुसलमान

<sup>१</sup> रामदास स्वामेना, ए हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर।

ने हिन्दी 'पद्मावत' का अनुवाद किया, जिसमें संस्कृत शब्दों की भरमार है। अशरहवीं शताब्दी के आरम्भ में पश्चिमी बंगाल में नवद्वीप के राजा कृष्णचन्द्र का दरबार बंगाल के कवियों का मुख्य केन्द्र था। इनमें रामप्रसाद और 'अन्नदामल' तथा 'विद्यासुन्दर' के रचयिता भारतचन्द्र राय गुणाकर मुख्य थे। भारतचन्द्र की रचनाओं में संस्कृत शब्दों तथा छन्दों का प्रयोग बड़ी स्वतंत्रता के साथ किया गया है। पूर्वोक्त बंगाल में इन्हीं दिनों विक्रमपुर के राजा राजवल्लभ के दरबार में जयनारायण सेन तथा उनकी भतीजी आनन्द-मयी का बड़ा नाम था। बंगाल के गाँवों में भी कीर्तन, यात्रा तथा 'कवि-वालाओं' द्वारा ग्राम्य साहित्य की उन्नति होती रही। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में चन्द्रनगर में ऐटनी नाम का एक पुर्तगाली बड़ा प्रसिद्ध 'कवि-वाला' था। इन्हीं दिनों करमशर्मा, अलीराज तथा अन्य कई सुमल-माना न भी सुन्दर गीतों की रचना की।<sup>१</sup>

बंगाली गद्य के कुछ नमूने 'शून्यपुराण' और न्याय तथा स्मृति-सम्बन्धी ग्रन्थों में अवश्य मिलते हैं, पर वास्तव में इसका विकास अँगरेजों के आने के बाद में आरम्भ हुआ। श्रीरामपुर के मिशनरियों ने इसकी उन्नति में बड़ा योग दिया। डाक्टर कैरी तथा प्रैसी हालहेड ने कई एक पुस्तकें लिखीं। सर चार्ल्स विलकिंस ने बंगाली अक्षरों के छापने का प्रयत्न किया। 'फोर्ट विलियम कालेज' में पढ़ाई के लिए प्रायः सभी विषयों पर बंगाली पुस्तकें लिखी गईं। हिन्दी, उर्दू तथा बंगाली के गद्य-साहित्य की उन्नति में इस काल की उपयोगिता अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी। 'प्रबोधचन्द्रिका' के रचयिता मृत्युञ्जय तथा रामराम वसु इस काल के मुख्य बंगाली अध्यापक थे। इन दिनों गद्य की जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं, वे साधारण शिक्षा की दृष्टि से लिखी गई थी, उनकी गणना उच्च साहित्य में नहीं की जा सकती। इसका आरम्भ वास्तव में राजा राममोहन राय ने किया। परन्तु उनकी भाषा में फारसी शब्दों की अधिकता रहती थी। पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने इसको संस्कृत

<sup>१</sup> प्लिनेचन्द्र मेन, डिप्टी ऑफ बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर।



का आश्रय देकर 'प्राधुनिक स्वरूप' दिया। इतने दिनों में अँगरेजी शिक्षा के प्रभाव से आचार-विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया। समाज-सुधार तथा स्वदेश-भक्ति ने जोर पकड़ा, जिसके साथ साथ साहित्य ने भी राष्ट्रीयता के क्षेत्र में पैर रखा।

'आनन्दमठ' के रचयिता श्री बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के समय से बंगला साहित्य का नया युग प्रारम्भ हुआ। उन्होंने तत्कालीन भाषा के भद्देपन को दूर करके उसे स्वच्छ और उच्च विचारों के प्रकट करने योग्य बनाया। उनके ग्रन्थों का प्रायः सभी हिन्दुस्तानी भाषाओं में अनुवाद हो गया है। पद्य में श्री माइकेल मधुसूदन दत्त ने श्रुतकान्त कविता का प्रचार किया। उनका 'मेघनादवध' बड़ा प्रसिद्ध काव्य है। बाद में हेमचन्द्र, नवीन सेन, रंगलाल तथा कामिनी राय की रचनाओं का बड़ा आदर हुआ। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्धि तो भारत के बाहर भी फैल गई है। उनके मुख्य मुख्य ग्रन्थों का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो गया है। साहित्य में उन्हें विख्यात



'नोबेल पुरस्कार' भी मिला है। नाटकलेखकों वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय में श्री द्विजेन्द्रलाल राय का बड़ा नाम है। विज्ञान तथा दर्शन के उच्च और सूक्ष्म विचारों को सुन्दर तथा सरल भाषा में प्रकट करने का यश श्री रामेन्द्र-सुन्दर त्रिवेदी को प्राप्त है। उपन्यास तथा गल्प लिखने में बंगालियों को अच्छी सफलता हुई है। देशी भाषाओं में बंगला ने बड़ी उन्नति की है। इसका साहित्य बहुत कुछ मौलिक है। सुसम्पादित पत्र-पत्रिकाओं तथा उच्च कोटि के ग्रन्थों द्वारा इसकी बराबर उन्नति हो रही है।

**मराठी**—अठारहवीं शताब्दी के मराठी साहित्य में मोरोपन्त का नाम सबसे विख्यात है। उनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिकता

से मिलता है। काव्य की दृष्टि से वे उच्चकोटि की भले ही न मानी जायें पर वे उच्च विचारों से पूर्ण हैं। मराठी की गणना उन इनी-गिनी भाषाओं में है जिनका बाल्यकाल पद्य में नहीं बल्कि गद्य में प्रारम्भ हुआ। मतारा के राजा प्रतापसिंह के समय तक मल्हार रामराव तथा अन्य लेखकों ने मराठी गद्य साहित्य की परम्परा को जारी रखा। परन्तु अँगरेज पाठरियो ने कुछ कोप, व्याकरण तथा साधारण अँगरेजी पुस्तकों के अनुवाद निकाले, जिनमें मराठी साहित्य अपनी प्राचीन परम्परा से बहुत कुछ अलग हो गया। सरकारी अफसरों ने प्रायः इस ढंग के साहित्य को आश्रय दिया। श्री विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने 'निबन्धमाला' में बड़े जोरों के साथ मराठी के इस 'अँगरेजी अन्तार' की खर ली और उसके साहित्य को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाया। इस समय से वास्तव में मराठी साहित्य का नवीन युग प्रारम्भ हुआ।

नाटक लिखने में पहले विष्णु भावे तथा अण्णा किर्लोस्कर और बाद में ठाण्णाजी प्रभाकर गायडिलकर, वासुदेवशास्त्री खरे तथा राम गणेश गडकरी ने बड़ी सफलता प्राप्त की। केशवसुत, त्र्यम्बक बापूजी ठोमरे (बालकवि) और नामिक के गोविन्द ने कविता को उच्च कोटि पर पहुँचा दिया। ऐतिहासिक साहित्य में विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे तथा वासुदेवशास्त्री खरे ने बड़ा काम किया। उपन्यासलेखकों में हरिनारायण आपटे तथा नाथमाधव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। आपटे के कई एक ऐतिहासिक उपन्यासों का हिन्दी में भी अनुवाद हो गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 'गीतारहस्य' चिरस्मरणीय रहेगा। मराठी साहित्य में इसकी गणना 'ज्ञानेश्वरी' तथा 'दायगोव' के साथ की जा सकती है। बँगला की तरह मराठी की भी इस तरफ बड़ी उन्नति हुई। इसका भी आधुनिक साहित्य बहुत कुछ मौलिक है।

**गुजराती**—अनिश्चित राजनैतिक परिस्थिति के कारण अठारहवीं शताब्दी में गुजराती साहित्य की विशेष उन्नति नहीं हुई। इस काल में कई एक भक्त कवि अवश्य हुए, पर उनकी रचनाओं में अधिकतर 'साम्प्रदायिकता' दृश्यती है। दयाराम प्राचीन शैली के अन्तिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। गुजराती के अनिरिक्त उनकी रचनाएँ ब्रजभाषा, मराठी, संस्कृत तथा

उर्दू में भी मिलती है। गुजरात में उनकी 'गरवी' तथा पदों के गाने की बड़ी चाल है। उनकी भाषा सरल, स्वच्छ तथा भावमयी है। अँगरेजी शिक्षा के साथ आधुनिक गुजराती साहित्य का भी प्रारम्भ हुआ। पहले पढ़ाने के काम की कुछ साधारण पुस्तकें लिखी गईं, पर जब से सन् १८४८ में फोर्ब्स ने 'गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी' स्थापित की तब से गुजराती साहित्य की उन्नति के लिए संगठित रूप से प्रयत्न होने लगा। दलपतराम और नर्मदा-शंकर के साथ आधुनिक साहित्य का युग प्रारम्भ हुआ। इन दोनों ने समाज-सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया। नवलराम के शब्दों में दलपतराम की कविताएँ 'चतुराईपूर्ण' तथा 'सभारजिनी' हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल तथा सुन्दर है। नर्मदाशंकर की भाषा बड़ी जोरदार है, पर कहीं कहीं 'बजारू' शब्दों से मिश्रित है। प्राकृतिक सौन्दर्य के वर्णन में उनके उच्च भाव और कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है। गुजराती साहित्य की उन्नति में पारसियों ने भी भाग लिया। फर्दूनजी मर्जवानजी ने बम्बई में पहला गुजराती छापाखाना स्थापित किया। कहा जाता है कि गुजराती में श्रुतुकान्त कविता का एक पारसी ने ही पहलेपहल प्रचार किया।

सनद तथा फरमानों और कुछ नीति-सम्बन्धी ग्रन्थों में गुजराती गद्य का प्रयोग अवश्य मिलता है, पर इसका विकास वास्तव में ब्रिटिश काल के प्रारम्भ में ही हुआ। कुछ पादरियों ने इसमें बाइबिल के अनुवाद करने का प्रयत्न किया। बाद में रणछोडदास गिरधर भाई ऐसे लोगों ने इसमें प्रारम्भिक शिक्षा योग्य पुस्तकों के लिखवाने की ओर ध्यान दिया। पर आधुनिक गद्य के प्रवर्तक वारतव में नर्मदाशंकर ही हैं। उनका 'राज्यरंग' इतिहास तथा साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि का ग्रन्थ है। उनके बाद नवलराम गद्य के सबसे अच्छे लेखक माने जाते हैं। आलोचना उनका मुख्य विषय था। ये तो नाटक लिखने का प्रारम्भ दलपतराम से ही हो गया था पर इसके उच्च श्रेणी पर पहुँचने का यश रणछोडभाई उदयराम को प्राप्त है। राव-दादुर नन्दशंकर तुलजाशंकर ने 'करणघेलो' नामक आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लिखा। गोवर्धनराम त्रिपाठी का 'सरस्वतीचन्द्र' गुज-

राती में बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका कई एक भाषाओं में अनुवाद हो गया है।<sup>१</sup>

**तामिल-तेलुगू**—इन दोनों भाषाओं की गणना प्राचीन भाषाओं में है। पर इनके भी गद्य का विकास ब्रिटिश काल ही में हुआ। तामिल साहित्य का आधुनिक काल पन्द्रहवीं शताब्दी में माना जाता है। अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी में परणज्योति मुनि, शिवप्रकाश स्वामी, त्रिकुट-राजप्पा तथा एलप्पा नावलर प्रसिद्ध कवि हुए। प्राचीन ग्रन्थों की टीकाओं तथा कुछ जैन ग्रन्थों में तामिल के प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है। परन्तु आधुनिक गद्य का लिखना वीर्म मुनि तथा अरुमुग नावलर ने ही प्रारम्भ किया। वैज्ञानिक साहित्य में सूर्यनारायण शास्त्री ने अच्छी सफलता प्राप्त की। गद्य साहित्य में शैल्यकेशवराय मुदली का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय स्वामीनाथ शास्त्री ने कई एक प्राचीन ग्रन्थों का सरल भाषा में अनुवाद किया है। तेलुगू में 'नीतिचन्द्रिका' के रचयिता चित्रयसूरि की लेखनशैली बड़ी उच्च कौटिली की मानी जाती है। तेलुगू साहित्य को देशकाल के अनुसार बनाने का यश वीरेशलिगम् को प्राप्त है। सभी विषयों पर उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। नाटक लिखने में लक्ष्मीनरसिंहम् तथा सुब्बारायडू और वेंकटेश्वर कवुलु के नाम प्रसिद्ध हैं। 'आन्ध्र साहित्य-परिपन्' की ओर से तेलुगू की उन्नति के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है।

**विज्ञान**—ज्योतिष तथा गणित में तो कुछ काम होता रहा पर भौतिक विज्ञान को भारत हजारों वर्ष से भूला हुआ था। ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हो जाने का फल यह हुआ कि इस ओर फिर ध्यान आकर्षित हो गया। हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने यह बतलाया था कि वृक्षों में भी जीव हैं और उन्हें भी सुप्त दुग्ध का अनुभव होता है। अपने सूक्ष्म यंत्रों द्वारा सर जगदीशचन्द्र बोस ने इसमें प्रत्यक्ष दिग्गल दिया। भारत के अन्य कई एक विद्वानों ने भी अपनी वैज्ञानिक योग्यता का परिचय दिया है। पाश्चात्य

१ इंग्लिश मोहनगल जेबरी, माइल स्टोन्मश्न गुजराती लिटरेचर, २ भाग।

विज्ञान की सहायता से देश को किस तरह सुसम्पन्न बनाया जाय, इस ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। गणित में अब भी भारत का नम्बर बड़ा हुआ है। साधारण शिक्षा होते हुए भी हाल ही में मदरास के स्वर्गीय श्री रामानुजम् ने अपनी विलक्षण बुद्धि से केम्ब्रिज के गणितज्ञों को चकित कर दिया था।

**उपसंहार**—भारत के भविष्य पर बहुत कुछ समार का भविष्य निर्भर है। यह सबसे बड़ा पराधीन देश है। ब्रिटिश साम्राज्य की तो यह 'धुरी' है। परन्तु अब यहाँ स्वतंत्रता की लहर उठ पड़ी है, जो दब नहीं सकती। ग्रेट ब्रिटेन को यह देखना चाहिए कि उसके राजनैतिक भविष्य पर असन्तुष्ट तथा दुखी भारत का क्या प्रभाव पड़ सकता है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि असन्तुष्ट भारत उसके शत्रुओं के लिए बराबर पटुयंत्र का क्षेत्र बना रहेगा। ऐसी परिस्थिति में उसे भारत में समझौता कर लेना ही ठीक है। स्वर्गीय लाला लाजपतराय के शब्दों में "विश्व की शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और महानुभूति, अँगरेज जाति का गौरव, मनुष्य-मात्र की उन्नति और संसार के आर्थिक मंगल के लिए यह परमावश्यक है कि भारत में शान्ति के साथ प्रजातन्त्र शासन की सस्थाओं का विकास हो।" अँगरेज लोग इस निश्चित बात को जितना ही गीघ्र समझ ले उतना ही अच्छा है।<sup>१</sup>

भारत के सामने राजनैतिक के अतिरिक्त एक और जटिल समस्या है। संस्कृति तथा सभ्यता की दृष्टि से उसके और यूरोप के आदर्श तथा सिद्धान्तों में बड़ा अन्तर है। यूरोप के साथ सम्बन्ध हो जाने से इन दिनों भारत के आचार-विचारों में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यह बात निश्चित है कि भारत अब पुरानी लकीर का फकीर नहीं रह सकती, अवस्था देखकर उसे अपनी व्यवस्था अवश्य बदलनी पड़ेगी। पर इसके साथ ही यूरोप की वर्तमान परिस्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महायुद्ध के बाद से वहाँ के कई एक विचार-शील विद्वानों को पाश्चात्य सभ्यता के सिद्धान्तों पर सन्देह होने लगा है और उनकी दृष्टि पूर्व की ओर फिर रही है। ऐसी दशा में भारत की आँखें क्या

<sup>१</sup> लाला लाजपतराय, दुखी भारत, पृ० ४४५।

यूरोप की अवस्था पर पहुँचकर खुलेगी या वह उसकी भूलों से शिक्षा प्राप्त करके संसार का पथप्रदर्शक बनेगा ? अपने उच्च सिद्धान्तों के रहते हुए भी आज भारत निर्धन, दुखी तथा पराधीन है और धन तथा वैभव से सम्पन्न शक्तिशाली यूरोप अपनी अवस्था से अमन्तुष्ट तथा भविष्य के लिए चिन्तित है। इसी से स्पष्ट है कि दोनों ने भूले की है और एक दूसरे के गुणों की दोनों को आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व तथा पश्चिम के परस्पर सहयोग में ही विश्व तथा मानवजाति का हित दिखलाई पड़ता है।

---

## संक्षिप्त विवरण

- सन् १४९८ वास्कोडगामा का आगमन ।
- ॥ १५०९ एलबुकर्क की नियुक्ति ।
- ॥ १५१० गोआ पर पुर्तगालियों का अधिकार ।
- ॥ १५१५ एलबुकर्क की मृत्यु ।
- ॥ १५८० स्पेन और पुर्तगाल की एकता ।
- ॥ १५८८ स्पेन के जहाजी वेडा 'आर्मडा' पर अंगरेजों की विजय ।
- ॥ १६०० पहली ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
- ॥ १६०२ डच ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
- ॥ १६०८ हाकिंस का जर्हागीर के दरवार में आगमन ।
- ॥ १६१२ सूरत में अंगरेजों की कोठी ।
- ॥ १६१५ सर टामस रो का आगमन ।
- ॥ १६२२ हरमुज पर अंगरेजों का अधिकार ।
- ॥ १६२३ अम्बोयना का हत्याकाण्ड ।
- ॥ १६४० मदरास की नींव ।
- ॥ १६६१ बम्बई की प्राप्ति ।
- ॥ १६६४ फ्रांसीसी कम्पनी ।
- ॥ १६७४ पाण्डुचेरी की नींव ।
- ॥ १६८५ ईस्ट इंडिया कम्पनी का आरंगजेब के साथ झगड़ा ।
- ॥ १६९० कलकत्ता की नींव ।
- ॥ १६९८ नई ईस्ट इंडिया कम्पनी ।
- ॥ १७०० दोनों कम्पनियों की एकता ।
- ॥ १७०८ संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी ।

- सन् १७२० हैदराली का जन्म ।
- , १७३० सादतअली खाँ अवध का सूबेदार ।
- , १७३५ ड्यूमा पाहुचेरी का गवर्नर ।
- , १७४१ अलीवर्दी खाँ बगाल का सूबेदार ।
- , १७४० डूप्ले पाहुचेरी का गवर्नर ।
- , १७४६ फ्रासीसियों के साथ अंगरेजों का पहला युद्ध, मदरास पर फ्रासीसियों का अधिकार ।
- , १७४८ पाहुचेरी के आक्रमण में अंगरेजों की असफलता, एलाशपल की सन्धि, निजाम आसफजाह की मृत्यु ।
- , १७४६ मदरास अंगरेजों को वापस, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु, अम्बर की लड़ाई में चान्दा साहब की विजय ।
- , १७५१ फ्रासीसियों के साथ अंगरेजों का दूसरा युद्ध, चान्दा साहब द्वारा त्रिचनापल्ली का घेरा, अर्काट पर क्लाइव का अधिकार और उनकी रक्षा ।
- , १७५२ त्रिचनापल्ली में फ्रासीसियों की हार, चान्दा साहब की मृत्यु ।
- , १७५४ डूप्ले की वापसी, शुजाउद्दौला अवध का नवाब ।
- , १७५५ घेरिया पर क्लाइव और वाट्सन का आक्रमण ।
- , १७५६ अलीवर्दी खाँ की मृत्यु, मिराजुद्दौला की नवाबी, कलकत्ता पर आक्रमण, कालकोठरी की दुर्घटना, फ्रासीसियों के साथ तीसरा युद्ध ।
- , १७५७ कलकत्ता में अंगरेजों की विजय, चम्पनगर पर अंगरेजों का अधिकार, पलासी का युद्ध, मिराजुद्दौला की मृत्यु, २४ परगना की प्राप्ति, मीरजाफर की पहली नवाबी ।
- , १७५८ लैली का आगमन, सेंट डेविड के क़िले पर अधिकार, मदरास के आक्रमण में असफलता, उत्तरी सरकार में कर्नल फ़ोर्ड की विजय ।
- , १७५६ त्रिदरा में उच्च लोगों की हार, अलीगौहर की बगाल पर चढ़ाई ।



- न् १७६० वाडवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों पर अंगरेजों की विजय, क्लाइव की वापसी, वैनसिगार्ट बगाल का गवर्नर, मीरकासिम की नवाबी ।
- , १७६१ पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठों की पराजय, पेशवा बालाजी की मृत्यु, माधवराव बल्लाल पेशवा, पाहुचेंरी पर अंगरेजी अधिकार, हैदरअली मैसूर का शासक ।
- , १७६३ मीरकासिम से झगडा, उदवानाला की लड़ाई में उसकी हार, पटना का हत्याकांड, मीरजाफर की दूसरी नवाबी, फ्रांसीसी युद्ध का अन्त, पेरिस की सन्धि, चन्द्रनगर तथा पाहुचेंरी फ्रांसीसियों को वापस ।
- , १७६४ बक्सर के युद्ध में अंगरेजों की विजय ।
- , १७६५ क्लाइव की दूसरी गवर्नरी, मीरजाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की सन्धि, दीवानी-प्रदान ।
- , १७६७ पहला मैसूर युद्ध, हैदर तथा निजाम की त्रिन्नोमली में हार, क्लाइव की वापसी, वेरेल्स्ट बगाल का गवर्नर ।
- , १७६८ नेपाल में गोरखों का राज्य ।
- , १७६९ कार्टियर की गवर्नरी, हैदर के साथ मदराम की सन्धि ।
- , १७७० बगाल तथा बिहार में दुर्भिक्ष ।
- , १७७२ हेस्टिंग्स बगाल का गवर्नर, पेशवा माधवराव की मृत्यु, नारायणराव पेशवा ।
- , १७७३ रेग्यूलेंटिंग ऐक्ट ।
- , १७७४ रहेला-युद्ध, हेस्टिंग्स बगाल का गवर्नर-जनरल ।
- , १७७५ राघोबा के साथ सूरत की सन्धि, पहले मराठा युद्ध का आरम्भ, महाराजा नन्दकुमार को फांसी, शुजाउद्दौला की मृत्यु, आसफुद्दौला अवध का नवाब ।
- , १७७६ पेशवा के साथ पुनर्धर की सन्धि, कर्नल मानसन की मृत्यु ।
- , १७७८ फ्रांसीसियों के साथ युद्ध ।

- सन् १७७६ मराठों के साथ वडगाव का समझौता ।
- „ १७८० फ्रांसिस की वापसी, ग्वालियर पर अंगरेजों का अधिकार, दूसरा मैसूर युद्ध, कर्नाटक पर हैदर का आक्रमण, कर्नल बेली की दुर्दशा, रणजीतसिंह का जन्म ।
- „ १७८१ पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर की हार, बनारस के राजा चेतसिंह का झगडा ।
- „ १७८२ अवध की बेगमों की लूट, मराठों के साथ सालवाड़े की सन्धि, कर्नल ब्रेथवेट पर टीपू की विजय, हैदर की मृत्यु ।
- „ १७८३ फ्रांसीसियों के साथ सन्धि ।
- „ १७८४ माहादजी सिन्धिया का प्रभुत्व, टीपू के साथ मंगलोर की सन्धि, पिट का इंडिया ऐक्ट ।
- „ १७८५ हेस्टिंग्स का इस्तीफा ।
- „ १७८६ लार्ड कार्नवालिस गवर्नर-जनरल ।
- „ १७८८ गुलामकादिर की निष्ठुरता ।
- „ १७९० तीसरा मैसूर युद्ध, मराठा और राजपूतों के बीच पाटन की लड़ाई ।
- „ १७९१ मराठों के साथ मिरथा की लड़ाई में राजपूतों की हार ।
- „ १७९२ टीपू के साथ श्रीरंगपट्टन की सन्धि ।
- „ १७९३ फ्रांस की राज्यक्रान्ति का आरम्भ, बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त, कम्पनी का नया आजापत्र ।
- „ १७९४ माहादजी सिन्धिया की मृत्यु ।
- „ १७९५ सर जान शोर गवर्नर-जनरल, खर्दा की लड़ाई में निजाम पर मराठों की विजय, सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु, बनारस में इस्तमरारी बन्दोबस्त, अहिल्याबाई की मृत्यु ।
- „ १७९६ दूसरा बाजीराव पेशवा ।
- „ १७९८ मादतअली खाँ अवध का नवाब, सर जान शोर की वापसी, लार्ड वेलेजली गवर्नर-जनरल, निजाम के साथ सन्धि ।

- सन् १७६६ चौधा मैसूर युद्ध, टीपू की मृत्यु, तजोर और सूरत का अ-  
हरण, रणजीतसिंह लाहौर का राजा ।
- , १८०० नाना फडनवीस की मृत्यु, हेदराबाद की सहायक सन्धि ।
- , १८०१ कर्नाटक का अपहरण, अवध के साथ ज्यादाती, लखनऊ  
की सन्धि ।
- , १८०२ फ्रांसीसियों के साथ अमीन्स की सन्धि, पूना पर होलकर का  
अधिकार बाजीराव के साथ वेसीन की सन्धि ।
- , १८०३ दूसरा मराठा युद्ध, अलीगढ़, दिल्ली, असेई, लासवाडी, अरगाव  
की लडाइयाँ, भोसला के साथ देवगाव की सन्धि, मिन्धिया के  
साथ अर्जुनगाव की सन्धि ।
- , १८०४ होलकर के साथ युद्ध, मानसन की हार, ढींग की लडाईं ।
- , १८०५ भरतपुर के आक्रमण में असफलता, वेलेजली की वापसी, लार्ड  
कार्नवालिस दूसरी बार गवर्नर-जनरल, लार्ड कार्नवालिस की  
मृत्यु, सर जार्ज वालों गवर्नर-जनरल, मराठों के साथ सन्धियाँ ।
- , १८०६ विल्लोर का उपद्रव ।
- , १८०७ लार्ड मिंटो गवर्नर-जनरल ।
- , १८०८ फारम और काबुल के साथ सम्यन्ध ।
- , १८०९ रणजीतसिंह के साथ अमृतसर की सन्धि, मदरास में सैनिक  
उपद्रव ।
- , १८१० फ्रांसीसी द्वीपों पर अधिकार ।
- , १८११ जावा की विजय ।
- , १८१३ कम्पनी का आज्ञापत्र, लार्ड हेस्टिग्स गवर्नर-जनरल ।
- , १८१४ नेपाल-युद्ध, अवध के नवाब सादतअली की मृत्यु ।
- , १८१६ मिगाली की सन्धि ।
- , १८१७ पि डारी और मराठा युद्ध, खट्की, सीतावलडी, नागपुर और  
महीदपुर की लडाइयों में अंगरेजों की विजय ।
- , १८१८ कोरेगाव और आष्टी की लडाइयाँ, पेशवाई का अन्त ।

- सन् १८१६ गाजीपट्टीन अचध का पहला वादशाह ।
- ,, १८२० सर टामस मानरो मद्रास का गवर्नर ।
- ,, १८२३ लार्ड हेस्टिंग्स की वापसी, लार्ड एम्हर्स्ट गवर्नर-जनरल ।
- ,, १८२४ पहला बर्मी युद्ध, वारिकपुर का विद्रोह ।
- ,, १८२६ भरतपुर किले का पतन, बर्मियों के साथ याडवू की सन्धि ।
- ,, १८२७ दौलतराज सिन्धिया की मृत्यु ।
- ,, १८२८ एम्हर्स्ट का इस्तीफा, लार्ड विलियम बेटि क गवर्नर-जनरल ।
- ,, १८२९ सती-प्रथा का अन्त, ठगी का दमन, ब्रह्मसमाज की स्थापना ।
- ,, १८३० कचार की जन्ती ।
- ,, १८३१ मैसूर का राजा पदच्युत, रणजीतसिंह के साथ रूपुर में भेंट ।
- ,, १८३३ कम्पनी का आज्ञापत्र ।
- ,, १८३४ कुर्ग का अपहरण ।
- ,, १८३५ अंगरेजी शिक्षा का निर्णय, बेंटिंक की वापसी, दोस्तमुहम्मद काबुल का अमीर ।
- ,, १८३६ लार्ड आक्लैंड गवर्नर-जनरल ।
- ,, १८३७ रानी विक्टोरिया को गद्दी, बर्न्स की काबुलयात्रा, उत्तरी भारत का अकाल ।
- ,, १८३८ रणजीतसिंह तथा शाहशुजा के साथ सन्धि, अफगान-युद्ध की घोषणा ।
- ,, १८३९ रणजीतसिंह की मृत्यु, गजनी की विजय, काबुल पर अधिकार ।
- ,, १८४० अफगानियों का विद्रोह ।
- ,, १८४१ बर्न्स और मैकनाटन का वध ।
- ,, १८४२ अफ़्ग़रख़ा के साथ सन्धि, अंगरेजी सेना की हुंदाशा, आक्लैंड की वापसी, लार्ड एलिनबरा गवर्नर-जनरल, जलालाबाद की रक्षा, काबुल की विजय ।
- ,, १८४३ मियानी की लड़ाई, गिन्ना का अपहरण, महाराजपुर और पनियर की लड़ाई में सिन्धिया की हार ।

- मन् १८४४ लार्ड एलिनबरा की वापसी, हेनरी हार्डिंज गवर्नर-जनरल ।
- , १८४५ पहला सिख युद्ध, मुदकी और फीरोजशहर की लडाइयाँ ।
- , १८४६ अलीवाल और सोवरांव की लडाइया, अंगरेजों की विजय, लाहौर की सन्धिया ।
- , १८४८ हार्डिंज की वापसी, लार्ड डलहौजी गवर्नर-जनरल, मूलराज का विद्रोह, दूसरा सिख युद्ध, मतारा के राजाओं का अन्त ।
- , १८४९ चिलियानवाला और गुजरात की लडाइयाँ, पंजाब का अपहरण ।
- , १८५२ दूसरा बर्मी युद्ध, पीगू पर अधिकार ।
- , १८५३ भारत में पहली रेल, कम्पनी का अन्तिम आज्ञापत्र ।
- , १८५६ अवध का अपहरण, डलहौजी की वापसी, लार्ड कैनिंग गवर्नर-जनरल ।
- , १८५७ निपाही-विद्रोह, मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ तथा झांसी में उपद्रव ।
- , १८५८ विद्रोह की शान्ति, कम्पनी का अन्त, विक्टोरिया का घोषणा-पत्र, लार्ड कैनिंग पहला वाइसराय ।
- , १८५९ तात्या टोपे को फाँसी ।
- , १८६१ हार्डिंजों की स्थापना, डियन कांसिल ऐक्ट ।
- , १८६२ लार्ड एलगिन वाइसराय, अन्तिम मुगल बादशाह बहादुरशाह की मृत्यु ।
- , १८६३ अमीर दोस्तमुहम्मद की मृत्यु ।
- , १८६४ सर जान लारेंस वाइसराय ।
- , १८६८ गेरशली काबुल का अमीर ।
- , १८६९ लार्ड मेयो वाइसराय, अम्बाला में गेरशली के साथ भेंट, ड्यूक आफ एडिनबरा का आगमन ।
- , १८७२ लार्ड मेयो का वध, लार्ड नार्थब्रुक वाइसराय ।
- , १८७५ मल्हारराव गायकवाड पदच्युत, आर्य्यमाज की स्थापना, युवराज ( प्रिंस ऑफ वेल्स ) एडवर्ड की यात्रा ।

- मन् १८७६ लार्ड लिटन वाइसराय, इंग्लैंड के गामको को 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि, दक्षिण में दुर्भिक्ष ।
- ,, १८७७ दिल्ली का दरबार ।
- ,, १८७८ वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट, दूसरे अफगान-युद्ध का आरम्भ ।
- ,, १८८० लार्ड लिटन का इस्तीफा, लार्ड रिपन वाइसराय ।
- ,, १८८१ मैसूर की वापसी, पहली मनुष्य-गणना ।
- ,, १८८२ वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट रह ।
- ,, १८८४ लार्ड डफरिन वाइसराय ।
- ,, १८८५ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, पजदेह की घटना, तीसरा यमी युद्ध ।
- ,, १८८६ बर्मा के राज्य का अन्त ।
- ,, १८८८ लार्ड लैसडौन वाइसराय ।
- ,, १८९१ मनीपुर का उपद्रव ।
- ,, १८९२ दूसरा इंडियन कैसिल ऐक्ट ।
- ,, १८९४ दूसरा लार्ड एलगिन वाइसराय ।
- ,, १८९५ चित्तूराल पर धावा ।
- ,, १८९६ प्लेग और अकाल ।
- ,, १८९७ तीराह पर आक्रमण ।
- ,, १८९९ लार्ड कर्जन वाइसराय ।
- ,, १९०१ ब्रिटिश की मृत्यु, सातवां एडवर्ड सम्राट्, हवीकुल्ला अफगानिस्तान का अमीर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ।
- ,, १९०२ तिब्बत पर धावा, दिल्ली में दरबार ।
- ,, १९०४ यूनिवर्सिटीज ऐक्ट ।
- ,, १९०५ बंग-विच्छेद, स्वदेशी आन्दोलन, दूसरा लार्ड मि टो वाइसराय ।
- ,, १९०६ मुसलिम लीग ।
- ,, १९०७ कांग्रेस में फूट ।
- ,, १९०८ प्रान्तिकारी दल, बम से हत्याएँ ।

- मन् १६०६ मार्ले-मिंटो सुधार ।
- „ १६१० दूसरा लार्ड हार्डिज वाइसराय ।
- „ १६११ सम्राट् पंचिवे जार्ज का दिल्ली में राज्याभिषेक, बग-विच्छेद रद्द ।
- „ १६१२ बिहार और उड़ीसा का नया प्रान्त ।
- „ १६१३ दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह ।
- „ १६१४ यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ ।
- „ १६१६ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना, लार्ड चेम्सफर्ड वाइसराय, कांग्रेस में एका, हिन्दू-मुसलमानों का निर्वाचन-सम्बन्धी समझौता ।
- „ १६१७ बगडाद विजय, मेसोपोटामिया कमीशन, पार्लामेंट में भारत-मन्त्रि की विज्ञप्ति ।
- „ १६१८ माटेयू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट, रौलट कमेटी रिपोर्ट, रौलट-ऐक्ट, महायुद्ध का अन्त ।
- „ १६१९ रौलट-ऐक्ट सत्याग्रह, जलियानवाला बाग का हत्याकाण्ड, हंटर कमेटी की नियुक्ति, सुधार-कानून, अमानुल्ला अफगानिस्तान का वादशाह, तीसरा अफगान-युद्ध ।
- „ १६२० खिलाफत का झगडा, लोकमान्य तिलक की मृत्यु, अमहयोग आन्दोलन का आरम्भ, लिवरल केंडरेसन ।
- „ १६२१ लार्ड रीडिंग वाइसराय, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, मोपला विद्रोह, चौरीचौरा की दुर्घटना, बारडोली-निर्णय, मविनय-श्रवज्ञा स्थगित, अकाली आन्दोलन, अमानुल्ला के साथ सन्धि ।
- „ १६२२ माटेयू का इस्तीफा, महात्मा गान्धी को जेल, म्वराज्य दल ।
- „ १६२४ खिलाफत का अन्त, हिन्दू-मुसलमानों में झगडा, कटारपुर और कोहाट की दुर्घटनाएँ, दिल्ली में एकता सम्मेलन ।
- „ १६२६ लार्ड अरविन वाइसराय, कृषि कमीशन ।
- „ १६२७ साइमन कमीशन की नियुक्ति ।

- सन् १९२८ नेहरू कमेटी रिपोर्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार, लाला लाजपतगय की मृत्यु, कलकत्ता में सर्वदल सम्मेलन, ।  
 ,, १९२९ औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में लार्ड अरविन की विज्ञप्ति, बाल-विवाह-निषेध कानून, पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का ध्येय ।

### बंगाल के गवर्नर-जनरल

- ,, १७७४ वारेन हेस्टिंग्स ।  
 ,, १७८५ सर जान मैकफर्मन ।  
 ,, १७८६ लार्ड कार्नवालिस ।  
 ,, १७९३ सर जान शोर ।  
 ,, १७९८ सर अल्बर्ट क्लार्क \* ।  
 ,, १७९७ लार्ड वेलेजली ।  
 ,, १८०५ लार्ड कार्नवालिस दूसरी बार, सर जार्ज बार्लो , पहला लार्ड मि टो ।  
 ,, १८१३ लार्ड हेस्टिंग्स ।  
 ,, १८२३ जान ऐडम , लार्ड एमहर्स्ट ।  
 ,, १८२८ बटरवर्थ वेली, लार्ड विलियम बटिक ।

### भारत के गवर्नर-जनरल

- ,, १८३३ लार्ड विलियम बेंटिक ।  
 ,, १८३५ सर चार्ल्स मेटकाफ ।  
 ,, १८३६ लार्ड आकले ड ।  
 ,, १८४० लार्ड एलिनबरा ।  
 ,, १८४४ लार्ड हार्डिज ।



- मन् १८४८ लाड डलहौजी ।  
 ,, १८५६ लार्ड कैनिंग ।

### गवर्नर-जनरल तथा वाइसराय

- ,, १८५८ लार्ड कैनिंग ।  
 ,, १८६२ पहला लार्ड एलगिन ।  
 ,, १८६३ मर राबर्ट नेपियर , मर विलियम डेनिमन\* ।  
 ,, १८६४ सर जान लॉरेन्स ।  
 ,, १८६६ लार्ड मेयो ।  
 ,, १८७२ सर जान स्ट्रैची , लार्ड नेपियर , लार्ड नार्थब्रुक ।  
 ,, १८७६ लार्ड लिटन ।  
 ,, १८८० लार्ड रिपन ।  
 ,, १८८४ लार्ड डफ्रिन ।  
 ,, १८८८ लार्ड लैंसडौन ।  
 ,, १८९४ दूसरा लार्ड एलगिन ।  
 ,, १८९६ लार्ड कर्जन ।  
 ,, १९०४ लार्ड एमथिल , लार्ड कर्जन दूसरी बार ।  
 ,, १९०५ दूसरा लार्ड मिंटो ।  
 ,, १९१० दूसरा लार्ड हार्डिज ।  
 ,, १९१६ लार्ड चेम्सफर्ड ।  
 ,, १९२१ लार्ड रीटिंग ।  
 (छुट्टी के अवसर पर बंगाल का गवर्नर लार्ड लिटन स्थानापन्न)  
 ,, १९२६ लार्ड थरविन ।  
 (छुट्टी के अवसर पर मडराम का गवर्नर लार्ड गोशेन स्थानापन्न)



इ

इटली, ४१६, ४५६, ४६१, ४८२।

इचकेप डमेटी ४६६।

इचकेप, लार्ड, ४६८।

इचवर्ड, कप्तान, ७७।

इडियन कॉमिल ऐक्ट, (सन् १८६१)

३८३ (सन् १८६२) ४२८, ४३४।

इडिया कॉमिल, ३७७, ३८५, ४१२,

४२८, ४५२, ४६५।

इडो-चैना, ४१८।

इशाउल्लान्वा, ५२०, ५२४।

इन्डो १५०, २०३, २८०, ३३४,  
३६४, ५०५।

इनाम कमीशन, २५०, ३५७।

इनिंग, जनरल, ३७६।

इन्सुअर, वहाबी सुलतान, ४८७।

इम्पी, सर एलाइजा, जज, ६८,  
१०१, १०२, १०३।

इम्पीरियल सर्विस ट्रस्ट, ४१६।

इमामगट, ३०७।

इलवर्ट विल, ४११, ४१२, ४२२।

इलाहाबाद, ४६, ५७, ६७, ६८, ६९,  
६३, ११२, १३६, १४६, १६८, २००,

२४२, २७२, २७५, २७६, ३२६,

३५१, ३६०, ३६४, ३६५, ३६६, ३७३,

३७६, ४३८, ४८६, ५००, ५०५।

इलाहीबन्ग, २२८।

इममरारी बन्दोबस्त, ११७, १३०,

१३१, १३३, १४०, १४५, ४०८,

४०६, ४३४।

इस्मार्शल वेग, १४१।

ई

ई० आई० आर०, ३५१, ४६८।

ईंग्रीज की लडाई, ४६०।

उ

उजनाला का कुँआ, ३६०, ३७३।

उज्जेन, १८८।

उड़ीसा, १६८, २५४, ४४३, ४५५।

उटीसा का अकाल, ३८७, ३८८।

उदयपुर, १४१, २२२, २३१।

उदयपुरी, गोमाट १६८।

उदयराम, रणद्योड भाई, ५०६।

उदवानाला की लडाई, ५४।

उमदतुलउमरा, कर्नाटक का नवाब,  
१४७, १६८।

उरसुज का बन्दरगाह, ५, ६, ११।

उम्मानिया यूनिवर्सिटी, ५२५।

ऊ

ऊर्म, ३०, ३६, ४४, ८४।

ए

एक्जीक्यूटिव कॉमिल, ३८३, ४५२।

एकता सम्मेलन, दिल्ली, ४८८।

एडवर्ड, युवराज, ३६५, मन्नाट्, ४३६,

४५०, ४५२, ४५४।

पडवर्ड्स, इतिहासकार, ३४८ ।

पुन्थिल, लार्ड, ४४४ ।

पुम्हर्स्ट, लार्ड, गवर्नर-जनरल, २६३,  
२६४, २६७, २७०, २७२, २७३ ।

पुलगिन, लार्ड, बाइसराय, ३८४,  
३८५ ।

पुलगिन, (दूसरा) लार्ड, बाइसराय,  
४०६, ४३१ ।

पुलफिस्टन, २३०, २४४, २५४, २५६,  
२५७ ।

पुलवुकर्क, ४, ५, ६, ७ ।

पुलाश्वल की सन्धि, २४ ।

पुलिचपूर, १६४ ।

पुलिजवेथ, इंग्लैंड की रानी, ६, १० ।

पुलिनवरा, लार्ड, गवर्नर-जनरल,  
३०४, ३०५, ३०६, ३०६, ३१०,  
३११ ।

पुलिम, ५३, ५४ ।

पुलेनवी, जनरल, ४६१ ।

पुशर, लार्ड, २६४ ।

पुशियाटिक सोमायटी, ११८ ।

## रे

रेडम, २८७ ।

रेडम, जान, २६३, २६२, २६३ ।

रेटनी, पुर्तगाली कविवाला, ५०६ ।

रेडरमन, १४१ ।

रेस्ट, कप्तान, ३०४ ।

## श्री

श्रीडायर, सर माइकेल, ४७१, ४७३ ।

श्रीयन, मिडनी, १८५, २१३ ।

## श्री

श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की विज्ञप्ति,  
५०६, ५१० ।

श्रीरगजेव, मुगल सम्राट्, १०, १३,  
१६, ३७, ८३, २३७, २७७, ४४६ ।

श्रीरंगाबाद, २०३, ५२५ ।

श्रीसले, विलियम, ५१८ ।

## श्री

श्रीडमन द्वीप, ३६३ ।

## क

कचार, २६५, २६८, २८३, ४०७ ।

कजिंस, डाक्टर जेम्स, ५१४ ।

कटक, १६२, १६८ ।

कडा, ६१, ६८ ।

कन्दहार, २८३, २६८, ३००, ३०४,  
४०३, ४०५ ।

कनाडा ( कैनाडा ), ४१५, ४४७,  
४८३, ४६२ ।

कनाडा, १६०, १६६ ।

कनानूर, ४ ।

कनाट, ल्यूक थाफ, ४७० ।

कनिंघम, इतिहासकार, ३१७ ।

कपूरमिह, चित्रकार, ५१७ ।

कवीर, ८३ ।

कम्बरमियर, सेनापति, २७१ ।

कमाज २३५, २३६ ।

कर्केपेट्टिक, १५६, १५७, २३४, २३५ ।

कर्जन लार्डे, चाङ्गमराय ४३२ ४३३,

४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४४०, ४४१,

४४२, ४४३, ४४४ ४४६, ४४७,

४४६ ४५५ ४५६, ४६३, ५१४ ।

कर्णधेलो, ५०६ ।

कर्नाटक, २१, २५, २६, २७, ३०,

७६, ८०, ८३, ११४, १३५, १३६,

१३८, १४७, १६८, १६९ ।

कर्नूल, २६६ ।

करमग्रली, ५०६ ।

कराची, २७५ ।

करी, लाहोर का रेजीडेंट, ३२३ ।

करीमगवा, २३८, २३९ ।

करौली, ३३८ ।

कलकत्ता, ११, १२, १३, १४, १५,

३८, ४०, ४१, ४३, ४४, ४६, ५१,

५३, ५४, ५६, ६०, ८६, ६१, ६७,

११८, १२५, १२८, १३४, १५०,

१५६, १५८, १६१, १७३, २००,

२११, २१६, २१७, २२५, २३०,

२३३, २६६, २६७, २७५, ३३२,

३३६, ३४२, ३५१, ३५२, ३६०,

३६१, ३८४, ३८६, ४०७, ४११,

४१२, ४२३, ४४३, ४५०, ४५५,

४५६, ४६८, ४७४, ४८६, ५०४,

५१०, ५१२, ५१३, ५१४, ५२०,

५२१, ५२५ ।

कलकत्ता का मरफारी भवन, २१६,

२१७

कलकत्ता जरनल, २६३ ।

कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ४६६ ।

कबुलु, वेस्टेश्वर, ५३० ।

कागडा, २८४, ३२०, ५१७ ।

कागडी, गुरुकुल, ४८६ ।

काग्रैस, इंडियन नेशनल, ४०२, ४०३,

४२४, ४२८, ४२९, ४३१, ४३४,

४३७, ४३६, ४४१, ४४३, ४४५,

४४८, ४४९, ४५२, ४५३, ४५७,

४६२, ४७०, ४७३, ४७४, ४७५,

४७६, ४७८, ४८५, ४८७, ४८८,

५०३, ५०४, ५१०, ५११ ।

काटन, सर हेनरी, ४२२ ।

कानपुर, १६६, ३६४, ३६५, ३७२,

३७३, ५०७ ।

काव्डन, ३३१ ।

काबुल, २२२, २३०, २८४, २९७,

२६८, २६९, ३०३, ३०४, ३०५,

३०८, ३०९, ३५०, ४००, ४०१,

४०२, ४०३, ४०५, ४८१ ।

कार्टियर, ८७ ।

कालीकट, ३, ४, ६, १७, २०, ३६, ७३ ।

कालपी, १६७, ३७१।

काला समुद्र, १।

कालिवन, मर, ४१८।

क्लाइड, लार्ड, सेनापति, ३६८।

क्लाइव, लार्ड, १८, २७, २८, २९,

३०, ३१, ३४, ४४, ४५, ४७, ४८,

४९, ५०, ५१, ५८, ५९, ६०, ६१,

६२, ६३, ६४, ६५, ६७, ७८, ८०,

८८, ८९, ९०, १०६, १६८, २८६,

३५५।

क्लाइव, लार्ड, मद्रास का गवर्नर,

१८८, १६६।

क्लार्क, गोलार्ड, १६१, १८७।

क्लार्क, मर जार्ज, बम्बई का गवर्नर,

३३३, ३३६।

क्लार्क, मेजर, ६०।

क्लार्कवालिम, लार्ड, गवर्नर-जनरल,

१२५, १२६, १२७, १२८, १२९,

१३०, १३१, ३२, १३४, १३५,

१३६, १३७, १३८, १३९, १४०,

१४१, १४२, १४५, १४६, १४७,

१४०, १५३, १६८, १७४, १८३,

२११, २१८, २१९, २२०, २२१,

२३२, २३३, २३४, २६३, ४१६।

क्लार्क, २०।

क्लार्कस्ट्री, कनकता, ४२, ३६२।

क्लार्क कानून, २६४।

कालिम, १८८, १८९, १९३।

काश्मीर, २८४, ३००, ४००, ४०४,

४०६, ४१८, ४२५, ४२७, ५००।

काशी नागरीप्रचारिणी मभा, ५०३।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ४५८,

४५९।

काशीराव, १६०, २०४।

कास्पियन समुद्र, १।

कासिमगजार, १३, २०, ४०, ४१,

४५, ८८।

किचनर, लार्ड, प्रधान सेनापति,

४४३, ४४४, ४५४, ४६०।

किमिया, ३६०।

किश्चियन पुराण, ६।

किलोस्कर, अण्णा, ५२८।

किरकी (खडकी), २४५।

किरवी की जागीर, ३७०।

किंकेड, इतिहासकार, २५७।

किलात, ३५०, ४००।

की, रेवरेंड, २८८।

कीनिया, ४६२।

कुमारी, गन्तरीप, ३३१।

कुर्ग, १३७, २८०, २८१।

कुर्ग की घाटी, ४०२।

कुलावा, ७७।

कुँवरसिंह, ३६६।

कुम्भुनतुनिया, १५५।

- कूट, पटना की कोठी का अध्यक्ष, ५३ । कैबेरनरी, ४०२ ।  
 कूट सर आयर, ३५, ११४, ११७ । केमरवाग की लूट, ३६८ ।  
 कूपर, डिप्युटी कमिश्नर । फंसलरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष,  
 ३६०, ३७३ । १८४, १११ ।  
 कृष्ण, ५२४ । कोचीन, ४, १३६, ५१६ ।  
 कृष्णचन्द्र, तवद्वीप का राजा, ५२६ । कोटा, २२२ ।  
 कृष्णराज, मंसूर का राजा, ५१७ । कोयम्बटूर, १६६ ।  
 कृष्णदाम, ४०, ४१ । कोयल, १६६, २०० ।  
 कृष्णाकुमारी २३१ । कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स, १४, ११६ ।  
 कृषि कमीशन, ४६७ । कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, १४, ११६ ।  
 कृषि विभाग, ४४० । फोरिया, ४३३ ।  
 के, ( काये ) सर जान, २३६, २४० । कोलब्रुक, १२३, १८७ ।  
 ३३७, ३७२ । क्लोज, मेजर, १८६, ३०८ ।  
 केब्राल, ४, ६ । कोलमरम, २ ।  
 केवो, जान, २ । कोल्हापुर, ३७५ ।  
 केस्विज, ५३१ । कोलावा, ३३३ ।  
 कलेवरिंग, ६८, ६६ । कोमीजुरा का जमीन्दार, १०२ ।  
 कवेटा, ४०० । कोहनूर हीरा, २८२, ३०६, ३२७ ।  
 कोणवसुत, ५२८ । कोहाट, ४८८ ।  
 केमरी, ममाचारपत्र, ४३१, ४५० । कौमिल आफ स्टेट ( राज्य-परिषद ),  
 कनिग, लार्ड, गवर्नर-जनरल, ३५६, २६६, २६७ ।  
 ३६७ ३६८, ३७६, वाट्सराय, ३७६, ख  
 ३८२, ३८४, ३८६ ३६५, ४२० । गडगमि ह, ३१५ ।  
 केनिंग कालेज, लग्नतड, ३८२ । गर्दा की लट्टाई, १२७, १५२, १५६,  
 वेम्पवेल, सर आर्चीबोल्ड, २६७, २८८, १७८ ।  
 ३६८, ३७३ । खरे, वासुदेव शास्त्री, ५२८ ।  
 १) केंरी, पादरी २८८, ५०६ । खाडिलकर, कृष्णाजी प्रभाकर, ५०८ ।

खाडेराव, ७०, ७३ ।  
 खानदेश, १६३ ।  
 खिलाफत, ४७४, ४८७ ।  
 खबर घाटी, २८४, ४०२ ।  
 खैरपुर, ३०६ ।  
 खैरीगढ़, २५३ ।

## ग

गडकरी, राम गणेश, ५०८ ।  
 गजनी, ३००, ३०४, ३०५ ।  
 गजनवी, महमूद, ३०५ ।  
 गढ़वाल, २३६, ५१७ ।  
 गदर पार्टी, ४६३ ।  
 गफ, लार्ड, सेनापति, ३२५ ।  
 गट्टिस, मार्टिन, ३६४ ।  
 ग्वालियर १०६, १६७, २०२, २१८,  
 २२१, ३०८, ३०६, ३७०, ३७१,  
 ३६४, ४१८ ।  
 गाजीउद्दीन, पिंडारी, २३७ ।  
 गाजीउद्दीन हैदर, अवध का बादशाह,  
 २५२, २५३, २५४, ३४६ ।  
 गाजीपुर २१६, २२० ।  
 गान्धी, मोहनदास परमचन्द(महात्मा),  
 ४५७, ४५८, ४७१, ४७२, ४७४,  
 ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०,  
 ४८२, ४८५, ४८६, ४८८, ४८९,  
 ४९०, ४९३ ।

गायकवाड, ७६, १४७, १६६, ३०१,  
 ( मल्हारराव ) ३६४ ।  
 गार्डन, कप्तान, ७७ ।  
 गालिय, ५०४ ।  
 गाविलगढ, १६५ ।  
 ग्रिविल, इतिहासकार, १६६ ।  
 गिरधरभाई, रणछोडदास, ५०६ ।  
 गिलक्राइस्ट, डाक्टर, ५०१, ५०५ ।  
 गिलगिट, ४२५, ४७७ ।  
 गीता-रहस्य, ५०८ ।  
 ग्रीथेड, कमिश्नर, ३७४ ।  
 गुजरात, ७६, १०६, १५५, १६६,  
 २०१, २०६, ४३४ ।  
 गुजरात की लडाई, ३२४, ३२५ ।  
 गुजरात बर्नाकुलर सोसायटी, ५२६ ।  
 गुडहोप, अन्तरीप, ३, १०५, २३१ ।  
 गुप्त कमेटी, ११६, १५८, २७१ ।  
 गुरु का वाग, ४८३ ।  
 गुरुदास, ६० ।  
 गुलबर्गा, ४८८ ।  
 गुलाबसिंह, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७,  
 ३१८, ३१९, ३२०, ४२५, ४२६ ।  
 गुलामकादिर, १४०, २०० ।  
 गुलामनवी, ५२२ ।  
 गुलामहुसेन, ३७, ७१ ।  
 ग्लेडस्टन, हंग्लैंड का प्रधान मन्त्रि,  
 ४०२, ४०३, ४०६, ४१३ ।



गोआ, ४, ८, ९ ।

गोमले, गोपाल कृष्ण ४४५, ४८९ ।

गोखले, बापू २४५ ।

गोड्डार्ड जनरल, १०६ ।

गोरखपुर, २३५ २३६, २६०, २६१,  
४७८ ।

गोविन्द ५०८ ।

गोविन्दगढ़, ३५६ ।

गोविन्दराव कालपी का सूबेदार,  
१६७ ।

गोविन्द, पट्काल ५१६ ।

गोविन्दमिह, ३१७ ।

गोहद, १६०, २१८, २२१ ।

गंगा नदी १६१, २६५, ३६४ ।

गंगा की नहर, ३५३ ।

गंगाधरराव, ३७० ।

गंगाधर शास्त्री, २८४ ।

गट्टर, ८०, ११३, ११८, १०२,  
१३५ ।

गडमक की मन्धि, ४०२ ।

## घ

घासीराम, वातवाल २५१ ।

घेरिया की लटाई, ५४ ।

घाष लालमोहन, ४३६ ।

## च

चटर्गाव, ५० २६५, ४४० ।

चटोपाध्याय, रविमचन्द्र, ५०७ ।

चन्दूलाल, २२४, २८१ ।

चन्द्रगिरि का राजा, ११ ।

चन्द्रनगर, १५, २०, २१, ३४, ३६,  
३८, ४४, ४५, २७८, ५०६ ।

चम्बल, नदी, २०६, २२२, २०३,  
३७५ ।

चर्खा संघ, ४८६ ।

चाइल्ड, जोशिया, १० ।

चान्दकुंवरि, ३१५ ।

चान्दासाहब, २५, २६, २७, २८,  
२९, ३० ।

चार्नक, जाब, १२ ।

चार्ल्स दूसरा, ईंग्लैंड का राजा, १२,  
१४ ।

चितराल, ४२४, ४२५, ४२६, ४३० ।

चिदम्बरम्, ५०० ।

चिनसुरा, ८, ३८, ४६, २७८ ।

चिन्नयमूरि, ५३० ।

चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री, ५२८ ।

चिलियानवाला, की लटाई, ३०४,  
३०५ ।

चीतू, २३८, २३९ ।

चीन, ५, २३८, २६३, २७५, २८६,  
३८५, ४३०, ४३६ ।

चुनारगढ़, ५७, ३०८ ।

चुगी की लाइन, ३६८ ।

चेट्टि, अन्नामलै, राजा, ५०० ।

चेतमिह, बनारस का राजा, १०७, १०८, १०९, ११०, ११२, १२०, १२४ ।	जमुना, नदी, १६१, २१८, २२८, ३७४ ।
चेम्बरलेन, ४०१, ४०२ ।	जम्मू, ३१४, ३१५, ३१८ ३२०, ४२६ ।
चेम्सफर्ट, लार्ड, वाइसराय, ४६१, ४६२, ४६४, ४६५, ४७३ ।	जमोरिन, कालीकट का राजा, ३, ४ ।
चैतू, चित्रकार, ५१७ ।	जयन्तिया, २६८, २८३ ।
चैम्पियन, कर्नल, ६४ ।	जयपुर, ७१, १४१, २०१, २०४, २०७, २३१, ३६४, ५१५, ५१६ ।
चौधरी, बटरीनारायण, ५२२ ।	जयाजीराव, सिन्धिया, ३७० ।
चौवीस परगना की जमीन्दारी, ४६ ।	जर्मनी, ४१६, ४३५, ४५६, ४६०, ४६१, ५१६ ।
चौरीचौरा, ४७७, ४७८ ।	जलालाबाद, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ४८१ ।

## छ

छत्रमजिल, ३६६ ।
छत्रमिह, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६ ।

## ज

जकात, २४८ ।	जससिंह, सरदार, ७० ।
जगत मेट, २४, ४६ ।	जर्हागीर, मुगल सम्राट्, १०, ११ ।
जगदीशपुर, ३६६, ३७० ।	जर्हानारा, ११ ।
जगन्नाथजी का मन्दिर, १६८ ।	जापान, ५, ४४६, ४६१, ४६६ ।
जकोजी, सिन्धिया, ३०६ ।	जानोजी, भोसला, १६, ३३७ ।
जनकोजी, सिन्धिया, ७६ ।	जार्ज पांचवा, सम्राट्, ४५४, ४५५ ।
जन्मलपुर, २७७ ।	जार्ज, लायड, इंग्लैंड का प्रधान सचिव, ४८० ।
जमरूद, २८४, ४६३ ।	जाधरा की जागीर, २४३ ।
जमशेदपुर, ४६७ ।	जावा द्वीप, ८, ५०, २३१ ।
जमागाह, १४६, १५५ १७१, १७३, १७७, १८२, १८६, १८७, २१४, २२०, २२६ ।	जिजी, ३६ ।
	जिनोआ, १ ।

जिलेस्पी, जनरल, २३५।  
 जी० आर्हो पी० रेलवे, ३५१।  
 जीनतमहल, बहादुरशाह की बेगम,  
 ३४६।  
 जेकिम, रिचर्ड, ३३७, ३३८।  
 जम्म पहला, ईंग्लैंड का राजा, १०,  
 ११।  
 जेम्सेलम, ४६१।  
 जेनावाद, ३३८।  
 जोधपुर १४१, २०१, २२२, २३१,  
 २४२, २५०।  
 जोन्स, सर विलियम, ११८, ५१८।  
 जोक, ५२८।  
 जंगबहादुर, नेपाल का प्रधान मन्त्रि,  
 २३७, ३६८।

### झ

झाजलाल, १२८।  
 झासी, ३३६, ३७०।  
 झिन्द, २२८।  
 झिन्दन रानी, ३१५।

### ट

टांगेड, जनरल, ४६०।  
 टाट, बर्नल, १४१, २३८, २५७, २५८।  
 टामस, मन्त, ६।  
 टिहरी, ५१७।  
 टीपू सुलतान, ११८, ११६, ११७  
 १२२ १२४, १२५, १२६, १३७,

१४०, १४६, १५०, १५४, १५५,  
 १५६, १५७, १५८, १५९, १६०,  
 १६१, १६२ १६३, १६५, १६६,  
 १६८, १६९, १७०, १८७, २०३,  
 २१४, २१५, २२० २२४, २२५,  
 २३८, २५०, २८०।

टेनामरिम, २६४, २६८।  
 टेम्पल, सर रिचर्ड, ३३६, ३६३।  
 ट्रेड्स डिस्प्यूट विल, ५०७।  
 टेड यूनियन विल ५०७।  
 टेरिफ बोर्ड, ४६७।  
 टोम गेट की चढ़ाई, २३।  
 टोक, २००, २४३।

### ठ

ठगों का दमन, २७६, २७७।  
 ठाकुर, श्रवनीन्द्रनाथ, ५१८।  
 ठाकुर, ज्योतीन्द्रमोहन, ४११।  
 ठाकुर, हारकानाथ, २७६।  
 ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ५०७।  
 ठाकुर, सुरीन्द्रमोहन, ५१८।  
 ठोमरे, न्यम्बक वापूजी, ५०८।

### ड

डफ, २८८।  
 डफ, ग्राट, ७६, १३६, १६३।  
 डफरिन, लार्ड, ब्राडमराय, २१५,  
 २१६, २१८, २१९, २२३, २०२,  
 ४०६, ४०७, ४२८।

डवल भत्ता, ६१ ।

डलहौजी, लार्ड, गवर्नर-जनरल,  
२५१, ३२०, ३२४, ३२५, ३२६,  
३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१,  
३३२, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७,  
३३८, ३४०, ३४१, ३४२, ३४४,  
३४५, ३४६, ३४८, ३४९, ३५०,  
३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५,  
३५६, ३५८, ३६०, ३६७, ३७४,  
३८१, ३८५, ३८६, ३८७, ४४८,  
४६१ ।

दाक, ३५०, ३५३ ।

डाक्ट्रिन ऑफ लैप्स (दायावसान का  
मिद्धान्त), ३३४ ।

डामन, ८ ।

दायर, जनरल, ४७२, ४७३, ४७४ ।

दायर्जी (देहरी शासन-व्यवस्था),  
४६७, ४६० ।

डिंडीगल, ७२, १३७ ।

डियाज, २ ।

डिरोम, मेजर, १६८ ।

डीग, २०८, २०९, २१० ।

डीवोयन, १४०, १४१, १४२, १६६  
२०३ ।

टुराड, हेनरी मार्टिंमर, ४०५ ।

टुटाज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर अ यत्न,  
१८८ ।

डुडीखा, ६६ ।

दूप्ते, २१, २२, २३, २४, २५, २६,  
२७, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४,  
६५, २१० ।

ड्यू, ८ ।

ड्यूमा, २०, २१, ३० ।

डे, कप्तान, ५१८ ।

डेकन वर्नाक्युलर ट्रान्स्लेशन सोमा-  
यटी, २५० ।

डेन्मार्क निवासी, १५ ।

डेक, कलकत्ता का गवर्नर, ४०, ४१,  
४४ ।

डेविड सेंट का किला, २४, ३४, ३५ ।

ढ

ढाका, २०, ५०, १०८, २६५,  
४४२, ५०० ।

त

तकी, मीर, ५२४ ।

तहफतुल मुजाहदीन, ३ ।

त्यागराज, ५१६ ।

तात्या टोपे, ३७०, ३७१, ३७२ ।

तार, ३५२ ।

ताशकन्द, ४०१ ।

तिब्बत, २३४, २६१, ४३६, ४३७,  
४४८, ४६४ ।

तिलक, बाल गंगाधर, ४३१, ४४८,  
४५०, ४६२, ४७५, ५०८ ।

तीराह, ४०६ ।

तुकोजी, होलकर, ७५, ७६, १८० ।

तुलक जर्हागिरी, ४३० ।

तुर्किस्तान, ४०१ ।

तुर्की, ४१५, ४३०, ४३५, ४६०,

४६१, ४७४, ४८१, ४८७ ।

तुलजाजी, तजोर का राजा, १७०,

५१६ ।

तुलजागकर, नन्दगकर, ४०६ ।

तुलसीदाई, होलकर, २४३ ।

तुलभद्रा, नदी, १३७ ।

तेजसिंह, ३१८, ३१९ ।

तेमूर का घराना, ३४६ ।

तेलग, बार्जानाथ त्र्यम्बक, ४०० ।

तजोर, २०, २५, २६, २८, २९, ३३,

८१, १७०, १७१, १७३, २७८,

३५०, ५१७, ५१६ ।

## थ

थार्नटन, इतिहासकार, १२४, २६० ।

थियामाफिकल सोसायटी ४०० ।

थीदा, दर्मा का राजा ४१६, ४१७,

४१८ ।

थार्न, मेजर, १६८, २०८ ।

## द

दत्त, माहकल मधुसूदन, ५२७ ।

दमःक, ४६१ ।

दमाजी, गायकवाट, ७२ ।

दयानन्द सरस्वती, स्वामी, ४१६, ४२०

दयाराम, ५०८ ।

दयालसिंह, ४०३ ।

दर्द, दर्द कवि, ५०४ ।

दलपतराम, ५०६ ।

दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह, ४५६ ।

दादा ग्वाग्गीवाला, ३०६ ।

दारापुरम्, १६६ ।

दासलडलूम, देवचन्द्र, ५०३ ।

दाम, चित्तरजन, ४८४, ४८५, ४८६ ।

दाम, यतीन्द्रनाथ, ५०६ ।

दामरोध, ५०८ ।

दिनकर राय, ३७६ ।

दिलीपसिंह, ३१५, ३१६, ३०१,

३०२, ३२६, ३०७, ३०८ ।

दिल्ली, १६, २४, ६०, ६३, ६८,

७५, १०७, १४१, १४२, १५२,

१६१, १६६, २००, २०८, २१६,

२७०, २७३, ३२६, ३५१, ३५७,

३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३७३,

३७४, ३७५, ३७६, ३८७, ४३६,

४४७, ४५२, ४५६, ४६१, ४६२,

४७०, ४७१, ५००, ५१०, ५१२

५१७, ५२२ ।

दिल्ली दरबार, (सन १८७७), ३६७,

(सन १९०३) २३६, (सन १९११)

४५४ ।

दीनाजपुर, १३२ ।

दीनानाथ, ३१४ ।

डीनापुर, ३६०, ३६६ ।

डीवान्, ६१, ६२, ६३, ८७, १३०,  
१४१ ।

दुर्जनसाल, २७०, २७२ ।

देवगाव की सन्धि, २०१, २०२ ।

देवनगिरि, ३८६ ।

देवीफोर्ट, ८१ ।

देहरादून, २३६, ४६५ ।

दोस्तमुहम्मद, जमीर, २८३, २८४,

२६७, २६८, २६९, ३००, ३०१,

३०२, ३०५, ३०८, ३५०, ३८३ ।

दोलतराव, मिर्जिया, १८०, १८२,

१८५, १८६, १८७, १८८, १८९,

१९०, १९१, १९३, १९४, १९७,

१९६, २००, २०५, २१८, २२१,

२२५, २२८, २४२, २४३, २७३ ।

दालताघाट, १४७ ।

## ध

धर्मशाला, ३८५ ।

ध्यानमिह, ३१४, ३१५ ।

धारवार, १३७ ।

## न

ननमुहोला, ५७, ५८, ६२, ६० ।

नडवतुलडलमा, लखनऊ, ५०३ ।

नदिया, १३० ।

नन्दकुमार, राजा, ५८, ६०, ६६

१००, १०१, १०२ ।

ननकाना का महन्त, ४८२ ।

नर्मदा, नदी, २४२, ३७५ ।

नर्मदाशकर, ५०६ ।

नरसिंहम्, लक्ष्मी, ५३० ।

नरेन्द्रमंडल (चेम्बर आफ प्रिसेज)

४६६, ५०६ ।

नवलराम, ५०६ ।

नसरुल्ला, ४८१ ।

नसरु, २३७ ।

नसिफेतोपाख्यान, ५२१ ।

नमीरुद्दीन हैदर, अवध का बादशाह,  
२८२, २६५ ।

नाइल का युद्ध, १६० ।

नागपुर, १८८, २४१, २७३, २६६,

३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३५७,

४७५, ५०० ।

नॉट, जनरल, ३०४ ।

नाट्टभाई, ४३१ ।

नादिरशाह, ३६२ ।

नादिरखान, ४८१, शाह, ४८२ ।

नानक, ८३ ।

नाना फड़नवीस, ७६, १०४, १०५, १०६,

१०७, ११५, १४२, १४३, १४४, १४६,

१४७, १५५, १७८, १७९, १८०,

१८१, १८२, १८३, २५०, २५१ ।

- नाना ग्राहक, ३५०, ३५७, ३६२, न्यूवरी, ६।  
 ३६५, ३६६, ३७५। न्यूयार्क, ४००।  
 नाभा, २०८, ४८३, ५०५। न्यूशपल की लडाई, ४६०।  
 नार्थग्रुक, लाई वाइसराय, ३६३, नूरमुहम्मद, मीर, ३०७।  
 ३६४, ३६५, ३६६, ३६६, ४०८। नूरमुहम्मद, मयद ( अफगानी राज-  
 नारायणराव पेशवा, ७६। दत्त ) ४००।  
 नावनिहालगिंह ३५५, ३५६। नगापट्टम, ८।  
 नावलर, अरमुग, ५३०। नपियर सर चार्ल्स, ३०७, ३०८,  
 नावलर, एलप्पा ५३०। ३०५ ३३३, ३५४, ३७५।  
 नानिक, ५२८। नपोलियन, १३४ १५५, १६० १६६,  
 नागिरजग, २४, २५, २६ २७। २३३, २४०, ३११।  
 निकलगन, कर्नल ३६० ३७३, नेहरू, मोतीलाल, ५०३।  
 ३७६। नेहरू रिपोर्ट, ५०४।  
 निवगन कप्तान, ७४। नटाल, ४५६, ४५७।  
 निजाम, १६, २४, २५, २६, ३०, ननीताल, २३६।  
 ३४, ७५, ७६, ८०, ११३, १२५, नेपाल २३२, २३५, २३६, २३७,  
 १३६ १३७, १४५, १४६, १४७, २४०, २४२, २४८, २४९, २५१,  
 १५४, १५६, १५७, १५८, १५९, २०६, २१४।  
 १६०, १६५, १६७, १६८, १६८, नाटन, कप्तान, २३६।  
 १६३, २०३, २०४, २०८ २५८, २८१, नेवेल पुरस्कार, ५०५।  
 २६५ ३१०, ३४० ३४१, ३५७, नेालन, इतिहासकार, २०३।  
 ३७६, ३८१, ४०७, ४२८ ५०५। नागिजी डाढाभाई २००, २०३, २०६,  
 निवन्धमाला ५२८। ४२८।  
 नीतिचन्द्रिका, ५३०। प  
 नील, कर्नल, ३६५ ३६६, ३६८, ३७३। पटना, १३, २०, २५, २६, ५३, ५४,  
 नीलगिरि की पहाटी ३८४। ८५, ६१, १००, १०८, २६० ३६६,  
 न्यूपाउडलेट, २। ५००, ५१८।

- पटियाला, ७०, २२८, ४८३, ५०७ । पामर कम्पनी, २५८ ।  
 पटेल, विट्ठलभाई, असेम्बली के पहले पामर, कर्नल, १८० ।  
 निर्वाचित अध्यक्ष, ५०८, ५०९ । पामस्टन, लार्ड, ३५८ ।  
 पन्नावत, ५२६ । पायनियर, समाचारपत्र, ४३८ ।  
 पनियर, की लडाई, ३०९ । प्राइज, विलियम, ७८ ।  
 पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ३५३, ३६१ प्लाउडन, रेजीडेंट, ४१८, ४२६ ।  
 ५१३ । पाल, १७४ ।  
 पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ४२८ । पालमैन, जर्मन अफसर, १६३ ।  
 पब्लिक मेपटी बिल, ५०८ । पालीलूर, ११४ ।  
 प्रतापसिंह, काश्मीर का महाराजा, पाशा, मुस्तफा कमाल, ४८७ ।  
 ४२६, ४७७ । पिट, इंग्लैंड का प्रधान सचिव, १५४  
 प्रतापसिंह, जयपुर का महाराजा, २११ ।  
 ५१८ । पिट का इंडिया ऐक्ट, ११६, १२३,  
 प्रतापसिंह, तजोर का राजा, ८१ । १३६, १४०, १४६, १५४, २१५ ।  
 प्रतापसिंह, सतारा का राजा, २६६, पिडारियो का दमन, २३७, २३८,  
 ३३६, ५२८ । २३६, २४० ।  
 प्रबोधचन्द्रिका, ५२६ । पिरार, फ्रांसीसी यात्री, ३ ।  
 प्रशिया, १५ । पिलाई, आनन्दरग, २५ ।  
 पलामी का युद्ध, ४७, ४८, ५७, ६७, प्रिसेप, २८६ ।  
 ३६० । पीगू, २६४, ३३१, ३३२ ।  
 पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, ४३४, ४६३ । पीलीभीत, ६६ ।  
 पाटन का युद्ध, १४१ । पुआवा का राजा, ३६८ ।  
 पाटणाह वेगम, २६५ । पुर्तगाल, २, ४, ६, ७, ८, १२, १५  
 पाटुचेरी, १५, २०, २१, २२, २३, १७ ।  
 २८, ३८, ३९, ३६, ४५, ११३, पुरन्दर, ( पुरन्धर ) २४४ ।  
 १८० । पुरन्दर की सन्धि, १०४ ।  
 पार्नापन, ६७, ६८, ७१, ७४, ७६, ७६ । पुर्णिया के नवाब, ४० ।



पुर्णिया, मैसूर का मंत्री, ११५, १६४

१६७, २८० ।

पूर्ण स्वराज्य-दिवस, ५११ ।

पूना, ६४, १०३ १०४, १२०, १५५,

१७६, १८०, १८८, २०३, २४५,

२४८, २४६, २५०, ३३८, ४३१,

५०० ।

पूलीकट, ८ ।

पूना का कृषि कालेज, ४६७ ।

पेटी, ८१ ।

प्रेमगानर, ५२१ ।

पेरन, ८३ ।

पेरिस की मन्धि, ३६ ।

पेरी, अर्मकाइन, ४१४ ।

पेरी, मिन्धिया का प्राप्तीली अफसर,

१६६ ।

प्लेग, ४३०, ४३१ ।

पेमली २६० ।

पेणावर, २३०, २८४, २६७, २६६

३०१ ३१६, ३२४, ३८६ ४००

४०८, ४३० ।

पेलेस्टाइन, ( फिलिस्तीन ) ४६० ।

पोप का आज्ञापत्र, ४, ६ ।

पोपम, मंजर, १०६ ।

प्रोम, २६८ ।

पोर्टोनांचो, ११४ ।

गोलव, जनरल, ३०४ ।

पजदेह ४१५, ४१६ ।

पजाव बोर्ड, ३०६ ।

## फ

फतहगढ़, १३६, २०८, ३०८ ।

फतहपुर, ३६५ ।

फतहपुर, मीरूरी, ६, ४४० ।

फर्ग्युसन, ५१४ ।

फर्ग्युसन, मुगल सम्राट्, ३८ ।

फाकम, ११६, १०० ।

फार्देस्क इतिहासकार, १६३ ।

फारम १७७, २००, २०८ २०६,

२३०, २५७, २६६, २६७, २६८,

२६६, ३६०, ३६१, २३३, ४३६ ।

फारम की न्यायी, १. ५, ११, ४३५,

४३६ ४४७ ।

फारेस्ट, इतिहासकार, ११६ ।

फामेट, हेनरी, ५०० ।

फास, १५, १७, २१, ३३, २१, ११३,

१३२, १३६, १५३, १५४, १५५,

२०७ २०६, २३१, २१६, ४३५,

४५६, ४६० ।

फामिस, फिलिप, ६८, ६६, १०४,

११७, ११६, १२०, १२०, १८३,

१६०, २०० ।

फिच गल्फ, ६ ।

फिरगिया, टग, २७७ ।

फिलिप दूसरा, स्पेन का राजा, ७ ।

फ़ीरोज़पुर, ३००, ३०६, ३१६, ३१७,

३१८ ।

फ़ीरोज़गढ़, की लडाई, ३१८ ।

फ़्रीमैन, ३८१ ।

फ़्रीस्टेट, ४५७ ।

फ़ुलर्टन, ८०, ८३, ८६ ।

फ़ुलर, मर बैमफील्ड, ४४६ ।

फ़ेन, प्रधान सेनापति, २६६ ।

फ़ेजर, हंदरावाद का रेजीडेंट, ३४०,

३४१ ।

फ़ेरे, मतारा का रेजीडेंट, ३३६ ।

फ़ैजाबाद, १११, ११२, २८२,

३६८ ।

फ़ैज़ुल्लाखा, ६५ ।

फ़ैमिन इन्ड्योरमेंस फंड ( अकालरत्ना-

कोष ), ३८८ ।

फ़ैमलिन, ११० ।

फ़ोर्ट विलियम, क़िला, १२, ८६ ।

फ़ोर्ट विलियम कालेज १७५, १७६,

१७७, २१०, ५२१, ५२५, ५२६ ।

फ़ोर्ड, कर्नल, ३८ ।

फ़ोर्म्स, ५२६ ।

## व

वक्कर, ३०० ।

वक्कर की लडाई, ५७, ५८, ५९, ६२ ।

वगदाद, ४६० ।

वच्चा मक्का, ( हवीबुल्ला ), ४८२ ।

वजघज, ८८ ।

वटलर, मर हारकोर्ट, ५०६ ।

वटलर कमेटी, ५०५, ५०६, ५०७ ।

वडौदा, १०६, २४४, ३६४, ५०५,

५२० ।

वदखर्गा, ३६१ ।

वदलीसराय की लडाई, ३६२ ।

वनजी, समेशचन्द्र, ४२३ ।

वनजी, मर गुरुदास, ४४१ ।

वनजी, सुरेन्द्रनाथ, ४०२, ४४२,

४४६ ।

वनारस, ६३, ६४, ६५, १०७, १०८,

१०९, १११, १२७, १३१, १७१,

१८७, २७२, २८१, २६६, ३२४,

३७३, ५१५ ।

वम्बई, नगर तथा प्रान्त, ११, १२,

१४, ५१, ७२, ७७, ८१, ६७,

६८, १०३, १०५, १२०, १२२,

१३७, १६२, २५६, २५७, २६६,

२६४, ३०८, ३३३, ३३६, ३८४,

४०७, ४११, ४१६, ४२२, ४२३,

४५२, ४६४, ४७१, ४७६, ५०७,

५१२, ५१३, ५२६ ।

वर्क, एडमंड, १००, १२१, १४५,

१५४, २२७, ४२२ ।

वर्टन, रिचर्ड, ३०७ ।

वर्टवान, ५२ ।

- वर्नियर, ३१ ।  
 वर्न्स, २६७, २६८, ३०६ ।  
 वर्मा का राज्य, २६२ ।  
 ब्रह्मममाज, २६० २००, ५०१ ।  
 बरार, १८८, २०१, ३४०, ३४१, ४३७ ।  
 बरहानपुर, १८८ १८९ १९४,  
 ३३८ ।  
 बरेली, ३६८, ३६९ ।  
 बलभद्रगिरि, २३५ ।  
 बमरा, ४६० ।  
 बमालतजग, निजाम का भाई, १३५ ।  
 बहादुरशाह, अन्तिम मुगल सम्राट्,  
 ३४६, ३५७, ३६१, ३६३, ३७५,  
 ४२४ ।  
 बास्टन, डाक्टर, ११ ।  
 बाजीराव ( पहला ), पेशवा, ७६,  
 २३७ ।  
 बाजीराव ( दूसरा ), पेशवा, १७६  
 १८०, १८३, १८५, १८६, १९६,  
 २४० २४४, २४५, २४६, २४७,  
 २५०, २५१, २५६, २५७, २७८,  
 ३०८, ३५०, ३६४ ।  
 बापू गोमले, २४५ ।  
 बायजाबाई, २७४ ।  
 बाइट, जान, २०२ ।  
 बाइटन, जान, डाक्टर, ३०३ ।  
 बाउन, जानपुर का कलेक्टर, २८२ ।  
 बास्टन, लार्ड, ३३५ ।  
 बार्कर, ६३ ।  
 बारडोली-निगुय, ४७८ ।  
 बारडोली से मर्याद ५०७, ५०८ ।  
 बारवेल, ६८, १०० ।  
 बाल-विवाह-निषेध कानून ५०१ ।  
 बालाजी, पेशवा, ७४, ७८, २४७ ।  
 बाला साहय, २४१, २४२ ।  
 बालामोर, ११, १६८ ।  
 बालेस्वर, २० ।  
 बारहद्वार, ३८६ ।  
 बारिकपुर, २६६, ३५८, ३५९, ३६० ।  
 बारिकपुर, का अनाययगर, २१६ ।  
 बारी दोआब नहर ३५३ ।  
 बालों मर जान, २२०, २२१, २२२,  
 २२३, २२४ २२५, २२६ ।  
 बावरिग, ११६ ।  
 बामनिया, २६० ।  
 ब्रिगो, मरजेट, ४४ ।  
 ब्रिटिश इंडियन मैनोमियमन, ४०३  
 ब्रिस्टो, ११० ।  
 ब्रिटिश म्युजियम, ५१८ ।  
 बिट्टर, २४६, ३३८, ३६४, ३६५ ।  
 बिलोचिन्मान, (बलचिन्मान), ३५०,  
 ४२४, ४३६ ।  
 बीकानर, ५०५ ।  
 बीजापुर के सुलतान, ४ ।

ब्रीटमन, कर्नल, १६० ।

ब्रीवीघर, का. रून, ३६५, ३६६ ।

ब्री० बी० मी० आई० रेलवे, ३५२ ।

बुकानन, डाक्टर, २१६, २६०, २६१ ।

बुटवल, २३५, २३६ ।

बुमी, २७, ३०, ३४, ३५ ।

बुटेलखंड, १६२, १६६, १६७, २०४

२०६, २७३, ३७०, ३७१, ३८८, ५१७ ।

बेकमफील्ड, लार्ड, इंग्लैंड का

प्रधान मन्त्रि, ३६७, ४०२, ४०३ ।

बेडनूर, ७३ ।

बेंटिक, विलियम लार्ड, २२४, २७४,

२७५, २७६, २८१, २८२, २८४,

२८५, २८८, २८९, २९०, २९२,

२९८, २९९, ३०३, ३५७, ४०५ ।

बेनफील्ड, पाल, १३८ ।

बेन, बेजवड, भारतसचिव, ५०६ ।

बेयर्ड, कर्नल, १७० ।

बेयरेट, कर्नल, ११४ ।

बेल, इब्राम, मेजर, २८०, ३२७ ।

बेल, फ्रेड्रिक, २८७ ।

बेलजियम, ४६० ।

बेली, कर्नल, ११४ ।

बेली कर्नल, लयनरु का रेजीडेंट,

२४० २४३ ।

बेली, बटवर्थ, २७५ ।

बेवरिन, इनिहामकार, १२४ ।

बेमीन, ७७, १०३, १०४ ।

बेसीन की मन्धि, १८२, १८३, १८४,

१८७, १८८, १८९, १९१, १९६,

२०३, २११, २२४, २४४ ।

बेम्बेट, मिसेज, एनी, ४२०, ४६३ ।

बैडला, सर चार्ल्स, ४२२, ४२७ ।

ब्लैकटफी, मैडम, ४२० ।

बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ११६, १५४, १८४

२११, २२७, २३८, ३०४, ३३१,

३३२, ३३५, ३४१, ३४२, ३७७ ।

बोर्ड ऑफ ट्रेड, ३२२ ।

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, २७५ ।

बोल्ड्स, ५६ ।

बोलन दर्रा, ३०० ।

बोस, आनन्दमोहन, ४२२ ।

बोस, सर जगदीशचन्द्र, ५३० ।

बोस्टन, ५१८ ।

बंग-विच्छेद, ४४२ ।

बगलौर, ७२, १३७ ।

बंगाल आर्टिजनेस, ४८६ ।

बंगाल की खाड़ी, १६६, ३३१ ।

बंगाल टेनेसी बिल, ४१६ ।

**भ**

भट्ट, बालकृष्ण, ५२२ ।

भट्ट, पद्माकर, ५२२ ।

भट्टीच, १६२, १६६, २०१ ।

भरतपुर, ७१, ७५, २०८, २०९, २१०

२१६, २२५, २७० २७१, २७२,  
५०५।

भागलपुर, २६०।

भाटगाँव, २३४।

भारतीय ढंड-विधान, २८६।

भावलपुर, २६७, ३००।

भावे, विष्णु, ५०८।

भूटान, २३४, ३८६।

भूपाल, ५२५।

भूपाल की ब्रेगम, ३८१, ३८६।

भूमध्य सागर, १।

भोमला फाट, ३३७।

भोमला शासन, ३३७, ३३८।

## म

मकमूदावाद, ३७।

मकाशरीफ, १३।

मछलीपट्टन की बोटी, १३, १५, २०।

मछेरी, ( अलवर ), २२५।

मसुरा २०८, ५१५।

मदरमनुल आलिया कलकत्ता, ५०३।

मदराम, नगर तथा प्रान्त, ८, ११,  
१२ १४ २१ २२, २३ २४, २७

२८, ३६, ३५, ४४, ४५, ५१, ७८,

८०, ८६ ६७, ६८, १०३, ११३,

११४ ११७, १२० १२२, १२५,

१३७, १४७, १५५, १५६ १५८,

१६२, २२०, २२४ २२५, २२७,

२५५, २५७, २६०, २६१, २६६  
२६७, २७४ २६८, ३८४, ३६७

४०७, ४११ ४२०, ४२२, ४२३  
४२५, ४२८ ४६४, ५१२ ५१३।

मनरो, सर टामस, २१३, २४०, २५४,  
२५५, २५६, २६० २७२।

मनरो, हेक्टर, ५७ ११४।

मनीपुर, २६४ २६५, २६८, २८३  
४०७।

मनुष्य-गणना, ( मनु१८८१ ) ४०६।

मजवानजी फर्दूनजी, ५२६।

मर्तमान, ३३१।

मर्ष, ४०३, ४१५।

मर्सर, डाक्टर, २६०।

मरे, कर्नल, २०६।

मलकापुर १८८।

मलका पर विनय, ५, ८।

मल्हारराव गायकवाड, ३६८।

मल्हारराव, हेलकर, ७६।

मलावार, ३, ८, ७३ ११३ १३५,  
१६८, १६६, २८५, २७७।

मलाना प्रायद्वीप ३३१।

मलावली १६२।

ममाला के टापू, ८, १०, २३१।

मसूरी, २३६।

महद्वजली खा निजाम, ४३८।

महाजनमभा, ४०३।

महानदी, ३६८ ।	२४५, २४६, २५७, २६२, २७५
महानसिंह, २२७ ।	४२२ ।
महाबन्धूला, बर्मा सरदार, २२५, २६६, २६८ ।	मालवा, ७६, १५५, २२२, २२५, २३७, २३८, २४४, २४६, २७३, ३७१ ।
महाराजपुर, ३०६,	मालवीय, मदनमोहन, ४२३, ४५८ ।
महीदपुर, २४३ ।	मास्टिन, टामस, ७२, १०४ ।
महीपतराम, २२३ ।	माहादजी, सिन्धिया, ६८, ७५, ७६, १०६, १०७, १२५, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४७, १६७, १६६, २०३ ।
माणिक्य, चित्रकार, ५१७ ।	माही, २०, ३६, ११३ ।
माणिक्यचन्द, राजा, ४३ ।	माटसोरी सिस्टम, २८७ ।
माधवराव, बल्लाल, पेशवा, ७४, ७५, ७७, ७८, ८६, १४३, २५० ।	माटिग्यू, एडविन, भारतसचिव, ४६०, ४६४, ४६६, ४८० ।
माधवराव, सर, दीवान, ३६५ ।	माटिग्यू-चेम्सफर्ड सुधार, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९ ।
माधवराव, सवाई, पेशवा, १०६, १७८, १७९ ।	मानसन, कर्नेल, २०६, २०८, २११ ।
मामा साहय, ३०६ ।	मानसन, ६८, ६९ ।
मार्कडम, रेजीडेंट, १०६ ।	माडवी, ३३३ ।
मार्टिन, इतिहासकार, ३६२ ।	मिडिल्टन, रेजीडेंट, ११२ ।
मार्टिन, फ्रांसीसी, २०, ३२ ।	मिदनापुर, ५२ ।
मार्ले, सर नान, भारतसचिव, ४५१, ४५४, ४६४ ।	मियानी का युद्ध, ३०७ ।
मार्ले-मिटो सुधार, ४५२, ४६२ ।	मिरथा का युद्ध, १४१ ।
मार्गमैत्र, १२४, १२६, २६३, २८८, २९० ।	मिल, इतिहासकार, ६५, १२४, १२६ ।
मारिगम, १५७, २३०, २३१ ।	मिलार्न, २६१ ।
मालकम, सर जान, ७०, ७६, १२३, १५१, १५६, १५७, २२२, २२३, २२६, २३०, २३७, २३८, २४१,	

- मिश्र, प्रतापनारायण, ५०० ।  
 मिश्र, नवल, ५०१ ।  
 मिश्र देव, १ १५५, १७७, ४१३,  
 ४१५ ।  
 मिटो, लार्ड, गवर्नर-जनरल, २०६,  
 २०७ २०८ २०९, २३०, २३१,  
 २३२ २३३, २५७, २६३, २६६ ।  
 मिटो (दूसरा) लार्ड, वाइसराय, ४२७,  
 ४४८, ४५० ४५३, ४५४, ४६३ ।  
 मीरआलम, २२३ ।  
 मीरकामिम, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५,  
 ५७, ६१, ८८ ।  
 मीरजाफर, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९,  
 ५०, ५१, ५२ ५४, ५५, ५७,  
 ५८, ६०, ६५ ८८ ९० ।  
 मीरन, ४८ ५१ ।  
 मीरनपुर बटारा, ६४ ।  
 मीरपुर, ३०६ ।  
 मीरमदन, ४७ ।  
 मुकुन्दरा, २०६, २०७ ।  
 मुजफ्फर खाँ, २८४ ।  
 मुजफ्फरजग २५, २६ २७ ।  
 मुजफ्फरपुर, ४४६ ।  
 मुहम्मद कमेटी, ४६० ५०१ ।  
 मुदकी की लटार्ड ३१८ ।  
 मुदली 'गेल्ड कंपनी' ५०० ।  
 मुन्ताजान, २६५ ।  
 मुनि, पर्णज्योति ५०६ ।  
 मुनि, वीरम ५३० ।  
 मुन्नी बेगम, ६० १०० १०४ ।  
 मुर्शिदकुलीया ३७, ३८ ।  
 मुर्शिदाबाद ३७ ४३ ४८, ८७,  
 ९१, १०८, ५१३ ।  
 मुलतान २८४, ३०३, ३०४, ३०५ ।  
 मुसलिम लीग, २४८, ४६० ।  
 मुसलिम विश्वविद्यालय अलीगढ़,  
 ५००, ५०५ ।  
 मुहम्मदअली शाह, अयध का शाह-  
 शाह, २६५, ३४१, ३४७ ।  
 मुहम्मदअली, कर्नाटक का नयाय,  
 २६, २७, २६, ३१, ८०, ८१,  
 १०७ १६८, १६९, ३५७ ।  
 मुहम्मदगाम, कर्नाटक का नयाय,  
 ३२६ ।  
 मुहम्मदरिजा खाँ ५७, ६०, ६०,  
 १००, १०१ ।  
 मुहम्मदरिजा, 'नगमाने आसफी' का  
 लेखक ५१८ ।  
 मुहम्मदशाह, सुगल मन्दाट ५१८ ।  
 मुनेर ५३ ।  
 मूर १६८ ।  
 मूलाज ३०३ ३०४ ३०६, ३०८ ।  
 मृत्युञ्जय, 'प्रचारचन्द्रिका' का लेखक,  
 ५०६ ।

मेघनादबध काव्य, ५२७ ।

मेटकाफ, सर चार्ल्स, २०५, २०८,  
२३६, २७०, २७१, २७२, २८१,  
२८६, २६२, २६३, ३०० ।

मेडोज, मदरास का गवर्नर, १३६,  
१३७ ।

मेयो कालेज, अजमेर, ३६० ।

मेयो, लार्ड, वाइसराय, ३८६, ३६०,  
३६२, ३६३, ३६५, ४०६ ।

मेरठ, ३५१, ३६०, ३६१, ३६२,  
३७४ ।

मेरान्द, ४०५ ।

मेमोपोटामिया, (हुराक) ४६०, ४६८ ।

मेहता, मर फीरोजशाह, ४२२, ४४६ ।

मकुडानल, सर एंटनी, ४३१, ४३४ ।

मेकडोनाल्ड, १८० ।

मकुनाटन, २६८, २६६, ३०१, ३०२,  
३०५ ।

मैफर्सन, मर जान, १८५ ।

मेकममूलर, ५२० ।

मेकाले, १०२, १२४, २८६,  
२८६, २६०, २६४, ३८३ ।

मैमनसिंह ४४२ ।

मैरिम संगीत-विद्यालय, लखनऊ, ५१६ ।

मैलापुर, २३ ।

मैलेसन, इतिहासकार, ३६३, ३६८,  
३७१, ३७२, ३७४ ।

मैसूर, ७२, ७३, ७५, ११३, ११५,

११६, १३४, १३५, १३६, १३७,

१३८, १४०, १४२, १४६, १५६,

१५८, १५६, १६२, १६६, १६७,

१६८, १८३, १६२, २४६, २६०,

२६२, २८०, २८१, ४०५, ४०६,

४६६, ५०५, ५१७, ५२० ।

मैचेस्टर, १३३, २६०, ३८३, ३६४,  
४३२ ।

मैसेल, रेजीडेंट, ३३६ ।

मोपला-विद्रोह, ४७७ ।

मोर्स, मदराम का अध्यक्ष, २१ ।

मोरोपन्त, ५२७ ।

मोलाराम, चित्रकार, ५१७ ।

मोहकमचन्द, २२८ ।

मोहतरफा, २४८ ।

मोहनलाल, मुणी, ३०२ ।

मगल पाडे, ३६० ।

मगलोर, की सन्धि, ११६, नगर, ११७,  
१२० ।

मेंडाले, ४१६, ४५०, ४६२ ।

## य

यशवन्तराव, होलकर, १८२, १८७,

१६०, २०३, २०४, २०५, २०६,

२०७, २०८, २०६, २१८, २२०,

२२२, २२३, २२५, २२८, २३१, २४३ ।

याकूबखां, ३६६, ४०२, ४०३ ।



याडव की सन्धि, २६८ ।

यूनान, ४६१ ।

यूनिवर्सिटीज ऐक्ट, ४४१ ।

यूफ्रेटीज, नदी, १ ।

यूरोपीय महायुद्ध, ४५६ ४६०, ४६१ ।

यंगहमवेड, कर्नल, ४३६ ।

## र

रघुनाथराव, ( राघोबा ) ७५, ७८ ७९, १०३, १०४, १०५, १०६,

११३, १७६, १८०, १८३ ।

रजवप्रली बेग, मिर्जा, ५०५ ।

रजासातव २६ ।

रणजीतसिंह पंजाब का महाराजा, २००, २०७, २०८, २०९, २३०,

२४२, २८३, २८४ २८५, २९७, २९८, ३००, ३०६, ३०७,

३१३, ३१४, ३१५ ३१७, ३२३, ३२५, ३२६, ३५७ ।

रणजीतसिंह, भरतपुर का राजा २०८ ।

रणवीरसिंह, काश्मीर का महाराजा, ४२५ ४२६ ।

रत्नागिरि, ४९८ ।

राउट टेबल कान्फरेन्स, ५९० ।

राघोजी ( पहला ), भोसला, २०, ७६ ।

राघोजी ( दूसरा ), भोसला, १८६

१८७, १८८ १८९, १९४ २०१,

२०२, २००, २४१, २४२, ३३८ ।

राजफोट ३६० ।

राजप्या त्रिकुट, ५३० ।

राजपूताना, ७०, ३७३, ३८८, ३८९, ५०७ ।

राज्यरंग ५०६ ।

राजवल्लभ, ४०, ६० ।

राजवल्लभ, विक्रमपुर का राजा, ५०६ ।

राजवाडे, विश्वनाथ शाहीनाथ, ५०८ ।

राजगाही, १३० ।

राजाराम, ७७ ।

राणोजी, पटेल, ७६ ।

रानाटे महादेव गोविन्द, ४०० ।

रानी केतकी सी रानी, ५०० ।

रानीगज, ३५१ ।

रायट्स, इतिहासकार, १२३, ४१८ ।

रायट्स, जनरल, २००, ४०५ ।

रामकृष्ण, परमहंस, २०१ ।

रामचन्द्रराव, ३३६ ।

रामनगर, १०८ ।

रामनारायण, बिहार का हाकिम, २६, ५३ ।

रामप्रसाद, ५२६ ।

रामपुर ६५ ५८५ ।

रामपुरा, २०६ २०७ २०८ ।

रामानुजम् ५३१ ।

रामराव, मल्हार, ५०८ ।  
 रामशास्त्री, न्यायाधीश, ७६, २४८ ।  
 रायगढ़, २४४ ।  
 रायदुर्लभ, ४७, ४६ ।  
 रायल इंडियन मेरीन, ४६६ ।  
 राय, कामिनी, ५२७ ।  
 राय, द्विजेन्द्रलाल, ५२७ ।  
 राय, भारतचन्द्र, गुणाकर, ५२६ ।  
 राय, राममोहन, राजा, २७६, २८६,  
 २८८, २८९, २९१, २९२, ४२१,  
 ५२६ ।  
 रायलपिडी, ३२५ ।  
 राय साहब, ३७१ ।  
 राष्ट्रमंडल (लीग ऑफ नेशंस) ४६२ ।  
 रिपन, लार्ड, वाइसराय, ४०४, ४०६,  
 ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११,  
 ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६,  
 ४१६, ४२२, ४२६ ।  
 रीडिंग, लार्ड, वाइसराय, ४७५,  
 ४७६, ४६१, ५०५ ।  
 रीणलू, फ्रांसीसी मंत्री, १५ ।  
 रकुनुद्दीन, निजाम का दीवान, १४५ ।  
 रहेलखंड, १६, ६६, ६४, ६५, १७३,  
 ३६८, ३६९, ३७५ ।  
 रपुर, २८५ ।  
 रुम, २८३, २८६, २८८, ३८७,  
 ३९१, ४०१, ४०४, ४१३, ४१५,

४१६, ४१८, ४३०, ४३५, ४३८,  
 ४४६, ४५६, ४६०, ४६१, ४६३,  
 ४८१, ५०८ ।  
 रेग्यूलेटिंग ऐक्ट, ६७, ६८, १०२,  
 १०३, १०६ ।  
 रेनल, मेजर, ११८ ।  
 रेर्मा, १४५, १५६, १५७, १६० ।  
 रेल, ३५१, ३५२ ।  
 रेलवे बोर्ड, ४६८, ४६९ ।  
 रैयतवारी बन्दोबस्त, २५५ ।  
 रो, सर टामस, १०, ११ ।  
 रोज, सर हथू, ३७१ ।  
 रोम साम्राज्य, १ ।  
 रोशनबेग, २४३ ।  
 रौलट, जस्टिस, ४७० ।  
 रौलट-बिल सत्याग्रह, ४७०, ४७१ ।  
 रगलाल, ५२७ ।  
 रंगून, २६६, २६७, २६८, ३३०,  
 ३३१, ३३२, ३६३, ४१६, ५०० ।

## ल

लखनऊ, ११२, १४८, १७३, ३३४,  
 ३४४, ३६४, ३६६, ३६७, ३६८,  
 ३७५, ३८२, ४६२, ४६६, ४८८,  
 ५००, ५१३, ५१६, ५२४,  
 ५२५ ।

लखनऊ कालेज, २८२ ।

लडलो, इतिहासकार, ३२७, ३७७ ।

- लतीफगढ़, १०८ ।  
 लन्दन, ६, १०, ५१० ।  
 लल्लू लालजी, ५०१ ।  
 लहामा, ४३७ ।  
 लक्ष्मणमिह, राजा, ५०१ ।  
 लक्ष्मीबाई, झाँसी की रानी, ३७०,  
 ३७१ ।  
 लक्ष्मीश्वरमिह, दरभंगा महाराज,  
 ४२० ।  
 लाजपतराय, लाला, ४५०, ५०३,  
 ५३१ ।  
 लायरडोने, २०, २३ ।  
 लायल, सर एल्फ्रेड, इतिहासकार  
 ११०, १२८, २१० ।  
 लारेंस, सर जान, ३६१, ३७८, ३७६,  
 वाइमराय, ३८५, ३८६, ३८७,  
 ३८८ ३८९, ३९०, ३९१, ३९५,  
 ४१५ ।  
 लारेंस सर हेनरी, १४६, ३००,  
 ३२४, ३२६, ३२६, ३४३, ३४८,  
 ३४५ ३४७, ३४८, ३६७, ४०० ।  
 लालसमुद्र, १ ।  
 लालसिंह, ३१६, ३१७, ३१८,  
 ३२० ।  
 लामवाटी की लड़ाई, २०१ ।  
 लाहौर, ७०, १४६, २०७, २८५,  
 २८४, २८६, ३०६, ३१७, ३१८  
 ३१६, ३०१, ३०३ ३०४, ३०५,  
 ५०८ ५०९ ५१० ५१०, ५१७ ।  
 लिटन, लार्ड, वाइमराय, ३८७, ३८६,  
 ३८७, ३८८, ३८९, ४००, ४०१,  
 ४०२, ४०३ ४०४, ४०५, ४०६,  
 ४१०, ४११, ४१४, ४२३, ४२६ ।  
 लिटन, लार्ड, दंगल का गवर्नर,  
 ४६१ ।  
 लिबरल फेडरेशन, नेशनल, ४७०,  
 ५०१ ।  
 लिम्पन, ३ ।  
 ली र्मागन, ४६८ ।  
 लीड्स, जारही, ६ ।  
 लीयार्नेर, इतिहासकार, ३३६ ।  
 लुधियाना, २०८, २१०, ३१८ ।  
 लूकन, एडमंड आर्चबिशप गवर्नर, २०० ।  
 लू की लड़ाई, ४६० ।  
 लेक, लार्ड, मेनापति, १८६, १८६,  
 २०१, २०५, २०६, २०८, २१०,  
 २१६, २३० ।  
 लेजिस्लेटिव आमेन्सली ४६६, ४८७,  
 ४८६, ४६८, ४६५ ।  
 लैली, ३८, ३९ ।  
 लैंग, मैथ्युण्ड, आर्मेन्स, ३८० ।  
 लैंगडोन लार्ड, वाइमराय २०८  
 २०५ ।

गमराव, मल्हार, ५०८ ।

रामशास्त्री, न्यायाधीश, ७६, २४८ ।

गयगढ, २४४ ।

रायदुर्लभ, ४७, ४६ ।

रायल इंडियन मेरीन, ४६६ ।

राय, कामिनी, ५२७ ।

राय, द्विजेन्द्रलाल, ५२७ ।

राय, भारतचन्द्र, गुणाकर, ५२६ ।

गय, राममोहन, राजा, २७६, २८६,  
२८८, २८६, २६१, २६२, ४०१,  
५२६ ।

रावलपिंडी, ३२५ ।

राव साहव, ३७१ ।

राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशंस) ४६२ ।

रिपन, लार्ड, वाइसराय, ४०४, ४०६,  
४०७, ४०८, ४०६, ४१०, ४११,  
४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६,  
४१६, ४२४, ४२६ ।

रीडिंग, लार्ड, वाइसराय, ४७५,  
४७६, ४६१, ५०५ ।

रीशलू, फ्रांसीसी मंत्री, १५ ।

रकुनुद्दीन, निजाम का दीवान, १४५ ।

रहेलखंड, १६, ६६, ६४, ६५, १७३,  
३६८, ३६६, ३७५ ।

रपुर, २८५ ।

रूम, २८३, २६६, २६८, ३८७,  
३६१, ४०१, ४०४, ४१३, ४१५,

४१६, ४१८, ४३०, ४३५, ४३६,

४४६, ४५६, ४६०, ४६१, ४६३,  
४८१, ५०८ ।

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट, ६७, ६८, १००,  
१०३, १२६ ।

रेनल, मेजर, ११८ ।

रेर्मा, १४५, १५६, १५७, १६० ।

रेल, ३५१, ३५० ।

रेलवे बोर्ड, ४६८, ४६६ ।

रैयतवारी बन्दोबस्त, २५५ ।

रो, सर टामस, १०, ११ ।

रोज, सर ह्यू, ३७१ ।

रोम साम्राज्य, १ ।

रोशनबेग, २४३ ।

रोलट, जस्टिस, ४७० ।

रोलट-बिल सत्याग्रह, ४७०, ४७१ ।

रंगलाल, ५२७ ।

रंगून, २६६, २६७, २६८, ३३०,  
३३१, ३३२, ३६३, ४१६, ५०० ।

## ल

लखनऊ, ११२, १४८, १७३, ३३४,  
३४४, ३६४, ३६६, ३६७, ३६८,  
३७५, ३८२, ४६२, ४६६, ४८८,  
५००, ५१३, ५१६, ५२४,  
५२५ ।

लखनऊ कालेज, २८२ ।

लडलो, इतिहासकार, ३२७, ३७७ ।

- लतीफगढ, १०८ ।  
लन्दन, ६, १०, ५१० ।  
लखलालजी, ५२१ ।  
लहासा, ४३७ ।  
लक्ष्मणसिंह, राजा, ५२१ ।  
लक्ष्मीबाई, फार्सी की रानी, ३७०,  
३७१ ।  
लक्ष्मीश्वरसिंह, दरभंगा महाराज,  
४२२ ।  
लाजपतराय, लाला, ४५०, ५०३,  
५३१ ।  
लावरडोने, २२, २३ ।  
लायल, सर एल्फ्रेड, इतिहासकार,  
११०, १०४, ०१२ ।  
लारेंस, सर जान, ३६१, ३७४, ३७६,  
वाइसराय, ३८५, ३८६, ३८७,  
३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९५,  
४१५ ।  
लारेंस, सर हेनरी, १४६, ३२२,  
३२४, ३२६, ३२६, ३४३, ३४४,  
३४५, ३४७, ३४८, ३६७, ४२२ ।  
लालसमुद्र, १ ।  
लालसिंह, ३१६, ३१७, ३१८,  
३०० ।  
लामवाडी की लडाई, ००१ ।  
लाहोर, ७०, १४६, २२७, २४५,  
२८४, २६६, ३०६, ३१७, ३१८,  
३१६, ३२१, ३२२, ३२४, ३२५,  
३२७, ३६१, ३६०, ४१६, ४२३,  
५०८, ५०९, ५१०, ५१२, ५१७ ।  
लिटन, लार्ड, वाइसराय, ३८७, ३६६,  
३६७, ३६८, ३६९, ४००, ४०१,  
४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६,  
४१०, ४११, ४१४, ४२३, ४२६ ।  
लिटन, लार्ड, दगाल का गवर्नर,  
४६१ ।  
लिबरल फेडरेशन, नेशनल, ४७०,  
५०१ ।  
लिस्वन, ३ ।  
ली कमीशन, ४६८ ।  
लीड्स, जौहरी, ६ ।  
लीवानर, इतिहासकार, ३३६ ।  
लुधियाना, २२८, २६७, ३१८ ।  
लूकन, एक अँगरेज अफसर, २०० ।  
लू, की लडाई, ४६० ।  
लेक, लार्ड, सेनापति, १८६, १६६,  
२०१, २०५, २०७, २०८, २१०,  
२१६, २७० ।  
लेजिस्लेटिव असेम्बली, ४६६, ४८७,  
४८६, ४६४, ४६५ ।  
लैली, ३४, ३५ ।  
लैंग, सैम्युएल, अर्थसदस्य, ३८२ ।  
लैसडोन, लार्ड, वाइसराय, ४२४,  
४२५ ।

लो, हैदराबाद का रेजीडेंट, ३४० ।

लोसान की सन्धि, ४८७ ।

लंका १७७ ।

लकाणायर, ३६८, ४३० ।

## व

वडगोव का समझौता, १०४, १०५ ।

वजीरअली, १४८, १४९, १७१,

१७३, १८७ ।

वयनाड, १६६ ।

वर्धेमा, इटालियन यात्री, ३ ।

वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट, ३६६, ४०६ ।

वसु, रामराम, ५२६ ।

वाजिदअली, अवध का अन्तिम बाद-

गाह, ३४१, ३४२, ३४५, ३४६,

३६७, ५२४ ।

वाटरलू का युद्ध, १६६ ।

वाट्स, ४५, ४७ ।

वाट्सन, ४४, ४७ ।

व्यास, अम्बिकादत्त, ५२२ ।

व्यास, कृष्णानन्द, ५१८ ।

वार्ड, २८८ ।

वास्कोडिगामा, २, ३, ४, ६ ।

वामिलमुहम्मद, २३८, २३९ ।

वाडवाश की लडाई, ३५, ७६ ।

विक्टोरिया, ईंग्लैंड की रानी, ३०४,

३११, ३२६, का घोषणापत्र, ३७६,

३८०, ३८१, ३८६, भारत की

सम्राज्ञी, ३६७, ३६९, ४१०,

४१२, ४३६, ४४४, ४५० ।

विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता,

५१४ ।

विक्रमपुर, २६५, ५२६ ।

विजयदुर्ग, ७७, ७८ ।

विजयनगर, ७० ।

विजय, पु गी, ५०६ ।

विद्यासागर, ईश्वरचन्द्र, ५२६ ।

विद्यासुन्दर, ५२६ ।

विनगेट, ४२६ ।

विलकिस, सर चार्ल्स, ५२६ ।

विलर्ड, कप्तान, ५१८ ।

विल्सन, अमरीका का राष्ट्रपति, ४६३ ।

विल्सन, इतिहासकार, २१३, २३५,

२३८, २६०, २८६ ।

विल्सन, जेम्स, अर्थसदस्य, ३८० ।

विलियम, कैसर, ४६१ ।

विलियम चौथा, इंग्लैंड का राजा,

२८५ ।

विवेकानन्द, स्वामी, ४२१ ।

वीरेशलिगम्, ५३० ।

वुड, चार्ल्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का

अध्यक्ष, ३४१, ३४२, ३५३, ३५४,

३८४, ४६१ ।

वुड, डाक्टर, ३७४ ।

वेडरवर्न, सर विलियम, ४२२ ।

वेनिस, १, २ ।

वेरेल्स्ट ८७ ।

वेल्लेजली, आर्थर, १६२, १६७, १८४,

१८५, १८६, १८८, १८९, १९०,

१९०, १९३, १९४, १९५, २०२,

२०३, २०५, २०६, २११, २१४,

२१८, २३८, वेल्लिगटन, ड्यूक,

२६६, ३११ ।

वेल्लेजली, लार्ड, गवर्नर-जनरल, १४६,

१५३, १५४ १५५ १५६, १५७,

१५८, १५९, १६०, १६१, १६२,

१६५, १६६, १६७ १६८, १६९,

१७०, १७१ १७२, १७३, १७५,

१७६, १७७, १८१, १८२, १८३,

१८६, १८९, १९०, १९१, २०२,

२०३, २०७, २१०, २११, २१२,

२१३, २१४, २१५, २१६, २१८,

२१९, २२०, २२१, २२६, २३१,

२३२, २३५, २३८, २५६, २६०,

२६३, २६१, २६५, २६६, ३०३,

३११, ३५५, ४४४ ।

वेल्लेजली, हेनरी, १६७, १७३, १७४ ।

वेचुरा, २२७ ।

वेनमिटार्ट, वगाल का गवर्नर, ५०, ५४ ।

श

शम्भाजी, ७७ ।

श्याम, ४३३ ।

श्यामसिंह, ३१६ ।

श्यामस्तार्फ, ३८ ।

शालिगढ़, ११४ ।

शास्त्री, श्रीनिवास, ४६२ ।

शास्त्री, स्वामीनाथ, ५३० ।

शास्त्री, सूर्यनारायण, ५३० ।

शाहआलम, मुगल सम्राट्, ५७,

५८, ६१, ६७, ६८, ७५, ८०,

१४०, १४१, १६१, १६६, २००,

२०१, २१६ ।

शाहगज, ३४७ ।

शाहजहाँ, मुगल सम्राट्, ११, ३६२ ।

शाहजहाँपुर, ३६८ ।

शाहपुरी का टापू, २६५ ।

शाहशुजा, अमीर, २३०, २८३,

२८४, २८५, २८७, २८९, ३००,

३०१, ३०५, ३०७, ३१६ ।

शाहाबाद, २६० ।

शाहू, महाराज, ७६, ७७, ८१ ।

शिकारपुर, ३०० ।

शिकिम, २३५, ( सिक्किम ) ४३६ ।

शिताधराय, ६०, १०० ।

शिमला, २७२, २६६, ४४१, ४५६,

४६२ ।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी,

४८२, ४८३ ।

शिवप्रसाद राजा, ५०१ ।

शिवाजी, ७७, ८१, २३७, २४६,  
२४७, २५१, २५२, ३५७ ।

शिवाजी, तंजोर का अन्तिम राजा,  
३५०, ५१७ ।

शिवप्रकाश, स्वामी, ५३० ।

शिक्का कमीशन, ( सन् १८८१ ),  
४०६ ।

श्रद्धानन्द, स्वामी ४८६ ।

श्रीनिवासदास, लाला, ५२२ ।

श्रीरामपुर, १५, २३१, ५०१, ५२६ ।

श्रीरंगपट्टन, १३७, १५६, १६१,  
१६२, १६६ ।

शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, ५७,  
५८, ६१, ६३, ६८, ११०, ११२,  
१२६, ३४६ ।

शून्यपुराण, ५२६ ।

शेफर्ड, १६७ ।

शेरअली, अमीर, ३८६, ३८७, ३६०,  
३६५, ३६६, ३६६, ४०२, ४०३,  
४०५ ।

शेरमिह, छत्रमिह का लडका, ३२४,  
३२५ ।

शेरमिह, रणजीतसिंह का दूसरा  
लडका, ३१५, ३१६ ।

शेरिडन, १२० ।

शोर, फ्रेडरिक, २८२ ।

शोर, सर जान, गवर्नर-जनरल, १३०,  
१३१, १४०, १४२, १४५, १४६,  
१४७, १४८, १५०, १५३, १५४,  
१७२, १७४, २१२ ।

शोरी, ५१८ ।

श्यांराज, २३५, २३६ ।

शवाई, ४८३ ।

## स

सखाराम बापू, १०४ ।

सनलज, नदी, २२८, २२६, २३४,  
२८४, २८५, ३०८, ३१७, ३१८,  
३१६ ।

सतारा, ३३५, ३५७ ।

सतारा के राजा, २४६ ।

स्कीन, जनरल, ४६५ ।

सती-प्रथा, ५, ८४, २५०, २७७,  
२७८, २७६, २६१, ३२१, ३५८,  
५०१ ।

सदर दीवानी अदालत, १२८, २६४ ।

सदर निजामत अदालत, १२८ ।

सदाशिवराव भाऊ, ७१ ।

सदासुखलाल, मुशी, ५२० ।

सफदरजंग, ६८ ।

समरू, ५४ ।

समरू ब्रेगम, १६४, २०१, २०४ ।

समाचारदर्पण, (वैंगली पत्र) २६३ ।



सरफोजी, नजोर का राजा, १७०  
 ५१७।  
 सर्वदल-सम्मेलन, ५०३, ५०५  
 ५०५।  
 सर्विया, ४६०।  
 सेवट ऑफ दि पीपुल सोमायटी,  
 लाहोर, ५०३।  
 सरम्बतीचन्द्र, ५०६।  
 सरहिन्द, ७०।  
 सलावतजग, २७, ३०।  
 स्वराज्य दल, ४८४, ४८५, ४८६,  
 ४८७।  
 सहायक प्रधा, १५६, १६७, १६८,  
 २१०, २१३।  
 महारनपुर, ४८७।  
 स्थानीय स्वशासन, ४०६, ४०७।  
 साइमन, सर जान, ५०२।  
 साइमन कमीशन, ५०१, ५०२, ५०३  
 ५०६।  
 सागर का जिला, २४२।  
 साडर्स, पुलिस कमिश्नर, ५०८।  
 साडर्स, मदरास का अध्यक्ष, २८।  
 सादतशली, अवध का नवाब, १४८  
 १४६, २५०, ३४६।  
 सादतखा, अवध का सूबेदार, १६,  
 ६८।  
 सादरग, ५१८।

माटी, गेम्स, ५०४।  
 मायितजंग, ६६।  
 मालवाई की सन्धि, १०६, ११५,  
 ११७, १४०, १४१, १४४, १६६।  
 मालमट, १०३, १०४।  
 स्काट, कर्नल, १७३।  
 स्याम, २६४।  
 सालिमवरी, भारतसचिव, ३६६।  
 सार्वजनिक सभा, ४२३।  
 मालारजग, ३७६, ४३६।  
 सावनमल, ३२३।  
 साहबदयाल, सर, ४१४।  
 सिगौली की सन्धि, २३६।  
 स्टिफन, सर जेम्स, १००, १०२, ३८१।  
 सिघेल्म, ६।  
 सिटन, ३६८।  
 स्टिवार्ट, मेजर, २७३।  
 स्टिवेंस, ६।  
 स्टिवेंसन, १८६, १६४।  
 सिन्ध, २३०, २८३, २८४, २६७,  
 ३००, ३०६, ३०७, ३०८।  
 सिन्ध, नदी, २८३, २८४, २६६, ३००,  
 ३०६।  
 सिन्ध, इतिहासकार, ६५, १०२, ११३,  
 ११६, १३१, २२१, २७३, ३०४।  
 सिन्ध, कर्नल, ७३।  
 सिन्ध, जार्ज, ८०।

स्मिथ, मेजर, ६७ ।

मिराजुद्दौला, ८०, ८३, ४५, ८८,  
४६, ५८, ८४, ८८ ।

सिंह, सत्येन्द्रप्रसन्न, कानूनी सेम्बर  
८५०, लार्ड भारत का उपमन्त्रि,  
८६१, ४६५, बिहार और उड़ीसा  
का गवर्नर, ४७० ।

सीतावलदी, २४२ ।

स्लीमैन, कर्नेल, २६२, २७७, ३०६,  
३०३, ३२४, ३४३, ३४४, ३४५,  
३४७, ३४८ ।

सुखसागर, ५०० ।

सुचेतसिंह, ३१४, ३१५ ।

स्टुअर्ट, १६२, १६५, २११ ।

सुप्रीम कोर्ट, ६७, ६८, १००, १०१,  
११८, २६४, ३८३ ।

सुप्रीम कौंसिल, ३३२ ।

सुन्दरारायडू, ५३० ।

सुवर्णदुर्ग, ७७, ७८ ।

सूरजमल, ७१, २०८ ।

सूरत, १०, १३, १५, १७, २०, ३६,  
८१, १३३, १७५, २४८, ५१३ ।

सूरत की फोटी, १० ।

स्टेट्समैन, पत्र, ४४३ ।

स्टेपर, ६ ।

स्पेन, ७, १०, ३११ ।

स्पेन का राजा, २ ।

स्वेज की नहर, ३६४, ८१३ ।

सेन, फेणवचन्द्र, २६०, ८०१ ।

सेन, जयनारायण, ५०६ ।

सेन, नवीन, ५०७ ।

सेटल हिन्दू कालेज, बनावर, ८५८ ।

सेट हेलेना का टापू, २४० ।

सेलेक्ट कमेटी, ८७, १०४ ।

सेलम, १३७ ।

स्कैपटन, ८० ।

स्टैची, सर जान, ३३४, ३६३, अर्थ-  
सदस्य, ३६७, ३६८ ।

सैयद अहमद खाँ, सर, ३६८, ३६९,  
५०५ ।

सोज, उर्दू कवि, ५०४ ।

सोने की चिड़िया, २ ।

सोमनाथ का फाटक, ३०५ ।

सोवराव की लडाई ३१८ ।

सौदा, उर्दू कवि, ५२४ ।

संगीतरागकल्पद्रुम, ५१८ ।

संगीतसार, ५१८ ।

संगीतमरामृतम्, ५१६ ।

समारचन्द्र, राजा, ५१७ ।

ह

हकीम मेहदी, २८० ।

हजारा, २८४, ३२०, ३०४ ।

हटन, इतिहासकार, २१४ ।

हदीम, ६१ ।



